



# विषय-सूची

कृति	कर्त्ता	क्रम
भूमि समस्या के दो पहलू	श्री रगनाथ रामचन्द्र दिवाकर	१
भूमि उपयोग की योजना	श्री जे० सी० कुमारप्पा	४
जमीन्दारी उन्मूलन का इतिहास	प्रो० एन० जी० रागा	७
प्राचीन भारत के गाव	डा० राधा कुमुद मुखर्जी	१०
भारत में भूमि व्यवस्था का भविष्य	डा० सुविमल चन्द्र सरकार	१४
प्राचीन, मध्ययुगीन एवं वर्तमानकालीन छोटानागपुर	श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह	२१
भारत में भूमि समस्या के समाधान की योजना	डा० श्रीमती सीता परमानन्द	२५
कौटिलीय अर्थशास्त्र में भूमि व्यवस्था	डा० वी० पी० सिंह	२९
मिन्न की नई भूमि व्यवस्था	श्री हरेन्द्रदेव सिंह	३१
सोवियत रूस की भूमि व्यवस्था	श्री गिरीन्द्र मोहन भट्ट	३३
भूमिसुधार कानूनों का क्रम	डा० एम० श्रीनिवासन्	३६
भारत में भूमिस्वत्व	प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र	४१
बिहार में कृषि भूमि एवं उसकी समस्याएँ	श्री सरस्वती प्रसन्न शास्त्री	४५
पड़ोसी नेपाल में भूमि की हीन दशा	श्री रुद्र प्रसाद गिरि	४८
बम्बई में भूमि सुधार	डा० जी० डी० पटेल	५१
हमारी खाद्य समस्या, उत्पादन की दृष्टि से	श्री रामावतार लाल	५४
भूमि का कार्याकल्प	श्री कन्हैयालाल माणिक लाल मुन्शी	६२
बिहार में सामुदायिक विकास योजना के तीन वर्ष	श्री आर० बालचन्द्र	६५
उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कानून	श्री जी० डी० अग्रवाल	६७
राजस्थान में भूमि सुधार	श्री दूल सिंह	७०
कश्मीर, हैदराबाद, आसाम, हिमाचल प्रदेश, पेश्वू, मध्यभारत, पश्चिम बंगाल और सीराष्ट्र में भूमि सुधार	श्री कैलासनाथ भारती	७६
बिहार में भूमि सुधार की प्रगति	श्री राम लखन सिंह यादव	८०
प्राचीन भारतीय ग्राम पंचायतें	श्री देव प्रसन्न मालवीय	८५
भारत में छोटे तालाबों से सिंचाई की संभावनाएँ	श्री न० व० गादरे	८९

कृति	कर्ता	क्रम
भारत की आर्थिक प्रगति	.. श्री गगन विहारी लाल मेहता .	९१
ग्राम पचायत और ग्राम विकास	... श्री त्रिलोक सिंह . . ....	९४
मध्ययुगीन यूरोप की किसान क्रान्तिया और भूमि सुधार एक सिंहावलोकन	श्री हर्षदेव मालवीय . .	९७
वेदों में कृषि का उल्लेख	श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव, विद्यावाचस्पति . .	१११
आधुनिक हिन्दी साहित्य में किसान	श्री मन्मथ नाथ गुप्त . .	११३
भूमि समस्या के सम्बन्ध में चीन का दृष्टिकोण	प्रो० अर्जुन प्रसाद चौबे 'काश्यप' .	१२०
आर्थों की ग्राम पचायतों और उनकी चुनाव व्यवस्था	श्री प्रभाकर माचवे . .	१२६
भारतीय कृषि का एक महान रोग, खेतों का विभक्तिकरण	श्री अरुनीन्द्र कुमार विद्यालकार ...	१२९
वन सम्पदा का महत्त्व	श्री योगेन्द्र नाथ सिन्हा तथा श्री सच्चिदानन्द सिंह .	१३७
बिहार में कृषि का पुनस्तघटन	प्रो० केदार नाथ प्रसाद	१४२
भूदान आन्दोलन का आघार	डा० ओम प्रकाश गुप्त	१४५
ग्रामीण उद्योगों का विकास	श्री जयनारायण सिंह	१५२
बिहार भूमि की देन, खान, धातु और खनिज	श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी .	१५७
घरती के गीत	श्री देवेन्द्र सत्यार्थी .	१६९
कृषि की उत्पत्ति और वैदिक युग में भूमि व्यवस्था	श्री प्रमथनाथ गुप्त . ....	१७३
नवीन चीन के खेती सम्बन्धी कानून सुधार का एक विश्लेषण	श्री बी० एन० गागुली	१७७
वन्य सस्कृति की आघारशिला	श्री जगदम्बा शरण शर्मा	१८२
आज के चीन की भूमि और किसानों की समस्याएँ	श्री तारकेश्वर प्रसाद वर्मा	१८५
घरती किसकी ?	.. डा० पाण्डेय रामावतार शर्मा	१९२
नये समाज के निर्माण में भूमि समस्या का समाधान	श्री शारदा रजन पाण्डेय	१९२
भूमिहीनों का स्वत्व	. रेवरेंड फादर ई० डी० म्युल्डर	१९८
सोवियत रूस में सम्मिलित कृषि	..	२००



# भूमि समस्या के दो पहलू

श्री रंगनाथ रामचन्द्र दिवाकर

यह प्रायः कहा जाता है कि ममस्त ससार की तुलना में एशिया में ही भूमि-समस्या सर्वाधिक जटिल है, यानी समस्याओं की समस्या है। यह समस्या भारत में अधिक पेचीदी है और भारत देश के भी उन राज्य में, जहाँ मुख्यतया लोगों के जीवन का साधन कृषि ही है। इसके लिए अनेक समाधान प्रस्तुत किये गये हैं और यथामाध्य उन्हे वैधानिक एवं व्यावहारिक रूप देने की मच्चेप्टाए की जा रही है। लेकिन उनके साथ ही कोई भी व्यक्ति निश्चित होकर यह नहीं कह सकता कि केवल वैधानिक व्यावहारिकता में ही ममस्त समस्याओं का हल हो जायगा। तर्क और फिर पूर्ण कार्यकारण व्यवहार की दृष्टि में विधान या कानून का अत्यन्त सरल होना अनिवार्य होगा। फिर ऐसे मूलभूत कार्य न तो स्वतः मरल होते हैं और न उनका कार्यरत ही बहुधा आमान हुआ करता है। जो भी कार्य उन दिना में हुए हैं या हो रहे हैं उन पर प्रगल्भता प्रकट की जा सकती है फिर भी उनमें किसी प्रकार की ढीलाई अनरिहार्य रूप में अप्रशमनीय समझी जायेगी। समस्या अपने आप में पेचीदी है तथा कई कारणों से अपने आप में उलझी हुई भी। पर वर्तमान परिस्थिति को तो चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना होगा एवं अपनी योग्यता के अनुकूल इसका सही समाधान निकालना होगा।

भूमि की समस्या कृषि योग्य भूमि का प्रमुख प्रश्न है या वैसे भूमि-खड का जिनका उपयोग वागवानी या चारागाह के रूप में होता है। इसमें तमिक भी सदेह नहीं कि जमीन ही साद्योत्पादन का प्रमुख साधन है। इसके साथ ही उद्योगों के लिए कच्चे मालों का उत्पादन भी भूमि में ही सम्भव होता है। भूमि का उद्देश्य उत्पादन है, उसकी उपयोगिता अत्यधिक उत्पादन है, वैसे उत्पादन जैसा समाज अपनी आवश्यकता के अनुसार चाहता हो या उसे जरूरत हो। अतः भूमि साधन है और उत्पादन साध्य, इसलिए मालकियत का ज्वलत प्रश्न मम्मुखीन हो जाता है, चूँकि इसी पर अधिक उत्पादन की समस्या निर्भर है। सम्भवतः इसी कारण अत्यन्त प्राचीन काल में ही भूमि के उद्देश्य के बारे में कहा जाता रहा है कि "समस्त भूखड पर मानव समाज का अधिकार है, राज्य का स्वामित्व है या जोतनेवालों की जमीन होनी चाहिए।" इन सब नारों का इसीलिए एक निश्चित दार्शनिक मूल्य स्थिर हो चुका है व इनका दीर्घकालीन एक निश्चित स्वरूप बन गया है।

भूमि की यह समस्या इतनी सश्लिष्ट हो गई है इसके भी अनेक कारण हैं। पर ममस्त सश्लिष्टता या उलझन की जड में एक कारण है और वह यह कि सर्वापेक्षा महत्त्वपूर्ण होने पर भी भूमि ही यहाँ उत्पादन का एक मात्र साधन है। उत्पादन का क्रम भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न स्तर का है और परिवर्तित परिस्थितियों में इसका क्रम प्रायः बदलता रहता है। भूमि एवं उसके उपयोग करनेवालों में पारस्परिक प्रभेद है और वह प्रभेद मालकियत पर निर्भर करता है एवं इसके अतिरिक्त अन्य कई मनोवैज्ञानिक पहलू भी इसके हैं, जैसे भूमिहर, मालकियतके प्रभेद, सरक्षण तथा सामाजिक दायित्व का बोध। जो लोग अत्यधिक उत्पादन का आदेश अपने नम्मुख रखते हैं व जिनके समक्ष मनुष्यों, भूमि के उपयोगको और इसी प्रकार के अन्य विचार रखनेवालों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे भूमि-समस्या के साथ-साथ ऐसे उपाय या हल निकालें जिसमें भूमि का प्रग्न उत्पादन की समस्या के साथ सुव्यवस्थित हो जाय। इसके साथ ही एक प्रकार का कार्यकरण सदा के लिए नहीं तो कम-से-कम सर्वाधिक अवधि के लिए अवश्य ठीक रहे।

हमारे देश में भूमि-समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब सब लोगों को सामाजिक न्याय मिले, अत्यधिक एवं अत्युत्तम फसल उपजें। सामाजिक न्याय दिलाने एवं प्राप्त करने की आवश्यकता लोक जागरण के सर्वथा अनुकूल है। भारतीय विधान की ३८, ३९, ४१, और ४३ धाराओं में इसका स्पष्ट उल्लेख भी कर दिया गया है। यह आज की सरकार का पुनीत कर्तव्य है। अत्यधिक उत्पादन इसलिए भी आवश्यक है चूँकि हमारा वर्धिष्णु देश द्रुत गति से बढ़ती हुई आवादी के पेट भरने के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं कर सकता है। इनमें से किसी भी तथ्य की उपेक्षा करना अत्यधिक हानिकर सिद्ध हो सकता है। उपेक्षा का सीधा अर्थ होगा क्रांति को आमंत्रण करना, अपने देश को अधिकाधिक गरीब बनाना या बड़े पैमाने पर निकट भविष्य में अकाल को बुलावा देना। जो लोग केवल भूमि के बटवारे को ही अधिक उत्पादन का जरिया मान लेंगे और यह समझ लेंगे कि केवल भूमि के समविभाजन से ही अपने आप उत्पादन बढ़ा जायगा व वास्तविकता से दूर, बहुत दूर हट जायगे। सब लोग यह जानते हैं कि लाखों ऐसे किसान हैं जो पर्याप्त एवं प्रचुर भूमि रहने पर भी कई कारणों से अधिक

अन्न नहीं उपजा सकते। इसके भी कई कारण हैं। किसान की लगन, उसकी रुचि, उसकी मौलिक उद्भावना के साथ-साथ स्थिति-सम्मत साधन एवं उपादान उसे चाहिये, जैसे पर्याप्त सिंचाई का इन्तजाम, कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक शिक्षा, अच्छे बीज और पूजी की आवश्यकता पड़ती है। अगर किसी को जमीन मिल गई तब भी उपादान उसे उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। किसानों की सब आवश्यकता भी मिटानी पड़ेगी, यह समाज एवं सरकार का दायित्व है। यह भी ध्यान में रखना जरूरी है कि अत्यधिक उत्पादन से समान वितरण भी संभव नहीं होने को। आज के सप्ताह में कोई भी सम्यक् समाज समान वितरण के बिना संरक्षित नहीं रह सकता है। इसलिए केवल अधिक अन्न उपजाओ के समाधान से ही स्थायी तुष्ट समाज की स्थापना निरापद रूप से नहीं हो सकती है। अतः हम सबका उद्देश्य हो जाता है कि दोनों पहलुओं के समाधान पाने की चेष्टा करें। अगर इन दोनों में से किसी का भी सतुलन विगड़ा तो समता का आदर्श ध्वस्त हो जायगा और उसीके परिमाणस्वरूप समस्त सामाजिक आकृति में विशु खलता फैल जायगी।

यह कहा जा चुका है कि भूमि के वितरण एवं अत्यधिक उत्पादन की समस्याएँ परस्परवलंबित हैं और दोनों समान रूप से महत्त्वपूर्ण हैं लेकिन इसमें भी सन्देह नहीं कि सामाजिक संरक्षणवाला पहलू आज अत्यधिक सक्रियता की अपेक्षा रखता है। इस समस्या पर जनता का ध्यान स्थिर हो चुका है, इसके भी कई कारण हैं, सामुदायिक जागरूकता, आर्थिक सन्निपात, लोगों में जमीन की लिप्सा, राजनीतिक दलों द्वारा विभिन्न आकारों के आन्दोलन एवं सर्वाधिक भारतीय संविधान में इसकी प्रतिष्ठा। अब भय इस कारण है कि कहीं इसकी अवहेलना के कारण प्रतीक्षा न की जाय और भावनात्मक प्रक्रियाओं को अधिक दिन कार्यकारी होने से रोक रखा न जाय। इसके अतिरिक्त देश में और देश के बाहर भी ऐसी शक्तियाँ हैं जो मौका पाकर विद्रोह फैलाने की ताक में बैठी हैं। यह भी मान लिया गया है कि अपर्याप्त उत्पादन का अर्थ आर्थिक विपर्यय होता है। यह विपर्यय न केवल भावनात्मक उभाड़ के रूप में होता है बल्कि इससे सामाजिक व्यवस्था भी कमजोर होने लगती है। प्रत्येक को यह स्वीकार करना होगा कि असंगत सामाजिक और आर्थिक अवस्थाएँ लोगों को आदोलित, प्रेरित एवं विक्षोभ-विकम्पित करती हैं। लोगों को पहले सामाजिक अन्याय, आर्थिक विषमता खटकती है। जो लोग अत्यन्त सुनिश्चित व्यवस्था करना चाहते हैं वे ऐसी परिस्थिति सहन नहीं कर सकते। ऐसे नियामकों एवं व्यवस्थापकों का प्रधान कर्तव्य हो जाता है कि वे भूमि-समस्या का हल करते समय इन दोनों पहलुओं पर ध्यान रखें।

अब उन कार्यों का एक-एक करके लेखा-जोखा उपस्थित किया जाय जो हमें दिया में सुनिश्चित रूप से किये गए हैं। सर्वप्रथम यह देखा जाय कि सामाजिक संरक्षण की दिशा में क्या किये गये हैं और अभी उसके सम्बन्ध में किम प्रकार के आदर्शों की स्थापना की गई है या मान्यता दी गई है।

स्वतंत्र भारत में देशी रियामतो का उन्मूलन और उनका एकसत्ता के अन्तर्गत विलयन सबसे पहला महान, निदिष्ट एवं बलवान कदम है। देशी रियामतो के पाम अपनी गलतदमन, अपनी आय, अपनी सुरक्षा थी,

अपने दुर्ग और किले थे और क्या-क्या नहीं था। उनके राज्य विस्तार में जमीन्दारी, जागीरदारी तथा अन्य ऐसी पद्धतियाँ प्रतिष्ठित थी जिस कारण रैयतो को उनके अधीन बरबस रहना पड़ता था। दूसरा महत्त्वपूर्ण कदम है कई राज्यों में जमीन्दारी प्रथा के उन्मूलन का। जमीन्दारी उन्मूलन का उद्देश्य यह था कि राज्य एवं प्रजा के बीच की मध्यस्थ दीवार तोड़ दी जाय। यह क्रम अभी भी जारी है। फिर प्रत्येक परिवार के लिए भूमि का अत्यधिक मान स्थिर किया जा रहा है। इसमें एक ही व्यक्ति के कब्जे में अधिक भूमि नहीं आवेगी, चाहे वह जिस जरिये से आती रही थी। ये कदम सघीय सरकार या राज्य सरकारों द्वारा उठाये जा रहे हैं और कुछ अन्य सुनियोजित समस्याओं के समाधान पर दृढ़तापूर्वक विचार किया जा रहा है।

पर सर्वाधिक लोकप्रिय, निदिष्ट और सुचिन्तित कदम जो अब तक उठाया गया है वह है भूदान यज्ञ का। यह सन्त विनोबा भावे की प्रेरणा के फलस्वरूप प्रारंभ हुआ है, जिनकी असाधारण निष्ठा, दृढ़ विश्वास के कारण आरम्भ काल में ही इसकी अत्यधिक प्रगति हुई। भूदान यज्ञ का नैतिक प्रभाव भौतिक उपलब्धि से कहीं अधिक प्रसारित हुआ है। बड़े पैमाने पर यह मनोवैज्ञानिक आन्दोलन जनमानस को कोरी भावना के हिल्लोल से बहुत हद तक मुक्त कर सकने में समर्थ हुआ है। यह सर्वथा उन्नत व परिष्कृत आन्दोलन है जिसकी प्रगति इस देश की पारस्परिक आस्था के कारण हुई है। इसकी व्यावहारिकता का पक्ष भी अत्यधिक सवल है। भूदान के दो उद्देश्य हैं। पहला यह कि असतुलित शक्तियों को यह सतुलित परिधि में आबद्ध रखता है जिससे सयम की सत्ता रहे और लोग हिंसा करने को प्रेरित न हो। दूसरा उद्देश्य भूदान यज्ञ का यह है जिससे लोगों को स्वामित्व की हेयता, अस्वाभाविकता तथा उसके अभिमान का शन शन नाश हो। कोई भी यह विश्वास नहीं करता कि केवल इसी आन्दोलन से भूमि समस्या का समाधान संभव हो सकता है या हो जायगा। पर अब तक कई लाख एकड़ भूमि भूमिहीनों के लिए माग ली गई है। आचार्य विनोबा भावे ने एक ऐसा वातावरण बना दिया है जिससे भूमिहीनों को जमीन के मालिकों से अहिंसात्मक ढंग से जमीन प्राप्त हो जायगी। जब जरूरत पड़ेगी इसके निमित्त कानून बन जायेगा जिसे जनता का पूर्ण समर्थन प्राप्त हो सकेगा।

जहाँ तक सामाजिक न्याय और संरक्षण का प्रश्न है उस पर प्रायः सभी पहलुओं से विचार कर लिया गया है। कुछ एक को कार्यरूप दे दिया गया है और कुछ अभी कार्यकरण की अपेक्षा में तैयार रखे गये हैं। यह कोई भी नहीं कह सकता है कि जितना काम होना चाहिये उसमें उतनी प्रगति हो चुकी है। लेकिन आरम्भिकी स्फूर्तिदायिनी है। सामाजिक तथा आर्थिक न्याय के लिए दोन्तीन पहलुओं पर विशेष चिन्तन करने और विचार करने की जरूरत है। अगर समान वितरण की परिपाटी चलानी हो तब आर्थिक ईकाइयों पर ध्यान देना अनिवार्य हो जायगा। यह कहना ही पर्याप्त नहीं है कि एक परिवार के लिए इतने एकड़ भूमि की आवश्यकता है। अगर ईकाई आर्थिक नहीं हुई तब किसान बराबर कर्ज में रहेगा। इस प्रश्न का घनिष्ट सबंध हिन्दू उत्तराधिकार कानून से है जिस कारण होल्डिंग छोटी-छोटी एवं अनाधिक हो जाती है। यह पुराना कानून सामाजिक

न्याय पर अवलम्बित है। इसमें विशेषतया पुरुष वर्ग को ही अधिक लाभ प्राप्त होता है। लेकिन इस पद्धति से समाज के अन्य व्यक्तियों का हित अरक्षित रहता है। इस कारण गावों से बहुत सी आवादी बाहर चली गई है। लेकिन उस प्राचीन पारस्परिक कानून का उद्देश्य यह कतई नहीं था। समान वितरण और भूमिहीनों को भूमि वितरण के निमित्त यह आवश्यक है कि (१) विविध इलाकों में आर्थिक ईकाई कितने का होगा, (२) यह ध्यान रखना आवश्यक होगा कि होल्डिंगों का विभाजन अधिक न हो सके या कम-से-कम २५ या ३० वर्षों तक उस पर किसी प्रकार के पारिवारिक विभाजन का असर न पड़ने पावे, (३) इसका ध्यान रखा जाय कि ऐसी ईकाइया उन लोगों के हाथ में न पड़े जिनकी रुचि अधिक उत्पादन की ओर न हो, (४) उत्तराधिकार कानून का इस प्रकार सगोवन किया जाय ताकि वह ईकाई एकवद्ध रह सके। इन उपायों से उत्पादन वृद्धि व भूमि का समान वितरण संभव हो सकता है, सामाजिक संरक्षण एवं न्याय प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त हो सकेगा और सर्वाधिक लाभ यह होगा कि समाज के ढाँचे को बदलने के निमित्त अधिनायकवादी तरीकों के प्रयोग नहीं हो सकेंगे, वल्कि मानवीयता पर आधारित एक ऐसे समाज की रचना हो सकेगी जिनमें मानवीय प्रतिभा, प्रेरणा, प्रेम एवं आस्था समाज में सहिष्णुतापूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हो सके।

ऊपर यह भी कहा जा चुका है कि सामाजिक न्याय का सम्पूर्ण संवर्ध अत्यधिक उत्पादन से है। यदि किसानों को गतानुगतिकता की गरीबी से मुक्ति नहीं दिलाई जा सकती तब भूमि के समान वितरण का उद्देश्य सर्वथा निष्फल हो जायगा। उत्पादन वृद्धि के लिए भी कई साधनों का उपयोग किया जा रहा है। इनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न है सिंचाई का इतजाम करना। जगलों की भी मुख्यवस्था की जा रही है ताकि उचित वर्षा हो और भूमि का अकारण और जब तब क्षय न हो। अन्य लघु योजनाएँ भी कार्यान्वित की जा रही हैं। इनका विस्तार किया जा सकता है। अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन अधिक सफलता लाभ कर चुका है तथा कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स द्वारा भी अधिक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। अच्छे बीज एवं अन्य प्रकार के प्राकृतिक व रासायनिक खादों के इस्तेमाल के बारे में लोगों में निरन्तर प्रचार किया जा रहा है। पशु-पालन एवं संरक्षण की दिशा में भी तत्परता दिखाई पड़ रही है। स्थिति को पूर्ण सफलता के लिए कई वर्षों के अनवरत प्रयास की आवश्यकता है तब कही वर्तमान अवस्था में आमूल परिवर्तन हो सकता है और अन्य सम्मुन्नत देशों के उत्पादन में यह देश भी समक्ष ठहर सकता है।

कृषि की उन्नति तथा उत्पादन में, प्रगतिमूलक वृद्धि के रास्ते में कई कठिनाइयाँ हैं। किसानों की दयनीय गरीबी, वैज्ञानिक ज्ञान का अभाव, सिंचाई की कमी के साथ ही कतिपय अन्य कारण भी इसके साथ सम्बद्ध हैं जिनके उन्मूलन के बिना वास्तविक विकास व उन्नति असंभव ही है। हमारे देश की वर्तमान शिक्षण प्रणाली ऐसी है जिस कारण हम भूमि से और गावों में विलग हो गए हैं। जो भी विद्यार्थी, चाहे लड़का हो या लड़की

यह समझता है कि गावों और कृषि तथा उत्पादन से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। जब विद्यार्थी माध्यमिक विद्यालयों में ही रहते हैं तब उनके सामने टेबिल, कुर्मी, डेस्क और अफसरी के स्वप्न सुनहले लगने लगते हैं। अतएव ऐसे स्कूलों की स्थापना अनिवार्य है जिनमें कृषि सम्बन्धी शिक्षा दी जाय ताकि पढ़-लिखकर भी लोग गावों को त्याग न दें और वे शहर की ओर मुड़ कर वहाँ के लिए भी समस्या न बन जाय। एक किराने से एक किसान का अधिक सम्मान होना चाहिये चूँकि किसान रचनात्मक कार्य करता है। औद्योगिक विकास से हमारी सारी समस्याएँ हल हो जायगी। यह विचार भी उत्पादन के ख्याल से हितकर नहीं होगा। यह स्मरण रखना चाहिये कि चाहे जितना भी औद्योगिक विकास हो उत्पादन की समस्या एवं कृषि की उन्नति केवल उन्नीसे नहीं हो सकेगी। उद्योगों के प्रसार तथा वृद्धि की भी अपनी अलग समस्याएँ होती हैं जैसे पूँजी का प्रश्न व ट्रेनिंग प्राप्त लोगों की समस्या उपस्थित होती है और अन्त में उत्पादित वस्तुओं के बाजार का सवाल भी आ खड़ा होता है विकराल रूप में। भारतवर्ष तब तक सुखी नहीं रह सकता है जबतक भूमि और जन से सर्वाधिक उत्पादन न होगा। यह भी ध्यान में रखना होगा कि भारत में कृषि ही सबसे बड़ा उद्योग है।

एक दूसरी महत्वपूर्ण समस्या भी हमारे सामने आज सम्मुखीन है, कृषि के विकास तथा उत्पादन की वृद्धि के लिये हमें विदेशों के नकल करने की या उनकी टेकनीक या उनके तरीके पर निर्भर रहने की आवश्यकता विलकुल नहीं है। उद्योगों की समृद्धि के उनके चाहे जो भी मान हो लेकिन देश की आवश्यकता तथा यहाँ के साधनों का ही पूर्ण प्रयोग करना पड़ेगा। यही बात बड़े-बड़े उद्योगों या कुटीर उद्योगों के संवर्ध में भी कही जा सकती है। चीन, जापान और कोरिया का कृषि उत्पादन हमारे देश से प्रायः द्विगुणित है। क्या इन देशों से लाभ उठाना हमारे लिए सर्वथा श्रेयस्कर और लाभजनक नहीं है? प्रसिद्ध अमरीकी कृषि शास्त्री श्री एफ० एच० किंग ने अपनी विख्यात पुस्तक 'फारममें आव फोर्टी कट्रीज' में इन तमाम देशों की कृषि-प्रणाली का विशद एवं सर्वांगीण वर्णन किया है। इस किताब का नवीनतम संस्करण १९४९ में प्रकाशित हुआ है। पुस्तक की भूमिका में किंग ने लिखा है कि अत्यधिक धनी आवादी के बावजूद इन देशों की मिट्टी में सर्वाधिक उर्वरता है। १९०७ में जापान में एक एकड़ जमीन से तीन व्यक्तियों का भरण-पोषण हो जाता था और प्रत्येक वर्गमील में २३४९ व्यक्तियों का। प्रति वर्गमील कृषि योग्य भूमि में आदिमियों के अतिरिक्त ६९ घोड़े, ५६ जानवर और ८६ घरेलू मुर्गियों का पालन भी होता था। इसके अलावा कुछ भेड़ों, सूअरों और बकरे-बकरियों का भी। इससे पता चलता है कि हमलोगों को अभी कितनी दूरी तय करनी है।

लेकिन, अन्त में, यह आवश्यक है कि अधिक उत्पादन के साथ-साथ सामाजिक न्याय का भी सर्वोपरि ध्यान रखा जाय। योजना के दोनों पक्षों को सफलता जितनी जल्दी मिले उतना ही कृषि व भूमि-व्यवस्था लाभदायक एवं फलप्रसू हो सकती है।

# श्रमि उपयोग की योजना

## श्री जे. सी. डारपा

इस बड़े देश में सर्वत्र उत्पादन एवं गरीबी का एक प्रकार से सम्मिलित व्यवधान है। प्रत्येक व्यक्ति यह कल्पना करता है कि सम्पदा के उत्पादक गरीबी से मुक्त रहेंगे। हमारे देश में वस्तुतः किसानों को भरपेट भोजन-वस्त्र नहीं मिलता, यों तो प्रत्येक कृषि प्रधान देश में जहाँ, बड़े पैमाने पर कच्चे मालों का उत्पादन होता है वहाँ उत्पादक विलकुल निचली सतह पर रहते हैं। मिलों में काम करनेवाले मजदूर और अन्य लोगों को किसानों से अधिक प्राप्त होता है। किसान को कभी-कभी तो अपना घर तक नहीं होता।

फिर यह भी देखा जाता है कि मालों की खपत और उपभोग में भी जो वास्तविक उत्पादक हैं, वे एकदम छूट जाते हैं। आराइश की सामग्री के लिए हमारी आमदनी का अधिक भाग व्यय होता है और वास्तविक आवश्यकता के लिए उनसे एकदम कम। जिस समाज का आदर्श प्रजातंत्र और न्याय ही उन समाज में यह विषमता परिस्थिति-विवश है।

अतः प्रत्येक समाज निर्माता व विधायक का यह कर्तव्य ही जाता है कि उनमें वास्तविक कारण का पता लगावे। सरसरी तौर पर जो विवेचन किया जाता है उनमें व्यवस्था की गलती मालूम पड़ जाती है। यह एक प्रकार से ऐसी चेतनावनी है जिसके परिणामस्वरूप हमलोग उस प्रचलित

एक परम्परागत भूल का परिमार्जन कर सकते हैं। किसान प्रकृत आवश्यकता की सभी चीजें उत्पादन करता है। अतः सम्पदा उत्पादन करनेवालों की श्रेणी में निश्चय ही उसका स्थान ऊँचा होना चाहिये एवं उसकी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति बखूबी होनी चाहिये। हमारे चतुर्दिके जो वातावरण है उसमें इस शर्त की पूर्ति नहीं दीख पड़ती है।

कई प्रकार की अपूरित शर्तें हैं जिन कारण ऐसी स्थिति आ गई है। इसके लिए सभी तथ्यों का अध्ययन एवं विवेचन जरूरी है जिसकी वजह वर्तमान स्थिति अपनी समस्त विभीषिका के साथ विकराल स्वरूप में खड़ी है, अपनी डरावनी शकल लेकर।

सन्निकट एवं सापेक्ष अध्ययन के अनन्तर यह पता चलता है कि हमारे देश के किसान परिश्रमी हैं और अपने काम या उत्पादन करने की प्रक्रिया में बहुधा असाधारण दुख उठाते हैं। परम्परा के मुताबिक वे अपने को अधिक समझदार समझते हैं। कृषि के सम्बन्ध में भी उनकी धारणा बिलकुल अर्वाचीन नहीं है, वैज्ञानिकता तो दूर की बात रही। ऐसा जान पड़ता है कि आधुनिक ज्ञान एवं साधन उन्हें किसी प्रकार से भी कुछ सिखा सकने में असमर्थ हैं। देश में जिस प्रकार की परिस्थिति है, उसमें उनके उत्पादन अत्यन्त पुरातन होते हुए भी, उनके लिए पर्याप्त-सा ही है। इसमें उन्नति की गुंजाइश बहुतायत से है परन्तु उसके लिए भी अन्य प्रकार के सफल नियोजनों की जरूरत है। उदाहरण के लिये बिना पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था किये, पर्याप्त एवं उचित परिमाण में खाद और रासायनिक खाद नहीं दिये जा सकते हैं और न तो उसके बिना गहरी चास ही की जा सकती है। हमारे देश में केवल जन-बल से ही इन दो समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। हमलोगों को बराबर प्राकृतिक अवस्था के प्रतिकूल काम करना पड़ता है।

अभी कृषि की जो प्रक्रियाएँ हैं उनका विकास युगों के अनुभव के आधार पर हुआ है। यह संभव है उनके विकास के क्रम में प्रयोग की आस्था निहित रही हो। चाहे जो भी हो, वर्तमान काल में तो ये ही साधन समीचीन जान पड़ते हैं।

श्रम-शक्ति पर्याप्त है और किसी भी प्रकार के श्रम के निमित्त विलकुल प्रस्तुत। देश के कई भागों में तो श्रम किसी खास ऋतु में होता है, कुछ लोग चलते-फिरते हैं, इसलिए उनका मन एक ही क्षेत्र में नहीं बस सकता है।

लेकिन इसके साथ ही कृषि की प्रणाली कुछ ऐसी है जिसे असंगत कहा जा सकता है। आदमी अधिक सख्या में भूखी मरते हैं लेकिन लाखों

एकड़ जमीन से तम्बाकू या अन्य प्रकार की औद्योगिक जिन्सों का उत्पादन किया जाता है । किसानों को उपयोगिता एवं आवश्यकता के मान के सम्बन्ध में गलत सलाह दी जाती है जिस कारण वे कम उपयोगी जिन्सों का उत्पादन करते हैं । ऐसा इसलिए भी होता है चूकि जिनके हाथ में आर्थिक सतुलन की कुजी है यानी जो पूजीपति हैं वे किसानों को गलत सलाह देते हैं जिनका उद्देश्य केवल धनोपार्जन ही रहता है । इस तथ्य का पता लगाना पड़ेगा कि आवश्यक कृषि के वाद किसानों को इसके लिए सुविधा और समय है कि नहीं ताकि वे खाद्यान्नों के अतिरिक्त अन्य माल का उत्पादन भी कर सकते हैं । यह भी जान लेना जरूरी है कि उनकी गरीबी क्या उनकी काहिलियत के कारण है या उन्हें जबरदस्ती बेकार रखकर गरीब बना दिया गया है ।

अब तक जितनी जानकारी हमलोगों को प्राप्त हुई है उससे यह पता चलता है कि लोगों की आवश्यकता दूसरे प्रकार की है और उनको विलकुल दूसरी जिन्स के उत्पादन का परामर्श दिया जाता रहा है । ऐसा इसलिए किया जाता है चूकि समाज के वित्तशाली और प्रभावशाली व्यक्ति उन्हें फुसला कर, सामाजिक कल्याण की कीमत पर, उनमें दूसरी किस्म की जिन्सों का उत्पादन कराते हैं । जिसमें आम जनता के हित का सर्वथा साधन नहीं हो पाता है । अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुचते हैं कि वर्तमानकालीन जो व्यवस्थित अरुगति है वह एकदम मानव निर्मित है । जब इनका निर्माण मनुष्य ने किया तब इसका समाधान भी सामाजिक पुनरुत्थान व शिक्षा के द्वारा हो सकता है । अगर हम इन्ही निदान के अनुमार काम करे तब इस दिशा में प्रयोग बड़े और छोटे पैमाने पर किया जा सकते हैं । इसीमें इस कुब्यवस्था के अन्त के लिए उचित मार्ग मिल जायगा ।

प्रयोग केवल अनुसंधानशालाओं के पैमाने पर ही नहीं चलाये जायेंगे बल्कि इनमें किमान तथा अन्य वर्गों का सक्रिय सहयोग भी प्राप्त करना अनिवार्य हो जाएगा । वे भी अपना महत्त्वपूर्ण पार्ट इन दिशा में अदा करेंगे । जिस प्रयोग में तथ्यों की अवहेलना की जाती है उसका आदर्श ही समाप्त हो जाता है । गावों के दैनंदिन वातावरण में ही इस प्रकार के प्रयोग चल सकते हैं चूकि हमारा यह प्रयोग मुख्यतया टेकनिकल नहीं होगा । उनका तो मूलभूत मिद्धान्त सामाजिक पुनर्निर्माण का है । अतएव पूर्ण सामाजिक विकास का काम केवल कृषि सवधी उन्नति से व उत्पादन वृद्धि से ही संभव नहीं है । अन्य प्रश्न भी महत् रूप से सलग्न हैं ।

जीवन की सच्ची परम्परा प्रतिष्ठित करने में केवल मानसिक या वैदिक या तार्किक पद्धति से ही काम नहीं चलने का, प्रत्युत प्रात्यहिक सुविधाओं-असुविधाओं एवं अन्य इतिवृत्तों को ध्यान में रख कर नियोजन करना होगा । ग्राम्य जीवन के लिए जिन सत्यादर्शों को कार्यान्वित करने की आवश्यकता है उनका उचित निर्धारण तभी हो सकता है जब सामाजिक सवध अधिक घना हो, तभी भलाई करनेवालों और उससे लाभ उठानेवालों को सतोप होगा । कृषि से भोजन की सफलता के निमित्त जीवन की प्राथमिक जरूरियात का अव्ययन कर उसे पूर्ण करना सर्वोत्कृष्ट है । जैसे, भोजन, वस्त्र, मकान, स्वस्थ परिवेश, उचित शिक्षा ।

इसकी पूर्ति के पश्चात् ही उत्पादन की शर्त ठीक-ठीक निभ सकेगी, कच्चे माल प्रचुर मात्रा में मिल सकेंगे ।

खाद्य स्वतः हमारे जीवन के लिए बहुविध आवश्यकता के रूप में मौजूद है । स्वास्थ्य व जनकल्याण के वास्ते कई प्रकार के विटामिनो तथा अन्य पोषक तत्वों की जरूरत पडती है केवल रासायनिक कारखाने की आवश्यकताओं की तरह नहीं प्रत्युत इसकी पूर्ति समस्ततः वनस्पति से प्राप्त करनी पड़ेगी । शेष के लिए पशु-जगत पर निर्भर रहा जा सकता है ।

उपर्युक्त प्रत्येक जिन्सों की जरूरत परिमाण के अनुसार होगी इसलिए भूमि की जुताई भी आनुपातिक ढंग में ही करनी पड़ेगी । प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन सोलह आंस अन्न की जरूरत पड सकती है । जिसमें चार आंस चर्बी, ६ आंस दूध और कुछ अश अन्य खनिज तत्वों की तथा अन्य विटामिनो की । इसलिए हमारे उत्पादन में इन सबकी तालिका सम रहनी चाहिये । तभी हमारे गाव स्वयं सम्पूर्ण एवं आत्मनिर्भर रह सकने हैं ।

अगर हम अच्छी भूमि में ही उन तमाम जिन्सों का उत्पादन करें जो अपेक्षाकृत कम उर्वर जमीन में उत्पन्न हो सकती हैं तब ऐसी योजना भूमि के ठीक व उचित उपयोग की दृष्टि से गलत, अहितकर एवं हानिकर होगी । जिन जमीन में गेहूँ की फसल अच्छी हो सकती है उममें बाजरे का उत्पादन नहीं किया जा सकता है । और जहाँ घान की फसल अच्छी हो सकती है उममें जूट का उत्पादन किसी भी दृष्टिकोणसे अच्छा नहीं माना जायगा । भूमि उपयोग में न्यायिक उर्वरता या अनुवर्तता के आधार, बुद्धि मता एवं प्रत्युत्पन्नमतित्व से काम लेना चाहिये, जिससे उस क्षेत्र के लोगों की जरूरतें हल हो सकें । इस प्रकार यदि भूमि का उपयोग जनता की आवश्यकता पूर्ति के निमित्त किया गया तब तोपपूर्ण परिस्थिति आने पर आराइश की सामग्री का उत्पादन किया जा सकता है ।

वर्तमानकालीन सरकार सम्भवतः इनकी पूर्ति नहीं कर सकती है हालांकि यह काम सरकारी एजेंसियों द्वारा ही किया जा सकता है । व्यापक एवं बडी कठिनाई इस प्रयोग की दिशा में यह है कि सरकारी नौकरों एवं मुलाजिमों का जीवन-स्तर, मान एवं विचार ग्रामीणों की तुलना में एकदम ऊंचा है और वे शायद गावों की आवश्यकताओं को देखी नहीं समझ सकें । इसके अतिरिक्त जनता तथा सरकार के बीच पारस्परिक सवध, विश्वास एवं अवस्था पर अवलंबित नहीं है । केवल सरकारी मशीनरी व उपकरणों ने इसकी सिद्धि संभव नहीं जान पडती है, अतः कुछ ऐसे लोग इस प्रयोग को हाथ में लें जो सरकार और जनता दोनों को समझा-बुझा कर सतुलित रख सकें तभी वे प्रयोग बड़े पैमाने पर सफल हो सकते हैं ।

उत्पादन के अलावा विनिमय के मिद्धान्तों का अनुशीलन करना होगा जिससे यह पता चलेगा कि मध्यस्थ तो कही विनिमय में अधिकधिक नहीं है । यह देखा गया है कि अन्य उद्योगों के उत्कोच या दवाव के कारण अन्य औद्योगिक कर्मियों और उत्पादकों को किसानों से अधिक अधिकार मिलते हैं और खाद्यान्न उत्पादकों को उसमें भी कम । इसके लिए यह अच्छा होगा कि विनिमय के मामलों में मुद्रा का प्रचलन जहाँ तक हो सके किया जाय या मिश्रित अर्थव्यवस्था रखी जाय जिससे औद्योगिक या खाद्यान्न के उत्पादकों के स्तर, मुनाफे, जीवन मान में विपमता की गहरी खाई, जो



अवतक प्रचलित है, शीघ्र घट जाय। इस प्रकार के प्रयोग में भी ग्रामीण जनता के अत्यधिक सक्रिय सहयोग की जरूरत पड़ेगी। यदि इस प्रकार के प्रयोग सफल हो जाय तब इस पर हुए व्यय का बोझ अधिक प्रतीत नहीं होगा तथा लोगों में बड़े पैमाने पर सहयोगिता की भावना बढ़ेगी।

इसे पूर्ण सफल बनाने के लिए ऊंची किस्म की अर्थनीति, बड़े उद्योगों एवं औद्योगिकों के पड़ यत्रो एवं लाभ उठानेवाले लोगों के गलत परामर्शों से बचे रहना पड़ेगा। कतिपय गावों के चुनना पड़ेगा जिनका बड़े उद्योगों से और उद्योगपतियों से कम-से-कम सबंध हो और औद्योगिक उथल-पुथल का असर वहां कम पड़ता हो। इस सब को मूर्त रूप देने के पहले यहा भी जनता का हार्दिक सहयोग समष्टि रूप से वाछनीय है। सामाजिक कल्याण, रचनात्मक कार्य, स्कूल, अस्पताल आदि के केन्द्रों का संचालन करना होगा। ये शर्तें अगर पूरी कर दी गईं तब मंत्री, सहयोगिता एवं पारस्परिक सहिष्णुता के आधार पर सफलता निश्चितरूपेण मिलेगी।

इस प्रयोग के व्यय अधिक नहीं होने चाहिये। केवल उन्ही सामानों को बाहर से मगाना चाहिये जो वहां उपलब्ध न हों। गाव के जो लोग ऐसे प्रयोग में काम करें उनका व्यय भार उसी काम से निकलना चाहिए। उदाहरणस्वरूप हमारा प्रयोग ही प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्तिमात्र है। पाच या छ परिवार के लोग चुने हुए स्थान पर बस जाय और वही के उत्पादन पर पूर्णरूप से निर्भर करें। हा, आवश्यकता पडने पर उन्हें बाहर से भी कुछ चीजें लेनी पड़ेगी। इस तरह उत्पादक प्रयोग की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और जो वस्तु उत्पादित नहीं हो सकती है उसका ऋण शेष जिन्सों की अधिकता से सम्भव हो सकता है।

इन प्रयोगों का पहला आधार होगा भूमि। भूमि पर हमें पूजा लगानी पड़ेगी। वैंलो, गावों या अन्य जानवरों पर हम जो पैसा व्यय करेंगे वह भी सुरक्षित रह कर लाभदायक होगा तथा उसे जब चाहे तब बेच भी

सकते हैं। कुछ और खर्च की भी आवश्यकता है जैसे कुआरा खोदना, बांध बाधना, भूमि का सरक्षण करना। जानवरों के लिए मकान बनाने की आवश्यकता भी पड़ेगी। लेकिन इन पर जो व्यय होगा वह पूरी रकम की तुलना में एकदम कम होगा। एक ईकाई पर निम्नलिखित व्यय किया जा सकता है—

(१)	दो सौ एकड़ भूमि (सब किस्म की)	२५,०००
(२)	१६ वैंल और ५ गाव	१०,०००
(३)	कुए इत्यादि	७,५००
(४)	पानी आदि	२,५००
(५)	मकान, शेड आदि	२५,०००
(६)	प्रथम वर्ष की लागत पूजा	३०,०००

कुल—१,००,०००

अगर उपर्युक्त पूजा या वजट के अनुसार काम किया जाय तब हमारा ख्याल है किसी भी प्रकार की घटी होने की गुजाइश नहीं रहेगी। ठीक इसके विपरीत जब प्रयोग चलने लगेंगे तब कइयों से लाभ ही होने की सभावना रहेगी।

ऊपर कहा जा चुका है कि इस प्रयोग का उद्देश्य सारे देश के लिए विकास कार्य चालू करना है जिससे आर्थिक ईकाइया स्वयं निर्भर एवं सम्पूर्ण रह सकें और सामाजिक पुनर्निर्माण का अवलम्बन कर देश की सर्वांगीण उन्नति की जा सके और यह मुख्यतया कृषि के जरिये ही हो सकता है। अब तक सरकारी एजेंसियों द्वारा इस तरह के प्रयोग नहीं हुए हैं और पूर्ण सफल हो ही नहीं सकते। अतएव यह आवश्यक है कि देश की उन्नति के इस क्षेत्र को जो अवतक निर्दयता व निर्भयतापूर्वक उपेक्षित रहा है पर्याप्त तौर पर सफलता के पथ पर अग्रसर कर दिया जाय।



# जमीन्दारी उन्मूलन का इतिहास

प्रो० एन० जी० रांगा

स्वराज के बाद भी भारत में जमीन का दो तिहाई हिस्सा जमींदारों और ताल्लुकदारों के हाथ में था। उनकी बड़ी-बड़ी इस्टेटें थीं जिनके या तो वे स्वामी थे या उसमें कर वसूलते थे। ये जमींदार और ताल्लुकदार प्रायः २० करोड़ रुपया प्रति वर्ष वसूलते थे। इनकी जमीन पर इस देश के प्रायः १०,००० लाख किसान निर्भर करते थे।

जिन क्षेत्रों में जमीन्दारी प्रथा प्रचलित थी उन क्षेत्रों के वामियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति अत्यन्त खराब थी। राजनीतिक जागरण से परिचय प्राप्त करना तथा शिक्षा प्राप्त करना एकदम मुश्किल हो गया था। कई क्षेत्रों में तो उनका जीवन खटालों के जानवरों से भी गया-बीता था। जमींदारों का समारम्भ कैसे हुआ इस प्रश्न पर बहुत से इतिहासकारों का आपसी मत वैभिन्य है। लेकिन अधिकांश इतिहासकार यह स्वीकार करते हैं कि मुगल शासन के पहले किसान ही भूमि के स्वामी थे। वे राज्य को केवल निर्धारित भूमि-कर देते थे। दसवीं शताब्दी तक दक्षिण के चोल राज्य में अगर राजा को मंदिर या किसी अन्य देवालय-धर्मालय के लिए जमीन की जरूरत पड़ती थी तब वह किसान से ही भूमि खरीदता था। ठीक इसी तरह कश्मीर के राजा भी जमीन पर अधिकार पाने के हेतु उसका मूल्य उसके मालिक को देते थे। कहलून ने एक स्थान पर लिखा है कि एक किमान राजा द्वारा जमीन ले लिये जाने पर उनके लिये डट कर विरोध करता है। चूंकि जमीन के जरिये किसान का पालन-पोषण होता था अतः राजा उसे लेने के लिए किसान को मुआवजा देना जरूरी समझता था। कीमत देने की प्रथा इसलिए भी चालू की गयी थी ताकि राजा उदण्डतापूर्वक एवं बल प्रयोग करके किसानों को उनके अधिकार से वंचित न कर दे। अगर ऐसी प्रथा चल गई तब यह परम्परा-सी बन जायगी जिसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जा सकती।

परन्तु मुगल काल में, और विशेषतया जहांगीर के राजत्वकाल में जमींदारों ने अधिक सुविधा प्राप्त कर ली और उनके अधिकार भी बढ़ गए। जब औरंगज़ेब मुद्दो में रत रहने लगा तब ये जागीरदार अपने अधिकार बढ़ाते गये। इस तरह धीरे-धीरे किसान के अधिकारों का अपहरण होने लगा। मुगलों के पश्चात् अंग्रेज आये और उनके कारण किसानों की रहीं-

सही स्थिति डावाडोल हो गई। वे ब्रिटिशकाल में केवल जमींदारों की स्वच्छा पर ही निर्भर रहे। जब चाहा जमीन दी, जब चाहा ले ली। इससे भारतीय ग्राम्य व्यवस्था की शकल बदल गई तथा उनके दुर्दिन आरम्भ हुए। लार्ड कार्नवालिस के चिर स्थायी प्रवन्ध से भारत की प्राचीन व्यवस्था एकदम नष्ट हो गई। ऐसी प्रथा यहाँ की परम्परा के विलकुल विपरीत थी। लार्ड कर्जन ही ऐसा पहला ब्रिटिश शासक था जिसने जमींदारों के उपद्रवों एवं बढ़ते हुए अत्याचारों को बगाल और विहार में रोका। लेकिन कर्जन को भी केवल किसानों की वेदखली रोकने में ही मफलता मिली और आंशिक रूप में करो का बोझ भी कम हुआ।

मद्रास सरकार के एक उच्च पदस्थ कर्मचारी फोरबिस ने अपना ध्यान इस ओर आकर्षित किया और उसकी समझ में पहले-पहल यह बात आई कि भारतीय किसानों के प्रति अत्यधिक अन्याय किया गया है। इसी अफसर ने यह चेष्टा की कि स्थायी तौर पर किसानों के साथ जमीन की बन्दोबस्ती की जा सके। उसने कर के रूप में साढ़े बारह प्रतिशत ले लेने को मोचा। यह १९०८ की बात है। पर ठीक उसके बाद के ही बगाल टेंनेन्सी ऐक्ट, यू० पी० टेंनेन्सी ऐक्ट तथा अन्य ऐसे ही कानूनों के प्रचलित हो जाने के कारण फोरबिस की कल्पना सत्य का स्वरूप नहीं ग्रहण कर सकी। इन कानूनों के द्वारा केवल थोड़े से किसानों का संरक्षण संभव हो सका। और लोग तो सिर्फ जमींदारों की कृपा पर ही आश्रित रह गये।

ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा जो राजनीतिक अधिकार क्रमशः भारत को दिये जा रहे थे उन पर इन्हीं जमींदारों का एकाधिकार हो गया। इनके बाद शहर में रहनेवाले मुट्ठी भर पढ़े-लिखे लोगों को अधिकार मिले तथा इनके साथ ही बड़े-बड़े व्यवसायियों को भी सुविधाएँ प्राप्त हुईं। यह क्रम १९०८ से १९३६ तक चलता रहा। अधिकार केवल सीमित लोगों को इसलिए मिले चूंकि जनता अधिक अशिक्षित थी एवं पिछड़ी हुई, दबी हुई यानी सिर उठा कर अधिकार मागने के लायक नहीं थी। स्थायी प्रवन्ध के सम्बन्ध में कुछ कहना बड़ा गुनाह माना जाता था। प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री डाक्टर रमेशचन्द्र दत्त तथा रानाडे आदि सभी लोग स्थायी प्रवन्ध के ही पक्ष में थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इस स्वत्वहारिणी

प्रथा के खिलाफ आवाज नहीं उठाई ताकि किसानों को उससे मुक्ति मिल सके ।

१९२९ में हम कतिपय कार्यकर्ता प्रादेशिक स्तर पर विजयवाड़ा में एकत्र हुए । उसका एक मात्र उद्देश्य रैयतों को मुक्ति दिलाना था । यह उल्लेख योग्य तथ्य है कि मद्रास के केवल एक तिहाई किसान ही जमीन्दारी प्रथा की क्रूरता के शिकार थे । इनमें बहुसंख्यक किसानों ने अपने स्वत्व के लिए तरह-तरह से संघर्ष करना शुरू कर दिया था । वे कचहरियों में मुकदमों दायर कर चुके थे । उन्हें १९०८ के इस्टेट्स लैंड ऐक्ट के अनुसार जमीन पर अधिकार प्राप्त हो गया था । इस कानून के अनुसार किसानों की स्थिति अच्छी हो गई थी । कृष्णा तथा गोदावरी डेल्टा के कारण किसानों की आर्थिक अवस्था दिनोदिन सुदृढ़ होती जा रही थी । किसानों को कर्ज मिलता था तथा वे इन साधनों द्वारा कृषि की उन्नति कर सकते थे । उक्त विजयवाड़ा सम्मेलन में जमीन्दारों के विरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया । गांधी-इरविन पैक्ट के बाद राजनीतिक उत्कर्ष के कारण इस आन्दोलन को अधिक बल मिला । इसका संचालन अत्यन्त उद्देगपूर्ण उत्साह से चलने लगा ।

जब मैं १९२० से १९२६ तक यूरोप में था तब आयरलैंड की भूमि व्यवस्था का अध्ययन करता था । डेनमार्क में कैसे भूमि सुधार कानून लागू किये गये इसका भी क्रमिक अध्ययन किया । इटली एवं फ्रांस में प्रगति बड़े जोरों पर हो रही थी । इन तमाम देशों में राष्ट्रीय, सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के चिन्ह परिलक्षित हो रहे थे । यह भी उस समय स्पष्ट-तया परिलक्षित हो रहा था कि प्रथम-विश्व युद्ध के पश्चात् यूरोप की जमींदारी प्रथा अन्तिम सांस ले रही थी । वहाँ की अर्थव्यवस्था में कृषकों को अधिकार प्राप्त होता जा रहा था । इन अनुभवों के पश्चात् मुझे बड़े पैमाने पर जमीन्दारों के विरुद्ध किसानों के पक्ष में आन्दोलन करने की प्रेरणा मिली । १९३१ में जब आन्ध्र में जमीन्दारी जाच कमिटी बनी तब मैं उसका चेयरमैन बना ।

उस कमिटी के समक्ष जितनी गवाहिया दी गई उससे कृषकों की अवस्था के सम्बन्ध में न केवल मद्रास की जनता को ही ज्ञात हो गया बल्कि सारे देश के सामने एक बड़ी उत्तेजनापूर्ण स्थिति उपस्थित हो गई । देश भर की जनता उम स्थिति से अवगत हुई और उस समय के सभी पत्रों में उस प्रथा की निर्मम आलोचनाएँ की गई । ये जमीन्दार इतने अधिक प्रभावशाली व शक्ति सम्पन्न थे कि किसान उनके विरुद्ध कुछ भी बोल नहीं सकते थे । अधिकार मागने की उनकी हिम्मत एकदम नहीं हो सकती थी ।

इन जाच से आगे काम करने की पूर्ण सुविधा प्राप्त हो गई और उसका विवरण भारतीय राजनीतिक इतिहास के साथ जुड़ गया । उसी समय चार बहुत महत्वपूर्ण काम हुए । कांग्रेस के कराची अधिवेशन के अन्तर पर कृषकों के मौलिक अधिकारों पर एक रिपोर्ट तैयार हुई । एक समिति का निर्माण भी हुआ जिसकी रिपोर्ट पर अखिल भारतीय कांग्रेस को वन्द्य की बैठक में १९३१ अक्टूबर में विचार हुआ । मुझे इस आन्दोलन का पर्याप्त अनुभव था, अतः अखिल भारतीय कांग्रेस में मैंने किसानों की तरफ से जोरदार वकालत की । मैंने यह भी सुझाव रखा कि महानगरों तथा अन्य जलानगरों का, जगरों का और अन्य उपयोग में आने-

वाली जमीन का राष्ट्रीकरण किया जाना चाहिये । मुझे किसी में सफलता नहीं मिली । परन्तु इतनी सफलता अवश्य मिली कि इस ओर समस्त देश का ध्यान आकर्षित हो गया और पूरे भारत देश के लोग, जिनमें राजनीतिक चेतना थी या कृषकों का कल्याण चाहते थे उनके समक्ष एक ऐसा विवरण प्रस्तुत हो गया ताकि वे इस दिशा में आगे बढ़ सकें । उस समय सब लोग यह समझने लगे कि यदि जमीन्दारी उन्मूलन पूर्णतया न भी हो जाये लेकिन उसमें आवश्यक सुधार की अत्यधिक आवश्यकता है ।

मेरी रिपोर्ट, जो प्रकाशित हुई और जिसका महत्व भी कम नहीं था, उसका नाम था 'जमीन्दारी रैयतों की आर्थिक स्थिति' । इसका भी पर्याप्त प्रभाव लोक मानस पर पड़ा । वेंकटगिरि में होनेवाले आद्य रैयत सम्मेलन में जमीन्दारी उन्मूलन का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । यह तीसरा महत्वपूर्ण कदम इस दिशा में है । इसके बाद भी एक चौथी महत्वपूर्ण घटना घटी । वेंकटगिरि के सम्मेलन पर तत्कालीन मद्रास सरकार ने प्रतिबन्ध लगा दिया । उसका विरोध किया गया और उसी समय सबसे पहले राजनीतिक चेतना से बहुत पृथक रहनेवाले किसानों में जागृति आई । ये लोग भी राजनीतिक कदम उठाने के लिए प्रस्तुत हो गये । जमीन्दारी उन्मूलन के इस आन्दोलन को सर्वाधिक बल तब मिला जब महात्मा गांधी ने इसे आशीर्वाद दिया । वे १९३४ में वेंकटगिरि आये थे । वेंकटगिरि में ही सर्व प्रथम स्थायी प्रबन्ध के खिलाफ आन्दोलन किया गया था और इसके खिलाफ १९३१-३२ में कई बार सत्याग्रह भी किये गये ।

१९३१ की जाच का परिणाम तो पहले बड़ा भयकर जान पड़ा लेकिन पश्चात् उसके प्रभाव हितकर व कल्याणकर हुए । जाच समिति के समक्ष जिन किसानों ने गवाहिया दी थी उन्हें जमीन्दारों ने अनेक प्रकार से तबाह और तग किया । एक किसान से तो भविष्य के सबूत के लिए ६ एकड़ भूमि जमीन्दार ने ले ली । एक दूसरे जमीन्दार ने एक किसान परिवार को अपने गांव से निकाल दिया । तीसरे जमीन्दार ने पुलिस की पैरवी करके किसानों पर लाठी चार्ज करवाया । पर इन तमाम अत्याचारों, ज्यादतियों के फलस्वरूप वेंकटगिरि में ३१-३२ में आन्दोलन शुरू किये गये । यद्यपि मुझे पकड़ कर दो वर्ष के लिये जेल में बन्द कर दिया गया फिर भी किसानों के आन्दोलन के फलस्वरूप जमीन्दारों को झुकना पड़ा और वे किसानों को सुविधाएँ देने को तैयार हुए । जमीन्दारों की आखें खुल गई । इसी प्रकार बड़े और छोटे पैमाने पर १९३२-३६ तक छोटे-छोटे कई किसान आन्दोलन चलाये गये और उनमें सफलताएँ मिली । मद्रास, मेरठ और लखनऊ सम्मेलनों में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का जन्म हुआ । फैजपुर में जब अधिवेशन हुआ तब आद्य के किसानों के जलसे का रूप वार्षिक हो चका था । इसका महत्व सम्पूर्ण देश में हो गया । किसानों में चेतना आई । फैजपुर में करीब ४५ हजार किसान एकत्र हुए । इसका प्रभाव कांग्रेसी नेताओं पर पूर्ण रूप से हुआ । उसी साल कृषि सुधार समिति बनी, चूँकि आम चुनाव होनेवाले थे । मैंने उस समय जमीन्दारी उन्मूलन का प्रस्ताव रखा । उस समय, मुझे इसमें सफलता नहीं मिली । फिर भी किसानों की स्थिति सुधरी । लगान कम किये गये । इसे कम सफलता नहीं कहा जा सकता है ।

१९३७-३९ तक, जब कांग्रेसी मन्त्रिमंडल कार्य कर रहे थे अंग्रेज अफसरों ने कहा कि केवल वैधानिक तरीकों से ही जमीन्दारी का ख़ात्मा नहीं किया जा सकता। इनसे स्थायी प्रबन्ध का समूल नाश नहीं किया जा सकता था। लेकिन मद्रास के तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री चन्द्रवर्ती राजगोपालाचारी ने घोषित किया कि जमीन्दारियों का उन्मूलन होना तथा स्थायी प्रबन्ध का ख़त्म होना अत्यन्त आवश्यक है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार में जब टेनेन्सी कमिटियाँ बनीं तब भी जमीन्दारी उन्मूलन की सिफारिशों की गईं। मद्रास असेम्बली ने श्री टी. प्रकाशम की अध्यक्षता में जो समिति बनी उसने भी उन्नी की सिफारिश की। उन्नी समिति ने कहा कि जमीन्दारी उन्मूलन के बाद का मुआवजा देना भी उचित ही है।

प्रायः सभी राज्य सरकारों ने बाकी लगान माफ कर दिया और अधिकांश इलाकों में कर कम कर दिया गया। लेकिन इनसे जमीन्दारों का उन्मूलन सम्भव नहीं हो सका।

१९३६ से १९४० तक मनें देश भर का दौरा किया। विधान सभा के सदस्यों, मंत्रियों ने अनुरोध किया कि वे किसानों की रक्षा करें तब मैं अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का अध्यक्ष था। युद्ध के कारण सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक सुधार नहीं हो सके। इनके अनिश्चित राष्ट्रीय आन्दोलन में राष्ट्र की नारी सक्रिय लग गई थी।

१९३७ के मन्त्रिमंडलों के निर्माण ने किसान आन्दोलन को अत्यधिक बल मिला। आज में राज्यव्यापी हजारों मील लम्बा किसानों का जुड़ून गठित किया गया। प्रत्येक प्रान्त में इस प्रकार के जुड़नों का नेतृत्व किया गया। लगनऊ में लगभग एक लाख किसानों ने विधान भवन के सामने प्रदर्शन किया। पटने का प्रदर्शन तो एक अस्पष्ट बन गया। कांग्रेसियों को स्वामी महजानन्द द्वारा आयोजित प्रदर्शन में कम्युनिस्टों का हाथ मालूम हुआ और कांग्रेसियों को अपने अलग रखने का आदेश दिया गया। इनके बाद आंध्र और बिहार में बड़े पैमाने पर भूमि सत्याग्रह किये गये। इनका उद्देश्य था किसानों को संदेसरी से बचाना। उन सत्याग्रह को कुचलने के लिए हिंसात्मक उपाय किये गये और किसानों पर निर्भर प्रहार किये गये। महात्मा गांधी ने स्वयं "उडामार्च" का विरोध किया जिस कारण स्वामी महजानन्द सरकारों के साथ महात्माजी का बड़ा लम्बा विवाद हुआ। इनके फलस्वरूप स्वामीजी ने बिहार के किसानों का बड़े पैमाने पर संगठन किया।

युद्ध काल में ब्रिटिश साम्राज्य के पिछाफ राष्ट्र-मुक्ति के लिए सभी किसान कार्यकर्ताओं ने उठ कर काम किया। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझसे और स्वामीजी में फूट डालने में कम्युनिस्टों को सफलता मिली। उन्नी वक्त में किसान आन्दोलन जो अब तक जबरदस्त स्वरूप अखिलार कर चुका था विभक्त हो गया और अब तक वह भेद मिट नहीं सका है।

जब दूसरी लड़ाई चल रही थी तब भी राजनीति चेतना-सम्भूत जनता ने अपना आन्दोलन जारी रखा। उन्नी समय कम्युनिस्टों ने जनयुद्ध का नारा दिया। स्वामी महजानन्द ने १९४५ में महात्मा गांधीजी को और १९४६ में कांग्रेस पार्टी के मान को जमीन्दारी उन्मूलन के लिए

प्रस्तुत किया। १९४५-४६ के चुनाव पत्रक में कांग्रेस ने किसानों की मांगों को मान लिया और हम सब लोगों, जो गत मगह वर्षों में इस दिशा में प्रयत्न कर रहे थे, का विश्वास महात्मा गांधी में जम गया।

कांग्रेस का जमीन्दारी उन्मूलन मिद्धान्त लोगों के लिए शुभ सूचक हो गया। अब कांग्रेस मन्त्रिमंडलों को और विशेष कर मंत्रियों की योग्यता पर उनसे स्वरूप देना निर्भर रह गया। जब तक इस उद्देश्य की पूर्ति हुई तब तक मन्त्रिमंडलों को अनेकानेक कार्य करने में सलग्न हो जाना पड़ा। नवने बड़ी समस्या थी मुआवजा दे देने की। किसान मुआवजा देने के पक्ष में नहीं थे। पर क्या यह सम्भव था कि अहिंसक तरीके से बिना मुआवजा दिये जमीन्दारियों पर अधिकार किया जा सकता? तब यह प्रश्न सम्मुखीन होता है कि जमीन्दारों को किम मात्रा में मुआवजा दिया जाय। कांग्रेस मंत्रियों के लिए यही व्यावहारिक राजनीति रणवच रही थी। इनके कई कारणों से स्वीकार कर लेना पड़ा। क्या जमीन्दारों को उनके वसूलों के मुताबिक मुआवजा दिया जाय या लगान कम करके उनके मुताबिक दिया जाय? क्या सभी जमीन्दारों को एक ही दर मुआवजा दिया जाय या उतम भी प्रभेद रहे और क्या किसान ही अपने क्षेत्र के जमीन्दारों को मुआवजा स्वयं दे देंगे या सरकारी स्रोतों के जरिये देंगे? उन्नी तरह के कई प्रश्न उठ सके हुए।

तब हमलोगों ने यह अनुभव किया कि अपनी मांग, जमीन्दारी उन्मूलन की पूरी हो गई, परन्तु सामाजिक न्याय के आधार पर तथा सभी वर्गों की तथा जनता की तुष्टि पर भी ध्यान रख कर इस पर विचार करना था। उनका दायित्व एक बड़े योग्य व्यक्ति के हाथों में पडना चाहिये। बिहार राज्य में इन कार्य को मेरे मित्र श्री कृष्ण वल्लभ सहाय ने बड़ी योग्यता एवं तत्परता के साथ किया है। विधान परिषद के समक्ष इस प्रश्न को जिन प्रकार उपस्थित किया गया था और उनके लिए हमारे इन मित्र को अत्यधिक कोपभाजन बनाना पड़ा था। यह भी सच है कि बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बहुत से कांग्रेसी जमीन्दार घरानों के हैं जिनकी आमदनी कम न थी। इन लोगों ने इसे स्वीकार कर अतिशय सहृदयता का परिचय दिया है। श्री कृष्णवल्लभ सहाय के लिए यह बड़ा कठिन काम था कि वे अपने विरोधियों का सामना करें और उन्हें कम मुआवजा के लिये तैयार कर सकें। कांग्रेस कार्य समिति ने इन जमीन्दारों को अधिक मुआवजा देने की नीति स्वीकृत की थी लेकिन श्री सहाय ने बिहार में मुआवजा की रकम को कम निर्धारित रखने में अपूर्व सफलता प्राप्त की। यह सफलता इतिहास में उल्लेख योग्य है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ६ वर्षों के अनवरत कार्य करते रहने के फलस्वरूप अब देश के अधिक भागों के किसान अपनी भूमि के मालिक बन जा सकते हैं। मनें इस आन्दोलन को आरम्भ किया था। आज इस बात का गर्व है और मुझे श्री सहाय के मित्र होने का भी गौरव प्राप्त है। चीन में भी इस तरह के कार्य किये जा रहे हैं लेकिन बहा दवाव तथा तानाशाही का राज्य है। हमलोग उन तमाम अमर कार्यकर्ताओं, और मंत्रियों, विधायकों के ऋणी हैं।



---

---

## प्राचीन भारत के गाँव

---

---

प्राचीन भारत में जीवन वैयक्तिक सम्पत्ति पर व्यवस्थित था यानी भूमि पर लोगो का अधिकार होता था। सबसे प्राचीनकालीन रचना, सम्भवत मानव जाति के इतिहास में प्रथम, ऋग्वेद में मेंडो और भूमि के टुकडो का वर्णन मिलता है। उन टुकडो को क्षेत्र कहा जाता था और मेंडो को खिल्या। उसका मालिक क्षेत्रस्यपति कहलाता था और उसकी मालकिन क्षेत्रस्यपती। यह इस बात का प्रचुर प्रमाण है कि वेदकालीन भारत में विभिन्न होल्डिंगें थी।

सत्यपथ ब्राह्मण में इसका विस्तृत वर्णन है और जमीन के वर्गीकरण का पूरा चित्र भी। यह उल्लिखित है कि क्षत्रिय या राजा, लोगो के परामर्श के अनुसार भूमि की व्यवस्था करता था। इस प्रथा के अनुसार एक-एक क्षेत्र एक-एक व्यक्ति को माप कर दिये जाते थे। इसका वर्णन भी ऋग्वेद में आता है। अतः वैदिक साहित्य में भूमि की सामूहिक मालकिन्यत का कोई वर्णन नहीं मिलता और न सामूहिक कृषि का ही उल्लेख है। केवल परती भूमि पर समाज का अधिकार होता था। इस भूमि का उपयोग चारागाह के लिए होता था। भूमि पर वशानुगत अधिकार उसी युग से चला आ रहा था। उत्तराधिकारियों को ऋग्वेद में भूमिपति के बालक की सज्ञा दी गई है। छान्दोग्य उपनिषद में आयातमानी का विवरण मिलता है जिसकी व्याख्या करने पर उसमें स्टेट, खेत, और मकानो का विवरण है। तत्तरीय उपनिषद में भूमिपति किस तरह अपने पुत्रों में बटवारा करता है इसका वर्णन मिलता है। इसका भी विशद वर्णन है कि जो लडका कही चला जाता था उसे क्षति पूर्ति दी जाती थी। मुख्यतया क्षति पूर्ति के रूप में उसे धन मिलता था। जमिनीय ब्राह्मण में एक ब्राह्मण के अपने चार पुत्रों के बीच भूमि बांटने का जिक्र आता है। विभाजन पहले पशुओं और चल सम्पत्ति से शुरू हुआ और फिर अचल सम्पत्ति यानी भूमि आदि का भी विभाजन हुआ। बटवारे के अनुरोध को दाय कहते हैं और उत्तगधिकारी दायदा कहलाता है। इसका पूर्ण विवरण यास्क निरुक्त में मिलता है।

जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है जमीन राज्य की मर्जी से बांटी जाती थी और इन तरह भूमि चाहनेवालों को तामकामा कहते हैं। इस कानून

में एव भूमि बन्दोवस्ती के नियमों में यदाकदा परिवर्तन होते आये हैं। जब राजा ने एक व्यक्ति को जमीन का मालिक बना दिया तब वह जमीन्दार हो गया और दूसरे जो वस्तुतः भूमि जोतते थे, वे रैयत हो गये। भूमि का राजस्व मिट्टी की उर्वरा शक्ति के अनुकूल उपज का चौथा हिस्सा, आठवा हिस्सा और बारहवा हिस्सा वसूल किया जाता था। सम्राट अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया कि राज्य द्वारा गौतम बुद्ध के जन्मस्थान लुम्बिनी में चौथाई राजस्व घटा कर आठवा हिस्सा लिया जाय। लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। प्राचीन साहित्य में यह वर्णन भी मिलता है कि कृषि मजदूर लगा कर की जाती थी। बौद्ध साहित्य में एव शिलालेखों में मजदूर लगाने की निन्दा की गई है। जातक कथाओं में इस सामाजिक पतन का उल्लेख कर उस पर दुःख प्रकट किया गया है कि किसानों को अपनी जमीन छोड़कर भूमिपतियों के यहाँ मजदूरी करनी पड़ती है। लेकिन इस कृषि व्यवस्था द्वारा यह निश्चित नहीं किया गया था कि एक परिवार को अधिक-से-अधिक कितनी भूमि रहे। जातकों में एक हजार एकड़ के पाच सौ हलो द्वारा जोते जाने का जिक्र है। इतनी कड़ी खेती के लिए मजदूर लगाने की प्रथा थी उसे मतिका कहा जाता था।

उस युग में उपज के हिस्से पर भी खेतों को बन्दोबस्त किया जाता था। बौद्ध साहित्य में इसका सप्रमाण विवरण मिलता है। दान में मिली हुई भूमि से बौद्ध सघों का व्यय चलता था। इस जमीन की खेती सघ द्वारा कराई जाती थी किन्तु खेती करना भिक्षुको का काम नहीं था। अतएव सघ की ओर से भी कृषि के लिए भूमि का बन्दोबस्त किया जाता था। महावाग्गा के अनुसार किसी भी खेत के लिए बीज दिया जाता था और उसमें आधी उपज सघ को दे देने की शर्त लगायी जाती थी। उस युग में खेत जोतनेवालों को आधी फसल दे दी जाती थी। बुद्धकालीन भारत की कृषि व्यवस्था का बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन चीनी विद्वान यात्री आईतसिंग के वर्णन में मिलता है। इस यात्री ने बारह वर्ष भारत में बिताये थे। विहार के शिक्षण के अनुसार जब खेती सघ द्वारा कराई जाती थी तब उसके एवज में मठ के नौकरों को परिवार पोषण के लिए अन्न दिया जाता था। फसल का विभाजन छ हिस्सों में किया जाता था और मठ को पँदावार का छठा हिस्सा मिलता था। कभी-कभी इस विभाजन में ऋतु के अनुसार परिवर्तन और परिवर्द्धन किया जाता था। उस जमाने के मठ इसी नियम

---

---

डाक्टर राधा कुमुद मुखर्जी

---

---

के पाबन्द थे। लेकिन कहीं-कहीं मठायीय नौकरों को काम देते थे ताकि उपज अच्छी हो सके। तत्कालीन हिन्दू पुस्तकों में भी उत्पादन का एक निर्धारित हिस्सा लेकर चेत बन्दोबस्त करने का जिक्र आता है।

अब हम प्राचीन भारत में प्रचलित कृषि व्यवस्था की विशेषताओं का उल्लेख करेंगे। जमीन की मालकियत निर्धारित कर देने का श्रमली उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना ही था जिसमें समाज की आर्थिक और सामाजिक प्रगति अवरुद्ध न हो जाय। युगों ने भारत का मुख्य उद्योग कृषि रहा है। धन का जादू ऐसा होता है जिस कारण सभी काल में लोग मिट्टी को सोना बना देने के प्रयत्न करते हैं। पंच विनया ब्राह्मण में एक शब्द का प्रयोग हुआ है जिसे ब्राह्मण कहते हैं और यह शब्द उन लोगों के लिए लिया गया जो लोग ब्राह्मण धर्म में परे थे। वे लोग कृषि नहीं करते थे।

निचाई के लिए कुएँ बने हुए थे जिनमें बाल्टियों द्वारा चमड़े की टोरी में पानी गीचा जाता था। फिर कढ़ी द्वारा नेतों में जल पहुँचाया जाता था। निचाई के किण्व जल झीलों और नहरों में भी निवाला जाता था। कभी-कभी नहरयोगिता के आधार पर नहरें भी खोदी जाती थीं। नहरों के बाढ़ कभी-कभी झगड़े भी हो जाते थे। रोहिणी नदी के बाढ़ के लिए तो झगडा भी हो गया था, जिनका फौजदारी न्याय बुद्धदेव ने करवाया था। नेतों की आकृति प्रायः चतुर्भुज जैसी होती थी। उन जमाने के बौद्ध भिक्षु के कपड़े भी पुराने टुकड़ों में ही मिले होते थे।

कृषि कार्यों में भी चार विभाग होते थे। आज भी वही प्रथा है, जोतना, बोना, काटना और दबना जिन्हें क्रमशः वैदिक भाषा में कृषणन्त वपन्त लुणन्त एव मृणन्त कहते हैं। वैदिक काल में विविध किस्म के अन्नो का भी उत्पादन होता था। यम और धान्य उनमें प्रमुख अन्न हैं। वृहदारण्यक उपनिषद् में दान प्रकार के ग्राम्यणी का विवरण मिलता है, चावल, यम, वृक्षय, मुद्ग, माप, तिल, अणु, मत्स्य, गोमूत्र, निवार। इनके अतिरिक्त प्रियगु, भगूर तथा ध्यामक का उल्लेख है। दो फसलों की खेती ही की जाती थी। वैदिक काल में निम्न प्रकार के कृषि-कर निर्धारित किये जाते थे। (१) सरकारी महामात्य लगी फसल पर दाना करता था जिसे तत्कालीन भाषा में तिये कहा जाता था। दाना करने का अधिकार केवल गाव के मुखिया को ही प्राप्त था जिसे ग्रामजन कहा जाता था (२) युद्ध एव अकाल तथा अन्य विशेष परिस्थितियों में सामना करने के लिये उत्पादन पर अधिक कर लिया जाता था (३) बेगार की प्रथा का भी उल्लेख प्राप्त होता है जब राजा के काम के निमित्त लोगों को अपना काम-धाम छोड़ कर लग जाना पड़ता था (४) राज्य के उत्तराधिकारी के जन्म के अवसर पर प्रजा राजा को कर दिया करती थी (५) वनों, जंगलों एव स्वामीविहीन भूमि पर राज्य का अधिकार होता था। उसकी बन्दोबस्ती के लिए कर निर्धारित था।

खाम महाल, जिसे मीता कहा जाता था, उसके अतिरिक्त राजस्व निर्धारण निम्न प्रणालियों में किया गया था (१) भाग, जिसके जरिये उपज का छठा हिस्सा राजस्व में ले लिया जाता था (२) कर, यह वाग वगीचों पर वसूल किया जाता था (३) विविक्त, चारागाहों का कर (४) वर्तनी पातायात और मडक कर (५) रज्जु, भूमि के बन्दोबस्त के

समय लिया गया कर (६) चोर रज्जु, यानी चौकीदारी टैक्स (७) सेतु, फल, साक-शब्जियों, ईख, पान, केला, शदा, (सुपारी), केदारा, मसाला (मूलवता) पर निर्धारित होनेवाले कर (८) वन कर, जिसमें जानवर, हरिण, काठ, खर और हाथी रहते थे।

उपयोगी वनों और जंगलों का विवरण निम्न प्रकार का मिलता है। (१) दारुवर्ग (काठ) (२) वेणवर्ग (वाम), (३) वल्ले वर्ग (ईख और लताये), (४) बल्कल वर्ग (५) रज्जु वर्ग (मुज), (६) पत्र वर्ग (भोजपत्र आदि) (७) पुष्प वर्ग जिनमें रगई के फूल भी होते थे जैसे किंदुक, कुमुभ और कुकुम, (८) शीपव वर्ग (कंदमूल फल) और (९) विप वर्ग। कौटिलीय अर्थशास्त्र में चमड़े के सामान, हड्डियों के सामान दात, सींग, गुर आदि में बहुत उपयोगी चीजें बनायी जाती थी (१०) पशु ब्रज में भी कर मिलता था और पशु पालन बड़े पैमाने पर होता था (११) उन सब करों के अतिरिक्त राजा को यदा-कदा प्रजा में उपहार भी प्राप्त होता था (१२) उन सब जीपकों के अतिरिक्त खानों में भी राजस्व प्राप्त होता था जिनमें गेना, चादी, हीरा, मोती आदि कई प्रकार के मनिज निकाले जाते थे।

कृषि निर्देशक मीताव्यवस्था कहलाता था और वही खाम महाल की कृषि व्यवस्था करता था। पहले मीताव्यवस्था सभी प्रकार की उपमा के वीज एकत्र करता था। फिर उन सबकी रोपनी होती थी। उसके काम में नौकर, गजदूर और कंदो लगाये जाते थे। आदमियों को सभी प्रकार के सामान भी वही मुहैया करता था। वह बटाई पर जमीन का बन्दोबस्त भी करता था। इन व्यवस्था को अर्थशास्त्र कहते हैं। खेती करने के लिए जमीन लेनेवालों को शाना वीज और सामान लगाना पड़ता था पर जो खेती में सिर्फ श्रम करते थे उन्हें उज का चौथा या पाचवा हिस्सा दिया जाता था।

गावों के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न प्रकार के रेकार्ड भी रखे जाते थे जिन्हें निवध कहा जाता था। गावों का वर्गीकरण प्राचीन निवधों के अनुसार निम्न प्रकार का है। (१) परिहरक (करमुक्त), (२) श्रायुधीय (सैनिक सेवा में नियुक्त), (३) हिरण्य जो अनाज या नकद कर देते थे, जो कच्चे गाल देते थे या जो कर प्रतिकार के बदले श्रम देते थे जिसे विस्टी कहा जाता था। गावों में पाटों का विभाजन भी हो गया था। (१) जोतने लायक भूमि, (२) परती जमीन, (३) हीला टावर, (४) केदारा (नम और दलदल आदि), (५) पार्क (अरम), (६) शड (वगीचे), (७) वट, (इच्छु उत्पादक), (८) ई धन तथा अन्य प्रकार की लकड़ीवाले जंगल, (९) वाम्तु (जहा वस्तिया हो, (१०) चैत्य (पूजा के पेड जैसे पीपल, आवला, वट आदि), (११) मन्दिर और देवालय (१२) सेतु (निचाई के स्थान), (१३) अर्थेष्टि स्थान, (१४) मत्र (१५) प्रय पानी चलति (१६) तीर्थ स्थान (१७) विविक्त (चारागाह), और (१८) सडकें और राजपथ।

प्रत्येक ग्राम में मख्या लिखने के लिए बहिया थी जिनमें निम्न विवरण रहता था, (१) प्रत्येक व्यक्ति का विवरण रहता था, (२) कर दाता या कर मुक्त, (३) जाति के अनुसार विवरण, (४) कृषको, गोरक्षको, वैदेहको, कारुषो, कर्मकारो और दामो का विवरण, (५) पशुओं की संख्या, (६) प्रत्येक व्यक्ति द्वारा राज्य को क्या मिलता है इसका क्रमिक

वर्णन, (७) पुरुषों, स्त्रियों, वच्चो का विवरण, (८) गाव या परिवार व धर्म एव धार्मिक मान्यताएँ (९) घरेलू बजट, आय और व्यय। इन पुस्तकों से सरकार को देश की स्थिति का पूरा पता चल जाता था।

ग्राम अध्यक्ष के अतिरिक्त सरकार की तरफ से गाव-गाव में निरीक्षक बराबर वेश बदल-बदल कर घूमा करता था। वह प्रत्येक गाव के रकाड़ों का निरीक्षण करता था जिसमें उसे प्रत्येक तथ्य की पूरी जानकारी हो जाती थी। इन्स्पेक्टर प्रत्येक गाव के अनर्थकम् पर भी नियंत्रण रखता था। इस श्रेणी में वे लोग आते थे जैसे नर्तकियो, कलाकारो और अन्य प्रकार के लोग। बाहरी तत्त्वो पर कड़ी निगाह रखी जाती थी। कृषि तथा अन्य उत्पन्न के प्रवध में भी राजा को खबर पहुचानेवाले दूत थे। जिन जिन्सो का आयात होता था उसके द्वारा भी कर निर्धारित था और उसकी वसूली मुस्तद्दी से की जाती थी। माल रखने के लिए जो गोदाम बने होते थे उनका किराया भी सख्ती से नियमित वसूल किया जाता था। जिला अधिकारियो के ऊपर प्रदेशतर यानी प्रदेशाधिकारी भी थे जो जिले के कारवार का निरीक्षण करते थे। कृषि करो के अतिरिक्त अन्य उत्पादनो पर भी कर लगाये जाते थे। वशिष्ठ में नदियो के विविध इस्तेमाल के निमित्त भी कर निर्धारित था, पहाडियो व सूखी घासो पर भी वसूला जाता था। गणतंत्र में पेट की जडो, फलो, डालियो, जडी-बूटियो, मधु, मास और ई धन के लिए भी राजस्व का विवरण मिलता है। इन करो के अतिरिक्त राजा किसानो से पशु कर भी वसूल करता था। विष्णु पुराण में विविध प्रकार के करो का वर्णन आता है।

प्राचीन भारतीय ग्रामीण अर्थनीति में कृषि के अतिरिक्त अन्य धधो का भी सुन्दर इत्तजाम था। ऋग्वेद में बढई, करमर, लुहार, सोनार, चमार तथा बुनकर का उल्लेख है। बुनकर ओतु और तन्तु के जरिये कपडा बुनता था। इनके अलावा प्रत्येक परिवार का जिक्र आता है जिसमें पिता भिषज था, बेटा दार्शनिक, स्त्री आदर्श गृहिणी जिसके लिए उपल प्रकषिणी शब्द आया है। यजुर्वेद में मलाहो, घोबियो, हलवाहो, नाइयो, वधिको, कसाइयो, हरकारो तथा अन्य प्रकार के शिल्पो में लगे हुए लोगो का पूर्ण विवरण है जिसमें पता चलता है कि समाज में कर्म श्रेणिया अत्यन्त बारीकी से बाटी गई थी। समाज का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जिसे विधान एव नियम के अन्तर्गत न रखा गया हो।

उद्योगो का सघटन भी श्रेणी में विभक्त था। गौतम ने कई उद्योगो में लगी जमातो का क्रमवार वर्णन किया है। जातको में अट्टारह उद्योगो का वर्णन है और इन सबो का पृथक-पृथक प्रमुख तथा जेठक हुआ करता था। इस श्रेणी विभाजन के अलावा जातको में ऐसे गावो के वर्णन भी आते हैं जिनमें केवल एक वर्ग के व्यवसाय करनेवाले रहते थे। इससे पता चलता है कि उद्योग छोटे-छोटे पैमाने पर विकेन्द्रित थे। यदि केन्द्र बडे-बडे होते थे तब विविध उद्योगो के नाम पर गलियो और सडको का नामकरण होता था। आज भी बनारस में हमलोगो को पेशे एव उद्योगो के नाम पर गलियो एव वाजारो के नाम मिलते हैं। जातको में भी इसका विशद विवरण है।

गहरो के फाटको पर ग्रामीणो के वाजार लगते थे जिसमें केवल धनाज की विक्री होती थी। जातको में मछली बेचने के केन्द्र का भी जिक्र

है। साथ ही उत्तर पाचाल में मछली तथा अन्य सामानों की दूकानें थीं। बनारस शहर के बाहर एक बधशाला का विवरण भी उसीमें प्रस्तुत है। मिथिला के चारो फाटको पर भी चार वाजार लगते थे। प्राचीन काल में गावो में जिन्सो का उत्पादन भी होता था और उनका वाजार भी वहा था। अन्य बडे-बडे सामानो की विक्री के लिए भी दूकानें पृथक-पृथक थी। बडे-बडे स्टोर भी थे जिन्हें अ्रवतर्पण कहा जाता था। वाजारो में मद-मास, दास-दासी, अस्त्र-शस्त्र आदि सब कुछ मिलता था। जातको में व्यावसायिक अनुमानो का जिक्र भी है। वाजारो में जानवरो और मनुष्यो की सुविधा के लिए सब कुछ बना रहता था जैसे मनुष्य के लिए पुरीपालय एव पतिहार।

प्राचीनतम पुस्तको एव रेकाडों में चौसठ कलाओ का विवरण सर्वत्र मिलता है। सस्कृत तथा प्राकृत में समान रूप से चतुषष्टी कला का वर्णन है। प्राचीन काल में भारतीय गावो में कृषि एव उद्योगो की समुचित स्थिति थी। अ्रव सभी प्रकार में गावो का वर्णन लिया जाय। वैदिक काल में गाव अधिक दूर पर नहीं थे। उनके साथ यातायात का सबध अच्छी तरह रहता था। प्रत्येक गाव में स्टोर रहता था जिसे गविष्ठी करते थे। जानवरो के कानो पर मालिको के चिह्न रहते थे। गाय चरानेवालो को गोपाल कहा जाता था। वैदिक काल में गाय, बैल, घोड़े, कुत्ते, बकरे, भेडे, गदहे आदि जानवर थे जिसका सरक्षण समाज द्वारा होता था। ऊट और खच्चरो का उल्लेख भी प्रचुर मात्रा में मिलता है।

ग्रामीणो के नैतिक उन्नयन के लिए एव सामाजिक स्तर के सरक्षण के लिए नियम थे तथा सस्थाए थी जिनके द्वारा सबको उनका आचरण अपरिहार्य माना जाता था। उस समय जो लोग सांस्कृतिक या धार्मिक कार्य करते थे उन्हें कर-मुक्त जमीन दी जाती थी। इस श्रेणी में शिक्षक, पुरोहित, कुल गुरु, विद्वान तथा पडे प्रमुख थे। उस समय गावो के जीवन में भी कई प्रकार के विभाजन थे। अध्ययन एव तपश्चर्या के लिए ब्रह्म, सोम, अरण्य एव साधन के लिए तपोवन हुआ करते थे। राजगृह के वेणुवन और श्रावस्ती के जेतवन के बिहारो में बौद्ध भिक्षु रहते थे।

प्रत्येक गाव में जन-कल्याण के लिए समाज में कार्य किये जाते थे (१) कुए खोदे जाते थे जिन्हें कूप या उड्डुपा कहा जाता था (२) तडाग खोदे जाते थे (३) पोखरा (सारा) (४) जलवाह (खायी) (५) प्रश्रवण (झरने) (६) सेतु (७) उपवन (८) अरम (पार्क) बनाये जाते थे। इनके अतिरिक्त गावो के रहने के लिए बडी-बडी गोशालाएँ बनाई जाती थी जिसमें एक साथ एक हजार गायें रह सकती थी। इस प्रकार गाव भर के जानवर एक साथ भी रह सकते थे। प्रत्येक गाव में कम-से-कम छ सौ फीट का चारागाह रहना आवश्यक माना जाता था। राज्य की ओर से भी गावो को अधिक सुखी-सम्पन्न बनाने के लिए प्रयास किये जाते थे ताकि लोगो को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। पुण्य स्थान, देवस्थान आदि राज्य की ओर से बनाये जाते थे परन्तु व्यक्ति विशेष को भी इनके निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाता था।

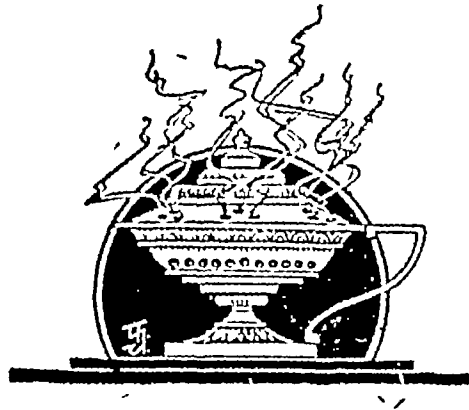
ग्राम-प्रशासन, अध्यक्ष, सख्याध्यक्ष, गोप, स्थानिक, आदि चलते थे। जानवरो की चिकित्सा के लिए अनिकस्थ रहा करते थे। अन्त में यह भी देखना जरूरी हो गया कि आवादी क्रमानुसार बढ़ती हुई। उसी अनुपात

में करो में भी वृद्धि होती गई। गुप्त एवं गुप्तोत्तरकालीन शिला लेखों में जो वर्णन मिलते हैं (१) उद्वंग कर, यह जमीन की बन्दोवस्ती के समय लिया जाता था। (२) उपरिफ, उन किमानों ने बमूल किया जाता था जिनका जमीन पर किमी प्रकार का हक नहीं होता था। इसके अतिरिक्त बट, अरबट, हिरण्य, विष्टिक आदि कर वसूले जाते थे। उस समय अपराध कर अधिक माना में कर वसूला जाता था। मानसिक, कायिक और वाचिक तीनों प्रकार के अपराधों के लिये लोगों को दंड देना पड़ता था। इन तीन प्रकार के अपराधों की तीन-तीन शाखाएँ होती थीं। भोगभाग आदि अन्य कई प्रकार के कर भी लागू होते थे, वसूले जाते थे।

प्राचीन ग्रन्थों के मिलनिलेवार अध्ययन में यह पता चलता है कि गावों का शासन सम्पूर्ण, नर्वा गीण एव समीचीन था। जनता की आर्थिक सामाजिक, नैतिक, धार्मिक एव सांस्कृतिक उन्नति भरपूर हुई थी।

ग्राम का सघटन एकदम वैज्ञानिक तरीके से किया गया था। ग्रामीणों में पूर्ण एकता, पारस्परिक सद्भाव था। विशेष कर प्राचीनकालीन जनगणना विलकुल अत्याधुनिक चीज है जिसका इस युग में भी अनुकरण होना चाहिये।

दस गावों की यूनियन को शान्तिग्रहण कहते हैं। दो सौ गाव मिलकर कर्बतिक कहलाते थे, चार सौ गाव द्रोणमुख और आठ सौ गावको माताग्राम कहा जाता था। इसके लिए प्रशासनिक शब्द स्थानीय था जो आधुनिक थाने से कुछ मिलता था। एक गाव में एक सौ से लेकर पाच सौ तक परिवार रहते थे। उसके बाद के माहिर्य में यह उल्लिखित है कि शासन में दशक नियम का प्रचलन हुआ जिनके मुताबिक दस गावों पर शासन करनेवाला दशकग्रामी कहलाया, बीसगावों वाला विशनिया और सौ गावों का प्रशासक सतकग्रामी कहलाया। ये सबके सब अधिपति के मातहत रहते थे जो हजार गावों पर प्रशासन करता था।





# भारत में भूमि-व्यवस्था का भविष्य

स्वर्गीय डाक्टर सुविमल चन्द्र सरकार

जमीन्दारी प्रथा को लोग आदिम काल से ही अन्यायपूर्ण, अनौचित्यपूर्ण एवं विनाशक मानते आये हैं। सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक एवं वैधानिक सभी दृष्टियों से यह प्रथा दोषपूर्ण है। वस्तुतः अठारहवीं शताब्दी के अन्तिम चरण में ब्रिटिश मत भी इस दिशा में विभाजित नहीं था। उसी समय ईस्ट इंडिया कम्पनी जमीन की बन्दोबस्ती करने जा रही थी। उस समय कम्पनी को बहुत सा नकद रुपया चाहिए था जिससे युद्ध के लिए व्यय निकाला जा सके। आरम्भ से लेकर अब तक उसकी उपादेयता, उपयोगिता तथा सुविधासम्पन्नता के बारे में तर्क उपस्थित किये जा रहे हैं। यह कहा जाता था कि यह व्यवस्था ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी देन है।

यह कहना तो बिलकुल गलत होगा कि जो व्यवस्था पहले से चली आ रही थी उसे ही अंग्रेजों ने पक्का बना दिया। अंग्रेजों ने यह देखा कि किसी एक प्रकार की प्रथा व्यवस्थित नहीं रहती है बल्कि जो प्रथाएँ चलती थी वे भी सड़ी-गली आकृति में। जो प्रथा पहले म्रियमाण हो चुकी थी वह जमीन्दारी नहीं थी। विश्रु खल होने के पहले वह मुगलों द्वारा आरम्भ की हुई अफगानी प्रथा थी। उस प्रथा द्वारा अफगान यह प्रयास करते थे कि भूमि राष्ट्रीय उपयोग के अनुकूल एवं पूर्ण रूप से पैदावार हो जाय। इसका आवार वही प्राचीन भारतीय प्रणाली ही थी। मुगलकाल में जो जागीरदारी या मनसबदारी प्रथा चलाई गई वह वस्तुतः शेरशाह द्वारा आरम्भ की गई थी। उसके आरम्भ करने वाले राजा टोडरमल थे। इस तरह प्राचीन भूमि व्यवस्था, राज्य के परिवर्तन से, अनवरत युद्धों से और शाही दरबार एवं हरमों के बड़े हुए खर्चों से बरबाद हो गई। केन्द्रीय देखरेख भी नहीं रही और भारत के बहुत से प्रदेश विदेशी रागनीतिक लुटेरों द्वारा बरबाद कर दिये गये। इसका परिणाम व्यापक रूप से इतिहास पर पड़ा। अंग्रेज इन सभी स्थितियों से परिचित थे। इसलिए उन्होंने इस देश में एक ऐसी व्यवस्था दी जिस कारण यहाँ गरीबी जड़ जमा गई। देश का भविष्य, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक सब अवरुद्ध हो गया। यह सत्य है कि अंग्रेजों ने नीलामी को खत्म कर दिया इसके पहले वे दीवानी बन्दोबस्त कर चुके थे और इसीमें कृषि अर्थ व्यवस्था समूल नष्ट हो चुकी थी। इसके पश्चात् उन्होंने दमामी बन्दोबस्त किया जो यहाँ की परम्परा के पूर्णतया प्रतिकूल था। इस प्रथा में युरोपीय प्रथा की समानता है। इतना आवश्यक नहीं कि इस भूमि

व्यवस्था के कारण निर्धारित करते समय किसी तरह का आक्षेप लगाया जाय। परन्तु प्रत्येक कदम किसी उद्देश्य को लेकर ही उठाया जाता है और इतना कहना ही अनिवार्य होगा कि अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त यह जमीन्दारी प्रथा हमारे देश के लिए विनाशक सिद्ध हुई। वे भारतीय तो थे नहीं अतः उन्होंने सभी दृष्टिकोणों से विचार करना आवश्यक नहीं समझा ताकि यहाँ का उत्पादन बढ़े और गरीबों में समृद्धि विराजे। जो भी भारतीय चैतन्य होकर इस प्रथा की खराबियों के बारे में सोचते थे उनके पास इतनी शक्ति नहीं थी कि इस दिशा में वे कुछ कर सकें। अभी जब देश आजाद हो गया है तब हम भूमि सुधार, भूमि नियोजन आदि के लिये अमरीकी या रूसी प्रणालियों से प्रेरणा प्राप्त करना चाहते हैं। ईस्ट इंडिया कम्पनी के शासकों को मीरकासिम और सिराजुद्दौला की भूमि व्यवस्थाओं का ज्ञान था। इस प्रकार सतत राज्य परिवर्तनों तथा प्रबन्ध परिवर्तनों के कारण भूमि व्यवस्था का अपना मूल स्वरूप एकदम नष्ट हो गया। पठान और मुगल कालों में जो थोड़ी अच्छाई बच गई थी उसे भी अंग्रेजों ने खत्म कर डाला। यह क्रम १८वीं शताब्दी के अन्त में और १९वीं शताब्दी के आरम्भ में चलता रहा।

भारतीय ग्राम्य व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था को कितनी क्षति पहुँचाई गई और उसके लिए क्या-क्या किये गये उसका पता तब चलेगा जब कोई क्लाइव और हेस्टिंग्स के समय के भूमि सबधी कागजातों का अध्ययन करे। यहाँ दो-चार महत्त्वपूर्ण खराबियों का ही उल्लेख कर रहा हूँ और इसी कारण १८वीं शताब्दी में बंगाल में क्रान्ति हुई थी जिसका प्रचलित नाम मन्वन्तर है।

(१) अंग्रेजों ने इस देश में भूमिपतियों का एक नया वर्ग पैदा कर दिया जिसका निर्वाह लाखों किसानों के कठिन श्रम और उनकी अमानुषिक गरीबी पर होता था और जिनके सारे अधिकार अपहृत किये जा चुके थे।

(२) जो लोग बहुत जमाने से भूमि के मालिक थे उनके स्थान पर नये लोगों के साथ जमीन बन्दोबस्त की गई। इस तरह लोग दूसरों पर निर्भर रहने लगे और एक प्रकार के अर्द्धदास हो गये। अब इन किसानों का



# भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मूल आकृति

श्री पी० के० मुखर्जी

भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था पर कई जिल्दों में पुस्तकें लिखी गई हैं और उसका विवरण एक छोटे से लेख में देना कुतूहलजनक प्रतीत होगा। अगर वास्तविक स्थिति की आलोचना की जाय तब यह पता चलता है कि आर्थिक क्षेत्र एवं आकड़े सम्बन्धी कितना भ्रमात्मक विचार एवं तथ्य सरकारी अफसरों, जनता एवं अनुसंधान करनेवालों के मस्तिष्क में स्थित हैं इस पर आश्चर्य होना स्वाभाविक है। बहुधा यह कहा जाता है कि ग्रामीण अर्थ व्यवस्था स्वतः सम्पूर्ण होने के साथ-साथ एकदम आत्म निर्भर हो गयी है। गभीर पाठक अगर अर्थ शास्त्र की पोथी के पन्ने उलटें तब पता चलेगा कि कई दशकों से ऐसी विचारधारा पोषित होती चली आई है। यह भी कहा जाता है कि खाद्यान्नों की कीमत बढ़ जाने से कृषकों की आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो गयी है। दुर्भाग्यवश इस देश के अर्थ शास्त्रियों ने कृषि एवं ग्राम्य अर्थ व्यवस्था सबधी आकड़े नहीं इकट्ठा किया है जिसपर ग्रामीण अर्थनीति एवं व्यवस्था आधारित की जा सके। जो भ्रान्त धारणायें प्रचलित हैं उसका प्रधान कारण है मस्यतया पाश्चात्य देशों में प्रचलित अर्थ प्रणाली का विवेचन। दूसरा कारण है देश की वास्तविक ग्रामीण स्थितियों के संघर्ष में कम रुचि तथा कृषि प्रणालियों का स्वल्प ज्ञान। एक लेखक का मत है, जब ग्राम्य जीवन सबधी प्रश्न प्रमुखता धारण कर लेते हैं तब अर्थ शास्त्री उसे विस्तृत कर देने की धारणा बना लेते हैं जिसके आधारस्वरूप सामान्य अर्थनीति और ग्राम्य जीवन के सम्बन्ध में आनेवाले बहुत से भ्रान्त तथ्य निहित रहते हैं और जिनका उपयोग ठीक-ठीक गावों के वातावरण में नहीं किया जा सकता है।

इस लेख का मुख्य उद्देश्य है भारतीय ग्रामीण अर्थ नीति की व्याख्या करना। किमी भी भूमि सुधार योजना लागू करने या अधिक उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम आरम्भ करने के पहले इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लेना बड़ा जरूरी हो जायगा। इसका अध्ययन दो भागों में विभक्त होगा। पहले भाग में ग्रामीण जीवन के स्तर की चर्चा करेगा जिसमें प्राचीन-कालीन व्यवस्था एवं ब्रिटिश काल की व्यवस्था, दोनों का विशद उल्लेख रहेगा। इन विवरणात्मक एवं ऐतिहासिक पर्यालोचन में नियोजकों को पूर्ण जानकारी होगी और तार्किक तथ्यों का विवेचन हो सकेगा।

भारत कृषि प्रधान देश है। यहां सत्तर प्रतिशत लोगों की जीविका कृषि पर ही अवलम्बित है। इसकी तुलना में ब्रिटेन में छ प्रतिशत लोगों का, अमेरिका में उन्नीस प्रतिशत लोगों का, युद्धपूर्व जर्मनी में चौदह प्रतिशत का और फ्रांस में पच्चीस प्रतिशत लोगों की जीविका का सधान कृषि है। प्रत्येक व्यक्ति यह जानता है कि प्राचीन भारत में युग-युग से सम्यता एवं समृद्धि के केन्द्र गाव ही थे। डचों, फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों के आने के पहले और इन व्यापारिक शोषकों के जाल विस्तृत होने के पहले भारत एशिया का सर्वोत्कृष्ट तथा समुन्नत देश था, कृषि की धातु एवं विश्व के औद्योगिक केन्द्र के रूप में।

भारत के औसत गाव में, प्राचीन काल में, प्रायः तीन सौ घर होते थे जिनमें ५० प्रतिशत किसान होते थे। प्रत्येक गाव में प्रायः दो सौ एकड़ उर्वर एवं अनुर्वर भूमि रहती थी। छोटे-छोटे गावों के चतुर्दिक खेत रहते थे। ऐसी खेती नहीं होती थी जिसे मालकियत या केन्द्रित प्रबन्ध की आवश्यकता पड़े। प्रत्येक गाव के शासक रूप में पटेल ही गाव का मुखिया हुआ करता था। वही व्यक्ति ग्रामवासियों के झगड़ों का निपटारा करता था और गाव की मालगुजारी वसूल करता था। पटेल के बाद गाव का कुर्णम होता था जो गाव का बही-खाता और आय-व्यय का लेखा-जोखा रखता था। इसके अतिरिक्त ग्राम रक्षक होता था और सीमा का निरीक्षण करनेवाला एक दूसरा व्यक्ति भी। गाव के पूजनादि तथा धार्मिक उपचारों के निमित्त ब्राह्मण पुरोहित रहता था। इन सबके अलावा ग्राम शिक्षक तथा ज्योतिषी भी हरेक गाव में रहते थे।

अब प्रत्येक गाव की सामाजिक एवं आर्थिक आकृति का दिग्दर्शन किया जाय। सब लोगों का निर्वाह कृषि से, छोटे उद्योगों से ही होता था। सामाजिक तथा आर्थिक सघटन में स्वयं निर्भरता रहती थी। इसके अलावा ग्रामवासी एक दूसरे पर पूर्ण निर्भर रहते थे।

तत्कालीन स्थिति में लोगों की आवश्यकताएं गावों के उत्पादन, कृषि तथा कुटीर उद्योगों से ही पूरी हो जाती थी। सहकारिता के आधार पर कृषि होती थी और खाद्यान्नों का वटवारा हो जाता था। सूत कातने और बुनने का काम प्रत्येक परिवार में होता था। गाव का लुहार और बढई



इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि हमारी अर्थ व्यवस्था, जो समाज और देश के बिल्कुल समीचीन थी, वह लुप्त हो गई। ब्रिटेन में यदि बुनकरो के करघो का सर्वनाश हुआ तो वहा उनकी जगह पर मशीनो के उद्योग चालू कर दिये गये। लेकिन भारतवर्ष में लाखो कारीगरो को वेकार कर उनके बदले मशीन के जरिये भी नये उद्योग-धधे नही आरम्भ किये गये। इस प्रकार जनता को केवल कृषि पर ही अवलम्बित रहना पडा। इस पद्धति से भारतवर्ष समान रूप से कृषि एव कुटीर उद्योगो का सतुलित देश न रहा, प्रत्युत ब्रिटेन का कृषि उपनिवेश बन गया।

इसी लेख में ऊपर कहा जा चुका है कि प्राचीन पद्धति के अनुसार भूमि पर समस्त ग्रामवासियो का अधिकार होता था। यह सच है कि जब अंग्रेजो ने देशी राजाओ से छीन कर अपना अधिकार यहा जमाया तब कृषको से अधिकारिक कर लिये जाते थे। इस तरह किसानो से माग बढती गई कि उन्हें अपने सरक्षित बीज एव बैलो को बेचकर भी लगान देने को विवश होना पडा। इससे भी अधिक ब्रिटिश विजय के अनन्तर भूमि व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया। अंग्रेजो के पाचसाला एव सातसाला बन्दोबस्त करने के बाद १७९३ में लार्ड कार्नवालिस ने भूमि का चिरस्थायी प्रबध कर दिया जिसके फलस्वरूप जमीन्दार वस्तुतः कर वसूल करनेवाले हो गये जो पहले भूमि के मालिक नही थे। इस प्रबन्ध से जो खराबिया हुई उससे कर्ज देनेवालो का एक वर्ग हो गया और जमीन्दारो के साथ-साथ ये लोग भी शासन के पिटू हो गये।

अब केवल कृषि से ही वर्धिष्णु समाज के व्यय वहन का आसरा हो गया। कृषि भी यहा उन्नत एव तमाम साधन से पूर्ण नही थी, इस कारण उत्पादन अत्यन्त कम होता था। इन्ही सब कारणो से जमीन पर समाज का समष्टिगत अधिकार नही रहा। राज्य एव किसानो के बीच जमीन्दार की एक नई जाति पैदा कर दी गई। इन्ही सब कारणो से किसान दिनोदिन कर्जखोर होता गया।

अब वर्तमान काल की ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था का समीक्षण करना होगा। गावो की आवादी में अब छ वर्ग हो गये हैं। इनमें (१) वे लोग जो भस्वामी हैं और जिन्हें भूमि बन्दोबस्त करने का पतुत अधिकार है। (२) वे लोग जिनसे जमीन बन्दोबस्त की जाती हो और जिन्हें मालिक की इच्छा पर ही वेदखल कर दिया जाता हो (३) भूमिहीन खेतिहर मजदूर (४) गाव के कारीगर (५) कर्ज देनेवाले और दूकानदार (६) वे लोग जो नौकरियो में हैं, जैसे डाक्टर, वकील इत्यादि। ये सभी वर्तमान समाज के प्रमुख अंग हैं। यद्यपि एक जाति का दूसरी जाति से, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, एक पेशेवाले का दूसरे पेशेवालो से घनिष्ठ सम्बन्ध है। परत सभी एक दूसरे के साथ पारस्परिक सलग्नता में निबद्ध हैं। एक व्यक्ति जमीन का मालिक भी है, स्वयं किमान भी, कर्ज देनेवाला भी और पुरोहित-पुजारी भी। एक किसान खेतिहर मजदूर भी है और कारीगर भी।

गाव के खेत जोतनेवाले या तो सीधे सरकार मे जमीन बन्दोबस्त लेते हैं या जमीन्दारो मे, जिन्हें वे कर देने हैं। वे उस खेत पर समस्त परिवार के साथ काम करते हैं और कभी-कभी मजदूरो से भी काम करवाते हैं। कुछ पूजो वे अपने पास ले लाते हैं और कुछ, घट जाने पर, जमीन्दार या

कर्ज देनेवालो से लेते हैं। वे उपज की विक्री गावो के हाटो में करते हैं जिसके बदले अपनी जरूरत के अन्य सामान प्राप्त करते हैं।

तीसरा वर्ग भूमिहीन खेतिहर मजदूरो का है जो समाज के सबसे गरीब वर्ग का है। ये लोग सतत कठिन परिश्रम के बाद भी अपनी भूख नही मिटा पाते हैं। भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में इनकी प्रमुख सख्या हो गई है। १८८२ की जनगणना के अनुसार उस समय सत्तर लाख खेतिहर मजदूर थे। इनकी सख्या १९११ में करीब दो सौ बीस लाख हो गई और बढते-बढते १९३१ मे तीन सौ तीस लाख हुई। इन मत गणना रिपोटों के अनुसार यह पता लगाना कठिन हो गया है कि पेशा सम्बन्धी पार्थक्य कितना था और प्रत्येक गाव में इस तरह के पार्थक्य की सीमा कितनी दूर तक आगे बढी है। पुन यह पता लगाना भी मुश्किल हो गया है कि उनके जीवन का मान और स्तर कितना ऊबड-खावड है। हमारे देश मे इन खेतिहर मजदूरो की यह स्थिति है कि वे अपनी व्यक्तिगत आजादी को भी बन्धक रख चुके हैं।

हमारे देश में इस वर्ग की गरीबी केवल सम्बन्धित आदर्शों पर ही आधारित नही है। अमेरिका और ब्रिटेन की तरह यहा जीवन-स्तर के उन्नयन की माग नही है। वल्कि यहा का सुविधावादी वर्ग सम्प्राप्त सामानो से ही अपने को सुखी रखता है तथा उसकी तुलना में गरीब वर्ग एकदम उपेक्षित है। यदि यूरोप के स्तर से हम अपने देश की तुलना करें तब हमारी प्रचड गरीबी का अनुमान लग जायगा। हमारे खाद्य पदार्थ इतने कम हैं जिनसे शरीर का भरपूर पोषण नही होता। इस दयनीय स्थिति के बहुत से कारण हो सकते हैं। बहुत से विद्वानो का यह मत है कि हमारी यह स्थिति सामाजिक कारणो से अधिक है और आर्थिक कारणो से बहुत कम। उदाहरण के लिये वे तर्क करते हैं कि हमारे किसान धर्म और परम्परा के अनुसार सुख और सुविधा पाने की चेष्टा करते हैं। इससे अस्वीकार नही किया जा सकता है कि सादा जीवन का आदर्श गावो की सादगी का मुख्य कारण है। पर इससे भी इनकार नही किया जा सकता है कि हमारी गरीबी केवल इसी विकार के कारण है। एक अर्थ शास्त्री का मत है ग्रामीण जीवन में आध्यात्मिक सतोप पर बहुत लिखा गया है लेकिन यह सत्य खेतिहर मजदूरो पर लागू नही होता चूकि उन्हें तो औद्योगिक मजदूरो की अपेक्षा बहुत कम पारिश्रमिक मिलता है।

रैयतो और खेतिहर मजदूरो के बाद भी कारीगरो की एक जमात बच जाती है जो गावो की अर्थ व्यवस्था में भरपूर योग देती है। बुनकर, लुहार, तेली, कुम्हार, सोनार आदि समाज की आवश्यकताएं पूर्ण करते हैं। इन्हें नकद दाम मिलता है। कपडो की बुनाई हमारे यहा सर्वोत्तम ढंग से होती थी और हमारे यहा का बना हुआ मलमल जगत प्रसिद्ध था। लकाशायर और मैनचेस्टर के कपडो ने इस उद्योग को बर्बाद कर दिया जिस कारण लाखो कारीगर वेकार हो गये। इन घक्को के वावजूद ये उद्योग अभी तक जीवित है। बर्तन बनाने का काम भी हमारे देश मे बखूबी होता था। बढई, लुहार के काम भी इतने सुन्दर होते थे कि जिनका मिसाल मिलना दुर्लभ है। कृषि व्यवस्था मे सबका सहयोग बराबर रहता था और सब एक दूसरे के सुख-दुख, उत्थान और

पतन के साक्षीदार होता था। इसी बात पर समाज की गरीबी या अमीरी का अनुमान लगाया जाता है। इनकी रीढ़ टूट जाने के बाद देश में बार-बार अकाल पडने लगा और ऐसी स्थिति आ गई जिस कारण लोगो की पूजी नष्ट हो गई, घर के सामान विक गये, कला और कारीगरी मर गई।

हमारे यहा खेतो का जिस प्रकार से विभाजन हुआ है उससे एक परिवार का साल भर तक व्यय नहीं वहन हो सकता। जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो जाने के कारण लोग अच्छी तरह खेती नहीं कर सकते। तब किसानो के लिये कर्ज लेने के सिवाय कोई रास्ता नहीं रहता। मसल मश-हूर है कि भारतीय किसान कर्ज में पँदा होता है, कर्ज में डूबता रहता है और कर्ज में ही मर जाता है। बहुत से किसानो के खेत कर्ज देनेवाले ले लेते हैं, जिनकी रुचि न खेती करने की ओर रहती है और न उत्पादन बढ़ाने की ओर। इस क्रम से किसान मजदूर हो जाते हैं जिन्हें केवल खेती के दिनों में ही काम मिलता है। एक दूसरे अर्थशास्त्री का मत है, भारतवर्ष की गरीबी का कारण न तो वीमारी है, न निरक्षरता, न बढ़ी हुई जनसंख्या बल्कि इस दुर्दान्त गरीबी का कारण है आर्थिक व्यवस्था में बेहद विपमता।

वर्तमानकालीन भारत की आर्थिक व्यवस्था कोष्ठबद्ध है और साथ ही इतना कमजोर जिसे किसी भी नाजुक स्थिति से क्षति पहुचने की सम्भावना रहती है। इसकी व्याख्या बेकारी और बेरोजगारी तथा कम उत्पादन में ही सन्निहित है। ये दोनो अवस्थायें साथ-साथ चलती हैं और दोनो एक दूसरे पर अवलम्बित हैं।

परिवर्द्ध आर्थिक प्रणाली में बाहर से बहुत कम विनिमय होता है। इसके निम्नकारण हैं (१) क्षेत्र में उत्पन्न सभी चीजो की खपत एक ही जगह हो, (२) विनिमय का बहुत सा भाग अद्धता रहता हो, (३) परिवर्तनो में अपने यहा की निर्मित चीजों भी न मिलती हो। गाव के आपसी विनिमय तो बहुत कम होते है क्योंकि अब वे स्वयसम्पूर्ण नहीं रहे। इसके कई कारण हैं (१) आवादी की वृद्धि, (२) क्षेत्र में न उन्मन्न होनेवाले जिनतो की अधिक माग। इन चीजो की अधिक माग उन लोगो में बढ़ी है जिनकी आय विविध साधनो से बढ़ कर मोटी हो गई हैं। इसलिए हमारा देश दरिद्र हो गया है। लोगो के पास कुछ जमा नहीं रहता और समाज का सचालन बहुत कम आय में होता है। कुछ लोग ऐसी स्थिति में रहते हैं कि वे न तो अपनी आय का हिसाब रखते हैं और न व्यय का। गावों में कृषि के अलावा न तो कोई दूसरा रोजगार मिलता है और न वे स्वय कुछ पूजी लगाकर कुटीर उद्योगो का सचालन ही कर सकते हैं। यदि मजदूरी भी मिली तब उससे आय नाममात्र की होती है। हमारे देश की आर्थिक स्थिति का आधार न तो उत्पादन का अनुपात है और न दामो की अस्त-व्यस्त अवस्था। वस्तुतः उपनिवेश या अर्द्ध-उपनिवेश में शहरी और देहाती अर्थ व्यवस्था में कोई विशेष अन्तर नहीं पडता। युद्ध काल आ जाने पर हमारी आवादी अपना निर्वाह भी नहीं कर सकती थी।

१९४५ में बगाल अकाल जाच समिति की रिपोर्ट में लिखा है, युद्ध के पहले तक भारतवर्ष में खाद्य की कमी की कोई बड़ी समस्या न थी। युद्ध के कारण लोग अधिक तबाह हुए और भूखो मरने तथा किसी तरह प्राण रक्षा करने में कोई अन्तर न रहा। अकाल की अवस्थाओ में भी हमारी आर्थिक व्यवस्था असतुलित हो गई। लोगो की क्रय शक्ति इतनी कम हो

गई थी कि पेट पालने भर भी अनाज नहीं खरीद सकते थे। दो कारणो से गाव का उत्पादन लोगो को वृद्धि के लिये अभिप्रेरित नहीं कर सकता। पहला कारण यह है कि हमारे बढ़ते हुए जीवन स्तर के साथ हमारा उत्पादन निभ नहीं सकता। दूसरा कारण है बढ़ती हुई आवादी के दबाव के पैमाने पर कृषि की व्यवस्था नहीं की जा सकती। कारण खेत छोटे-छोटे टुकड़ो में बटे हुए हैं। अधिक उत्पादन न होने पर थोक रूप से उनकी विक्री भी नहीं हो सकती है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि अगर जीवन का स्टैण्डर्ड बढ़ जाता है और खपत ज्यादा बढ़ने लगती है तब चीजो का दाम भी घट जाता है।

कतिपय अर्थशास्त्रियो का मत है कि भारतीय कृषि में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जिससे आवद्ध अर्थनीति सचालित हो सके। इसके विपरीत विचार रखनेवाले का मत है कि १९३० से ही इस देश के आर्थिक सिलसिले में व्यतिक्रम लाकर पुराने सम्बन्ध विच्छिन्न कर दिये गये। इस वर्ग का यह भी मत है कि कृषि पर ही बढ़ती हुई आवश्यकताओ का बोझ पड गया हालांकि उद्योग और कृषि दोनो पर समन्वित रूप से पडना चाहिये था।

दूसरे पक्ष का ही मत अधिक सही जान पडता है। ग्रामीण क्षेत्रो में विकेन्द्रित शिल्प कुटीर की उन्नति के लिये प्रयास एकदम नहीं किये गये। इसे औपनिवेशिक अर्थ-व्यवस्था कह सकते हैं जिस अर्थ व्यवस्था में किसी प्रकार की विभिन्नता का दृष्टिकोण कार्यान्वित नहीं किया जाता। यह तर्क पेश किया जाता है कि जिस देश का जितनी द्रुत-गति से औद्योगीकरण होता है और इमी कारण सभी वर्गों की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं। पर जब यह सिद्धान्त अर्द्धविकसित समाज पर लागू किया जाता है तब कई शक्तियां परस्पर विरोधी दिशाओ में काम करती हैं। भारत और चीन की ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में बहुत से उल्लेख योग्य परिवर्तन हुए हैं। यहा का उद्योग और व्यवसाय विदेशी आदर्शों पर सचालित होता है। इसलिए इसका प्रभाव मूर्त रूप से गावों में नहीं पहुचता, अतः गावों की व्यवस्था पर उसका कम प्रभाव पडता है।

ऊपर की सैद्धान्तिक दलील का व्यवहार कार्यकारी तौर पर हो सकता है। गावों में कई परिवार रहते हैं और उनके समक्ष जमीन की चकवर्दी तथा उत्पादन के अन्य प्रश्न उपस्थित रहते हैं। उनके लाख प्रयत्न करने के बावजूद कृषि की, अर्द्धविकसित प्रणाली के कारण एवं अवैज्ञानिक पद्धति के कारण, प्रगति नहीं हो पाती। इसके अतिरिक्त उनके पास कोई जरिया नहीं रहता कि वे जमीन्दारो और कर्ज देनेवालो से मुक्ति पा सकें। इसलिए किसानो को परिवार पालन के हेतु मोटे अन्न अधिक परिमाण में पैदा करना पडता है। वे चारागाह के लिये भी या जमीन की उर्वरा शक्ति के सरक्षण के लिये भी जमीन परती नहीं छोड़ सकते हैं, इसी क्रम से खेतिहरो को जमीन से हाथ धो लेना पडता है।

ऊपर के तर्कों पर विचार करने के बाद अदरी विनिमयित अर्थ-नीति तथा गावों की अनाधिक व्यवस्था में बड़ी दीवार खड़ी रह जाती है। इन क्षेत्रो में पहले काम की कमी है, साधनो की कमी है, और ये ही कारण आर्थिक प्रणाली के डावाडोल हो जाने में प्रचुर सहायता करते हैं।

अब उस अर्थ व्यवस्था पर विचार कर लिया जाय जिसके अन्तर्गत समाज को खिलाने मात्र भर ही उत्पादन होता है। इन क्षेत्रों में न तो निर्यात करने भर अन्नोत्पादन होता है और न उत्पादित सामानों को बेचा ही जाता है। भारतवर्ष में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ आयात के बिना काम चल सके। उन्नति के लिये कृषि और उद्योग का समान रूप से विकास होना जरूरी है। प्रत्येक आदमी जानता है कि यहाँ प्रत्येक परिवार का बजट मुश्किल से पूरा होता है। जहाँ की आबादी अधिक है वहाँ बटाई-दार ही अधिक हैं। जहाँ आबादी कम है और जमीन अनुबंध है वहाँ कृषि की सुविधाएँ नहीं हैं। कम उत्पादन दोनों कारणों से है। होल्डिंगों का छोटा होना, कृषि की पुरानी व्यवस्था और अतिरिक्त काम की कमी है।

इस स्थिति का सही तौर पर समाधान तब तक नहीं किया जा सकता जब तक होल्डिंग छोटे रहेंगे। तब तक न तो कृषि की उन्नति हो सकती है और न विविध साधनों से अधिक उत्पादन ही बढ़ाये जा सकते हैं। यह भी सच है कि ऐसी स्थिति बहुत दिनों के लिये सत्य नहीं हो सकती। इसके साथ ही यह कहना भी सत्य है कि एकवारगी सारे देश में इसका उन्मूलन भी नहीं किया जा सकता। किसानों को यदि सुविधाएँ दी जाय तब वे उत्पादन कर सकते हैं और अपनी आर्थिक भित्ति को समान रूप से बनाये रख सकते हैं। यह भी स्मरण रखना चाहिये कि आर्थिक एवं अनार्थिक शब्दों का प्रयोग केवल नैतिक व मानवीय दृष्टिकोण में ही काम देता है। कांग्रेस कृषि सुधार समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि (१) कृषकों को खुशहाल रखना चाहिए ताकि वे जीवन से ऊब कर भाग्यवादी एवं निराशावादी न हो जाय (२) एक परिवार के लिये पूरा काम रहे तथा कृषि के सारे समान उन्हें उपलब्ध हो। यह अधिक आशाजनक सिद्धान्त है। भारत सरकार के योजना आयोग की कृषि-शाखा की रिपोर्ट में लिखा गया है कि किसानों के पास साल भर का काम नहीं रहता फिर भी वे सालों भर खेती में ही व्यस्त रहते हैं, चूँकि उन्हें कोई दूसरा धन्धा नहीं है जिससे उन्हें अधिक आय हो। इस समस्या के समाधान में ही कृषि की उन्नति सम्मिलित है और यह इसलिए कि देश में प्रकृति द्वारा प्रदत्त साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है। जमीन का ही लेखा-जोखा अगर उपस्थित किया जाय तो इस देश में २१४० लाख एकड़ भूमि को कृषकों में बांट देने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो एकड़ जमीन पडती है। कृषि योग्य भूमि का बटवारा समान स्तर पर नहीं किया गया है। जमीन्दार जोतनेवालों से अधिक हैं और खेतिहर मजदूर सबसे ज्यादा। बहुत से जमीन्दारों को तो सौ गावों में जमीन्दारियाँ हैं। करीब १० लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास ३० एकड़ से अधिक भूमि है। इनकी तुलना में लगभग ३२० लाख खेतिहर मजदूर हैं जिनमें २३० लाख के पास एक घूर भी जमीन नहीं है। शेष ७०० लाख ऐसे किसान हैं जिन्हें आधे एकड़ में भी कम जमीन है और इनमें से भी करीब सौ लाख आदिमियों को अपनी जमीनें हैं और शेष रैयतों को जमीन बन्दोबस्त किया

जाता है। उत्पादन अधिक इसलिए नहीं होता चूँकि खेत के टुकड़े छोटे-छोटे हैं। इन कारणों से गावों में औद्योगिक विकास के लिए भी पूजा नहीं प्राप्त होती है। सबसे प्रमुख समस्या है कि भूमि का सुन्दर उपयोग किया जाय जिसका परिणाम स्थायी हो। कृषि श्रम जाच हो जो १९५१ में की गयी थी। उसमें यह लिखा है कि बिहार के औरवा गावों में साल भर में खेतिहर मजदूरों को करीब १५५ दिन ही काम मिलता है। इसमें कृषि तथा अन्य प्रकार के काम भी सम्मिलित हैं। कृषि में ही गावों में अधिक काम मिल सकते हैं। इस आधार पर लोग छ महीने तक ही काम पाते हैं। जो लोग यदा-कदा काम पाते हैं उनका सालाना अनुपात करीब ९५ दिन का होता है। स्त्रियों को साल में ५३ दिन काम मिलता है।

इस लेख में यह बतलाया गया है कि किन-किन उपायों को काम में लाने से इसकी उन्नति हो सकती है। एक व्यावहारिक सुझाव पर विचार किया जाय। मान लीजिये तीन गावों में एक बरदपुर, दो मधुवनी और तीन घेउरा। यह मान लिया जाय कि इन्हीं तीन गावों के लोगों में सभी काम-काज बटा हुआ है और आर्थिक विनिमय भी इन्हीं के बीच होता है। यह भी अनुमान कर लिया जाय कि इन तीनों गावों में जीविकोपार्जन का काम खेती से ही चलता है। भोजन के पदार्थों के अलावा इन्हीं तीनों गावों की दूकानों और हाटों से अन्य सामानों का काम चलता है। उदाहरण के लिये तीनों गावों में एक मोदी की दूकान, एक कपड़े की और एक अन्य सामान की दूकान है और इन्हीं तीनों दूकानों से इस क्षेत्र का काम चल जाता है। व्योरेवार इस तथ्य सग्रह के बाद यह पता चल जायगा कि इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई और कितना परिवर्तन हुआ, इसी आधार पर सारे देश में प्रयोग आरम्भ किये जा सकते हैं।

अब बगाल के एक गाव का उदाहरण दू। यह कलकत्ते के पास का एक गाव है। वहाँ की आबादी में कारखानों के मजदूरों की अधिक संख्या थी। उनके अलावा मध्य वर्ग के कुछ किराने भी निवास करते हैं और सबसे कम आबादी खेतिहरों की है। तथ्य सग्रह के बाद निम्नलिखित दिलचस्प बातें पायी गईं। (१) गाव की दूरी कलकत्ते से १० मील थी वहाँ के लोग प्रतिदिन शहर आते-जाते हैं लेकिन खपत के सामानों का ५० प्रतिशत क्रय गाव की दूकानों और स्टोरो से होता है। अतः उस गाव का सारा कारबार गाव पर ही निर्भर रहता है। (२) मरम्मत के व्यय और नयी पूजा का उपयोग भी उसी क्षेत्र से होता है। केवल १० प्रतिशत बाहर का आसरा रहता है। अब इस जाच के बाद पता चलता है कि अब भी हमारी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था परिवर्द्ध रहती है। इसे अन्य आर्थिक वर्गों से सयुक्त कर देना होगा। यह सयोग कैसे स्थापित हो इस पर विचार करना होगा। यदि यह संभव हो जाय तब कृषि की उन्नति हो सकती है और बहुरूपी विकास बड़े पैमाने पर हो सकता है।

अन्त में यह कह देना आवश्यक है कि कृषि और अन्य उद्योग एक दूसरे पर पूर्णतया आधारित हैं। उत्पादन, क्रय, विक्रय एवं सम्मिलित अर्थ नीति का सामंजस्य ही देश को वर्तमान आर्थिक दुरवस्था से निकाल सकता है।

# प्राचीन, मध्युगीन

## एवं वर्तमानकालीन

श्री नागेश्वर प्रसाद सिंह

छोटानागपुर

प्रशिक्षित को जब एक दुष्ट नाग ने काट लिया तब उनके पुत्र जन्मेजय ने नागयज्ञ किया। एक-एक कर सभी नाग यज्ञ-कुंड में गिर-गिर कर जल मरने लगे। लेकिन एक सर्प जिसका नाम पुडरीक था, वह मनुष्य का स्वरूप धारण कर शिव की नगरी काशी में चला गया।

काशी में पुडरीक ने एक ब्राह्मण की कन्या पार्वती से विवाह किया। लेकिन उनकी जीभ साप की ही रही। वह मुह फेर कर अपनी पत्नी के साथ सोता था। उसकी सारी कोशिशें बेकार हो गईं। इस तरह उसकी पत्नी को शका उत्पन्न हुई और वह वार-वार पूछ-ताछ करने लगी। अपनी पत्नी के प्रश्नों को टालने के निमित्त और उसे भुलावा देने के लिये पुडरीक उसे जगन्नाथपुरी ले गया। लौटती वार दोनो छोटानागपुर के ही एक जंगल में टिके। वही पार्वती को प्रसव बेदना आरंभ हुई। और साथ ही उसने अपने पति से उसकी जीभ के बारे में पूछताछ करना शुरू कर दिया। पुडरीक अब अधिक देर तक अपने रहस्य को छिपा नहीं सका। उसने अपना असली रूप धारण किया और तालाब में धुस गया। पार्वती को पुत्र उत्पन्न हुआ। लेकिन पति के वियोग में वह वही सती हो गई। तब वच्चा अकेला रह गया। पुडरीक से वच्चे का कष्ट नहीं देखा गया। उसने निकल कर वच्चे के सिर पर अपने फन से छाया किया। इसी समय एक ब्राह्मण सूर्य पूजा के बाद तालाब में पानी पीने आया। उसने तालाब के किनारे सूर्य की मूर्ति रख दी और उठाना मूल गया। वह खड़ा होकर सोचने लगा। इसी समय उसकी नजर उस नवजात वच्चे पर पड़ी, जिसे एक नाग अपने फन से ढके हुए था। ब्राह्मण को देख कर पुडरीक ने मनुष्य रूप धारण किया और कहा कि यह वच्चा फणिमुकुट राय के नाम से राजा होगा, ब्राह्मण होगा इसका पुरोहित और सूर्य देवता। इतना कह कर पुडरीक पुनः तालाब में चला गया। वही वच्चा नागवशी राज्य का प्रथम सम्राट हुआ। उसकी राजधानी चूटिया थी जो वर्तमान राची से १०० मील की दूरी पर स्थित है।

चूटिया नागवशी राजाओं की राजधानी थी और पुर का अर्थ गाव होता है। अतः उस स्थान का नाम चूटिया नागपुर हो गया। आधुनिक शिक्षित समुदाय इस कहानी को स्वीकार करने से इन्कार करता है लेकिन नृतत्व शास्त्री प्राचीनतम दन्तकथाओं एवं किवदंतियों से भी अपने परिणाम निकालते हैं। मानव जाति की जिज्ञासा बहुत दूर-दूर तक अन्वेषण करती है, तौर-तरीके और सम्यता का पता लगाती है। वेद के पुण्य मंत्र अवतक २००० या ३००० वर्ष के बाद भी गुजरित है। पिटाई ने लिखा है कि आदिम काल से अवतक भारत भूमि पर बहुत से लोग बसते रहे हैं। इस प्रकार अनेक ऐसे प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि मनुष्य की प्राचीनतम प्रवृत्तियां आजतक भी चालू हैं और उन्हींका विकास होता गया है।

नागवशी राजाओं के सम्बन्ध में चाहे जितनी कल्पनाएं की जा सकें लेकिन आजतक इसका प्रतिवाद नहीं किया गया है। राची गजेटियर के लेखक एम० जी० हैलेट ने लिखा है कि यह दन्तकथा समस्त राची जिले में प्रचलित है। छोटानागपुर के राजा ने १७९४ में गवर्नर जनरल को जो कुर्सीनामा दिया था उसमें भी इसका उल्लेख है। आज भी वह वंश छोटानागपुर में किमी-न-किसी रूप में चल रहा है।

आदिवासियों की कहानी मानव जाति की कहानी है। पचतत्व का इतिहास भी कुछ इसी प्रकार का है। वैदिक युग के पहले की कल्पना करना तो अकल्प की भावना से अनुप्राणित होना है। फिर भी पुरातत्त्ववेत्ताओं एवं इतिहासकारों के मतों का हवाला देना बड़ा जरूरी होगा :

(१) मुंडा शब्द का प्रयोग वैदिक साहित्य में आता है। आदिवासी शब्द तो अधिक पुराना जान पड़ता है। अन्य प्राचीन कहानियों में मुंडो के आदि पुरुष श्रवक है। कोई-कोई श्रवकों को भील भी कहते हैं।

(२) वैदिक आर्यों ने पुरो की स्थापना की और निर्जन स्थानों में पुरो की स्थापना की। पहाड़ी इलाकों में रहनेवाले लोग मुख्यतया दास थे और वे सम्य थे। इन्हें आदिवासियों से कुछ और मान लेना अनावश्यक



होगा। रामायण और महाभारत में भी जगलो में रहनेवालो को कोल और भील कहा गया है। अधिकारी इतिहास लेखको का यह मत है कि समस्त ससार में प्राचीनकाल में केवल आदिवासी ही रहते थे।

(३) आदिकाल का मानव, चाहे वह जिस श्रेणी का रहा हो, तीन भागों में विभक्त था। काकेशियन, मगोलियन और इथियोपियन, ये क्रमशः यूरोप, एशिया और अफ्रीका में रहा करते थे।

(४) मुडा भाषा-भाषी लोग जगली इलाको में रहते थे। ये प्राचीनतम निवासी थे। अब भी पहाड़ों और जगलो के इलाको में इनकी पिछड़ी हुई जातियाँ रहती हैं जहाँ सम्यता का प्रकाश नहीं हुआ है। छोटानागपुर के सताल और सिंहभूमि के कोलो की भी गणना इसी श्रेणी में की जा सकती है।

आदिवासियों के जीवन-स्तर पर उपर्युक्त उदाहरणों से अच्छा और पर्याप्त प्रकाश पड़ता है। यह सदेहात्मक है कि सम्यता की आधुनिक परिभाषा के अनुसार वे अब भी सम्य हैं या नहीं। उस जमाने में उनकी स्थिति चाहे जैसी रही हो लेकिन आधुनिक लेखक तो उन्हें सम्य मानते हैं। होल्कर कालेज के प्रोफेसर पी० सी० वसु ने लिखा है

अनायों के किले थे, उनके समृद्ध नगर थे। ये धातुओं के उपयोग जानते थे। भौतिक स्तर पर भी वे उन्नत थे। इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिक युग के आदिवासी पर्याप्त प्रगतिशील थे और उनमें कई अन्य जातियों का मिश्रण हो चुका था।

अंग्रेज लेखक वेदों को तब तक महत्त्वपूर्ण नहीं मानते जबतक उसकी आवश्यकता प्रमाण देने के लिये बहुत जरूरी न हो। उनके लिए यह सम्भव नहीं था कि वेद मंत्रों के द्वारा आदिवासियों के जीवन पर कुछ प्रकाश डालें। ऐसा करने से ईसाई धर्म का प्रचार नहीं होता और न अंग्रेज वाइविल का प्रचार ही कर पाते। प्रसिद्ध इतिहास लेखक मैरियट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक "दी इंगलिश इन इंडिया" में लिखा है

भारत में कुल आबादी के दश प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके उद्भव के विशेष सूत्र अज्ञात हैं। इतिहास के अत्यन्त प्राचीनतम काल से ही इनका होना ज्ञात है और उन्हें आदिकाल से ही आदिवासी कहा गया है। ये अधिक सख्या में अदमान द्वीप, दक्षिणी मद्रास तथा हिमालय पर्वत के निचले हिस्से में बसे हुए हैं।

वे लोग सम्य थे, प्रगतिशील थे और अत्यन्त उन्नत थे। विदेशी इतिहास लेखक इसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं। उल्लेख न किये जाने पर भी इतना अवश्य ज्ञात हो जाता है कि ये लोग समृद्ध थे, जिसमें किसी प्रकार के मतभेद की गुंजाइश नहीं है। वैदिक सम्यता के प्रति यह अन्याय होगा अगर केवल विदेशी लेखकों के आधार पर आदिवासियों के बारे में किमी प्रकार का निर्णयात्मक फैसला दिया जाय।

मुडा और सतालो के पूर्व पुरुष सोन नदी पार कर छोटानागपुर के जगलो में आये थे। ये मुख्यतया हजारीवाग, पलामू, और राची जिलों में बस गये थे। सताल पहले दामोदर पार कर हजारीवाग में रहे और फिर मानभूमि और नताल परगने में बसे। मुडा छोटानागपुर की उपत्यका में ही रहने लगे। उराव रोहतास किले के पास से आये। रोहतास के पास ही गुग्गो का असली निवास स्थान था।

अबतक कोई ऐसा प्रमाण नहीं है जिससे मुडो और उरावो के छोटा नागपुर आने के ठीक काल का पता चल जाय। लेकिन इन दो जातियों के आने के पहले छोटानागपुर के क्षेत्र में अधिक सम्य जाति रहती थी। राची गजेटियर में स्पष्टतः लिखा है

सिगबोग के एक मुडा किंवदन्ती के अनुसार इस क्षेत्र में तथा जिले के कुछ क्षेत्रों में असुर रहते थे। जिले में तुमुली का विवरण है और तुमुली असुरों की कन्न को कहते हैं। इनमें पुरानी सम्यता के कुछ चिह्न प्राप्त होते हैं। मानभूमि, सिंहभूमि तथा राची जिलों के कुछ हिस्सों में प्रस्तर युग के कतिपय अवशेष पाये गये हैं। झरिया के कोयले के पास प्राचीनकालीन अस्त्रादि मिले हैं। ताम्रयुग के कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। मुडो के वर्तनों में भी तब से अबतक अत्यधिक पार्थक्य पाया जाता है। इन सब प्रमाणों से साबित होता है कि वर्तमान जातियों से पहले भी, यहाँ इस क्षेत्र में, एक ऐसी जाति रहती थी जो इनसे अधिक सम्य थी।

इस प्रमाण से तथा पुण्डरीक की किंवदन्ती से यह पता चलता है कि छोटानागपुर में सम्य लोग बसते थे। यह हो सकता है कि ये आदिवासी भी उन्हीं के समय में रहते थे। अब तक यही धारणा काम करती रही है। इस क्षेत्र में अधिक जंगल थे और जंगल में सम्य लोग नहीं रह सकते हैं। विकास की गति बराबर चालू रही और रद्वेदल होते रहे हैं। कालान्तर में साम्राज्य बदलते हैं। रहन-सहन और सम्यता बदलती रहती है। पहाड़, जंगल, ऊसर सबों में परिवर्तन हुए, पुरानी सम्यता लुप्त हो गई, नई सम्यता ने स्थान लिया। नालन्दा, एलोरा, साची, मोहनजोदड़ो, ये सब-के-सब इसी बात के प्रमाण हैं। इनसे यह पता चलता है कि हजारों वर्ष पहले किस प्रकार की सम्यता थी। इसका भी ज्ञान होता है कि बड़ी-बड़ी इमारतों किस प्रकार मिट्टी के नीचे चली गई। अभी जो लोग यहाँ रहते हैं उनके जीवन के क्रम के अध्ययन के अनन्तर यह बतलाना कठिन हो जाता है कि इनके पहले किस प्रकार के लोग रहते थे। उनकी पुरानी सम्यता काल की गति के साथ समय की शिला के नीचे दब गई।

१९११ की जनगणना रिपोर्ट में लिखा गया है जाति प्रथा के अध्ययन के पश्चात् पता चलता है कि आदिमकाल से उनमें अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। इन जातियों के पहले विशेष काम करनेवालो का वर्ग था और आगे चल कर इसीका विकास जाति के सगठन में हुआ। कई प्रकार के मिश्रणों से ऐसा हो गया है कि अब किसी उप जाति के सबध में असली या प्राचीन जानकारी प्राप्त करना कठिन काम हो गया है।

एक दूसरे नेतृत्वशास्त्री का मत है— ये आदिवासी मलायो-मोलिने-शियन वंश के हैं या नहीं, या द्रविडों का सबध आस्ट्रेलियनो या समो-येदो से है या नहीं, या आर्य डैन्यूब नदी के समतल से आये थे या साइबेरिया के बर्फीले मैदान से, सत्य चाहे जो भी हो लेकिन आज की आबादी एक अजीब प्रकार की खिचड़ी है।

हमलोग रिजले की पुस्तक का थोड़ा उद्धरण लें। इस पूरे देश के आदिवासियों की तेजी से जाति बनती जा रही है। इसका क्रम विविध स्थानों में विभिन्न तरीके का होता है। रक्त के परिवर्तन से पुराना नाम एकदम बदल जाता है। इस जाति की स्थिति शुद्ध रक्तवालो हिन्दुओं से

सर्वथा भिन्न होती है और ऐसा जान पड़ता है कि इसका उद्भव द्रविड या मगोल जाति से हुआ है। अब आदिवासी इस प्रकार मिल गये हैं कि उच्च वर्ग के हिन्दुओं से इनका कम वैभिन्य रह गया है। रिजले ने नागवशी राजाओं का उल्लेख किया है और इस लेख में भी पहले उन्हींका जिक्र किया गया है।

हिन्दू समाज में आदिवासियों का प्रवेश हो चुका है। आदिवासियों के मुखिये पहले क्षत्रियो या राजपूतो में मिला लिये गये। आदिवासियों में जिनकी जमीनें अधिक थी उन्हें भी हिन्दू मान लिया गया।

ऊपर जो भी कहा गया है उससे पता चलता है कि छोटानागपुर केवल आदिवासियों का ही क्षेत्र नहीं था। आदिवासी थे इस इलाके में, परन्तु इनके अलावा दूसरे लोग भी रहते थे। झारखंड प्रत्येक अर्थ में और प्रत्येक दृष्टि से एक गलत शब्द है। इस शब्द का कोई राजनीतिक महत्त्व नहीं है। साड का अर्थ होता है जगल और खड से एक खास भू-भाग का बोध होता है। इस संस्कृत शब्द का अर्थ होता है वह भूखंड जिसमें अधिक जगल हो। केवल छोटानागपुर ही नहीं, बल्कि समस्त भारतवर्ष या सम्पूर्ण ससार ही एक समय जगल रहा होगा। वैदिक युग में भी इस शब्द का प्रचलन अवश्य रहा होगा। अतः यह शब्द अपने अर्थों में लोगों को तोप देने के लिये पर्याप्त है। जब तक लोग इसका सही अर्थ नहीं समझ लेंगे तब तक एक ऐसी स्थिति रहेगी जिसे सर्वथा स्वस्थ नहीं कहा जा सकता और इसे गलत अर्थ में व्यवहृत किया जाता रहेगा। यह गलत धारणा जब खत्म हो जायगी तब आन्दोलन भी समाप्त हो जायगा। इस लेख का यह आशय नहीं है कि क्यो एक वारगी एक युग के सम्य एव प्रगतिशील आदिवासी एकदम पिछड गये। पिछडी हुई स्थिति अब ऐसी हो गई है जिसमे सरकार या अन्य कोई उन्हें आसानी से ऊपर नहीं उठा सकती है।

वर्तमानकालीन छोटानागपुर की स्थिति में पूर्ण परिचित होने के लिए इतिहास पर सरसरी निगाह रखना आवश्यक हो जायगा। विहार और उड़ीसा के बीच की जंगली भूमि पर पहले-पहल मुगल वादशाह अकबर की नजर गई। उसने १५८५ में छोटानागपुर पर चढाई करने का इन्तजाम कर दिया। उस कारण छोटानागपुर के राजा की स्थिति विलकुल विपरीत हो गई। पुन १६१६ में जहागीर के सिपाहमालार इब्राहिम खा ने राजा को कैद कर ग्वालियर के किले में भेज दिया। १६३२ में शाहजहा के पलामू की जागीर में छोटानागपुर को मिला लिया और उसे पटना के सूबेदार के जिम्मे दे दिया। १६६९ में कुडा के सरदार को मुगलो ने सनद लेने को बाध्य किया ताकि मराठो को प्रगति रोकनी जा सके। १७२४ में पटना के सूबेदार ने छोटानागपुर के राजा से नजराने में बडी रकम ली। १७४४ में भी इसी तरह से पुन नजराना वसूल किया गया। लेकिन इस बार रामगढ राजा ने अपने दक्षिण के पडोसी के वरले १२००० रुपया दिया। इसी तरह कई बार धन दिय गये। कभी नकद, कभी सोना और हीरा। सुदर्णरेखा का नाम इसी कारण पडा है चूकि उसकी वालुकाराशि में पर्याप्त सोना प्राप्त था। पटोलमी ने लिखा है कि छोटानागपुर में हीरा भी पाया जाता था। मुसलमानी राजत्वकाल के कागजात में भी हीरे का उल्लेख आता है। चूकि यहा लाखो के हीरे पाये जाते थे अतः जहागीर ने इमे अपने कब्जे में लाना चाहा।

मुसलमान वादशाह राजाओं की राज्य-व्यवस्था में दखल नहीं देते थे। अतः राजाओं का जनता पर पूरा अधिकार रहता था। राजा अपनी प्रजा से सख्ती से पेश आता था और उनसे अधिक कर वसूल भी करता था। इसी कारण आम जनता एकवारगी असन्तुष्ट रहती थी।

१७६५ में शाह आलम ने वगाल, विहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कम्पनी को दे दी। रामगढ को, इसी कारण ईस्ट इंडिया कम्पनी को भी नजराना देना पडा। राजा पहले तो कम्पनी के प्रभुत्व को स्वीकार करना नहीं चाहते थे इसी कारण जनता में असतोष फैलाकर उन्हें उभाडते थे। अन्त में इनकी पराजय हो गई और छोटानागपुर का शासन रेगुलेंटिंग ऐक्ट के मुताबिक होने लगा। इसके बाद ही छोटानागपुर में अंग्रेजो के हस्तक्षेप बढ गये। अंग्रेज धीरे-धीरे वहा कानून बनाने लगे। पहले १८६९ में छोटानागपुर टेन्योर ऐक्ट बना। फिर १८७९ में छोटानागपुर लैडलार्ड ऐण्ड टेनेन्टम प्रोप्रीटोर ऐक्ट के अनन्तर न जाने कितने कानून बनाये गये। कम्प्यूटेशन आंव रेंट्स ऐक्ट (१८९७) और छोटानागपुर टेनेन्सी ऐक्ट (१९०८) के बावजूद वठ-बेगारी के प्रश्न पर किसानों में बराबर असन्तोष बना रहा। यह स्थिति, आज भी जमीन्दारों के अत्याचार के कारण ज्यो-की-न्यो बनी है चाहे वह किसी रूप में हो। कांग्रेसी सरकार ने, जो किसानों के कल्याण करने के लिए शपथबद्ध थी, जमीन्दारी उन्मूलन कानून स्वीकृत किया। विहार ने ही सर्व प्रथम भूमि सुधार कानून बनाना शुरू किया। अन्य सभी राज्यों में इसी प्रकार के कानून यथासाध्य बनाये जा रहे हैं।

ब्रिटिश राज्य का सर्वाधिक प्रभाव ईसाई मिशनरियों के आगमन के कारण हुआ। यह सभी स्वीकार करते हैं कि अगर छोटानागपुर के राजा लोग जनता पर अधिक अत्याचार नहीं करते तब ईसाई धर्म का अधिक प्रचार नहीं होता। राजाओं के जुल्म से रैयत मिशनरियों की शरण में जाने लगे। स्कूल, अस्पताल और कालेज आदि खोल मिशनरियों ने पीडित जनता की अधिक सेवा की। सिपाही विद्रोह यानी प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम के समय मिशनरियों को अधिक क्षति उठानी पडी लेकिन वे बच गये। उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य से स्वराज्य आ जाने के अनन्तर तक इन ईसाई मिशनरियों का काम अत्यन्त लाभदायक, कल्याणकर एव समृद्धि के मार्ग में हुआ है। स्वतंत्रता के बाद इन मिशनरियों का कार्य किम दिशा में चल रहा है, इसके निरीक्षण का दायित्व उन लोगों पर है जो शासन के सर्वोच्च शिखर पर हैं। एक बात निस्सकोच और बिना किसी डर के कहा जा सकता है। इन मिशनरियों के कार्यकलाप विगत चुनावों के समय पूर्णतया उन्हीं के मिशन के लिए अनुमानजनक थे।

युगो से छोटानागपुर के हीरे ही आकर्षण के केन्द्र रहे हैं। इसी कारण कई बार विदेशियों के हमले हुए। अब उनके लिए रास्ता बन्द हो गया है। मदियों गुजर गये और अब काला हीरा प्राप्त किया गया है। कच्चा लोहा, ताम्बा, अवबरख तथा अन्य प्रकार के खनिज प्राप्त किये गये। सिंहभूमि, मानभूमि और हजारीबाग के जिलों में चिमनियों से घुए निकलने लगे। बडे-बडे औद्योगिक शहर बस गये, जहा प्राधुनिकतम जीवन की सारी सुविधाएँ प्राप्य हैं। तिलैया का बाघ, बेकारो का थर्मल प्लैंट, जमशेदपुर का कारखाना, सिन्दरी खाद का कारखाना, भुरकुडा ग्लाम फैक्टरी

आदि छोटानागपुर के गौरव के चिह्न हैं। प्राचीनकालीन हीरो की तुलना में आजकल की खानों से निकलनेवाले खनिज पदार्थों के कारण यहाँ की समृद्धि में चार चाद लग गया है। इनके अलावा वन सम्पदा की राशि भी अपार है और उनका विकास क्रमानुसार हो रहा है। छोटानागपुर के प्रत्येक निवासी को इसका गर्व हो सकता है कि आज यह भूखंड भारत के औद्योगिक नक्शों में प्रमुख स्थान रखता है। यहाँ के उद्योगों में बहुत से लोगों को रोजी मिलती है। इस कारण यहाँ का जीवन स्तर विलकुल परिवर्तित हो गया है। ससार के सभी लोगों को बिना किसी प्रभेद के इस क्षेत्र में प्रोत्साहन एवं सहयोग मिलता है। लेकिन सर्वाधिक आश्चर्य का विषय है कि औद्योगिक सम्यता आदि के बावजूद अब भी लोग आदिवासियों का शोषण करते हैं। इस शोषण करनेवालों की सख्या में बड़े जमीन्दार भी हैं, उद्योगपति भी और सूदखोर भी हैं। शहरों से दूर, आधुनिक सम्यता से बहुत दूर, गावों में रहनेवाले अनपढ़ यह भी नहीं जानते थे कि आजादी के बाद भारत की क्या स्थिति हो गई है।

लार्ड कार्नवालिस के स्थायी बन्दोबस्त के अनन्तर छोटानागपुर के राजा और जमीन्दार किसी से भी भय नहीं खाते थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में संचालित स्वातंत्र्य आन्दोलन के जमाने में इन जमीन्दारों ने अंग्रेजों का ही साथ दिया था। १८५७ में ही इन लोगों ने एक बार ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने की अपरिपक्व चेष्टा की थी। इस विपरीतता का अव्ययन बड़ा दिलचस्प है कि उन्होंने सिपाही विद्रोह में तो प्रयास किया कि अंग्रेजों की सलतनत समूल उखड़ जाय, लेकिन जब गांधीजी का अहिंसात्मक संग्राम आरम्भ हुआ तब वे अंग्रेजों के मित्र और सहायक हो गये और इन बातों की चेष्टा की कि आन्दोलन को कुचल डाला जाय। इतिहास इस बात का साक्षी है कि किस प्रकार इस देश से ब्रिटिश शासन का अन्त हुआ। कांग्रेस ने केवल देश को ब्रिटिश शिकंजे से मुक्त करना चाहती थी प्रत्युत इसका उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता लाना भी था। कांग्रेस शासन ने सही तौर पर सबके विकास का कार्यक्रम अपनाया। बिहार भी इस कार्य में पिछड़ा नहीं रहा और बिहार के सरी डाक्टर श्रीकृष्ण सिंह के नेतृत्व में यहाँ भी विकास कार्य का अभियान आरम्भ हुआ। छोटानागपुर का हीरा कृष्णवल्लभ भी इसी समय चमकने लगा। इसके बाद छोटानागपुर के विकास की कहानी कृष्णवल्लभ की कहानी है।

कृष्णवल्लभ छोटानागपुर के गावों से भी परिचित हैं और शहरों से भी। ये गाव-गाव पैदल घूमें और वहाँ तक जागरण का नाद सुनाया जहाँ तक कोई न जा सका था। इन गावों में जीवन के निकटतम सघर्ष करनेवाले आदिवासी रहते थे जिन्हें प्रगति का कोई संदेश भी मालूम नहीं था। कृष्णवल्लभ उनकी खोहों तक गये, उनकी शोषणियों तक पहुँचे। आदिवासियों की दशा देखकर इनके मस्तिष्क पर उसका बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। आदिवासियों की कठिनाइयाँ केवल जीवन-यापन तक ही नहीं थी प्रत्युत राजकर देने का ऐसा बोझ उनके अशक्त कंधों पर था

जिसे वे सह नहीं सकते थे। जमीन्दारों की माँगों भी अधिक बढ़ी थी। अगर आदिवासी थोड़ी सी जमीन साफ कर उसे खेती के लायक बनाते तब जमीन्दार की तेज नजर फौरन उस पर पड़ जाती और उसके लिये भी अतिरिक्त कर वसूला जाता था। बड़ी सलामी न देने पर उसे बंदखल कर दिया जाता था। उस जमीन को दूसरे रैयत के साथ बन्दोबस्त कर दिया जाता था।

इन्हीं लोगों के कल्याण के लिए, चूँकि ये ही गरीब आदिवासी जनसंख्या की मोटी रीढ़ थे, कृष्णवल्लभ ने भूमि सुधार कानून को स्वरूप दिया। बहुत विरोधों के बावजूद इन्हें सफलता मिली और अब यह कानून छोटानागपुर में लागू है और बिहार के अन्य भागों में भी। इस भूमि सुधार से भूमि सम्बन्धी पुरानी व्यवस्था समाप्त हो गई। छोटे-बड़े समस्त जमीन्दारों में इसके लिए एक प्रकार का जागरण हुआ लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक ने इसकी जरूरत समझ कर इसे न्यायिक मान्यता एवं समर्थन प्रदान किया। पुराने खडहरो की रीढ़ पर नये समाज का जन्म हो रहा है। भूमि सुधार तथा अन्य प्रकार के सुधारों से जनता के जीवन में एक प्रकार की आशा दिखलाई पड़ रही है। सर्वत्र अनाजों के गोले खोले गये हैं ताकि गरीब किसानों की मुनाफाखोरी से रक्षा हो सके। तमाम छोटानागपुर में अब स्कूल खोले जा चुके हैं। आदिम जाति सेवा मंडल और सताल पहाड़िया सेवा मंडल, इन दो गैर सरकारी संस्थाओं की देखरेख में बहुत से ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जिनके द्वारा शैक्षणिक कार्य एवं सामाजिक कार्य बहुत बड़े पैमाने पर होगा। सरकार आदिवासियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को स्वतंत्र देश के आत्म सम्मान एवं गौरवपूर्ण नागरिक बनाने की चेष्टा कर रही है। अन्य कई प्रगतिशील योजनाएँ तैयार हैं जिनके द्वारा भी इस क्षेत्र की जनता का कल्याण संभव हो सकता है। भारत सरकार व बिहार सरकार से और अनेकानेक सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग के प्रयत्नों से जितने काम हुए हैं वे सब कल्याणकर हैं। इन कार्यों के फलस्वरूप छोटानागपुर का नेतृत्व कृष्णवल्लभ सहाय के हाथों में आ गया है।

फिर, पूर्ण सफलता के रास्ते में कई प्रकार की अड़चनें हैं। कई ऐसे प्रभावशाली प्रतिगामी व्यक्ति हैं, ऐसी संस्थाएँ हैं जिनसे अकल्याण होने का भय है। अतएव इन पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। छोटानागपुर जैसे क्षेत्रों में तो विशेष एहतियात से कार्य सम्बद्ध रखने के लिए अधिकाधिक लोगों का शीघ्र कल्याण किया जाना चाहिये। साधारण लोगों को यह देखकर आश्चर्य होता है कि इतने कम समय में इतनी प्रगति कैसे संभव हो सकी है। छोटानागपुर तो नागों के युग से आज तक आश्चर्य मूलक किंवदन्ती ही रहा है। और यह भी कौन जानता था कि आखिरी नाग को नायक उसके फन पर नर्तन करने का सौभाग्य कृष्णवल्लभ को ही प्राप्त होगा! इनके साथ कांग्रेस और जनता का उल्लासपूर्ण नृत्य भी सम्मिलित है।



# भारत में भूमि समस्या के समाधान की योजना

डा० श्रीमती सीता परमानन्द

वर्तमान सप्ताह में भूमि समस्या का अर्थ केवल शाब्दिक ही नहीं रह गया है बल्कि इस शब्द का व्यवहार अब अधिक व्यापक हो गया है। भूमि समस्या और भूमि सुधार का प्रयोग एशिया के नेताओं और विद्वानों ने बहुतायत से किया है। चीन के किसानों के आन्दोलन के फलस्वरूप इस समस्या की ओर लोग अधिक आकर्षित हुए हैं और इसकी महत्ता भी अधिक समझी गई है। भूमि समस्या स्वतः प्रश्न है और भूमि-सुधार उसका समाधान।

सीधी-सादी भाषा में इसका अर्थ यही है कि बढ़ती हुई आबादी के लिए खाने का प्रबन्ध किया जाय और उतनी ही भूमि में जितने में खेती होती चली आई है। इसलिए अधिक उत्पादन का प्रश्न प्रमुख है। इसके लिए भूमि चाहिये, कृषि की वैज्ञानिक प्रणाली चाहिये, सुधरे हुए और पुष्ट बीज चाहिये, सिंचाई की व्यवस्था, पर्याप्त खाद और सहकारिता के आधार पर खेती चाहिए। अतः भूमि के पुनर्वितरण के लिए उसकी मिल्कियत तथा किसानों को कितनी भूमि मिले आदि का प्रश्न आ जायगा। भूमि वितरण, सुविधाओं का इन्तजाम, वैज्ञानिक प्रणाली से खेती आदि सभी प्रश्न एक दूसरे से सलगन हैं। इन तमाम सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए ऐसे उपाय काम में लाने होंगे जिससे आशान्ति न फले। यह स्मरण रखना चाहिये कि प्रचलित उत्पीड़नों के कारण और सहिष्णुता की हद की वजह से समाज जाग्रत हो गया है। इस जागृति का मुख्य कारण है राजनीतिक चेतना का प्रसार। यह विषय इतना विशाल है कि एक लेख में उसका समाधान नहीं प्रस्तुत किया जा सकता।

भूमि समस्या उसी तरह विराट और वृहत् है जिस प्रकार यहाँ की आबादी। १९५१ की जनगणना के अनुसार हमारे देश के लगभग पच्चीस करोड़ आदिमियों का गुजर खेती द्वारा होता था। जो लोग खेती करते हैं उनकी चार श्रेणियाँ हैं (१) १६७४ करोड़ आदिमी जमीन के मालिक हैं (२) ३१७ करोड़ ऐसे किसान हैं जो भूमि की बन्दोबस्ती लेकर खेती करते हैं (३) ०५३ करोड़ लोग कर प्राप्त करके अपनी जिन्दगी व्यतीत करते हैं (४) भूमिहीन कृषि मजदूरों की संख्या ४४८ करोड़ है। इस हिसाब से पहली और चौथी श्रेणी की कृषा एव अनुग्रह पर करीब साढ़े सात करोड़ लोगों का वसर होता है। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के लोग अपनी

जमीन से अधिकाधिक उत्पादन नहीं कर सकते और इन्हीं लोगों के कारण भूमि की समस्या बहुत क्लिष्ट हो गई है।

अतः यह आवश्यक है कि देश में प्रचलित भूमि क्षुधा को तृप्त किया जाय। समाधान चाहे तो अहिंसक तरीके से हो सकता है, जैसा विनोबा भावे का विश्वास है, या जबरदस्ती कानून बनाकर। जितनी देर की जायगी समस्या उतनी ही सश्लिष्ट होती जायगी, असतोप उतना ही बढ़ता जायगा। तँलगाना की विकट स्थिति को उदाहरण एव चुनौती दोनों प्रकार से समझा जा सकता है। तँलगाना की यात्रा के बाद ही विनोबा भावे ने भूदान यज्ञ का समारम्भ किया था। अहिंसा में पूर्ण विश्वास होने के कारण यज्ञ के लिए अनुभूति और प्रेरणा उन्हें मिली। यज्ञ शब्द के कारण प्रामीणों पर इसका अधिक असर पड़ा है। पहले वर्षा होने के लिए यज्ञ किया जाता था। अन्य और कई प्रकार के यज्ञ थे जिनसे प्राचीन काल से परिचित होने के कारण कोई कठिनाई नहीं हुई। भूदान यज्ञ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि जिनके पास थोड़ी जमीन है वे अधिक भूमि दान कर रहे हैं। भारत ने अहिंसात्मक मार्ग अख्तियार करके स्वतंत्रता प्राप्त की है। इस कारण दुनिया के समस्त एक नया विश्वास एव आस्था का प्रकाश पड़ा है। यह आशा की जाती है कि राष्ट्रपिता द्वारा प्रदत्त अहिंसा से ही भूमि समस्या का समाधान हो जायगा।

तँलगाना की घटनाओं और अतीतिकर स्थिति के लिए केवल कम्यूनिस्टों को दोष दिया जा सकता है। लेकिन इस देश की तमाम राजनीतिक पार्टियाँ भूमि समस्या पर अपना अलग दृष्टिकोण रखती हैं। समाधान के लिए उनके पास अलग-अलग मूत्र हैं। समाजवादियों ने भूमि के लिए पार्टी सत्याग्रह किया था। सोशलिस्टों और कम्यूनिस्टों के दृष्टिकोण में अन्तर है। किन्तु, ठीक इसके विपरीत अभी कांग्रेस शासन सम्हाल रही है, अतः इसे भूमि समस्या का समाधान करना चाहिये। पंचवर्षीय योजनाओं में बड़ी-बड़ी सिंचाई योजनाओं के कार्यकारी होने से ही किसानों में जमीन की भूख नहीं शान्त होने को है। इन तमाम कार्यों से किसानों को प्रेरणा नहीं प्राप्त होती है। भूदान-यज्ञ ने भूमि समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। दूसरा कदम है कानून बना देना, जिस कारण किसानों की क्षुधा मिट सके। यह भी हमलोगों को स्मरण रखना चाहिये कि गत चुनावों

के कारण जनता अपने अधिकारों के लिए सतर्क हो गई है। राज्य का उनके प्रति यह कर्तव्य हो जाता है कि दिये गये आश्वासनों को कार्य रूप में परिणत किया जाय। अब यह समय आ गया है जब कांग्रेस अपने आदर्शों की पूर्ति कर सकती है। आजादी के बाद यह उम्मीद की गई थी कि राम राज्य स्थापित हो जायगा। लेकिन अब भी किसानों के बीच निराशा की लहरे व्याप्त हैं। यदि ऐसी ही स्थिति रही तब बड़े पैमाने पर अशान्ति फैल जायगी।

भूमि की समस्या, जन सख्या एवं खाद्योत्पादन के कारण ही, आर्थिक समस्या नहीं है। यहाँ १९४७ में प्रति वर्गमील २५५ आदमी बसते थे और वेल्लियम के १९४४ तक ७६८ व्यक्ति प्रतिवर्ग मील थे। १९४० में जापान में २५० व्यक्ति प्रति वर्गमील तथा जर्मनी में १९४७ में प्रति वर्गमील ३८२ आदमी थे। कृषि योग्य भूमि का रकबा चीन से भी भारत में कम है लेकिन ठीक उसके विपरीत चीन में भूमि समस्या का समाधान जल्दी हो गया। इसका कारण यह था कि चीन का किसान अत्यन्त उत्पीड़ित एवं त्रसित था। राजनीतिक आन्दोलकों ने इसका अत्यधिक फायदा उठाया और इससे सूदखोर तथा बड़े-बड़े जमीन्दार शीघ्र खत्म हो गये। एक बार जब बड़े भूपतियों से भूमि छीन ली गई तब उसका वितरण भूमिहीनों में कर दिया गया। किसानों में अधिकार पा लेने पर दायित्व आ पडा और जब कृषि अत्यन्त अविकसित अवस्था में थी, तभी वहाँ कठोर परिश्रम से अधिक अन्न उत्पादन किया जाने लगा। उनका जीवन स्तर भी उन्नत हो गया। असमानता जो एकदम चरम अवस्था पर पहुँच गई थी, उसके खात्मे के बाद विश्वास उत्पन्न हो गया। चीन का जन साधारण उत्पादन की ओर पिल पडा। अवस्था बदल तो गई, लेकिन इसके वास्ते बहुत बड़ी कीमत चुकानी पडी। भारत को उससे शिक्षा लेनी चाहिये।

सम्यता के आरम्भ काल से ही कृषि की जाती रही है। इसीलिए भूमि को मातृभूमि और पितृभूमि कहा गया है। इससे लोगों की उन्नत सुभावनाएँ ही प्रकट होती हैं। प्राचीन काल में आदिम मानव भूमि की खोज में जहाँ-तहाँ भटकता फिरता था ताकि उसे भोजन की व्यवस्था के लिए उपजाऊ भूमि मिले। आर्य भी सम्भवतः उपजाऊ भूमि की ही खोज में आये होंगे। फिर जितने भी आक्रमण हुए वह भूमि के ही लिए हुए होंगे। साम्राज्य भी इसी बुनियाद पर बने और ध्वस्त हुए। जब जनसख्या उत्तरोत्तर बढ़ती गई तब इच्छानुसार सब जगह बस जाना दुर्लभ हो गया।

समस्त ससार में आवादी की वृद्धि, विशेषकर भारत में वर्तमानकालीन भूमि समस्या की जड़ है। सघन आवादीवाले देशों में बसना और जमीन पाना स्वयं एक असमाधेय प्रश्न बन जाता है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे स्वतंत्र देशों ने इस समस्या का समाधान औद्योगीकरण द्वारा तथा उपनिवेश बढ़ा कर किया। आखिर औद्योगीकरण की भी एक सीमा होती है। इसके लिए बड़े-बड़े बाजारों की जरूरत पड़ती है। जब जर्मनी का सब बाजार बन्द हो गया तब उसे अकारण बूढ़ कर युद्ध की घोषणा कर देनी पडी। युद्ध, त्रास के योग्य भूमि के कारण ही होते हैं और हुए हैं, और जब औद्योगीकरण एवं उपनिवेशवाद दोनों ठप्प पड़ जाते हैं तब आदमी का दिनाग ही एकमात्र रास्ता रह जाता है। टामस मात्थन ने १७०८ में ही जनसख्या के

नियंत्रण के प्रश्न की ओर ससार का ध्यान आकर्षित किया था। उसने इस सबध में ससार के लोगों को चेतावनी दी थी।

जन-कल्याण, भूमि एवं उत्पादन के अनुपात पर निर्भर रहता है। जब अंग्रेज आये तब इस देश की आवादी कितनी थी यह ठहना अत्यन्त कठिन है। विगत जनगणना के मुताबिक भारत की आवादी ३९०,०००,००० है यानी प्रत्येक दशक में आवादी में पन्द्रह प्रतिशत की वृद्धि हुई है और अगर यही गति रही तब आगामी पचास वर्षों में जन-सख्या दुगुनी हो जायगी। अंग्रेजों के जमाने में आवादी की यह वृद्धि उत्साहवर्द्धक कतई नहीं है, हालांकि गृह युद्ध नहीं हुए और शान्ति बराबर बनी रही। रहन-सहन की सुविधाओं के फलस्वरूप लोगों की आयु बढ़ी और साथ ही प्रजनन भी बढ़ा। आयु के परिमाण में वृद्धि के कारण लम्बी प्रवधि तक जीवित जन-सख्या को खिलाने का भार राष्ट्र पर पड़ गया। यही अन्न कण्टो की जड़ है। मूलभूत प्रश्न है कि आधा पेट खाकर, अस्वस्थ रह कर अधिक दिन जीवित रहना वृण है, मजे में आराम से खा-पीकर कम दिन जीना श्रेयस्कर है। आज सत्तर प्रतिशत लोगों को स्वास्थ्यवर्द्धक एवं सुसुचि-पूर्ण भोजन नहीं मिलता। अतः सरकार को इस समस्या की ओर शीघ्र ध्यान देकर इसका हल ढूँढना चाहिए।

ऐसी स्थिति में ऐसे भी लोग हैं जो यह समझते हैं कि भारत का उत्पादन दुगुनी आवादी का पोषण कर सकता है यानी ऐसे लोगों की सम्मति में आवादी की समस्या दुरुह नहीं है। इस श्रेणी की मान्यता है कि आधुनिक वैज्ञानिक साधनों के जरिये यहाँ उत्पादन बढ़ सकता है और उद्योगों का भरपूर विकास भी हो सकता है। अबतक विकास नहीं हुआ चूँकि उसका निचोड़ सही और दुरुस्त नहीं हो सका। अतः प्राकृतिक प्रसाधनों के पूर्ण उपयोग के पश्चात् दुगुनी आवादी का पालन-पोषण मजे में हो सकता सम्भव है। लेकिन मेरी राय में यह धारणा बिल्कुल गलत है। यदि इसे मान लिया जाय कि देश की आवादी मान्य स्तर पर जीवन-यापन कर रही है तब यह परले सिरे की भ्रान्ति होगी। हमारा जीवन स्तर ससार के सब देशों की अपेक्षा निम्नतम है। जहाँ के लोग शाकाहारी होते हैं वहाँ दूध, घी, माखन, आदि प्रचुर मात्रा में मिलना चाहिए। हमारे देश में कितने लोगों को यह प्राप्त होता है? शुद्ध दूध का भी यहाँ एकदम अभाव है। आवादी की वृद्धि के पहले इन शर्तों को पूर्ण कर लेने की नितान्त आवश्यकता है।

ससार की जनसख्या इतनी बढ़ गई है कि प्रतिदिन ७५००० नये व्यक्तियों का उद्भव होता है। ससार के ग्राम लोगों में यह धारणा घर कर गई है कि भगवान प्रत्येक प्राणी को जन्म देकर भोजन और वस्त्र का प्रबन्ध कर देता है, यह कथन हमें सतोष दे सकता है लेकिन वास्तव में इससे जीवन की आवश्यकताएँ नहीं पूर्ण हो सकती हैं। वैज्ञानिक पद्धति से भी बहुत कुछ सहायता ली जा सकती है। हम एक बार ही विज्ञान की न तो सराहना कर सकते हैं और न उसकी निन्दा ही कर सकते हैं।

उदार धरित्री, चाहने पर सब कुछ दे सकती है, इस सुन्दर एवं सुकुमार कल्पना को मदा के लिए त्याग देना ही उचित जान पड़ता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत प्रकृति के सहार के भी नियम हैं। यह इस विश्वास की दूसरी आकृति है। मनुष्य तो वैज्ञानिक विकास द्वारा प्रकृति

कें प्रकोपो से अपनी रक्षा कर सकता है पर जानवर, यानी, मनुष्य ने बहुत हद तक प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा की है। अगर इसान जन्म के वृद्धिगत क्रम को भी रोक दे या सतुलित या नियंत्रित कर दे तब वह प्रकृति को अपना अनुगत बना सकता है। अतः जन्म नियंत्रण, जैसा कि पुरातनपथी अपनी धारणा बना चुके हैं, न तो अर्वाचनिक है और न नृशस और न अमानवीय ही।

जमीन की उर्वरा शक्ति दिनोदिन कम होती जा रही है चूँकि इसान उसका अत्यधिक उपयोग करता है या बहुत लापरवाही बरतता है। वर्षा से और बाढों से जमीन की ऊपरी सतह धुल जाती है और इसी सतह पर उर्वरा शक्ति रहती है। यह भी निर्णीत हो चुका है कि प्रायः तीन सौ या एक हजार वर्ष में मिट्टी पर उपजाऊ पतल पड़ती है। लेकिन इसकी तुलना में क्षय बहुत शीघ्र ही हो जाता है। जगलो या घनी वनस्पति के अभाव के फलस्वरूप और अधिक जुताई के कारण भी पृथिवी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। इन सब कारणों से उत्पादन कम हो जाता है। उत्पादन के पैमाने व अनुपात पर भी अगर भूमि-समस्या का समाधान किया जाय तब भी एक पहलू पर सुविचार और सुनिश्चित मत प्राप्त हो सकता है। किसी भी तरह विलकुल कम समय में समाधान मभव नहीं है।

द्वितीय विश्व युद्ध के पहले तक भारत में खाद्यान्न की कमी नहीं अनुभूत की जाती थी। अगर कहीं कमी हो भी जाती थी तब बाहर से उसका आयात कर लिया जाता था। पर भारत के ग्रामीण इलाकों में भूमि की क्षुधा बनी रही जिसे शायद किसी ने नहीं सुना। कंट्रोल एव युद्ध के अन्य परिणामों के फलस्वरूप यह प्रश्न अत्यन्त उग्र रूप से सम्मुखीन हो गया। रेडियो के द्वारा बड़े-बड़े उद्योगपति अनाज के भाव शीघ्र जान लेते हैं और उसीके मुताबिक वे दाम बढ़ा या घटा देते हैं। भारत के बाहर भी युद्ध के कारण खाद्य सकट उपस्थित हो गया। चीन, वर्मा, इंडोनेशिया और मलाया के गृहयुद्धों का व्यापक प्रभाव भी खाद्य समस्या पर पड़ा चूँकि इन देशों के लोगों को भी खाद्योत्पादन पर कम ध्यान देने को बाध्य हो जाना पड़ा।

विभाजन के कारण भी हमारे देश की खाद्य स्थिति पर प्रभाव पड़ा। बहुत बड़ी सख्या में शरणार्थियों को खिलाने की व्यवस्था करनी पड़ी है। एक और कारण भी है और वह यह कि युद्धकालीन स्थिति में गावों की बहुत बड़ी आवादी शहरों में चली आई। युद्धकालीन अवस्था में औद्योगिक जिन्यों के मूल्य बढ़ गये, मजदूरी बढ़ गई और इस कारण वे लोग अधिक महंगे दामों पर भी खाद्यान्न खरीदने पर विवश हो गये और मनमाने दाम देकर उसे उपलब्ध किया। युद्ध के पहले देहातो में वे लोग किसी प्रकार कुछ भी खाकर गुजर-बसर करते थे। कोई शिकायत किसान की तरफ से सुनी नहीं जाती थी। लेख और वक्तृताएँ गावों तक पहुँचने में एकदम असमर्थ थीं। जबतक अधिक सख्या में लोग मर नहीं जाते थे तबतक अकाल की घोषणा नहीं की जाती थी। अस्सी प्रतिशत तक की आवादी को केवल एक बार भोजन चौबीस घंटों में मिल सकता था। आज सौभाग्य से यह स्थिति नहीं है, फिर भी जनसख्या की वृद्धि के कारण पुनः खराब हो गई है।

खाद्यान्न के कंट्रोल होने के अनन्तर ही लोगों को कमी का पूर्ण आभास मिला और समाज खाद्य के मामले में चैतन्य हो गया। सरकार को भी जब नियंत्रित तौर पर अन्न देना पड़ा तब उसके समझ भी इसकी गरिमा तथा आवश्यकता स्पष्ट हो गई। इसके पहले सरकार को भी इसकी महत्ता का आभास नहीं था। बगाल के बड़े मर्यान्तिक अकाल से रही-सही अज्ञानता भी समाप्त हो गई। उस अकाल में पचास लाख से भी अधिक लोग अन्न के बिना तड़प-तड़प कर मर गये।

खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भरता की आवश्यकता है और यह जितनी जल्दी हो सके उतना ही लाभजनक होगा। विदेशों से खाद्यान्न मगाने के लिए १०० करोड़ रुपये की जरूरत पड़ती है, यानी देश के बजट का एक चौथाई इसी मद में व्यय हो जाता है। इस रकम की बचत की जानी चाहिए ताकि मशीनरी की खरीद की जा सके तथा देश की स्थिति में अन्य तरीकों से सुधार लाया जा सके। देश की आमदनी कम है इसलिए विदेशों से कर्ज लेना पड़ता है। विकास कार्य को सम्पादित करने के लिए अभी कमी-कमी तो मदद भी लेनी पड़ रही है, जिसे एक प्रकार का दान ही कहा जाना चाहिये। विदेशी सहायता लेना मामूली अर्थों तक तो ठीक कहा जा सकता है। यह भी इसलिए, चूँकि हमारे साधन अल्प हैं और इतने कम साधनों से हम अपना काम नहीं चला सकते हैं। विभाजन के कारण भी हमारे साधन घट गये थे। पर विदेशों की सहायता अपने देश के विकास के लिए भी, बहुत लम्बी अवधि तक लेना तो सर्वथा अनैतिक है। अग्रतक हमारे देश, चाहे जिस कारण से भी हो, हमें बड़े पैमाने पर आर्थिक सहायता देते रहे हैं। इस देश में बहुत से लोग भूख और बीमारों से मरते हैं। इसके अलावा हमारी शिक्षा, हमारे उद्योग राष्ट्रीय सम्स्कार भी प्रगति की दिशा में बाधक हैं। ऐसी स्थिति में दूसरे देश अधिक समय तक आर्थिक व अन्य प्रकार की सहायता नहीं दे सकते। सहायता लेते रहने से हम स्वतः अनैतिक हो जायेंगे तथा जरूरत पड़ने पर अपना राष्ट्रीय चरित्र भी ऊँचा नहीं रख सकते। देश बहुत दिनों तक अकर्मण्य नहीं रह सकता। अकर्मण्य रहने से किसी भी जाति का शीघ्र विनाश हो जाता है।

अमेरिका, जो हमारे देशों की इन दिनों अधिकाधिक सहायता दे रहा है, कुछ दिन बाद बदल कर दे सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत से अमेरिकन ऐसे हैं जो इस उदार सहायता का विरोध भी करते हैं। इसका असर औसत अमेरिकन करदाता पर भी पड़ता है। उसके जीवन स्तर पर भी इसका प्रभाव इतना अधिक पड़ रहा है जिसकी प्रतिक्रिया स्वाभाविक है। कुछ दिन हुए एक अमेरिकन लेखक ने ठीक ही पूछा था—अमेरिका भारत तथा अन्य देशों की सहायता क्यों करेगा। ये देश अपनी नीति निश्चित नहीं कर सकते और ऐसा न केवल उत्पादन के क्षेत्र में देखा जाता है और न जन्म नियंत्रण के क्षेत्र में। ऐसे देशों की सहायता पाने का कोई हक नहीं है।

यह सवाल विलकुल जायज है तथा सरकार को भी इस ओर ध्यान देना ही चाहिए। पश्चिमी राष्ट्र सहायता इसलिए दे रहे हैं चूँकि उन्हें अपनी रक्षा करनी है। वे सहायता इसलिए भी देना

चाहते हैं क्योंकि इन देशों में कम्यूनिज्म का प्रभाव अधिक बढ़ रहा है। इसी कारण से भूदान आदि कई प्रकार के आन्दोलन भी चलाये जा रहे हैं।

कम्यूनिज्म का प्रसार वही होता है जहाँ गरीबी और भुखमरी का साम्राज्य रहता है। जो विदेशी राष्ट्र हमारी सहायता कर रहे हैं वे यह नहीं चाहते कि यह देश कम्यूनिस्ट हो जाय। इसका एक दूसरा पहलू भी है। पश्चिमी देशों ने बहुत दिनों तक शोषण किया है और प्रायश्चित्त या मुआवजा की तरह वे आर्थिक सहायता दे रहे हैं।

सरकार ने खाद्य सकट को टालने के लिए जितना भी उद्योग किया है, उसमें पर्याप्त सफलता मिली है। सरकार का ऐसा अन्दाज है कि दस या पन्द्रह वर्षों से कम में खाद्य की निर्भरता नहीं सम्पन्न हो सकती है। भूमि की उर्वरता बढ़ाना, सिंचाई की व्यवस्था करना, जंगल लगाना, रासायनिक खाद उत्पादन करना आदि कई समस्याएँ हैं जिनकी ओर हमारा ध्यान गया है। जंगलों का जो बड़े पैमाने पर उजाड़ हो चुका है, उसके लिए हम स्वतः जिम्मेदार हैं। झम्मिग कृषि प्रणाली देश के कई हिस्सों में आदिवासियों द्वारा अनुसूत हो सकती है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में इस कृषि प्रणाली के कई नाम हैं, आसाम में झम्मिग, मध्य प्रदेश में पोडू और डाह्या तथा पश्चिमी घाट में कुमारी। पेड़ काट कर फेंक दिये जाते हैं, जला दिये जाते हैं, जमीन जोत दी जाती है तथा हाथ से बीज छोट दिये जाते हैं। तीन या चार वर्षों के पश्चात् जब वह भूमि अनुर्वर हो जाती है तब जंगल का दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है। इस अति प्राचीन कृषि प्रणाली को यथाशीघ्र रोकना होगा तथा इसके स्थान पर किसी दूसरे प्रकार की प्रणाली अपनायी पड़ेगी।

यदि हम आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों से अत्यधिक उत्पादन करना चाहते हैं तब शायद पूर्ण सफलता नहीं मिल सकती है। अतिशय पैदावार की कल्पना, ट्रैक्टरों से खूब गहरी जुताई तथा बड़े पैमाने पर रासायनिक खाद देने से यहाँ की जमीन पर अक्सर ठीक विपरीत प्रभाव पड़ सकते हैं। यह अभिमत आम जनता का ही नहीं बल्कि कृषि विशेषज्ञों का है। इस पर पूर्ण ध्यान दिया जाना चाहिये। मरनेवालों को दिये जानेवाले कोरामिन इन्जेक्शन को तरह ये साधन असली उत्पादन की वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इन नये साधनों के सबध में अधिक सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर अधाधुध पश्चिम का अनुकरण किया जाय तब वह आपत्तिजनक हो सकता है। यहाँ का अशिक्षित किसान इन पश्चिमीय साधनों का ठीक तरह से उपयोग भी नहीं कर सकते हैं। परिणाम के उल्टा होने की आशंका बराबर बनी रहेगी। फिर जब तक बड़े पैमाने पर सामूहिक या सहयोग कृषि प्रणाली नहीं अपना ली जाती तब तक छोटे-छोटे खेत के टुकड़ों में इस ढंग से कृषि नहीं की जा सकती है।

नमन्त ममार में कृषि की उन्नति के लिए योजनाएँ बनाई जा रही हैं। जिन देगों में बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण हो चुका है वहाँ भी कृषि की उन्नति पर ध्यान दिया जा रहा है। प्रथम महायुद्ध के तुरन्त बाद ही, सर्वप्रथम जागरण देखते हुए ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधान मंत्री लायड जार्ज ने

अग्रजों को एक नारा दिया था—कृषि से अधिक उत्पादन होना चाहिये उस समय ब्रिटेन को एक वर्गमील में २५०० आदमियों का पोषण करना पड़ता था। युद्ध के जमाने में उस देश को अपनी खपत के खाद्यान्न का ७५ प्रतिशत बाहर से मगाना पड़ता था। वहाँ तभी दो फसलें उगाने का सिद्धान्त स्वीकृत हो चुका था, अधिक अन्न उत्पादन के निमित्त कई प्रकार के उपाय काम में लाये गये थे।

भूमि की समस्या बहुत कम दिनों में पेंचीदी नहीं हो गई थी। यह समस्या बहुत धीरे-धीरे खराब होती गई। आर्थिक एवं राजनीतिक अवस्था के कारण अब यह प्रमुखता धारण कर चुकी है। चीन के जमीन्दारों की तरह भारत के जमीन्दार आततायी नहीं रहे हैं। चीन के जमीन्दारों ने तो अपने असामियों पर बर्बर अत्याचार किया था हालांकि चीनी क्षमा विलकुल प्रसिद्ध है। लेकिन चीनी जमीन्दार का लालच उसे इस क्षमा की परम्परा के निर्वाह से वंचित कर देता था। चीन में जिस प्रकार भूमि सुधार हुआ है उससे शिक्षा ग्रहण कर उसी प्रकार यहाँ भी किया जा सकता है। चूँकि भारत और चीन इन दोनों देशों में स्थिति एक सी है। लेकिन जिन तरीकों से चीन में भूमि सुधार किया गया उन्हीं तरीकों को यहाँ नहीं अपनाया जा सकता है। वैज्ञानिक प्रगति के अनुसार दुनिया बहुत नजदीक आ गई है और एक देश का अच्छा या बुरा प्रभाव दूसरे देश पर भी पड़ जाता है। चीन का सम्बन्ध तो भारत से बहुत पुराना है।

भारत कृषि प्रधान देश है। इस देश में ५००,००० गाव हैं और औसत आबादी प्रत्येक गाव की ५१७ व्यक्तियों की है। अग्रज शासकों ने इसका औद्योगिकरण अपनी जरूरतों तक ही किया। अगर भारत को इसे स्वतः करना होता तब अबतक औद्योगिकरण की प्रगति तीव्र हो गई होती। इस प्रकार गावों से हटकर आबादी धीरे-धीरे शहरों में सिमटती गई। द्वितीय विश्वयुद्ध के पश्चात् तो शहरों की आबादी अत्यधिक बढ़ गई। १८७२ में गावों की आबादी ९१३ थी और शहरों की आबादी ७७ थी। अगर यही आबादी रहती तब कृषि से उत्पादन की स्थिति बिल्कुल भिन्न होती। इस देश में प्रचलित जात-पात की प्रथा ने कृषि को और भी पीछे ढकेल दिया है। विविध राज्यों में विविध प्रकार की भूमि व्यवस्था थी, अतः किसी नियम का पालन नहीं किया जा सकता था। समाजगत प्रचलित व्यवस्था सुदृढ़ आधार पर इन्हीं राजतंत्रों के कारण नहीं चल सका।

देशी राज्यों के सघ में मिल जाने से तथा जमीन्दारी एवं जागीरदारी की प्रथा का अन्त कर दिये जाने के कारण स्थिति दूसरी हो गई है। अब चाहे जो भी राजनीतिक पार्टी किसानों को सुख देना चाहे वह कानून बनाकर ही कर सकती है। इससे कोई भी दूर नहीं हट सकता है। कांग्रेस सरकारों को भी इसे शीघ्र कानून बनाकर लागू कर देना चाहिए। ऐसा करने के लिए रास्ता साफ कर दिया गया है। अगर इस काम में देश को किसी कारणवश देर हो गई तब चीन या दूसरे देशों की तरह हिंसा यहाँ भी हो सकती है। भूमि का वितरण नैयायिक स्तर पर जितनी जल्दी किया जायगा उतना ही आसान होगा नहीं तो इस सरकार के विरुद्ध वर्गों को उकसाया जा सकता है। भूमि वितरण का प्रमुख उद्देश्य अधिक उत्पादन का व्यय होना चाहिये।

## कौटिलीय अर्थशास्त्र में भूमि व्यवस्था

प्राचीन भारतीय समाज-संघटन में भूमि की मिल्कियत का प्रश्न बड़ा पेचीदा एवं गहन था। प्रश्न केवल यह नहीं है कि उस समय भूमि राज्य की थी या समाज के व्यक्ति उसके मालिक थे या होते थे। दोनों पक्ष की ओर से तर्क मिलते थे पर अबतक किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सका। आदिकाल में चाहे जो भी स्थिति रही हो किन्तु कौटिलीय अर्थशास्त्र में राज्याधिकार में जमीन के बड़े-बड़े टुकड़ों का विवरण मिलता

डाक्टर वी० पी० सिंह

है। कुछ जमीनें रँयतो को वन्दोवस्त कर दी जाती थी और कुछ में राज्य के अधिकारियों द्वारा खेती कराई जाती थी। उस युग में किसानों को जमीन वन्दोवस्त की जाती थी तथा उनसे कर वसूल किया जाता था जिसे भाग की सजा दी गयी थी। कुछ लोगों का कहना है कि भाग कर को ही कहते हैं। कतिपय पुराने इतिहासज्ञों का ख्याल है कि भाग उस कर को कहते हैं जो सरक्षण के बदले राजा को प्राप्त होता था। पुराने कागजातों से भी यही पता चलता है। अतः यह नहीं माना जा सकता है कि जमीन के कर को ही भाग कहा जाता था। कौटिल्य अर्थ शास्त्र में भाग गावों से प्राप्त होनेवाला कर ही था। उत्पादन का अधिक भाग भी कभी-कभी राज्य कर के स्वरूप में लिया जाता था। राज्य को यह अधिकार भी सन्निहित था कि कर अधिक लिया जा सकता है। मेगास्थनीज की रिपोर्ट के अनुसार फसल का चौथाई कर लिया जाता था।

यद्यपि भूमि पर वैयक्तिक अधिकार लोगों का होता था लेकिन यह अनुमान कर लेना गलत होगा कि राज्य की दिलचस्पी केवल कर वसूल करने में ही थी और राजा को प्रजा के कल्याण का कोई उद्देश्य नहीं था। राज्य भूमि की व्यवस्था में तत्पर इसलिए रहता था ताकि सरक्षण हो एवं भूमि का इन्तजाम ठीक से हो सके, भूमि चाहे रँयतो के वन्दोवस्त में रहे या राजा की ओर से खेती होती हो। कौटिल्य प्रशासन जमीन के इन्तजाम में उद्बुद्ध व सतर्क था। उत्पादन बढ़ाना, कृषि की रक्षा करना और

आय बढ़ाना राज्य का उद्देश्य था। भूमिकर ही प्रधान आय थी जिस पर देश की उन्नति निर्भर थी। इसलिए शासन राज्य की आमदनी में पितृवत् रचि दिखलाता था।

तब राज्याधिकार में वनों की व्यवस्था और मालकियत भी थी। ये जगल भी कई भागों में विभक्त रहते थे। हाथी के जगल तो राज्य के होते ही थे चूकि हाथी सेना का प्रधान अंग होता था। जगलों का इन्तजाम अफसरों के हाथ रहता था। अन्य कई किस्म

के व्यवसाय भी राज्य के द्वारा ही सरक्षित किये जाते थे। लेकिन कभी-कभी उद्योगों के लिए भी व्यापारियों से वन्दोवस्ती की जाती थी। इनके लिए कर लिया जाता था। अर्थशास्त्र में खानों, खनिजों एवं समुद्र गर्भ से मोतियों को निकालने का इन्तजाम कराया जाता था।

परती जमीन पर राजा का अधिकार होता था। इन्हीं जमीनों पर नई वस्तियाँ बसाई जाती थी और इन्हें ही जोत-कोड कर उपजाऊ खेत बनाया जाता था। कौटिल्य ने पुराने एवं उजड़े हुए गावों, बड़े हुए गडों के स्थान पर नए गाव बसाने का सिद्धान्त स्थिर किया। यह वन्दोवस्त इसलिए किया गया था ताकि आबादी का स्तर एक सा रहे। नई वस्तियों में सरकारी आदेशानुसार आनुपातिक तरीकों से आबादी बसाई जाती थी। वस्तियों की सीमा रेखा निर्धारित कर दी जाती थी। उसके नजदीक ही शूद्रों और वैश्यों को बसाया जाता था। ये ही दो जातियाँ अत्यन्त परिश्रम के साथ कृषि कार्य कर सकती थी। एक वर्ष के लिए जमीन वन्दोवस्त कर अधिक उत्पादन पर जोर दिया जाता था ताकि सब लोग अधिकाधिक मेहनत कर सकें। पुरोहितों, आचार्यों आदि को भी जमीन वन्दोवस्त की जाती थी। इस भूमि के लिए किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता था। इसे ब्रह्मदाय भूमि कहते हैं। अन्य राज्य व्यवस्थापकों को उनके कार्य के लिए भी भूमि ही दी जाती थी। इन जमीनों की खरीद-विक्री नहीं हो सकती थी। प्रत्येक ग्राम की सफाई का इन्तजाम रहता था। सब के लिए काम का इन्तजाम किया जाता था। वन्दोवस्ती में जब उत्पादन को अधिक प्रश्रय



नहीं मिलता था तब वही भूमि दूसरे किसान को दे दी जाती थी। उसके लिए यह शर्त रहती थी कि अधिक-से-अधिक उत्पादन हो सके। इसका उद्देश्य यह था कि आलसी किसानों की वजह से राज्य को घटी नहीं होने पावे। पर साथ ही उन किसानों पर बड़ा अनुग्रह रखा जाता था जो समय पर कर वसूल कर दिया करते थे। जरूरत पड़ने पर इन लोगों को अन्न, जानवर तथा नकद भी दिये जाते थे। राज्याधिकारी इसका भी ह्याल रखते थे कि इन सुविधाओं के देने से अन्ततः राज्य कर में वृद्धि ही होगी। जिससे राज्य को कोई लाभ होने की आशा नहीं होती थी उसे सुविधा नहीं दी जाती थी।

भूमि की उचित सिंचाई के लिए आहर, पोखर और तालाब बनवाये जाते थे। खनिजों के विकास के लिए शोध कार्य किये जाते थे। इन कामों में प्रजा की सहायता ली जाती थी। सड़को, राजपथों एवं यातायात के अन्य साधनों का निर्माण भी कराया जाता था। राज्य के समस्त जानवरों को चारा मिले इसका मुआइना करना भी शासन की जिम्मेदारी थी, देव-मंदिर, तालाब तथा कई प्रकार के जनोपयोगी कार्य करने को सबको प्रोत्साहन दिया जाता था। इन कार्यों में भाग लेने की एक प्रकार की अनिवार्यता सिद्ध कर दी गयी थी। कभी-कभी तो टाल-मटोल करनेवालों को कड़ा दंड भी दिया जाता था। यह इसलिए किया जाता था ताकि प्रजा कृषि कर्म से विरक्त होकर गरीब न हो जाय। कभी-कभी तो नर्तको-नर्तकियों का जाना गावों में रोक दिया जाता था। सड़को और राजपथों पर लुटेरे और डाकू तथा रहजन न रहें इसका प्रवध भी शासन की तरफ से किया जाता था।

खास महाल की कृषि राज्य के द्वारा की जाती थी। इसका नाम था सीता। खास महाल का अधीक्षक या निर्देशक योग्य व्यक्ति ही होता था, अत्यन्त कुशल एवं अनुभवी। वह मजदूरों की सहायता से खेती करवाता था। बढई, लुहार, जानवर, बीज आदि का निरीक्षण भी उसीके जिम्मे रहता था। जलाशयों, नहरों से सिंचाई की सुव्यवस्था रहती थी। आदमी तथा जानवर, दोनों मिल कर सिंचाई का काम करते थे। प्रत्येक बीज का सग्रह एवं सुधार अपरिहार्य रूप से किया जाता था। मौसम विशेषज्ञ किसानों को उचित सलाह दिया करते थे। उत्पादन बढ़ाने के लिए खादों के सबध में अनुसंधान किया जाता था तथा किसानों को तत्परता के साथ इन सबकी जानकारी कराई जाती थी। खास महाल की सिंचन-सुविधाओं से अन्य भी लाभ उठा सकते थे। इसके लिए जलकर वसूल किया जाता था।

उत्पादनो के विक्रय का इन्तजाम भी राज्य का दायित्व था। विशेषतया इस बात की निगरानी की जाती थी ताकि खाद्यान्नो के भाव अकारण नहीं बढ़ जाय। भिन्न-भिन्न जिनसों के मूल्य भी राज्य द्वारा निर्धारित कर दिये जाते थे। परती जमीनों की बन्दोबस्ती जब किसानों के साथ की जाती थी तब उन्हें निश्चित सहायता दी जाती थी ताकि वे उस भूमि में कृषि कार्य कर सकें। जानवरों की बीमारियों का इलाज भी बड़े पैमाने पर कराया जाता था। चारागाहों की व्यवस्था करना भी राज्य का काम था।

इन प्रमाणों से पता चलता है कि कौटिलीय राज व्यवस्था के अन्तर्गत भूमि व्यवस्था बिलकुल पूर्ण थी। चन्द्रगुप्त मौर्य ने सुप्रसिद्ध सुदर्शन झील खुदवाया था। बाहरो तथा ग्रामों की आवादी की गणना भी अच्छी तरह की जाती थी ताकि उसमें किसी प्रकार की भल नहीं रहने पावे। गोप गावों का पूर्ण विवरण रखता था। इसके अलावे भिन्न-भिन्न प्रकार की सूचनाएँ भी उसके पास रहती थी। मर्दुमशुमारी का काम भी वही करता था। गोपों के वाद स्थानिकों के पास भी ऐसे ही रेकार्ड रहते थे। इन कामों का महत्त्व इतना अधिक माना जाता था। इसके निरीक्षण एवं परीक्षण के लिए गुप्तचर भी छोड़े जाते थे। इसीके अनुसार कर प्रत्येक श्रेणी से वसूल किया जाता था। कौटिल्य राज्य में इन सब सुविधाओं एवं राजाज्ञाओं का सुप्रवध इसलिए था चूकि राजा के लिए प्रजा के हित के समस्त कामों में रुचि रखना पुनीत धर्म व कर्त्तव्य दोनों था। यह मान्यता भी थी कि अधिक स्तर का विकास प्रजा और राजा के सबधों को दृढतर बना कर राज्य समृद्ध करता है।

लेकिन दैवी प्रकोपों के समय, जैसे अकाल पड़ने पर या बाढ आने पर तथा इसी प्रकार की अन्य प्रकार की विपदाओं के सम्मुखीन हो जाने पर राज्य की ओर से प्रजा को भरपूर सहायता दी जाती थी। गरीबों को कई प्रकार की सहायता देने के लिये धनिकों से कर वसूल किये जाते थे। बेकारी दूर करने के लिये सबके बनवाई जाती थी, आहर-पोखर-तालाब खुदवाये जाते थे एवं अन्य जनोपयोगी कार्य राज्य की ओर से बड़े पैमाने पर कराये जाते थे। किसान ऐसी परिस्थितियों में साग-सब्जी तथा अन्य प्रकार के जल्दी से उगनेवाले अन्नो का उत्पादन करने को प्रस्तुत रहते थे।

इस प्रकार कौटिल्य के अर्थ शास्त्र के अनुसार उत्पादन के दृष्टिकोण से भूमि की व्यवस्था की जाती थी तथा छठा हिस्सा के अतिरिक्त भी अन्य कई प्रकार के कर प्रजा से वसूल किये जाते थे।

# मिश्र की नई भूमि-व्यवस्था

श्री हरेन्द्रदेव सिंह

बुधवार २३ जुलाई, १९५२ के प्रातः ७ बजे मिस्र में शामन-सूत्र वहाँ की फौज के हाथ में आया। आते ही इसने भूमि-सुधार के विचार को प्रकट किया। इस क्रांति से पूर्व भी यह सवाल कई बार विचारार्थ उपस्थित हुआ था किन्तु बराबर इसे टालने की ही चेष्टा रही। फलस्वरूप किसानों के ऊपर भूमिपतियों का उत्पात बढ़ता गया और किसानों की अवस्था गिरती गयी। इसका अमर अन्न के उत्पादन पर भी पडा। उत्पादन में गिरावट को रोकने और किसानों की क्रय-शक्ति को बचाने के लिए भी भूमि सुधार को तुरत लागू करना नयी सरकार के लिये आवश्यक हो गया। किसानों की अल्प क्रय-शक्ति के कारण देश का औद्योगिक विकास भी संभव नहीं था। भारत और चीन में हुए भूमि-सुधार के उदाहरण भी उनके सामने थे। इन देशों में उत्पादन को बिना थोडा भी नुकसान पहुँचाये भूमि सुधार के नियम लागू किये गये थे और उसका समाज पर अच्छा असर पडा था।

मिस्र में भूमि का स्वामित्व थोडे से लोगों के हाथ में था जो समाज के उत्पादन को अपने निजी स्वार्थ में इस्तेमाल करते थे। जमीन की इस विपमता के रहते देश में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और औद्योगिक सन्तुलन संभव नहीं था। नीचे के आकड़ों से इस विपमता का अन्दाज कीजिये

## भूमि सुधार से पूर्व भूमि का स्वामित्व

क्षेत्रफल	भू-स्वामियों की संख्या
१ फेदन के अन्दर	१९८१,३३९
१ से ५ फेदन ..	६१७,८६०
५ से २०० फेदन ..	१५९,३४७
२०० से ८०० फेदन ..	१,८३५
८०० से १,००० फेदन	९२
१,००० से २,००० फेदन	१२७
२,००० फेदन से अधिक	६१
२,७६०,६६१	

## भूमि सुधार का उद्देश्य

भूमि के इन असमान वितरण का अन्त कर मिस्र के आर्थिक जीवन में सन्तुलन लाना ही भूमि-सुधार का उद्देश्य था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए नयी सरकार ने भूमि के बड़े-बड़े क्षेत्रों को तोड़ने का निश्चय किया। उसने जमीन की अधिक-से-अधिक हदवन्दी २०० फेदनो का रखा। एक फेदन लगभग एक एकड़ के बराबर होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि मिस्र की कुल ६०,००,००० फेदन उपजाऊ जमीन में ६००,००० फेदन खेती-हरी में बांटने के लिये मिल गयी। इन्हीं पाच साल के अन्दर बांट देने का निश्चय मिस्र ने किया था और अब तक इस ओर काफी प्रगति सफलतापूर्वक हो चुकी है। इन जमीन को प्रत्यक्ष रूप से खेती करनेवाले किसान के अन्दर बांटा जा रहा है। इस प्रकार कुल जोत की जमीन में से १० प्रतिशत के पुनर्वितरण को पाच साल में पूरा करने के कार्यक्रम में प्रशासन की भी कोई समस्या पैदा नहीं होती। अन्य देशों के अनुभवों से इस अर्थ में मिस्र को अवश्य ही काफी सहायता मिली है। आगे चल कर भी कोई समस्या पैदा न हो जाय इसीलिए अधिकारियों ने जल्दी-वाजी से काम नहीं लेकर पाच साल की अवधि में पूरा करने का फैसला किया था।

कुछ लोगों का ऐसा भी ख्याल था कि इससे उत्पादन को बहुत बक्का लगेगा। किन्तु अधिकारियों ने देखा कि बड़े-बड़े भूमिपति स्वयं तो खेती करते नहीं बल्कि छोटे-छोटे किसानों को लगान पर दे देते हैं। अतः अगर उन जमीनों के मालिक वे किसान बना दिये जाते हैं तो अवश्य ही उत्पादन बढ़ाने के लिए उनमें अधिक जोश होगा और वे अधिक मिहनत से ज्यादा उत्पादन करेंगे। साथ ही उर्वरा शक्ति के अनुसार खेतों का क्षेत्रफल भी २ से ५ फेदन का कर दिया गया, जिससे भी उत्पादन में वृद्धि की आशा की गयी। यह सच था कि किसान बीज, खाद और रुपये जमीन्दारों से कर्ज लेते थे, जो नयी व्यवस्था के लागू होने पर उन्हें नहीं मिल सकता था। क्रेडिट एग्रीकोल को-ऑपरेटिव ने इन दिक्कत को बहुत हद तक हल कर दिया और नयी-नयी सहकारी सोसाइटियों की स्थापना के लिए आन्दोलन आरम्भ किया गया। बदरी हुई परिस्थिति ने गांव के प्रशासन और सहकारिता को चलाने के लिए नये प्रशासकों की शिक्षा आरम्भ की गयी।

## सुधार का आरम्भ

१ सितम्बर १९५२ से भूमि सुधार कानून लागू किया गया। कानून की प्रथम धारा में स्वीकार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति २०० फेदन से अधिक जमीन नहीं रख सकता।

इस कानून का असली मकसद भूमि पर से सामन्तवाद को समाप्त कर खेती योग्य भूमि का पुनर्वितरण करना है। कानून के अन्तर्गत भूमिपतियों को अपने पुत्रों के नाम ५० फेदन तक जमीन परिवर्तित कर देने का हक प्राप्त है। वशत कि इस प्रकार की जमीन १०० फेदन से अधिक नहीं हो। जमीनें किसी से भी बिना मुआवजा के नहीं छीनी गयी। मुआवजा की दर लगान के १० गुना रखी गयी जो ३ प्रतिशत सूद के साथ सरकारी वाड के रूप में भूमिपतियों को मिले और जिसको वे ३० वर्ष में भुना सकेंगे।

जमीन प्राप्त करनेवाले नये लोग ३० वार्षिक किशतों में जमीन की कीमत अदा करेंगे। जमीन के साथ-साथ उन्हें जमीन के अन्दर पडनेवाले मकान की कीमत, ३ प्रतिशत सूद और १५ प्रतिशत अतिरिक्त खर्च भी देना पड़ेगा। कानून के अनुसार मिस्र में लगान की दर बुनियादी कर का सात गुना रखा गया।

लगभग ७५ प्रतिशत किसानों ने इस धारा से लाभ उठाया। कानून की ३२ वी धारा के अनुसार जमीन उन्हें दी जा सकती है जो कृषिजीवी हैं। धारा ३३ के अनुसार जमीन की लगान बुनियादी कर के सातगुना से अधिक नहीं होगा और वटाईदारी की अवस्था में जमीन के मालिक को आधे से अधिक नहीं मिलेगा।

कानून के लागू करने के बाद बड़े-बड़े भूमिपतियों से जमीन प्राप्त करना आरम्भ हुआ। नवम्बर १९५३ तक उच्च समिति को १८७,७४३ फेदन जमीन प्राप्त हुई। प्राप्त की गयी जमीन के अन्दर पडनेवाले कृषि साधनों तथा अन्य स्टाको का भी लेखा लिया गया जिससे कृषि के लिए आवश्यक सामान की कमी न हो।

भूमि सुधार के लिए निर्मित उच्च समिति को भूमि प्राप्त करने और उसके वितरण काल तक भूमि की व्यवस्था का अधिकार दिया गया है। यही समिति किसानों के हाथ भूमि बन्दोबस्त करती है। वे ही किसान भूमि प्राप्त कर सकते हैं, जिन्होंने कभी उस भूमि में पहले कार्य किया है।

आधुनिक ढंग में कम-से-कम खर्च पर उत्पादन में वृद्धि की गारंटी के लिए समिति किसानों को आर्थिक और टेक्निकल सहायता प्रदान करती है। उस प्रकार मिस्र में कृषिजन्य उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है।

कई स्थानों में चन्द टेक्निकल कारणों से उच्च समिति ने भूमिकर में भी कमी कर दी, जिसमें किसानों ने बिना विलम्ब के कर अदा किये हैं। नेशनल एग्रिकल्चरल क्रेडिट बैंक ने भी किसानों को काफी कर्ज दिया है। उपरी मिस्र में ईज्र उपजानेवाले किसानों को प्रति एकड १५ मिस्री पाँड तक कर्ज में दिये गये। एक मिस्री पाँड भारतीय १३ २५ रुपये के बराबर होता है।

## चार मुख्य आधार

जमीन के जटिल के पूर्व भूमि सुधार उच्च समिति ने विशेषज्ञों के द्वारा चार प्रमुख बातों का अध्ययन कराया जो पुनर्वितरण की नीति के पुन आसार हैं

१ प्राप्त किये गये इस्टेटों के रजिस्ट्रो की छान-बीनकर पुराने रैयतों के नाम की सूची तैयार की गयी।

२ सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा खेतिहरो की स्थिति का अलग से अध्ययन किया गया। उच्च समिति और किसानों के बीच में मध्यम कडी हैं। आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोणों से इन्होंने किसानों के जीवन-स्तर का अध्ययन किया।

३ किसानों की आय के तखमीने के लिए तीन साल की परिवर्तित खेती के आधार पर प्रति फेदन उत्पादन का अध्ययन किया गया।

४ विभिन्न सख्या के परिवारों की जीविका की औसत आय का पता लगाया गया।

इस सामाजिक अनुसंधान के द्वारा उच्चसमिति को विभिन्न रैयतों के बीच जमीन के वटवारे की सीमा निर्धारण में सहायता मिली।

भूमि सुधार कानून की धारा ९ में कहा गया है कि प्रत्येक गाव में प्राप्त जमीन का वितरण छोटे किसानों में इस प्रकार हो कि जमीन की कोटि के अनुसार प्रत्येक को दो फेदन से कम और ५ फेदन से अधिक नहीं मिले। अत वे ही मिस्रवासी जमीन पाने के हकदार हैं (१) जो किसी असम्मान-जनक अपराध में दोषी नहीं करार दिये गये हो, (२) कृषि कार्य कर रहे हो और (३) पाच फेदन से कम जमीन रखते हो। इन गुणों के रहते हुए भी पहले जमीन उन्हें दी जायगी जो रैयत या किसान की हैसियत से खेती कर रहे हैं, बाद को उनलोगों को जिनके परिवार गाव में बहुत बड़े ह, इसके बाद उनलोगों को जो गाव में गरीब हैं और सबसे बाद में उनलोगों को जो दूसरे गाव के हैं। इस प्रकार से दी गयी जमीन फिर से पूर्व क्रम के अनुसार सरकार नहीं लेगी।

कुछ दिनों के बाद देखा गया कि कुछ परिवारों को, जो औसत आकार से बड़े थे, पाच फेदन के उत्पादन से अधिक की आवश्यकता है। ऐसी परिस्थिति में बड़े परिवारों को बाटकर उन्हें अलग से जमीन प्राप्त करने योग्य बनाया गया।

जमीन के वटवारे के सिलसिले में निम्न बातें भी देखी गयी। जैसे किसानों के घर से अधिक-से-अधिक निकटतम दूरी पर उन्हें जमीन मिलनी चाहिये।

कम जमीन पानेवालों को जमीन उनके निवास स्थान से कम-से-कम दूरी पर ही हो।

प्रत्येक खेत को तीन बराबर हिस्सों में बाट देना चाहिये जिससे कि बदल-बदल कर तीन साल तक वे खेती कर सकें।

नये जमीन पानेवालों में एकरूपता का होना भी आवश्यक है।

भविष्य में सामाजिक, स्वास्थ्य सबन्धी और शैक्षणिक मकानों के निर्माण के लिए अधिक-से-अधिक जमीन सुरक्षित छोड़ देना चाहिये।

उच्च समिति ने किसानों के लिए बीज, खाद, मवेशी, कृषि-औजार, तथा गुदाम और यातायात की गारंटी के हेतु सहकारिता आन्दोलन पर जोर दिया गया है जिससे उत्पादन की वृद्धि में किसी प्रकार की अडचन नहीं होने पावे। सभी गावों में ऐसी सहकारी समितिया कायम की जा रही हैं। भूमि-वितरण और सहकारिता के फलस्वरूप उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई है।

१९१७ की अक्तूबर क्रान्ति से पूर्व प्रायः सारा रूसी साम्राज्य छोटी-बड़ी जमीन्दारियों में विभक्त था। ये जमीन्दार अधिकतर जार के वंश के या उनके नजदीकी लोग थे जो जमीन के साथ-साथ किसानों के भी मालिक थे। केवल जार के वंश के लोग, सिर्फ यूरोपीय रूस में ८० लाख हेक्टेयर तथा अन्य २८ हजार जमीन्दार ६ करोड़ २० लाख हेक्टेयर जमीन के मालिक थे। २८ हजार जमीन्दारों की जोत में उतनी जमीन थी जितनी १ करोड़ किसान जोतते थे। किसानों की जमीनें अपेक्षाकृत अत्यन्त ही न्यून श्रेणी की और कम उपजाऊ थीं। किसानों का हर प्रकार से शोषण किया जाता था। उन्हें बेगार खटना पड़ता था, अधिक लगान देना पड़ता था और बेदखली तो साधारण सी बात थी। किसानों के अन्दर भी जमीन्दारों ने त्राण पाने के लिए बड़ी बेचैनी थी।

१९०५ में लेनिन ने इस बात को आवश्यक समझा कि क्रान्ति में मजदूर वर्ग के निकटतम दोस्त ग्रामीण गरीब किसानों को भी संगठित करना चाहिये। एक कारण और भी था जिससे लेनिन ने किसानों के संगठन पर अधिक जोर दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी तथा आस्ट्रिया आदि पश्चिम यूरोप के देशों में किसानों को पूँजीवादी नेतृत्व में सामन्तवाद से त्राण मिला था, जिससे किसानों और मजदूरों की एकता नहीं कायम हो सकी और पूँजीवाद के विरुद्ध संघर्ष में मजदूर वर्ग अकेला रह गया। अतः मजदूर वर्ग की जीत के लिए किसानों का समर्थन प्राप्त करना आवश्यक था। देहातों में जमीन्दार किसानों के साथ गुलाम जैसा सलूक करते थे। जिससे गावों में भी किसानों के अन्दर जमीन्दारों के विरुद्ध वर्ग चेतना जगाने में आसानी हुई। शहर में पूँजीपतियों के विरुद्ध मजदूर लड़ रहे थे और गावों में जमीन्दारों के विरुद्ध किसान। दोनों की मिली-जुली शक्तियों के सहारे रूस में १९१७ के नवम्बर में लेनिन के नेतृत्व में क्रान्ति पूर्ण सफल हुई। रूसी साम्राज्य को समाजवादी सोवियतों का देश घोषित किया गया।

समाजवाद संपत्ति का स्वामित्व समाज के हाथ में देता है, वह संपत्ति चाहे औद्योगिक हो, चाहे कृषि सबही। क्रान्ति के प्रथम वर्ष में ही सोवियत रूस में खेती पर से जमीन्दारों का प्रभुत्व खतम कर दिया गया। जमीन्दारों के अन्त होने से किसानों को सिर उठाने का अवसर तो अवश्य मिला, किन्तु भयंकर गृहयुद्ध के कारण कृषि सबही अन्य कदमों को उठाने में तीन साल तक उनकी कोई भी प्रगति नहीं हो सकी। गृह-युद्ध के बाद

## सोवियत रूस की भूमि-व्यवस्था

श्री गिरीन्द्र मोहन भट्ट

भी सोवियत नेताओं ने पहले उद्योगों का समाजीकरण आरम्भ किया। असल में क्रान्ति के तुरन्त बाद ही उद्योगों को राजकीय कर देने पर भी गृह-युद्धों के कारण वे उन्हें चलाने में असमर्थ रहे। नयी आर्थिक नीति (नेप) के अन्तर्गत उन्होंने फिर से व्यक्तिगत उद्योगों को छूट दी।

१९२४ में लेनिन की मृत्यु हो गयी। मृत्यु के पश्चात् प्रमुख नेताओं में नीति के प्रश्न को लेकर बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। कामेनेव और जिनोवियेव का विचार था कि नेप की नीति से देश में फिर से पूँजीवाद का प्रादुर्भाव हो जायगा। बुखारिन और राजकोव का मत था कि किसानों को व्यक्तिगत खेती के लिए और भी अधिक-से-अधिक छूट तथा व्यक्तिगत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाय। १९२७ तक यही बखेड़ा चलता रहा। अन्त में ट्राट्स्की और उनके समर्थकों का पतन हुआ। वे लोग कई पड्यत्रों में सक्रिय पाये गये और कई फासी पर चढ़ा दिये गये और कई को देश निकाला हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी और सरकार का नेतृत्व स्तालिन के हाथों में आया। स्तालिन ने खेती को पचायती बनाने का कार्य आरम्भ किया और यही से कोलखोज आन्दोलन का सूत्रपात हुआ। किन्तु कोलखोज से पूर्व सोवखोज को जानना जरूरी है।

### सोवखोज

१९१७ की अक्तूबर क्रान्ति के बाद जमीन्दारियां जब्त कर ली गयीं और कुछ ही सरकार स्वयं खेती करने लगी। यही सरकारी खेती सोवखोज कहलाती है। पहले बड़े-बड़े जमीन्दारों की अपनी जोतवाली जमीनों को ही सोवियत सरकार ने सोवखोज के रूप में परिणत किया, पीछे जंगल काट कर या नहर निकाल कर वज्र भूमियों का कर्षण कर और भी नये सोवखोज बनाये गये।

सोवियत विधान कहता है कि जमीन, खानें, पानी, जंगल, कारखाने खनिज पदार्थ, रेल, जल और वायु-यातायात, बैंक, वहन के साधन (डाक तार, टेलीफोन, रेडियो इत्यादि) विशाल राजकीय कृषि प्रतिष्ठान (राजकीय खेती, मशीन और ट्रैक्टर स्टेशन आदि) तथा म्युनिसिपल सस्थाएँ और शहर एव औद्योगिक केन्द्रों के अधिकतर निवास गृह राज्य की संपत्ति हैं। इस प्रकार सोवखोज (सोवियत खेती) राज्य की निजी संपत्ति है—जिसके व्यवस्थापक को, राज्य के योग्य अधिकारी बहाल करते हैं। ये ही व्यवस्थापक इसकी तमाम आर्थिक गतिविधियों की देख-भाल करते हैं और उत्पादन योजना की सारी जिम्मेदारी इन्हीं के सिर पर होती है। सरकारी फ़ैक्टरियो और सोवखोजों के कर्मचारी की एक ही स्थिति होती है और प्रत्येक को काम के गुण और परिमाण के अनुसार मजदूरी मिलती है। अतः सोवखोजों को आप अनाज उपजाने की बड़ी-बड़ी फ़ैक्टरी कह सकते हैं जिसका हर एक कार्यकर्ता वैसा ही मजदूर है, जैसा सरकार के किसी और कारखाने का।

सोवखोजों के अतिरिक्त कितनी ही जगहों पर कुछ आदर्शवादी साम्यवादियों ने साम्यवादी खेती (कम्प्यून) भी स्थापित की और सोवियत सरकार की सहायता से वे भी सफलतापूर्वक चल रही हैं।

### कोलखोज

१९२७ तक उद्योगों का समाजीकरण हो चुका था और उत्पादन युद्ध से पूर्व की स्थिति में पहुँच चुका था। अब आगे की प्रगति के लिए खेती का समाजीकरण आवश्यक था। नियोजित आर्थिक उन्नति के लिए उद्योगों के साथ कृषि योजना भी आवश्यक थी। समाजवादी उत्थान के लिये खेती के समाजीकरण के बिना अब आगे का कार्यक्रम संभव नहीं था। सोवखोजों का प्रबन्ध सरकार के हाथ में था किन्तु सोवखोज इतने अधिक नहीं थे कि उनकी उपज से सारी मजदूर जनता की भूख की आवश्यकता की पूर्ति हो। साथ ही वैयक्तिक किसानों की आमदनी का कोई निश्चय नहीं। व्यक्तिगत तौर पर वे प्राकृतिक आपदाओं का मुकाबला भी नहीं कर सकते थे। खेत के चप्पे-चप्पे से वैज्ञानिक आधार पर अधिक-से-अधिक अन्न प्राप्त करने के अतिरिक्त देहातो में रहनेवाले किसानों की सांस्कृतिक उन्नति के लिए भी उनकी आमदनी का बढ़ाना आवश्यक था। यह वे अपने घर-द्वार अपने चार अंगुल के हल और मरियल वल और छोटे-छोटे टुकड़ों में बटे अपने खेत का अलग ससारा बना कर नहीं कर सकते थे। अतः कृषि को भी सामाजिक आधार देना आवश्यक था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए १९२७ में स्तालिन के नेतृत्व में कम्प्युनिस्ट पार्टी और सोवियत सरकार ने कोलखोज की नीति अपनायी।

अब कृषि में राजकीय प्रतिष्ठानों अर्थात् राजकीय खेत, मशीन और ट्रैक्टर केन्द्रों के अतिरिक्त सहकारी या कोलखोज आन्दोलन का आरम्भ हुआ। लाखों लाख किसानों ने अपने साधनों और श्रम शक्ति को कोलखोजों अर्थात् सामूहिक खेती में संगठित करना आरम्भ किया जिससे सहकारी और कोलखोज मिलिक्यत की सृष्टि हुई।

यह संगठन १९२८ में आरम्भ हुआ था। बड़े किसानों (कुलको) और पुणेहितों ने इसका विरोध किया। उन्होंने किसानों को उभारना

शुरू किया। बहुत से किसान उनके चकमें में आ गये। अपने बाप-दादाओं के समय से चली आती हुई जमीन पर से अपना स्वामित्व छोड़ने में उन्हें बड़ा मोह हुआ। असल में इसके संगठन में कुछ घावली भी हुई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर सोवियत सरकार ने एक खास सख्या तक कोलखोजों के संगठन का निश्चय किया था। किसानों में उतनी जागृति नहीं थी। उस हद तक किसान सामूहिक खेती के लिए तैयार नहीं थे। कुलको ने अपनी जमीन को अपने हाथ से जाते देख कर उसे बरबाद करना आरम्भ किया। उन्होंने किसानों से भी ऐसा ही करने को कहा। गाव-के-गाव उजाड़ हो गये। लोगों ने जमीन परती छोड़ दी। अन्न जला डाले। पेड़-पौधों को काट दिया। मवेशियों को मार दिया गया। देश में अन्न, फल और मास की कमी हो गयी।

देश की इस विगड़ती हुई परिस्थिति को देख कर स्तालिन ने कोलखोज आन्दोलन को धीमा किया। जिन किसानों ने कोलखोजों से लौटने का विचार किया उन्हें वैसा करने की छूट दी गयी।

किन्तु तब तक संगठित कोलखोजों के आशातीत उत्पादनों को देख कर कोलखोज आन्दोलन को आगे बढ़ाना उत्पादन की वृद्धि के लिए आवश्यक था। किन्तु कुलको से पिंड छुड़ाये बिना गावों में इस आन्दोलन को चलाना कठिन था। एक दूसरे कारण से भी कुलको का नाश आवश्यक था। कुलको की उपस्थिति से पूँजीवाद के विकास का खतरा था। इसलिए सरकार ने कुलको से अनाज का एक खास भाग वसूल करने का विशेष कानून लागू किया। कुलको ने इसका पालन नहीं किया। उन्होंने अव्यवस्था फैलाना आरम्भ किया। अतः सोवियत सरकार ने इन्हें बाकी मालगुजारी तुरत अदा करने का आदेश दिया और बचे हुए अनाज को भी निर्धारित मूल्य पर बेचने के लिए उन्हें विवश किया गया। कुलको के विश्वासघातकारी किसानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए कुलको से छीने गये अन्न का २५ प्रतिशत उन्हें उधार देने की घोषणा सरकार ने की। कुलक भी संगठित रूप से सरकार के विरुद्ध मोर्चा लेने के लिए तैयार हो गये। इस प्रकार देश भर के गावों में वर्ग युद्ध आरम्भ हो गया। इस अभियान में कुलको का सफाया हो गया।

### द्वितीय नियोजन

इसी पृष्ठभूमि में स्तालिन ने प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरम्भ किया। १९२९ तक देश के बहुत से भागों में राजकीय खेती, मशीन और ट्रैक्टर-स्टेशनों का जोरदार संगठन कायम हो चुका था और वे कोलखोजों को बीज, औजार और ट्रैक्टर उधार देने की अवस्था में पहुँच चुके थे। नये वैज्ञानिक तरीकों से उत्पादन में वृद्धि को देख कर प्रोत्साहन मिला। वे भी अपने खेत पर अधिक से-अधिक उपजाने की कामना करने लगे जो उनके पुराने बीज, हल-फाल से संभव नहीं था। अतः १९२८ के आरम्भ से १२ महीने के अन्दर ही कोलखोजों की सख्या दुगुनी हो गयी। कोलखोजों की सफलता को देख कर मध्यम किसान भी इसमें सम्मिलित होने लगे। पहली फरवरी, १९३० में मजदूरी कराना और जमीन को लगान या बटैया लगाने की प्रथा का कानून बना कर अन्त कर दिया गया। अब व्यक्तिगत तौर से अधिक खेती करना संभव भी नहीं था। फलस्वरूप

गाव के सभी किसानों के सामने कोलखोजों को अपनाते का और कोई चारा भी नहीं रह गया। कोलखोज आन्दोलन की प्रगति की रफ्तार तेज हो गयी।

१७ फरवरी १९३५ को द्वितीय अखिल सघ कोलखोज उर्दन्क-कांग्रेस ने कोलखोज सम्बन्धी नियम नये सिरे से बनाये जिसे सोवियत सरकार ने मान्यता दी।

कोलखोज का उद्देश्य गाव के मिहनती किसानों को उनकी इच्छा से कृषि सम्बन्धी सहयोग में सम्मिलित करना है, जिनसे कि वे उपज के साधनों तथा सब के सगठित श्रम के द्वारा अपने लिए बेहतर-से-बेहतर जीवन की सृष्टि कर सकें। सहयोग के सदस्य निम्न बातों की जिम्मेदारी लेते हैं— अपने सहयोग को मजबूत करना, सच्चाई से काम करना, कोलखोज की सम्पत्ति की रक्षा करना, ट्रैक्टर और मशीन को ठीक से सभालना, घोड़ों की ठीक से निगहबानी करना, सोवियत सरकार द्वारा सौंपे गये कर्त्तव्य का पालन करना और कोलखोजी किसानों को मजबूत बनाना। कोलखोजों के सगठन के बाद सहयोग के सदस्यों को अलग करनेवाली जमीन की मंड तोड़ दी गयी और सभी खेत महान क्षेत्र के रूप में सगठित कर लिये गये। ये क्षेत्र सारी जनता की राजकीय संपत्ति हो गयी। सहयोग सघ भी इसे न खरीद-बेच सकता है और न किसी को लगान पर दे सकता है।

जहाँ तक सहकारी और कोलखोजी मिलिकयत का सवध है—सोवियत विधान के अनुसार उन्हें सामूहिक खेती और सरकारी सगठनों पर उनकी तमाम संपत्ति, मवेशियों, औजार, सामूहिक खेती और सहकारी सगठनों के उत्पादन तथा उनके सामान्य मकानों पर उनके अधिकार हैं। कोलखोजों के उत्पादन के साधन के मालिक कोलखोजों के सदस्य हैं। केवल निवासघर, कुछ मवेशियाँ, मुर्गें, फूल और तरकारी उपजाने योग्य आधी हेक्टेयर से एक हेक्टेयर तक जमीन, कुछ औजार ही कोलखोजनिकों के व्यक्तिगत अधिकार की वस्तुयें हैं। अपने उत्पादन के कुछ हिस्सों को निर्धारित मूल्य पर कोलखोज राज्य के हाथ बेच देते हैं। राज्य के प्रति अपने कर्त्तव्य की पूर्ति तथा मशीनों और ट्रैक्टरों के व्यवहार का किराया आदि

चुका देने के बाद कृषि नियमों के अन्तर्गत कोलखोज के सदस्य अपने उत्पादन का मनमाने ढंग से व्यवहार कर सकते हैं।

कोलखोज का प्रबन्ध कोलखोज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। कृषि कानून के नियमों के अनुसार कोलखोजों का प्रबन्ध सदस्यों की साधारण सभा करती है। दो साधारण सभाओं के बीच साधारण सभा द्वारा निर्वाचित बोर्ड और अध्यक्ष के ऊपर कोलखोज के प्रबन्ध का भार रहता है। सौ-सौ डेढ़-डेढ़ सौ काम करनेवाले स्त्री-पुरुषों की सम्मिलित या अलग-अलग टोली पर एक-एक त्रिगेंडियर चुना जाता है। अपने-अपने त्रिगेंड या टोली की देख-भाल करना इनका काम है। फिर रगोइया, वच्चों की देख-रेख के लिए घाइया, लोहार, वडई, गाय, घोड़े, मुर्गियों के अलग-अलग रखवाले चुने जाते हैं। त्रिगेंड को आठ-आठ, दस-दस की छोटी-छोटी टुकड़ियों या लिकों में बाटा जाता है। गोल के भी सरदार और मरदारिन होती हैं। त्रिगेंडियर स्वयं काम नहीं करता। उसके ऊपर मात्र निरीक्षण की जिम्मेदारी होती है, किन्तु सरदार और सरदारिनो को स्वयं काम भी करना पड़ता है। कोलखोज के अधिकारियों में निश्चित तनखाह पानेवाले हैं—अध्यक्ष, प्रबन्धक, वही-खाता रखनेवाले और त्रिगेंडियर। उनको एक दिन के वास्ते डेढ़ दिन की मजदूरी मिलती है। प्रत्येक कोलखोजनिकों को मजदूरी के रूप में उनकी मिहनत के परिणाम और गुण के अनुसार उन्हें कोलखोजों की आय से हिस्सा दिया जाता है। कोलखोजनिकों की इस आय पर किसी प्रकार का कर नहीं लिया जाता। अपनी तरकारी के वगीचे, मुर्गी और मवेशियों ने भी उनकी अतिरिक्त आय होती है।

कोलखोजों और कोलखोजनिकों की सामारिक और सांस्कृतिक उन्नति का आवार ही उनकी सामूहिक संपत्ति और सामूहिक मवेशियाँ हैं। सामूहिक संपत्ति की जितनी उन्नति होती है उमी अनुपात में कोलखोजों के सदस्यों की भी उन्नति होती है। इसलिए कोलखोजों के विकास और उन्नति की ओर प्रत्येक कोलखोजनिकों का विशेष ध्यान रहता है। इस प्रकार सोवियत देश के प्रत्येक किसान ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को सामूहिक स्वार्थ के साथ लगा दिया है। सामूहिक उन्नति में ही वे अपना भी कल्याण मानते हैं।

# भूमि सुधार कानूनों का क्रम

डा० एम० श्रीनिवासन्

इन दिनों, देश की राजनीतिक स्थिति में परिवर्तन के पश्चात् भूमि सुधार कानूनों की महत्ता अधिक बढ़ गई है। किसानों की भूमि-क्षुधा अतृप्त है। स्वतंत्रता के बाद इसके समाधान के हेतु बड़े पैमाने पर प्रयास किया जाना चाहिए था। जमीन्दारी, रयती, बन्दोबस्ती तथा बंदखली, इस चतुर्भुज की परिधि से कृषकों को निकाल कर उनका संरक्षण आज का ज्वलन प्रश्न है। राजनीतिक एवं विविध प्रगति के निमित्त इसको स्थायी तौर पर हल कर देना प्रत्यावश्यक है। अर्थविदो, नियोजको, अध्यापको एवं अन्य भूमि विशेषज्ञों ने योजना आयोग को जो सुझाव दिये हैं, उसका भी यही अर्थ है।

भूमि सुधार में विविध राजनीतिक विचारों का भी ख्याल रखना होगा और विशेषतया उन सबका जिनकी ममता भूमि पर युग-युग से चली आ रही है। गरीब और अमीर समान रूप से भूमि पर पूजा लगाना चाहते हैं, एक की पूजा और दूसरे वर्ग का श्रम। यदि यही किया जाय तब भी समाधान निकालना बड़ा मुश्किल हो जायगा। बन्दोबस्ती, कृषि एवं उत्पादन की सर्वाधिक सुविधा उन्नति की बड़ी शक्तें हैं। आज जब साखान्त का एकदम अभाव है तब परती भूमि का कर्षण सबसे बड़ा साधन होगा जिसे सरकार ही कर सकती है। समाज या समुदाय इस बात में दिलचस्पी लेता है कि भूमि उसे साधन के रूप में मिले जिसके उपयोग से वह अधिक उत्पादन कर सकने में समर्थ हो सके। समता का आदर्श सामने रख कर काम करने के लिए भूमि का वितरण सबसे पहली जरूरत है।

हमारे राज्य का आदर्श है कि जोतनेवाला जमीन का मालिक हो। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य एवं रयत के बीच मध्यस्थ नहीं रहे। १९४६ साल के कांग्रेस चुनावपत्रक में इसे ही प्रमुखता दी गयी थी। १९४५ में मद्रास राज्य में तीन प्रकार की व्यवस्था थी, जमीन्दारी, रयतदारी और इनामदारी, इनके अलावा मालावार जिले में मूली व्यवस्था भी थी। मद्रास राज्य की कुल कृषि योग्य ८०,५३०,००० एकड़ भूमि में रयतों के पास ४८,३८७,००० एकड़ भूमि थी यानी समस्त का ६० प्रतिशत, जमीन्दारों की मातहत १६,४२३,००० एकड़ जमीन थी यानी २० प्रतिशत और इनामदारी भूमि कुल मिलाकर ४,७४६,००० एकड़ यानी ५ प्रतिशत। गेप १०,९७४,००० यानी १३ प्रतिशत में

जंगल, पहाड़ या सरकारी प्रक्षेत्र थे। रयतवारी जमीनों की बन्दोबस्ती नहीं की जाती थी।

## समान वितरण

उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश में जमीन्दारों के कब्जे में अधिक भूमि थी। बम्बई, हैदराबाद, मसूर तथा राजस्थान में भी जागीरदारी और अन्य प्रकार की कई तरह की बन्दोबस्ती बड़े अस्थिर पैमाने व ढग पर चालू थी। अधिकांश राज्यों में जमीन्दारियों का उन्मूलन किया जा चुका है। जमीन्दारी उन्मूलन कानून में भी कई प्रकार की सश्लिष्टताएँ हैं, जैसे, मुआवजा कितना दिया जाय, कितनी किरतो में दिया जाय, किस तरह दिया जाय और छोटे-छोटे जमीन्दारों को पुनःस्थापन-व्यय दिया जाय।

इस दिशा में मद्रास सरकार ने तीन कानून बनाये (१) मद्रास इस्टेट्स (रिडक्शन आंव रेंट्स) ऐक्ट (२) मद्रास इस्टेट्स कम्यूनल फारेस्ट ऐंड प्राइवेट लैंड्स (प्राहिविशन आंव एलाइनेशन) ऐक्ट और (३) मद्रास इस्टेट्स (एवोलिशन आंव जमीन्दारी ऐंड कनवर्शन इन टू रयतवारी) ऐक्ट। ये तीनों कानून १९४९ में ही पास कर दिये गये। पहले कानून से जमींदारी हल्को में रहनेवाले किसान को संरक्षण प्राप्त हुआ और भूमिकरों में कमी हुई और करो का स्तर रयतवारी क्षेत्रों में आ गया। तीसरे कानून के लागू होते ही समस्त किस्म की भूमि पर कृषकों का अधिकार हो गया। सरकार ने जमीन्दारों को १७ १५ करोड़ रुपया मुआवजा देना स्वीकार कर लिया है। मद्रास में मुआवजे की रकम अन्य राज्यों से बहुत कम है। बिहार में जमीन्दारों को तिगुना से बीसगुना तक दिया गया है। उत्तर प्रदेश में जमीन्दारी की आय का आठगुना दिया गया है। आसाम में जमीन्दारी उन्मूलन के अन्तर्गत तिगुना से पन्द्रहगुना देने का निश्चय किया गया है।

इसी प्रकार इन तमाम राज्यों में प्राप्त अधिकारों में भी अंतर है। बिहार में पेड़ों, जंगलों, तालाबों, अन्य जलकर, घाटों, हाटों, बाजारों, खानों तथा खनिजों पर भी अधिकार कर लिया गया है। अन्य राज्यों में जमीन्दारों से जमीन्दारियां छीन ली गयी हैं और बम्बई में तो कानून बनाकर केवल उनके अधिकार कम कर दिये गये हैं।

श्रीर प्राप्त या अधिकृत भूमि की व्यवस्थाओं में भी प्रत्येक राज्य में कुछ-कुछ अन्तर है, जैसे, बिहार में इस्टेटों की व्यवस्था ग्राम पचायतों को दी जायगी और सरकार के भूमि सुधार कानून को स्वरूप देने के लिए भूमि आयुक्त होगा। मद्रास में पैमाइश के अनन्तर भूमि रयतों को दे दी जायगी। उत्तर प्रदेश में जो किसान अपनी लगान के वारहगुना देगे उन्हें भूमिधारी अधिकार प्राप्त हो जायगा। गाव समाज की स्थापना की योजना भी है। गाव समाज के जिम्मे भी कुछ भूमि दी जायगी। ये ही कई प्रकार के विकास कार्यों के लिए उत्तरदायी भी होंगे। मध्य प्रदेश में किसानों को मालिक मालगुजार का अधिकार तिगुना कर दे देने पर प्राप्त होगा। उड़ीसा में भूमि व्यवस्था का भार ग्राम पचायतों या सहयोग समितियों को दिया जायगा। जहाँ कई राज्यों में जमीन्दारियों का उन्मूलन ही श्रेय है वहाँ बिहार तथा उत्तर प्रदेश में भूमि व्यवस्था और ग्रामीण पुनर्निर्माण की दिशा में बड़ा सा लक्ष्य कार्यान्वित किये जाने की ओर कदम बढ़ाया गया है।

### मद्रास का वर्गीकरण

मद्रास में इस्टेटों के लिए निम्न छ प्रकार का वर्गीकरण कर मुआविजे की रकम निर्धारित की गई है :

वर्ग	वार्षिक रकम	रकम का गुना
१,००० तक	.. ..	३०
१,००० से अधिक लेकिन ३,००० हजार नहीं		२५
३,००० से अधिक लेकिन २०,००० हजार नहीं		२०
२०,००० से अधिक लेकिन ५०,००० हजार नहीं		१७।।
५०,००० से अधिक लेकिन १००,००० हजार नहीं		१५
१००,००० से ऊपर	.. ..	१२।।

पाचवें और छठे वर्ग में दरअसल निर्धारण क्रमश पाचवें व छठेके लिए ८,७५,००० और १५,००,००० सालाना के हिसाब से किया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है कि मुआविजे की कुल रकम १७ १५ करोड़ है। यह रकम राज्य की आय का २८ प्रतिशत है। इसकी तुलना में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश का प्रतिशत, क्रमश २२ प्रतिशत, ४७९ प्रतिशत, ३३० प्रतिशत है और उड़ीसा में ८५ प्रतिशत।

सबसे कम निर्धारित आय की रकम पर पुनस्तस्थापन व्यय देने का कोई इन्तजाम नहीं है। अग्रिम मुआविजा की रकम कुछ तो नकद दी जायगी और कुछ ढाड़ के रूप में। कितनी किश्तों में मुआविजे की रकम चुका दी जायगी इसके लिए भी इन्तजाम है। जिनकी वार्षिक आय ३,००० है उन्हें एक वार में ही चुकाया जायगा। ३,००० से ५०,००० वालों को तीन किश्तों में चुकाया जायगा, ५०,००० से अधिकवालों को पाच किश्तों में। बिहार में मुआविजा नकद भी दिया जा रहा है और ढाड़ों में भी। उत्तर प्रदेश में केवल ढाड़ ही दिये जा रहे हैं।

ऊपर जिन भूमि सुधार कानूनों का जिक्र किया गया है वे सुनियोजित नहीं हैं और खड़-खड़ करके स्वीकृत किये गये हैं। अखिल भारतीय पैमाने पर भूमि सुधार कानून बनाने की आवश्यकता थी। देशव्यापी असतोप

या भूमि वुभुक्षा के लिए राज्यव्यापी कानून अधिक कार्यकारी नहीं दीख पड़ता। इन छिट-पुट कानूनों से उत्पादन की समस्या भी थोड़ी प्रगति कर सकती है और किसानों में सतोंप की भावना भी बढ सकती है। आर्थर यंग की कहावत, मान लीजिए, चरितार्थ हो जायगी कि धन के लालच में मनुष्य मिट्टी को सोना बना देता है। अगर सरकारें चाहती हैं कि पुराने जमीन्दारों, जागीरदारों एवं ताल्लुकेदारों के स्थान पर, कानूनों के बावजूद नये स्वार्थ न खड़े हो जाय तब पूरे देश को मद्देनजर रखकर कानून बनना चाहिए था जिसमें एकरूपता तथा सरल व्यावहारिकता होती। जमीन्दारी का उन्मूलन ही पर्याप्त नहीं है। इसके बाद क्या होगा इस ओर अत्यधिक ध्यान देना होगा। यह प्रसन्नता की बात है और सतोंप का विषय भी, कि भारत सरकार ने, अभी हाल में ही, एक भूमि कमीशन की नियुक्ति की है। इस कमीशन का काम होगा विभिन्न राज्यों से नीति का अनुसरण कराना तथा सघीय सरकार को समस्त भूमि समस्याओं के प्रति सही निर्णय लेने को प्रेरित करना। प्रोफेसर पारसन ने सुझाव दिया है कि भूमि समस्या के समाधान के लिए एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना की आवश्यकता है। ऐसे केन्द्र का रहना इसलिए अतीव आवश्यक हो जाता है चूँकि कई गावों के आनुमानिक अव्ययन से ही, बदलती हुई आर्थिक अवस्थाओं की पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। पुन इस बात की जाच भी होनी चाहिये कि अबतक के किये गये भूमि सुधारों के कारण उत्पादन में कितनी प्रगति हुई और किसानों की रचि अत्यधिक उत्पादन की दिशा में कहा तक वर्द्धित हुई है।

### कृषि क्षेत्रीय सबन्ध

कृषि की उन्नति एवं उत्पादन की वृद्धि के लिए समाजगत सबंधों में मृदुलता व स्थायित्व की सर्वाधिक जरूरत होती है। कृषि सुधार तथा भूमि कानून को सफल बनाने के लिए तीन शर्तों को पूर्ण किया जाना चाहिए (१) किसानों को भूमि पर पर्याप्त समय तक अधिकार रहे। अगर राज्य की ओर से आवश्यकता पड़ने पर सामयिक बन्दोबस्ती का नियम भी बनाया जाय तब भी पाच वर्ष पर ही तबदली किसी प्रकार की हो, (२) किसानों को उपज में इतना हिस्सा मिले जिससे उनकी लागत तो वसूल हो ही जाय, इसके अलावा उनके श्रम का प्रचुर मात्रा में बदला भी प्राप्त हो। अभी जो जमीन की दर है उससे मुनाफे का हिसाब ठीक नहीं किया जा सकता, (३) मालिक को, जो अब राज्य सरकार के अधिकारी ही होंगे, उपज या फसल के बटवारे में श्रम के अनुपात को छोड़कर ही हिस्सा मिले।

मद्रास में मालावार टेनेन्सी (अमेंडमेंट ऐक्ट) १९५१ के अनुसार जो मालावार, दक्षिण कनारा तथा नीलगिरि जिले में लागू होता है, रयतों को तीन सुविधाएँ प्राप्त हुई हैं, (१) उचित कर निर्धारण, (२) स्थित जोत का अधिकार और (३) मुफ्त अदला-बदली। नवम्बर १९५२ में जो सबसे महत्वपूर्ण कानून बना वह है तजौर टेनेन्ट्स ऐण्ड पनैयाल ऐक्ट। इस कानून ने बेदखली को एकदम रोक दिया। इस कानून के द्वारा रयतों के साथ पाच माल की अवधि के लिए जमीन बन्दोबस्त की जा सकेगी तथा पनैयालों की निम्नतम मजदूरी निर्धारित हो गई। मालिक और रयत का हिस्सा उपज में ६०।४० का होगा। अन्य सामयिक फसलों में ४।५ का अनु-



पात रहेगा। इस कानून से भूमि सम्बन्धी झगडों का फ़ैसला आसानी से हो सकेगा।

वम्बई सरकार टेनेन्सी ऐण्ड एग्रिकलचरल लैंड्स ऐक्ट पास कर इस दिशा में अग्रगण्य बन गई है। इस कानून के जरिये भूमि कर निर्धारित कर दिये गये हैं तथा वेदखली को एकदम रोक दिया गया है। इसी प्रकार का कानून हैदराबाद सरकार ने भी पास किया है। कुमारप्पा कमिटी ने मालिकों द्वारा बन्दोवस्ती का विरोध किया है लेकिन नाबालिगों, विधवाओं तथा शरीर से अशक्त व्यक्तियों के लिए छूट देने की सिफारिश की है। १९५० में मद्रास सरकार द्वारा नियुक्त सुब्रह्मण्यम् कमिटी ने भी इसका पूर्ण समर्थन किया है। बन्दोवस्ती के आधार सूदृढ एव निश्चित बना देने पर कृषि क्षेत्र के सबध मधुरतम रहेंगे और इस कारण उत्पादन भी बढ़ जायगा। अगर इतना नहीं किया जा सका तब कृषकों की अशान्ति तथा उनके विद्रोह नहीं रोके जा सकेंगे।

### होलिडगो की हदबदी

१९४७ साल में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त जमीन्दारी उन्मूलन आयोग ने और १९४३ के अकाल जाच आयोग ने किसी भी व्यक्ति या परिवार के लिए हदबदी का विरोध किया था। १९५३ के अक्टूबर में कृषि मंत्रियों के सम्मेलन में सघीय कृषि मंत्री डाक्टर पजाब राव देशमुख ने इसी मत का जोरदार समर्थन किया था। ठीक इसके प्रतिकूल कुमारप्पा कमिटी ने सिफारिश की थी कि आर्थिक ईकाइयों के तिगुने क्षेत्रफल के हिसाब से होलिडगो की हदबदी निश्चित की जाय। कुमारप्पा कमिटी ने कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया कि एक आर्थिक ईकाई का क्षेत्रफल कितना होगा। योजना आयोग ने, किन्तु, इसी सिफारिश को स्वीकार कर लिया है। एक अर्थशास्त्रज्ञ की परिभाषा में वह ईकाई आर्थिक मानी जायगी जिसमें एक कृषक परिवार को साल भर काम मिले और उसकी आय से उसके जीवन का निश्चित मान के अनुसार भरण-पोषण हो जायगा। मदी के समय में, अकाल की अवधि में भी उसका काम निवह जाना चाहिए। सितम्बर १९५३ में हैदराबाद सरकार ने एक कानून बनाकर आर्थिक ईकाई की आमदनी ८०० रुपया सालाना का स्वीकार कर लिया है, लेकिन इससे जो कठिनाइया उत्पन्न होगी उसका ख्याल ही नहीं किया गया है। यह कानून कहा तक कारगर होगा इसका नमूना अभी देखा जाने को बाकी है। कोई भी यह नहीं चाहेगा कि कुछ लोगों के पास बड़ी-बड़ी होलिडगों रहें और अधिकांश कृषकों के पास विलकुल कम जमीन हो, फिर भी भूमि आयोग को इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर निर्णय देना चाहिये। यह इतना महत्त्वपूर्ण, गंभीर एव तुनुक विषय है जिस पर तनिक भी असावधानी नहीं बरती जा सकती और न बरदाश्त की जा सकती है।

### जो खेती नहीं करते हैं

जो खेती नहीं करते हैं और अपनी जमीन बराबर बन्दोवस्त कर उसका मुनाफा खाते हैं, उनका बन्दे रहना एक अभिशाप है जिसे जितनी जल्दी हो गठे दूर कर दिया जाना चाहिए। १९४८ के वम्बई टेनेन्सी ऐक्ट के अनुसार भूमि परिवर्तन को रोकना गया है। किन्ती वैसे व्यक्ति से जमीन की विक्री, दान, परिवर्तन या रीज नहीं की जा सकती जो खेती नहीं करता हो। इस पानन की ६३-६६ धाराओं के अन्तर्गत उचित व निर्धारित मूल्य पर

जमीन की विक्री उसीके साथ की जा सकती है, (१) जो उसका अधिकारी हो (२) बगल के खेत का मालिक हो (३) कृषि सहयोग समिति को, जिसका रजिस्ट्रेशन १९२५ के वयवई कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट के अनुसार हो चुका हो (४) उस व्यक्ति को जो खेती-बारी करने को इच्छुक हो और जिसके पास स्थानीय शासन के अधिकारी का प्रमाणपत्र हो।

१९५२ के अगस्त में हैदराबाद में जो कानून बना उसके मुताबिक १९५२ के २१ मार्च तक वेदखल किये गये किसानों को जमीन पर अधिकार दे देने का अधिकार कलक्टरों को दे दिया गया है। इस प्रकार की वेदखल भूमि की विक्री पर भी नियंत्रण लगा दिया गया है। कानून पास होने के दिन से ही किसी भी कचहरी में वेदखली के मुकदमे की सुनवाई नहीं हो सकेगी, ऐसा नियम भी बना दिया गया था और जिस अदालत में इस तरह के मुकदमे चल रहे थे उन्हें खारिज करने का या रोकने का आदेश किया गया था। जो भूमिपति इस कानून की अवहेलना करे और किसान को वेदखल कर दे और जमीन स्वयं अपने कब्जे में रख ले या किसी दूसरे के साथ बन्दोवस्त कर दे उसके लिए सजा बहाल की गई थी, जिसके मुताबिक वेदखल करनेवाले भूपति को छ महीने की कैद की सजा और दो सौ रुपये का जुर्माना किया जायगा। कैद और जुर्माना दोनों की गुजाइश भी कानून में रखी गई है। यह आदेश उन्हीं जमीनों की वेदखली पर लागू होगा जिनका जिक्र हैदराबाद टेनेन्सी एग्रिकलचरल लैंड ऐक्ट (१९५०) में है।

किसानों को वेदखली से रोकने के लिए जितने कानून बने हैं उनमें उत्तर प्रदेश का जमीन्दारी ऐण्ड लैंड रिफार्मस ऐक्ट (१९५१), एग्रिकलचरल रैयतस ऐण्ड टेनेन्ट्स (एक्जीजीशन आब प्रिविलेजेंज) ऐक्ट (मध्य प्रदेश), वर्गादार ऐक्ट (पश्चिम बंगाल १९५०), मैसूर ऐलियेनेट विलेजेंज (प्रोटेक्शन आब टेनेन्ट्स ऐण्ड मिसलेनियस प्रोविजन्स) ऐक्ट १९४९ तथा १९५० में स्वीकृत अजमेर टेनेन्सी ऐण्ड लैंड रेकार्ड्स ऐक्ट प्रमुख तथा कार्यकर हैं। राजस्थान के जागीरदारों के सबध में पंडित गोविन्द वल्लभ पत ने जो फ़ैसला दिया है उससे और इस सब कानूनों से भी इस वृत्ति की जड़ नहीं खोदी जा सकती है। जमीन की बढ़ती हुई भूख के कारण इन कानूनों को अमली जामा नहीं पहनाया जा सकता। इसके अलावा हमारे देश में बढ़ती हुई आबादी का दबाव भी बड़े पैमाने पर है। भूमि पर जो भार है उसे कम करने के लिए सुनिश्चित औद्योगीकरण एव परिवार नियोजन की आवश्यकता है।

### जमीन की सुव्यवस्था

मान लीजिए, बड़े पैमाने पर देश भर के लिए या विभिन्न राज्यों में भूमि सुधार कानून भी बनाये गये, पर, जब तक उससे अत्यधिक उत्पादन का इन्तजाम नहीं किया जायगा तबतक कानूनों का महत्त्व नहीं रह सकता। कृषि से खाद्य की निर्भरता अगर नहीं हो सकी तो इससे बढ़कर बिडम्बना और क्या होगी। लापरवाह और आलसी भूपति के रहने से लाभ क्या? ठीक इसी तरह रैयत भी यदि सर्वाधिक उत्पादन नहीं कर सकते तब उनके साथ भी जमीन की बन्दोवस्ती का विशेष महत्त्व नहीं रह जाता। जमीन राष्ट्र की सम्पत्ति होती है। सरकार को और समाज को समान रूप से तत्पर रहकर उसके जरिये उत्पादन बढ़ाना चाहिए। विधान द्वारा स्वीकृत किसी भी प्रकार के मौलिक अधिकार का अर्थ यह नहीं कि उत्पादन के साधनों

को कतिपय ऐसे लोगों के अधिकार में छोड़ दिया जाय जो उत्पादन की वृद्धि विविध साधनों से नहीं कर सकें। कुमारप्पा कमिटी की रिपोर्ट में लिखा है कि किसान सामाजिक थाती का दृष्टी है। अगर वह ट्रस्ट के दायित्वों को नहीं निवाह सकता तब वह उसे अपने कब्जे में रखने का हकदार नहीं है। ग्रेट ब्रिटेन में १९४७ में जो कृषि कानून (एग्रिकलचरल ऐक्ट) बना था उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि प्रत्येक किसान भूमि के अधिकारी होने के साथ-साथ उसका सेवक भी है। इस कानून की १६वीं धारा के अनुसार यदि सुव्यवस्था नहीं हो सके तब उसे अधिकार-रहित कर दिये जाने का आदेश है। ब्रिटिश एग्रिकलचरल ऐक्ट के आधार पर ही १९४८ में मद्रास सरकार ने भी एक एग्रिकलचरल विल स्वीकृत किया था जो पास नहीं हो सका। उस विल की प्रमुख धाराएं थीं (१) सरकार को यह अधिकार रहे कि आलसी या कम उत्पादन करनेवाले किसानों या मालिकों से जमीन छीन ले, यानी प्रत्येक किसान को उतना उत्पादन करना होगा जितना सरकार चाहती है (२) किसानों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य मिले और पर्याप्त बाजार प्राप्त हो (३) सरकार द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जाय। इसके लिए सरकार समय-समय पर किसानों को विशेषज्ञों द्वारा सलाह दिलावे (४) सरकार को यह अधिकार भी प्राप्त हो कि अनुमानित उत्पादन नहीं होने पर कृषि सरकारी देखरेख में ही कराई जाय। कुमारप्पा कमिटी ने भी कुछ इसी तरह का सुझाव पेश किया था। ग्राम सहयोग समितियां इस दिशा में अग्रसर होकर उचित दिशा में कार्य कर सकती हैं। युद्ध के जमाने में ब्रिटेन में काउंटी वार एग्रिकलचरल कमिटियों ने खाद्य उत्पादन बढ़ाने की दिशा में सर्वोत्तम काम किया था। इस देश में कुछ इसी प्रकार के कार्य करने की जरूरत पट गई है। इस दिशा में सुनिश्चित व दृढ़ कदम उठाये जाने चाहिये। कृषि सबंधी आकड़े निर्भर योग्य नहीं हैं। अतएव भूमि समस्या और उत्पादन की दिशा में ठोस कदम शीघ्र नहीं उठाये जा सकते हैं।

### जमीन की कीमत निर्धारण

आवादी अधिक बढ़ जाने से और यद्ध के बाद की परिस्थितियों से जमीन की कीमत बृहद बढ़ गई है। इसी कारण कृषि का क्षेत्र सतुलित रूप से स्थिर नहीं रह सकता। आस्ट्रेलिया के रूरल रिकशट्रक्शन कमीशन ने इस बारे में पहले ही सरकार को सावधान कर दिया था। एक आदमी अधिक मुनाफा करके अधिकाधिक भूमि पर अधिकार कर लेता था। कुमारप्पा कमिटी ने भूमि के मूल्य स्थिर कर दिये जाने की सिफारिश की है। भूमि आयोग के निर्धारण के बावजूद अगर कोई व्यक्ति जमीन का दाम ज्यादा ले तब ग्रामीण समाज को उस पर निगरानी रखना आवश्यक हो जायगा। देश के किसी भी राज्य में इस प्रकार का कानून नहीं बनाया गया है। १९४८ में स्वीकृत बम्बई एग्रिकलचरल ऐंड टेनेन्सी ऐक्ट के द्वारा भूमि ट्राइब्यूनल उस भूमि का दाम स्थिर कर सकता है जिसपर मुआवजा देना हो, लेकिन इसे बढ़ते हुए दाम रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है।

### चकवन्दी को प्रोत्साहन

भारत में अभी तक ऐसा कोई कानून नहीं है जिसमें भूमि को टुकड़े-टुकड़े और अनाधिक होने से रोका जा सके। १९४८ में बम्बई सरकार ने

प्रिवेंशन आव फॉगमेंटेशन ऐण्ड कसोलिडेशन आव होल्डिंग्स ऐक्ट स्वीकृत कर चकवन्दी का निर्धारण किया था कि स्टैंडर्ड क्षेत्र, उस कानून के द्वारा वह क्षेत्र होता है जिसका उत्पादन अर्थकर व पर्याप्त हो। खेत के किसी भी टुकड़े को लीज देने या बेचने का अधिकार किसान को नहीं प्राप्त है। वह उसी हालत में बेच सकता है जब उसके पासवाला ही खरीद कर अपनी होल्डिंग में मिला ले। सरकार स्वतः चकवन्दी की व्यवस्था राज्य के किसी भी गांव में कर सकती है। कोई किसान अगर इस कानून की अवहेलना या अवमानना करे तब जिलाधीश के आदेशानुसार उसे ज़ुर्माना देना पड़ता है। १९५० में हैदराबाद सरकार ने भी भूमि के विभक्तिकरण रोकने के लिए कानून स्वीकृत किया है। इस कानून के मुताबिक सहयोग कृषि समितियों का रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है।

गत ६ वर्षों में पंजाब में जो कानून इसे रोकने के लिए बनाये गये हैं उसमें किसानों पर दवाव की गुंजाइश भी है। १९५२ के नवम्बर में उत्तर प्रदेश की सरकार ने तेरह सामुदायिक योजना केन्द्रों में चकवन्दी का काम आरम्भ किया। ग्राम पंचायत को भूमि का मूल्य निर्धारित करने का अधिकार मिला है। अगर किसी प्रकार की शिकायत ग्राम पंचायत से किसी को हो तब उसकी मुनवाई जिलाधिकारी के पास होती है। इस स्कीम के लिए जो व्यय होगा उसकी पूर्ति प्रति एकड़ चार रुपये किसानों से लेकर की जायगी। चकवन्दी कानून वहा १९४० में ही स्वीकृत कर लिया गया था लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं हुआ था और न उस दिशा में कार्य ही हुए थे। पेप्सु में भी इस प्रकार के कानून पास किये गये हैं जिसके मुताबिक दस वर्षों के अन्दर समस्त राज्य में चकवन्दी पूरी कर दी जा सकेगी। केवल मद्रास सरकार ने इस दिशा में अभी तक कोई कानून पास नहीं किया है, हालांकि ३५ वर्ष पहले, डाक्टर गिलवर्ट स्लेटर ने इस आशय की सिफारिश की थी।

इस टुकड़े-टुकड़े होने की गति को क्यों नहीं रोकी जा सकती है ? इसका कारण है (१) ट्रेनिंग प्राप्त अनुभवी अफसरों की कमी (२) मिट्टी का अन्तर जिससे उपज में पर्याप्त विभिन्नता रहती है (३) किसानों को अपनी जमीन के छितराये हुए टुकड़ों में भी मोह रहना है (४) किसी प्रकार के सत्तामूलक अधिकार का बलपूर्वक लागू करना हमारे प्रजातंत्र का आधार नहीं है (५) भूमि पर ही पूरी आवादी के पोषण का भार है। परिवार नियोजन तथा औद्योगिककरण इस समस्या को नहीं समाधान दे सकते हैं, ऐसा बहुतायत अर्थविदों का विचार है। पश्चिमी सभ्यता के फलस्वरूप हमारे सयुक्त परिवार प्रायः समाप्त हो गये हैं। ऐसी स्थिति में कानून पास किये जा सकते हैं।

### भूमि का उचित उपयोग

सबसे महत्वपूर्ण कदम उत्पादन बढ़ाने की दिशा में है। ऐसा करने से खाद्योत्पादन में जो मजबूती कठिनाई है वह खत्म हो जायगी। १९५० के नितम्बर में मद्रास सरकार ने मनी परती भूमि के उपयोग के निमित्त एक आदेश जारी किया। यह आदेश १९४६ के एग्रेसिवल मप्लांटज ऐक्ट (टेम्पोररी पावर्स) के अन्तर्गत था। इसका नाम है मद्रास लैंड यूटिलिजेशन आर्डर। इस आदेश के द्वारा जिलाधिकारियों को यह अधिकार प्राप्त हो

गया कि वे किसी भी परती भूमि के मालिक को उस जमीन में खेती करने को निर्देश दे सकता है, चाहे वह स्वयं खेती करे या किसी को बन्दोवस्त करके खेती करावे। खाद्यान्न में सभी प्रकार के अन्न सन्निहित किये गये थे। अगर किसान या भूमिपति इस आदेश के मुताबिक काम नहीं करे तब जिलाधिकारी को अधिकार था कि वह उस जमीन की बन्दोवस्ती दूसरे के साथ नीलाम करके कर दे। ऐसी बन्दोवस्ती तीन वर्ष के लिए की जा सकती है। जो व्यक्ति बन्दोवस्ती लेगा उसे भी उपज बढ़ानी होगी। अगर वह भी उपज नहीं बढ़ावे तब उसके लिए भी दंड की व्यवस्था है। सरकारी लागत वसूल हो जाने पर उपज उस कृषक को दे दी जाने की व्यवस्था उस आदेश के अन्दर है। मध्य प्रदेश का ग्रोथ आव फूड क्राफ्ट ऐक्ट इस दिशा में अच्छा कारगर हुआ है। अगर इस दिशा में उचित कदम नहीं उठाये गये तब बाजारों की अनिश्चितता एवं भूमि उद्योगों का, खाद्यान्नों के दामों को, निश्चितरूपेण नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसका परिणाम यह होता है कि यहाँ खाद्यान्नों का उत्पादन ठीक से नहीं हो सकता। गुजरात जिले में तमाखू का उत्पादन किया जाता है, बंगाल में धान के खेतों में जूट बोया जाता है और कोयम्बटूर में कम्बोडिया की रूई उपजाई जाती है। ऐसी दशा में समाजगत कल्याण का कार्य कतिपय लाभ करनेवालों के हाथ में चला जाकर द्रष्टव्य परिस्थिति में पड़कर खटाई में पड़ जाता है।

### परती भूमि में खेती

देश में खाद्य की कमी के कारण कृषि की वृद्धि एवं प्रसार जरूरी है। मध्य भारत में सेंट्रल ट्रेक्टर एसोसियेशन ने कास से भरी जमीन में

खेती करना शुरू कर दिया है। यह एक अच्छा उदाहरण है। इस देश में परती भूमि का अनुमान प्रायः ३०० लाख एकड़ से ९०० लाख एकड़ तक है। मद्रास में इनके उपयोग के लिए कानून स्वीकृत किया गया है। १८ अगस्त १९५२ को पेंप्सू में परती भूमि पर कृषि के निमित्त दो आर्डिनेंस स्वीकृत किये गये। इस कानून द्वारा सरकार को उस भूमि पर अधिकार करने का हक है जो दो या तीन वर्ष तक परती पड़ी रह जाती हो। ऐसी जमीनों की बन्दोवस्ती बीस वर्ष के लिए कर दी जाती है। जिनकी भूमि ली जाती है उन्हें मुआविजा दे दिया जाता है। लेकिन सरकार अमूमन दस वर्ष से अधिक ऐसी भूमि पर अपना कब्जा नहीं रख सकती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि अगर परती भूमि का उपयोग कर लिया गया तब भविष्य में उसकी किस प्रकार व्यवस्था पूर्णरूपेण की जायगी। कुछ लोग कहते हैं कि सहयोगिता के आधार पर कृषि की जाय। लेकिन सघीय सरकार ने ऐसा निश्चय किया है कि ऐसी भूमि की बन्दोवस्ती शरणार्थियों के साथ की जाय। फिलहाल अधिकांश लोग सहयोगिता के आधार पर ही कृषि के पक्षपाती हैं। बम्बई सरकार ने इस दिशा में कानूनी प्रयास भी आरम्भ कर दिया है।

इस सरसरी दृष्टिकोण से यह पता चलता है कि भूमि समस्या का समाधान उलझनपूर्ण है तथा सरकार के अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की सिफारिशें भी भिन्न-भिन्न हैं। इस ओर सम्मिलित प्रचेष्टाए की जानी चाहिए। इसका समाधान बहुत दिनों से अपेक्षित था। तब भविष्य में समाज शान्तिपूर्ण, सुखद एवं समृद्धिपूर्ण हो जायगा।



## भारत में भूमिस्वत्व

प्रो० जगन्नाथ प्रसाद मिश्र

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हम पाते हैं ' प्रजा सुखे सख राज्ञ , प्रजाना च हिते हितम् । नात्म प्रिय हितं राज्ञ , प्रजानतु प्रिय हितम् । प्रजा के सुख में राजा का सुख है, और प्रजा के हित में राजा का हित है । अतः राजा अपना हितचिन्तक न होकर प्रजा का हितचिन्तक बने । प्राचीनकाल के अन्यान्य ग्रन्थों, काव्य-पुराणों में सर्वत्र यह निर्देश किया गया है कि "राजा प्रजा को अपनी सन्तान के समान समझेगा ।" इस प्रकार के अनेक पौराणिक उपाख्यान मिलेंगे जिनमें राजा और प्रजा के स्वार्थ को समान सूत्र में ग्रन्थित बताया गया है । प्रजा की उन्नति और अवनति के ऊपर राजा की उन्नति और अवनति निर्भर करती थी । राजा प्रजा का निर्मम भाव से शोषण नहीं करता था । प्रजा से कर ग्रहण करके राजा उसका उपयोग सार्वजनिक कल्याण में करता था । कौटिल्य ने लिखा है पुष्पोद्यान का माली फूल के प्रत्येक पेड़ से फूल प्राप्त करने के लिये क्या करता है ? हर पेड़ को वह ठीक समय पर सींचता है, उसकी जड़ की मिट्टी को खोद कर उसमें खाद डालता है, अपनी सन्तान के समान हर पेड़ का पालन करता है, और फूल तोड़ने के समय भी इस बात पर ध्यान रखता है कि फूल तोड़ने से कोई पेड़ शोभाश्रीविहीन न बन जाय । प्रजा से कर ग्रहण करते समय राजा को भी इसी नीति का अनुसरण करना चाहिये । कर का निर्धारण इस रूप में होना चाहिये जिसमें प्रजा का सर्वस्वान्त न हो जाय ।

प्राचीन हिन्दू राजस्व के आर्थिक क्षेत्र में ग्रामों का महत्त्व सबसे बढ़कर था । ग्रामों में मूलतः कृषिजीवी रहा करते थे । अर्थ नीति का मूल भूमि और उसके अधिकार पर केन्द्रित था । इसलिए स्वभावतः यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि हिन्दू राज्य व्यवस्था में भूमि पर किसका अधिकार होता था ? मीमांसा ग्रन्थों में लिखा है कि सम्राट का इस पृथ्वी पर कोई स्वत्व नहीं होता था—और राजा को भूमि पर कोई अधिकार नहीं होता था । राजा दुष्टों का दमन एवं शिष्टजनों का पालन करेगा और इसके लिए कृषकों से कर ग्रहण करेगा, और अपराधियों को दंड देगा । किन्तु भूमि का मालिक वह नहीं है । जैमिनि ने लिखा है—'इस पृथ्वी पर

सबका समानाधिकार है ।" कोलब्रुक ने लिखा है, "हिन्दू मीमांसा में यह कहा गया है कि यह पृथ्वी राजा की संपत्ति नहीं है, यह उसकी है जो परिश्रम करके उपाजन करता है ।" श्रेष्ठ मीमांसक शबर ने अपनी टीका में कोलब्रुक का समर्थन किया है । शबर कहता है "राज्य की रक्षा के लिए सम्राट कुछ परिमाण में उत्पन्न शस्य का अंश ग्रहण कर सकता है, किन्तु वह भूमि का स्वामी नहीं है ।" मेघातिथि ने मनु संहिता के अपने भाष्य में लिखा है "राजा प्रजा से जो कर ग्रहण करता है वह राज्य-रक्षा या प्रजा की जान माल की रक्षा के लिए, किन्तु इससे भूमि पर उसका अधिकार सिद्ध नहीं होता ।" नीलकण्ठ ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ व्यवहार मयूस में इस विषय का विवेचन विशद भाव से किया है । कात्यायन, मिश्रमिश्र, माधवाचार्य तथा अन्य शास्त्रज्ञों के वचन भी इसके प्रमाण में उपस्थित किये जा सकते हैं । बौद्ध जातक तथा शिलालेखों से भी यह प्रमाणित होता है कि भूमि का मालिक राजा नहीं होता था । मैकडोनल और कीय ने लिखा है कि वैदिक युग के आरम्भ से ही भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार विद्यमान था—*"It is a fair conclusion, from the evidence that the system of separate holdings already existed in early vedic times"* (Vedic Index I P 211) ऐतिहासिक Bury ने लिखा है कि प्राचीन ग्रीस में भूमि समग्र देशवासियों की संपत्ति समझी जाती थी व्यक्ति विशेष की नहीं.—*The land belonged to the whole kin, but not to any particular member"* (J B Bury History of Greece) Indian Taxation enquiry Committee की रिपोर्ट में इस विषय पर विशेष छानबीन करके यह मत व्यक्त किया गया है कि हिन्दू और मुसलमान राजत्व में किसी भी समय राजा या बादशाह या नवाब ने भूमि पर अपने एकपक्ष अधिकार का दावा नहीं किया था । अपने मत के समर्थन में उन्होंने वर्म्बई हाईकोर्ट का एक निर्णय उद्धृत किया था :—*"The review of the authorities leads us to the conclusion arrived at also (after careful discussion*

of the question) by prof H R Wilson that the proprietary right of the sovereign derives no warrant from the ancient laws or institutions of the Hindus”

मुसलमानों के शासनकाल में भी भूमि पर कृपको का ही अधिकार था। इस्लामी कानून के विशेषज्ञ कर्नल गैलवय का मत उक्त कमीशन की रिपोर्ट में इस प्रकार उद्धृत किया गया है —“जमीन असल में किसानों की है। जब तक वह नियमित रूप से लगान चुकाता रहेगा तबतक कानून को उसके स्वत्व में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं होगा। यदि वह लगान नहीं चुकायगा तो उसकी जमीन पर दखल की जा सकती है। वर्तमान अर्थनीति के अनुसार राज्य किसी शासक की निजी संपत्ति नहीं समझा जाता। मध्ययुग में शासन जिस प्रकार अपने राज्य की निजी संपत्ति समझ कर उसे बंधक रख सकते थे, बेच सकते थे या उसका बटवारा कर सकते थे वैसे अब नहीं कर सकते। जैसा कि J W Garner ने अपनी पुस्तक “Introduction to Political science” में लिखा है:—The territorial domain of the state is not the property of the state or of any ruler; the patrimonial state in which the monarch was considered the ultimate owner of the land is a thing of the past Rulers can no longer, as they, often did in mediæval times, sell, pawn, give away or partition their domains as though they were private property”

कौटिल्य के अर्थशास्त्र से मालूम होता है कि राज्य की ओर से प्रजा को नाना प्रकार की सुविधाएँ प्रदान की जाती थी। राजा को भूमि के ऊपर कर लगाने का अधिकार था, प्रजा जब तक भूमि कर चुकाती रहती थी तबतक भूमि पर उसका स्वत्व बना रहता था। राजा किसी भी कृषक को अन्यायपूर्वक जमीन से बंदखल नहीं कर सकता था। कौटिल्य ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि कृषि योग्य भूमि प्रत्येक करदाता को देनी चाहिये। कोई व्यक्ति यदि अनुर्वर भूमि को उर्वर बनावे तो राजा बलपूर्वक उस भूमि पर अपना अधिकार नहीं कर सकता। जो लोग स्वयं भूमि नहीं जोतते उनसे भूमि लेकर राजा उपर्युक्त व्यक्तियों को देगा, या वह जमीन ग्राम्यश्रमिक (ग्राम भृत्यकम्) अथवा व्यवसायी द्वारा जोती जायगी। कौटिल्य ने यह भी लिखा है कि जिन खेतों के मालिक ठीक तरह से खेती करने में असमर्थ हों, उनके लगान में कुछ कमी की जा सकती है। नियमित रूप से लगान चुकानेवाले कृषकों को राज्य की ओर से बीज, अन्न, बैल आदि पशु प्रदान करके सहायता पहुँचायी जायगी। हाँ, राजा इस बात पर अवश्य ध्यान रखेगा कि राजकोष को क्षति न हो।

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि ग्राम से राजस्व संग्रह करने का मूल उपादान भूमि था। राजा कर के रूप में एक चतुर्थांश और जलकर के रूप में भी उतना ही पाने का अधिकारी था। जितनी जमीन की मिर्चाई होती थी उतना विश्वाम योग्य विवरण रखा जाता था। कृषिजीवियों को एक पचमास से लेकर एक तृतीयाश या चतुर्थांश

जलकर (उदकभागम्) देना पड़ता था। मनु ने लिखा है कि भूमि की उर्वरता और उसे आवाद करने में जितना खर्च पड़े उसके अनुसार राजा एक छटा भाग से लेकर बारहवा भाग तक कर ले सकता है (मनु संहिता अध्याय ७ और महाभारत, शान्तिपर्व)। राजा और प्रजा दोनों कृषि से लाभ उठा सके ऐसा विचार करके प्रजागण को अणुमात्र भी क्षति पहुँचाये बिना जोक जिस तरह रुधिर पान करता है, वछडा जिस तरह थन का दुग्ध पान करता है और भौरा जिस तरह फूलों का मधुपान करता है उसी प्रकार थोड़ा-थोड़ा करके राजा प्रजा से कर ग्रहण करेगा।

उपर्युक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि भारत में अति प्राचीन काल से ही कृपको से राज्य खेती की पैदावार का एक हिस्सा कर के रूप में ग्रहण करता था। यह हिस्सा जमीन की उर्वरता या अनुर्वरता के हिसाब से और जिस परिमाण में कृषि करने में श्रमशक्ति लगती थी इसके अनुसार घटता-बढ़ता था। कहीं बारह भाग का एक भाग और कहीं छ भाग का एक भाग कर दे ना पड़ता था। युद्धकाल में यह बढ़कर एक चतुर्थांश भी हो जाता था। ज्यो-ज्यो जन सख्या में वृद्धि होती गयी और आवादी जमीन का परिमाण बढ़ता गया त्यो-त्यो पैदावार के एक अंश के रूप में लगान वसूल करना अत्यन्त कठिन होता गया। इन्ही सब कारणों से अन्य रूपों में कर ग्रहण करने की चेष्टा होने लगी। अन्ततः खेत की पैदावार का एक अंश देकर लगान चुकाने की प्रथा क्रमशः मुद्रा में परिवर्तित होने लगी और मुसलमानों के शासनकाल में सर्वत्र मुद्रा का प्रचलन हो गया।

तैमूर के समय में मुद्रा के रूप में राजस्व ग्रहण करने की प्रथा प्रवर्तित हुई। इसके बाद शेरशाह ने इस ओर कुछ ध्यान दिया। किन्तु शेरशाह बहुत समय तक राज्य नहीं कर सका। इसलिए उसका प्रयास किसी तरह सफल नहीं हुआ। अकबर के शासन काल में उसके मंत्री टोडरमल ने प्रजा से भूमि कर वसूल करने के लिए भूमि-व्यवस्था में सुधार किया। विभिन्न प्रकार की भूमि की उत्पादिका शक्ति की भलीभाँति परीक्षा करके उसका वर्गीकरण किया गया। इसके बाद कुल पैदावार का एक तिहाई भाग कर के रूप में निर्धारित किया गया। नकद या जिन्स के रूप में भूमि कर चुकाया जा सकता था। मुद्रा के रूप में कर चुकाने पर गत नौ वर्षों की फसल का औसत दाम निर्धारित कर दिया जाता है और इसके अनुसार कर देना पड़ता था। प्रति नौ वर्ष के बाद कर का परिमाण निर्धारित किया जाता था। टोडरमल की इस प्रथा के फलस्वरूप राज्य के साथ प्रजा का प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित हुआ और दोनों के बीच कोई मध्यवर्ग अर्थात् बीच का दलाल नहीं रह गया। प्रत्येक ग्राम में प्रत्येक किसान से प्रत्यक्ष रूप में कर वसूल किया जाता था। जमीन कर किसी का जन्मगत अधिकार नहीं माना जाता था।

मुसलमानों ने पुरातन समाज की व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया। ग्रामीण समाज के आचार-विचार एवं रीति-नीति में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। फिलिप्स साहब ने अपने टैंगोर ला लेक्चर्स में इस बात का उल्लेख करते हुए लिखा है कि इस देश में मुसलमानों का शासन प्रतिष्ठित होने पर जो लोग कर वसूल करते थे वे कभी जमीन पर अपने मालिकाना हक का दावा नहीं करते थे। उन्होंने केवल कर वसूल करने का अधिकार अपने लिए रखा था।

इसके बाद जब अंगरेज इस देश के शासक हुए उन्होंने उत्तर भारत में सामन्त प्रथा का प्रचलन देखकर भूमिस्वत्व के सम्बन्ध में भ्रान्त धारणा अपने मन में कायम कर ली। उन्होंने यह मान लिया कि जो बड़े-बड़े जमींदार जमीन पर दखल जमाए हुए थे उनका अधिकार उस पर कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। जमीन्दारों का भूमि पर किस प्रकार अधिकार हुआ इसके सम्बन्ध में उन्होंने कोई अनुसन्धान नहीं किया। उन्होंने यह समझ लिया कि राज्य ही सदा से जमीन का मालिक रहा है। अंग्रेजों की यह इतनी बड़ी भूल थी जिसके कारण लाखों मनुष्य भूमि स्वत्व से वंचित हो गए। सन् १७९१ ई० में सर ब्राउटन राउस ने लिखा था कि जमीन के ऊपर राज्य का कोई अधिकार नहीं है, और कम्पनी को देशी राजाओं से केवल राज्य शासन का अधिकार मिला है भूमि या संपत्ति पर अधिकार नहीं मिला है। अध्यापक राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक "लैंड रिफार्म इन इंडिया" में लिखा है कि "भारत में भूमि गोष्ठी या परिवार के अधिकार से थी, और कभी वह राजा की संपत्ति नहीं मानी गयी।" सन् १८१२ में सिलेक्ट कमिटी ने अपना यह मन्तव्य दिया कि जमीन्दार किसी समय भी जमीन के मालिक नहीं थे और न हो सकते हैं। उनका काम केवल जमीन की देखभाल करना और कर वसूल करना रहा है। सन् १७९२ में कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स की ओर से जो आदेश जारी किया गया था उसमें भी यह कहा गया था कि जमीन्दारी एक आफिस मात्र है। कोर्ट का काम होगा जमीन्दारी का कर्तव्य मार्ग निर्धारित कर देना और कर्तव्य में त्रुटि होने पर नाजिम के हुक्म से उन्हें बर्खास्त कर देना। स्वयं लार्ड कार्नवालिस ने भी कहा था कि "जमीन्दार स्वेच्छा से लगान में वृद्धि नहीं कर सकते थे।"

सन् १७९३ ई० में भारत के तत्कालीन बड़े लार्ड कार्नवालिस ने कलम के जोर से जमीन के असल मालिक की भूमिस्वत्व से वंचित कर दिया। उस दिन से ही कृपकों की दुःख-दुर्दशा का सूत्रपात हुआ जो केवल कर के मालिक थे वे जमीन के मालिक बन गये। जमीन्दारी प्रथा के प्रवर्तक के रूप में अंग्रेज सरकार ने अंग्रेज शासन को एक ऐसे कलक से कल्पित किया जिसका मोचन इतने दिनों के बाद स्वदेशी सरकार द्वारा हुआ है। इसके इतिहास की आलोचना करने से पता चलता है कि जब ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारत का शासन भार ग्रहण किया तब उसने देखा कि देश में अच्छी शासन-व्यवस्था नहीं है, गृह-विप्लव और अन्तर्विरोध के कारण देश की शान्ति नष्ट हो गयी है और सर्वत्र अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है। प्रजा यथासमय लगान नहीं चुकाती थी और जो लोग लगान वसूलने के काम में नियुक्त थे वे अपने कर्तव्यपालन में दत्तचित्त नहीं थे। प्रजा स्वेच्छा से जितना लगान देती थी उसे वे राजकोष में जमा कर देते थे। वाकी लगान वसूल करने के लिए वे प्रजा के साथ बलात्कार नहीं करते थे। राजस्व ठीक तरह से वसूल नहीं होने के कारण शासन कार्य में बाधा पहुँच रही थी। मुसलमानी शासन काल में लगान वसूल करने के लिए हर परगने में एक-एक कर्मचारी नियुक्त था। कम्पनी के समय में भी आरम्भ में यही व्यवस्था थी, किन्तु लगान की वसूली ठीक तरह से नहीं होने के कारण कम्पनी ने इस नीति में परिवर्तन कर दिया और लगान वसूल करने के लिए ठीकेदारों को बहाल किया। उन्हें निर्देश दिया गया कि कम्पनी

की निर्दिष्ट राजस्व चुका देने के बाद वे चाहे जितना प्रजा से वसूल कर सकते हैं। यह अतिरिक्त राजस्व उनकी अपनी संपत्ति होगा। यह नियम कुछ दिनों तक जारी रहा। बंगाल, विहार, उड़ीसा की दीवानी पाने के पांच साल बाद कम्पनी की असलदारी में भीषण अकाल पड़ा। इस अकाल में अन्नाभाव के कारण देश की जनसंख्या में तीन भाग में दो भाग मनुष्य कालकवलित हुए। किन्तु कम्पनी के राजस्व में कोई कमी नहीं हुई। कुछ समय के बाद जब लार्ड कार्नवालिस बड़े लाट हुए उन्होंने देखा भूमि का राजस्व ग्रहण करने में जो त्रुटि है वह त्रुटि तब तक दूर नहीं होती जब तक राज्य की श्रीवृद्धि नहीं हो सकती। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि राज्य की श्रीवृद्धि की अपेक्षा वणिकों के स्वार्थ की वृद्धि ही मुख्य अभि-प्राय था। कम्पनी के समय में जो सब ठीकेदार और तहसीलदार थे, उनका जमीन के ऊपर कोई अधिकार नहीं था। जमीन्दारियों के प्रति तहसीलदारों का मोह नहीं होने से वे लगान वसूल करने में भी विशेष तत्परता नहीं दिखायेंगे ऐसा सोचकर कार्नवालिस ने सन् १७९३ में दमामी बन्दोबस्त या चिरस्थायी प्रवन्ध प्रचलित किया जिसके फलस्वरूप जमीन के असली मालिक के बदले लगान वसूल करने वाले ठीकेदार जमीन के मालिक बन गये। जो लहू को पसीना बनाकर खेतों में फसल उपजाते थे उनका भूमि पर कोई स्वत्व नहीं रह गया। कानून के बल पर जमीन्दार यदि चाहे रैयत को जमीन से बंदखल कर सकता था। जमीन्दार सरकार को कितना राजस्व देगा यह तो निर्दिष्ट कर दिया गया किन्तु जमीन्दार को कानून द्वारा यह अधिकार दिया गया कि वह लगान में वृद्धि कर सकता है। सन् १७९३ साल के कानून की आठवीं धारा में लिखा था कि गवर्नर जनरल प्रजा के कल्याण के लिए जब जैसा कानून बनाना आवश्यक समझेगा, बना सकेगा। किन्तु कानून बनाने की वह आवश्यकता कभी नहीं समझी गयी। १८१९ में कोर्ट ऑफ डाइरेक्टर्स ने जो पत्र लिखा था उसमें भी कहा गया था "चिरस्थायी प्रवन्ध के बाद इतने वर्ष बीत गये, फिर भी प्रजा के स्वार्थ की रक्षा के लिये जो अधिकार हमने हाथ में रखा था, उसके अनुसार आज तक कोई काररवाई नहीं हुई।" अंग्रेजों राज के अन्त तक नहीं हुई, ऐसा यदि हम कहें तो अनुचित नहीं होगा।

कृत्रिम उपायों से जमीन्दारों को इस प्रकार जमीन का मालिक बना देना एक अत्यन्त अन्यायपूर्ण कार्य था। और इस कानून में इतनी शीघ्रता की गयी कि जमीन्दारों के साथ जमीन बन्दोबस्त करने के पहले जमीन की पैमाइश, उर्वरता के अनुसार जमीन का वर्गीकरण, किम जमीन के ऊपर किस व्यक्ति का किम रूप में अधिकार चला आता है इन सब आवश्यक बातों पर कुछ भी विचार नहीं किया गया। उस समय के कुछ अधिकारियों ने यह कॅफियत दी थी कि जमीन की पैमाइश के लिए अच्छे कर्मचारियों का अभाव था, गावों में पहुँचने के रास्ते और घाट नहीं थे। किन्तु इस प्रसंग में हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि टोडरमल के समय में ये सब असुविधाएँ कम नहीं थी, किन्तु इनके बावजूद उन्होंने भूमि का वर्गीकरण करके उसकी उत्पादिका शक्ति के अनुसार कर निर्धारण किया था। असल बात यह थी कि उस समय के अंगरेज अधिकारियों को यह आशंका थी कि धन-संपत्ति सम्बन्धी भीतरी मामलों में दखल देने से जमीन्दार विलकुल विगड जायेंगे, और अंगरेजी राज की रक्षा के लिए इन

जमीन्दारों को सन्तुष्ट रखना आवश्यक है। इसीलिए ऐसा किया गया। गरीब किसानों की स्वार्थ-रक्षा की चिन्ता किसी को नहीं थी। उनकी अवस्था क्रमशः शोचनीय होती गयी और जमीन्दार उनके साथ मनमाना व्यवहार करने लगे। बेंडन पावल ने अपनी पुस्तक "लैंड सिस्टम" में लिखा है "विना आगा-पीछा किये और किसी तरह की जाच-पडताल न करके, जमीन के ऊपर किसका स्वत्व अधिक है इस बात पर विचार किये बिना चिरस्थायी प्रबन्ध प्रचलित कर दिया गया। इस व्यवस्था से जितनी क्षति हुई है उतनी क्षति किसी अन्य व्यवस्था से हुई है या नहीं इसमें सन्देह है।"

चिरस्थायी प्रबन्ध के प्रवर्तित होने के फलस्वरूप किसानों का भूमि पर जो अधिकार अत्यन्त प्राचीन काल से चला आ रहा था वह नहीं रहा और अत्याचारी जमीन्दारों की दया के ऊपर उनका भाग्य निर्भर करने लगा। लगान की दर बहुत बढ़ गयी, और जमीन्दारों ने अत्यन्त गैरकानूनी ढंग से लगान वसूल करना शुरू किया। मनु का धर्म शास्त्र यदि उस समय प्रचलित होता तो इन सब अत्याचारी जमीन्दारों की जमीन सरकार द्वारा जब्त कर ली जाती। कर जाच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था—जिस समय चिरस्थायी प्रबन्ध प्रवर्तित किया गया, उस समय कोर्ट आफ डाइरेक्टर्स की इच्छा थी कि जो सब किसान इस व्यवस्था के फलस्वरूप भूमिस्वत्व से वंचित कर दिये गये हैं उन्हें वे सब अधिकार लौटा दिये जायेंगे और उनकी रक्षा की जायगी। किन्तु १७९३ की व्यवस्था में किसानों का अधिकार स्वीकार करना तो दूर रहा, क्रमशः १७९९ और १८१२ ई० के कानून द्वारा उन्हें संपूर्ण रूप से जमीन्दारों की मुट्ठी में डाल दिया गया। लगान की दर चाहे जितनी बढ़ जाय, उसे नहीं चुकाने पर किसान की जमीन जब्त कर ली जा सकती थी, यहाँ तक कि उसे जेलखाने की सजा दी जा सकती थी। बंगाल सरकार की १८७२-७३ ई० की रिपोर्ट में यह स्वीकार किया गया है कि "जमीन्दार अपनी विलासिता अथवा अनावश्यक व्यय की पूर्ति के लिए यथेष्ट भाव से किसानों से लगान वसूल करते हैं। जमीन्दारों के कर्मचारी और नायबों का खर्च रैयतों को ही चुकाना पड़ता है—आयकर उनसे ही वसूल किया जाता है। डाकखाने का कर, हाथी का खर्च, कचहरी का मकान और माल-गुजारी की रसीद का खर्च, मामला दायर करने और वकील का खर्च सब उन्हें ही देना पड़ता था। किसी उत्सव या घर्मानुष्ठान में, किसी उत्तराधिकारी के जन्म या विवाह के अवसर पर रैयत से मोटी रकम वसूल की जाती थी। जमीन की विक्री बिना मालिक की मजूरी के नहीं हो सकती थी। जमीन की विक्री होने पर खरीदार को नजराना देना पड़ता था। बिना नजराना दिये मालिक के सिरिस्ते में उसका नाम दर्ज नहीं हो सकता था। रैयतों के आपसी झगड़ों को निवटा देने, किसी मजिस्ट्रेट या दारोगा के गाव में आने पर अथवा गाव में दगा-फसाद होने पर रैयतों से जुर्माना वसूल किया जाता था। यदि किसी रैयत का कोई पालतू पशु किसी दूसरे के गेन में फमल को क्षति पहुँचाता था तो इसके लिए भी उसे मालिक को अर्धदंड देना पड़ता था। इस प्रकार गैर कानूनी ढंग से मालिक रैयतों से अग्रदाव वसूल करते थे। जमीन्दारों प्रथा के साथ ये अग्रदाव अविच्छेद्य रूप में जुड़े हुए थे। हर जमीन्दार के नीचे एक नायब, उसके नीचे एक

गुमास्ता और उसके नीचे प्यादा होता था। नायब बिना सूचना दिये ही गाव में पहुँच जाता था। उसके पहुँचने पर प्रत्येक किसान से जो लगान देता था, व्यक्ति पीछे एक रुपया वसूल किया जाता था। जो सब प्यादा या सिपाही जमीन्दार की ओर से लगान का तकाजा करने जाते थे या जो रैयत कचहरी में बुलाये जाते थे, वे रैयतों से दैनिक पाच-छ आने वसूल करते थे।"

इस प्रकार लार्ड कार्नवालिस ने जो आशा की थी कि जमीन्दारी प्रथा के प्रवर्तित होने पर किसानों के धन-जन की रक्षा होगी, उनकी उन्नति होगी वह आशा सर्वथा निराशा में परिणत हुई यह ऊपर की रिपोर्ट से स्पष्ट है। जितने कानून बने सब जमीन्दारों की स्वत्व-रक्षा के लिए। इसलिए जमीन्दारों ने जमीन की उन्नति आदि के सम्बन्ध में कभी माथा-पच्ची नहीं की। इधर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। विलायत की भूमि प्रथा कुछ अशोभे यहाँ प्रचलित हुई। जमीन्दार स्वच्छा से लगान की दर बढ़ाने लगे और नाना प्रकार के अवैध उपायों से कर बँटा कर वसूल करने लगे। मुसलमानों के शासनकाल तक जो ग्राम पंचायत गणतांत्रिक आधार पर चल रही थी उसका मूल सूत्र था जमीन के ऊपर किसानों का मालिकाना हक। किन्तु अब पंचायत प्रथा दुर्बल होने लगी, समाज व्यवस्था में शिथिलता आने लगी और इसके साथ-साथ जमीन के ऊपर किसानों का अधिकार नष्ट होने लगा।

सन् १८१२ ई० के अधिनियम ५ के अनुसार जमीन्दार स्वच्छा से जमीन का लगान बढ़ाने लगे और रैयतों को बाध्य होकर जमीन्दार और उनके कर्मचारियों की लोभ-लालसा की पूर्ति करनी पड़ी। जमीन में पैदावार चाहे जो भी हो किन्तु लगान में कमी होने का कोई उपाय नहीं। जमीन में इतनी पैदावार नहीं हुई कि उससे किसान लगान चुका सके और जमीन्दार लगान में कुछ भी कमी करने के लिए तैयार नहीं। ऐसी अवस्था में कड़ी सूद की दर पर महाजन से कर्ज लेकर या जमीन बंधक रखकर अथवा बँचकर लगान चुकाने के सिवा और दूसरा उपाय ही क्या था। इस प्रकार लगातार कई वर्षों तक लगान चुकाते रहने से किसान सर्वथा उपायहीन बन गये और महाजन उनकी जमीन नीलाम करा कर जमीन के मालिक बनने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि भूमिहीन कृषकों की सख्या बढ़ने लगी। जिन किसानों के पास जमीन बची रही उनके ऋण का परिणाम दिन-दिन बढ़ने लगा। मतगणना कमिश्नर सर टामस मुनरो की रिपोर्ट से मालूम होता है कि सन् १८४२ ई० में भारत में कोई भी भूमिहीन कृषक नहीं था। किन्तु ३० साल बाद १८७२ ई० में भूमिहीन कृषकों की सख्या बढ़कर साढ़े सात करोड़ हो गयी। इसके विपरीत जमीन्दार और ठेकेदारों की सख्या बढ़ने लगी। सन् १९३१ की जनगणना रिपोर्ट से यह पता चलता है कि चिरस्थायी प्रवर्धवाले प्रदेशों में जमीन्दार और ठेकेदारों की सख्या जहाँ प्रतिशत ६२ बढ़ गयी थी वहाँ किसानों की सख्या प्रतिशत ३४ घट गयी थी। इसके साथ ही भूमिहीन खेत मजदूरों की सख्या ५० प्रतिशत बढ़ती थी।

साडमन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया था कि चिरस्थायी प्रवर्धवाले प्रदेशों के जमीन्दार किसानों से लगान के रूप में जो रुपया वसूल करते हैं उसकी तीन चौथाई भाग अपने पास रख लेते हैं और बाकी एक भाग

राजस्व के रूप में सरकार को देते हैं। एक और तो जमीन्दारों का यह निष्पूर शोषण और दूसरी ओर सरकार की पक्षपातमूलक कर नीति के फलस्वरूप किसानों की दुरवस्था सहनशीलता की सीमा को अतिक्रमण कर गयी है। कमीशन ने इस कर नीति के सम्बन्ध में मन्तव्य किया था —“Grave inequalities which prevail in the distribution of taxation” रिपोर्ट में कहा गया था A poor cultivator, who not only pays to the state a substantial portion of his income from land, but also bears the burden of the duties on sugar, kerosine oil, salt and other articles of general consumption, seems to receive very different treatment from the king zamindar or landholder in areas where “permanent settlement” prevails, which owns extensive estates for which he may pay to the state a merely nominal charge fixed over a century ago and declared to be unalterable for ever, while his agricultural income is totally exempt from income tax”

किसानों के ऋण का परिणाम क्रमशः बढ़ते-बढ़ते, अवस्था यहाँ तक पहुँच गयी कि जो ऊँची जातियों के किसान थे वे तो भूमिहीन बन कर शहरों में अन्य वृत्तियों को ग्रहण करने लगे और निम्न जातियों के किसान खेतिहर मजदूरों के रूप में जमीन्दारों या बड़े-बड़े किसानों के श्रौतदास बन गये। इनके सम्बन्ध में उक्त रिपोर्ट में कहा गया था —

“Under the Kamianti system in parts of Bihar, and the Veth and Khanibari systems in the north of Madras, the labourer borrows money from the landlord under a contract to work until the debt is repaid. The debt tends to increase rather than to diminish, and the man, and sometimes his family, is bound for life, serfs are even sold and mortgaged. Such systems have now no legal sanction, and in Bihar special legislation has been adopted in the endeavour to eradicate the abuse; but it continues to exist”

जमीन के ऊपर जोतनेवालों का मालिकाना हक होना चाहिये यह सिद्धान्त आज सर्वजन मम्मत् है। इस सिद्धान्त को मानकर ही कांग्रेस सरकार ने भारत के विभिन्न राज्यों में जमीन्दारी प्रथा का उन्मूलन कानून द्वारा कर दिया है। किन्तु जमीन्दारी प्रथा के विलोप हो जाने से ही किसानों का भाग्योदय हो जायगा, ऐसा समझना भूल होगी। कानून द्वारा जमीन के ऊपर किसानों का अधिकार हो भी जाय तब भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कारण, अधिकार और अधिकृत वस्तु का यथोपयुक्त व्यवहार एक बात नहीं है। जमीन के सम्बन्ध में उसका व्यवहार ही प्रमुख प्रश्न है। Land is a social asset The cultivator is more or less a trustee of the social asset जमीन एक सामाजिक संपत्ति है और किसान इस संपत्ति के न्यासरक्षक या ट्रस्टी है।

जमीन के ऊपर मालिकाना हक दो रूपों में हो सकता है। एक, राष्ट्र की समस्त भू-संपत्ति पर सरकार का मालिकाना और नियंत्रण, दूसरा किसानों को मालिकाना हक अर्पित करना। जमीन के ऊपर राष्ट्र के व्यापक

मालिकाना और नियंत्रण का दृष्टान्त सोवियत रूस है। यूरॉप के भी कई देशों में यह प्रथा प्रचलित है। आर्थिक दृष्टि से इस प्रथा की उपयोगिता असन्दिग्ध है। किन्तु इसके अनुसार उत्पादन को एक कठोर नियम-भू खला के अन्दर रखा जाता है। अधिकार बोध द्वारा आत्म प्रसाद लाभ करने की इच्छा प्रत्येक मनुष्य को मन में प्रच्छन्न रहा करती है। खास कर जमीन को जो जोतता है और उसके लिए परिश्रम करता है उसके मन में तो स्वभावतः यह इच्छा और भी प्रबल होगी। इसलिए आत्म प्रसाद की लालसा को अक्षुण्ण रखकर राष्ट्र की सहायता द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना ही सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। सोवियत रूस में जहाँ सामूहिक कृषि प्रणाली प्रचलित की गयी है वहाँ भी किसानों को भूमि पर अधिकार लाभ करने के आनन्द से सर्वदा वंचित नहीं किया गया है। रूस में प्रत्येक किसान को एक एकड़ जमीन उसकी निजी संपत्ति के रूप में दी गयी है। और यह भी देखा गया है कि राष्ट्र के नियंत्रण में सामूहिक जोत-जमीन की अपेक्षा किसान अपनी इस निजी जमीन का ही अधिक ख्याल रखते हैं और उमकी देखभाल करते हैं। अमेरिका और रूस की तरह जो लोग यत्रचलित सामूहिक कृषि प्रणाली पर जोर देते हैं उन्हें यह भी स्मरण रखना चाहिये कि उन सब देशों की तरह यहाँ जनवल अग्रचर नहीं है। भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या बेकाम कर्मक्षम लोगों को काम में लगाने की है। जनवल ही हमारे देश की प्रधान पूजा है। इसलिए किसानों को जमीन पर यदि व्यक्तिगत अधिकार दिया जायगा तो वे खेतों की पैदावार बढ़ाने में ढिलाई करेंगे ऐसी आशंका करने का कोई कारण नहीं है। वल्कि निजी अधिकार होने से उन्हें जो आत्मतुष्टि होगी उससे प्रेरणा प्राप्त करके वे और भी मन लगाकर खेती करेंगे। इस प्रकार के व्यक्तिगत अधिकार भूमि पर होने से उत्कृष्ट प्रणाली द्वारा कृषि हो और उत्पादन एवं वितरण लाभ-जनक रूप में हो इसके लिए सहयोग पद्धति पर कृषि कार्यके लिए सहयोग कृषि प्रणाली चलानी होगी।

भारत में अति प्राचीन काल से ग्राम मंडल या ग्राम पंचायत यह काम करती आ रही थी। ग्राम पंचायत द्वारा इस सामाजिक दायित्व का पालन होने से ही ग्रामवासियों में एक सघन समाजचेतना का उदय हुआ था जो शताब्दियों तक राष्ट्र के जरीर को स्वस्थ एवं गतिमान बनाये रहा। भारत का आर्थिक इतिहास हमें बताता है कि गांव की जमीन का दृष्टवारा और उसके सरक्षण का भार ग्राम मंडल या ग्राम पंचायत के ऊपर न्यस्त था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी इस बात का उल्लेख मिलता है “जमीन को गैर आवाद हालत में छोड़ देने या किमी दूसरे के जिम्मे छोड़ कर चले जाने पर किसान की जमीन कुर्क कर ली जाती थी।” सन् १९४७ में ब्रिटेन के सशोधित कृषि कानून के अनुसार जमीन के मालिक को नियमानुसूल अच्छी तरह में खेती करने का पूर्ण दायित्व ग्रहण करना होगा। इस निर्देश को जो अमान्य करेगा उसे जमीन के मालिकाना हक से वंचित कर दिया जायगा। भारत में भी इस प्रकार का कानून बनना चाहिये। खेती करने का अधिकार किसान को होगा, किन्तु उसे सामाजिक नियंत्रण को मानकर चलना होगा। इसमें बल प्रयोग की कोई बात नहीं है कारण ग्राम पंचायत में किसान प्रतिनिधियों की ही तो प्रधानता होगी।



# बिहार में कृषि-भूमि एवं उसकी समस्याएँ

श्री सरस्वती प्रसन्न शास्त्री

बिहार में साढ़े चार करोड़ एकड़ भूमि है। यह भारत के कुल क्षेत्र का ५५ प्रतिशत है। बिहार की आबादी घनी है। यहाँ की कुल जनसंख्या ४ करोड़ है, जो भारत की कुल आबादी का ११ प्रतिशत होता है। इस राज्य में आबादी का औसत घनत्व ५७२ प्रति वर्गमील है। यहाँ चार जिले ऐसे हैं जहाँ की आबादी का औसत घनत्व राज्य के शेष भागों के औसत घनत्व से दूना पड़ता है। इन चार जिलों में राज्य के कुल क्षेत्रफल का १९ प्रतिशत पड़ता है। यह विशाल आबादी मुख्यतः कृषि पर आश्रित है। कृषिकर आबादी, राज्य की कुल आबादी का ८६ प्रतिशत है। लगभग ९३ प्रतिशत लोग गावों में बसते हैं और केवल ७ प्रतिशत विभिन्न शहरों में बटे हुए हैं।

भौगोलिक दृष्टि से, बिहार दो मुख्य प्रदेशों में बटा हुआ है— उत्तर और केन्द्र में गंगा की समतल भूमि और दक्षिण का पठार। दक्षिण का पठार राज्य के कुल क्षेत्र का ४७ प्रतिशत है। यहाँ की आबादी छेहर है, जो राज्य की कुल आबादी का केवल २७ प्रतिशत ही पड़ता है। यह पठार प्रदेश कृषि की दृष्टि से कुछ गरीब है जहाँ राज्य के कृष्य भूमि का केवल ३१ प्रतिशत है। किन्तु, इस प्रदेश में खनिज पदार्थों और जंगलों की भरमार है। यहाँ प्रधानतः आदिवासी बसते हैं।

बिहार की भूमि के वर्गीकरण से पता चलता है कि कुल क्षेत्र के २९ प्रतिशत में जंगल और अन्य अकृष्य भूमि है, १८ प्रतिशत क्षेत्र वर्तमान वन्य भूमि को छोड़कर कृष्य वन्य है, वर्तमान वन्य भूमि ११ प्रतिशत है और बुआई की कुल जमीन राज्य के कुल क्षेत्र का केवल ५२ प्रतिशत है। इस प्रकार हमारी ३ करोड़ ४६ लाख की कृषिकर आबादी की जीविका २ करोड़ १९ लाख एकड़ कृष्य भूमि पर आश्रित है, तात्पर्य यह कि कृषिकर आबादी के एक व्यक्ति के हिस्से दो-तिहाई एकड़ कृष्य भूमि पड़ती है, हमारी कुल कृष्य भूमि के केवल २३ प्रतिशत अंश में ही मिर्चाई की मविद्या है और ३१ प्रतिशत में एक वार से अधिक बुआई होनी है। कुल कृष्य भूमि के ७० प्रतिशत में पांच प्रधान अन्न, अर्थात् चावल, गेहूँ, चना, मकई और जौ होते हैं और इनकी प्रति एकड़ उपज केवल ७।। मन है। चावल हमारी मुख्य फसल है। कुल कृष्य भूमि के ४५

प्रतिशत में चावल ही होता है और इसकी उपज बिहार की पांच मुख्य फसलों की कुल उपज का ७२ प्रतिशत है।

बिहार में भूमि पर आबादी का बहुत अधिक बोझ है। सारन जैसे कुछ जिलों में तो कृष्य भूमि के केवल १०० एकड़ पर ही कृषिकर आबादी के २३० व्यक्तियों की जीविका निर्भर है। साथ ही, जनगणना से पता चलता है कि कृषि पर आश्रित रहनेवालों की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि १९३० ई० में जहाँ ७८७ प्रतिशत का मुख्य पेशा कृषि थी, वहाँ १९५१ ई० में यह संख्या बढ़कर ८७३ प्रतिशत हो गई। पिछले ४० वर्षों में कृष्य वन्य भूमि का क्षेत्रफल कम होता गया है। ४० वर्ष पहले यह क्षेत्र कुल क्षेत्र का १३ प्रतिशत था और १९४५-४९ ई० में यह आकार केवल ८ प्रतिशत रह गया। साथ ही, सिंचाई का क्षेत्र भी १७ प्रतिशत से बढ़कर १९४५-४८ में २३ प्रतिशत तक पहुँच गया है। इसी प्रकार, एक से अधिक वार की बुआईवाला क्षेत्र २६ प्रतिशत से बढ़कर ३१ प्रतिशत हो गया है।

बिहार में दमामी बन्दोबस्ती के कारण हाल-हाल तक गावों में आज तक के रेकर्ड रखने के लिए कोई संस्था नहीं थी। उपलब्ध आकड़ों से पता चलता है कि जमीन्दारों और पट्टेदारों की जोत में कुल ३४ लाख ६० हजार एकड़, विभिन्न कोटि के दखली रँयतों की जोत में २ करोड़ ३ लाख ६० हजार एकड़ तथा गैरदखली काश्तकारों और दर रँयतों की जोत में ६ लाख ६० हजार एकड़ जमीन थी। विगत जनगणना के अनुसार ३ करोड़ ४६ लाख की कुल कृषिकर आबादी में से ८८ लाख व्यक्ति भूमिहीन खेतिहर मजदूर और उनके परिवारवाले थे, ३३ लाख व्यक्ति दर-रँयत और उनके परिवारवाले थे और शेष, यानी २ करोड़ २५ लाख व्यक्ति दखली रँयत जमीन्दार और पट्टेदार तथा उनके परिवारवाले थे। इस विवरण से यह स्पष्ट है कि बिहार में अधिकांश जमीन दखली रँयतों की जोत में है, जिस पर उनका स्थायी और पुस्तनी अधिकार रहता है। यह भी स्पष्ट है कि कृषिकर वर्गों में इन दखली रँयतों की ही संख्या सबसे अधिक है। खेतिहर मजदूरों की संख्या कुल कृषिकर आबादी का २५ प्रतिशत है जो भारत के किसी भी राज्य

से अधिक है। यह हमारी आवादी का सबसे निचला वर्ग है और इस वर्ग को जमीन की बड़ी भूख रहती है।

विहार की स्थिति अधिक खेदजनक इसलिए हो जाती है कि यहाँ औद्योगिक कच्चे मालों की प्रचुरता है। यहाँ सभी पेशों में प्रति व्यक्ति सबसे कम आय कृषि से ही है। अतएव, इस राज्य में कुटीर और लघु उद्योगों के विकास की बहुत अधिक आवश्यकता है। हमारे यहाँ कृषि के सम्बन्ध में भी अनेक त्रुटियाँ हैं। विहार में प्रतिवर्ष औसतन ५० इंच पानी पड़ता है, किन्तु वर्षा निश्चित नहीं रहती, विशेष कर तिरहुत डिवीजन में, जो कि विहार का अन्न भांडार कहा जाता है, वर्षा और भी अनिश्चित रहती है। वहाँ पिछले १७ वर्षों में १० वर्ष के औसत से कम पानी पड़ा है। यह शोक-प्रवाहिनी कोशी प्रतिवर्ष विपत्तियाँ डाल देती है। यह हजारों हजार एकड़ उर्वर भूमि को तहस-नहस कर डालती है। हर्ष की बात है कि कोशी योजना का काम तत्परता से शुरू कर दिया गया। १९४५-५१ से, जबकि यहाँ लगभग दुर्भिक्ष जैसी स्थिति हो गयी थी, लगातार यहाँ बाढ़ और सूखा का प्रकोप होता रहा है। कृषिकर आवादी का जीवन-स्तर ऊँचा करने, बढ़ती हुई आवादी को देखते हुए वर्तमान स्तर को ही बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कृष्य वजर भूमि को आबाद किया जाय, सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाई जाय, दोफसला क्षेत्र बढ़ाया जाय और अधिक उपज की पद्धतियाँ काम में लाई जाय। इन दिशाओं में महत्वपूर्ण काम हो रहे हैं। विभिन्न भूमि-सुधार, जलनिकासी और वजर-भूमि कर्षण योजनाओं के अन्तर्गत ५ लाख एकड़ भूमि आबाद की जा चुकी है। सिंचाई की सुविधाओं के विस्तार के साथ दोफसला क्षेत्र भी उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है और धान की खेती के जापानी तरीके से धान की उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है।

कृषि की उपज बढ़ाने के लिए यह एक आवश्यक तत्त्व है कि खेतिहर को अपना खेत यथासंभव उत्तम रूप से जोतने की प्रेरणा मिलनी चाहिए। दुर्भाग्यवश मार्ग में अनेक बाधाएँ हैं। जमीन्दारी प्रथा ने भूमि के मालिक और खेतिहर के बीच एक बीचवान खड़ा कर दिया था। पट्टे की अनिश्चितता तथा मालगुजारी की ऊँची दर के कारण, खेतिहरों को खेत में जी-जान से मेहनत करने की प्रेरणा नहीं मिलती थी। इन दोनों को दूर करने की आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। विहार भूमि सुधार कानून, १९५० के द्वारा दमाही बन्दोवस्ती और जमीन्दारी की प्रथा का अन्त किया जा रहा है। १७ जिलों में से ८ जिलों में जमीन्दारियाँ ली जा चुकी हैं और शेष जिलों में भी एक दो वर्षों के अन्दर यह काम सम्पन्न हो जायगा। दखली काश्तकारों को, जो हमारी कृषिकर आवादी के ६५ प्रतिशत हैं, वेदखली और लगान वृद्धि के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। दर रैयत भी जमीन से वेदखली तभी किये जा सकते हैं जब वे लगान देना बन्द कर दें, खेत को इस तरह जोतें कि वह बिल्कुल बर्बाद हो जाय या लिखित

पट्टा होने पर उसकी अवधि बीत जाय। अन्यथा वे वेदखली नहीं किये जा सकते। दर रैयतों को दखली अधिकार देने और खेत के स्वामित्व की अधिकतम सीमा निश्चित करने के प्रस्ताव भी सरकार के विचाराधीन हैं। एक इस आशय का भी विधान बनाने का निश्चय हुआ है कि निश्चित एकड़ से अधिक जमीन होने पर सरकार अतिरिक्त अंश को ले लेगी, यदि खेत के मालिक उसका समुचित रूप से प्रबन्ध नहीं कर सकते हो, और उसे भूमिहीन व्यक्तियों में बाँट देगी। दर-रैयत के मामले में भी लगान बढ़ाने के सम्बन्ध में भू-स्वामी के अधिकार कम कर दिये गये हैं। रजिस्टर्ड पट्टा होने पर भू-स्वामी दर-रैयत से कुल उपज का ५० प्रतिशत से अधिक लगान के रूप में नहीं ले सकता और नकदी लगान लेने पर वह अपने मालिक को दिये जानेवाले लगान पर २५ प्रतिशत से अधिक नहीं वसूल कर सकता। सरकार जिसके रूप में लगान की दर कम कर देने का विचार कर रही है। दखली रैयत और दर-रैयतों को अपने घर-वाड़ी से वेदखली के विरुद्ध पूरा बचाव सुलभ है। १९४८ ई० में विहार प्रिविलेज्ड परमन्स होमस्टेज टेनेन्सी ऐक्ट पास कर इस बचाव को और भी दृढ़ कर दिया गया है। वर्तमान काश्तकारी कानून में गैर-कानूनी तरीके से वेदखली किये गये दर-रैयतों को उसका अधिकार दिलाने के लिए कई व्यवस्था नहीं है। विहार काश्तकारी (सशोधन) विधेयक, १९५४ के द्वारा कलकटों को यह अधिकार देने का विचार है कि वे गैर-कानूनी तरीके से वेदखली किये गये दर-रैयतों को उनका अधिकार वापस दिला दे। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की जमीन की भूख की तृप्ति के लिए भी आवश्यक व्यवस्था की जा रही है। निश्चित सीमा से अधिक जमीनवालों को अतिरिक्त जमीन लेकर और वजर भूमि को कृष्य बना कर भूमिहीनों में बाँटने की योजना है।

विहार जैसे राज्य में, जहाँ जमीन पर एक बड़ी आवादी का इतना बोझ है, जमीन का बहुत अधिक टुकड़े किया जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं होती। सच तो यह है कि विगत सर्वेक्षण तथा बन्दोवस्ती के समय यह पाया गया कि कुछ जिलों में जैसे सारन, मुजफ्फरपुर और दरभंगा में खेतों का औसत आकार दो एकड़ से अधिक नहीं था जबकि उसके अन्तर्गत टोपरो के औसत ०.४ एकड़ या उससे भी कम के थे। तब से अब तक के बीच जो कुछ पड़तालें की गई हैं, उनसे पता चलता है कि खेतों और टोपरो के औसत आकार और भी छोटे होते गये हैं। अवखटन की इस गति को, जो सुचारु रूप से खेती करने के मार्ग में बड़ी बाधा है, रोकने के लिए तथा चक्रवन्दी के लिए राज्य सरकार निश्चय कर चुकी है कि वह एक विधान बनायेगी। इस विधान द्वारा विभिन्न जमीनों का क्षेत्र निश्चित और घोषित कर दिया जायगा जिसमें कम के टुकड़े बिक्री, पट्टा, बटवारा तो अन्यथा नहीं किये जा सकेंगे। सरकार ने एक ममिति की भी स्थापना की है जो इस राज्य में सहकारिता के आधार पर खेती करने की सभावनाओं को जाच करेगी। इस ममिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा सिफारिशों सरकार के विचाराधीन हैं।

# पड़ोसी नेपाल में भूमि की हीन दशा

श्री रुद्र प्रसाद गिरि

तीन ओर से भारतीय क्षेत्रों से घिरा हिमालय की गोद में नेपाल, सदियों तक बाहरी दुनिया के लिए अज्ञात ही बना रहा। अंग्रेजों और नेपाल के राणा शासकों की पूरी कोशिश के बावजूद १९५० के अन्त में यहाँ एक सफल क्रान्ति हुई, जिसके फलस्वरूप १०४ वर्ष पुराना राणा शासन का अन्त हुआ और १८ फरवरी १९५१ में नेपाल नरेश स्वर्गीय श्री त्रिभुवन के वैधानिक नायकत्व में राणाओं और नेपाली कांग्रेस की मिली-जुली सरकार बनी। तब से अब तक इस पाच साल की अवधि में छ सरकारें बन चुकी हैं और अब तो स्वर्गीय श्री त्रिभुवन की जगह उनके सुपुत्र श्री महेन्द्र वीर विक्रम नेपाल के नरेश हैं और प्रत्यक्ष रूप से अपने सलाहकारों की सहायता से नेपाल का शासन चला रहे हैं—किन्तु अन्य समस्याओं की तरह भूमि समस्या अपनी जगह पर वहाँ ज्यों-की-त्यों बरकरार है।

तमाम पिछड़े मुल्कों को अपने आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए अनुकूल पृष्ठभूमि तैयार करना आवश्यक होता है, और इसीलिए भूमि समस्या का समाधान उनकी प्राथमिक आवश्यकता बन जाती है। खास कर नेपाल जैसे देश के लिए जहाँ कि ९० प्रतिशत आबादी खेती पर ही निर्भर है और सरकार की आमदनी का भी मुख्य श्रोत जमीन है—किन्तु जमीन से भी वमूल की गयी पूरी-की-पूरी मालगुजारी सरकारी खजाने में नहीं पहुँच पाती। नेपाल की भूमि व्यवस्था मध्ययुगीन सामन्तवाद है और इसमें सुधार की नितान्त आवश्यकता है। इने महाराजाधिराज स्वर्गीय श्री त्रिभुवन ने भी स्वीकार किया था और वहाँ के तमाम राजनीतिक दल तो इसके लिए आन्दोलन ही करते रहे हैं।

## भूमि सुधार

राणागद्दी के अन्त के बाद आरम्भ के दिनों में नरेश त्रिभुवन ने एक वक्तव्य में भूमि सुधार की आवश्यकता की घोषणा की थी। मन्त्रिमण्डल के सदस्यों ने तो बार-बार कहा कि नेपाल में प्रचलित भूमि व्यवस्था को बदलकर किसानों की दशा में उन्नति लायी जायेगी। नरेश त्रिभुवन ने किसानों को आश्वासन भी दिया कि उन्हें जोत की जमीन से बेदखल

नहीं किया जायगा। उसके बाद एक भूमि आयोग का भी गठन किया गया, जिसने अपना प्रतिवेदन भी सरकार के सामने उपस्थित किया। भारतीय योजना आयोग के विशेषज्ञों ने भी नेपाल की भूमि-समस्या का अध्ययन कर समाधान के कुछ सुझाव नेपाल सरकार के सामने उपस्थित किये थे। कोई साढ़े चार साल हुए, सयुक्त सरकार के दिनों में नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष श्री वी० पी० कोइराला, जो उन दिनों गृह मंत्री थे, ने भूमि सुधार सम्बन्धी कुछ वृहत् कार्यक्रमों को मन्त्रिमण्डल से स्वीकृत कराया था। उसके अनुसार वित्त जमीन की खरीद-बिक्री या बन्दोबस्ती को बन्द कर दिया गया था तथा जमीन पर से जोतनेवाले किसानों की बेदखली भी नाजायज करार दी गयी थी। इस सरकार ने सारे-के-सारे जगलों को भी राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दिया जिससे वित्तवालों का कब्जा जगल पर से जाता रहा। किन्तु सरकार इसे लागू नहीं कर सकी। इसके कारण कुछ तो अनुकूल और योग्य प्रशासन व्यवस्था का अभाव और कुछ वी० पी० कोइराला और मोहन शमशेर के सयुक्त सरकार का पतन था।

नेपाल सरकार के पास भूमि का नक्शा-खतियान भी नहीं है। जो है भी वे दोपरहित नहीं कहे जा सकते तथा अधिकतर नक्शा-खतियान गैर सरकारी सूत्रों के हाथ में है।

## वर्तमान अवस्था

नेपाल में भूमि व्यवस्था कई प्रकार की है। वहाँ की जमीन्दारी व्यवस्था भारत में अभी हाल तक प्रचलित जमीन्दारी व्यवस्था से भिन्न है। यहाँ के जमीन्दार वस्तुतः मालगुजारी वसूलने तथा जमीन के बन्दोबस्त करने के लिए बीच के दलाल हैं जिन्हें मालगुजारी और सलामी में कुछ दलाली कमीशन मिल जाता है। इसके अतिरिक्त जीवन यापन के लिए कुछ जमीन भी दी जाती है। कुछ चन्द जमीन्दारों को तो १०,००० एकड़ तक जमीन मिली हुई है। इम जमीन को 'सीर' जमीन कहते हैं, जो कि रयतों को जोतने के लिए दे दी जाती है। सीर जमीन को जोतनेवाले रयतों का जमीन पर कोई मालिकाना हक नहीं होता और वे पूर्णतः जमीन्दारों की दया पर जीते हैं।

विभिन्न स्थानों में प्रचलित परम्परा के अनुसार इन्हें उपज की एक तिहाई से आठे हिस्से तक जमीन्दारों को देना पड़ता है। रैयती को अपनी जमीन पर कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं है। और अगर कानून या परम्परा के अनुसार कुछ अधिकार उन्हें प्राप्त भी हो तो वे लिखित प्रमाण के अभाव में उसका प्रयोग नहीं कर सकते। जमीन्दारों की ओर से उन्हें कोई रसीद भी नहीं दी जाती। इसके अतिरिक्त जमीन्दारों के पास अपने लठेंतों और गुण्डों के दल हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर जमीन्दारों की चाकरी बजाते हैं और किसानों पर जुल्म डालने में जमीन्दारों की मदद करते हैं।

भारतीय जमीन्दारी से मिलती-जुलती एक प्रकार की व्यवस्था नेपाल के पहाड़ों में प्रचलित है, जिसे 'कीपट' कहते हैं। नेपाल के पुराने नरेशों और राणा प्रधान मंत्रियों ने किरातियों को खुश करने के लिए इस्टेटों को उन्हींके जिम्मे छोड़ दिया और उन पर कुछ मोटा-मोटी मालगुजारी तय कर दी। इससे पहाड़ के किराती सरदार सरकार के भक्त बन गये। बाद में धीरे-धीरे यह कीपट भी किरातियों के हाथ से निकल कर राजधानी काठमांडू से गये लोगों के हाथ में चली आयी। ठीकदारों ने पहाड़ के किसान की जमीन बाकी मालगुजारी और कर्ज नहीं अदा करने के कारण नीलाम करा लिया। पहाड़ों में जमीन की कमी और कीपटदारों के उत्पात से तग आकर बंचारे सीधे-साधे पहाड़ी उजड़ कर अंग्रेजों के भरोसे होते हैं तथा भारत के प्रमुख शहरों में दरवान और घरेलू नौकर का काम करते हैं। जमीन्दारों, कीपटवालों तथा धनी किसानों की सख्या कुल मिला कर लगभग दस प्रतिशत होगी, जो कुल जोत की जमीन के २५ प्रतिशत के मालिक हैं।

### सर्वसत्ता सम्पन्न विर्तावाल

नेपाल में जोत के अन्दर कितनी जमीन है इस सम्बन्ध में कोई आकड़ा प्रस्तुत नहीं है, किन्तु यह निस्संकोच होकर कहा जा सकता है कि कुल जोत की जमीन के पचास प्रतिशत के मालिक वहाँ के विर्तावाल हैं। विर्ता की ठीक-ठीक व्याख्या करना आसान नहीं—क्योंकि विर्ता के भी कई प्रकार हैं। अधिकतर विर्ता तो राणाओं के ही हैं और कुछ विर्तावाल राणा के पास लगभग १० लाख एकड़ विर्ता जमीनें हैं। पश्चिम नेपाल तराई का भाग १८५७ के गदर में अंग्रेजों की सहायता करने के पारितोषिक के रूप में राणा जग बहादुर को मिला था। इसे नेपाली 'नया मुलुक' कहते हैं। यहाँ तो किसानों को रैयती हक नाम की कोई चीज ही नहीं है। यहाँ लगभग सभी-के-सभी जमीन विर्तावालों के हैं। सरकारी दृष्टिकोण से यह व्यवस्था अत्यन्त ही हानिकारक है। विर्ता जमीनों की मालगुजारी सरकारी खजाने में नहीं जाती बल्कि विर्तावालों के यहाँ जाती है। इसके अतिरिक्त विर्तावालों की भी अपनी 'मीर' जमीन होती है, जिसे वे अपनी शर्त पर बँटाया जुतवाते हैं। इन विर्तावालों को अपनी-अपनी कच-हरिया हैं जहाँ मालगुजारी सम्बन्धी मामलों की इनके सुब्बा (मैजिस्ट्रेट) सुनवाई करते हैं और अपराधी को तीन महीने कैद तथा सौ रुपये जुर्माने तक की सजा दे सकते हैं। इनके सजायापस्त कँदी सरकारी जेलों में सजा भुगतते हैं और जिसका खर्च भी सरकार को ही वहन करना पड़ता है।

मध्यवित्त किसानों की सख्या वहाँ नगण्य जैसी है। कुल जोत की जमीन के २५ प्रतिशत का विभाजन मध्यम किसानों और छोटे किसानों में हुआ है। लगभग ६० प्रतिशत लोगों के पास अपनी जमीन नहीं है। वे बटाई या मजदूरी पर जीवन यापन करते हैं।

### सुकुमवासी

भूमिहीन बटाईदार या मजदूर को नेपाली सुकुमवासी कहते हैं। कहने को तो दास प्रथा का अन्त नेपाल में राणा चन्द्र शमशेर जग बहादुर ने १९२६ में ही कर दिया था किन्तु इन सुकुमवासियों की हालत दासों से किसी भी प्रकार अच्छी नहीं कही जा सकती। वस्तुतः उनके या उनके पिता के द्वारा जमीन्दारों के कर्ज नहीं अदा कर सकने के कारण उनकी यह दशा है। चूँकि कर्ज अदा नहीं हो सकते इसलिए गरीब किसानों में से नये सुकुमवासी दास पैदा होते जा रहे हैं। और इनकी सख्या बढ़ती ही जा रही है। सुकुमवासियों की स्थिति के सम्बन्ध में मैं अपनी आँखों देखा अनुभव प्रस्तुत कर रहा हूँ।

जमीन की समस्या मुख्यतः नेपाल तराई की समस्या है। पहाड़ों में उपजाऊ जमीन की कमी है, और उद्योग-धंधों का भी विकास नहीं हो पाया है, इसलिए पहाड़ी जमीन की परवाह नहीं कर बाहर नौकरी पर चले जाते हैं। किन्तु तराई के साथ यह बात नहीं है।

तराई के अधिकतर क्षेत्रों को पिछले १०० वर्षों के अन्दर जगल काट कर बसाया गया है। स्थानीय आदिवासी थारू, मगर, भोट, और मुसहरो आदि ने वीहड जंगलों को काट-काटकर तथा खेती में आड़ी धूर बाँधकर जमीन को आबाद किया। ये लोग स्वभाव से शान्त, ईमानदार और अशिक्षित हैं। खेती के लिए ये लोग अकपर कर्ज लेते हैं। उचित व्याज पर कर्ज की कोई और व्यवस्था के अभाव में ये लाचार होकर गर्दनतोड़ सूद पर जमीन्दारों से कर्ज लेने पर मजबूर होते हैं। जमीन्दार सवाई और ड्योडा दर पर कर्ज देते हैं। आम तौर पर आपाद और श्रावण में किमान अपने खाने और खेत में बीजों के लिए अनाज कर्ज लेते हैं और माघ-फागुन में धान की फसल तैयार होने पर सवाई और ड्योडा सूद की दर से कर्ज चुकाते हैं। खेती के लिए मिर्चाई को कोई व्यवस्था नहीं है। वर्षा के दगा देने पर फसल मारी भी जाती है। ऐसी परिस्थिति में किसानों के ऊपर पुराना कर्ज तो रहता ही है, साथ ही नये वर्ष के लिए उन्हें फिर से कर्ज लेना पड़ता है। इस प्रकार कर्ज, सूद, कर्ज और दरमद मिलाकर किसानों के ऊपर एक भारी बोझ बन जाता है जिसे चुका सकना उनकी सामर्थ्य के बाहर की बात होती है और अन्त में उन्हें अपनी कुछ बची-बूची जमीन से भी हाथ धोकर जमीन्दारों की गुलामी करने की मजबूर होना पड़ता है।

कोई २१-२२ साल पूर्व लगातार कई वर्षों तक सूखा रहा। किसानों को बराबर कर्ज लेने की आवश्यकता पड़ती गयी। उपज नहीं होने के कारण किमान न तो कर्ज चुका सके और न मालगुजारी ही। कर्ज और बाकी मालगुजारी में किसानों की जमीनें नीलाम हो गयीं। नीलामी में बावली और अत्याचार की कोई इन्तिहा न रही। बावली का हिमाव इनमें रहना ही लगाया जा सकता है कि २० रुपये बाकी मालगुजारी में किसानों की इतनी जमीनें नीलाम हो गयीं, जिसका मूल्य बाद

के वर्षों में २० हजार से ३० हजार रुपये तक होता। इस प्रकार ये जमीनें काठमांडू के राणाओं, थापाओं और गुरु-पुरोहितों के हाथ में चली गयी और किसान अपनी जमीन से बेदखल होकर सुकुमवासी बन गये।

इसके अतिरिक्त किसानों की जमीनें बाकी कर्ज और सूद चुकाने में महाजनो के हाथों में भी गई हैं। किसानों के हाथ से जमीन निकलने का सिलसिला निरन्तर जारी है। सिंचाई और खाद की कमी के कारण उत्पादन घटता गया। सेरी, सलामी और चक्रवृद्धि व्याज के चलते छोटे किसानों को प्रतिवर्ष अपनी जमीन का एक टुकड़ा गवा देना पड़ता है। नेपाल तराई के किसानों पर हो रहे शोषण और लूट को स्पष्ट रूप से समझन के लिये नीचे के एक ज्वलन्त उदाहरण पर गौर फरमाइये।

एक किसान अगर एक बीघे में ४० मन अनाज उपजाता है तो उसका वितरण निम्न तरीके से होता है

२० मन मालिक को आधे बटाई की दर से। ४ मन मालिक को सलामी १० सेर प्रतिमन की दर से। ७ मन खेती में बीज और अन्य खर्च। २ मन ३० सेर बीज और खर्च में लिये गए कर्ज के सूद में। १० सेर हटवे को तौलने में और १० सेर जमीन्दार के सिपाही को। बटाईदार किसान और उसके परिवार के लिए बाकी बचता है ५ मन ३० सेर।

यह परिस्थिति उस समय की है, जब उपज ठीक हो, जो अक्सर नहीं होती। साथ ही अगर तिखुर की प्रथा है तो किसानों को एक तिहाई ही हिस्सा मिलेगा। नेपाल तराई में कई जगह जमीन्दार दो भाग लेता है और किसानों को तिहाई हिस्सा ही मिलता है। इस व्यापक लूट के चलते किसान बेजमीन हो चुके हैं और होते जा रहे हैं।

खेती के अतिरिक्त सरकारी आय का एक अन्य साधन वहा का जंगल है। नेपाल के जंगलों में बहुमूल्य लकड़ियां हैं। इसकी भी पैमाइश नहीं कराई गयी है। अन्दाज है कि उत्तर प्रदेश के जंगलों से दशगुना जंगल नेपाल में है, किन्तु उत्तर प्रदेश को केवल जंगल से उतनी आमदनी है जितनी नेपाल को सभी श्रोतों से भी नहीं आती। इसके अतिरिक्त नेपाल में जंगल की सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं की गयी है। वहा अभी भी नीलामी प्रथा के द्वारा जंगल काटने के लिए ठेकेदार को दे दिया जाता है, जो निर्ममतापूर्वक जंगल का सफाया ही कर देता है। जनतंत्र के आरम्भ के दिनों में विर्तावालों के हाथ से जंगलों को छीन कर उनका राष्ट्रीकरण कर दिया गया था किन्तु अब सुना जाता है, जंगल फिर से विर्तावालों को दे दिया गया है।

अतः सरकारी आय और जनकार्य की वृद्धि और विकास के लिए भी जमीन और जंगल का सुधार और संरक्षण आवश्यक है।



# बम्बई में भूमि सुधार

डा० जी० डी० पटेल

बम्बई राज्य में मुख्यतया रयतवारी जमीन है। विहार, उत्तर प्रदेश,

उड़ीसा तथा अन्य राज्यों की तरह यहाँ चिरस्थायी प्रबन्ध के अन्तर्गत जमीन नहीं थी, लेकिन कुछ गैर रयतवारी जमीन थी जिसे इनामदारी कहते हैं, खोटी, ताल्लुकदारी, मालिकी, मेहवासी, भागदारी, नरवादारी, सालसेट खोटी, कौली तथा कुतुवन के नाम से बहुत-सी व्यवस्थाएँ चली आ रही हैं। गुजरात में ताल्लुकदार थे और कोकण में खोटी। गुजरात के अन्य जिलों में मालिकी, मेहवासी, भागदारी तथा नरवादारी प्रथाएँ चालू हैं। कौली और कुतुवन प्रणालियाँ केवल कोकण में ही पाई जाती हैं। परगना कुलकर्णी वतन और वैयक्तिक या राजनीतिक तथा सरजाम के नाम पर पूरे राज्य में लोगों के नाम भूमि बन्दोबस्त की गई थी। देशी राज्यों के विलयन के पश्चात् मुलगिराज, सलामी, वतन, अकादिया, तथा मातादारी व्यवस्थाओं एवं बन्दोबस्तों का पता चला। जितने राज्य विलीन हुए उनकी जागीरदारी प्रथा के कारण समस्या और भी सङ्गिष्ट हो गई चूँकि इन जमीनों के मालिकों को विविध प्रकार के अधिकार प्राप्त थे। उनकी सामाजिक स्थिति एवं वंश परम्परा के मुताबिक वे अधिकारी थे। हालाँकि विहार की तरह की जमीन्दारी प्रथा बम्बई में प्रचलित नहीं थी पर तरह-तरह की अन्य प्रथाओं के अवस्थित रहने के फलस्वरूप बम्बई की भूमि समस्या कम पेंचीदी नहीं थी। इसी कारण राज्य सरकार को अन्य जमींदारी-वाले राज्यों की तुलना में विलकुल दूसरे प्रकार का कानून बनाना पड़ा जो पृथक-पृथक और खड-खड है। यदि समस्त राज्य के लिए एक ही प्रकार का कानून बनाया जाता तब समस्या अधिक विकट हो जाती चूँकि स्थानीय या क्षेत्रीय प्रशासक उसे न तो समझते और न उसको ठीक प्रकार से कार्यरूप ही दे पाते।

भूमि समस्या के समाधान के लिए कानून दो दृष्टिकोणों को सामने रखकर बनाये गये (१) ताकि सरकार और रयत के बीच के मध्यस्थ खत्म हो जाय (२) सरकार एवं रयतों के सबब नुदृढ हो। १९४८ में बम्बई टेनेन्सी ऐण्ड एग्रिकलचरल लैंडम ऐक्ट पारित किया गया जिससे मध्यस्थों एवं रयतों के आपसी सन्धियों को स्थिर कर दिया गया। इस एक कानून के अलावा भिन्न-भिन्न किस्म की भूमि व्यवस्थाओं के निमित्त पृथक-पृथक कानून बनाये गये हैं, जिसका विवरण यहाँ है :

- (१) भागदारी और नरवादारी भूमि
- (२) पचमहाल मेहवासी
- (३) ताल्लुकदारी
- (४) मालिकी
- (५) खोटी
- (६) परगना तथा कुलकर्णीवतन
- (७) वातवा बजीफदारी अधिकार
- (८) मालसीट इस्टेट
- (९) वैयक्तिक इनाम
- (१०) सरजाम और राजनीतिक इनाम
- (११) अकादिया प्रथा
- (१२) मातादारी
- (१३) बडौदा वतन
- (१४) मुलगिराज
- (१५) कौली और कुतुवन
- (१६) सलामी
- (१७) जजीरा और भोर क्षेत्रों की खोटी प्रथाएँ
- (१८) विलीन राज्यों की जागीरदारी
- (१९) सविम इनाम

इन भूमि व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में उपर्युक्त कानून बनाने समय सरकार ने उन्मूलन एवं सञ्चावजा दोनों पर विचार किया है। अतः इन कानूनों का क्रमिक अध्ययन करना बड़ा लाभदायक है। ये कानून तुरत उन क्षेत्रों में लागू कर दिये गये हैं। इन जमीनों के मालिकों के मयस्त अधिकार जो वे पहले इस्तेमाल में लाते थे एकदम छिन लिये गये।

इन प्रथाओं के उन्मूलन के अनन्तर इन्हीं कानूनों के द्वारा रयतों को जमीन पर मालिकाना हक भी प्राप्त हो गया है। इन कानूनों के द्वारा भूमि का वितरण सामान्य स्तर पर हो गया और मालिकों की, जो केवल रयतों की गाड़ी कमाई पर जीते थे, मर्यादा में एकदम कमी हुई गई। इन कानूनों के द्वारा घरखेडों की रखा हो गई जिन पर अधिकार प्राप्त करने के लिए किसान को किसी प्रकार का कर या रकम नहीं चुकानी पड़ी। इनके अलावा

भी अन्य छोटे-छोटे रैयत थे जो विविध प्रकार के कर दिया करते थे उन्हें भी इन कानूनों के द्वारा मान्यता दे दी गई है। कुछ ऐसे रैयत भी थे जो जागीरदार, भागदार, ताल्लुकेदार आदि को बन्दोवस्ती लेकर कर दिया करते थे, इन्हें इन कानूनों द्वारा सरक्षण प्राप्त हो गया।

इन कई कानूनों द्वारा समस्त गावों एवं जमीनों पर बम्बई सरकार का अधिकार हो गया है। इन कानूनों के बनाने का एकमात्र यह उद्देश्य रह गया है कि रैयत और सरकार के बीच कोई बीच की दीवार न रह जाय। अब रैयतों से सरकार का बिलकुल सीधा सम्पर्क स्थापित हो जायगा। इस प्रकार की व्यवस्था से यह सुविधा हो गई है कि जन-कार्य के लिए सरकार भूमि निश्चित कर सकेगी। लेकिन मिलो और फँटरियों के निर्माण में इन जमीनों को इन कानूनों के अन्तर्गत नहीं रखा गया है।

इन कानूनों के अन्तर्गत पेड़, खान-खनिज आदि नहीं आते। अन्य प्रांतों में जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश आदि में इन तमाम चीजों पर भी सरकार का अधिकार जमीन्दारी उन्मूलन कानून के कारण हो गया है। जो जंगल जमीन्दारों या उस कोटि के लोगों के अधिकार में थे उन पर सरकार ने कब्जा नहीं किया है। लेकिन प्राइवेट जंगलों को अरक्षित नहीं छोड़ा गया है। १९२७ के इंडियन फॉरेस्ट ऐक्ट में १९४८ में संशोधन करके सरकार ने सभी जंगलों पर अधिकार प्राप्त कर लिया है। इस कानून के अनुसार बहुत से जागीरदारों को ऐसी नोटिस दे दी गई है कि वे जंगल को नष्ट नहीं करें। लेकिन यह कानून राज्य की वन्य-सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए माकूल एवं मौजू नहीं है। सरकार इसके लिए अलग कानून बनाने की बात सोच रही है।

अन्य राज्यों में खानों एवं खनिजों पर भी सरकार ने अधिकार कर लिया है लेकिन बम्बई में ऐसा इन्तजाम नहीं है। सरकार ने ऐसा तुरन्त इसलिए नहीं किया चूँकि तत्काल ही व्यवस्था के लिए अधिक रूपों की आवश्यकता पड़ जाती। मुआवजों के निर्धारण में भी सरकार ने विविध भूमियों का अलग-अलग निश्चय किया है। जैसे इमानदारी को समस्त मूल्य देकर सरकार ले लेंगी। इसी तरह बहुत सोच-विचार कर सभी शर्तें निश्चित की गई हैं। इस सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार की शिकायत हो तो उसे अपील करने का अधिकार भी दिया गया है। मुआविजा देने के सम्बन्ध में तीन प्रकार के विशिष्ट निर्णय किये गये हैं।

(१) अगर किसी ऐसी जमीन पर सरकार अधिकार कर लेती है जो परती हो या बंकार हो लेकिन जिसमें खेती की जा सकती हो तब उस परती भूमि की कीमत से तिगुना से अधिक मुआविजा नहीं दिया जा सकता।

(२) अगर किसी जमीन के टुकड़े का इस्तेमाल जन कार्य के लिए किया जाता हो या किसी एक व्यक्ति का अधिकार हो गया हो तो उसका मुआवजा भी गाव की वंजोती हुई जमीन की कीमत भर ही दिया जायगा।

(३) अगर किसी अधिकृत भूमि में पेड़ हो या मकान बने हुए हो तो उनके लिए बाजार दर के मुताबिक ही मुआवजा दिया जायगा। बाजार दर का निर्धारण करते समय अधिकारी १८९४ के लैंड एक्विजिशन ऐक्ट २१ (१) और २४ धाराओं को ध्यान में रखेंगे।

मालिकों, वजीफदारों और श्रंकदारों को दिये जानेवाले मुआविजे की रकम तिगुनी निर्धारित की गई है।

मुआविजा का भुगतान वाडों में किया जायगा जिनपर ३ प्रतिशत सूद भी प्राप्त होगा। २० वर्षों में इसका भुगतान हो सकेगा। वाड क्रमशः ५०, १००, २००, ५०० और १,००० रुपये के हैं। पचास रुपये से नीचे की रकम का मुआवजा नकद दे दिया जायगा।

भागदारी, नरवादानी, मेहवासी और मालिकी प्रथा उन्मूलन के लिये जो कानून बने हैं उन्हें तत्काल लागू कर दिया गया है। ३,४,६ से १० तक के उल्लिखित कानून अभी लागू किये जा रहे हैं। ११ से १५ तक को १९५३ के अग्रस्त से ही लागू कर दिये गये हैं। १६ से १९ तक को १९५३ के शरतकालीन अधिवेशन में स्वीकृत कर उसे समस्त राज्य में लागू कर दिया गया है।

इन कानूनों को अति शीघ्र लागू करने में भी तीन पहलुओं पर विचार कर लिया गया है

(१) सरकारी अधिकार हो जाने पर भूमि की व्यवस्था किस प्रकार की जाय।

(२) पैमाइश, बन्दोवस्ती और खतियानी हक किस प्रकार दिये जाय।

(३) मुआविजा कैसे और कितना दिया जाय और उसका भुगतान कितने समय में किया जाय।

अधिकृत जमीन्दारियों की सुव्यवस्था के लिए सरकार तहमातियों और पाटिलों की नियुक्ति कर चुकी है। इनके अतिरिक्त गांवों में काम करनेवाले अन्य छोटे-छोटे कर्मचारी भी हैं। बहुत से गाव ऐसे हैं जहाँ भूमि की न तो पैमाइश हुई है और न वहाँ आखिरी तौर पर जमीन की बन्दोवस्ती ही हो सकी है। इस काम में देर तो लग ही सकती है। इस कार्य में व्यय एकमुश्त नहीं होगा और यह काम दस वर्ष से कम में नहीं पूर्ण होने को है। इस काम पर जो व्यय होगा उसका भार एकवारगी ही सरकार पर नहीं पड़ेगा। ठीक इसके विपरीत सरकार को वैज्ञानिक पैमाइश तथा सरक्षण के अनन्तर आय भी अधिक होगी।

यह सत्य है कि इन तमाम भूमि व्यवस्थाओं को समाप्त कर देने में सरकार को अधिक मुआवजा तो देना पड़ा है लेकिन इससे लाभ भी कम नहीं हुआ है और आमदनी भी बढ़ ही गई है। भूमि सुधार के बाद सरकार को कर प्राप्त करने में सुविधा हो गई है। अनुमान के मुताबिक सरकार को ४४३ करोड़ मुआवजा देना पड़ेगा लेकिन इससे आय प्रतिवर्ष १११ करोड़ बढ़ जायगी। किसानों को अपनी जमीन का ममत्व अधिक रहेगा। उत्पादन भी बढ़ेगा और सामाजिक शांति भी रहेगी। अन्य प्रकार की भूमियों के सम्बन्ध में भी पूरे राज्य भर में लागू करने के लिए कानून बनाने का ध्यान सरकार को है। अतएव सारी जमीन पर सरकारी अधिकार हो जाने से ग्राम्य-विकास की योजनाएँ भी शीघ्र कार्यान्वित की जा सकती हैं।

अवतक बम्बई सरकार निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण भूमि सुधार कानून बना चुकी है और अन्य कई बनाये जाने के क्रम में निर्धारित हैं। जो

राज्य विधायिकाओं से स्वीकृत किये जा चुके हैं उन पर राष्ट्रपति की सम्मति लिया जाना शेष रह जाता है

- (१) भागदारी ऐण्ड नरवादादी टैन्पोर एवोलिशन ऐक्ट, १९४९।
- (२) पच महात्स मेहवासी टैन्पोर ऐक्ट १९४९।
- (३) वम्बई मालिकी टैन्पोर एवोलिशन ऐक्ट, १९४९।
- (४) वम्बई ताल्लुकदारी टैन्पोर एवोलिशन ऐक्ट, १९४९।
- (५) वम्बई खोटी टैन्पोर एवोलिशन ऐक्ट १९४९।
- (६) वम्बई परगना ऐण्ड कुलकर्णी वतनस एवोलिशन ऐक्ट १९५०।
- (७) वम्बई वातवा वजीफदारी राइट्स एवोलिशन ऐक्ट, १९५०।
- (८) सालसीट इस्टेट्स (लैंड रेवेन्यू एक्वीजीशन) एवोलिशन ऐक्ट, १९५१।
- (९) वम्बई परसनल इनाम एवोलिशन ऐक्ट, १९५२।
- (१०) वम्बई मज्दं टैरीटरीज (अकादिया टैन्पोर एवोलिशन ऐक्ट १९५३।
- (११) वम्बई मज्दं टैरीटरीज (वडौदा वतन्स) एवोलिशन ऐक्ट १९५३।

- (१२) वम्बई मज्दं टैरीटरीज (वडौदा मुलगिराज टैन्पोर) एवोलिशन ऐक्ट, १९५३।
- (१३) वम्बई मज्दं टैरीटरीज (मातादारी टैन्पोर) एवोलिशन ऐक्ट, १९५३।
- (१४) वम्बई कौली ऐण्ड कुतुवन टैन्पोर एवोलिशन ऐक्ट, १९५३।
- (१५) वम्बई मज्दं टैरीटरीज (जागीरस) एवोलिशन विल, १९५३।
- (१६) वम्बई सर्विस इनामस (यूजफूल टू कम्युनिटी) एवोलिशन विल, १९५३।
- (१७) वम्बई मज्दं टैरीटरीज (जजीरा ऐण्ड भोर खोटी टैन्पोर) एवोलिशन विल, १९५३।
- (१८) वम्बई मज्दं टैरीटरीज (वडौदा सलामी टैन्पोर) एवोलिशन विल १९५३।
- (१९) वम्बई सरजाम्म जागीरस ऐण्ड अदर इनामस आव पालिटिकल नेचर रिजम्पसन रुल्स, १९५२।





# हमारी खाद्य-समस्या उत्पादन की दृष्टि से

श्री रामावतार लाल

राष्ट्रों के उत्थान-पतन, अन्तर्राष्ट्रीय युद्धों और मानवता के उत्तरोत्तर विकास में जितना स्थान भोजन की समस्या का रहा है, उतना अन्य किसी समस्या का नहीं। राजनैतिक विप्लवों के मूल्य में पेट की ज्वाला ही प्रत्यक्ष-परोक्ष रूप से कार्यशील रहो है। और वर्तमान में तो भारत की नयी आजादी ही इस प्रश्न को लेकर आशंकित है। है यह आश्चर्य की बात, किन्तु साथ ही एक कटु सत्य भी कि भारत जैसे देश में—जहाँ विश्व के किसी भी भूखंड से अधिक एकड़ों में कृषि होती है, जहाँ कृषि नामक प्रकृति के व्यवसाय पर ६८९ प्रतिशत जनता निर्भर है, और जहाँ की कृषि कुल राष्ट्रीय आय का अकेले ४७६ प्रतिशत उत्पन्न करती है। लोगों की न्यूनतम भोजन-मात्रा के स्तर पर भी पर्याप्त खाद्यान्न नहीं उत्पन्न हो पाता। पुरानी कहावत जो आज भी उतनी ही सटीक उतरती है—कि “भारतीय कृषि जीवन-यापन का साधन-मात्र है, लाभ प्राप्ति का व्यवसाय नहीं”, के वावजूद हमें भर पेट भोजन के लाले पडे रहते हैं। समस्या की विकटता तब और बढ़ जाती है जब हम इसके पुराने स्वभाव पर ध्यान देते हैं। १८८० में अकाल कमीशन ने देश में प्रतिवर्ष लगभग ५० लाख टन के भोजनाधिक्य का अनुमान लगाया था, किन्तु तबसे निरन्तर देश में खाद्यान्न का अभाव ही रहा है। १८९० और १९१२ के बीच हमने सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए पर्याप्त मात्रा में भोजन कभी नहीं पंदा किया। विगत दोनों महा-युद्धों के मध्यवर्ती काल में भी भोजन की कमी ही रही और द्वितीय महा-युद्ध के पूर्व वर्मा-विभाजन के पश्चात् हमारा भोजन आयात प्रतिवर्ष १५-२० लाख टन रहा है। युद्धोत्तरकालीन समय में तो समस्या और भी विकट होती गयी है क्योंकि १९५२ तक देश के खाद्यान्न की मात्रा ४०-४५ लाख टन प्रति वर्ष रही है। भोजन हमारी प्राथमिक आवश्यकता है और इसके अभाव का प्रत्यक्ष प्रभाव देश के अति ही निम्न अथवा पशुवत जीवन यापन-स्तर, ऊँची मृत्यु-दर, सक्रामक रोगों-विशेषकर क्षय की रूढ़ि, प्राणिक अकुशलता, विदेशी विनिमय के हास तथा आर्थिक विकास की धीमी प्रगति पर इतना पड़ रहा है कि राष्ट्र की नयी आजादी, आन्तरिक और भ्राम्यन्तरिक दोनों स्तरों पर खतरे में हैं। राष्ट्र के लिए खाद्यान्न

जंसी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर-निर्भरता अवाञ्छनीय तो है ही, देश के भीतर भी इसके कारण अराष्ट्रीय भावनाओं को अकल्याणकारी प्रगति मिलने की सम्भावना है। बुभुक्षित किं न करोति पापम्। निस्सन्देह तब इस समस्या की जटिलता, कारणों की खोज और सुलझाव के आवश्यक उपायों का अध्ययन और सक्रिय प्रयत्न आज हमारी सबसे बड़ी समस्या है।

१९३९ के पहले हिन्दुस्तान कुछ मात्रा में विदेशों को अन्न निर्यात करता था और खाद्यान्न-निर्यात को इंगित कर कुछ आर्थिक अचलो में यह भ्रामक विचार है कि द्वितीय महायुद्ध से पहले हमारी भोजन-व्यवस्था सन्तोषजनक थी। अस्तु, इस भ्रम का निराकरण अत्यन्त आवश्यक है। सर्व प्रथम, हिन्दुस्तान जितना निर्यात करता था उससे बहुत अधिक आयात करता था जहाँ १९३८-३९ में हमारे भोजन-आयात की मात्रा १६०३ लाख टन थी, वहाँ निर्यात-मात्रा केवल ७४२ लाख टन थी—दूसरे शब्दों में हमारे खाद्यान्न की आयात-मात्रा निर्यात की अपेक्षा ५३८ प्रतिशत अधिक थी। १९३६-३७ और १९४१-४२ के पञ्चवर्षीय काल में हिन्दु-स्थान प्रतिवर्ष औसतन लगभग १० लाख टन के अधिक ही खाद्यान्न दूसरे देशों से मागता रहा और परिणामस्वरूप आयात में प्राप्त भोजन के लिए उसे प्रति वर्ष लगभग १३५ करोड़ रुपये का व्यय करता पड़ता था। दूसरे, हमारे भोजन-निर्यात की मात्रा इन वर्षों में लगभग नगण्य सी रही है १९३८-३९ में हमारे गेहूँ-निर्यात की मात्रा कुल खाद्यान्न-उत्पादन का केवल २८ प्रतिशत थी और चावल निर्यात का यह प्रतिशत केवल १२ प्रतिशत था। तीसरे, भारत ने खाद्यान्न का जो कुछ भी निर्यात किया, उसका कारण इसका आधिक्य नहीं था, अपितु अन्तर्राष्ट्रीय खाद्यान्न मूल्य का लोभ था यदि यह निर्यात आधिक्य से प्रेरित रहता तो इसी काल में हमारी आजादी के ३० प्रतिशत को अत्यथेष्ट मात्रा से ही सन्तोष न करना पड़ता। चौथे, इन वर्षों का भोजन-निर्यात एक प्रकार से हमारी विवशता थी, जिस तरह इस काल में व्यापार-सतुलन का घनात्मक पक्ष हमारी विवशता थी। न चाहते हुए भी इंग्लैंड जैसे अपन साहूकार देश को

हमें भोजन का निर्यात करना ही पड़ता था। अन्तु, यह निर्विवाद है कि १९३९ से पहले भी भारत खाद्यान्न की अभाव-भावना से प्रताडित ही रहा।

हमारी खाद्यान्न-मस्य्या के मुख्यत दो पक्ष हैं मात्रात्मक और गुणात्मक, दूसरे शब्दों में हमारी अविबल जनसख्या को यथेष्ट मात्रा में तो खाद्य सामग्री नहीं ही प्राप्त होती, जो कुछ मिल पाती है वह भी अत्यन्त ही निम्न कोटि की। प्रथमतः जैसा हम अभी निर्देश कर चुके हैं १८९२ से ही भारत में खाद्यान्न का अभाव रहा है। प्रथम महायुद्ध के आरम्भ तक का खाद्यान्नाभाव का विस्तृत विवरण 'मूल्य-अनुसन्धान-समिति १९१४' की विज्ञप्ति से उपलब्ध है। दोनो युद्धों के अन्तरिम-काल को परिस्थिति भी नितान्त असन्तोषजनक रही है। १९३०-४० की अवधि के प्रत्येक वर्ष में हिन्दुस्तान में १२ प्रतिशत खाद्यान्न की कमी रही। अर्थ यह कि इन वर्षों में हम केवल ८८ प्रतिशत लोगों के लिए ही अन्न पैदा कर सके थे। शेष के लिए हमें विदेशी बाजारों पर निर्भर करना पड़ता था। १९३६-३७ के वर्मा-विभाजन से खाद्यान्न पर निर्भरता और भी बढ़ गयी क्योंकि इस विभाजन से देश को लगभग १२-२० लाख टन चावल की प्रति वर्ष क्षति हुई। द्वितीय महायुद्धजनित कठिनाइयों ने इस खाद्यान्न-सकट के साथ गटबन्धन किया, जिसका प्रथम प्रहार १९४३-४४ के लोम-हर्षक बगाल-अकाल के रूप में मिला, जिसमें भूखी मानवता ने घुट-घटकर दम तोड़ा, इस भयकर क्षुधा-ज्वाला में लगभग १५ लाख व्यक्ति स्वाहा हो गये—द्वितीय महायुद्ध की कुल मृत्युसख्या का लगभग ४०-५० प्रतिशत। यह अकाल वर्षों से कार्यशील अन्न सकट का केवल वाह्य विस्फोट मात्र था। १९४१-४२ में अन्त होनेवाले पंचवर्षीय काल में प्रतिवर्ष देश लगभग १० लाख टन अनाज बाहर से खरीदता रहा। १९४५-४६ में केवल फसलों की बर्बादी के कारण हमें ७५ लाख टन भोजन-सामग्री की कमी रही, दूसरे शब्दों में देश के ६ करोड़ लोगों के लिए खाद्य सामग्री का आयोजन नहीं था। फिर भी अप्रैल और नवम्बर (१९४५) के बीच देश ने अंग्रेजी सरकार की उदार-नीति के फलस्वरूप लगभग ४३ हजार टन चावल विदेशों को निर्यात किया। यद्यपि १९४७ से ही राष्ट्रीय सरकार इस समस्या की ओर जागरूक रहने लगी है, फिर भी १९४९-५२ के बीच हमारे खाद्यान्न की मात्रा औसतन लगभग ४०-४५ लाख टन प्रतिवर्ष रहती आयी। १९४८-४९ के खाद्यान्न-अभाव को ५३ लाख टन रखने पर और वर्तमान जन-सख्या वृद्धि दर रहने पर हमारी अभाव-मात्रा हर पाचवें वर्षान्ति पर ५३ लाख से बढ़कर ९९ लाख और फिर बढ़ कर १२६ लाख टन पर पहुँच जायगी। खाद्य सकट का सबसे आधुनिक अनुमान योजना अयोग ने दिया है।

योजना आयोग ने अन्नाभाव का विवरण निम्न प्रकार से दिया है—

- (अ) (१) १९५० की कुल वास्तविक आवादी (बच्चे, जवान, स्त्री और बृद्धों को मिलाकर)—३५७ करोड़।  
 (२) १९५० की (३५७ करोड़ आवादी को प्रौढ व्यक्तियों में बदलने पर) प्रौढ आवादी ४३०७ करोड़  
 (ब) (१) १९४६ की कुल अनुमानित आवादी ३८३ करोड़  
 (२) १९५६ की कुल अनुमानित प्रौढ आवादी ४०९ करोड़

- (१) प्रति प्रौढ व्यक्ति को प्रतिदिन १३ ६७ पाँड की अन्न-मात्रा रखने पर (पर १२॥ प्रतिगत वीज वर्ग-रह के लिए छोड़ देने पर) १९५९ में उपलब्ध अन्न-मात्रा ३९८ लाख टन  
 (२) उम माल ने अन्न-आयात को मिलाकर देश में कुल उपलब्ध अन्न मात्रा ४२७ लाख टन  
 (१) वीज आदि जोड़कर १९५६ की अनुमानित प्रौढ आवादी के लिए आवश्यक अन्न की मात्रा  
 (१) प्रतिदिन प्रति प्रौढ को १३ ६७ पाँड मिलने पर ५२४२ लाख टन  
 (२) प्रतिदिन प्रति प्रौढ को १४०० पाँड मिलने पर, ५३६९,,  
 (३) प्रतिदिन प्रति प्रौढ १५०० पाँड मिलने पर, ५७५३,,  
 (४) प्रतिदिन प्रति प्रौढ १६०० पाँड मिलने पर, ६१३६,,  
 (१) (१९५० की तुलना में) १९५६ में अन्नाभाव की मात्रा,  
 (१) १३ ६७ पाँड की दर पर, ६९०४ लाख टन  
 (२) १४०० पाँड की दर पर, ८१७० लाख टन  
 (३) १५०० पाँड की दर पर, १२०१० लाख टन  
 (४) १६०० पाँड की दर पर, १५८४० लाख टन

इस तरह कमीशन की राय में, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति वर्ष में भी देश में अन्न की कमी (आवादी के प्रति प्रौढ व्यक्ति को १३ ६७ पाँड प्रतिदिन मिलने पर) लगभग ७० लाख टन की होगी और १४, १५ और १६ पाँड की उपलब्धि पर यह कमी क्रमशः ८२, १२० और १५८ लाख टन हो जायगी। इस तरह योजना-काल के अन्त तक कम-से-कम १ करोड़ टन अन्न का उत्पादन तो बढ़ना ही चाहिये और खाद्यान्न के अभाव की मात्रा न्यूनतम ७० लाख रहेगी ही।

किन्तु यह तो हमारे खाद्यान्न-सकट का केवल मात्रात्मक पक्ष है। गुणात्मक दृष्टि से भी हमारी भोजन-व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है। यही नहीं कि देशवासियों को भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, बल्कि जो कुछ भी मिल पाता है, वह अत्यन्त ही निम्न कोटि का होता है उनमें जीवनी-शक्ति या पोषक तत्वों का बड़ा अभाव रहता है तथा नरक्षात्मक शक्ति की नितान्त कमी। अमेरिकन भोजन विशेष श्री ऐंटवाटर की राय के अनुसार, एक व्यक्ति को प्रतिदिन ३५०० कैलोरीज भोजन में प्राप्त होनी चाहिये परन्तु एक औसत भारतीय को केवल १८०० कैलोरीज मिल पाती है। कट्टोल और राशनिंग के जमाने में तो नगर-जनसख्या के औसत व्यक्ति को प्रतिदिन केवल १२०० कैलोरीज उपलब्ध थी, जब राशन को मात्रा केवल १२ छटाक प्रतिदिन प्रति व्यक्ति थी। अन्य देशों की तुलना में हमारे भोजन में उपलब्ध जीवनी शक्ति की अभाव मात्रा का अनुमान तब लगता है जब हम निम्नलिखित तालिका पर ध्यान देने हैं

देश	भोजन में प्रति व्यक्ति उपलब्ध जीवनी शक्ति
अमेरिका	३३०० कैलोरीज
इंग्लैंड	३००० "
डेनमार्क	२४०० "
नार्वे	२४०० "
जैकोस्लोवाकिया	२४०० "
भारत	१८०० "

द्वितीय महायुद्ध के पूर्वकालीन समय में एक अनुसंधान के आधार पर हमारी जनसंख्या के केवल ३९ प्रतिशत लोगो को ही उच्च कोटि का भोजन यथेष्ट मात्रा में मिल पाता था, ४१ प्रतिशत लोगो को निम्न कोटि का और शेष २० प्रतिशत लोगो को अति ही निकृष्ट कोटि का भोजन उपलब्ध था। डाक्टर आक्रायड की राय में देश के ९५ प्रतिशत निवासियों को समुचित प्रकार का भोजन नहीं मिलता था। १९४४ के आकड़ो के अनुसार यह ७० प्रतिशत है। दूध, साग-सब्जी, अंडा, मछली-मास तथा अन्य पौष्टिक तथा सरक्षात्मक भोजनो की कमी तो एक खुला रहस्य है। उदाहरणतः दूध का उपयोग हमारे यहां अन्य देशो के मुकाबिले में निम्नलिखित है —

देश	हर व्यक्ति का प्रति दिन दूध का उपयोग
न्यूजीलैंड	६७ औंस
डेनमार्क	४० "
इंग्लैंड	३९ "
अमेरिका	३५ "
भारत	७ "

देहातो में तो एक भारतीय को औसतन १ छटाक भी प्रतिदिन दूध नहीं मयस्सर हो पाता, जबकि भारत जैसे देश में एक आदमी को न्यूनतम १६ औंस दूध अवश्य मिलना चाहिये। चीनी और गुड जैसे शक्करीय पदार्थों का उपभोग (प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष), इंग्लैंड में ११२ पाँड, अमेरिका में १०३ पाँड और जापान में ३० पाँड है वहा भारत में केवल २० पाँड है। इस तरह भोजन में पोषक तत्वो की कमी के सम्बन्ध में अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं। थोड़े में, हमारी भोजन समस्या के गुणात्मक पक्ष का परिचय, महावरेदारी में, यह है कि हमें भर पेट चना तो नहीं ही मिलता, जो मुट्ठी भर मिल पाता है वह भी सड़ा-गला।

और खाद्यान्न सकट के मात्रात्मक एवं गुणात्मक पक्षो का सामूहिक प्रभाव देश की अर्थ-व्यवस्था के प्रत्येक पहलू पर बड़ा भयंकर पड़ रहा है। भोजन जैसी प्राथमिक आवश्यकता की पूर्ति के अभाव में हमारा राष्ट्रीय जीवन यापन का स्तर पशुवत् होकर इतना नीचा है कि भोजन प्राप्ति और फाकाकशी के बीच की सीमा-रेखा लगभग अदृश्य जैसी है। जीवनी-शक्ति के अभाव में अधिकांश निवासी नाना प्रकार के सक्रामक रोगो के शिकार होते हैं और हमारी मृत्यु दर लगभग सभी सम्य देशो की तुलना में अधिक है, जनता की जीवनावधि बहुत ही कम है—

देश	पुरुषो की जीवनावधि	स्त्रियों की जीवनावधि
न्यूजीलैंड	६५.५ वर्ष	६८.५ वर्ष
स्वीडन	६४.३ "	६६.९ "
अमेरिका	६३.७ "	६८.६ "
ऑस्ट्रेलिया	६३.५ "	६७.२ "
स्विटजरलैंड	६०.७ "	६५.६ "
डैन्ड	६०.२ "	६४.४ "
जर्मनी	५९.९ "	६०.७ "
फ्रान्स	५४.३ "	५५.९ "
भारत	२६.९ वर्ष	२६.६ वर्ष

खाद्यान्न के अभाव का दूसरा भयानक कुपरिणाम यह है कि पेट की खाई को पाटने के लिए हम प्रतिवर्ष करोडो रुपयो का अन्न बाहर से मगाते रहे हैं। समय प्रवाह के साथ भोजनायात की मात्रा और मूल्य दोनो बढ़ते ही गये हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के वर्षों में तो समस्या और भी विकट रही है जिसका अनमान आयात सम्बन्धी निम्न तालिका से लग सकता है—

वर्ष	आयात मात्रा	मूल्य
१९४८	२८४१ हजार टन	१,२९,९२ लाख रुपया
१९४९	३७०६ " "	१,४४,६० " "
१९५०	२१२५ " "	८०,६० " "
१९५१	४७२५ " "	२,१६,३५ " "
१९५२	३८६४ " "	२,०१,०० " "
१९४८-५२	१७२६१ " "	७७२,२७ " "

इस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के केवल प्रथम पांच वर्षों में अन्नायात के लिए लगभग ७७२२७ करोड रुपया खर्च किया है, जिसका प्रत्यक्ष प्रभाव युद्धोत्तरकालीन समय के लिये अत्यन्त उपयोगी विदेशी विनिमय के निरन्तर ह्रास पर पड़ता आया है। इस महान क्षति का अन्दाज हमें तब और स्पष्ट रूप से मिलता है जब हम इस बात पर गौर करें कि देश की चालू २३ बहुददेशीय नदी घाटी-योजनाओ का कुल खर्च लगभग इसका आधा ही अर्थात् केवल ३८५ करोड रुपया है और उनसे लाखो एकड़ भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा मिलेगी, लगभग २७ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न और १७ लाख किलोवाट अतिरिक्त विद्युत शक्ति का उत्पादन होगा। खाद्यान्न के आयात पर हमारा वह वैदेशिक विनिमय खर्च होता है, जिसका उपयोग हम कृषि और उद्योग सम्बन्धी कल-पुर्जों, मशीनो और अन्य आवश्यक सामगियो पर करते और देश में औद्योगीकरण की नींव ठोस करते। अस्तु, अन्न का आयात हमारे आर्थिक विकास की प्रगति में एक अवाञ्छनीय रोड़ा बन रहा है। खाद्यान्न सकट के अन्य कुविपाक भी कम नहीं हैं। केन्द्रीय सरकार १९५२ तक जनता को सस्ता भोजन देने के लिए खाद्यान्न तकावी पर प्रतिवर्ष औसतन २०-२५ करोड रुपया खर्च करती रही है लगभग उसीके बाराबर 'अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन' की प्रगति के लिए प्रतिवर्ष राज्य सरकारो को सहायता के रूप में देती रही है, अन्न प्राप्ति और अन्नाधिक्य-प्रान्तो के वोनस का खर्च भी करोडो रुपया रहा है और स्वयं खाद्यान्न प्रवन्ध का प्रशासन खर्च लगभग १० करोड रुपया प्रतिवर्ष है। इस प्रकार खाद्यान्न का आयात तथा भोजन सम्बन्धी अन्य खर्च मिलकर केन्द्रीय सरकार की सालाना बजट आमदनी का लगभग १०-१६ प्रतिशत प्रतिवर्ष हजम करते रहे हैं।

और इन सब खर्चों का प्रभाव देश के विकासात्मक व्यय की कटौती पर पड़ता है। ऊपर दिये गये भोजन-सम्बन्धी व्यय (१) १९४८-५२ का आयात मूल्य ७७२२७ करोड रुपया और (२) केन्द्रीय बजट की आय का १०-१६ प्रतिशत प्रतिवर्ष बढ़ी आसानी से आर्थिक विकास में

खर्च होता। स्वतंत्र भारत की निर्माण-योजनाओं में खाद्यान्न-समस्या किस प्रकार बाधक हो रही है, इसका अनुमान इससे लगता है कि प्रथम पांच वर्षों के अन्न आयात का सामूहिक योग ७७२२७ करोड़ रुपया जो (१) हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना के कुल खर्च का लगभग ३७४ प्रतिशत है, और (२) इस निर्माण योजना के प्रमुख मद्दिनाई-शक्ति पर किये जाने वाले कुल ५१८ करोड़ रुपयों का ढेढगुणा है। देश की उदर-पूर्ति का यह आवर्तक व्यय भावी निर्माण पर कुठाराघात कर रहा है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी भुगतान-व्यवस्था अस्थिर हो रही है और हमारा खाली पेट राष्ट्र के सम्पूर्ण आर्थिक जीवन को खोखला बनाता जा रहा है। हमारी पर-निर्भरता दूसरे राष्ट्रों पर इतनी बढ़ गयी है कि किसी भी आकस्मिक अन्तर्राष्ट्रीय जिच की अवस्था में देश में कितने ही बगाल अकालों की पुनरावृत्ति हो जायगी। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यन्त आवश्यक है कि खाद्यान्न-समस्या के कारणों की सही छानवीन की जाय क्योंकि इसके बिना सुलझाव के प्रयत्न सफल नहीं हो सकते।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि भारत का खाद्यान्न सकट "मांग-पूर्ति के अस्थायी सन्तुलन से उत्पन्न समस्या नहीं, अपितु यह देश की उत्तरोत्तर वृद्धिशील जनसंख्या तथा निरन्तर ह्रासमान अन्नोत्पादन के स्थायी असन्तुलन के केवल आत्म प्रकाशमात्र है।" अकाल कमीशन १८८० ने बताया था कि तब देश में लगभग ५० लाख टन खाद्यान्न का आविष्य था परन्तु तब से अन्नोत्पादन सदैव आवादी वृद्धि से पीछे ही रहा है। १८९० और १९१२ के बीच जिम अनुपात में आवादी बढ़ी, उस अनुपात में न तो कर्पित भूमि का क्षेत्रफल, और न तो खाद्यान्न फसलों का ही क्षेत्रफल बढ़ा है, दूसरे शब्दों में इस अवधि में आवश्यक अन्न की मात्रा अधिक बढ़ती गयी, अपेक्षाकृत देश में उत्पादित अन्न की मात्रा से। इस तरह मोटे रूप से हमारे स्थायी खाद्यान्न-सकट का प्रारम्भ वर्तमान शताब्दी के आरम्भ-काल से ही होता है। और तबसे आवश्यकता और उत्पादन का असन्तुलन बढ़ता ही गया है अन्नोत्पादन कभी भी आवादी-वृद्धि के साथ कदम नहीं मिला सका है, जो निम्न तालिका से स्पष्ट है —

वर्ष	जन संख्या दस लाख में	प्रतिशत वृद्धि	अन्नोत्पादन, लाख टन में
१९११-१२	२३१६	—	—
१९२१-२२	२३३६	०.९ प्रतिशत	५४३
१९३१-३२	२५६८	१०.६ प्रतिशत	५०१
१९४१-४२	२९५८	१४.८ प्रतिशत	४५७
१९४९-५०	—	—	४५५
१९५०-५१	—	—	४४२
१९५१-५२	३५६८	१३.५ प्रतिशत	४४५

हमारे स्थायी खाद्यान्न-सकट की समस्या में एक तरफ बढ़ती आवादी और दूसरी तरफ घटते अन्नोत्पादन के पारस्परिक असन्तुलन का कितना हाथ है, यह इस तालिका में पूर्णरूपेण स्पष्ट है। वह असन्तुलन विशेष रूप

से १९२१ से अग्रिम वर्षों में और विकटतर होता गया, क्योंकि इसके पहले देश की आवादी की वृद्धि दर बहुत कम थी, परन्तु १९२१ से जनसंख्या लगातार बढ़ती गयी है और वह भी अधिक दर पर। १९२१ और १९५१ में हमारी जनसंख्या २३३६ लाख से बढ़कर ३५६८ लाख हो गयी परन्तु अन्नोत्पादन की मात्रा बढ़ने के बजाय ५४३ लाख टन में घटकर ४४४ लाख टन पर आ गयी दूसरे शब्दों में १९२१ की तुलना में १९५१ की आवादी में जहाँ ५५ प्रतिशत की वृद्धि हुई, खाद्यान्न-उत्पादन में २० प्रतिशत का ह्रास हुआ। कौसी विडम्बना है! १९०० और १९३० के ३० वर्षों में जबकि आवादी में ३४० लाख की वृद्धि हुई वहाँ खाद्यान्न क्षेत्रफल में केवल ४० लाख एकड़ की वृद्धि हुई अर्थात् एक आदमी पर लगभग १।८ एकड़ की वृद्धि। १९३० और १९४० के मध्यकालीन दशक में जहाँ जनसंख्या में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई, खाद्यान्न क्षेत्रफल की वृद्धि केवल १.५ प्रतिशत रही, और खाद्यान्न-उत्पादन में तो वास्तविक रूप से ४ प्रतिशत की कमी हो गयी। कोई आश्चर्य नहीं यदि इस दशक के प्रत्येक वर्ष में, श्री राधा कमल मुखर्जी के मतानुसार, औसतन १२ प्रतिशत जनसंख्या के लिए भोजन का कोई आयोजन नहीं था। यह भयानक प्रवृत्ति युद्धोत्तरकाल में भी कार्यशील रही है। १९४१ की तुलना में १९५१ में जहाँ आवादी में १३.५ प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहाँ अन्नोत्पादन ४५७ लाख से घटकर ४४० लाख टन पर आ गया अर्थात् उसमें ३ प्रतिशत की कमी हुई।

फलस्वरूप यदि कभी खाद्यान्न फसलों के क्षेत्रफल में प्रतिव्यक्ति वृद्धि हुई है तो उपज प्रति एकड़ कम हो जाती गयी है और आवादी वृद्धि के साथ खाद्यान्न मात्रा घटती गयी है। १९३०-४० का दशक इसका जलन्त उदाहरण है, जिसमें खाद्यान्न क्षेत्रफल में १.५ प्रतिशत की वृद्धि के बावजूद अन्नोत्पादन मात्रा में ४ प्रतिशत की कमी हो गयी, जबकि जनसंख्या में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। जनगणना के पिछले दशक के अनुसार भारत की आवादी वृद्धि दर १.२५ प्रतिशत या लगभग ४४-४५ लाख प्रतिवर्ष है, जिसके लिए देश में प्रतिवर्ष ४-५ लाख टन अतिरिक्त अन्न की आवश्यकता है। हिसाब लगाने पर ज्ञात होगा कि हमारी आवादी की वृद्धि दर प्रति घंटा १२०० या प्रति मिनट लगभग ८ है। क्यों न भोजन समस्या विकट हो।

आवादी और अन्नोत्पादन के असन्तुलन से उद्भूत हमारी खाद्यान्न समस्या पर निरन्तर ह्रासमान प्रतिव्यक्ति खाद्यान्न क्षेत्रफल पर दृष्टि डाला जा सकता है।

वर्ष	प्रति व्यक्ति खाद्यान्न भूमि क्षेत्रफल
१९११	०.८३ एकड़
१९२१	०.८६ "
१९३१	०.७९ "
१९४१	०.६७ "
१९५२	०.७७ "

इस तरह जनसंख्या प्रत्येक दशकान्त में बढ़ती गयी है पर खाद्यान्न क्षेत्रफल प्रति व्यक्ति या तो घटता गया है या यथावत् रहा है। परन्तु इस क्षेत्रफल के यथावत् रहने या घटने से कोई आशंका नहीं रहती, यदि हमारी कृषि की प्रति एकड़ उत्पादकता बढ़ती रहती। यह सबको ज्ञात है कि भारतीय कृषि की प्रति एकड़ उपज दुनिया में सभी देशों से कम है, परन्तु इससे भी अधिक चिन्ताजनक बात यह है कि यह उत्पादकता वर्षानुवर्ष घटती जा रही है जो निम्नांकित तालिका से स्पष्ट है।\*

'पेट पर पैसे का प्रहार' हमारी स्थायी खाद्यान्न समस्या का दूसरा कारण है। सोची-सादी भाषा में इसका अर्थ है पिछले कुछ वर्षों में खाद्यान्न क्षेत्रफल के ह्रास पर मुद्दा-फसलो के क्षेत्रफल में वृद्धि। खाद्य फसलो में मुख्यतया चावल, गेहूँ, दाल और ज्वार-बाजरा व मक्का है तथा मुद्दा-फसलो में मुख्यत गन्ना, कपास, तम्बाकू और मूँगफली को स्थान है। १९१३ से लेकर १९४१ तक खाद्यान्न-क्षेत्रफल में ह्रास होता गया है परन्तु मुद्दा फसलो के क्षेत्रफल में वृद्धि होती गयी है जहा कुल कर्षित भूमि में खाद्यान्न क्षेत्रफल का स्थान १९१४, १९२४ और १९४१ में क्रमश घटता हुआ ८१.९ प्रतिशत, ८०.९ प्रतिशत और ८० प्रतिशत

रहा, वहा इन्ही वर्षों में मुद्दा-फसलो का क्षेत्रफल बढ़ता हुआ क्रमश १८.१ प्रतिशत, १९.१ प्रतिशत और २० प्रतिशत था। इन ३० वर्षों में जहा खाद्यान्न क्षेत्रफल में कठिनाई से ५ प्रतिशत मात्र की वृद्धि हुई, वहा कपास और जूट जैसी फसलो के क्षेत्रफल में ५३ प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

अब तक हमने खाद्यान्न-मात्रा की ही कमी पर प्रकाश डाला है, परन्तु इसके साथ-साथ ऐसी प्रवृत्तिया भी कार्यशील रही है जो गुण की दृष्टि से भी हमारे अन्न-सकट को उग्रतर बनाती गयी है। १९१० से लेकर १९४० तक सदैव चावल और गेहूँ जैसी उच्च कोटि के खाद्य फसलो की उत्पादन-मात्रा कम होती गयी है परन्तु ज्वार-बाजरा वगैरह जैसी निम्न कोटि की खाद्य फसलो की उत्पादन-मात्रा में वृद्धि हुई है और जनता उच्चस्तरीय खाद्य के बदले निम्नस्तरीय खाद्यान्न को अपने भोजन में प्रधानता प्रदान करती गयी है। इन फसलो के निरन्तर कार्यशील उत्पादन सूचनाक निम्नलिखित है। †

उत्तरोत्तर बढ़ती जनसंख्या तथा निरन्तर घटती खाद्यान्न उत्पादन मात्रा के स्थायी असंतुलन के साथ कुछ और भी बातें हुई जिसने हमारे अन्न सकट को बढ़ा दिया। इनमें १९३६-३७ के बर्मा-विभाजन और

\*

### पौंड में प्रति एकड़ उत्पादन

	चावल		गेहूँ		
	बंगाल	बिहार	सी० पी०	बम्बई	बंगाल
१९३१-३२ से १९३५-१९३६	८९६	७३८	६६६	४२८	६२४
१९३६-३७ से १९४०-१९४१	८३७	६७६	५९०	३९४	५७७
उत्पादन-ह्रास	५९	६२	७६	३४	४७

### ‡ निम्न कोटि की अन्न-मात्रा की अपेक्षाकृत वृद्धि

अन्न		१९१०-१९१५ (आधार-वर्ष)	१९१५-१९२०	१९२०-१९२५	१९२५-१९३०	१९३०-१९३५	१९३५-१९३८ (अन्तिम-वर्ष)	१९१०-१९३८
के उच्च कोटि कृषि	चावल	१००	११४०	१०८४	१९७२	११०२	१०३५	+ ३५
	गेहूँ	१००	९६२	९३४	९३३	९७८	१०४२	+ ४२
निम्न कोटि के कृषि	ज्वार	१००	१५७४	१६७०	२१०८	२०७१	२०९७	+ १०९७
	जौ	१००	२२४२	२०२६	१७२२	१७३४	१५७१	+ ५७१
	बाजरा	१००	१४००	९०५०	१२६०	१२५०	१२५०	+ २५०
	मक्का	१००	११४०	१०००	१०६०	११२०	१०५०	+ ५०

१९४७ के पाकिस्तान विभाजन के नाम विशेष उल्लेखनीय है। वर्मा-विभाजन के कारण देश को प्रतिवर्ष १३-१५ लाख टन चावल की क्षति हुई। यह स्मरणीय है कि हमारे अनाज-सकट में चावल के अभाव की समस्या प्रमुख है। १९५२ तक चावल की कमी का अनुमान ५ से ७ लाख टन प्रति वर्ष रहा है, जिसका आयात मूल्य लगभग ४०-५० करोड़ रुपये हुआ। पाकिस्तान विभाजन ने हमारे पेट पर और बड़ा प्रहार किया। देश के बटवारा के कारण हमें ७५ लाख शरणार्थियों के लिए अतिरिक्त भोजन-व्यवस्था करनी पड़ी परन्तु इसके कारण हमें ७-८ लाख टन खाद्यान्न सामग्री का घाटा हुआ। पूर्वी बंगाल का चावल प्रान्त, पश्चिमी पंजाब का गेहूँ क्षेत्र तथा दुनिया का सर्वकुशल नहर प्रान्त हमसे अलग हो गया। देश विभाजन के पश्चात भारत में अखंडित हिन्दुस्तान की खानेवाली आवादी का ८२ प्रतिशत रह गया परन्तु कुल कर्षित भूमि का केवल ७७ प्रतिशत, कुल गेहूँ क्षेत्रफल का ७० प्रतिशत, कुल चावल क्षेत्रफल का ७२ प्रतिशत, कपास क्षेत्रफल का ७७ प्रतिशत और पाट क्षेत्रफल का २३ प्रतिशत मात्र रह गया। इस प्रकार पाकिस्तान विभाजन का कुपरिणाम हमारे खाद्यान्न और कच्चे माल दोनों समस्याओं पर भयकर पड़ा। इस तरह वर्मा और पाकिस्तान के अलग होने ने भारत के वार्षिक अन्न भांडार में २०-२२ लाख की क्षति पहुंची।

उत्पादन मात्रा सम्बन्धी उपर्युक्त सूचनाओं से स्पष्ट है कि १९१० और १९३८ के वर्षों में जहां चावल और गेहूँ जैसे उच्च कोटि की उत्पादन मात्राओं में केवल क्रमशः ३५ और ४२ प्रतिशत की वृद्धि हुई, वहां ज्वार, जौ, बाजरा और मक्का जैसे निम्नकोटि की फसलों की उत्पादन मात्रा में क्रमशः १०९७ प्रतिशत, ५७१ प्रतिशत, २५० प्रतिशत और ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई। फलस्वरूप हमारे दैनिक जीवन के आहार में पौष्टिक अन्न की जगह पर निकृष्ट भोजन का व्यवहार होता गया और जीवनी-शक्ति की कमी होती गयी।

साधारण रूप से व्यवस्थित भोजन के लिए अन्न के अतिरिक्त फल-शाक-सब्जी और कन्द तथा मान की आवश्यकता होती है। इनको मिलाकर यूरोप में प्रति व्यक्ति औसत १५ एकड़ कृषिभूमि पड़ती है, परन्तु भारत में यह क्षेत्रफल केवल ०.७७ एकड़ ही है। यदि भारत को अ विकास शाका-हारी भी माना जाय तो सन्तुलित आहार के लिए फलों और तरकारियों का उत्पादन पर्याप्त होना आवश्यक है। परन्तु तथ्य इसके विरुद्ध है। १९४१ के आकड़ों के अनुसार कुल क्षेत्रफल की ८० प्रतिशत कर्षित भूमि में साग-सब्जी और फल आदि की खेती का स्थान केवल ४६ प्रतिशत है। यही नहीं समग्र रूप से देखने पर पौष्टिक आहार के लिए आवश्यक उन फलों और तरकारियों का उत्पादन भी कम होता गया है। जहां अखंड भारत में इनकी खेती का क्षेत्रफल लगभग ४०-४५ लाख एकड़ था १९२० से १९४० तक यहीं औसत कायम रहा—वहां १९४१ में यह कम होकर केवल ३९ लाख एकड़ रह गया—१९१३-१४ में तो शाक-सब्जी और कन्दों का सामूहिक क्षेत्रफल ४७ लाख एकड़ के लगभग रहा।

ऊपर के सक्षिप्त विवरण से यह स्पष्ट है कि हमारा खाद्यान्न सकट स्थायी कारणों का ही प्रभाव है और इसमें निरन्तर बढ़मान जनसंख्या के साथ निरन्तर ह्रासमान अन्नोत्पादन का ही प्रमुख हाथ है। मात्रा और

गुण दोनों दृष्टियों ने यही बात है। वर्मा विभाजन और पाकिस्तान बटवारा भले ही आकस्मिक कारण रहे हों। परन्तु अनिवार्य बढ़ती आवादी, घटता अन्नोत्पादन, खेती की ह्रासमान उत्पादकता, एवं पौष्टिक फसलों का अपर्याप्त स्थान व उत्पादन ही हमारी खाद्या समस्या के रहस्य हैं जो १८९० से आरम्भ हुई, १९२१ से अप्रतर हुई, वर्मा और पाकिस्तान विभाजन से जिसे प्रोत्साहन मिला और युद्धोत्तरकालीन भारत में अत्यन्त विकट होकर राष्ट्र की सर्व प्रथम समस्या बन उठी है।

इसके पूर्व कि हम खाद्यान्न सकट के निराकरण का व्यावहारिक अध्ययन करें, यह आवश्यक है कि तत्सम्बन्धी पिछले प्रयत्नों पर दृष्टिपात कर लें, क्योंकि विगत नीति की सापेक्ष सफलता भावी नीति-निर्धारण में सहायक होगी। जैसा पहले कहा जा चुका है, भारत की खाद्य समस्या बहुत पुरानी है परन्तु लगभग द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ तक वही आमक मत प्रचलित था कि हमारे यहां भोजन समस्या है ही नहीं। फलस्वरूप एक अतिकल योजना के रूप में सरकार की तरफ से कोई प्रयत्न नहीं किया गया। विनाशकारी युद्ध की प्रगति में रत ब्रिटिश सरकार बंगाल अकाल की विभीषिका की ओर भी लगभग उदासीन ही रही। इसके सिवा कि १९४२-४३ में केन्द्र में खाद्यविभाग की स्थापना हुई और खाद्यान्न-नीति समिति ने कुछ सुझाव उपस्थित किये, कोई ठोस कदम इन दिशा में नहीं उठाया गया। यद्यपि 'अधिक अन्न-उपजाओ' आन्दोलन का श्रीगणेश १९४३ में ही किया गया था परन्तु इसकी प्रगति स्वतंत्र राष्ट्रीय सरकार के तत्त्वावधान में ही हो सकी, क्योंकि पाकिस्तान के विभाजन से सरकार इधर अधिक जागरूक रहने लगी। इस मन्त्रव में किये गये सरकारी प्रयत्नों को हम निम्नलिखित खंडों में देख सकते हैं।

(अ) अधिक अन्न उपजाओ-आन्दोलन (१९४३ से १९४७), १९४३ में आरम्भ हुए इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य था (१) तालाब, कुआ, बाघ और ट्यूबवेल वर्ग रह से मिचाई की अतिरिक्त सुविधा प्रदान करके, (२) साधारण और केमिकल खादों के उपयोग में (३) बजर भूमि उद्धार योजनाओं से खेती में विस्तार करके तथा (४) उच्च कोटि के बीज के प्रचार से अधिक खाद्यान्न उत्पादन करना। सरकार ने बीज, खाद वर्ग रह के व वष व वितरण तथा बजर भूमि उद्धार वर्ग रह के लिए आर्थिक आर्थिक मदद द्वारा खेतिहरों को काफी प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया। इस आन्दोलन के अन्तर्गत सरकार को ओर ने ४२ लाख टन अमोनियम मल्फेट नामक रासायनिक खाद, ३२१ लाख टन कम्पोस्ट, ४८४ लाख टन खली तथा ४ लाख टन अच्छे बीज का खेतिहरों के बीच वितरण किया गया। मिचाई के लिए ६४२१७ साधारण कुए खुदे, ४१७ नल-कूप गड़े, ३००० तालाबों का प्रबन्ध हुआ तथा छोटी-बड़ी लगभग २२००० मिचाई की योजनाए पूरी की गयीं। किन्तु लावां रपयों के व्यय और ४-५ वर्षों की अवधि के पश्चात भी आन्दोलन ने कोई विशेष लाभ न हो सका। इसके कारण कुल केवल ९० लाख एकड़ों में खेती का विस्तार हुआ और खाद्यान्न के उत्पादन में केवल २० लाख टन की वृद्धि हो सकी। उत्पादन में केवल २० लाख टन की वृद्धि हो सकी। १९४३-४७ के पांच वर्षों में आन्दोलन की प्रगति के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कुल

लगभग १५ करोड रुपये की सहायता दी जिसमें ६॥ करोड रुपये कर्ज और ८॥ करोड रुपये अनुदान के रूप में दिये गये थे ।

(व) खाद्यान्न की आत्म-निर्भरता योजना—अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की धीमी प्रगति को देखकर १९४७ से इसके स्वरूप को बदला गया और इसे व्यापक रूप देकर योजना में परिणत करने का प्रयत्न किया गया और १९५१ क मार्च तक इसके द्वारा देश को खाद्यान्न के सम्बन्ध में पूर्णरूपेण स्वावलम्बो बनाने का लक्ष्य रखा गया परन्तु बाद में इस लक्ष्य को बढ़ाकर १९५५ मार्च तक कर दिया गया । खाद्यान्न की इस आत्मनिर्भरता पंचवर्षीय योजना का कुल व्यय २८२ करोड ६० रखा गया तथा मार्च १९५२ तक ४४ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया—जिसमें ३६ लाख टन खुली खेती से, ३ लाख टन बजर भूमि उद्धार से, २८ लाख टन नल कूप सिंचाई से तथा २२ लाख टन ईख-क्षेत्रफल के एक भाग को भोजनोत्पादन में लगाने का निश्चय किया गया । इस योजना की मुख्य विशेषताएँ हैं (१) केन्द्रीय ट्रैक्टर सस्था की व्यवस्था, जिसका मुख्य काम है बजर भूमि उद्धार, (२) केला, पपीता तथा साग-सब्जी जैसे दूसरे खाद्यान्नों के उत्पादन को प्रोत्साहन और (३) लगभग ६२ लाख एकड बजर भूमि का उद्धार । विशेष बात इस योजना को यह थी कि इसमें प्रयत्न और लक्ष्य में अधिकतम सामंजस्य लाने के लिये एक-एक वर्ष के अलग-अलग लक्ष्य निश्चित किये गये । इस योजना के फल कुछ उत्साहवर्द्धक रहे । १९४९-५० और १९५०-५१ में क्रमशः ८ लाख और १४ लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन हुआ, परन्तु चूँकि १९५१-५२ में प्राकृतिक कोप के कारण लगभग ८-९ लाख टन की बर्बादी हुई, इस कारण वास्तविक अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि केवल १४ लाख टन ही रही । इसी बच १९५० में आवश्यकता महसूस होने पर एकीकृत उत्पादन योजना के द्वारा अन्नोत्पादन के साथ-साथ कपास और पाट के उत्पादन वृद्धि की भी योजना अपनाई गयी ।

(स) अधिक अन्न उपजाओ—आन्दोलन जाच समिति (१९५२)—युद्धकालीन १९४३ से लेकर १९५०-५१ तक सरकार ने कुल लगभग ६७५ करोड रुपया अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन पर खर्च किया परन्तु फिर भी सफलता सन्तोषजनक नहीं रही क्योंकि १९४९-५१ के दो वर्षों के लिए निश्चित २७ लाख टन अतिरिक्त अन्नोत्पादन लक्ष्य में केवल ५२ प्रतिशत अर्थात् १४ लाख टन ही प्राप्त हो सका । फलस्वरूप सरकार ने फरवरी १९५२ में खाद्यान्न उत्पादन योजना की प्रगति को जाच और आवश्यक उपयोगी सुझावों के लिए श्री कृष्णमाचावी को अध्यक्षता में जी० एम० एफ० इन्क्वायरी कमिटी की स्थापना की ।

समिति ने आन्दोलन की धीमी प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालते हुए बड़े उपयोगी सुझाव पेश किये । समिति की राय में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन अथवा प्रमत्तता के प्रधान कारण हो रहे हैं आर्थिक जीवन के केवल एकांगी पक्ष यह आर्थिक आधार पर मगठिन था । प्रगति के लिए आन्दोलन वे

सगठन का सुझाव देकर इस बात पर जोर दिया है कि इसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण फसल में समुन्नति लाने का प्रयास किया जाय । इसके लिये समिति ने (१) अधिकतम १० वर्षों की अवधि में ही ग्रामीण विस्तार सेवा योजना की सिफारिश की है तथा (२) आन्दोलन को स्थायी अथवा दीर्घकालीन आधार पर सगठित करने का सुझाव दिया है—जिसका मुख्य कार्य हो खेतों का विकास, व्यापक प्रचार एवं प्रसार, लघु सिंचाई योजनाओं पर जोर और खाद्यान्न तथा खेती मन्त्रालय पर पंचवर्षीय योजनागत व्यय के अतिरिक्त लगभग १० करोड रुपये का प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय । केन्द्रीय सरकार ने लगभग सभी सुझावों को स्वीकार किया है । स्मरण हो कि १९५३ अक्टूबर में उद्घाटित स्थायी राष्ट्रीय (विशेषकर) ग्रामीण विस्तार सेवा योजनायें विगत अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के ही विकसित रूप हैं ।

(द) खाद्यान्न का आयात—अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन की प्रगति से स्पष्ट है कि इसके द्वारा राष्ट्र का खाद्यान्नाभाव कभी भी पूरा नहीं हो सकता । फलस्वरूप सरकार १९४८ से ही विदेशों से अन्न मगाती रही है । पीछे हम इनका विस्तृत विवरण दे चुके हैं, जिसके अनुसार राष्ट्र ने १९४८ से १९५२ के पांच वर्षों में कुल लगभग १७३ करोड टन खाद्यान्न का आयात किया और इसके लिए लगभग ७७३ करोड रुपये का व्यय किया ।

(य) नियंत्रण-राशनिंग, अन्न-वसूली व वितरण, खाद्यान्न का सुरक्षित भांडार तथा विनियंत्रण खाद्यान्न की कमी के कारण देश में नवम्बर १९४७ में पूर्ण खाद्यान्न नियंत्रण था । परन्तु पुण्यस्मृति महात्मा गांधी के दबाव तथा १९४८ की भावी उत्पादन मात्रा के अच्छे भविष्य की आशा पर दिसम्बर १९४७ में सरकार ने क्रमिक विनियंत्रण की नीति अपनायी । १९४८ के लिए सुनहरे दृश्य उपस्थित किये गये । परन्तु घटना-चक्र ने आशाओं पर पानो फेर दिया और क्रमिक विनियंत्रण-नीति ने जुलाई-अगस्त १९४८ में आम जनता के लिये भोजन की समस्या बड़ी विकट कर दिया । फलस्वरूप १९४८ दिसम्बर में पुन नियंत्रण लागू किया गया । अभावग्रस्त क्षेत्रों और आधिक्यवाले क्षेत्रों के बीच यथाशक्ति समुचित सम्पर्क स्थापित किया गया तथा सुरक्षित अन्न-भांडार को ३०००० टन से बढ़ाकर दिसम्बर १९४८ तक ९०,००० टन करने का निश्चय हुआ । तब से १९५२ अक्टूबर तक नियंत्रण ही कायम रहा । इसके पश्चात् राष्ट्र भर में विभिन्न राज्यों को पुन विनियंत्रण की ओर अग्रसर होने की छूट मिली । इस दिशा में यह आधुनिकतम खाद्यान्न नीति है जिसे नियंत्रण में विनियंत्रण कहा जा सकता है क्योंकि मौलिक नीति, नियंत्रण की है परन्तु कुछ ढीलापन के साथ—जैसे अन्तर्प्रान्तीय अन्न प्रतिबन्ध के रहते हुए भी अन्तर्प्रान्तीय अन्न की खरीद परन्तु पर, तथा अतिथि स्वागत पर प्रतिबन्ध रहते हुए भी स तथा खुले बाजार के साथ-साथ सरकारी उचित मूल्य ।

का यह नीति परिस्थितियों के अन्तर्गत पिछले साल की अपेक्षा न अच्छी है

तथा सरकार का सुरक्षित अन्न-भांडार भी जनवरी १९५२ में १३३ लाख टन से बढ़कर जून १९५२ में ३३१ लाख टन पर पहुंच गया और १९५३ में अब तक इस भांडार की स्थिति सरकारी घोषणाओं में काफी सन्तोषजनक बतायी जा रही है। इसके अतिरिक्त, जैसी आशा की गयी थी अन्तोत्पादन क्षेत्र में भी काफी सफलता मिली है। अन्न फसलों का क्षेत्रफल बढ़ गया है। विनियत्रण-जनित आरम्भिक मूल्य बढ़ने से किसान को प्रेरणा मिली है क्योंकि १९५१ की अपेक्षा १९५२ के खरीफ क्षेत्रफल में लगभग ६५० लाख एकड़ की वृद्धि हुई है तथा लगभग सभी राज्यों में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा है।

(क) प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्न उत्पादन में सबसे अधिक महत्त्व कृषि को और उसमें भी खाद्यान्न उत्पादन को सर्वोपरि स्थान दिया गया है। खेती विस्तार, घनी खेती, बजर भूमि-उद्धार, रासायनिक खाद, अच्छे बीज वर्ग-रह की सहायता से १३७६ पाँड प्रति वयस्क की दर पर १९५५-५६ तक देश को भोजन के सम्बन्ध में स्वावलम्बी बनाना का सकल्प है। योजना के अंतिम वर्ष तक निम्नलिखित विकास प्रगति अतिरिक्त रूप से प्राप्त होगी —

अतिरिक्त सिंचाई सुविधा १९० लाख एकड़ में जिसमें केन्द्रीय ट्रैक्टर सस्था १४ लाख एकड़, विभिन्न राज्य १२ लाख एकड़ और सहायता प्राप्त किसान ४८ लाख एकड़ बजर भूमि का उद्धार करेंगे।

बजर भूमि उद्धार	७४ लाख एकड़ में
यांत्रिक खेती	२४ लाख एकड़ में
वायु, जल निकासी आदि से खेती विकास	३० लाख एकड़ की
खादों (रासायनिक) का उपयोग	३ लाख एकड़ की

और इस तरह खाद्यान्न उत्पादन को मिलाकर कृषि पर इस योजना के कुल व्यय का लगभग ३८ प्रतिशत खर्च होगा केवल खाद्यान्तोत्पादन पर लगभग १४५ करोड़ रुपया। इस पर १९५५-५६ तक प्रतिवर्ष लगभग ७६ लाख टन अतिरिक्त अन्न का उत्पादन होगा—जिसमें चावल की मात्रा ५४० लाख टन, गेहूँ की २० लाख टन, चना एवं दूसरी दालों की १० लाख टन तथा ज्वार-बाजरा वर्ग-रह की ६ लाख टन होगी। विभिन्न साधनों से कुल ७६ लाख टन खाद्यान्न प्राप्ति का विवरण इस प्रकार है —

साधन	अतिरिक्त खाद्योत्पादन
वृद्ध सिंचाई	२००८७ हजार टन
लघु सिंचाई	२३८४४ " "
बजर भूमि उद्धार एवं विकास	१५१२५ " "
रासायनिक एवं देशी खाद	११४७९ " "
विकसित बीज	५५६६ " "
कुल योग	८११०१ हजार टन
गृहण (-) मुद्रा फसल उत्पादन	५००० हजार "
अन्तिम शुद्ध खाद्यान्न उत्पादन	७६१०१ " "
अर्थात्	७६ लाख टन

सरकारी विज्ञप्तियों और वर्तमान में खाद्यान्न मूल्य तथा मात्रा पर ध्यान देने में ज्ञात होता है कि देश ने खाद्यान्न-स्तर पर ठोस प्रगतिशील कदम उठाया है। १९५२ में ही केन्द्रीय सरकार के पास सुरक्षित अन्न भांडार में पर्याप्त खाद्यान्न था, जिससे क्रमिक विनियत्रण की नीति अपनाई गयी। अप्रिल १९५३ में खाद्यान्न मंत्री श्री रफी अहमद किदवई के अनुसार, अब हमारी भोजन समस्या लगभग सुलझ सी गयी है। हमें १९५४ में १० लाख टन से अधिक गेहूँ के आयात को आवश्यकता नहीं होगी—निश्चित ही यह अत्यन्त आशाजनक स्थिति थी क्योंकि हमारे गेहूँ-आयात की मात्रा पिछले वर्षों १९५१, १९५२ और १९५३ में क्रमशः ४७ लाख टन, ३९ लाख टन और २० लाख टन थी। श्री पञ्जावराव देशमुख के मतानुसार देश में दो वर्षों १९५३-५४ में चावल का आयात दुःस्थिति के कारण नहीं बल्कि अन्न भांडार को अत्यधिक टोम करने के लिए किया गया। १९५२-५३ में चावल, गेहूँ तथा अन्य खाद्यान्नों की फसल अत्यन्त सन्तोषजनक रही। पञ्जाव ने १९५२ के ३५००० टन चावल की अपेक्षा १९५३ में १,२५,००० टन चावल का आयोजन किया है और १९५३-५४ में इसकी मात्रा के २३ लाख टन पूर्ण हुआ है। १९५२-५३ में भारत में अबतक अधिकतम चावल अर्थात् २३४ लाख टन चावल का उत्पादन हुआ, १९५३-५४ के लक्षण और भी सन्तोषजनक दीखे। १९४५-४७६ से लेकर, अबतक देश में गेहूँ का उत्पादन १९५२-५३ में अधिकतम अर्थात् लगभग ६७ लाख टन हुआ है। जी और मक्का में भी १९५२-५३ में अधिकतम उत्पादन अर्थात् क्रमशः २६६ लाख टन और २६ लाख टन हुआ था। लगभग सभी राज्यों में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई और १९५१ की अपेक्षा १९५२ के खरीफ खाद्यान्न क्षेत्रफल में कुल मिलाकर लगभग ६५० लाख एकड़ की वृद्धि हुई है।

ऊपर के विवरण से यह ज्ञात होता है कि हमारी खाद्यान्न समस्या का हल लगभग निकल चुका है, परन्तु ऐसा सोचना सर्व प्रथम अमंगल होगा और दूसरी, हमारी समस्या सम्बन्धी कुछ निहित कठिनाइयों की ओर से मुह मोडना होगा। प्रथमतः उज्वल भविष्य की आशा १९५३-५४ की खाद्यान्न मात्रा की भावी सम्भावना पर आधारित है, हमारे १९५२-५३ के उत्पादन की तुलना १९५१-५२ के उत्पादन से की जाती है, जो वर्ष (अर्थात् १९५१-५२) भारतीय कृषि का साधारण नहीं अति ही दुःखदायी वर्ष था, तीसरे (जैसे सरकारी विज्ञप्तियों में भाजकल बहुधा देखा जाता है) वास्तविक कार्य-सम्पादन और प्रकाशित विवरण में पर्याप्त विमुख अन्तर की ऊँची सम्भावना है, चाँये अनुमान प्रति वयस्क के प्रतिदिन की न्यूनतम खाद्यान्न मात्रा (केवल १३६७ ग्राम) पर आधारित है। और अन्ततः इसमें पौष्टिक भोजन-तत्त्व को लगभग नहीं के बराबर स्थान है।

अस्तु, यह कहना कि १९५२-५३ में आगे हमारा खाद्यान्न-भविष्य अति ही उज्ज्वल है, सर्वथा मत्त नहीं। ऊपर के विवरण में स्पष्ट है कि हमारी खाद्यान्न समस्या के मूल में बढती आवादी और घटते उत्पादन का असन्तुलन नामक त्वायी कारण काम करता है। अब भी इस असन्तुलन की गहराई प्रगस्त है। ऐसी परिस्थिति में (१) दुःखदायी वर्ष १९५१-५२ की तुलना में १९५२-५३ की अच्छी फसल तथा



(२) १९५३-५४ की सन्तोषजनक उत्पादन-मात्रा जैसी अल्पकालीन एव आकस्मिक प्रवृत्तियों पर विश्वास करके भोजन समस्या के स्थायी निराकरण की चर्चा दुराशामात्र ही होगी। ईश्वर करे हमारे प्रयत्न सफल हों, परन्तु वर्तमान में और अधिक परिश्रम करना है। जिस देश में एक-तरफ आबादी-वृद्धि की दर प्रति मिनट ८ है और प्रतिवर्ष ४४-४५ लाख है और दूसरी तरफ खाद्यान्न-उत्पादन में क्रमागत उत्पादन-ह्रास-नियम की प्रवृत्ति उप्रता से कार्यशील है, वहा खाद्यान्न समस्या का प्रधान हल है एक ओर खाद्योत्पादन-वृद्धि तथा दूसरी ओर आबादी वृद्धि पर नियंत्रण।

खाद्यान्न में वृद्धि हमें विस्तृत खेती और गहरी खेती दोनों तरीकों से लानी होगी। दोनों के लिए पर्याप्त सम्भावना भी है। जहा तक विस्तृत खेती का प्रश्न है निम्नलिखित तालिका काफी उपयोगी है, जिसका सम्बन्ध भारत के कुल भूमि-उपयोग से है —

उपयोग	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल
१ जगल	९३० लाख एकड़	१५ प्रतिशत
२ खालिस जोतभूमि	२६६० " "	४३ " "
३ वर्तमान परती	५८० " "	९ " "
४ जोतयोग्य परती	९८० " "	१६ " "
५ जोत के अयोग्य भूमि	९६० " "	१६ " "
	६१५० " "	१,००००

अर्थात् वर्तमान में हम अपनी भूमि के केवल ४३ प्रतिशत में खेती करते हैं परन्तु उसको बढ़ाकर हम आसानी से ५९-६० प्रतिशत कर सकते हैं। १९४३ से ही कार्यशील वजर भूमि-उद्धार योजनाओं का यही महत्त्व है। यद्यपि ग्री० मो० फूड-कॉम्पेन के अन्दर लगभग ५० लाख एकड़ भूमि का उद्धार हुआ है और प्रथम पंचवर्षीय योजना में ७४ लाख टन के उद्धार का आयोजन है, परन्तु हमें लक्ष्य और विस्तृत करने होंगे, साथ ही उद्धार की प्रगति बढ़ानी होगी क्योंकि तत्सम्बन्धी पिछले प्रयत्न इस दिशा में लगभग दीर्घसूत्री रहे हैं। यदि ८८० लाख एकड़ वजर भूमि का उद्धार हो जाय तो वह हमारी खाद्यान्न समस्या के सुलझाव का एक स्थायी साधन होगा।

गहरी खेती अच्छी सिंचाई-सुविधा, उत्तम बीज, देशी और रासायनिक खादों के वैज्ञानिक उपयोग, विकसित औजारों के उपयोग तथा कीड़े-मकोड़ों से सुरक्षा आदि—से भी हमारी खेती के प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ने की काफी सम्भावना है। सामान्यतः हमारी फसलों के प्रति एकड़ उत्पादन में २० प्रतिशत से ३० प्रतिशत तक की वृद्धि लायी जा सकती है—२० प्रतिशत अच्छी खाद से, ५ प्रतिशत अच्छे बीजों के उपयोग से तथा ५ प्रतिशत कीड़े-मकोड़ों से रक्षा द्वारा चावल और गेहूँ की अवस्था में यह सम्भावना क्रमशः ५० प्रतिशत और १०० प्रतिशत है। उन मन्दर्भ में, जैसा कृष्णमाचारी समिति का सुझाव है, खाद्यान्न मूल्य की

उचित सीमा का निर्धारण अत्यन्त आवश्यक है ताकि किसान को उत्पादन वृद्धि का प्रोत्साहन मिल सके। उत्पादन प्रतियोगिता के व्यापक प्रचार से इस प्रवृत्ति को पर्याप्त सफलता मिलेगी। परन्तु यहा सबसे अधिक महत्त्व है भूमि-सुधार योजनाओं द्वारा कार्य सम्पादन। जमीन्दारियों का उन्मूलन हो रहा है परन्तु उसके स्थान पर समुचित भूमि व्यवस्था का सर्वत्र अभाव है। चाहे भूमि वितरण हो, चाहे कोई भी वैकल्पिक भूमि व्यवस्था हो, उत्पादन वृद्धि के लिए किसान को (१) न्यूनतम भूमि मात्रा (२) भूमि पर स्थायी अधिकार (३) तथा शोषण का अन्त, ये तीन सुविधाएँ अवश्य देनी होंगी। तत्पश्चात् सहकारिता पर आधारित खेती का सगठन।

परन्तु उत्पादन मात्रा की वृद्धि से कम महत्त्वपूर्ण पौष्टिक खाद्य का उत्पादन नहीं है। पिछले विवरण से यह स्पष्ट है कि किस प्रकार प्रथम महायुद्ध के पूर्वकाल से ही चावल और गेहूँ का क्षेत्रफल कुछ अंशों में निम्न कोटि की फसलों के उपयोग में आ रहा है। इस अस्वास्थ्यकर प्रवृत्ति को रोकना अत्यन्त आवश्यक है, साथ ही सिंचाई-प्राप्त क्षेत्रों में चावल व गेहूँ नामक खाद्यों का उत्पादन बढ़ाना चाहिये। साग-सब्जी का क्षेत्रफल जो वर्तमान में केवल ४६ प्रतिशत है—बढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि एक शाकाहारबहुल राष्ट्रके लिये इनका स्वास्थ्य-महत्त्व काफी है। इस सन्दर्भ में मास-मछली तथा अडा वगैरह के उपयोग के प्रचार का सरकारी कार्य बड़ा ही सराहनीय है। आज के युग में हमारे देश में लोगों की भोजन की आदत में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। चावल की अपेक्षा गेहूँ का अधिक उपयोग, साग-सब्जी तथा मछली-मास व अडा के उपयोग का व्यापक प्रचार सतुलित आहार के लिए बड़ा लाभप्रद सिद्ध होगा।

आबादी वृद्धि का नियंत्रण हमारी खाद्यान्न समस्या का दूसरा स्थायी हल है। पिछले दशक में यह वृद्धि दर १२.५% प्रतिवर्ष अर्थात् १२०० प्रति घटा है। दूसरे शब्दों में भारत अपनी जनसंख्या-वृद्धि की वर्तमान दर पर हर दसवें वर्ष एक इन्डो और हर छठवें वर्ष एक आस्ट्रेलिया बसा सकता है। मध्यवर्ती काल में भोजन-प्रशासन व्यवस्था का सुधार अत्यन्त आवश्यक है। जब तक देश पूर्णरूपेण आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है, हमें न्यून या अधिक मात्रा में नियंत्रण व्यवस्था को रखना होगा। इस बीच सरकार के लिये सुरक्षित अन्न भांडार को काफी सुदृढ़ करना चाहिये। इस में हम सरकार के उन प्रयत्नों की सराहना करते हैं, जिनके द्वारा वह अन्य देशों से खाद्यान्न-समझौता करके अन्न भांडार को ठोस कर रही है। इनमें मुख्य है (१) १७ अप्रिल १९५३ का अन्तर्राष्ट्रीय गेहूँ समझौता, जिसके अनुसार भारत का कोटा ४५ लाख टन का है, (२) १९५१ का बर्मा-चावल समझौता, जिसके अनुसार हमें प्रतिवर्ष बर्मा से ४ वर्षों तक ३५ लाख टन चावल प्राप्त होगा तथा (३) मार्च १९५३ का समझौता जिसके अनुसार हमें १५ लाख टन चावल मिलने का आयोजन है। खाद्यान्न समस्या के सफल एव स्थायी हल निकलने तक इस प्रकार का सरक्षात्मक आयोजन आकस्मिक परिस्थितियों के लिए परम अनिवार्य हैं।

## भूमि का कायाकल्प

श्री कहैयालाल साणिकलाल मुन्शी

भारतवर्ष में प्रति वर्ष २ अरब ७० करोड़ एकड़ फीट पानी वादलो द्वारा वृहत मोटे अदाज में इस प्रकार वितरित होता है —

(१) १३५ करोड़ एकड़ फीट पानी भाप बनकर उड़ जाता है, धरती गीली करता है, भूगर्भ में चला जाता है अथवा वह कर समुद्र में पहुँच जाता है।

(२) बाकी १३५ करोड़ एकड़ फीट पानी भूमि से वह कर नदियों द्वारा समुद्र में पहुँच जाता है अथवा झील व तालाबों में एकत्र होता है।

(३) इस १३५ करोड़ एकड़ फीट पानी में से सिर्फ एक करोड़ एकड़ फीट पानी मनुष्यों और पशुओं के पीने एवं अन्य कामों में आता है और ७॥ करोड़ के करीव सिंचाई के काम में।

भारत में ३१॥ करोड़ एकड़ भूमि जोती-बोयी जाती है। इसे सीचने के लिये हमें ४५ करोड़ एकड़ फीट पानी की जरूरत है।

यदि अगले दस वर्षों में सिंचाई की हमारी छोटी-बड़ी सभी योजनाएँ सफल रूप से कार्यान्वित हो जाय, तो हमें १० करोड़ एकड़ फीट पानी और मिलने लगेगा। किन्तु तबतक हमारी जनसंख्या ४० करोड़ और पशु संख्या २० करोड़ पर पहुँच जायगी। इस आवादी के निजी उपयोग और भूमि की सिंचाई के लिए ५० करोड़ एकड़ फीट पानी की जरूरत होगी जबकि आज के अदाज में पानी मिल सकेगा सिर्फ १७॥ करोड़ एकड़ फीट।

१७॥ करोड़ एकड़ फीट पानी में ४॥ करोड़ एकड़ की आज की सिंचाई बढ़कर ७॥ करोड़ एकड़ हो जायगी।

भारत की जनसंख्या आजकल ३६॥ करोड़ है। १७॥ करोड़ पशु, ८ करोड़ भेड़ें-बकरी और ७ करोड़ बन्दर एवं अन्य वन पशु हैं। १९६१ में हो जायेंगे क्रमशः ४०,२०, ८॥ और ७॥ करोड़।

आजकल हम ४॥ करोड़ टन खाद्यान्न उत्पन्न करते हैं। ८० लाख टन दाल चना और ३०-५० लाख टन अनाज विदेश में आयात करते हैं। जानवरों के लिए ७५ करोड़ टन घास-चारा निपजाने हैं। अगर केवल खाद्यान्न को ही ले तो वर्तमान आवादी एवं जानवरों को उचित प्रायश्चयना की पूर्ति के लिए ६ करोड़ टन खाद्यान्न और एक अरब टन घास-चारे की

जरूरत होगी। इसके अतिरिक्त १० लाख टन अनाज चाहिए बन्दरों एवं अन्य जगली जानवरों के लिए भी। इस प्रकार दूसरे अन्य उपयोगी पशुओं के लिए भी हमें ७० लाख टन अनाज व २॥ करोड़ टन घास-चारे की कमी पड़ रही है।

इसी हिनाव से १९६१ की आवादी के लिये हमें ५ करोड़ ६० लाख टन खाद्यान्न तथा ११ करोड़ टन घास-चारा चाहिए और इसके ऊपर १० लाख टन अनाज बन्दरों तथा अन्य जगली जानवरों के लिए। इस जरूरत और अब की पैदावार के बीच के अन्तर को अपना उत्पादन बढ़ाकर पूरा करना होगा। करीब १ करोड़ २० लाख टन अनाज और ३५ करोड़ टन घास-चारा और अधिक कैसे उपजाया जाय ? यह एक बड़ी समस्या है।

(१) सिंचाई की नयी योजनाओं के अनुसार करीब २॥ करोड़ एकड़ भूमि सीची जा सकेगी और उसमें ५० लाख टन अनाज ज्यादा-से-ज्यादा और पैदा हो सकेगा।

(२) यदि हमें जंगलों और पेड़ों का पूरा लाभ उठाना है, तो ८ करोड़ ४० लाख एकड़ जंगलों की जगह हमें चाहिए, १९ करोड़ एकड़ जंगल। यदि हम १० वर्षों में ३० करोड़ पेड़ भी लगायेंगे तो वे होंगे १० लाख एकड़ के बराबर ही। पेड़ों ने फल-पत्तों मिलने हैं, ईंधन मिलना है, जिन्में गोबर की बचत खाद के लिए होती है, धरती में नमी कायम रहती है, मिट्टी बहकर नहीं जा सकती और उपजाऊ भूमि क्षय में बचती है। इन सबके फलस्वरूप करीब २॥ लाख टन अनाज की अधिक निपज होगी।

(३) खेती करने योग्य मारी भूमि ४० करोड़ एकड़ है, जिन्में से १२ करोड़ ३० लाख एकड़ भूमि की मिट्टी टूट जाती है, २२ करोड़ ४४ लाख एकड़ में खेती होती है और ६ करोड़ २० लाख एकड़ बजर है ऐसी ही १ करोड़ ३० लाख एकड़ भूमि जिन्में जोतने योग्य माना गया है, पर जो बजर पड़ी है, उनमें में केवल एक करोड़ एकड़ भूमि का ही निष्चय रूप में दोआ जाना विदित है। यदि हमें अगले १० वर्षों में जोत-बोई लिया जाय, तो ३० लाख टन अनाज और मित्र सकेगा।

इस प्रकार फिर भी करीब ४० लाख टन अनाज की कमी पड़ेगी और इसके अतिरिक्त दाल-चने और घास-चारे की। और यह कमी पूरी हो सकेगी तो उस ५ करोड़ से ७।१ करोड़ एकड़ भूमि के द्वारा ही जिसमें सिंचाई मभव होगी। उस भूमि में अच्छा बीज बोना होगा, आवश्यक खाद देनी होगी, उसका जीव-जंतुओं से बचाव करना होगा, बरसात और सिंचाई का सही उपयोग करना होगा।

(४) इस प्रकार की धनी खेती से एक तिहाई टन प्रति एकड़ की साधारण निपज में एक तिहाई की वृद्धि मभव है अर्थात् प्रति एकड़ एक दशांश टन से कुल ५ करोड़ ऐसी भूमि में ५० लाख टन अधिक अनाज की आशा की जा सकती है।

लेकिन यह अनुमान भी पूरी तौर से विश्वसनीय नहीं है। पानी की कमी दूर हो जाने पर भी यह कैसे कहा जा सकता है कि हर जगह की उपज और खेती एक समान ही होगी। मान लीजिए येन-केन-प्रकारेण एक समान हो भी गयी तो सदा एक समान बनी ही रहेगी इसकी क्या गारंटी है ?

तब इन सभावित कठिनाइयों से किस प्रकार रक्षा की जाय ? इसका एक ही उत्तर है और वह है खादों की उपयोगिता। प्रति-एकड़ भूमि में ८२० पौंड की उपज को १३०० पौंड करने के लिए १२ लाख टन गंधक-क्षार, ८ लाख टन स्फुर अम्ल (सुपर फास्फेट), ७९ लाख टन मलवा और १७ लाख टन खली की आवश्यकता होगी।

यहां हम पशुधन के महत्व को भी नहीं भूल सकते। पशु भूमि की रक्षा के प्रमुख साधन हैं। गोमाता और नन्दी की पूजा के पीछे यही रहस्य छिपा है जिस पर हम गम्भीरता से विचार नहीं करते। हमारे देश में १३ करोड़ ४० लाख गायें और सांड हैं। इसमें से साढ़े पाच करोड़ बैल

हैं जो अन्नोत्पादन और सिंचाई कार्य में योग प्रदान करते हैं। इनका गोबर और इनकी हड्डिया तक भूमि को उपजाऊ बनाने में अत्यधिक सहायक होती हैं। हमारे पशुओं से हम एक करोड़ ८० लाख टन दूध प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में ५ औंस दूध पडता है जबकि प्रत्येक व्यक्ति को कम-से-कम १६ औंस दूध मिलना चाहिये। इस अभाव की पूर्ति तभी की जा सकती है जबकि हम उपयोगी पशुओं की रक्षा करना सीख लें। अनुपयोगी पशुओं को उपयोगी पशुओं से अलग रखना चाहिये, क्योंकि उपयोगी पशुओं के लिए ही चारे का पहले से अभाव है।

शहरों की बढ़ती हुई आवादी से भी बड़ी-बड़ी समस्यायें पैदा हो गयी हैं। पानी का अभाव है और शहरी लोगों को बहुत पानी चाहिए। उनके स्वास्थ्य के लिए तमाम चीजों की आवश्यकता पडती है लेकिन बनावटी आदतों के कारण वे धरती को बहुत कम पानी लौटाकर देते हैं। साथ ही जो कुछ मलत्रा आदि एकत्र होता है उसका समुचित उपयोग भी नहीं होता।

शहरों में लोग बड़े-बड़े कीमती मकानों में रहते हैं। अच्छी लकड़ी का सामान भी उपयोग में लाते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कितने ही वृक्षों का दुरुपयोग हुआ और तालावों आदि के निर्माण में जो पत्थर काम में आ सकता था वह न आ सका। ये बातें देखने में मामूली जान पडती हैं, लेकिन इनका बहुत बड़ा महत्त्व है।

देश में अन्न की रक्षा और वृद्धि के लिए हमें अपनी आदतों भी बदलनी चाहिये। भोजन की आदतों का बदलना खास तौर पर जरूरी है।

सक्षेप में, हमें अपने जीवन-दर्शन का बीज फिर धरती पर बोना है। भूमि ग्रामो, और ग्रामीणों में नयी जिन्दगी लानी है आज यही हमारा धर्म होना चाहिए।



वि  
हा  
र  
में

ती  
न  
व  
र्ष

## सामुदायिक विकास योजना के

श्री आर० बालचन्द्र

विहार के जिन हिस्सों में सामुदायिक विकास योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं, उन क्षेत्रों के परिदर्शन से दर्शक पर अमिट छाप पड़ जाती है। हम देखते हैं कि स्वस्थ एवं हट्टे-कट्टे ग्रामीण अपने को वस्तु-स्वच्छ एवं रजक परिवेश में पुनःस्थापित करते जा रहे हैं। अब तक, अविश्वसनीय एवं अकल्प ग्रामीण सामुदायिक अर्थ व्यवस्था की ओर प्रगति हो रही है। यह भी सत्य है कि ग्रामस्तरीय कार्यकर्ताओं को ग्रामीणों को समझा-बुझाकर नये रास्ते पर लाने में पर्याप्त समय लगा है। पर, अब ग्रामीण सहयोगिता के आचारों को समझ गये हैं और प्रत्येक ग्रामीण कृतमकल्प हो चुका है।

पुरानी रूढ़िगत अथ मान्यताएँ समाप्त होनी जा रही हैं और नवार्दश पर स्थापित ग्रामीण जीवन की नींव सुदृढ़ होती जा रही है। हमारा समाज युगों में अलस था, अकर्मण्य था, अब उनी ममाज में चेतना का संचार कर दिया गया है तथा जागरण की स्थिति प्रायः पूरी हो चुकी है। यह सफलता सतत प्रयत्न के अनन्तर मिली है।

ग्राम्य मस्तिष्क रक्ष था, अपरिवर्तित, लेकिन इनके विरुद्ध निश्चित प्रयत्न करने शुरू किये जाने लगे। उनकी रूढ़िगत इधर-उधर न केवल मनोवैज्ञानिक स्तर प्रस्तुत हो गये हैं बल्कि जो कुछ भी कहा गया है उसे पूर्ण करने को पूरे उतावले देखते हैं। ये पूर्ण अथविद्वानी नवार्दश प्राप्त करने के निमित्त अपने स्वार्थों को छोड़ने के लिए भी कर्म कर चुके हैं।

इन सफलता के लिये सरकार को नये मुलाजिमों का कृतज्ञ रहना चाहिए। इन नये अफसरों ने आत्मा के समस्त बल में इन दिशा में अभियान किया। इन अफसरों ने गावों में जाकर वहाँ की स्थिति का अध्ययन

किया, किसानों के दैनिक जीवन की कठिनाइयों का सूक्ष्म अध्ययन किया, अप्रस्तुत जनता को प्रस्तुत किया। भारत का किसान ही पूरे समाज में ऐसा वर्ग है जो केवल फसल के दिनों में ही श्रम करके बाकी समय में सुख में आराम करता है।

सामुदायिक विकास अफसरों ने अपनी कठिनाइयों की बाबत मुझे बतलाया है। वे पहले-पहल जब पेट और कमीज पहन कर गावों में किसानों के बीच जाते थे तब उनका मखौल उड़ाया जाता था। गाव की जनता समझती थी कि इन अफसरों को गावों के कार्यों में देखल नहीं देना चाहिए। लेकिन नवजवान अफसर तो स्वतंत्र भारत की भावना में परिचित हो चुके थे। पेट ऊपर उठाकर वे बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में भी गये। केवल इतना ही नहीं। वे गावों में रहे, सोये और खाया। अब किसान उन्हें नये भारत के नया साहब मानते हैं।

निम्नतम स्तर से नियोजन करने की भावना ग्रामीणों के मन में घर कर गयी है। अब नामूहिक कल्याण के आचार पर मोचने का नम द्रुत गति में घर करता जा रहा है। इन युग का ग्रामीण अब मनझने लगा है कि उसका हित गाव के हित के साथ मलग्न है। सभी क्षेत्रों में नये बुनियादी स्कूल स्थापित कर दिये गये हैं। ग्राम पंचायतों में अब मुकदमों का फैसला किया जाने लगा है। अतः अशान्ति की आयाकाएँ दिनोदिन कम होती जा रही हैं। सहयोग समितियों की स्थापनाओं ने किसानों को गर्दनतोड़ नूतनचारों में मुक्ति मिलनी जा रही है। नुचरे हुए ब्राह्मण मुलम होते जा रहे हैं। जापानी कृषि प्रणाली अब नाचारण भी बान होनी जा रही है और मिचाई के लिए पत्तों का इन्तजाम ग्राम दृग्घ हो गये हैं।

एक सरसरी नजर में गावों के जनबल, उत्पादन और जानवर देखे जा सकते हैं।

भौतिक प्रगति के साथ-साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी परिलक्षित हो रहा है। सामाजिक शिक्षण केन्द्रों में न केवल शिक्षा ही दी जाती है बल्कि जनकलाओं तथा ग्रामीण आमोदों के स्वरूपों का निखार भी हो रहा है। छोटे-छोटे गावों में भी अब पार्क बनाने लगे हैं। ग्रामीण कला और दस्तकारी दोनों ही, नये स्वरूप ग्रहण कर रहे हैं।

आज यदि ग्रामीणों से बात की जाय तब उनकी रचि का ठीक-ठीक पता चल जाता है। ग्रामीण राजनीति में दिलचस्पी उस स्तर पर लेता है जिस स्तर पर अन्य प्रजातंत्र देश के लोग लेते हैं लेकिन उनकी आकांक्षा समृद्ध सुन्दरतम गावों के निमित्त अधिक रहती है। गावोंकी सफाई बड़े पैमाने पर हो रही है। सामुदायिक योजना के अन्तर्गत शायद ही ऐसा कोई गाव है जहाँ कूड़ा-कतवार जमा रहता हो। इन साफ-सुथरे गावों में जाने पर बिहार के किसी भी शहर के स्लमों का स्मरण हो जाता है और अब इन गावों की तुलना में शहरों की गदगी बुरी लगती है।

नई परिस्थितियों के अनुकूल बिहार जैसे पिछड़े प्रान्त की महिलाएँ भी पर्दा छोड़कर आगे बढ़ आई हैं। बच्चों के भविष्य की चिन्ता में गाव की स्त्रियाँ बद्ध परिकर हो गई हैं। जमीन्दारी उन्मूलन कानून पास हो जाने के कारण दबे-पिसे किसान सबल दीख पड़ रहे हैं। सम्मिलित परिवार के विघटन से, सभी जातियों में शिक्षा के प्रचार के कारण, नई प्रवृत्तियाँ जाग्रत हो गई हैं।

लेकिन इन प्रगतियों के अलावा एक चेतावनी भी है। जन साधारण के शत्रुओं की कमी नहीं है। गाव गद्दी राजनीति के अखाड़े हैं। प्रबल राजनीतिज्ञ गावों में काम करने पर तुले हुए हैं। जाति और दल अभी हैं। देहाती समाज को इन दोनों शत्रुओं से रक्षा करने की आवश्यकता है।

सदियों से गाव पिछड़े हुए हैं और ग्रामीण समाज में परिवर्तन शीघ्र होने की सभावना बनी रहती है। ग्रामीणों को प्रगति के रास्ते पर निक्षिप्त रखने के लिए उचित एवं पर्याप्त प्रेरणा देने की आवश्यकता है।

अफसरो, ग्रामस्तरीय कार्यकर्ताओं तथा आँगों की अपेक्षा ग्राम-पचायतों को इस प्रगति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। प्रत्येक पचायत प्रजातांत्रिक केन्द्र की तरह कार्यरत है। बूढ़े लोगों को भी नये लोगों की कार्यकारी क्षमता पूरा विश्वास पैदा हो गया है और ये बूढ़े, जो प्रगति के बाधक माने जाते हैं, बिल्कुल मानो बदल गये हैं। गावों में दायित्व वहन करनेवाले लोगों की अवस्था बीस से तीस वर्ष तक की है। ये नवजवान अन्य राष्ट्रों की प्रगति के साथ कदम मिलाने को उत्सुक रहते हैं।

सामुदायिक विकास योजनाओं के केन्द्र चम्पारण जिले के मलैरिया ग्रस्त दलदल में भी हैं और छोटानागपुर के जगली और पहाड़ी क्षेत्रों में भी तथा इन सभी वितरीत भौगोलिक अवस्थाओं के निवासियों के कल्याण के निमित्त कार्य त्वरित गति से बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। प्रत्येक इलाके के विपरीत ज्वलत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि समस्याएँ हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक क्षेत्र के लोगों की श्रम-शक्ति में भी पर्याप्त अन्तर है, स्वभावों में भी परम्पराओं के अनुकूल।

विविधताओं के बावजूद सभी क्षेत्रों के निवासी आर्थिक विकास में दिलचस्पी ले रहे हैं और अति शीघ्र उन्नति के अन्तिम सोपान तक पहुँच जाने को उत्सुक हैं। इस गति को कई क्षेत्रों में देखने के पश्चात् भय केवल इस बात का होता है कि कहीं प्रतिगामी शक्तियाँ भी समानान्तर गति से काम न करने लग जाय। ऐसी आशा की जाती है कि ग्राम पचायतों के कार्यों के कारण और राष्ट्रीय विस्तार मडलों की वजह से विकास का मार्ग सदैव साफ रहेगा।



# उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार कानून

डाक्टर जी० डी० अग्रवाल

१८५९ में बंगाल टेनेसी ऐक्ट ही ऐसा कानून था जिससे जमीन्दारों के चंगुलों से किसानों को थोड़ी राहत मिली और उन्हें मालिकाना प्राप्त हुआ था। उसके बाद से जितने कानून स्वीकृत हुए उनका उद्देश्य था किसानों को बंदखली से बचाना ही। १८८६ में अब्बट टेनेसी रेंट ऐक्ट की २२वीं धारा के मुताबिक बंदखल करते समय एक वर्ष का मुआवजा जमीन्दार द्वारा दिये जाने की व्यवस्था थी और इसके अतिरिक्त एक वर्ष में किसान को कृषि की तरक्की में जितनी लागत लगी उसे प्राप्त करने का हक उसे प्राप्त था। १९२१ के अब्बट रेंट ऐक्ट के अनुसार किसानों से नजराना लेने पर रोक लगा दी गई। १९२६ के आगरा टेनेसी ऐक्ट द्वारा प्रत्येक किसान को मालकियत दी गई और ऐसा अधिकार दिया गया कि वह अपने खेत बँच सकता है या किसी के हाथ उसे बदल भी दे सकता था। १९३६ के यू० पी० टेनेसी के अनुसार सभी श्रेणी के किसानों को भूमि पर मालकियत दे दी गई। सिर जमीन की हदबन्दी के प्रयास भी किये गये, कानून द्वारा भूमि कर में कमी-बेशी करने की गुंजाइश रखी गयी। रयतों को जमीन में मकान बनाने के अधिकार भी प्राप्त हुए।

प्रायः एक सौ वर्षों के अनुभव के पश्चात् यह स्पष्ट हो गया कि केवल काश्त बना देने से ही रयतों की स्थिति में सुधार संभव नहीं था तथा केवल कानूनों से ही बद्ध जमीन्दारी प्रथा की बुराइयों से उनकी रक्षा नहीं की जा सकती है। बहुत से जमीन्दार गांवों के महाजन भी थे। अतः किसानों के आर्थिक जीवन पर उनका पूरा अधिकार रहता था। धीरे-धीरे यह अनुभूत हुआ कि जब तक कृषि कानूनों में आमूल परिवर्तन नहीं कर दिये जाते तबतक किसानों की स्थिति सुधर नहीं सकती। बिना ऐसे कानूनों के न तो किसान सुखी रह सकते हैं और न उत्पादन की ही अभिवृद्धि हो सकती है। इसी बीच भूमि को मालकियत के सम्बन्ध में क्रान्तिकारी

भाव उदित हुए। कई स्थानों में जमीन्दारियों के उन्मूलन का इतिहास भी प्रेरणा देने के लिए पर्याप्त था। अब कोई भी व्यक्ति जमीन्दारी प्रथा में सुधार की बात नहीं मोचता था बल्कि देश के लोगों के समक्ष जमीन्दारी उन्मूलन का ही प्रश्न प्रमुख रह गया था। २६ जनवरी १९५१ को उत्तर प्रदेश की सरकार ने जमीन्दारी उन्मूलन का श्रीगणेश कर दिया तथा १९५० में ही प्रस्तुत उत्तर प्रदेश जमीन्दारी उन्मूलन तथा भूमि-सुधार कानून स्वीकृत कर लिया गया। १९५२ में इसमें कई संशोधन किये गये।

जमीन्दारी उन्मूलन कानून के मूत्र निम्न तरीके के हैं —

(१) पहली जुलाई १९५२ में जमीन्दारी खत्म कर दी गई है और इसी तिथि में जमीन्दारियों पर सरकार का अधिकार हो जायगा।

(२) राज्य और किसान के बीच के सभी प्रकार के माध्यम समाप्त कर दिये गये। खेतों की बन्दोवस्ती केवल शरीर में अशक्त व्यक्ति, नाबालिग बच्चे तथा विधवाएँ ही कर सकती हैं। कई राज्यों में बन्दोवस्ती के कारण जमीन को गिरवी का स्वरूप दे दिया गया।

(३) रयतों को जितनी किस्में थी वे सब-के-सब हटा दी गई। अब नये कानून के अनुसार तीन प्रकार के कृषक रहेंगे (१) भूमिधर (२) निरदार (३) ग्रामी और (४) अधिवासी।

बुद्ध अबधि के पश्चात् केवल भूमिधर तथा ग्रामी ही रह सकेंगे हैं। इसमें राजस्व संबंधी रिकार्डों का माधारीकरण हो नकेगा तथा किसानों के मुकमेदवाजिया कम हो जायगी।

केवल भूमिधरों को ही भूमि बन्दोवस्ती करने का अधिकार प्राप्त है। इन्हें यह भी अधिकार है कि वे अपनी भूमि का चाहे जैसा और जिस प्रकार उपयोग कर सकें या उसे परती रख सकें। भूमिधर अपनी माती के साथ करा नकना है। माती को उपज का हिस्सा मिलता है। निरदार

भूतपूर्व प्रमुख किसान माने गये हैं। जो लोग सरकार को २५० रुपये भूमि कर देते थे उन्हें भी सिरदार मान लिया गया है। जो जमीन सिर या खुदकाशत को श्रेणी में नहीं हो उसे कोई भी सिरदार बंधक या गिरवी नहीं रख सकता जब तक वह उसका अधिकार प्राप्त न कर ले और ऐसा अधिकार प्राप्त करने के लिए पाचगुणा कर देना जरूरी हो जायगा।

असामी उन रयतों को कहा जाता है जिन्हें पहले भूमि पर किसी प्रकार का अधिकार नहीं था। अधिवासी उनलोगों को कहा जाता है जो २५० रुपये वार्षिक कर देनेवाले मध्यस्थों के असामी थे। लेकिन ऐसी श्रेणी के लोग अधिक दिन तक अवस्थित नहीं रहेंगे। और इनके लिए दूसरी कानूनी व्यवस्था शीघ्र ही की जायगी।

सिरदार, असामी और अधिवासी अपनी भूमि पर केवल खेती कर सकते हैं। खेती के अलावा वे उस पर बागवानी या पशुपालन कर सकते हैं। अगर भूमि दो वर्ष तक परती पड़ी रह गयी तब वे उसके हकदार नहीं रहेंगे। ऐसी जमीन पर गाव समाज का अधिकार रहेगा। सिरदार भी साझी रखकर खेती करा सकता है। सिरदार भी अपनी जमीन का जैसा चाहे इन्तजाम कर सकता है। असामी का अधिकार उसी समय समाप्त हो जाता है जब उसका मालिक अधिकारच्युत हो जाता है। असामी पर अगर लगान अधिक बाकी हो गया तब उसे बेदखल किया जा सकता है या जब बन्दोबस्ती की अवधि खत्म हो जाती है या जब भूमिधर उस भूमि पर स्वतः खेती करना चाहता हो। अधिवासी भी इसी तरीके से बेदखल किये जा सकते हैं।

नये कानूनों के अनुसार प्रत्येक किसान के किसान को अपनी भूमि की तरक्की करने के लिए सभी प्रकार के उपाय काम में लाने का अधिकार प्राप्त है। अधिक उपजाऊ इलाकों में तीस एकड़ की हदबंदी रखी गई है। और जिन इलाकों में जमीन कम उपजाऊ है उन क्षेत्रों में ४५ एकड़ की हदबंदी स्वीकृत की गयी है। सवा छ से दस एकड़ तक की होल्डिंगों का विभाजन, नये कानून से एकदम रोक दिया गया है। कृषि सहयोग समिति के लिए भूमि की अदला-बदली हो सकती है और होल्डिंगों के स्थायित्व के लिए भी। सहयोगिता के लिए भूमिधर और सिरदार कलक्टर से अधिकार माग ले सकते हैं। अगर कर में किसी प्रकार का अन्तर हो तो कलक्टर आज्ञा नहीं दे सकता है। कर वसूली के लिए जमीन बहाल किये गये हैं जिन्हें ग्राम पंचायतों से सभी प्रकार का सहयोग मिलता है। पहली अप्रिल १९५३ से ही २८२ पंचायतों को कर वसूल करने के अधिकार दे दिये गये हैं। इस कार्य के लिये सवा छ प्रतिशत कमीशन पंचायत को प्राप्त हो सकेगा। धार्मिक सम्पत्ति एवं वक्फों की सम्पत्ति पर भी कर निर्धारण किया गया है।

जितने लोगों को भूमि पर परिवर्तन का अधिकार है उन्हें उनकी खुदकाशत जमीनों पर भूमिधारों हक दे दिया गया है। वाग-वगीचों के मालिकों को भी यह अधिकार प्राप्त है। सिरदार अपने लगान का दम-गुना दे देने पर भूमिधर हो जा सकता है। ऐसी रकम एकमुश्त दी जा सकती है या चार छमाही किश्तों में। सरकारी विज्ञप्ति के तीन महीने पश्चात् भूमिधारी हक समाप्त हो सकते हैं। अधिवासी पहली जुलाई १९५७ से भूमिधर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें दो शर्तों का

पालन करना पड़ेगा (१) अपने जमीन्दार से लिखित सहमति लेनी पड़ेगी (२) सरकार को दिये जानेवाले लगान का पन्द्रहगुना देना पड़ेगा। गाव समाज के अधिकार की भूमि पर अगर कोई सिरदारी हक प्राप्त करना चाहेगा तो उसे लगान का दसगुना एक वर्ष में चुका देना होगा और वह भूमिधर हो जायगा। जमीन्दारी उन्मूलन कानून में भूमिधारी अधिकार प्राप्त करने के लिए क्षतिपूर्क वाड दिये जाने की व्यवस्था की गई है। एक सौ रुपये के वाड की कीमत नकद ८० रुपये के बराबर समझी जायगी।

भूमिधारी अधिकार प्राप्त हो जाने पर सिरदार और अधिवासी के लगान आधे हो जायेंगे और तबतक नहीं बढ़ाये जा सकते जबतक इस कानून के लागू होने के दिन से चालीस वर्ष नहीं पूरे हो जाय। जमीन्दारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत जमीन्दारी उन्मूलन कोष की वसूली ३३ ६१ करोड़ रुपये की थी। यह रकम कुल १५६ ३३ करोड़ के अनुमान का २१ ४९ प्रतिशत है। उसी समय तक ३६,६६,७६२ अधिकार पत्र भी दे दिये गये।

गावों में जितने भूमिविहीन किसान थे वे अपने मकानों, आसपास की थोड़ी जमीनों, कुओं और पेड़ों के मालिक हो गये हैं। गाव के अन्य निवासियों की तरह ही गाव की समस्त गैर आबाद भूमि पर, जिसका अधिकार गाव समाज को दे दिया गया है, उनका भी अधिकार है। गाव समाज भूमिहीनों को पहले जमीन बन्दोबस्त करता है। उत्तर प्रदेश में गाव समाजों को कुल मिलाकर ९३ लाख एकड़ परती जमीन दी गई है। इसमें से २० लाख एकड़ भूमिहीनों को दी जायगी।

गाव समाज के, दस और दस से अधिक व्यक्ति, अगर इन लोगों के पास सिरदारी या भूमिधारी का प्रमाण पत्र हो, तब सहयोगिता के आधार पर कृषि आरम्भ कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए कम-से-कम तीस एकड़ भूमि की आवश्यकता है। सहयोग कृषि के रजिस्ट्रेशन हो जाने पर वह तबतक स्थायी रहेगा जबतक सब लोग स्वेच्छा से हट न जाय, उसे विश्रु खल नहीं कर दें।

किसी भी अनाधिक होल्डिंग में सहयोग कृषि आरम्भ करने के पृथक अधिनियम हैं। अनाधिक होल्डिंगों की विशिष्ट परिभाषा भी कर दी गई है। अगर भूमिधर या सिरदार अनाधिक होल्डिंगों में सहयोग कृषि करने के लिए आवेदन करेंगे तब उन सबों की जमीन भी सहयोग कृषि क्षेत्र के अन्तर्गत कर दी जायगी। इसी कानून के अन्तर्गत उन किसानों को सरकारी सहायता दी जायगी जिनके खेत अनाधिक हैं और जिन पर अधिकार कर लिया गया है।

प्रत्येक गाव में ६ अगस्त १९५२ में ही गाव समाज स्थापित कर दिये गये थे। जिस गाव में पचास आदमी से कम हो उन गावों को पास के गावों में सम्मिलित कर दिया गया था। अबतक ८५००० गाव समाजों की स्थापना की जा चुकी है। गाव समाज के अन्तर्गत आनेवाले गाव या गावों की परिधि को सर्किल या क्षेत्र कहते हैं। उस क्षेत्र के सभी जनोपयोगी चीजें गाव समाज के अन्तर्गत रख दी गई हैं। पुन गाव समाज का उस भूमि पर भी अधिकार हो जाता है (१) जिसका कोई वारिस नहीं हों (२) जिस भूमि पर सिरदार या असामी बेदखल किये जा चुके हों

(३) जिसे मिरदार या अमामी छोड़ चुके हो (४) जिस पर कानून के अनुसार गाव समाज को अधिकार प्राप्त हो चुका हो।

प्रत्येक गाव के वालिग औरत और मर्द गाव समाज के सदस्य माने जाते हैं, गाव समाज को मुकदमा दायर करने का, फौजदारी देने का अधिकार है। अबतक के अनुभवों से पता चला है कि गाव समाजों के अधिकार एकदम छोटे हैं या यों कहना चाहिये कि प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से गाव समाज छोटे पडते हैं। अब ऐसा विचार किया गया है कि जिस गाव में २५० छोटे-बड़े लोग रहते हो उसे आसपास के गावों में मिला दिया जाय। इससे कई सुविधाएँ होगी और इसका ख्याल रखा जायगा। ऐसा कर देने से गाव समाजों की संख्या ८५००० से ६५००० तक हो जायगी।

गाव समाज का समस्त काम भूमि-व्यवस्था समिति करती है। गाव समाज के सदस्य भूमि-व्यवस्था समिति के सदस्य होते हैं। सदस्यों की संख्या अगर पाच से कम हो तब कलक्टर की नामजदगी से संख्या पाच कर दी जाती है। भूमि व्यवस्था समिति का मंत्री लेखपाल होता है। अव्यक्त के आदेशानुसार लेखपाल सभी वहीखातों को ठीक रखता है। समिति भूमि के इन्तजाम में पूर्ण तत्परता रखती है और अन्य सम्पत्तियों की निगरानी भी करती है जो समाज के अधिकार में आ गये हैं। गाव समाज के मुख्य काम हैं (१) खाली जमीन का इन्तजाम (२) असाधियों में लगान वसूल करना (३) गाव समाज की भूमि पर अगर किसी ने अधिकार कर लिया हो तब उसे बंदखल करना (४) सरकार की तरफ से भी भूमि कर वसूल करना (५) जमीन का नियोजित उपयोग करना (६) तालाबों, मत्स्यागारों, नालियों एवं रास्तों का निरीक्षण करना। भूमि व्यवस्था समिति के सदस्यों की ट्रेनिंग के लिए सरकार ने ट्रेनिंग देने का इन्तजाम किया है ताकि वे अपने दायित्वों का निर्वाह बखूबी कर सकें। उनके अनुसरण के लिए गाव समाज कानून की पुस्तिका भी प्रकाशित करा दी गई है। ऐसी समितियाँ अपने अधिकारों का दुस्प्रयोग नहीं करें अतः सरकार ने उनके सामयिक निरीक्षण का दायित्व अपने ऊपर ही रखा है। अतः भूमि-व्यवस्था समिति सरकारी आदेशों का पूर्णतया पालन करेगी। अगर समिति सरकारी आदेशों का पालन नहीं कर सके तब सरकार उसे विघटित कर दे सकती है। यह काम तब दूसरे जरिये से कराया जा सकता है। भूमि व्यवस्था समिति के कार्यों के निरीक्षण के लिए राजस्व विभाग के अधिकारी हैं। ये लोग समिति के कार्यों की रिपोर्ट मंडिबीजनल अफसर को देते हैं।

जमीन्दारी उन्मूलन कानून के अन्तर्गत वीचवानों को मुआवजा देने का निश्चय है। उन्हें उनकी वार्षिक आय का आठगुना दिया जायगा। इस रकम पर प्रतिवर्ष ढाई प्रतिशत मूद दिये जाने का इन्तजाम भी है। अन्तरिम रकम देने की गुजाइश नहीं है। दस हजार या उसने ऊपर आमदनीवालों को पुनस्तस्थापन व्यय नहीं दिया जायगा। अन्य कम आयवालों को उनकी आमदनी का बीसगुना दिया जायगा।

प्रत्येक गाव समाज की तरफ जमीन रहेगी जिनका उपयोग जलावन उत्पादन में किया जाय, बाग-बगीचे, फल-फूल आदि लगाये जाय और चारागाह के काम आवे। कानून बनाकर प्रत्येक गाव के लिए

[ इतनी जमीन मानो सुरक्षित रखने का आदेश दे दिया गया है। लेकिन गाव की दश प्रतिशत जमीन सुरक्षित रहनी ही चाहिए और गाव समाज चाहे तब अधिक भूमि भी रिजर्व रख सकता है।

खाली या परती भूमि की बंदोबस्ती के मन्वन्ध में कुछ अन्य नियम भी हैं यानी परती जमीन में से एक किमान को माढ़े सात बीघे जमीन दी जा सकती है। ऐसी जमीन केवल भूमिहीनों को ही बन्दोबस्त की सकती है। एक होल्डिंग पाच बीघे से अधिक की नहीं हो सकती। भूमिधर और सिरदार को सवा छ बीघे जमीन की एक होल्डिंग दी जा सकती है।

जो रयत अपने खतों में बराबर अन्न नहीं उपजा सकते उन्हें उसमें बाग लगाने का हक दिया गया है। बागवानी को प्रोत्साहित करने के हेतु बगीचों की जमीनों पर लगान नहीं वसूल किया जायगा। उन भूमिधरों और सिरदारों की जमीनों का लगान भी नहीं लिया जायगा जिनमें कानून में दर्ज उपयोगी लकड़ियों के पेड़ बंे लगावेंगे।

भूमिधरों और मिरदारों को तकावी कर्ज भी दिये जाने का इन्तजाम है। जब जमीन्दारी उन्मूलन कानून जगलो और परती भूमि पर नहीं लागू किया गया था तब ग्रामीणों को उममें थोड़ा लाभ होता था। हल जुआट आदि के लिए लकड़ियाँ भी मिला जाया करती थी और जानवरों को चरने की पर्याप्त जगह भी मुलभ थी। सरकार ने इस बात का ख्याल रखा है कि जनता के इन अधिकारों का हनन नहीं हो। इसके लिए बाजीबुल अज और दस्तूरदेही के अन्तर्गत किमानों की मुनवाई इन लाभों के निमित्त की जायगी।

पटवारियों को पहले कागजात में नाम दर्ज करने की जो छूट दी गई थी उसे समाप्त कर दिया गया है। पटवारी या लेखपाल का कर्तव्य अब इतना ही है कि वह जमीन सम्बन्धी गलत परतों को देखें और ऊपर के अधिकारी को जाच करने के लिए इत्तिया दे। खतियान और खमरा में लेखपाल किसी भी प्रकार का दर्ज स्वतः नहीं कर सकता है। पहले लेखपालों के तवादले का मामला नैयायिक था और अपने तवादले के मन्वन्ध में एक लेखपाल राजस्व बोर्ड में अर्जी कर सकता था, पर, अब जिग्गीशों को यह अधिकार दे दिया गया है कि वे लेखपालों का तवादल काम की सुविधा के मुताबिक कर सकते हैं। इन मुद्दों का किमानों ने बड़ा स्वागत किया है।

१९५३ में उत्तर प्रदेशीय सरकार ने चकवन्दी कानून पाम किया। इस कानून के मुताबिक ६ वर्षों में पूरे राज्य में चकवन्दी पूरी कर दी जायगी। चकवन्दी ने केवल भूमि का पुनर्वितरण ही नहीं होगा बल्कि गावों का समन्त नक्शा भी बदल जायगा। और नक्शों की व्यवस्था, नालियों का इन्तजाम, आवादी जमीन की वृद्धि, नद के गड़े, स्क्रू, बेल-बंद के मैदान, तालाब तथा अन्य कई प्रकार के सामान ऐसे मुहैया हो जायेंगे ताकि ग्राम्य-जीवन सुन्दर और सुखमय हो सके।

जमीन्दारी उन्मूलन कानून ने भूमि के अन्तर्गत जो जमीनवालों का बहुत दिनों का सजोया हुआ मन्वन्ध पूरा हो गया है। अब किमान पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी जमीन का मालिक हो चला है। यह कर देगा और अपनी जमीन की उज बर ल जायगा।



# राजस्थान में भूमि सुधार

श्री दूल सिंह

किसी भी राज्य व्यवस्था में किसानों को राहत दिलाने के उद्देश्य से बनाये गये कानून के तीन मुख्य आधार होते हैं (१) वन्दोबस्ती की अवधि की सुरक्षा (२) मालगुजारी का निर्धारण (३) मध्यस्थों का उन्मूलन। राजस्थान के भूमि सुधार कानूनों की समीक्षा इन्हीं आधारों पर की जा सकती है।

## अवधि की सुरक्षा

हाल के वर्षों में लगभग सभी प्रगतिशील राज्यों ने जमीन्दारों और रयतों के सम्बन्ध को नियंत्रित एवं निश्चित करने के लिए उचित कार-रवाई की है। राजपूताना की पुरानी रियासतों के टेनेन्सी कानून में जमीन्दारों और रयतों के सम्बन्ध निर्धारित किये गये थे। इनमें से प्रमुख कानून हैं (१) जयपुर टेनेन्सी ऐक्ट (१९४५), (२) बीकानेर लैंड रेवेन्यू ऐक्ट (१९४५), (३) जयपुर राज्य ग्राट्स लैंड टेन्योर ऐक्ट (१९४७) और (४) मारवाड टेनेन्सी ऐक्ट (१९४९)। ये कानून अत्यन्त ही दकियानूमी हैं और अधिक-से-अधिक भिन्न-भिन्न स्थानों में प्रचलित भूमि व्यवस्था को कानूनी रूप देते हैं। ये कानून कोई महत्त्वपूर्ण टेनेन्सी सुधार के लिए नहीं बनाये गये थे और न उनका उद्देश्य पूर्वकाल से शोषित-शासित किसानों को अधिकार ही दिलाना था। जयपुर स्टेट्स ग्राट्स टेन्योर ऐक्ट और मारवाड टेनेन्सी ऐक्ट को छोड़कर खालसा या पहलू से उपाजित रयतों के अधिकारों के समान, गम्भीर क्षेत्रों में रयतों को अधिकार दिलाने की कोई खास चेष्टा नहीं की गई। ये दो कानून जागीर रयतों को, उनके अधिकार को जमीन पर खातेदारी या मालिकाना हक प्रदान करते हैं। रयतों के वर्ग और उनके अधिकार के स्वरूपों को लेकर कानूनों में पर्याप्त विभिन्नता है। उत्तराधिकार या परिवर्तन के द्वारा जमीन पर अधिकार प्राप्त करने के नियमों में भी एकरूपता नहीं है। अधिकार परिवर्तन की अपेक्षा उत्तराधिकार की पद्धति अधिक प्रचलित है।

## खुदकाश्त का प्रश्न

इन टेनेन्सी कानूनों के अन्तर्गत खुदकाश्त की समस्या एक विचित्र प्रकार की है। सम्पूर्ण राजस्थान में खुदकाश्त, सीर या हवेली का प्रश्न

एक खास महत्त्व रखता है। खुदकाश्त के मानी हैं जागीरदार की निजी जोत की जमीन। पिछले कुछ दिनों में ही इसकी प्रमुखता हो गई है, जब से कृषिजन्य पदार्थों के मूल्य में वृद्धि से जमीन पाने की एक होड़ सी लग गई। बड़े-बड़े जागीरदारों ने जब देखा कि जागीरें जल्द की जा सकती हैं तब उनमें स्वतः खेती करने की भावना प्रचंडतर हो गई। उन्हें यह आशा बधी कि जागीरों के जल्द होने पर भी उनकी जोत की जमीनें उनके पास ही रहेंगी। और खासकर यह समस्या इतनी गंभीर नहीं होती अगर छोटे-छोटे जमीन्दारों के सामने नकद मालगुजारी का प्रश्न पैदा न हुआ होता।

## जयपुर व जोधपुर टेनेन्सी कानून

खुदकाश्त जमीनों पर कब्जा पाने तथा उसे निर्धारित करने के लिए जयपुर और जोधपुर टेनेन्सी कानूनों के अन्दर विशेष व्यवस्था है। इसकी मुख्य शकलें निम्नानुकूल हैं

(१) जोधपुर कानून के अन्तर्गत खुदकाश्त भूमि में हेरफेर की गुजाइश है जबकि जयपुर स्टेट्स ग्राट लैंड टेन्योर ऐक्ट के अन्तर्गत ऐसी कोई संभावना नहीं है।

(२) जागीरदार की सीर जमीनें वे हैं जो कानून के लागू होने के पूर्व उनकी जोत में थी, या कानून के लागू होने के बाद ऐसी जमीन, जिसे वे कम-से-कम पिछले छ सालों से जोतते आ रहे हों, किन्तु खुदकाश्त के लिए नई जमीनों पर कब्जा करने की कोई व्यवस्था नहीं है। जयपुर ऐक्ट के अन्तर्गत जमीन्दारों की जायज जरूरतों की पूर्ति के लिए ऐसी जमीनों पर कब्जा पाने की व्यवस्था है जो दुबारे बन्दोबस्त कर दी गई हैं, जिन पर गैर खेतिहरों का अधिकार हो, गैर खेतिहरों की जमीनें, इस्टेट होल्डरों के अपने खर्च से निर्मित पक्के कुओं के इर्द-गिर्द की जमीनें और बारह वर्ष से कम से खातेदार रयतों के कब्जे की जमीनें। इन दोनों कानूनों में अन्तर इतना ही है कि दोनों क्षेत्रों की स्थानीय समस्याएँ अलग-अलग हैं। जोधपुर में काफी जमीन प्राप्य है जबकि जयपुर के कुछ हिस्सों में, जैसे, उदयपुरवाटी, टोडावाटी और शेखावाटी में खुदकाश्त की समस्या सरकार के लिए अत्यन्त ही उलझनपूर्ण बन गई है क्योंकि इन क्षेत्रों में

छोटे-छोटे किसानों के पास जमीन की बहुत कमी है। उनी कानून की खुदकाशत सबधी धाराओं के मुख्य दोष यह थे कि वे रँयतो को सुरक्षा नहीं प्रदान करते जिन्हे परम्परा से जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त है। मालिकों की इच्छा मात्र पर निर्भर किमानों की दशा अत्यन्त शोचनीय हो गई। इस कानून का दूसरा मुख्य दोष यह था कि जागीरदारों द्वारा नाजायज वेदखली के खिलाफ रँयतो की सुरक्षा की भी कोई व्यवस्था सम्भव नहीं थी। यह समस्या इतना उग्र रूप नहीं धारण कर लेती तथा जागीरदारों को जुल्म की भी छूट नहीं होती अगर कानून निर्माता केवल एक और धारा जोड़ देते कि परम्परा से किसानों की जोत की जमीनों से वे वेदखल नहीं किये जा सकते।

### राजस्थान प्रोटेक्शन आव टेनेन्स आर्डिनंस (१९४९)

राजस्थान राज्य ने किमानों को कुछ सामयिक सुविधा प्रदान करने के लिए यह पहला कदम उठाया। वेदखली में वचाने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने जून १९४९ में राजस्थान प्रोटेक्शन आव टेनेन्स आर्डिनंस जारी किया। इस कानून के अनुसार वे सभी रँयत १ एप्रिल १९४८ से जो जमीन जोत रहे थे, या जो उसके बाद वेदखल कर दिये गये थे, पर काबिज कर दिये गये। इस आर्डिनंस की चौथी धारा के अनुसार कोई भी किसान किसी भी कारण से अपनी जोत के सम्पूर्ण या किमी भी भाग से वंचित नहीं किया जा सकता। इसमें वेदखल रँयतो को शीघ्र-से-शीघ्र अपनी जमीन पर एक महल वेदखली विरोधी न्यायालय के द्वारा अधिकार प्राप्त कराने की भी व्यवस्था कराई गई है। इस आर्डिनंस की दूसरी विशेषता यह है कि जो रँयत वेदखली विरोधी न्यायालय के अधिकारों के फँसले में मत्पुष्ट नहीं है वह रेवेन्यू बोर्ड के समक्ष अपील कर सकने का हकदार है, जिसका फँसला अन्तिम तौर पर मान्य समझा जायगा। इसका सर्वाधिक लाभ यह हुआ कि किसान मुकदमेवाजी की परेशानी एवं उसके व्यय से बच गये। किन्तु बाद में कतिपय स्वार्थियों ने इस अदालत को भी प्रभावित कर कई रँयतो को वेदखल कर देने में सफलता पाई है। इसके परिणामस्वरूप कई जिलों में वेदखली विरोधी अदालतों में मुकदमों की नस्य में अधिक वृद्धि हो गई है।

### राजस्थान टेनेन्सी ऐक्ट

प्रचलित भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानून के प्रत्यक्ष दोषों को देखते हुए इस ऐक्ट को स्वीकृत किया गया। इस ऐक्ट के द्वारा तीन प्रकार के रँयतो का वर्गीकरण किया गया है जिनके नाम हैं (१) खानेदार (२) गँर खानेदार और (३) अन्दर रँयत। खानेदार रँयतो को उत्तराधिकार और परिवर्तन के अधिकार प्रदान किये गये हैं वगैरे इन प्रकार के परिवर्तन को प्राप्त करनेवाले की जमीन ७५ एकड़ मून्वी जमीन से अधिक न हो। खुदकाशत जमीनों को छोड़कर अन्दर रँयतो के साथ बन्दोबन्दी जायज है वगैरे रँयत राज्य और वास्तविक जोतनेवाले के बीच कोई मुनाफा स्वयं नहीं ले। रँयतो की तरक्की करने तथा घरेलू एवं कृषि कार्यों के लिए वृक्ष काटने का अधिकार है। बाकी मालगुजारी के नही अदा करने, लगातार तीन माल तक जमीन नही आवाद करने तथा रँयती धनों के नही पालन करने पर रँयतो को जमीन से वेदखल कर दिये जाने की भी व्यवस्था

इस कानून में है। इस कानून के अन्तर्गत नाजायज वेदखली को समाप्त करने की भी गुजार्डश रखी गई है।

### कर निर्धारण

किमी भी भूमि-व्यवस्था के अन्तर्गत नवमे कटिन समस्या कर निर्धारण की है, जो रँयत जमीन के मालिक को देते हैं। राजस्थान में यह समस्या और भी अधिक उलझनपूर्ण रही है, क्योंकि इनमें सम्मिलित होने-वाली रियामतो में नन् १९५० के पूर्व तक कोई लिखित कानून नहीं था। अधिकतर रियामतो में बन्दोबस्ती की व्यवस्था तथा कर बमूली अव्यवस्थित आर्डिनेन्सों, नियमों, रेगूलरानों, मूचनाओं, मर्कूलरों, हिदायतों और सरकारों के द्वारा होती थी। इधर थोड़े दिनों में बन्दोबस्ती कानूनी तौर पर होने लगी है और इस सम्बन्ध में कुछ कानून स्वीकार भी किये गये हैं, जिनकी चर्चा हम उनी लेख में करने जा रहे हैं। जहा तक मालगुजारी के निर्धारण का प्रश्न है, रँयती कानून बहुत ही अस्पष्ट था। राजस्थान राज्य की स्थापना के बाद जमीन जोतनेवालों को राहत दिलाने की आवश्यकता को प्राथमिकता दी गयी, जिनमें जागीरदारों और जमीन्दारों की वेदखली के अधिकार में कमी हो।

राजस्थान के बहुत से भागों में जागीरदार सदियों में उपज के रूप में कर लेते रहे हैं। जमीन की अवस्था और रँयतो में प्रतिस्पर्धा के अनुसार जागीरदार के हिस्से छूटे भाग में आवे हिस्से तक होते थे। केवल महगी के दिनों को छोड़कर साधारण समय में यह पद्धति ठीक ही काम करती थी। पिछली लड़ाई और उसके बाद अन्न के मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि के बाद मुकदमों और मधुपों का निलमिला आरम्भ हुआ। इसलिए जून, १९५१ में राजस्थान सरकार को राजस्थान प्रोटेक्शन ऐक्ट रेगुलेटिंग ऐक्ट लागू करना पडा। इस कानून के लागू होने में किमी भी जागीरदार को उपज की एक चौथाई में अधिक लेने का अधिकार नहीं रह गया। मात्र इस कानून ने ही समस्या का अन्त नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही दिनों में निम्नवृत्तियाँ सामने आने लगी —

(१) इनके अस्थायी होने में बहुत से जमीन्दार इसे लागू ही नहीं होने दिये।

(२) कुछ स्थानों पर यह अनुपात पहले से कर के रूप में निर्धारित अनुपात में भी अधिक हो गया। निकटतम राज्य अजमेर की तुलना में अधिकतम अनुपात भी अधिक था।

(३) "कुल उत्पादन" शब्द की परिभाषा भी निश्चित नहीं की गयी थी, इसलिए, बहुत स्थलों पर यही झगड़े का कारण बन गया।

(४) आवश्यक रूप से इस कानून का क्षेत्र केवल गँर बन्दोबन्त इलाके तक ही सीमित कर दिया गया।

(५) निर्धारित अधिकतम अनुपात में अधिक कर बमूलने की समस्या में किमानों की सुरक्षा के लिए इस कानून के अन्तर्गत राज्य प्रशासन को अधिकार नहीं प्राप्त था।

१९५२ में इस कानून को सुधार कर कुछ दोषों का निवारण किया गया। इसकी अवधि और क्षेत्र में वृद्धि कर इसे सभी कृषिजन्य भूमि पर

लागू कर दिया गया है। "कुल उपज" की परिभाषा भी इस प्रकार की कर दी गई है कि उसमें भूसा, घास तथा अन्य प्राकृतिक उपज सम्मिलित नहीं है।

१९५२ के सुधार कानून का सबसे प्रमुख अंश यह है कि एक चौथाई कर को कम कर एक का छठा भाग कर दिया गया। किन्तु गर्दन तोड़ कर्ज से पीड़ित किसानों को इस परिवर्तन से भी राहत नहीं मिल सकती है, जबतक कि जिला अधिकारियों को इसे लागू करने के लिए विशेष प्रशासनिक अधिकार नहीं प्रदान किये जाते।

राजस्थान उच्च न्यायालय में जागीरदारों ने प्रोड्यूस रेन्ट रेगुलेंटिंग ऐक्ट की मान्यता पर भी प्रश्न उठाया था। जागीरदारों की ओर से यह दलील दी गयी थी कि इस कानून में सघ विधान की धारा १४ में दिये गये समान सुरक्षा के अधिकार की अवहेलना का भाव है और जमींदारों के विरुद्ध रैंयतो के पक्ष में विभेद पैदा करता है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि यह कानून सघ विधान की धारा १९(१) की भी अवहेलना करता है और जमीन्दारों को अपनी संपत्ति रखने में दखलान्दाजी करता है क्योंकि मनमाने ढंग से उनकी आमदनी एक तिहाई और एक चौथाई से घटाकर षष्ठांश कर दिया गया था। जागीरदारों के प्रथम विवाद के विषय में मुख्य न्यायाधीश श्री वाचू तथा उनके साथी न्यायाधीशों ने कहा कि अगर इस दलील को मान ली जाय तो एक विशेष वर्ग के नागरिकों के कल्याण के लिए सभी सुधारों की जड़ पर कुठाराघात होगा और अपने विधान की आत्मा का गला घोटना होगा। जहाँ तक दूसरी दलील का प्रश्न है, यह स्थिर किया गया कि कृषि-शान्ति की उपलब्धि के लिए इस कानून का स्वीकार किया जाना आवश्यक था, तथा कुल उपज का षष्ठांश विलकुल न्यायसंगत है और यह भी नहीं कहा जा सकता कि जमीन्दारों का हिस्सा उलझनपूर्ण बना दिया गया है या उसे मिल्कियत के मात्र निरर्थक अंश ही छोड़े गये हैं। तमाम परिस्थितियों पर पूर्ण सतर्कता से विचार करने के पश्चात् न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि रेन्ट्स रेगुलेंटिंग ऐक्ट विद्वेष-मूलक नहीं है बल्कि इसने संपत्ति रखने पर केवल न्यायसंगत सीमा निर्धारण किया है।

जमीन्दारों के रैंयतो को राहत पहुँचाने के लिए राजस्थान एग्रिकल्चरल रेन्ट्स कंट्रोल ऐक्ट, १९५२ एक दूसरा कदम है। इसे अलवर और भरतपुर जिलों पर लागू किया गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य राज्य के कुछ हिस्सों में जमीन्दारों द्वारा जान-बूझ कर अधिक लगान वमूली पर नियंत्रण करना था। इसके गभाव में रैंयतो की हालत बहुत बदतर हो रही थी। इस कानून के द्वारा निर्धारित भूमिकर के दुगुना लगान तक ही जमीन्दार वसूल कर सकते हैं इसमें शहरी हिस्सों (जिसकी आबादी १५,००० है), में पडनेवाली, विधवाओं, नावालिगों, निस्सहायों और विधायियों, जिनकी आय २१ साल से कम है, को वाद दिया गया है। इस कानून का दूसरा प्रमुख रूप यह है कि यह पैदावार के रूप में कर लेने की जगह द्रव्य के रूप में लेने की गुजाइश प्रदान करता है। रैंयतों में एक आवेदन प्राप्त कर उसी प्रकार की जमीन के लिए, जो किसी निकट की वस्ती में हो सकती है, तहमीलदार निर्धारित दर पर को उपज के रूप में भी कर दे सकता है। तहमीलदार द्वारा कर निर्वा-

रण से सतुष्टि नहीं होने पर रैंयत कलक्टर के यहाँ अपील कर सकता है, जिसका फैसला अन्तिम होगा।

राज्य विधान सभा द्वारा स्वीकृत राजस्थान समरी सेट्लमेंट ऐक्ट १९५३ एक दूसरा महत्त्वपूर्ण कानून है। राज्य के गँर बन्दोवस्त क्षेत्रों में कर निर्धारण के लिए यह एक संक्षिप्त पद्धति प्रदान करता है। यद्यपि सभी खालसा जमीनों और गँर खालसा जमीनों का भी एक प्रमुख भाग साधारण ढंग से बन्दोवस्त किया जा चुका है फिर भी राज्य में बहुत से खतरनाक भाग अभी भी ऐसे हैं जहाँ भूमि के स्वत्व का कोई लेखाजोखा नहीं है। और जहाँ बाकायदा बन्दोवस्ती में अभी कुछ साल और लगेंगे। अतः समरी सेट्लमेंट ऐक्ट समस्या के हल के लिए एक 'क्षिप्रमार्ग' है। यह बन्दोवस्ती विभाग के कर्मचारियों को रैंयतों के अधिकार, भूमि की किस्म, सिंचाई की अवस्था तथा अन्यान्य सुविधाओं को देखते हुए गँर बन्दोवस्त क्षेत्रों में कर निर्धारण का अधिकार प्रदान करता है। इन तथ्यों के आधार पर तबतक अस्थायी तौर पर कर निर्धारण कर दिया जाता है, जबतक कि बाकायदा बन्दोवस्ती नहीं हो जाती। इस पद्धति से, निस्सन्देह ही शेखावाटी आदि खतरनाक क्षेत्रों में रैंयतों को राहत मिली है जहाँ छोटे जमीन्दारों ने, जो स्थानीय तौर पर भोमिया कहलाते हैं, निराश होकर पूर्ण अतक फैला रखा था।

### बीच के तत्त्वों का अन्त

राज्य द्वारा स्वीकृत राजस्थान लैण्ड रिफार्मिंग एण्ड रोजम्पशन ऐक्ट, १९५२ एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कदम है। १९४९ में राजस्थान राज्य के निर्माण के पश्चात् केन्द्रीय सरकार ने राजस्थान और मध्यभारत में जागीरदारी और जमीन्दारी व्यवस्था की जाच तथा भूमि सुधार सम्बन्धी सुझाव उपस्थित करने के लिए वेंकटाचार कमिटी को नियुक्त की थी। इस कमिटी ने १९४९ में अपना प्रतिवेदन उपस्थित किया। इस प्रतिवेदन का निष्पक्ष होकर जाच करने पर यह स्पष्ट विदित होता है कि कमिटी ने उग्र विचारों से अलग रहकर सर्व सम्मति से यह सुझाव पेश किया था कि जागीरदारी और जमीन्दारी व्यवस्था की आवश्यकता अब समाप्त हो चुकी है और इसलिए उनका अन्त आवश्यक है। इस कमिटी के अनुसार जागीरदारों और जमीन्दारों को अपनी होल्डिंग पर कोई मालिकाना हक नहीं है और इसलिए वे अधिक कर के रूप में कोई मुआवजा की मांग नहीं कर सकते। अन्त में यह स्वीकार किया गया कि सामाजिक न्याय के आधार पर जमीन्दारों को मुआवजा के रूप में कुछ आर्थिक सहायता प्रदान की जाय। इन सुझावों के अनुसार राजस्थान सरकार ने जागीरदारी और जमीन्दारी प्रथा के अन्त के लिए नवम्बर १९५१ में एक विधेयक उपस्थित किया जो फरवरी १९५२ में कानून बन गया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य भूमि व्यवस्था से बीच के तत्त्वों का अन्त करना है।

### कानून की परिधि

यद्यपि कानून सम्पूर्ण राजस्थान राज्य पर लागू है किन्तु निम्न दो प्रकार की जागीरों को इससे अलग रखा गया है

- (अ) वह जागीर जिसकी आमदनी से किसी धार्मिक पूजा-पाठ के स्थानों का खर्च चलता है या पूजा-पाठ में लगायी जाती है और
- (ब) जिस जागीर की आमदनी ५,००० रु० से कम है।

सम्भवतः बेंकटाचार कमिटी के विचारों के आधार पर ही द्वितीय श्रेणी की जागीर इस कानून की परिधि से अलग रखी गयी है। कमिटी ने जागीरों को तीन श्रेणियाँ में विभक्त किया है—(१) एक या अधिक गावों की जागीरें, (२) खालसा गावों में छिट-फुट जमीन की मिल्कियत और (३) धार्मिक और दातव्य सस्याओं की व्यवस्था के लिए निर्धारित जागीरें। कमिटी के विचार के अनुसार भूमि-सुधार के लिए छोटी मिल्कियतों को समाप्त करना उतना आवश्यक नहीं था जितना कि बड़ी जागीरों को। निम्नान्वेह यह दृष्टिकोण दोषपूर्ण है क्योंकि समय-समय पर शोषित किसानों पर ये छोटे जमीन्दार बहुत ही जुल्म डालते रहे हैं। भूमियाँ तो सभी स्थानों पर एक ही अव्यवस्था फैलाते रहे हैं, खासकर तोरावाटी और उदयपुरवाटी तो इनके अपराधों के लिए प्रख्यात हो चुका है। इसमें यह साफ जाहिर होता है कि बड़ी-बड़ी जागीरों से भी पूर्व छोटी जागीरों का समाप्त करना अत्यन्त आवश्यक है।

धार्मिक और दातव्य अनुदानों के सम्बन्ध में भी इस कमिटी ने पुरानी व्यवस्था को समाप्त कर स्टैचुटरी इनडाउमेंट बोर्ड के संगठन का सुझाव दिया था। किन्तु कानून यह काम करने में असफल रहा क्योंकि धार्मिक और दातव्य अनुदानों को इस कानून की सीमा से बाहर रखा गया है। इस सम्बन्ध में मद्रास और मंसूर राज्यों की तुलना में राजस्थान का कानून बहुत पीछे है।

### रीजम्पशन (पुनर्ग्रहण) का परिणाम

जागीर के पुनर्ग्रहण के पश्चात् जागीरदारों की जागीर भूमि, जंगल, वृक्ष, कुआँ, खान, खनिज, बाजार इत्यादि बिना किसी अवरोध के सरकार द्वारा ग्रहण कर लिये गए। उन जमीनों की तमाम आमदनी सीधे सरकार को मिलने लगी। जागीरदारों द्वारा किसी तीसरी पार्टी के नाम किये गये वन्धकों आदि को सरकार ने मजूर नहीं किया। जागीर सम्बन्धी सभी आमदनी जागीरदारों को मिलना तथा उनसे कोई भी मालगुजारी आदि का वसूला जाना राज्य द्वारा बन्द करा दिया गया। किन्तु जागीरदारों के ऊपर जो सरकारी कर्ज थे, उसे मसूख नहीं किया गया तथा रँयतों से अपनी बाकी मालगुजारी वसूल करने का उनका अधिकार सुरक्षित माना गया। जागीरदारों के अन्दर के सभी स्कूल, दफ्तर, अस्पताल, और जन-कार्य सम्बन्धी अन्यान्य मकान सरकार को हस्तान्तरित कर दिये गये लेकिन व्यक्तिगत जमीन, मकान, कुआँ, पोखरा, घरवारा, घेरा, बगीचा इत्यादि पर जागीरदारों के हक बरकरार रहे। १ जनवरी १९४९ को या इससे पूर्व रीजम्पशन को मद्देनजर रखकर किये गये तमाम बन्दोवस्ती को भी जागीर आयोग द्वारा रद्द किये जाने योग्य माना गया। कानून में कलक्टर को यह अधिकार दिया गया कि रीजम्पशन के पश्चात् अगर जागीरदार गैर कानूनी ढंग से वसूली करते हैं, तो उन्हें इस प्रकार की वसूली वापिस करनी होगी और दंडस्वरूप ५०० रु० तक जुर्माना भी देना होगा।

### मुआवजा की अदायगी

कानून की दूसरी अनुसूची के अनुसार जागीरों की आमदनी का दसगुणा सरकार जागीरदारों को मुआवजा के रूप में अदा करेगी। इस्टेट मालिकों को दिये गये मुआवजा में जमीन्दार भी मुआवजा पाने

के हकदार घोषित किये गये। कानून की तीसरी अनुसूची में वर्णित धाराओं के अनुसार उनका मुआवजा भी उनकी आमदनी का दसगुणा होगा।

मुआवजा का निर्णय जागीर आयुक्त करेंगे जो जागीर आय से मिलनेवाला निर्वाह-भत्ता, जमीन्दारों को दिये जानेवाला मुआवजा तथा अन्य साक्षीदार को मिलनेवाले अंश का भी निर्णय करेंगे। इन द्रव्यों के अतिरिक्त सरकार से लिये गये कर्ज की रकम को घटा कर वे १५ सालाना किश्त में जागीरदारों को मुआवजा अदा करेंगे। कानून के अनुसार जमीन पर सरकारी कब्जा होने के दिनों से मुआवजा की अदायगी के दिनों तक जागीरदारों को मुआवजा की रकम पर अर्धवर्ष प्रतिवर्ष की दर से साधारण व्याज भी मिलेगा। अन्य हकदारों (जिनके लिए मुआवजा की रकम में हिस्से निकाले जायेंगे) को भी उतने ही दिनों में रुपये मिलेंगे जितने किश्तों में जागीरदारों को मुआवजा की रकम दी जायेगी। जागीरदार की मृत्यु की अवस्था में बाकी बची हुई रकम उसके कानूनी हकदार को मिलेगी। मुआवजा के सम्बन्ध में यह कानून बेंकटाचार कमिटी के सुझावों से थोड़ा भिन्न है क्योंकि उक्त कमिटी ने छोटे जागीरदारों को बड़े जागीरदारों की अपेक्षा अधिक सहायता का सुझाव दिया था। यह बहुत सुन्दर होता अगर मुआवजा सामाजिक न्याय पर आधारित होता।

खुदकाश्त जमीनों को जागीरदारों के हाथ बन्दोवस्त करने की आवश्यकता को यह कानून स्वीकार करता है। अगर किसी जागीरदार को खुदकाश्त जमीन नहीं है या निर्णय की गयी अधिकतम सीमा से कम है, तो उसे कलक्टर अथवा इसी कार्य के लिए सरकार द्वारा नियुक्त नमिति के द्वारा जमीन बन्दोवस्त की जा सकती है। जमीन की अधिकतम सीमा जागीर के क्षेत्र के अनुसार आनुपातिक ढंग से निर्णय किया जायेगा, किन्तु किसी भी परिस्थिति में खुदकाश्त जमीन का रकबा ५०० एकड़ से अधिक नहीं माना जायगा। खुदकाश्त के लिए आवश्यक जमीनें वे होंगी जिन्हें रँयतों अथवा दर-रँयतों ने छोड़ दिया है या वापिस कर दिया है तथा जागीर के अन्दर खेती करने योग्य परती जमीनें हैं। अगर छोड़ी गयी जमीनें प्राप्य नहीं हैं, तो वँसी परिस्थिति में खुदकाश्त के लिए निर्धारित खेती योग्य अधिक जमीन रगनेवालों में लेकर खुदकाश्त के लिए दी जायगी। इस प्रकार कानून ऐसी जमीन को भी खुदकाश्त के रूप में प्रदान करने की व्यवस्था प्रदान करता जो रँयतों की जोन में है। यद्यपि जागीरदारों को भी कुछ जमीन जोतने के अधिकार का लॉग स्वीकार करते हैं फिर भी इस बात की कटु आलोचना हुई है कि यह समय तथा भूमि-व्यवस्था के सिद्धान्त के विपरीत है। एक रँयत को उनकी जोन की जमीन से जागीरदार को खुदकाश्त जमीन प्रदान करने के लिए वेदवच कर देने को प्रतिगामी कदम कहा जायगा तथा आश्चर्य तो तब होता है कि किस प्रकार कानून की किताब में इसको जगह मिल गयी, बेंकटा-चार कमिटी ने यह स्पष्ट कहा था कि किसी भी जागीरदार को रँयतों को वेदवच कर खुदकाश्त जमीन नहीं दी जाय चाहे वह किसी भी श्रेणी का हो। खुदकाश्त की धारा में एक प्रत्यक्ष दुर्गुण यह है कि खुदकाश्त का क्षेत्र बहुत बड़ा रखा गया है।

## पन्त रिपोर्ट और उसके बाद

यद्यपि यह कानून १९५२ के आरम्भ में ही स्वीकृत हो चुका था लेकिन जागीरो द्वारा राज्य उच्च न्यायालय में आदेश के लिए आवेदन उपस्थित करने के कारण तत्काल लागू नहीं किया जा सका। बन्दोबस्ती को शीघ्र पूरा करने के लिए राजस्थान सरकार और जागीरदार दोनों ही विवादास्पद विषयो, जैसे खुदकाशत की बन्दोबस्ती और मुआवजा को पडित गोविन्द वल्लभ पन्त के यहाँ उपस्थित करने के लिए राजी हुये। पडित पत ने सारी बातों को छानबीन कर अपना सुझाव उपस्थित किया। पडित ने हेरू के आदेशानुसार ही यह बात पडित पत के समक्ष पेश की गयी थी इसलिए उन्हें इस विवाद में एक प्रकार का पंच माना गया। पडित पत ने देने और लेने के आधार पर यथासभव मेल-मिलाप का हल पेश किया। यद्यपि दोनों दलों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया, किन्तु, राजस्थान क्षत्रिय महासभा ने प्रधान मंत्री ने हेरू के समक्ष पत रिपोर्ट के बहुत से अशो को चुनौती देते हुए एक स्मृति-पत्र उपस्थित किया जिसमें मुआवजा देने की पद्धति पर उनकी विशेष आपत्ति थी। जागीरदार चाहते थे कि आधी मुआवजा उन्हें पहले मिल जाये और बाकी आधा दस अर्द्ध-वार्षिक किश्तों में। पडित ने हेरू ने इस विषय पर अपने फाँसले में कोई विश्वास नहीं दिलाया क्योंकि उन्होंने इसको सिद्धान्त का विषय नहीं मानकर आर्थिक स्थिति और श्रोतों का विषय माना। खुदकाशत एवं अन्य विषयो पर उन्होंने जागीरदारों से साफ-साफ कहा कि तमाम भूमि कानूनो का उद्देश्य जोतनेवालों और राज्य के बीच से तीसरे व्यक्ति का अन्त करना है और इसी उद्देश्य से देश के सभी राज्यों में इस प्रकार के कानून बनाये जा रहे हैं। अन्ततः यह तय पाया कि १९४८ तक उनके प्रत्यक्ष अधिकार की जमीनें और वे जमीनें जिन पर से १९४९ के राजस्थान प्रोटेक्शन अधिनियम के कारण रयतों की नहीं हटा सके, जागीरदारों को वापिस कर दी जाय। किन्तु जिन जमीनों को रयत बहुत लम्बे अर्से से जोतते आ रहे हैं उनपर से उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता। ऐसी जमीनों के बदले जागीरदार अपने लिए अन्य स्थानों से जमीन प्राप्त कर सकते हैं। प्रधान मंत्री श्री जवाहर लाल ने हेरू ने कहा है कि राजस्थान की भूमि समस्या का हल, चन्द छोटे-मोटे परिवर्तनों को छोड़कर पन्त रिपोर्ट के आधार पर ही करना चाहिए।

पन्त रिपोर्ट के फलस्वरूप जमीन्दारों को अस्थायी रयतों की जमीन पर निश्चय ही लाभ हुआ किन्तु सबसे बड़ी बात, जो इसमें कही गई है, वह है तमाम जागीरों पर सरकार का कब्जा चाहे उसकी आमदनी कम हो या अधिक। सैद्धान्तिक रूप से राजस्थान सरकार और जागीरदारों ने इसे मान लिया है तथा तदनु रूप कानूनो सुधार किये जा रहे हैं।

### राजस्थान भूमि सुधार का नया रूप

राज्य सभा ने १९५४ के मध्य में राजस्थान लैंड रिफार्म्स ऐण्ड रीजम्पशन आण्ड जागीर (अभेन्डमेंट) ऐक्ट स्वीकार किया। राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर करते हुए इसे १८ फरवरी १९५२ से ही लागू करने की अनुमति प्रदान की है अर्थात् मौलिक कानून के आरम्भ की तिथि से। इन अनुसार अब यह कानून उन जागीरों पर भी लागू होगा जिनकी आय धार्मिक मन्द्याओं की व्यवस्था पर खर्च होती थी या ५००० सालाना से

कम थी। दूसरा परिवर्तन जो इस सुधार के द्वारा लागू किया गया है वह है जमीन्दारी का इस कानून से अलग कर अन्य कानून के जन्म करना। इस प्रकार यह कानून मात्र जागीरदारी को ही समाप्त करने के लिए सीमित कर दिया गया है।

### जागीर जमीनों पर कर निर्धारण

इस कानून की एक अन्य मुख्य बात यह है कि अभी तक जागीरदारों से मिलनेवाली रकम को धीरे-धीरे भूमिकर के रूप में परिणत कर देना। जागीरदारों द्वारा दिये जानेवाले कर निर्णय उन्हें प्राप्त भूमिकर के आधार पर कलक्टर करेंगे। इसके बाद उनके द्वारा दिये जानेवाले भूमिकर को निम्नांकित ढग से आका जायेगा —

(क) १९५१-५२ के कृषि वर्षों के लिए उनके द्वारा सरकार को दिये जानेवाली रकम के बराबर।

(ख) इसके बाद पांच कृषि वर्षों तक मालगुजारी से होनेवाली आय का आठवा भाग या प्राप्त होनेवाली रकम के बराबर, जो अधिक होगा और,

(ग) १९५७-५८ के कृषि वर्ष और बाद के वर्षों में जागीर-जमीनों से होनेवाली मालगुजारी से होनेवाली आय का चौथा भाग।

### रयतों के द्वारा खातेदारी हक की प्राप्ति

उन रयतों को छोड़कर जो पहले से ही खातेदार, पट्टेदार या खादिमदार की हसियत से भूमि पर वशक्रमानुसार और परिवर्तन योग्य अधिकार रखते हैं, बाकी सभी को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए वार्षिक कर से दसगुना रकम राज्य के खजाने में जमा करना पडेगा। जागीर जमीन की व्यवस्था में इस प्रकार से प्राप्त सारी रकम सरकार की होगी। किन्तु अन्य स्थितियों में दो तिहाई जागीरदार को मिलेगी। पहले के रयती कानून के अनुसार लगभग किसी भी रयत को जमीन के परिवर्तन का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं था यद्यपि कुछ को छोड़कर बाकी सबों को परम्परागत वशक्रमानुसार भूमि जोतने का अधिकार था। राजस्थान की भौगोलिक अवस्था को देखते हुए खातेदारी अधिकार की प्राप्ति के लिए भुगतान की दर बहुत अधिक मालूम पडती है। यहाँ का अधिक क्षेत्र मरुभूमि है। परिणामस्वरूप खातेदारी अधिकार प्राप्त करना उनके लिए कठिन होगा। जमीन पर पूर्ण परिवर्तन का अधिकार भी श्रेयस्कर नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसी स्थिति में जमीन महाजनों और बाहरों के हाथों में ही प्रायः चली जाती है।

ऊपर कहे गये दोषों के अधिर्कृत भी कुछ बहुत भयकर दोष इस जागीर रीजम्पशन ऐक्ट में वर्तमान हैं। सर्व प्रथम तो इस कानून में उन जोतदारों के रयती हक के विषय में कुछ भी नहीं कहा गया है जो अभी जमीन जोत रहे हैं, वशानुक्रम से उन्हें जोतने का अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन द्रव्याभाव के कारण पूर्ण खातेदारी अधिकार हासिल करने में लाचार हैं। दूसरे इस कानून में परिवर्तन, दर-रयती या बन्धकी के द्वारा जमीन के गैर जोतदारों के हाथ में चले जाने के विरुद्ध कोई सुरक्षा नहीं प्रदान की गयी है। इस प्रकार की व्यवस्था रहनी ही चाहिए जिनमें कि जमीन के जोतनेवाले और राज्य के बीच कोई तीसरा व्यक्ति नहीं रहे जैसा कि उत्तर प्रदेश जमीन्दारी उन्मूलन कानून में है।

## पुनर्वास अनुदान

इस ऐक्ट के अन्तर्गत पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की गयी है। अब जागीरदारों को मुआविजा के अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान भी मिलेगा जिनकी व्याख्या सशोधन के अनुसार कानून की तीसरी अनुसूची में की गयी है। २५० रु० से ५,००० रु० तक की आमदनीवाले जागीरदारों को उनकी आय के ११ गुने से लेकर ५ गुने तक पुनर्वास अनुदान दिया जायगा। ५,००० रु० से अधिक आयवालों को चौगुना से दुगुना तक पुनर्वास अनुदान दिया जा सकता है किन्तु ऐसी परिस्थिति में इस कानून के अनुसार इसका हिसाब लगा लेना होगा कि अनुदान और मुआविजा की रकम मिलाकर जागीर की आय में दमगुणा नहीं हो। इसके अतिरिक्त ३० एकड़ से अधिक सिंचाई योग्य भूमि रखनेवाले जागीरदारों को और अधिक अनुदान देने की भी व्यवस्था है।

मुआविजा देने के सिद्धान्त में भी सशोधन किया गया है। पुराने कानून के अनुसार जागीरदारों को दसगुना मुआविजा देने का विधान था किन्तु अब उन्हें केवल सातगुना ही मिलेगा, लेकिन, अगर अनुदान और मुआविजा दोनों को मिलाकर देखा जाय तो यह रकम पहले से कहीं अधिक हो जाती है जिनकी व्यवस्था मौलिक कानून की दूसरी अनुसूची में की गयी थी। सुधार कानून में जागीरदारों द्वारा वसूल किये जानेवाले चुगी पर मुआविजा की व्यवस्था की गयी है। इस प्रकार जागीरदारों को अब-दान, मुआविजा, खुदकाश्त के लिए अतिरिक्त मुआविजा और चुगी के लिए मुआविजा मिलाकर एक बड़ी रकम की व्यवस्था हो गयी है।

पाठशाला और दातव्य सस्याओं को भी उनके हिस्से में पडनेवाली जागीरों के बदले उनकी आमदनी के बराबर रुपये सालाना मिला करेंगे। इस व्यवस्था से इन सस्याओं को बहुत लाभ हुआ क्योंकि अब बिना प्रयास के ही उन्हें रुपये मिल जाया करेंगे।

ऐसा प्रतीत होता है कि जागीरदारी उन्मूलन में राजस्थान की सरकार उन मानवीय सिद्धान्तों से प्रभावित हुई है, जिनकी स्थापना राजस्थान

मध्यभारत जागीरदारी उन्मूलन कानून आयोग ने भी की थी। जागीरदारों को केवल मुआविजा और अनुदान ही नहीं मिलेंगे बल्कि उनके अधिकारों को भी मुविचाए प्रदान की जायेंगी। नये कानून की धारा २७ की उपधारा २ के अन्तर्गत विधवाओं को विधेप मुविचा प्रदान की गयी है। इन प्रकार जागीरदारों की धार्मिक सस्याओं और अवकाशप्राप्त कर्मचारियों को भी कुछ रुपये प्रदान करने की व्यवस्था की गयी है। नयी धारा ३५ के अन्तर्गत मुआविजा की रकम नकद या वाउ के रूप में या कुछ नकद और कुछ वाउ के रूप में, जैसा सरकार निर्णय करेगी, दी जायेंगी।

कानून की नयी धाराओं के अनुसार खुदकाश्त जमीन की बन्दोवस्ती अब इसी कार्य के लिए नियुक्त खुदकाश्त आयुक्त करेंगे जिनका फौजदारी अन्तिम रूप में मान्य होगा। निस्सन्देह यह एक बड़ा दोष है क्योंकि अनु-तुष्ट पार्षदों को वोटों आफ रेवेन्यू में अपील के अधिकार से वंचित किया गया है।

जहां तक खुदकाश्त के रूप में जागीरदारों को जमीन बन्दोवस्त करने का प्रश्न है, उनमें अब रयतों को बंदखल करके जागीरदारों को जमीन देने का प्रश्न नहीं रह गया। हा, गैरम्पतेदार रयतों को उम जमीन में बंदखल किया जा सकता है जो पहले जागीरदार के निजी जांत में थी। इसके अतिरिक्त नयी सिंचाई क्षेत्रों में अन्दर जागीरों को रियायती शर्तों पर जमीने दी जा सकती है।

जागीर जमीन पर कर निर्धारण की धारण्य निम्न दो प्रकार की जमीनों पर लागू नहीं की जायेंगी, (क) वह जागीर जमीन जिनकी आमदनी किसी शैक्षणिक अथवा धार्मिक मस्या या धार्मिक कार्यों में खर्च की जाती है और (ख) जिनकी आमदनी ५०० रु० से कम है।

जागीर जमीनों के रयतों द्वारा खानेदारी अधिकार प्राप्त धाराओं का भी सुधार कानून में अन्त कर दिया गया है। राजस्थान की वर्तमान परिस्थिति में पुरानी धारायें अनुकूल नहीं कही जा सकती। इसलिए उन धाराओं का रद्द किया जाना अवश्य ही नहीं कदम माना जायेंगा।



कश्मीर, हैदराबाद, आसाम,

हिमाचल प्रदेश, पेश्वर, मध्यभारत

पश्चिम बंगाल और सौराष्ट्र में

## श्री कैलाश नाथ भारती भूमि सुधार की प्रगति

अवतक पूरे देश में भूमि-सुधार कानूनों की प्रगति जिस प्रकार चल रही है उससे अनुमान लगाया जा रहा है कि समस्त देश में भूमि की समस्या को अन्तिम समाधान दे दिया जायगा। लेकिन इसके बाद भी, जो खामिया रह जायगी, उनमें सशोधन के लिए विशेष तत्परता दिखाई पड़ रही है। यह देखा गया है कि बीच-बीच में स्वार्थ की शक्तियां इन कानूनों के रास्ते में रोड़े बनकर आती रही हैं जिस कारण कानूनों को अमली जामा पहनाने में प्रायः देर हो जा रही है। इससे सतोष होता है कि तमाम विरोधी अन्त में सहयोग करने को तत्पर हो जाते हैं। नीचे कई राज्यों के भूमि-सुधार कानूनों की प्रगति का औपचारिक विवरण है, हालांकि इन राज्यों में पूरे तौर पर, कानून लागू नहीं है। कानून बना देना एक अलग बात है। उमी अमल में लाया जाना दूसरी बात। प्रसन्नता इस बात की है कि शनै-शनै नयी परिस्थितियों के अनुसार मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ रहा है।

### कश्मीर में भूमि सुधार

एशिया में सम्भवतः कश्मीर ही ऐसा राज्य है जहां भूमि सुधार की प्रगति अत्यन्त छिप्र गति से हुई है। कार्यान्वयन अभी होता ही जा रहा है। कश्मीर में भूमि सुधार कानून बन जाने से साढ़े छ लाख एकड़ जमीन जो जमीन्दारों के अधिकार में थी, दो लाख किसान परिवारों के बीच बांट दी गई। इस कानून से लगभग दस लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंचा है। नवने आश्चर्यजनक और अनुकरणीय बात तो यह रही कि किसी तरह का मुद्राविजा कश्मीर सरकार ने किसी को नहीं दिया।

नव्य कश्मीर के राजा के अधिकार में ही पूरी चार तहसीलों थी जिनमें वृष्टि योग्य दो लाख एकड़ जमीन थी। छनानी के जागीरदार

साहब अकेले ही ४७ गावों के मालिक थे। दीवान साहब भी कोई १५ हजार एकड़ भूमि के मालिक थे। कश्मीर में भूमि के सम्बन्ध में इतना बड़ा वैषम्य फैला हुआ था। किन्तु कानून की तेज रफ्तार ने सबकी जमीनें ले ली। भूमि सुधार कानून की कार्यान्विति के समय मदिरों और मस्जिदों की जमीनें भी ले ली गई। जमीन्दार जमीन्दार हैं चाहे उसे जागीरदार कहा जाय या मटाधीश।

भूमि सुधार के अन्तर्गत कश्मीर में एक व्यक्ति के पास केवल वीस एकड़ भूमि पर ही कब्जा रह सकता है। जमीन्दारों के साथ कुछ रियायत की गई और उन्हें २२ एकड़ भूमि रखने की छूट मिली। २५ और ५० एकड़वाले जमीन्दार कोई बड़े जमीन्दार नहीं कहे जा सकते हैं। किन्तु ये लोग स्वयं खेती नहीं करते थे और केवल लगान पर बन्दोबस्त करके उसका लाभ उठाया करते थे। इससे किसानों पर अधिक बोझ बढ़ता जाता था।

इसी सुधार के अन्तर्गत लगभग एक लाख साठ हजार जागीरी जमीन किसानों में बांट दी गई। जो जमीन कुछ दिन पहले चन्द लोगों की मिल्कियत थी, वही अब साठ हजार किसानों की मिल्कियत हो गई। और यह सारा काम केवल सोलह महीनों में हो गया। खेतों पर किसानों की मिल्कियत स्थापित कर देनेवाले इस कानून की इतनी लोकप्रियता बढी कि लोग उसे आजादी का मसविदा कह कर घोषित करते हैं।

इसके बाद कश्मीर सरकार ने भूमि-सुधार के अनेकानेक कानून बनाये। जम्मू और कश्मीर दुखी कर्जदार ऐक्ट का सृजन किया गया। इस कानून के अनुसार कर्ज देनेवाले और लेनेवाले दोनों को समझौता

बोर्ड में समझौते के लिए अर्जी देनी पड़ती थी। जिस दिन से यह कानून लागू हुआ उसी दिन से चार महीने की अवधि के अन्दर ही कर्ज देनेवाले के लिए आवेदन पत्र दाखिल कर देना जरूरी हो गया। बाद में कर्ज देने का उनका अधिकार ही खत्म हो जाता।

१५ अप्रिल १९५२ तक इन बोर्डों के सामने ४१२९५ दावे दाखिल किये गये और उन सबका फाँसला कर दिया गया। दावे की कुल रकम ९६५९०३५ रुपये थी किन्तु सिर्फ २३०३८६६ रुपये के दावे को ही सरकार ने जायज माना। कर्ज में इतनी कमी भारत में किसी भी राज्य में नहीं हुई है। जापान की कृषि भी कुछ ऐसे ही तरीके से की गई है। कश्मीर सरकार ने इतना बड़ा परिवर्तन कम समय में ला दिया और खेती की जमीन हजारों किसान परिवारों में बंट गई। कश्मीर ने बराबर प्रगतिशीलता का उदाहरण देश के समक्ष रखा है। उसका जमीन सुधार कानून तो भारत-वर्ष के लिए सकेत है।

### हैदराबाद में भूमि सुधार

हिन्दू जनसंख्या बहुल मुसलमान नवाब के शासन के अन्तर्गत करा-हनेवाली जनता को अब आण मिली है। १९४८ के सितम्बर में वहा की तैमिक सरकार ने एक कानून द्वारा सफ़ेखाब को दीवानी में परिवर्तित कर दिया। निजाम की समस्त जमीन सरकार के कब्जे में आ गई और उन्हें ५,००,००० लाख वार्षिक निजी खर्ज के लिए दिया जाना निर्धारित किया गया। उसी साल जागीरदारी उन्मूलन कानून पास हुआ। १९५० में रैयतवारी जमीन की स्थिति सुधारने के लिए टैनेन्सी और कृषि भूमि कानून पास किया गया। इन कानूनों के जरिये वहा के आदिवासियों का पुनःस्थापन होने लगा है।

हैदराबाद राज्य में २५६०० वर्गमील जागीरें थी। पूरी भूमि के अनुपात में ३०९ प्रतिशत और इनका फ़ैलाव ६३५५ गावों में था। जागीरों की आमदनी छोटे मक्ते में ५०० सौ रुपये की थी और बड़े पंग्राह में २५,००,००० थी। अधिकांश जागीरदारों की अपनी व्यवस्थाएँ थी, इसी कारण विभिन्न क्षेत्रों में भूमि प्रशासन भिन्न-भिन्न था और इनके फल-स्वरूप किसानों की हालत सुधरती नहीं थी। सफ़ेखास जब दीवानी में परिवर्तित हो गया तब उससे जागीरदारों और हिस्सेदारों की मस्या एकदम कम हो गई। सैनिक गवर्नर ने उस समय इनके प्रशासन के लिए एक जागीर प्रशासक की नियुक्ति की।

हैदराबाद टैनेन्सी और कृषि भूमि कानून १० जून १९५० से लागू हो गया। इनके उद्देश्य यो हैं —

- (१) राज्य और रैयत के बीच कोई बीचवान न रहे।
- (२) किसानों की स्थिति सुधरे।
- (३) जमीन अधिक माप में एक ही व्यक्ति के जिम्मे न रहे और,
- (४) जमीन को वैसे व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त न की जाय जो खेती न करता हो।
- (५) महयोगिता के आधार पर कृषि को प्रोत्साहन दिया जाय।
- (६) जमीन में साधान का अधिकाधिक उत्पादन हो।

इन दो कानूनों में बराबर सुधार की गुजाइश बनी रहती है। योजना आयोग ने भी कतिपय निफारियों की है और क्षेत्रीय प्रशासकों को तरह-तरह के अधिकार दिए गए हैं ताकि वे इन कानूनों को पूर्णतया काम में लगा सकें।

### आसाम में भूमि सुधार

आसाम सरकार ने अबतक ५ महत्वपूर्ण भूमि सुधार कानूनों को स्वीकृत कर लागू किया है। आसाम भूमि विस्तार एवं अधिकार कानून द्वारा सरकार ने समस्त परती भूमि पर अधिकार कर लिया है जिसकी बन्दोबस्ती भूमिहीनों और विस्थापितों के माथ की जा चुकी है। यह कानून पहले १९४८ में स्वीकृत हुआ था और ४९-५० साल में भी इसमें पर्याप्त सुधार किये गए।

दूसरा महत्वपूर्ण कानून है आसाम अधिकार संरक्षण और नियन्त्रण कानून, जिसके द्वारा आसाम के समस्त जिलों के बटाईदारों का संरक्षण हुआ। इसके पहले अधिकारों के साथ जमीन के मालिक तरह-तरह के अत्याचार करते थे।

तीसरा महत्वपूर्ण कानून है आसाम इस्टेट व्यवस्था कानून, जिसके पास हो जाने से जगलो, पहाड़ो, बगीचों, तालाबों आदि की रक्षा निर्मम भूमितियों के अत्याचार में की गई। पहले जमीन्दार इनका अतिथय दुरु-पयोग करते थे। इस कानून के स्वीकृत होने पर कतिपय जमीन्दारों ने हाईकोर्ट में मुकदमा तक दायर किया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली और २३ अप्रिल १९५३ से यह कानून लागू कर दिया गया तथा उपर्युक्त सभी चीजों पर सरकारी अधिकार हो गया।

चौथा कानून 'आसाम जमीन्दारों उन्मूलन' कानून है जिसे राष्ट्रपति ने २६ जुलाई १९५१ को स्वीकृति दे दी है। इसके खिलाफ भी जमीन्दारों ने मुकदमा दायर किया, लेकिन अमफर रहे।

### पश्चिम बंगाल का भूमि सुधार

पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने सबसे पहले (१०४९ में 'नन-एग्री-कलचरल टैनेन्सी ऐक्ट' पास किया। इन कानूनों के पास होने के पहले शहरी इलाकों में रैयतों की हालत अच्छी नहीं थी। जमीन्दार के साथ इनका ठंका रहता था और कियो भी नमय ये बंदोबस्त किये जा सकते थे। इस कानून द्वारा शहरी इलाकों के रैयतों को म्यायी उत्तराधिकार्य और तवादर्ले के अधिकार प्राप्त हो गए।

दूसरा महत्वपूर्ण कानून है ५० व० बरगादार ऐक्ट। इन कानून की सर्वाधिक जरूरत बंगाल में थी, चूँकि जमीन बन्दोबस्त करने के बाद मालिक फल का तीन हिस्सा ले लेता था, जिसे 'तिमागा' कहते हैं। इस व्यवस्था के कारण उत्पादन में कमी हो गई थी और भाग चानियों और मालिकों में बराबर अमन्तोप रहता था। अब इन कानून के द्वारा उन्हें राहत मिल गई है। इन तरह के जगडों का फ़ैमला एक दोड़ के अधीन रहेगा।

### हिमाचल प्रदेश में भूमि सुधार

भारत के उत्तर में स्थित पहाड़ी क्षेत्रोंवाले उन प्रदेश में भूमि-सुधार के लिए एक समिति बनाई गई थी जिनमें सरकारी तथा गैर सरकारी दोनों प्रकार के प्रतिनिधि थे। इन समिति के अध्यक्ष थे मुख्य मंत्री जस्टर



वाई० एस० परमार । समिति को कृषि भूमि की अवस्था जाच करने में बहुत समय लगा और यह निश्चय किया गया कि इन्हीं सिफारिशों के आधार पर भूमि सुधार कानून बनाये जायगे । समिति की सिफारिशों को जान लेना जरूरी है चूँकि इनसे ही नये समाज की स्थापना के उद्देश्यों का एक अन्दाज मिल जाता है ।

(१) हिमाचल प्रदेश में जितनी भी छोटी-छोटी रियासतें विलीन हो गई हैं उनके मालिक "आला मालिक" कहलाते थे । राजस्व विभाग के खाते में इन आला मालिकों के अलावा इनसे छोटे-छोटे भूमिपतियों के नाम भी दर्ज रहते थे । लेकिन किसानों को जब चाहे बेदखल कर दिया जा सकता था । अब आला मालिकों के नाम दर्ज होने की मनाही सरकार द्वारा कर दी गई है ।

(२) बहुत दिनों से हिमाचल प्रदेश में छोटे-छोटे अन्य बन्दोबस्ती लेनेवाले किसान थे जिन्हें बंतु कहते हैं । इन बंतुओं को भूमि बन्दोबस्ती लेने के लिए जमीन्दारों की चाकरी बजानी पड़ती थी । १८८७ के पंजाब टेनेन्सी ऐक्ट के मुताबिक अब बंतुओं को भी जमीन पर अधिकार दे दिया गया है । दसगुना लगान देने पर ये बंतु जमीन के मालिक भी हो सकते हैं ।

(३) राज्य विधानसभा दो बिल स्वीकृत कर चुकी है और ये अब लागू भी कर दिये गये हैं । (१) पंजाब टेनेन्सी (हिमालय प्रदेश सशोधन) बिल (२) हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी (राइट्स ऐण्ड रेस्टोरेशन) बिल । इन दोनों बिलों के लागू हो जाने से किसानों की बेदखली एकदम रोक दी गई है । कोई किसान तभी बेदखल किया जा सकता है जब वह लगान न दे । ३० अगस्त १९५० से जो भी किसान बेदखल कर दिये गये हो उन्हें अपनी जमीन पर फिर से बेदखल दे दिया गया है । इसके लिए किसानों को केवल अर्जी देनी पड़ता है ।

### पेप्सू में भूमि सुधार

पेप्सू सरकार ने भी भूमि सुधार कानून बनाने में उत्साहजनक प्रगति की है । जमीन्दारी उन्मूलन कानून यहाँ भी स्वीकृत किया जा चुका है । विस्वादायी उन्मूलन कानून सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कानून है । कपूरथला तथा फरीदकोट की रियासतों को सर्वाधिक जमीनें थी । इन दोनों रियासतों के किसान को जोत का हक दे दिया गया है । विस्वेदारी कानून के अन्तर्गत भी किसानों को हक मिल चुका था । फरीदकोट और नालागढ़ रियासतों के अधिकारी आला मालिक समझे जाते थे । आला मालिकीय अधिकार उन्मूलन कानून भी पास किया गया है । किसानों को बेदखल होने से रोकने के लिए पेप्सू टेनेन्सी ऐक्ट स्वीकृत किया जा चुका है ।

होलिडगो के खड-खड हो जाने से रोकने के लिए भी कानून बनाया गया है जिसका नाम है पेप्सू होलिडग कंसोलिडेशन ऐण्ड फ्रैग्मेंटेशन कानून । इन कानूनों के लिए अधिक उत्पादन, परती जमीन में खेती करने तथा नियमित भूमि वितरण के निमित्त भी कानून बनाये गये हैं । पेप्सू आर्को-पैन्नी बिल और पेप्सू टेनेन्सी ऐण्ड एग्रीकलचरल लैंड्स बिल के पास कर दिये जाने पर जागीरदारों, जमीन्दारों और आला मालिकों से किसानों को प्राण मिल गया है । लेकिन अभी जमीन की कई किस्में ऐसी हैं, जिनका

पूर्णरूपेण समाधान बाकी है । इस दिशा में वहाँ की सरकार सतर्क एवं सक्रिय है । किसान भी केवल उसीको जमीन दे सकते हैं जो जमीन जोतते हों या उपज बढ़ाने में रुचि रखते हों । किसान अगर अपनी जमीन परती छोड़ दें तब उस पर सरकार या तो स्वयं खेती कर सकती है या दूसरे को जमीन बन्दोबस्त कर सकती है । ऐसी आशा की जाती है कि इन कानूनों से अधिक किसानों का कल्याण होगा । यह देखा गया है कि किसान सरकारी प्रयासों में पूर्ण सहयोग दे रहे हैं । किसान ही राज्य की अर्थ-व्यवस्था की रीढ़ हैं । सरकारी कानून इनकी दशा सुधारने की दिशा में लग रहे हैं ।

### मध्यभारत में भूमि सुधार

मध्यभारत में रयतवारी, जमीन्दारी और जागीरदारी प्रथाएँ चालू की । ग्वालियर राज्य में जमीन्दारी प्रथा थी और वहाँ इन्तजाम अर्च्छा होता था । प्रारंभ काल से ही मध्य भारत सरकार ने भूमि-सुधार कानून को लागू करने की चेष्टा की और इस दिशा में उन्हें अधिक सफलता मिली भी । जागीर इलाकों के थाने तथा अन्य अदालतों सरकार के कब्जे में आ गई । लैंड रेकर्ड्स मैनटिनेन्स ऐक्ट पास करके इस दिशा में प्रयास आरम्भ किया गया । खालसा इलाकों के लिए भी भूमि प्रशासन और रयतवारी भूमि अध्याय कानून बनाया गया । इन सबका कानूनी का उद्देश्य किसानों का संरक्षण था । उनकी बेदखली जो पहले बड़े पैमाने पर की जाती थी, रोक दी गई ।

इतना कर लेने के पश्चात् जागीरदारी और जमीन्दारी उन्मूलन का काम शेष रह गया । लेकिन लोग इस दिशा में बिना पर्याप्त अध्ययन के किसी प्रकार का कानून बनाना जायज नहीं समझा जाता । अतएव जमीन्दारी उन्मूलन के सम्बन्ध में जाच करने के लिए एक समिति संघटित की गई जिसमें तीन गैर सरकारी और दो सरकारी सदस्य थे । नवम्बर १९४९ में ही समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है । ठीक इसीके बाद संघीय सरकार ने एक ऐसी समिति का गठन किया जिसके ऊपर मध्य भारत और राजस्थान की जागीरदारी प्रथा की जाच करने के अधिकार सौंपे गये । इस समिति के अध्यक्ष श्री वेंकटाचार मनोनीत किये गये । इस समिति की रिपोर्ट भी उसी वर्ष दिसम्बर महीने में दे दी गई ।

इन्हीं रिपोर्टों के आधार पर मध्य भारत जमीन्दारी उन्मूलन कानून पास किया गया और फिर जागीरदारी उन्मूलन कानून भी । इन दोनों महत्त्वपूर्ण कानूनों का उद्देश्य था राज्य और प्रजा के बीच के बीचवानों को समाप्त कर देना । जैसे ही जमीन्दारी उन्मूलन कानून पास हुआ वैसे ही जमीन्दारों ने हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया । जागीरदारों की ओर से भी इसी प्रकार की अर्जिया दी गई, अत इन दोनों कानूनों के शीघ्र ही लागू किये जाने में थोड़ी देर हो गई । जमीन्दारी उन्मूलन कानून की निम्न धाराएँ हैं

(१) खुदाकस्तों को छोड़कर अन्य सभी जमीन सरकार के अधिकार में आ गई ।

(२) सभी किसानों को पक्का रयती अधिकार मिल गया । चाहे रयत किसी भी श्रेणी का है ।

(३) अन्य किसानों को भी किसी भी तरह से जमीन की बन्दोबस्ती लेंते थे उन्हें भी पक्का अधिकार दे दिये गये ।

(४) जमीन्दारों को देने के लिए मुआवजा का निर्धारण किया गया ।

(५) जमीन्दारों के जायज कर्जदारों की अजियों पर विचार करना ।

(६) जमीन्दारों के अन्दर की जमीनों के क्षगड़ों की सुनवाई और फसला करना ।

(७) उन जमीन्दारों को पुनःस्थापन व्यय देना जो केवल कृषि पर ही जीवित रहते थे ।

(८) पूरे राज्य में रयतवागी प्रथा जारी करना, ग्रामों की व्यवस्था के लिए पटेलों और लेखपालों की व्यवस्था करना ।

इसी प्रकार जागीरदारी उन्मूलन का कानून भी स्वीकृत किया गया है और उसकी विशेषताएँ भी कुछ इसी प्रकार की हैं ।

### सौराष्ट्र में भूमि सुधार

१५ फरवरी १९४८ में सौराष्ट्र राज्य की रचना हुई । इस राज्य में करीब दो सौ विविध जागीरदार और जमीन्दार थे । खालसा और गैर खालसा जमीन भी थी । ऐसी स्थिति में सरकार का पहला कर्तव्य था कि पूरे राज्य में एक प्रकार की भूमि व्यवस्था करें । सौराष्ट्र में भूमिकर समस्या तीन भागों में विभक्त थी और इन सबको का शीघ्र निर्णय

कर देना सरकार का कर्तव्य हो जाता था । (१) सरकार और रयतों के बीच नये सम्बन्ध पैदा करना (२) भूमि के अधिकारियों और किसानों के सम्बन्धों को स्थायी स्वरूप देना (३) और अन्त में जमीन्दारी और जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन कर देना ।

इन सिलमिलों में तीन बिल पास किये गये (१) सौराष्ट्र भूमि सुधार कानून (२) सौराष्ट्र वरखाली उन्मूलन कानून और (३) सौराष्ट्र इन्स्टिट्यूट अधिकरण ऐक्ट । इस कानून के अनुसार ताल्लुकदारों, भागदारों, आयतों और मुल्गिराजियों के अधिकारों में सशोधन कर दिया गया ताकि ये लोग अपने रयतों के साथ मनमाना नहीं कर सकें । दूसरे कानून के द्वारा वरखालीदार, जिनायीदार, चकारियत, खैराती और धर्मादाय इन सभी प्रकार की भूमियों के सम्बन्ध में सुधार किये गये । तीसरे कानून के अनुसार खेती की जानेवाली भूमि के अलावा अन्य जमीनों पर सरकारी अधिकार कर लिया गया । इन कानूनों के लागू करने के पहले ३३००० गिरमादार थे । इसके अलावा १९००० वरखालीदार थे । गिरमादारों को तीन श्रेणियों में विभक्त कर दिया गया । चूँकि यहाँ भूमि की समस्या महिल्ल्ट थी । अतएव जमीन का वर्गीकरण भी कई प्रकार में किया गया । राज्य की आय बढ़ेगी, अधिक उत्पादन होगा और जमीन्दार-किमान के सवर्ष का एकदम खात्मा हो जायगा ।



# बिहार में भूमि सुधार की प्रगति

श्री रामलखन सिंह यादव

बिहार में भूमि सुधार की प्रगति को निम्न प्रमुख शीर्षकों में बाटा जा सकता है —

(१) बीच के तत्त्वों का अन्त,

(२) टेनेन्सी सुधार

(३) चकले की हदबन्दी

(४) कृषि का पुनर्गठन जिसमें चकले की हदबन्दी और सहकारिता खेती का विकास और सहकारी ग्राम प्रबन्ध भी सम्मिलित है।

## (१) बीच के तत्त्वों का अन्त

बीच के तत्त्वों के अन्त के लिए यहाँ कानून का निर्माण सर्व प्रथम १९४९ में हुआ, जिसे बिहार जमीन्दारी उन्मूलन कानून, १९४९, कहते हैं। इस कानून की मान्यता को कुछ निहित स्वार्थवालों ने न्यायालय में चुनौती दी और कुछ मुकदमों में सरकार के विरुद्ध इन्जक्शन भी जारी किये गये। यह देखकर कि इस कानून में भूमि-सुधार की पूरी गुजाइश नहीं है, राज्य सरकार ने स्वयं ही इसे रद्द करने का निर्णय किया। अतः इस कानून को रद्द कर दिया गया और बिहार भूमि सुधार कानून, १९५०, को सितम्बर १९५० में स्वीकृत किया गया। इस कानून की मान्यता को भी चुनौती दी गयी। परिणामस्वरूप मई १९५२ से पूर्व बीच के तत्त्वों के अन्त का प्रारम्भ तब तक नहीं किया जा सका जबतक कि भारतीय सघ विधान की धारा ३१ में सुधार नहीं किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मान्यता नहीं प्रदान की।

(२) इस प्रकार बीच के तत्त्वों की समाप्ति के प्रथम चरण में, सितम्बर, १९५२ के अन्त तक राज्य सरकार ने १९५० के भूमि-सुधार कानून के अन्तर्गत उन जमीन्दारियों का अन्त कर दिया गया जिनकी आमदनी ५०,००० रु० सालाना से अधिक थी। इस प्रकार से समाप्त होनेवाले तत्त्वों की संख्या १५५ थी। १९५२ के मितम्बर महीने से आरम्भ होनेवाले इस अभियान के दूसरे चरण में गया, हजारीबाग, पलामू, और दरभंगा जिले से ऐसे तत्त्वों की पूर्ण समाप्ति का निश्चय किया गया और इसकी प्राप्ति के

लिए आवश्यक तैयारियाँ की गयीं। १९५३-५४ की अवधि में राज्य के बाकी जिलों में भी ५०,००० रु० से लेकर १०,००० रु० तक की आमदनीवाले बीच के तत्त्वों के अन्त का निर्णय भी लागू किया गया।

(३) बिहार भूमि सुधार (अमेंडमेंट) कानून, १९५४ से पूर्व बिहार भूमि सुधार कानून १९५० के अन्तर्गत प्रत्येक बीच के स्वार्थवालों को राज्य में उसके ऐसे स्वार्थ से सम्बन्धित वस्तुओं की सूची देनी पड़ती थी जिसे हासिल करना था। इससे उन्मूलन की गति बहुत धीमी हो गई थी। इसलिए राज्य सरकार ने १७ मई, १९५४ को उक्त कानून की धाराओं में आवश्यक सुधार कर इसे और भी अनुकूल बना लिया। इसके अनुसार राज्य सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो गया कि वह विशिष्ट क्षेत्र अथवा राज्य के किसी भी भाग में पड़नेवाले ऐसे स्वार्थ का अन्त तीन महीने की आम सूचना देकर कर सकती है। इसके बाद बीच के स्वार्थ के उन्मूलन की गति में तीव्रता आ गयी और २६ जनवरी १९५५ तक राज्य के आठ जिलों अर्थात् आवादी और रकबा में आधे राज्य में क्षेत्रीय सूचना के द्वारा ऐसे तमाम स्वार्थों का अन्त कर दिया। इस कार्यक्रम में सम्मिलित होनेवाले जिलों के नाम हैं—गया, हजारीबाग, पलामू, मुंगेर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और चम्पारण। १ जनवरी १९५६ से बाकी बचे हुए जिलों—पटना, शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, सारन, भागलपुर, सताल परगना, रांची, सिंहभूम और मानभूम (मानभूम सदर को छोड़कर) में भी ऐसे तमाम स्वार्थों के अन्त कर देने का निश्चय किया जा चुका है। इस सम्बन्ध में आवश्यक घोषणा भी की जा चुकी है जो १९ अगस्त, १९५५ को प्रकाशित हो चुका है।

(४) और भी तीव्र गति से उन्मूलन के कार्यक्रम को पूरा करने में दो प्रमुख कठिनाइयाँ रही हैं। ये हैं—गावों में पर्याप्त प्रशासनिक यंत्रों और आधुनिक भूमि-रेकार्डों का अभाव। छिट-फुट कागजों के सहारे गावों में मालगुजारी का निश्चय करना पड़ा। इस राज्य में तहसीलदार की कोटि के व्यक्तियों का पूर्णतः अभाव है, क्योंकि इस प्रकार के

मालगुजारी अफसर यहा होते ही नही रहे हैं। जुनियर निविल सर्विस मे नियुक्ति के कार्यक्रम मे काफी वृद्धि की गयी है, और आया है कि अगले चन्द्र वर्षों मे ही प्रतिशत अधिकारियों की कमी दूर हो जायगी। अस्त-गत स्वार्थवालो ने अपने नमी कागजात सरकार को सुपुर्द नही किये या उनके पास स्वयं कागजों का अभाव था। मापी और बन्दोवस्ती टूट भी कितने वर्ष हो गये। सबसे आधुनिक रेकॉर्ड ३० वर्ष पुराने हैं। और बहुत से जिलो में ५० वर्ष पुराने। मापी और बन्दोवस्ती का मशौघन कार्य भी तारम्भ किया गया है और आया है कि पूर्णिया जिले में यह शीघ्र ही पूरा हो जायगा। अन्य जिलो में इसके पूरा होने में अभी कुछ समय लगेगा।

## (२) टेनेन्सी सुधार

**अवधि की सुरक्षा**—विहार में कृषिजीवियों की सख्या ३ करोड़ ४६ लाख है, जिनमें ८८ लाख भूमिहीन कृषि मजदूर हैं, ३३ लाख दररैयत हैं और बाकी अधिकार प्राप्त रैयत हैं। इस राज्य में अपना अधिकार नहीं रखनेवाले रैयतों की सख्या नगण्य है।

(२) विहार टेनेन्सी ऐक्ट, छोटानागपुर टेनेन्सी ऐक्ट, या सताल परगना टेनेन्सी ऐक्ट की वर्तमान धाराओं के अन्तर्गत अधिकार प्राप्त रैयतों को अपनी जमीन पर स्थायी और वशानुगत अधिकार प्राप्त हैं। वेदखली या मालगुजारी में वृद्धि के विरुद्ध उन्हें पूर्ण सुरक्षा प्राप्त है। इस सम्बन्ध में उनकी स्थिति तथा मालिकों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है, खास कर, अब जबकि जमीन्दारी उन्मूलन के बाद एक मात्र सरकार ही जमीन्दार है। इस वर्ग के रैयतों को उनके वर्तमान अधिकारों में और किसी प्रकार की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है।

(३) कोई भी क्षेत्र जहा विहार टेनेन्सी ऐक्ट लागू है, वहा कोई भी दर-रैयत, जो लगातार १२ वर्षों से जमीन जोत रहा है, उसे उस पर अधिकार स्वतः प्राप्त है और मिवाय बाकी मालगुजारी की अदायगी में जमीन के विक्रय जाने तक वह उसमें वेदखल नहीं किया जा सकता।

उन दर-रैयतों को भी, जिन्हें जमीन पर अधिकार प्राप्त नहीं है, जमीन से मिवा निम्न परिस्थितियों के वेदखल नहीं किया जा सकता—

- (१) बाकी मालगुजारी नहीं देने पर,
- (२) जमीन को इस प्रकार व्यवहार करने पर कि वह कृषि के लिये बेकार हो जाय, और
- (३) जहा दर-रैयत रजिस्ट्री लीज के अनुसार प्रविष्ट कर चुका हो शील लीज की शर्तें नमाप्त हो गयी हो।

अभी हाल तक मालिकों द्वारा अपनी जमीन के वेदखल किये जाने पर दर-रैयतों को मिवा अदालत में जाने के और कोई अन्य चारा नहीं था। अदालत में मुकदमे वा अत्यधिक खर्च और फंसान में लम्बी अवधि के कारण गरीब रैयतों के लिए फंसले के दिन तक प्रतीक्षा करना घनम्भन था। वेदखल दर-रैयत के लिए कठिनाई और अधिक बट जानी थी क्योंकि न तो रैयत उनके साथ कोई रजिस्ट्री लीज ही करता था और न किसी प्रकार की रसीद ही उसे मिल सकती थी।

ऐसी परिस्थिति में अपने दावे के पक्ष में किसी प्रकार का प्रामाणिक मजत पेश कर सकना उनके लिए असम्भव था। दर रैयतों को गैर-गान्धूनी वेदखली में सुरक्षा प्रदान करने के लिए विहार टेनेन्सी ऐक्ट में विहार

टेनेन्सी (मेकेन्ड अमेंटमेंट) ऐक्ट, १९५५ के द्वारा सुधार लाया गया है। इस सुधार कानून के अनुसार जिलाधीश को १ फरवरी, १९५३ ने वेदखल किये गये दर-रैयतों को जमीन पर कब्जा दिलाने का विशेष अधिकार दिया गया है। १ दिनम्बर १९५५ में यह सुधार कानून लागू किया गया है।

अधिकार प्राप्त रैयतों और दर-रैयतों को पहले में ही वास की जमीन पर काफी अधिकार प्राप्त है और उन्हें कोई वेदखल नहीं कर सकता। जहा वाम की जमीन रैयतों की कृषि भूमि का हिस्सा है, वहा भी यही नियम लागू होता है। अन्य स्थानों में स्थानीय परम्परा और व्यवहार के अनुसार नियम लागू होता है। १ फरवरी, १९४८ में स्थायी विहार प्रिवीलेज्ड परमन्स होमस्टेड टेनेन्सी ऐक्ट के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने वाम की जमीन पर स्थायी अधिकार प्रदान कर दिया गया, जिनके अनुसार भूमिपति को केवल पूर्व निश्चयानुसार जायज मालगुजारी मात्र पाने का अधिकार रह गया। जिलाधीशों को यह अधिकार दिया गया कि गैर कानूनी वेदखली की स्थिति में रैयतों में आवेदन प्राप्त कर उन्हें वाम की जमीन पर फिर से अधिकार दिलावे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत योजना आयोग ने यह सुझाव दिया है कि भूमिकर किमी भी परिस्थिति में उपज का चौथाई या पाचवा भाग से अधिक नहीं हो।

विहार में भूमिकर का औसत दर प्रति एकड़ ३ रु० में ४ रु० तक है जो जमीन की कुल उपज का १०वा में १५ वा भाग होता है।

अभी हाल तक रैयत अधिक-से-अधिक अपनी उपज का ५।२०वा भाग जमीन्दार को मालगुजारी के रूप में देना था। विहार टेनेन्सी (मेकेन्ड अमेंटमेंट) ऐक्ट, १९५५ के अनुसार इसमें सुधार कर दिया गया है। अमेंटिंग ऐक्ट के अनुसार कर का अधिकतम दर कुल उपज का ५।२० वा भाग निश्चित कर दिया गया है।

कुछ दिनों पूर्व तक दर रैयतों द्वारा मालिक को दिये जानेवाले उपज के हिस्से का कोई दर निश्चित नहीं था। विहार टेनेन्सी (मेकेन्ड अमेंटमेंट) ऐक्ट, १९५५ के द्वारा अधिकतम हिस्सा भी तय कर दिया गया है। यह अधिकतम हिस्सा उपज का ७।२ वा भाग है।

विहार टेनेन्सी ऐक्ट ने पहले ही नकद मालगुजारी की दर तय कर दिया है। विहार टेनेन्सी ऐक्ट की वर्तमान धाराओं के अन्तर्गत उपज में हिस्सा देनेवालों के लिए नकद मालगुजारी देने की व्यवस्था नहीं है। इसलिए राज्य सरकार ने उक्त धाराओं में सुधार देने का फैसला किया है जिसमें कि उपज में हिस्सा देनेवाले दर-रैयतों को भी नकद मालगुजारी देने की सुविधा प्रदान हो सके और वे राज्य सरकार द्वारा निश्चित अधिकतम मालगुजारी से अधिक देने में बच सकें।

## जमीन्दारों द्वारा निजी खेती के लिए जमीन प्राप्त करने के अधिकार पर नियंत्रण

वर्तमान टेनेन्सी कानूनों के अन्तर्गत इस राज्य में जमीन्दारों को निजी खेती के लिए जमीन प्राप्त करने के लिए कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। जहा नव दर-रैयतों का प्रश्न है, उनके मालिकों को निजी लीज की नमाप्ति के बाद जमीन छोटा लेने का अधिकार है। निजी

लीज से पूर्व जमीन पर कब्जा प्राप्त करने का अधिकार मालिको को नहीं है । राज्य सरकार ने रयतो को निजी जोत के लिए जमीन लौटाने का अधिकार प्रदान करने का निश्चय किया है, बशर्ते कि इस सम्बन्ध में कानून बनाने में निम्न शर्तों का पालन हो —

(१) निजी जोत में जो जमीन वापिस की जायगी उसका क्षेत्रफल बिहार एग्रिकल्चरल लैंड्स (सीलीग एण्ड मैनेजमेंट) बिल, १९५५ के अन्तर्गत निश्चित अधिक-से-अधिक हदवन्दी के आवे से अधिक नहीं हो । इसके अन्तर्गत रयतो की पहले से निजी जोत की जमीन शामिल नहीं है ।

(२) अधिकरण के अधिकार का उपयोग इस प्रकार किया जायगा जिसमें किसी अन्दर रयत के पास दो एकड़ से कम भूमि न रह जाय । चाहे उस जमीन पर उसका मालिकाना हक हो या उसने वन्दोवस्ती ली हो । ऐसी प्रत्येक दशा में जहा स्वयं रयत खेत का मालिक हो और उसकी भूमि पाच एकड़ से अधिक भूमि नहीं हो, उसे तबदील की हुई भूमि पर अधिकार मिल जायगा ।

(३) प्रस्तावित कानून के लागू किये जाने के ६ महीने के अन्दर अधिकार प्राप्त का क्षेत्र दर्शाया जायगा । किन्तु इसकी अन्तिम सूची कलक्टर की स्वीकृति से तैयार की जायगी ।

(४) जमीन पर रयतो द्वारा कब्जा करने का अधिकार प्रस्तावित कानून के लागू होने के तीन वर्षों तक रहेगा ।

(५) कब्जा करने के एक साल के अन्दर अगर रयत जमीन को श्रावाद करने में असफल रहा अथवा चार साल के बाद भी वह जमीन को गैर-श्रावाद छोडेगा तो फिर कलक्टर को उसे उसी शर्त पर दर-रयतो के साथ वन्दोवस्त करने का अधिकार है ।

(६) इस कार्य के लिए "निजी खेती" के रयत के समुक्त परिवार के किसी सदस्य अथवा नौकर या मजदूर द्वारा की जानेवाली खेती भी सम्मिलित है ।

### रयत की जमीन को खरीदने का अधिकार

जहा तक अधिकार प्राप्त रयतो का सम्बन्ध है, यह प्रश्न पैदा ही नहीं होता । किन्तु दर-रयतो को, बिहार एग्रिकल्चरल लैंड्स (सीलीग एण्ड मैनेजमेंट) बिल, १९५५ के अन्तर्गत जमीन खरीदने का अधिकार दिया गया है । वे जमीन्दारो की वह जमीन जो उक्त कानून द्वारा निश्चित अधिकतम सीमा से अधिक है, खरीद सकते हैं, किन्तु इस रयती हक की प्राप्ति के लिए उन्हें मालगुजारी का पन्द्रहगुना मुआविजा देना होगा । बिना किसी अन्य विचार के यह अधिकार दर-रयतो को देने का प्रस्ताव किया गया है । इसके लिए यह आवश्यक नहीं कि वे विशेष श्रवधि से जमीन जोतते ही हो । बिल में इसके लिए खास धाराएं भी जोड़ ली गयी हैं ।

राज्य सरकार ने दर रयतो को, निर्धारित सीमा के अन्दर भी, उचित मुआविजा देकर रयती हक खरीदने का अधिकार देने का निर्णय किया है । सरकार ने यह भी निर्णय किया है कि अगर निर्धारित समय के अन्दर रयत जमीन को जोत में नहीं लाता है, या लाकर भी जमीन को चार साल के अन्दर गैर श्रावाद छोड देता है तो उस जमीन को भी दर-रयत को खरीदने का हक है । इस अधिकार का विस्तार उन

दर-रयतो के लिये भी किया गया है, जिन्होंने बिहार टेनेन्सी ऐक्ट की धारा ४८ ए के अन्दर अधिकार प्राप्त किया है ।

भविष्य में जमीन की दर वन्दोवस्ती के विषय में सरकार ने निम्नांकित कदम लेने का फंसला किया है और शीघ्रातिशीघ्र इस विषय में कानून बनाने की चेष्टा की जा रही है —

(१) जहा यह पहले से प्रचलित है, दर वन्दोवस्ती को नियमित भविष्य के लिये बन्द कर देना चाहिए ।

(२) दर-वन्दोवस्ती की छूट उन्ही परिस्थितियों में दी जा सकती है जहा रयत श्रविवाहित, तलाक प्राप्त या परित्यक्ता स्त्री, या विधवा हो या नाबालिग या शारीरिक, कानूनी या मानसिक रूप से अशक्त हो या सघ सरकार में सक्रिय सैनिक सेवा में काम करता हो ।

(३) ऊपर कही गयी श्रेणी के व्यक्ति की स्थिति में दर-वन्दोवस्ती केवल रजिस्ट्री लीज के द्वारा ही संभव है और वह भी कम से कम पाच साल की श्रविधि के लिए । इस लीज की समाप्ति पहले भी हो जा सकती है, अगर रयत स्वयं जमीन जोतना चाहे, किन्तु इसके लिए उसे एक साल की पूर्व सूचना रयत को देनी होगी । दर रयतो को पहले भी बेदखल किया जा सकता है अगर वे मालगुजारी नहीं देते हैं या जमीन का इस प्रकार व्यवहार करते हैं कि वह खेती के लिए अयोग्य हो जाय ।

(४) जहा तक उस जमीन का सबध है, जिसकी दर-वन्दोवस्ती हो चुकी है, दर-रयतो को, चाहे वे कितने भी दिनों से उसे जोत रहे हो, बिना किसी मूल्य के उस पर हक प्राप्ति का अधिकार होना चाहिये । लेकिन उप अनुच्छेद २ में कहे गये व्यक्तियों की जमीन की स्थिति में यह नियम लागू नहीं होगा ।

### कृषिजन्य भूमि का अकृषको के हाथ में जाने पर प्रतिबन्ध

वर्तमान कानून के अन्तर्गत कृषि जन्य भूमि की अकृषको के हाथों में बिक्री या लीज के द्वारा जाने पर (जहा ऐसा परिवर्तन अनुमत है) कोई प्रतिबन्ध नहीं है । इसके कारण बहुत से क्षेत्रों में भूमि कृषको के हाथ से निकलकर अकृषको के हाथ में चली आयी है । अकृषको के हाथ में कृषिजन्य भूमि के अधिक हिस्से का होना न तो किसी प्रकार की सतोष-प्रद कृषि श्रवधि-व्यवस्था के ही अनुकूल होगा और न इस प्रकार की जमीन पर अधिक पैदावार ही संभव है ।

अतः राज्य सरकार ने निर्णय किया है कि प्रचलित भूमि कानून में इस प्रकार का सुधार किया जाय जिससे अकृषको के हाथ भूमि की बिक्री न तो जायज हो और न इसकी अनुमति ही रहे । जमीन की बिक्री उसी स्थिति में संभव हो कि या तो खरीदनेवाले स्वयं कृषक हो या खेती या मकान निर्माण या वगीचा लगाने के उद्देश्य से वह जमीन खरीद रहा हो ।

### (३) चकले की हदवन्दी

इस सम्बन्ध में योजना आयोग की सिफारिशों को इस प्रकार रखा जा सकता है —

(१) भविष्य में भूमि की प्राप्ति पर पूर्ण सीमा निर्धारित होनी चाहिये ।

(२) तत्काल हल के लिए प्रत्येक राज्य को कृषि तथा प्रवन्ध का स्तर और आवश्यक यंत्र की स्थापना करने हुए भूमि व्यवस्था सम्बन्धी कानून बनाना चाहिये एक खास सीमा में ऊपर निर्दिष्ट होनेवाले फार्मों को दो भागों में विभाजित करना चाहिए—एक वह जिनका प्रवन्ध बहुत सुन्दर है और जिसके विभाजन में उत्पादन पर खान अन्न पड़ेगा और दूसरा वह, जिसके लिये यह स्तर आवश्यक नहीं है। दूसरे भाग की व्यवस्था में सरकार को भूमिहीन कृषकों को सहकारिता अथवा अन्य ढंग में व्यवस्थित करने का प्रवन्ध करना चाहिये।

(३) कोई भी व्यक्ति कितनी जमीन रखे उसके लिए सीमा निर्धारित होनी चाहिये।

(१) भविष्य में भूमि प्राप्ति की हदबन्दी के विषय पर राज्य सरकार विशेष रूप से विचार कर रही है।

(२) भूमि प्रवन्ध के सम्बन्ध में कानून और पूर्ण हदबन्दी— इस विषय में योजना आयोग की सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने विहार एग्रिकल्चरल लैंड (सिलीग एण्ड मैनेज-मेंट) बिल, १९५५ का मनविदा तैयार किया है जो विधान सभा के गत सत्र में पेश होकर नेलेक्ट कमिटी को विचारार्थ सुपुर्द किया गया है। इस बिल के प्रमुख अंग हैं—

(१) स्वयं मिलाकर पांच व्यक्तियों के परिवारवाले व्यक्ति को हदबन्दी का क्षेत्रफल मँदान इलाके में ३० एकड़ और प्लाटो या कम उपजाऊ क्षेत्र में ५० एकड़ से अधिक नहीं हो।

(२) एक परिवार का अर्थ होगा भूमिपति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र और पुत्रवधू, उसके पिता, माता, अविवाहिता पुत्री और बहन और उनके पोता-पोती।

(३) अगर भूमिपति के परिवार में सदस्यों की संख्या पांच से अधिक होगी तो प्रत्येक अतिरिक्त व्यक्ति पीछे मँदान में पांच एकड़ और अन्य क्षेत्रों में साठे आठ एकड़ जमीन उनके चकले में जोड़ी जा सकती है वगैरों की पूरा चकला ३०० एकड़ से अधिक नहीं हो।

(४) जहाँ भूमिपति के खेतों का पूरा रकबा हदबन्दी के रकबे से अधिक होगा वहाँ भूमिपति को यह अधिकार होगा कि उसके दर-रैयत के अन्दर भी कौन-सी जमीन उनके चकले की हदबन्दी में सम्मिलित की जाय।

(५) हदबन्दी के क्षेत्र में मिलाये जानेवाले दर-रैयत की जमीन का श्रम टेनेन्सी कानून में स्पष्ट कर दिया जायगा।

(६) रैयत की हदबन्दी में नहीं मिलायी गयी जमीन के दर-रैयत को मालगुजारी का पन्द्रहगुना मुआविजा खजाने में जमा करने पर अधिकार प्राप्त होगा।

(७) हदबन्दी के रकबा से अधिक जमीन रखनेवाले भूमिपति को निर्धारित किये जानेवाले सुन्दर खेती और पशुपालन के निद्वान्त के आधार पर ही खेती करना पड़ेगा।

(८) निर्धारित अधिकारी को किसी भी भूमिपति अथवा भूमिपतियों के किसी भी गिरोह या अछूती खेती और प्रवन्ध के स्तर को

निश्चित करने अर्थात् अन्न की ब्याई और पशु पालन के निद्वान्त के पालने के लिए आदेश करने का अधिकार होगा।

(९) निर्धारित अधिकारी द्वारा दिये गये आदेश को पालन करने में अगर कोई भूमिपति अनमर्प है, तो उसे स्वैच्छा में अपनी जमीन अधिकारी को सौंप देना चाहिये या रजिस्टर्ड सहकारी कृषि सोसाइटी में शरीक हो जाना चाहिये।

(१०) अगर कोई भूमिपति निर्धारित अधिकारी की आज्ञा पालन में असफल रहता है और स्वैच्छा में अपना खेत वापिस नहीं करता अथवा सहकारी खेती में सम्मिलित नहीं होता तो फिर वह अधिकारी की आज्ञा में अपनी जमीन से वे दखल किया जा सकता है।

(११) जहाँ भूमिपति आदेश नहीं मानने के कारण बंदखल कर दिया जाता है, उन जमीन को निर्धारित अधिकारी प्रत्यक्ष रूप में देख-भाल कर सकता है या किसी रजिस्टर्ड को-ऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी के द्वारा प्रवन्ध करा सकता है या अन्य भूमिपति अथवा खेतिहर मजदूरों के द्वारा खेती करा सकता है।

(१२) ऊपर की अवस्था में भूमिपति की अपनी जमीन में बंदखली पांच वर्षों में अधिक की अवधि के लिए नहीं होगी और उन अवधि में भूमिपतियों को वापिक तौर से द्रव्य देना होगा जो साम्यवादी भूमि कर में कम नहीं होगा या जैसा अधिकारी निर्णय करेगा।

(१३) २०० एकड़ से अधिक जमीनवालों में जमीन सरकार १० गुना मुआविजा देकर प्राप्त करेगी।

(१४) इस प्रकार में प्राप्त जमीन को सरकार निर्धारित धन पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के साथ बन्दोवस्त करेगी।

#### (४) कृषि का पुनर्गठन

चकलों का पुनर्गठन और टुकड़ों में बंटने से बचाव—सर्वप्रथम त्रॉर छोटे भूमिपतियों की समस्या का हल प्रदान करने के उद्देश्य में योजना आयोग ने राज्य सरकार से सिफारिश की है कि वे पूर्ण तन्त्रण के साथ चकले की हदबन्दी के कार्यक्रम को अगले वर्ष में शुरू करें। योजना आयोग की सिफारिशों को कार्यक्रम में परिणत करने के लिए राज्य सरकार ने विहार कन्सोल्डेशन आन्ड हल्डिंग्स एण्ड प्रिन्सिपल आफ फ्रॉगमेंटेशन बिल, १९५५ प्रस्तुत किया है। इस बिल का उद्देश्य चकले की हदबन्दी करना तथा भविष्य में जमीन का टुकड़ों में बंटने से बचाव करना है। राज्य विधान सभा के पिछले सत्र में इस बिल को उपस्थित किया गया था जो नेलेक्ट कमिटी को विचारार्थ सुपुर्द किया गया है।

इस बिल की विशेषताएँ ये हैं—

(१) राज्य सरकार स्वयं अथवा भूमिपति के आदेश पर प्राप्त जमीन नचना प्रसारित कर कितनी भी क्षेत्र में चकले का पुनर्गठन आरम्भ कर सकती है।

(२) पुनर्गठन के लिए आवश्यक सत्र की सहायता तथा प्रयोज्य कन्सोल्डेशन अथवा सेटलमेंट अथवा, मन्सनेट गमिन्स आदि की नियुक्ति करना।

(३) जिन क्षेत्रों में ग्राम पचायतें सगठित नहीं हैं, उन क्षेत्रों में कन्सोलिडेशन अफसर को पुनर्गठन की योजना तैयार करने में परामर्श करने के हेतु परामर्श समिति का सगठन करना ।

(४) कन्सोलिडेशन अधिकारियों की योजना को कार्यान्वित करने के लिए ग्राम सड़क आदि को भी व्यक्तिगत जमीनों से मिलाने का अधिकार ।

(५) कन्सोलिडेशन के सिलसिले में उत्पन्न बातों में अदालती काररवाई की मुमानियत ।

(६) पुनर्गठन से उत्पन्न परिवर्तन का नक्शा तथा अधिकार का रेकार्ड तैयार करना ।

(७) कम मान की भूमि प्राप्त करनेवालों को मुआविजा दिलाना तथा अधिक मान की भूमि प्राप्त करनेवालों से मुआविजा वसूलना ।

(८) पुनर्गठन के खर्च के पूरे या अंश का मूल्यांकन, बटवारा और वसूली ।

(९) पुनर्गठन के दौरान में खर्च या मुआविजा देने के लिए कृषकों को भूमि विकास कर्ज या कृषि कर्ज देना ।

(१०) पुनर्गठन में परिवर्तन या अदला-बदली से मुक्त करना ।

(११) इस सम्बन्ध में तमाम उपकरणों में रजिस्ट्री से मुक्ति ।

(१२) राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय क्षेत्र अथवा भूमि की किस्म को देखते हुए स्टैन्डर्ड क्षेत्र घोषित करना तथा भविष्य में परिवर्तन विक्री आदि के द्वारा टुकड़े होने से रक्षा करना । खेतों को टुकड़े में विभाजित होने से बचाने के लिए आदर्श तरीका तो यह होता कि वशानुक्रम से व्यक्तिगत अधिकार प्राप्त करने के कानून में आवश्यक संशोधन किया जाय, किन्तु माल विभाग अभी इसे बहुत कठिन मानता है और इसीलिए वह इसके लिए सुझाव नहीं दे रहा है ।

### सहकारी खेती

राज्य सरकार ने सहकारी खेती को इस राज्य में आरम्भ करने के प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए एक समिति भी नियुक्त कर चुकी है । इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है और राज्य सरकार इस पर विचार कर रही है ।

### सहकारी ग्राम व्यवस्था

सहकारी ग्राम व्यवस्था सम्बन्धी योजना आयोग की सिफारिशों को लागू करने के उद्देश्य से सरकार धीरे-धीरे कर वसूली गाव की सामान्य भूमि, तथा गैरमजदूरी खास भूमि की व्यवस्था, छोटे-छोटे सिंचाई कार्य की मरम्मत आदि को ग्राम पचायत को सुपुर्द कर रही है ।

# प्राचीन भारत में ग्राम पंचायतें

श्री देवप्रसन्न मालवीय

स्वर्गीय गोपाल कृष्ण गोखले ने कभी कहा था कि अंग्रेज विदेशी शासकों के राज्य में "हमारी मानवता जितना ऊँचा उठाने की क्षमता रखती है वहा तक वह कभी नहीं पहुँच सकती और लकड़ी काटनेवाले औजारों और पानी खींचनेवालों की तरह अपने ही देश में हमारा भाग्य कुटित हो गया है।" ऐसे विदेशी शासन ने अहिंसात्मक रूप से अपनी स्वतन्त्रता पा लेने के पश्चात् यह स्वाभाविक ही है कि हम आज अपनी मातृभूमि में चारों ओर आत्म अभिव्यक्ति एवं आत्ममग्न के लिए गहरा प्रयास होता देख रहे हैं। डा० राधाकुमुद मुखर्जी ने हमारे ग्रामीण समुदायों के लिए कहा है "वे ऐसे लोग हैं जिनमें सामाजिक प्रयोग और सामाजिक पुनर्रचना करने की एक निहित क्षमता सदा पायी गयी है।" नये भारत में होनेवाले उपर्युक्त प्रयोग स्वभावतः हमको अपने ग्रामों में ही अधिक दृष्टिगोचर होते हैं जहाँ इन समय सम्पूर्ण ग्राम पर ग्रामीण समुदाय को सर्वोच्च अधिकार प्रदान करने के लिए मिरतोड कोशिश की जा रही है। अपने व्यक्तित्व को पूर्णरूप से विकसित करने के लिए, अपने स्वाभिमान को पूर्णरूप से स्थापित करने के लिए शान्ति एवं नौहार्द्र के अपने चिर मदेश को समार को सुनाने के लिए यह अवश्य-म्भावी ही है कि भारत स्वतन्त्रता प्राप्त करने के कुछ ही वर्षों के अन्दर अपनी ग्राम पंचायतों को पुनर्जीवित करने के लिए गहरा प्रयास करे, नगरण ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं भौगोलिक दृष्टि से ग्राम पंचायतें ही भारतीय परम्पराओं एवं भारतीय प्रतिभा को व्यक्त करने की सर्वोच्च सच्चाई रही है। नहीं ही गत मान में कारण कार्यकारिणी ने ग्राम पंचायतों पर जो प्रस्ताव स्वीकार किया उनमें उनमें "भारत के विभिन्न भागों में पंचायत व्यवस्था के उत्तरोत्तर स्थापित किये जाने का स्वागत" किया था।

## हमारी पंचायत परम्पराएँ

कारण कार्यकारिणी ने नहीं ही कहा कि भारत में ग्राम पंचायतों का यह पुनः स्थापन "न केवल भारत की प्राचीन परम्पराओं के अनुरूप ही है, वरन् वह आधुनिक स्थितियों के अनुकूल भी है।" प० जवाहर लाल

नेहरू ने अपनी पुस्तक हिन्दुस्तान की कहानी में कहा है कि 'रोमन साम्राज्य के समय मत्ताशाही की जो कल्पना थी, उन समय स्वामी और दान का जो टाँचा था, वह भारत में कभी नहीं पाया गया।' गिन्दर महान के साथ एक यूनानी इतिहासकार आरियन आया था और उसने एक्सपेडिशन एलकुजान्डी नामक अपनी पुस्तक में गिन्दर की फौजी चटाइयों का जो वर्णन दिया है, उसमें उनमें बड़ी प्रशंसा करने हुए कहा है कि "भारत में प्रत्येक व्यक्ति स्वतन्त्र है।" मुप्रनिद्ध अंग्रेज इतिहासकार एल्फिन्स्टन ने लिखा है कि "आरियन ने अनुमान लंमीडेमोनियों की ही तरह कोई भारतीय दान नहीं हो सकता। पर लंमीडेमोनियों के विपरीत भारतीय किन्नी और देववालों को भी अपना दान नहीं बनाने हैं।" प० जवाहर लाल नेहरू ने भी कहा है—"हिन्दुस्तान के निवास कभी भी किन्नी सामन्त के दान या अर्द्धदान नहीं रहे।" पंडित जी ने यह भी कहा है कि भारत में "हमारी भूमि व्यवस्था महकाने एवं सामूहिक ग्रामों पर आधारित थी। व्यक्तियों के और कुटुम्बों के कुछ अधिकार भी थे और कुछ दायित्व भी थे, और वे दोनों परम्परागत नियमों के द्वारा निर्धारित और सुरक्षित होते थे।"

सन् १८७१ में मुप्रनिद्ध अंग्रेज विद्वान हेनरी मुमनर मैन ने आयर-फोड विश्वविद्यालय में पूर्व एवं पश्चिम के ग्रामीण समुदायों पर कुछ पाठित्यपूर्ण व्याख्यान दिए थे। उनमें कहा "भारत की अपनी पुरानी प्रथा यही है कि ग्रामीण समुदाय मिलजुल कर ग्रामीण नाथनों का उपभोग करते हैं और उन ग्रामीण समुदायों के अन्तर्गत कुटुम्ब रहकर उपयोग करता है। वहाँ व्यक्तियों को, भरे ही वे अपने कुटुम्ब के अध्यक्ष ही बनें न हों, अपनी अपनी तो मनमाने तरीके से निपटाने का अधिकार नहीं होता। वह नियमानुसार उद्वेग-उद्वेग वह पर मानता है कि कुछ करने नीमाओं के अन्दर अपनी अपनी तो अपने अन्तों में विनिरित करने के लिए नियम दे दे।" और आगे मैन कहता है "मैं काफी अधिकारपूर्ण तरीके से यह कहना है कि भारत के उन भागों में जहाँ ग्रामीण समुदाय बहुत पूर्ण हैं और जहाँ उन समुदायों के अन्तर्गत रहनेवाले सभी



कुटुम्बों में प्राचीन काल से आनेवाली साम्प्रतिक समानता है, वहा वे अधिकार जो अन्यत्र गाव के मुखियों के पास पाये जाते हैं, ग्रामीण परिषद के पास हैं। सदा ही ग्रामीण समुदाय को एक प्रतिनिधि सस्था के रूप में देखा जाता है, निहित अधिकार प्राप्त किसी सगठन के रूप में नहीं, और ऐसी परिषदों के सदस्यों की संख्या भले ही कितनी हो, पर उसका नामकरण सदा वही रहता है जिससे प्राचीन काल से चले आनेवाले पाच व्यक्तियों का आभास होता है।”

### केन्द्रीय एशिया में क्रीडा-स्थल से प्रथम महाप्रस्थान

वस्तुतः भारतीय ग्रामों का अतीत, उसके कार्य के प्रमुख नियम, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों एवं निवासियों के लिए बने नियम, उसका मूलतः स्वावलम्बी रूप, इत्यादि, ऐसी बातें हैं जो सर्वविदित हैं और प्रस्तुत लेख में हम उनकी चर्चा नहीं करना चाहते। गहरे ऐतिहासिक अनुसंधानों ने यह सिद्ध कर दिया है कि मानव के प्रथम क्रीडा-स्थल केन्द्रीय एशिया से जब उनका महाप्रस्थान प्रारम्भ हुआ तो उनके एक गुट ने सुप्रसिद्ध ईरानी साम्राज्य की स्थापना की थी। एक दूसरा गुट भूमध्यसागर के दक्षिण में पहुँचा और उत्तरी अफ्रीका के देशों को बसाया। एक और गुट भूमध्यसागर के उत्तर देशों को पहुँच कर यूनानी, इटैलियन और स्पेनिश राज्यों को जन्म देता है। कुछ और भी उत्तर पहुँचकर फ्रांसीसी, आयरिश और प्रथम अंग्रेज जातियों का पूर्वज बना। केन्द्रीय एशिया से प्रस्थान करनेवाला एक और भी गुट और भी उत्तर जाकर स्लाव, ट्यूटन और स्केन्डिनेवियन देशों का प्रथम नागरिक बना। हमारे महान् आर्य पूर्वज भी इसी केन्द्रीय एशियाई प्रदेश से चलकर सिन्धु और गंगा की नदियों के विशाल मैदानों में आकर बसे और जैसा हेनरी सुमनर मेन ने कहा है, ये सब अलग-अलग गुट अपने प्रारम्भिक प्राचीन क्रीडा-स्थल से वहा की ग्राम्य-व्यवस्था को लेकर आये। ऐतिहासिक अनुसंधानों ने सिद्ध कर दिया है कि ये प्राचीन सामूहिक ग्राम्य-समुदाय यूरोप में और अमेरिका में भी पाये जाते थे परन्तु कालान्तर में वे विनष्ट हो गये, उनके अधिकार नष्ट-भ्रष्ट हो गये और उनके स्थान पर यूनानी और रोमन साम्राज्यों जैसी सस्थाएँ आ खड़ी हुईं, जिनके अन्तर्गत मनुष्य का भयकर शोषण होता रहा, मानव-मानव को कुचलता रहा और गुलाम प्रथा और गुलामों का क्रय-विक्रय उस समाज का सबसे प्रमुख अंग हो गया। बाद में उन गुलामों के विद्रोहों ने उन शोषक प्रथाओं को जड़ से हिला दिया। दास प्रथा के स्थान पर अर्द्ध-दास प्रथा आयी और सामन्ती शासन और सम्राट व्यवस्था चली और केन्द्रीय एशिया के क्रीडास्थल से आनेवाली ग्राम व्यवस्था के चिह्न भी शेष न रहे।

### भारत में भूमि पर निजी सम्पत्ति कभी नहीं

परन्तु हमारे भारत में विकास क्रम विल्कुल भिन्न ही रहा। हम यहा भारत के इस विशिष्ट विकासक्रम के कारणों की समीक्षा नहीं करेंगे, परन्तु वास्तविकता यह है, जैसा प० जवाहरलाल नेहरू ने हिन्दुस्तान की कहानी में कहा है “भारत में कभी धर्म पर आधारित सम्राट-व्यवस्था नहीं रही है। भारत में राजा की शक्ति की जो कल्पना थी वह यूरोपीय सामन्तवाद से सर्वथा विभिन्न थी जिनके अन्तर्गत सम्राट का

अधिकार उसके साम्राज्य के सब प्राणियों और सब वस्तुओं पर एक-छत्र माना जाता था। वह सम्राट यह अधिकार कुछ लाटो और वरनों को प्रदान कर देता था और इस प्रकार एक के ऊपर एक अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का ढड्डा-सा खडा हो जाता था।”

भारतीय समाज के इस विशिष्ट विकासक्रम के सम्बन्ध में अर्थात् यहा पर दासों और अर्द्धदासों को रखनेवाली सामन्ती प्रथा के न होने के विषय में कुछ ही लोगों ने सदेह प्रकट किया है। सन् १९५२ में डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त द्वारा लिखित एक पुस्तक डायलेक्टिस आफ लैंड इकोनामिक्स इन इंडिया हमारे सम्मुख है जिसमें विद्वान लेखक ने इस कल्पना को चुनौती दी है। विद्वान लेखक ने पुस्तक की भूमिका में कहा है कि सन् १९२१ में वह मास्को में लेनिन से मिले थे और स्पष्टतः वह मार्क्सवादी ही प्रतीत होते हैं, यद्यपि साम्यवाद के अधिष्ठाता मार्क्स और एगिल्स से उनके गहरे मतभेद भी मालूम होते हैं। एगिल्स ने ६ जून १८५३ को मार्क्स को एक पत्र लिखा था, उसमें उसने कहा था “सम्पूर्ण पूर्व को समझने के लिए भूमि में व्यक्तिगत सम्पदा के अभाव के न होने को समझना ही वास्तविक कुजी है। इसीमें पूर्व का राजनीतिक और धार्मिक इतिहास छिपा हुआ है। पर इसका क्या कारण है कि पूर्व के निवासी कभी भी भूमि पर निजी सम्पत्ति की अवस्था को, उसके सामन्ती रूप में भी, नहीं प्राप्त करते।” डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त एगिल्स के इस कथन से सर्वथा असहमत हैं और कुछ क्रुद्ध भी हैं और कहते हैं कि “हेनरी सुमनर मेन के गलत मार्ग प्रदर्शन के फलस्वरूप ही मार्क्स और एगिल्स इस गलत निष्कर्ष पर पहुँचे कि भारत में कबाइली साम्यवाद था या साम्यवादी ग्राम थे, जिनको] मार्क्स ने सुखद गणतंत्र कहा है, और भारत में सामन्तवाद विकसित नहीं हुआ।”

### भारत के प्राचीन ग्रन्थों में ग्राम पंचायतों की चर्चा

एक मार्क्सवादी द्वारा मार्क्स को गलत कहना चाहे जितना ही आश्चर्यजनक और कौतूहलकारी हो, परन्तु इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि डा० भूपेन्द्रनाथ दत्त के विचार उन सूचनाओं से भिन्न हैं जो अपनी प्राचीन ग्राम पंचायतों के सम्बन्ध में सस्कृत के ग्रन्थों, वेदों, उपनिषदों, पुराणों इत्यादि से हमको प्राप्त हैं।

जैसा स्वर्गीय श्री रमेशचन्द्र दत्त ने कहा है “भारत में स्वायत्त शासन की प्रथा सबसे पूर्व विकसित हुई और सबसे लम्बे काल तक स्थापित रही।” ऋग्वेद में ग्रामणी अर्थात् ग्राम के नेता की चर्चा आती है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड में कहा गया है कि राजा दशरथ के राज्य में कोई ऐसा नहीं था जो लिखा-पढा न हो और “प्रत्येक व्यक्ति अपनी सासारिक सम्पत्ति से सतुष्ट था,” और उस समय कोई निर्धन नहीं था। वाल्मीकि रामायण में जनपदों की चर्चा हुई है, और इसी जनपदीय व्यवस्था के अन्तर्गत, जो विभिन्न ग्रामीण गणतंत्रों के स्वरूप ही थे उस समय इतनी समृद्धि थी। हमारे सबसे प्राचीन नीति-निर्देशक मनु ने कहा है कि ग्राम ही शासन की प्रथम ईकाई है। एक ग्राम के ऊपर उनके अनुसार १० ग्रामों की ईकाई थी, फिर १०० ग्रामों की ईकाई, फिर १,००० ग्रामों की ईकाई थी, और इस प्रत्येक ग्राम समूहों का निजीशासन प्रबन्ध हुआ करता था। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में भी गण और पुग की चर्चा आती है और ये दोनों ग्राम अथवा शहर नगरपालिकाओं के तुल्य थे।

महाभारत के वनपर्व में, और फिर शांतिपर्व में, ग्राम्य समुदायों की चर्चा पायी जाती है और यह दृष्ट अथा जाता है कि ग्राम के नेताओं का क्या दायित्व है। वांछ जातक कथाओं में भी ग्राम्य नभाओं की बहुधा चर्चा मिलती है। एक राजा की प्रेयसी ने राजा से कहा कि उसे भी शासन में अधिकार दिया जाय, तो राजा ने उत्तर दिया "प्रिये, अपने राज्य की जमता पर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। मैं तो केवल उन पर ही कुछ अधिकार रखता हूँ जो विद्रोह करते हैं और गलती करते हैं।" न्यर्गीया डा० एनी वेनन्ट ने कहा है "हमको कभी भी द्रविड अथवा आर्यकालीन भारत में कोई भी ग्राम नहीं मिलता था जो स्वशासित न रहा हो। यही युगो-युगो तक चलनेवाली भारत की अनुपम समृद्धि का मूल स्रोत और कारण था।" सुप्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान प्रो० राइज डेविड्स ने लिखा है, "बौद्ध पुस्तकों में कहा गया है कि ग्रामीण एकत्र होकर मुहल्ले बनाने थे, विश्रामगृह बनाते थे, मठों की मरम्मत करने थे और उद्यान भी निर्मित करते थे।"

### प्राचीन भारत की ग्राम्य व्यवस्था

दो प्राचीन पुस्तकें, कीटिलीय ग्रंथशास्त्र और शुक्रनीतिमार में, उस समय भारत में प्रचलित ग्राम्य-व्यवस्था का विस्तृत वर्णन पाया जाता है। उनमें बताया गया है कि ग्राम की भूमि पर ग्रामवालों का पूर्ण अधिकार था। प्रायः प्रत्येक ग्राम में तीन नस्थाएँ थीं और उनकी निजी इमारतें भी थीं, यथा (१) मन्दिर और उनमें मिला हुआ तालाब जहाँ पूजा की जाती थी, (२) ग्राम की पाठशाला, (३) विश्रामगृह जहाँ यानी ठहरते थे और जहाँ उनकी भेवा-शुश्रूषा की जाती थी। ग्राम की आबादी के क्षेत्र के शेष भाग में ग्रामीणों के मकान थे, मठों की और खुले स्थान थे। हर ग्रामीण के घर के साथ एक श्रद्धाता होता था और मञ्जी उगाई जाती थी। उन पुस्तकों में इन बातों का आरच्यचक्रित करनेवाला वर्णन पाया जाता है कि किस प्रकार, कहाँ पर, कौन से पेड़ लगाए जाय। ग्रंथशास्त्र में इन बातों की भी चर्चा है कि नये ग्रामों का निर्माण कहाँ और कैसे हो। कहाँ गया है। "राजा या तो नये स्थानों पर या पुराने उजड़े ग्रामों में बाहर से लोगों को बुलाकर या राज्य के बहुत ही धने वसे हिम्नों से लोगों को भेजकर नये ग्रामों का निर्माण कर सकता है।" कीटिलिय ने कहा है कि राजा का कर्तव्य है कि वह कुटुम्बों को ग्राम की एकता के मूल में बाधे। ग्रंथ शास्त्र में कहा गया है "जुधि करनेवाले मूढ़ वगैरे के कम-से-कम ५०० घरानों को लेकर और उनका क्षेत्रकण्ट एक या दो तोम में अधिक न रखकर ग्राम प्रभाव जायेंगे ताकि वे एक दूसरे की सुरक्षा कर सकें। ग्रामों की सीमा नदी द्वारा, पर्वत द्वारा, वनों द्वारा या बटोले पेड़ों द्वारा गुफाओं द्वारा, दृष्टि दीवारों द्वारा, अथवा अन्य वृक्षों द्वारा निर्माणि होगी।"

बन्तुत कीटिलिय ग्रंथशास्त्र के दाल में (सिन्हा के पूरे की सी शकतरी) प्रत्येक ग्राम या राज्य मन्ता में विभिन्न मन्तन या और नये ने यह है कि ग्राम ही पूरे राज्य शासन की दुनिया में। ये प्राचीन शासन न केवल शासकीय कार्य ही करते थे, बरन् वे न्याय काय भी चलाते थे।

### भविष्य निर्माण के लिए महान् भूत का अध्ययन

हम इस चर्चा को आगे नहीं चलायेंगे। वास्तव में प्राचीन भारत की ग्राम पंचायतों का अध्ययन बड़ा ही रोचक विषय है और उसकी तो बहुत अध्ययन की आवश्यकता है। हम जानते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसे तत्त्व हैं जो हमारी प्राचीन पंचायत व्यवस्था के महत्व को, उनके गौरव को नजरन्दाज करने की मञ्जान रखते हैं और वे उन हर प्रवृत्ति के विरोधी हैं जो उनके अनुसार उन पंचायतों को "पुनर्जीवित" कराना चाहती हैं। हम कदापि प्राचीन पंचायत व्यवस्था को विकृत उन्नी रूप में, "मधिका म्याने मधिका" नहीं लेना चाहते। हमारे उन गौरवपूर्ण अतीत से लेकर अब तक जमाया बहुत बढ़ गया है और आज समार की स्थिति उग समय की स्थिति से भिन्न है और हमको उन नव दलों को अपने मस्तिष्क में रखना होगा। हम यह भी जानते हैं कि प्राचीन और मध्ययुगीन काल में कभी-कभी पंचायतों पर तत्कालित उच्च वर्गों का अधिपत्य स्थापित हो गया और उनके द्वारा निर्णय वर्गों मूढ़ों पर, अत्याचार किया गया। हम जब उन पंचायतों की चर्चा करते हैं तो हमारा मस्तिष्क केवल इतना है कि हम अपने भूतकाल का अध्ययन करें ताकि हम उनसे भी महान् भविष्य निर्मित कर सकें। जैसा कि स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था "आपको अपने देश के प्राचीन वैभव और गौरव की स्मृति दिलाने में मेरा एक ही नानार्थ है। बहुधा मुझसे कहा गया है कि पीछे की ओर देखने से अथ पतन होता है, उनका कुछ फल नहीं होता, और हम लोगों को आगे देखना चाहिये। यही नहीं है, पर मन भूतियों, भूत के ऊपर ही भविष्य का निर्माण होता है। अतः पीछे देखो, जहाँ तक देय माने ही देखो। पीछे छुटे हुए अमर्योंतों के जल को पियो और उनके बार आगे देखो, आगे बटो, भारत को उनका महान् बनाओ, इतना चमकाओ जितना वह पट्टे कभी नहीं था। हमारे पूर्वज महान् थे। हमसे समझना चाहिये कि हमारे अपने अस्तित्व में क्या तन्व प्रिद्यमान है, हमारी नगों में कौन क्या बहना है। हमें उस रान में विद्वान रचना चाहिये। उस रान में भूतकाल में क्या किया उसे समझना चाहिये, और उन विद्वान में अनुप्राणित होकर अपने महान् भूत के गौरव को मन्तिष्क में राने हुए हमको एक ऐसे नये भारत का निर्माण करना है जो उनका महान् हो जितना कि वह पट्टे कभी नहीं था।" अपनी पुस्तक राज्य मन्ता में अमरीता के प्रेसीडेण्ट न्यर्गीय वृद्धने विद्वान ने कहा था, "प्रत्येक राष्ट्र तो, प्रत्येक देश के प्राणियों को अपने ही अनुभवों के आधार पर रचना चाहिये। जिस प्रकार एक व्यक्ति दूसरे ने उसके अनुभव उद्यम नहीं ले सकता, वैसे ही एक राष्ट्र भी अनुभव उद्यम नहीं ले सकता। हमारे लोगों का उद्विगत अमन्य हमको प्रताप दे सकता है परन्तु स्वतंत्र बनने काय करने की जिम्मे नहीं पिट सकती। प्रत्येक राष्ट्र का नया अपने भूत से अन्त मन्वय स्थापित राना चाहिये।"

### प्राचीन भारतीय ग्रामों पर नेहल जी का मत

जिन विद्वान् उन मत पर और राना मानते हैं चर्चा की थी अन्तम न्यर्गीय ने प्राचीन पुस्तक विद्वानों से अन्तम न्यर्गीय ने प्रस्ताव दे सकते हैं, जहाँ हमें विद्वान्, जहाँ नया के उद्यम विद्वान् को क्या माता मन्त और

और जहा व्यक्तिवाद को चरम सीमा पर पहुँचाया गया, वहा हमारे भारत में "समूह को ही समाज सगठन की बुनियादी इकाई माना गया।"

श्री नेहरू ने कहा है — "यह वाछनीय है कि हम भारत के पुराने सामाजिक ढांचे को समझें, जिसने हमारी जनता पर इतना गभीर और गहरा प्रभाव डाला है।" श्री नेहरू ने कहा है कि यह सामाजिक ढांचा तीन बातों पर आधारित था। प्रथम, स्वायत्त सत्ता सम्पन्न ग्रामीण समुदाय, द्वितीय, जाति सगठन, और तृतीय, सयुक्त परिवार। "इन तीनों में समुदाय का ही प्रभाव था, व्यक्ति का स्थान नीचा था।" और श्री नेहरू आगे कहते हैं "सामाजिक ढांचे के तीन खम्भे इस प्रकार सतह पर आधारित थे, व्यक्ति पर नहीं। उनका उद्देश्य था सामाजिक सुरक्षा, स्थायित्व और समूह को अर्थात् समाज को सुचारु रूप से स्थापित रखना। उसका उद्देश्य प्रगति करना नहीं था। अतः प्रगति नहीं हुई। प्रत्येक समूह में चाहे वह ग्राम समुदाय था, एक विशेष जाति के लोग थे अथवा सयुक्त कुटुम्ब था, एक

सामुदायिक जीवन हुआ करता था जिसमें सबों के समान अधिकार होते थे, सबों में बराबरी थी और जनतात्रिक तरीके से काम किया जाता था। आज भी यदाकदा जो जाति पचायते पायी जाती हैं, वे भी जनतात्रिक प्रणाली के अनुसार ही काम करती हैं।"

हमारे यह ग्रामीण गणतंत्र हिन्दू, मुस्लिम और पेशवाई हुकूमतों में वास्तविक जनतन्त्र और स्वायत्त शासन के अनुपम प्रयोग के रूप में बराबर चलते रहे। केन्द्रीय शासन सत्ता द्वारा जो नियन्त्रण रखा जाता था वह कुछ विशिष्ट बातों तक ही सीमित रहता था, यथा, मिंचन सुविधाएँ, सुरक्षा-सेना की स्थापना और केन्द्रीय करो का संग्रह। और, ग्राम के स्तर पर सिंचन सुविधाएँ स्थापित रखना और ग्राम से राज्य के केन्द्रीय करो को वसूल करने में ग्रामीण समुदाय ही प्रमुख भाग लिया करते थे। उस समय शासनयंत्र का मूल रूप ग्राम समुदायों पर आधारित विकेन्द्रित व्यवस्था थी।



चोलों के गौरवपूर्ण इतिहास का एक पृष्ठ

## भारत में छोटे तालाबों से सिंचाई की संभावनाएं

श्री न० ब० गादरे

सन् १९४६ के अगस्त मास के प्रभात में मुझे एक दिन छोटे तालाबों की बहु-प्रयोजनीय उपयोगिता एक अन्तर्दृष्टि के रूप में मिली। उस समय मैं वेलगाव में निरीक्षक अधिकारी के रूप में बम्बई-मंसूर सीमा पर स्थित मडग तालाब के निरीक्षण के लिये गया था। घोर वर्षा हो रही थी। पानी के नाले वह रहे थे। पूना-वगलौर की सड़क पर पानी कार से जा रहा था, जिसकी छत पर पानी गिरने की ध्वनि मेरे कानों में पड़ रही थी। तब मैं जिला रोड पर दक्षिण की ओर चल पड़ा। मैं एक ताल्लुका के कस्बे से गुजरा जहाँ एक छोटे तालाब के पास से सड़क पच्चीस मील की दूरी तक फौली हुई थी। यहाँ मुझे अन्तर्दृष्टि प्राप्त हुई उसकी स्मृति मेरे मन में आज तक ताजी बनी हुई है। सारा दृश्य सुख और समृद्धि का दृश्य था।

मुझे यह जानने में परेशानी नहीं हुई कि यह अन्तर इजीनियर के हाथों की करामात थी। क्या इजीनियर ने ही यह सब परिवर्तन ला दिया और क्या उसे केवल मात्र एक आकस्मिक घटना ही समझी जाय ?

कर्नाटक ही ऐसा प्रदेश क्यों है जहाँ विस्तृत क्षेत्रों में छोटे तालाबों द्वारा सिंचाई इतनी सफलता के साथ होती है ? अग्रजों की हुकूमत से उसकी पैदावार क्यों रुक गई ? और क्यों कोई सही सुधार अथवा व्यवस्था इन ७५ वर्षों तक नहीं हो सकी, इसके लिए इतने विशेष आयोग और समितियाँ बनाई गई थी ? हर साल क्यों ये छोटे तालाब बदतर हालत में होते जा रहे हैं ?

आधुनिक इजीनियरों की दृष्टि में इन छोटे तालाबों की व्यवस्था इजीनियरों के आविष्कारों से हमेशा अछूती ही रही। शायद उन्होंने उनमें किसी प्रकार की योजना अथवा आकृति नहीं देखी। दुर्भाग्यवश ब्रिटिश हुकूमत ने इन छोटे तालाबों का स्वामित्व और नियंत्रण अपने राजस्व विभाग के हाथ रखा तथा इजीनियर सगठनों के हाथों में तो यह

अधीक्षण नाम मात्र को था। जब कहीं कोई परेशानी पैदा हो जाती और कलक्टर उसका हल निकालने में असफल हो जाता तो इजीनियर उस परेशानी का निदान करने तथा उस पर नियंत्रण करने के लिए बुलाए जाते। इजीनियर को इन परेशानियों के कारणों पर प्रशासनिक और निरोधात्मक अधिकार नहीं होता था। अगर कोई उत्साही इजीनियर 'विकित्सक कार्य' से कुछ आगे करने के लिए हाथ-पैर बढ़ाता तो उसे निकाल दिया जाता था।

सरकार की ओर से काफी समितियों और आयोगों के होते हुए भी गत शताब्दी में छोटे तालाबों की अवस्था तीव्रता से विगड़ती रही है तथा इसकी रोकथाम भी नहीं हुई है। इसके विपरीत कोई नया तालाब नहीं बनाया गया। आज ऐसा लगता है कि दो-एक शताब्दी के बाद यह व्यवस्था ही समाप्त हो जायगी, जैसा कि हर पुरानी व्यवस्था के साथ होता आया है। मुझे लगता है कि जो कुछ हो रहा है वह ठीक नहीं है। एक इजीनियर और नागरिक होने के नाते मुझे इसका विरोध करने का अधिकार प्राप्त है।

जब तक कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक खोज इस सब में कोई अच्छा विकल्प हमारे सामने नहीं लाती मैं अपने "पानी सग्रह के दृष्टिकोण" को "चोल दृष्टिकोण" कहूँगा। यह नाम करीकल और राजराज चोलों की पुण्य स्मृति में रखा गया है जो हजार अथवा पंद्रह सौ वर्ष पूर्व कावेरी ग्रांड एनीकट तथा अन्य ऐसे ही कार्यों के निर्माता थे।

आधुनिक सिंचाई का इजीनियर बाधो, नालों और यातायात जैसी यान्त्रिक बातों को जानता है लेकिन छोटे तालाबों के विषय में उसने कभी चर्चा भी नहीं सुनी।

आधुनिक उच्च शिक्षा 'छोटे तालाबों की व्यवस्था के सिद्धान्त' के विषय में कुछ नहीं बतलाती है। परिणामस्वरूप इजीनियर असल में तो

मिस्त्री बन जाता है या एक ओवरसीयर। लेकिन छोटे तालाबों का इजीनियर, पानी देने और जमा करने तथा वर्षा की गति का तालाबों की दृष्टि से सतुलन करने के अतिरिक्त तालाबों के आसपास फँले हुए मैदान की मिट्टी का निर्माता और उसे सुरक्षित रखनेवाला है। यह वैज्ञानिक जादूगर साधारण वर्षा के क्षेत्र को कम जमीन में बदल देता है। अपने जिले के स्वास्थ्य, जलवायु और जगलात की भी वह देख-रेख करता है और उस जिले का कर्मचारी मात्र ही न होकर स्वास्थ्य-रक्षक और राज्य का निर्माता भी होता है।

नालो को नदियों से और पानी की धाराओं को नालो से अलग रखना चाहिये, घोर बाढ़ के अलावा, वर्षा का पानी जमीन द्वारा ही सोख लिया जाना चाहिये। भूमि से मिट्टी का एक कण भी सागर में नहीं जाना चाहिए।

अवकाश के समय मैंने इस विचार को सिद्ध अथवा असिद्ध करनेवाले तथ्यों और आकड़ों के अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसलिए मैंने उत्तर आरकोट के कुछ तालाबों को चुना क्योंकि इनके बारे में सूचना आसानी से मिल सकती थी। इन तालाबों का समग्र क्षेत्र नीचे लिखा है —\*

इस इलाके में प्रतिवर्ष वर्षा ४४ इंच के लगभग होती है। सम्भवत इसमें से २० इंच पानी तो जमीन सोख लेती है और बाकी तालाबों में चला जाता है। तालाब व्यवस्था का मुख्य प्रयोजन कम वर्षा-वाले प्रदेशों में ऊँची कीमत की फसलों को पानी पहुँचाने का है।

छोटे तालाब का विकास आसपास के क्षेत्रों में होना चाहिये। इनका विकास सम्भवत इसलिए नहीं हो सका क्योंकि पहले इन सब स्थानों पर जगल थे। इस क्षेत्र का कुछ हिस्सा ही तालाबों के लिए उर्वरुक्त है क्योंकि बाकी हिस्सा पहाड़ी और ऊबड़-खाबड़ है। अगर यह मान लिया जाय कि इस प्रदेश के आधे क्षेत्र में काफी छोटे तालाबों का निर्माण

किया जा सकता है तो इस निर्माण के द्वारा लगभग १२०० एकड़ भूमि उर्वर हो जायगी और १५०० एकड़ जमीन में चावल पैदा होने लगेगा। पूरे विकास के बाद इस क्षेत्र में नालों की शाखाएँ समाप्त हो जायेंगी जैसा कि चोल काल में छोटे तालाबों के कारण होता था।

तब इन उर्वर और लाभप्रद क्षेत्रों के मौजूदा मालिकों में जमीन को आपस में बांटने का काम राजस्व अधिकारियों का होगा। इसके लिए स्थानीय स्वच्छा से श्रम जुटाने और आवश्यक साधन-सामग्री एकत्रित करने का काम भारत सेवक समाज का होगा जिसकी सहायता पी० डब्ल्यू डी० करेगी। इस योजना को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार को ऐच्छिक मजदूरों को यह आश्वासन देना पड़ेगा कि दस साल तक वे ही अपने श्रम का उपभोग कर सकेंगे तथा उन पर किसी प्रकार का कर इत्यादि नहीं लिया जायगा। लेकिन इस योजना को हाथ में लेने के पहले यह देखना होगा कि पानी के उपभोग में कोई कानूनी बाधा न आए, लेकिन इसकी संभावना इस तथ्य के कारण कम हो जाती है कि ग्राड एनीकट नहर ने अपने बहाव की दिशा में आनेवाले इलाकों को पानी देने का उत्तरदायित्व ले लिया है। इस योजना को कार्यान्वित करते समय गाव के तमाम नकशों की सहायता लेनी आवश्यक होगी। यह सम्भव है कि १ मील ४ इंचों के नकशे मिल सकते हैं, वैसे तो कुछ इलाका अभी भी जगलात गिना जाता है।

यह कहना व्यर्थ होगा कि आज कोई भी इजीनियर हो, आधुनिक अथवा पुरातन, गैर इजीनियरों के इस विचार से सहमत नहीं होगा कि तालाब को साफ करने से उसकी पानी रखने की शक्ति को सुरक्षित रखा जा सकता है। यह आर्थिक दृष्टि से असम्भव है क्योंकि एक तालाब की सफाई करने में जो खर्चा होता है वह नया तालाब बनाने से बिसगुना है।

तालाब* व्यवस्था	अयाकट	अयाकट की औसत प्रति एकड़ सिंचित क्षेत्र	अयाकट की औसत प्रति एकड़ तालाब क्षेत्र	अयाकट की औसत प्रति एकड़ जल प्राप्त	तालाबों की औसत गहराई	तालाब भरने की औसत दर
१	२	३	४	५	६	७
संख्या	एकड़	एकड़	एकड़	क्यूसेक	फुट	
१	१२९०	५०	० ७५	४२	२७	१८
२	४१६	६१	० ६०	६३	४१	१६
३	१६१२	७३	० ६९	११८	२७	१८
४	१२४७	३८	० ६७	६०	४०	१४
५	८४८	६३	० ९०	११०	३६	१२
६	५६७	७०	० ८५	६२	४६	११
७	५०७०	५३	० ८०	८०	३१	१५

उपर्युक्त तालिका में ४,६ और ७वें कालमों का उत्पादन हरेक गुट के लिए कृत्रिम सिंचाई की गहराई को निम्नांकित रूप में मोटे तौर पर प्रकट करता है।

गुट संख्या	१	२	३	४	५	६	७
निर्माणों में	८४	४७	४१	४४	४७	५२	४५

**भारत** की आर्थिक समस्याओं ने गत २-३ वर्षों के भीतर काफी दिलचस्पी पैदा की है। इस समय हम प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में हैं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में मुख्य रूप से खेती पर जोर दिया गया था। योजना के अन्तर्गत, सार्वजनिक विनियोग का लगभग ४६ प्रतिशत अश खेती की पैदावार बढ़ाने के उद्देश्य से अपनाये गये उपायो और सिंचाई तथा शक्ति सम्बन्धी योजनाओं पर प्रयुक्त किया गया था। हमारा लक्ष्य यह था कि पाच वर्ष के बाद हमारे खाद्यान्नों का उत्पादन १४ प्रतिशत बढ़ जाय। कपास, गन्ना तथा खेती की दूसरी पैदावारों के सम्बन्ध में भी इसी तरह के लक्ष्य निश्चित किये गये थे। हमें इस दिशा में पर्याप्त सफलता मिली है और खेती के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। खाद्यान्नों की पूर्ति तथा खेती की दूसरी पैदावारों की वृद्धि में इस प्रकार के सुधार के फलस्वरूप हम अपने लोगों की दैनिक आवश्यकताएँ पूरी करने में समर्थ रहे हैं। इस कारण हमें विदेशों से अधिक आयात नहीं करना पडा है और खाद्य-नियंत्रण की परेशानी भी नहीं उठानी पड़ी है।

### खेती के उत्पादन में वृद्धि

निस्संदेह, खेती की पैदावार की वृद्धि का एक कारण यह भी था कि मौसम अनुकूल रहा। किन्तु, विकास सम्बन्धी विशेष उपायों के अपनाने तथा योजनाओं के पूर्ण हो जाने के कारण ही यह वृद्धि अधिकांशतः सम्भव हो सकी। योजना आयोग ने अनुमान लगाया है कि उत्पादन-वृद्धि का लगभग आधा अंश विकास सम्बन्धी प्रयत्नों का परिणाम रहा है। प्रमाण के रूप में मैं यह बताना चाहता हूँ कि यद्यपि सिंचाई और शक्ति सबंधी हमारी अनेक बड़ी-बड़ी बहु-उद्देश्यीय योजनाएँ अभी पूरी नहीं हो रही हैं, तथापि हमारे सिंचित क्षेत्र में लगभग १ करोड़ २० लाख एकड़ अथवा २५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। रासायनिक खादों का प्रयोग बराबर बढ़ रहा है और यह प्रति वर्ष २ लाख टन से बढ़कर चालू वर्ष में लगभग ६ लाख टन तक पहुँच गया है। इसी प्रकार का विस्तार हमारी बिजली की पूर्ति में भी हुआ है। पिछले तीन वर्षों के भीतर हमारी विद्युत उत्पादन क्षमता २ करोड़ ३० लाख किलोवाट से बढ़कर ३ करोड़ किलोवाट तक पहुँच गयी है। अगले एक-दो वर्षों में जैसे-जैसे हमारी बहु-उद्देश्यीय योजनाएँ पूरी होती जायेंगी, वैसे-ही-वैसे सिंचाई वाले क्षेत्र और बिजली की पूर्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होने की आशा है।

### औद्योगिक विकास

औद्योगिक क्षेत्र में कुछ नवीन बड़े उद्योगों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। सरकारी उद्योगों में सिन्धी का खाद का कारखाना उल्लेख-

नीय है जहाँ प्रतिदिन १ हजार टन रासायनिक खाद तैयार हो सकती है। यह कारखाना पिछले दो वर्षों से खाद का उत्पादन कर रहा है। चित्तूरजन का रेल-इंजिन का कारखाना प्रतिवर्ष १०० लोकोमोटिव तैयार कर सकता है। इसके अलावा, सरकारी उद्योगों में पेनिसिलीन, डी० डी० टी और अखवारी कागज के कारखाने भी उल्लेखनीय हैं। अभी दो सप्ताह पहले दो और कारखाने ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। इनमें से एक रेल के डिब्बे और दूसरा मशीनी औजार तैयार कर रहा है। वैयक्तिक उपक्रम ने भी विकास में योग दिया है। वैयक्तिक क्षेत्र के उद्योगों में उत्पादन ही नहीं बढ़ रहा है, बल्कि नये कारखाने भी खुले हैं। औद्योगिक उत्पादन का समूचा संकेतांक सन् १९५० के १०५ से बढ़कर सन् १९५५ के पहले तीन महीनों में १५२ तक पहुँच गया। उत्पादन की यह वृद्धि बराबर जारी है। सूती वस्त्र उद्योग का उत्पादन बढ़कर प्रतिवर्ष ५०० करोड़ गज सूती कपड़े तक पहुँच गया है। यह उत्पादन अब तक का सबसे अधिक उत्पादन है। इसके बल पर भारत सूती वस्त्र के निर्यात करनेवाले देशों में दूसरा स्थान प्राप्त कर चुका है। कागज उद्योग का उत्पादन भी ५० प्रतिशत बढ़ गया है। सिमेंट का उत्पादन सन् १९५०-५१ के २ करोड़ ७० लाख टन से बढ़कर सन् १९५४-५५ में ४ करोड़ टन तक पहुँच गया। बहुत से कारखाने हल्के इजीनिअरिंग के सामान भी तैयार कर रहे हैं और उनका उत्पादन पूरी क्षमता भर हो रहा है। विदेशी वैयक्तिक पूँजी और प्राविधिक निपुणता ने भी हमारे औद्योगिक विकास में पर्याप्त योग दिया है।

मैं जो चित्र उपस्थित कर रहा हूँ वह भारत के सर्वतोन्मुखी विकास का द्योतक है। हमारी प्रगति सभी क्षेत्रों में दृढ़ और व्यापक है। यह विकास जहाँ सार्वजनिक और वैयक्तिक, कृषि और उद्योग, यातायात और बिजली—सब पूँछिये, तो समस्त आर्थिक क्षेत्र में दिखलायी पड रहा है, वही शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण की दिशाएँ भी अछूती नहीं बची हैं। योजना में यह कल्पना की गयी थी कि हमारी राष्ट्रीय आय

## भारत की आर्थिक प्रगति

श्री गगनबिहारी लाल मेहता

५ वर्षों के बाद ११ प्रतिशत बढ़ जायगी । किन्तु, तीन वर्षों के भीतर स्थिर मूल्यों के रूप में हमारी राष्ट्रीय आय वस्तुतः १२४ प्रतिशत बढ़ गयी है । यदि हम पिछले दो-एक वर्षों में मौसम की अनुकूलता का योग स्वीकार कर लें, तो भी यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमारी राष्ट्रीय आय की वृद्धि की वार्षिक दर जनसंख्या वृद्धि की दर की अपेक्षा काफी अधिक हो गयी है ।

हमारे विकास सम्बन्धी प्रयत्न प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे हैं । सन् १९५४-५५ में सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे व्यय अनुमानतः ११ अरब डालर के रहे । चालू वर्ष में केन्द्रीय और राज्य सरकारों ने १५ अरब डालर विकास कार्यों पर व्यय करने का निश्चय किया है । जुलाई १९५५ में समाप्त होनेवाले १२ महीनों के भीतर उद्योगपतियों को लगभग ३७७ स्वीकृति-पत्र नये उद्योगों की स्थापना करने, अथवा वर्तमान उद्योगों के विस्तार के लिए प्रदान किये गये थे । इनमें से १०५ नये औद्योगिक कारखानों के लिए थे । इस प्रकार, विकास की गति तीव्र से तीव्रतर होती जा रही है । किन्तु, हम अभी रुकना नहीं चाहते । वस्तुतः हमारा उत्साह उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है ।

दरअसल, हमने अभी तक जो सफलता प्राप्त की है, वह तो सिर्फ शुरुआत है । हमने युद्ध और विभाजन के प्रभावों से अपनी आर्थिक व्यवस्था पर हुई क्षतियों को पूरा कर लिया है । एक ठोस नींव रखी जा चुकी है, लेकिन उस पर एक शक्तिशाली ढांचा खड़ा करने का कार्य पड़ा ही हुआ है । यद्यपि भारतीय जनता की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय ५३ से बढ़कर ५८ डालर हो गयी है, फिर भी वह बेहद कम है । जमीन पर जनसंख्या का भार बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि कारखानों में कुल रोजगार प्राप्त लोगों की २ प्रतिशत संख्या को ही काम प्राप्त है । गावों और शहरों में काफी बेरोजगारी और अर्द्ध बेरोजगारी है । इसके अलावा, देश की श्रम-शक्ति में प्रति वर्ष १५ लाख से २० लाख लोगों की वृद्धि हो रही है जिन्हें रोजगार देने की समस्या है ।

### द्वितीय योजना की तैयारी

इस पृष्ठभूमि पर ही द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तैयारी हो रही है । भारत में आयोजन एक लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया है । इसका अर्थ यह है कि लक्ष्यों, साधनों और कार्यक्रमों की प्राथमिकता के सबंध में जनता में काफी वातावरण चल रही है । अभी यह योजना अपनी तैयारी में है । अतः हमके सम्बन्ध में विस्तार के साथ कुछ कहना सम्भव नहीं है । किन्तु, उमकी कुछ मोटी-मोटी बातें बिल्कुल साफ हैं ।

भारत में सभी विकास सम्बन्धी प्रयत्नों का प्रमुख उद्देश्य जनता के जीवन-स्तर को शीघ्रतापूर्वक ऊंचा उठाना है । जहाँ जीवन-स्तर बहुत ही नीचा है, वहाँ इस दिशा में बहुत बड़ी कमी पूरी करनी है । अतः, इसमें नमय का तत्त्व स्वभावतः महत्त्वपूर्ण बन जाता है । प्रथम पंचवर्षीय योजना का अनुभव बताता है कि हमने राष्ट्रीय आय में ३ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि की है । योजना ढांचा के निर्माताओं ने यह विचार प्रकट किया है कि यदि दृढ़ निश्चय के साथ प्रयत्न किये जाय तो यह वृद्धि ५ प्रतिशत तक पहुँच सकती है । इस सम्बन्ध में योजना का जो रूप होगा, उस पर अभी वात्ता चल रही है । अतः अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता । फिर भी

यह बात स्पष्ट है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास की दर काफी ऊँची रहेगी और इसलिए, हमें यथासाध्य अधिकतम प्रयत्न करने पड़ेंगे । इसमें विनियोग की मात्रा भी पहली योजना से बहुत अधिक होगी ।

### उद्योगों की प्रधानता

भारत जैसे घनी आबादीवाले देश के सामने विकास संबंधी समस्या का एक अन्य महत्त्वपूर्ण पक्ष आर्थिक व्यवस्था को विविधतापूर्ण बनाने और रोजगार के अवसर बढ़ाने से सबंध रखता है । हमारे वित्त मंत्री ने अभी हाल में बताया था कि हमारे यहाँ लगभग ढेढ़ करोड़ लोग बेरोजगार हैं । योजना का जो ढांचा तैयार किया गया, उसमें ११० लाख वे रोजगार का लक्ष्य बताया गया है ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास को कम प्राथमिकता प्रदान की गयी थी, क्योंकि उस समय हमारे सामने खाद्यान्न की समस्या सबसे प्रमुख थी । उस समय ग्रामीण क्षेत्रों से निराशा और स्थिरता की भावना का मिटाना आवश्यक समझा गया था । मैंने ऊपर बताया है कि इस दिशा में हमने गत तीन वर्षों में काफी उन्नति की है । अतः दूसरी योजना में मुख्य जोर उद्योगों के विकास पर दिया जा रहा है । इन पर अधिक-से-अधिक व्यय किया जायगा, ताकि उत्पादन भी बढ़े और रोजगार भी । लेकिन, इसका मतलब यह नहीं कि अन्य क्षेत्रों में विकास अवरुद्ध रहेगा । वस्तुतः स्वयं उद्योगों का विकास तब तक संभव नहीं, जब तक यातायात और संचार, शक्ति, खनिज, आदि आधार-भूत आवश्यकता के क्षेत्रों में भी विकास न कर लिया जाय ।

### जनता का सहयोग

लोकतन्त्रात्मक व्यवस्थावाले देश में आयोजन तभी सफल हो सकता है जब जनता का सहयोग प्राप्त हो, और उसकी भावनाओं और अभिलाषाओं को मान्यता प्रदान की गयी हो । सत्तार भर में यह विचार फैला हुआ है कि आर्थिक उन्नति के परिणामों का वितरण अधिक-से-अधिक व्यापक रूप में होना चाहिए, ताकि कुछ थोड़े ही लोगों के हाथ में आर्थिक शक्ति केन्द्रित न होने पावे । यही धारणा 'समाजवादी ढंग के समाज' के हमारे लक्ष्य में अन्तर्निहित है । पहले, देश के सबसे बड़े राजनीतिक दल, कांग्रेस ने इस आशय का प्रस्ताव स्वीकार किया, और बाद में, भारतीय संसद ने इसे देश के आर्थिक आयोजन का उद्देश्य मान लिया । इसके सम्बन्ध में हमारे देश के बाहर कुछ भ्रम भी फैल गया है, अतः इस पर भी संक्षेप में कहूँगा ।

'समाजवादी ढंग के समाज' का उद्देश्य एक अर्थ में हमारे लिए कोई नयी बात नहीं है । वस्तुतः, यह उन भावनाओं का समन्वय है जो स्वतन्त्रता की प्राप्ति के बाद हमारी सामाजिक और आर्थिक नीति का मार्ग प्रदर्शन कर रही है । हमारे विधान में भी हमारा आदर्श कल्याणकारी राज्य निश्चित किया जा चुका है, जो सामाजिक न्याय पर आधारित होगा, और जिसमें स्वामित्व और समाज के भौतिक साधन इस प्रकार वितरित होंगे कि उनसे सार्वजनिक कल्याण में वृद्धि होगी और कुछ थोड़े लोगों के हाथों में ही संपत्ति केन्द्रित न होने पायेगी । मैं इस सम्बन्ध में 'वर्ल्ड टूडे' नामक पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का उद्धरण देना चाहूँगा

जो इस दिशा में अच्छा प्रकाश डालता है। इसमें कहा गया है, "भारत उन्मूलन नहीं करता, वह सशोधन करता है। पश्चिम से उसे जो विचार और प्रविधियाँ मिल रही हैं, उन्हें ग्रहण करके, वह स्वयं अपने विचारों, विशेष कर हिन्दू परम्पराओं, के साथ उन्हें समन्वित कर रहा है। इस प्रकार, वह एक नवीन सामाजिक उत्पन्न कर रहा है जो कालान्तर से विश्व के अर्द्धविकसित देशों के लिए हिंसा विना परिवर्तन और भय विना समानता का नमूना बन जायगा। भारतीय राजनीतिक परम्परा निरन्तरता को महत्त्व देती है, वाधाओं को नहीं, समुचित ढंग पर निर्मित सत्ता को महत्त्व देती है, क्रान्तिकारी वैधानिकता को नहीं।" वस्तुतः हम जनता के लिए, और जनता द्वारा आयोजन में ही विश्वास करते हैं।

### वैयक्तिक पूंजी और उपक्रम

हम जिस प्रकार के समाज की कल्पना कर रहे हैं, उसमें वैयक्तिक उपक्रम का निष्क्रमण नहीं होगा। वस्तुतः, एक व्यापक क्षेत्र में वैयक्तिक साहस को उसकी क्रियाशीलता की पूरी छूट प्राप्त है। पिछले वर्षों में वैयक्तिक क्षेत्र द्वारा औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारे इस क्षेत्र की स्वतंत्रता का अपहरण नहीं हुआ है।

भारत वैयक्तिक उद्योगों का राष्ट्रीकरण किसी सिद्धान्त के वशीभूत होकर नहीं करना चाहता। वह उद्योगों की क्रियाशीलता में हस्तक्षेप भी नहीं करना चाहता। हमारा सबसे प्रमुख आर्थिक क्षेत्र, अर्थात् कृषि, तो एकदम व्यक्तिगत किसानों के हाथों में ही है। हम केवल यही चाहते हैं कि खेत के जोतने-बोनेवाले ही उसके स्वामी रहे। हमारे गत वर्षों के अनुभव ने भी यह सिद्ध कर दिया है कि सरकार और वैयक्तिक हित, जिनमें विदेशी भी शामिल हैं, अनेक क्षेत्रों में सहयोग से काम कर सकते

हैं। सरकार वैयक्तिक उद्योगों को विकसित करने में तरह-तरह से सहायता भी देती है।

सार्वजनिक क्षेत्र के विकास ने अनेक दृष्टियों से वैयक्तिक क्षेत्र के विकास में सहायता पहुँचायी है और सरकार तथा वैयक्तिक क्षेत्र में उत्तरोत्तर बढ़ता हुआ सहयोग रहा है। मैं कहूँगा कि हम आज की समस्याओं को कल के नारों द्वारा नहीं हल कर सकते। जैसा कि कई वर्ष पहले एक अनुदारदलीय अंग्रेज नेता ने कहा था, "आज हम सभी समाजवादी हैं।" आज जन कल्याण के लिए सरकार का आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में सक्रिय हिस्सा लेना अनिवार्य हो गया है। यह स्थिति आज अर्द्धविकसित राष्ट्रों के लिए और भी अधिक महत्त्व रखती है। मैंने भारत में विदेशी वैयक्तिक पूँजी के भविष्य पर विशेष रूप से कुछ नहीं कहा है, क्योंकि हम उत्पादन के ढंग के किसी विदेशी या भारतीय उपक्रम में कोई खास भेद नहीं करते। हमारे प्रधान मंत्री ने अभी हाल में ही कहा है कि देश के औद्योगिक उत्पादन के स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से अन्य देशों के साथ सवध और सम्पर्क बढ़ाना होगा। हमने विदेशी पूँजी के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण विलकुल स्पष्ट कर दिया है। हम इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं करेंगे।

हमारे भावी समाज की जो रूपरेखा सोची गयी है उसमें राज्य की सक्रियता उत्तरोत्तर बढ़ती जायगी, जिससे आर्थिक विकास होता जाय, कुछ ही लोगों के पास संपत्ति अनुचित रूप से केन्द्रित न होने पाये और राष्ट्रीय संपत्ति का उचित बटवारा हो सके। हमारा लक्ष्य है सर्वसाधारण का कल्याण। हमारा प्रयत्न रूढ़िवादी नहीं, बल्कि गतिमान है। आज के युग में हमें सामाजिक न्याय को आर्थिक नीति के रूप में रूपान्तरित करना आवश्यक हो गया है। इस कठिन कार्य में मुझे विश्वास है कि हमें उन सभी का सहयोग और उनकी सद्भावना प्राप्त होती रहेगी, जो समानता और स्वतंत्रता को महत्त्व देते हैं।





# ग्राम पंचायत और ग्रामीण विकास

श्री त्रिलोक सिंह

ग्राम पंचायत को ग्रामीण-विकास के केन्द्र में स्थापित करने का प्रयत्न वस्तुतः, प्राचीन नाम के अन्तर्गत, एक नवीन सस्था की स्थापना का प्रयत्न है। नवीन और प्राचीन पंचायतों की सामाजिक पृष्ठ-भूमि एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है और उनके उद्देश्य, कार्य और अभिप्राय भी भिन्न-भिन्न हैं।

## वर्तमान स्थिति

अब हम ग्रामपंचायत का पुनर्निर्माण करने जा रहे हैं। ऐसी हालत में ग्रामीण समाज जिस प्रकार की अन्तर्कालीन स्थिति से गुजर रहा है उसका महत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा। कई दशाब्दियों से एक सुसंबद्ध सामाजिक संघटन के रूप में ग्राम समाज धीरे-धीरे, लेकिन नियमित रूप से, पतनोन्मुख है। ऐसी हालत में, जबकि गाव के भीतर और उसके बाहर व्यक्तिगत हितों की सिद्धि अधिकाधिक सामान्य रूप धारण करती जा रही है, अपने सदस्यों पर समाज का प्रभाव क्रमशः घटता जा रहा है। भूमि के स्वामित्व में असमानता की वृद्धि, खेती न करनेवाले लोगों के हाथों में अधिकाधिक जमीन का चला जाना और गाव छोड़ कर शहरों में जाना इस प्रगतिशील प्रवृत्ति के ज्वलन्त प्रमाण हैं। अपनी जनसंख्या की तुलना में भारत के गावों का पेशावार ढांचा इस समय जितना मुख्य रूप से ग्रामीण है, उतना शायद आज से १०० या ५० वर्ष पहले नहीं था। जनसंख्या के बढ़ जाने की वजह से लगातार और पूरे समय के रोजगार के अवसरों का अभाव पहले की अपेक्षा अधिक स्पष्ट हो गया है। इस कारण ग्राम समाज के कुछ वर्गों, जैसे छोटे भूस्वामियों, काश्तकारों, मजदूरों और कारीगरों की हालत बड़ी खराब हो गयी है और उन्हें बहुत कष्ट उठाना पडा है।

हाल में जो भूमि सुधार हुए हैं, उनके फलस्वरूप जमीन के स्वामित्व में अमानता कम होने लगी है लेकिन पर्याप्त रूप में नहीं। गाव के पुनर्नवतृत्व की स्थिति और उसके प्रभाव घटते जा रहे हैं, किन्तु उनका स्थान ग्रहण करनेवाले नये नवतृत्व का उद्भव नहीं हो पा

रहा है। जातीय प्रथा का सामाजिक प्रभाव घट गया है, लेकिन उसका आर्थिक प्रभाव बढ़ गया है, खास तौर पर अनुसूचित और पिछड़ी जातियों के लिए। शायद उत्पादन के स्वतंत्र साधनों के अभाव या वैकल्पिक अवसरों की कमी के कारण ही ऐसा हो रहा है। जमीन की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि के लक्षण अवश्य दिखलायी पड रहे हैं, लेकिन यह वृद्धि अभी इतनी कम है कि उसके कारण अभी ग्रामीण गरीबों के घटने में कोई विशेष सहायता मिलती दिखलायी नहीं पडती। देश की अर्थ-व्यवस्था ने अपने समूचे रूप में उन्नति की है, लेकिन जनसंख्या और उत्पादन के बीच की खाई के कम होने के संकेत नहीं मिल रहे हैं।

इस स्थिति में ग्राम समाज के भीतर हित-संघर्ष तीव्र हो उठा है और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है। अब ऐसे मूल्य बहुत ही कम हैं, जिसका सबब सारे समाज में सामान्य रूप में हो, और इनमें तो कोई शक ही नहीं है कि कोई ऐसा सार्वजनिक उद्देश्य नहीं रह गया है जो समान रूप से सभी वर्गों को प्रेरित कर सके। बहुत सी नयी बातों से कुछ लोगों को लाभ होता है और दूसरों को हानि। इस सम्बन्ध में, जमीन्दार के ट्रैक्टर और बिजली के कनेक्शन का दृष्टान्त दिया जा सकता है जिससे गाव के उपक्रमों को चावल और आटे की चक्की के लिए बिजली मिलती है। एक ही बात से, जहाँ एक ओर, कुछ लोगों की उन्नति होती है और वे समृद्ध होते हैं, वहीं दूसरी ओर दूसरे लोगों की गरीबी बढ़ती जाती है। समाज में इतनी शक्ति नहीं प्रतीत होती है कि वह इनमें से किसी एक प्रवृत्ति को भी रोक पाये।

इस प्रकार, नवीन ग्राम पंचायत का जन्म एक ऐसे समाज में हो रहा है, जिसमें अपनी एकता और अपने अन्त सम्बन्ध में अपना विश्वास प्रायः खो सा दिया है, और जिसके सदस्य अपने हितों की भिन्नता के प्रति अधिकाधिक जागरूक होते जा रहे हैं, ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि जिन आचारों पर ग्रामीण लोकतंत्र का शिलान्यास करना है, वे अब स्थिर नहीं रह गये हैं। ऐसी हालत में, गाव के आर्थिक और सामाजिक

विकास के साधन के रूप में पचायतो को भला कितनी सफलता मिल सकती है ?

### सफलता की शर्तें

चाहे हम ग्राम पचायत को ग्रामीण-विकास की दिशा में पहला कदम मानें, चाहे परिवर्तन और पुनर्निर्माण की दिशा का अग्रणी, एक बात विल्कुल निश्चित है कि इसे सफलता उसी सीमा तक प्राप्त हो सकेगी, जहां तक (१) यह एक समानतापूर्ण सामाजिक ढांचे के भीतर, जिसमें समाज के विभिन्न वर्ग सार्वजनिक प्रेरणाओं और भावनाओं से प्रेरित हों, क्रियाशील होंगी और (२) ग्रामीण जीवन का आर्थिक आधार विस्तृत और सवल बनाया जा सकेगा। पहली शर्त तो पचायतो के पिछले इतिहास और उन पर सौंपी गयी जिम्मेदारियों से ही निकली है, किन्तु दूसरी शर्त पिछली कुछ दशाब्दियों के भीतर जनसंख्या की वृद्धि और आर्थिक विकासो पर आधारित है। उन लोगों के लिए जो पचायतो को ग्रामीण-पुनर्निर्माण का साधन बनाना चाहते हैं, पहला सवाल पचायतो के स्वरूप और संघटन ( जो निस्संदेह महत्त्वपूर्ण है ) से उतना सवध नहीं है, जितना उस ढंग से जिसमें उपर्युक्त दोनों शर्तें पूरी की जा सकती हैं। ऐसी हालत में, परिवर्तन के वे कौन से सिद्धान्त हैं, जो ग्राम पचायतो की धारणाओं में निहित हैं और आज के गाव में उसकी स्थापना की शर्तें बने हुए हैं ?

### रोजगार की समस्या

ग्राम पचायतो के लिए जिन कामों का प्रस्ताव किया गया है, उन्हें कार्यान्वित करने में उनको समर्थ बनाने के लिए यह जरूरी है कि ग्रामीण समाज को इस प्रकार परिवर्तित कर दिया जाय कि वह एक ओर तो अपने सभी सदस्यों को पद और अवसर की समानता प्रदान कर सकें, और दूसरी ओर, व्यक्तिगत मजदूरों के लिए लाभप्रद रोजगार का प्रवन्व कर सकें। जाहिर है कि जमीन के स्वामित्व में गहरी असमानता का अस्तित्व इन उद्देश्यों से मेल नहीं खाता, और व्यक्तिगत अराजियों को सीमित कर देना उन्नति करने की आवश्यक शर्त है। फिर भी, इस कारण कि अविभाजित किसान गरीब हैं, जमीनवाले लोगों और भूमिहीन लोगों का भेद जारी रहेगा। इस समय जो लोग भूस्वामी या काश्तकार के रूप में जमीन जोतते-बोते हैं, उनमें से अधिकांश इसी रूप में बने रहेंगे, हालांकि जैसे-जैसे भूमि सुधार लागू होगा, जैसे-जैसे अधिकांश काश्तकार भूस्वामी बनते जायेंगे। अतः, भूमि के पुनर्वितरण के फलस्वरूप भूमिहीनो, और खाम तौर पर परिगणित और पिछड़ी जातियों के लोगों के जीवन-स्तर में बहुत ही कम, और सच तो यह है कि केवल मामान्य, सुधार ही हो पायगा। यह परिणाम हासिल करना असमानता दूर करने की अपेक्षा अधिक कठिन काम है। इसके लिए ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के परिवर्तन के ढंग और राष्ट्रीय आयोजन के बीच अधिक समन्वय की आवश्यकता है।

ग्रामीण जनसंख्या के एक बहुत बड़े वर्ग को नये काम की तलाश में शहरों में जाना ही पड़ेगा। अगर नई औद्योगिक ईकाइयों को स्थानित करने के सम्बन्ध में अन्य बातों के साथ ही, धनी आवादी के क्षेत्रों की सन्तुलित अर्थ व्यवस्था पर उचित ध्यान दिया जाय, तो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था

पर औद्योगीकरण का प्रभाव बहुत लाभप्रद सिद्ध होगा। अगर शहरी और ग्रामीण अर्थ व्यवस्थाओं के आयोजन में निकटतर समन्वय हो जाय, तो भी जमीन पर काफी भार बना रहेगा। उस हालत में भी, गावों के सम्भावित मजदूरों की एक बड़ी संख्या को जमीन पर, और उन पेशों में जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकसित हो सकते हैं, रोजगार की तलाश करनी ही पड़ेगी।

खेती की पैदावार को बढ़ाने में ग्राम पचायतो तथा अन्य संस्थाओं के कार्यों का महत्त्व उचित रूप में स्वीकार किया जा रहा है, लेकिन अभी तक यह बात समझ में नहीं आ सकी है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में काम और सेवाओं के नये रूप किस प्रकार और किसके द्वारा विकसित करने होंगे। गावों में रोजगार के नये अवसर स्वतः उत्पन्न नहीं हो सकते। और न वे शहरी विकास और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियाशील व्यापारियों, ठेकेदारों और छोटे उपक्रमियों के उपक्रमों के फलस्वरूप उत्पन्न होंगे। अतः यदि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था की विविधता का केवल औद्योगीकरण, जो अविभाजित गावों से दूर बड़े शहरों में ही केन्द्रित है, के माध्यमिक और अप्रत्यक्ष प्रभावों पर ही अवलम्बित नहीं होता है तो ग्राम पचायत को रोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा करने और उन्हें कायम रखने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी। अन्य शब्दों में, ग्राम पचायतो को स्थानीय उपलब्ध जनशक्ति के उपयोग के लिए साधनों के विकास और विभिन्न रूपों में रोजगार के अवसर जुटाने की जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी।

### आन्तरिक और बाह्य शर्तें

किसी भी समय, अनुकूल परिस्थितियों के अन्तर्गत भी, इस प्रकार के उद्देश्यों की सिद्धि बंधक कठिन होगी। इस प्रकार के स्थानीय विकास के लिये कुछ बाहरी बातों का, कम-से-कम, अनुकूल होना तो जरूरी है ही। इन बातों का सम्बन्ध मुख्यतः उद्योग के स्थानीकरण के लिए अपनाये गये आधार से, बड़े और छोटे उद्योगों के सम्मिलित उत्पादित कार्यक्रमों के कार्यान्वित होने से और ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से विशेष रूप से सम्बद्ध उद्योगों के लिए सामान्य स्वरूप में सहकारी और सार्वजनिक प्रवन्व को स्वीकार करने से है। इन बाहरी शर्तों का पूरा करना बहुत ही कठिन है और साथ ही, वे स्वतः पर्याप्त नहीं हो सकेंगे। ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था से सवधित कुछ आन्तरिक शर्तों का पूरा करना भी जरूरी होगा। इन आन्तरिक शर्तों का सवध संघटन, प्राविधिक परिवर्तन और साम्प्रतिक सवधों से है। इन पर संक्षेप में विचार करना जरूरी है।

### सहकारी ग्राम-प्रबंध

यद्यपि बहुत से उद्देश्यों की सिद्धि के लिए व्यक्तिगत गावों के वजाय, ग्राम-समूह ही उपर्युक्त आयोजन-ईकाई का निर्माण करते हैं, फिर भी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के और अधिक विकास के लिए सयुक्त अथवा सहकारी ग्राम प्रवन्व की धारणा बहुत महत्त्व रखती है। इसका मतलब यह है कि गाव की जमीन और सारे साधनों का प्रवन्व और विकास समूचे ग्राम समाज के कल्याण के लिए ही होना चाहिये। अन्य शब्दों में समूचा गाव ही एक आर्थिक ईकाई हो जिसमें खेती और दूसरे पेशों का संघटन, समाज द्वारा या उसकी ओर से, अधिकतम उत्पादन और रोजगार

हासिल करने के उद्देश्य को सामने रख कर किया जाता हो। इस ईकाई के भीतर व्यक्तिगत उत्पादको, सहकारी सस्थाओ और सार्वजनिक कार्यों के लिए उचित क्षेत्र होना चाहिये। इन क्षेत्रों में किसका अनुपात कितना हो, इस बात का सम्बन्ध उन्नति और विकास तथा यथार्थ आयोजन से होना चाहिये। गाव के किसी व्यक्ति को लाभप्रद रोजगार उपलब्ध है अथवा नहीं, यह बात इस समय अधिकांशत उत्तराधिकार, जाति या भाग्य पर निर्भर करती है। सहकारी ग्राम प्रबन्ध की व्यवस्था के अन्तर्गत, समाज ही उन सभी श्रमिकों को लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है जो गाव में ही रहते हो, काम की तलाश में हो, और जो भी काम मिल सके उसे करने के लिए तत्पर हो। समाज की इस तरह की जिम्मेदारी के साथ-साथ ही, व्यक्तिगत सदस्यों पर भी कुछ कर्तव्यों का भार आ पड़ता है, जिसके लिए समाज उन पर दबाव डाल सकता है। इनमें से प्रमुख है कठिन और सच्चाई के साथ श्रम करना।

### पेशे की विविधता

पेशे की विविधता उत्पादन करने में समर्थ होने के लिए यह बात बड़े महत्त्व की है कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था नयी प्रविधियों को स्वीकार करे और उन्हें विकसित करे। तेज प्राविधिक परिवर्तन जिसमें शक्ति और औजारों का उपयोग भी शामिल है, और आर्थिक विकास का आधार है, किन्तु प्राविधिक परिवर्तनों को सामाजिक और आर्थिक परिवर्तनों का वास्तविक और समन्वित पहलू माना जाना चाहिये। सिद्धान्ततः, यह बात व्यक्तिगत जमीन्दारों या पूजापतियों द्वारा श्रम-बचाऊ तरीके अपनाये जाने से सर्वथा भिन्न है जो ऐसा केवल अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि के लिए ही करते हैं और इस बात की चिन्ता नहीं करते कि उससे दूसरे गरीब लोगों पर कैसा बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अन्य शब्दों में, प्रविधियों का विस्तार और उनका लागू करना स्वयं ही आयोजन का एक विषय है और गाव की जनशक्ति को उत्पादक रोजगार देने तथा स्थानीय साधनों के विकास के साथ उसका अत्यन्त अविच्छिन्न सबंध है।

इस प्रकार व्यापक अर्थ में, सामाजिक परिवर्तन के अन्तर्गत सघटन और प्रविधियों के वास्तविक परिवर्तन और नये रोजगारों के अवसरों का तेज विकास शामिल है। एक अर्द्ध-विकसित देश में जहाँ छिपी बेरोजगारी काफी मात्रा में पायी जाती है और जहाँ भूतकाल की सस्थाएँ आर्थिक विकास के मार्ग में बाधक हो, राष्ट्रीय आयोजन द्वारा साम्प्रतिक सबंधों को व्यवस्थित करके सामाजिक परिवर्तन को बहुत तीव्र किया जा सकता है। इस विचार की सभावनाओं की जांच बहुत मावधानी में होनी चाहिए। किन्तु, इसमें जो सुझाव निहित हैं, वे आर्थिक जीवन के अनेक क्षेत्रों पर लागू होते हैं। उदाहरण के लिए, जमीन के स्वामित्व और प्रबन्ध के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातों का समावेश हो सकता है

(१) किसी भी व्यक्ति के कब्जे की संपत्ति सीमित होनी चाहिये। यह सीमा जिस स्तर पर निश्चित होगी उसका निर्धारण अनेक प्रकार

के दृष्टिकोणों, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, द्वारा होता है।

(२) समाज द्वारा निर्धारित शर्तों पर संपत्ति पर व्यक्तियों का कब्जा होता है। अतः, जमीन पर तभी तक कब्जा कायम रह सकता है जब तक कि किसान और उसका परिवार उसे जोतता और बोता हो, वह लगान पर न उठायी जाती हो और उसका प्रबन्ध निर्धारित पैमाने के अनुसार ही होता हो।

(३) सामान्यतया, ऐसी जमीन जिस पर उसका मालिक और उसका परिवार खेती न करता हो, ग्राम समाज के सहकारी प्रबन्ध के अन्तर्गत चली जायगी।

(४) प्रत्येक ग्राम की अर्थ-व्यवस्था के भीतर स्थित व्यक्तिगत फार्मों और स्वच्छिक सहकारी सस्थाओं के अलावा, सामाजिक स्वामित्व और सामाजिक क्रियाशीलता का भी एक क्षेत्र हो सकता है। समाज के हिस्सों की मात्रा और उसे व्यक्त करने के ढंग, हाथ में लिये गये कार्यों स्वभाव के अनुसार भिन्न-भिन्न होंगे।

### सामाजिक स्वामित्व

सामाजिक स्वामित्व और सामाजिक क्रियाशीलता के क्षेत्र में (१) गाव की जमीन का एक अंश और (२) गाव के सार्वजनिक कार्यों, जैसे दुग्धशाला, आटे और चावल की चक्की, नलकूप आदि शामिल होंगे। लोकतंत्रीय सिद्धान्तों पर आधारित विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सहकारी फार्मों के साथ-साथ ही, ऐसे व्यक्तिगत कृषक-फार्मों के लिए भी स्थान है, जिन पर उनके मालिक खेती करते हो। किन्तु, किसी उल्लेखनीय पैमाने पर पूजा निर्माण के साधन के रूप में अग्रयार्थ सिद्ध होते हैं। हर दिशा में, उनमें से अधिकांश को अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए ही प्रयत्नशील रहना होता है। धीरे-धीरे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के भीतर से ही साधनों को कुछ बढ़ाये बगैर, सरकार से कुछ सहायता मिलने पर भी, गाव की श्रमशक्ति को रोजगार पर लगाने के लिए आवश्यक सेवाओं और कार्यों के नये स्वरूपों का विकसित करना कठिन होगा। तेज औद्योगीकरण की हालत में भी उनकी बेरोजगारी की यह समस्या गम्भीर ही बनी रहेगी। समाज के पास जो जमीन का संप्रह होगा उसमें, उदाहरण के लिए सार्वजनिक जमीनों, निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक पड़नेवाली जमीनों, ऐसी जमीनें जिन पर उनके मालिक खेती न करते हों और इस कारण उन पर समाज का अधिकार हो गया हो, और भूमिहीनों में वाटन के लिए दान में मिली जमीनें शामिल हो सकती हैं। अगर ऐसी अराजियों की चकबन्दी कर दी जाय जो एकदम अलाभकर हो, तो उन्हें भी समाज की जमीनों के संप्रह के साथ या उसके अग्र के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

इससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायतों की स्थापना से पर्याप्त परिणाम प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि इस सस्था पर एक वृहत्तर प्रक्रिया अर्थात् ग्रामीण समाज के भीतर तथा शहरी और ग्रामीण समाजों के बीच, बुनियादी तौर पर सामाजिक और आर्थिक सबंधों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया के अविच्छिन्न अग्र के रूप में विचार किया जाय।

सहकारिता के अर्थ में किसान

भूमि सुधार और भूमि सुधार

श्री हर्षदेव मालवीय

## एक सिंहावलोकन

इस आधुनिक विज्ञान के युग में, ससार का वृहद औद्योगिकरण हो जाने के बाद भी, इसकी अधिकांश जनता अब भी कृषि पर ही आश्रित है। अनुमान लगाया गया है कि लगभग १३० करोड़ व्यक्ति, अर्थात् ससार की जनसंख्या के लगभग ७० प्रतिशत, आज भी किसान हैं। अतः सर्व्व की भांति आज भी ससार की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का ही मूल स्थान है।

अतीतकाल से, जबसे मानव का उद्भव हुआ तबसे ही, भूमि का जोतनेवाला अपने स्वत्वों एवं अधिकारों को प्राप्त करने के लिए सतत् प्रयत्नशील रहा है और बहुधा उसके प्रयत्नों ने हिंसात्मक संघर्ष का रूप भी धारण किया है।

अतीतकाल को छोड़कर भूमि पर सामन्ती स्थिर स्वार्थों के खात्मे का इतिहास, अथवा यों कहिए ससार में भूमि-सुधार का इतिहास, मूलतः निम्न तीन युगों में विभाजित किया जा सकता है

- (१) मध्ययुग से लेकर औद्योगिक युग के प्रारम्भ तक ।
- (२) औद्योगिक क्रान्ति एवं उसके बाद का काल ।
- (३) आधुनिक युग, अर्थात् प्रथम विश्व महायुद्ध के बाद के भूमि-सुधार ।

निम्न पंक्तियों में हम इस बात का प्रयास करेंगे कि पाठकोंके सम्मुख यूरप महाद्वीप में उपर्युक्त प्रथम एवं द्वितीय कालों में भूमि-सुधारों एवं किसान आन्दोलनों को जो प्रगति रही, उसकी संक्षिप्त समीक्षा प्रस्तुत करें।

### मध्ययुगीन ग्राम

मध्ययुगीन यूरप के ग्रामों में ग्राम की आवादी एकत्र होकर एक एक स्थान पर रहा करती थी, परन्तु किसानों की आराजिया चारों तरफ

छिन्तरी होती थी। अतीतकाल के अर्थात् उस कालके जिसको आदिम साम्यवाद का युग कहा गया है, ग्रामों की पंचायती प्रणाली और पारस्परिक सहकारिता के अवशेष खेती-बारी के कामों में दिखाई पड़ते थे। पर जैसे-जैसे सामन्ती शासन दृढ़ हुआ और बलशाली एवं विस्तृत होता गया, वैसे-वैसे उसने ग्रामों की इस पुरातन पंचायती सहकारी व्यवस्था को दबाया। ग्राम्य की सामान्य भूमि पर से किसानों के अधिकारों का तथा ग्रामों की एकता का खात्मा कर वहाँ फूट डाली तथा कृषि के अधिकांश मुनाफों को हड़ पने लगा। यहाँ पर कह दिया जाए कि भारत के ग्रामों की पंचायती व्यवस्था यूरोपीय ग्रामों की पंचायती व्यवस्था से कहीं अधिक प्रबल और शक्तिशाली सिद्ध हुई और अतीतकाल के अलावा सामन्ती युग में भी हमारे किसानों की पारस्परिक सहकारिता और पंच-नरमेश्वर की भावना पूर्ववत् स्थापित रही। गावों के चारागाहों पर और गावों की सामान्य भूमि पर उनके अधिकार स्थापित रहे। वह जंगल से लकड़ियाँ काटकर घर लाते रहे और गावों की सिंचन-मुविवाधों पर भी उनका अधिकार रहा। उसका तो खात्मा वास्तव में ब्रिटिश विदेशी शासकों ने किया। वास्तव में, जैसा कि कार्ल मार्क्स ने और जवाहर लाल नेहरू ने अपनी पुस्तकों में कहा है, अंग्रेजों ने भारत में सबसे बड़ी, जो खराबी कहिए अथवा क्रान्ति कहिए, की वह यही थी कि उन्होंने अति प्राचीन, अति सुदृढ़, अति व्यवस्थित हमारी ग्राम-पंचायती-व्यवस्था को विनष्ट किया। पर वह तो दूसरी ही गाथा है।

पश्चिमी देशों में कबीलों और जातियों का जो प्राचीन संगठन था, वही बाद में ग्रामों की पंचायती-व्यवस्था में परिवर्तित हो गया। यूनानी, वेल्शिय, स्लाव और ट्यूटानिक ग्रामीण प्रथाओं एवं पद्धतियों पर विनोबा-दोव द्वारा जो महान अव्ययन किया गया, उसने निम्न बातें स्पष्ट की

१ कबीलों में एक ही पूर्वज की संतान हुआ करती थी और उनका पारस्परिक रक्त सम्बन्ध ही उनकी अटूट एका का मूल कारण था। और वास्तव में यह कबीले पुरानी जाति प्रथा के ही एक रूप थे। एक ही पूर्वज की सन्तान अपनी सुरक्षा और पारस्परिक सहायता के लिए एक साथ मिलजुल कर दोस्ती करके रहती थी और आपस में उनके विवाह सम्बन्ध भी हो जाया करते थे।

२. इसी रिस्तेदारी के ही आधार पर और सब पड़ोसी किसानों के मंत्री-सम्बन्धों के फलस्वरूप ही उस समय खेतों का विभाजन होता था और कृषि की जाती थी।

३ कबीले जब अपनी खानाबदोशी छोड़कर व्यवस्थित ग्राम-समाजों के रूप में रहने लगे तो उसका कारण यही था कि कुछ दिनों के बाद, जैसे-जैसे कृषि विस्तृत हुई और जनसंख्या बढ़ी और कबीलों में ही घर-गृह-स्थिया और परिवार बनने लगे तो यह आवश्यक हो गया कि विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जोती जानेवाली आराजियों का समानीकरण हो, जिसका मूल तात्पर्य यही था कि किसानों के अधिकारों और कर्तव्यों में एक सतुलन स्थापित किया जाय।

संसार की भूमि व्यवस्थाओं के रूप का घनिष्ठ सम्बन्ध कृषि में लगे श्रम के रूप से रहा है। यथा, सामन्ती युग की खेती और खेती के तरीकों के पूर्व यदि हम, यूरोप से हटकर, और देशों की ओर भी दृष्टिपात करें तो प्रतीत होगा कि तब गुलामी प्रथा ही, और गुलामों का श्रम ही, कृषिका आधार था। वास्तव में गुलाम अथवा दास-युग में दास केवल एक उत्पादक यन्त्र के समान ही समझे जाते थे, जिनका अस्तित्व केवल मालिक की सुविधाओं और कार्यों के लिए ही समझा जाता था, और ऐसे दासों को जो खाना दिया जाता था एवं उनके निवास के लिए जो कुछ भी तथा-फथित प्रबन्ध किया जाता था, वह केवल इसीलिए कि वे जीवित रह सकें और मालिक के लिए परिश्रम कर सकें, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उस समय भी और आज भी मालिक अपने घोड़ों और अपने बैलों को चारा देते हैं और खूटे में बांधते हैं ताकि वे जीवित रहें और हमारे काम आवें। प्रारम्भ में तो यह दास अधिकांशतः वे लोग थे जो विजेता द्वारा दूसरे इलाकों से और पराजित देशों से पकड़कर लाये जानेवाले युद्धबन्दी थे, पर धीरे-धीरे जब मालिक की रियासत में रहते-रहते उन गुलामों की संतान बढ़ी हुई तो उनके साथ मालिक का व्यवहार कुछ-कुछ नरम-सा होने लगा और पूर्णरूप से उनको पहले जैसे यन्त्र समझा जाता था, उसमें कुछ अन्तर हुआ।

### दास प्रथा से अर्द्धदास प्रथा की ओर

शोषित, दलित और पीड़ित दासों ने भी भयकर शोषण से ऊब कर बड़े ही हिंसात्मक और भयकर विद्रोह किए, परन्तु उनके स्वामियों ने सर्वद्वय उनके विद्रोहों को खून की नदियों में वहा दिया। वास्तविकता तो यह है कि संसार के दास-काल में दिव्य के रजतपट पर जो शायं एव त्याग का महान् युद्ध लड़ा गया, उसकी गाथाएं ही लुप्त हैं। सम्भव है, गाथाएं अभी लिखी ही न गई हों, और इस प्रकार आज संसार उस जमाने के कुछ महान्तम स्वातन्त्र्य-संग्रामों के सम्बन्ध में सर्वथा अनभिज्ञ है। जो भी हो,

उस विवरण में जाने का हमारा यहाँ तात्पर्य नहीं है। एक वाक्य में हम केवल यही कहेंगे कि शोषित और पीड़ित दासों के विद्रोहों के फलस्वरूप दास प्रथा बदलकर अर्द्धदास प्रथा में परिणत हुई और दास युग के स्थान पर संसार में सामन्ती युग का प्रादुर्भाव हुआ।।

इस अर्द्धदास को, जिसे अंग्रेजी में 'सर्फ' कहा गया है, अपने स्वामी की रियासत में काम करना पड़ता था और विना स्वामी की आज्ञा के वह रियासत से बाहर नहीं जा सकता था। अब अर्द्धदास के पास निजी खेती के वास्ते नाम मात्र की भूमि भी रहने लगी, पर उसको इस प्रकार भूमि दिये जाने की शर्त यह थी कि वह अपने स्वामी की भूमि पर भी बराबर जाकर परिश्रम करेगा। प्रायः सप्ताह में ३ दिन वह अपनी भूमि पर काम करता था और ३ दिन स्वामी की भूमि पर जाकर काम करता था। इसके बाद एक ऐसी स्थिति आई जिसमें स्वामी अर्द्धदास को भूमि के अलावा कुछ खेती-बारी के साधन भी देने लगा, अर्थात् हल, बैल, लकड़ी, इत्यादि। ऐसे नए काश्तकार निर्धन तो होते ही थे, बहुधा वे अर्द्धदास ही थे, और स्वामी की इस देन के बदले वे केवल अपना श्रम ही दे सकते थे, कारण उनके पास सिवाय निजी श्रम के कोई और दूसरी पूजी न थी। बहुधा स्वामी की पूरी रियासत ही उसकी निजी भूमि और ऐसी अर्द्धदासों की भूमि में वितरित रहा करती थी और यह अर्द्धदास स्वामी की जमीन पर मेहनत करने के अलावा अपनी खेती की पैदावार का भी आधा हिस्सा मालिक को दिया करता था। धीरे-धीरे, जैसे-जैसे अर्द्धदास की स्थिति कुछ सुधरी और वह ऐसी दशा में आया कि अपने हल और बैल रख सके तो स्वामी और कृषक के उपर्युक्त समझौते में कुछ अन्तर हुआ। अब कृषक स्वामी से भूमि निश्चित समझौते के आधार पर प्राप्त करने लगा, जिसके अनुरूप उसे स्वामी को अपनी खेतीकी पैदावार का आधा अथवा तिहाई हिस्सा भी देना पड़ता था। इस प्रथा को फ्रांस में 'मेतिए' प्रथा कहा जाता है और आज भी वह फ्रांस और इटली के दक्षिण भागों में पाई जाती है। यदि पुरानी चली आनेवाली प्रणालियों व रीति-रिवाजों का आदर किया जाता है तो, अन्यथा कानूनी सुविधाओं की रू से ऐसे काश्तकार को मालिक द्वारा मनमाने तरीके से बेदखल नहीं किया जाता। ऐसा काश्तकार प्रायः दुखी नहीं रहता।

### परिवार के खेत

इस प्रकार शर्त शर्त सम्पूर्ण यूरोप में परिवारों द्वारा खेती वहा के कृषि संगठन का सबसे सामान्य रूप हो गया, यद्यपि उसका कुछ परिवर्तित रूप भी, स्थानीय स्थितियों के अनुसार, यदा-कदा पाया जाता था। यहाँ यह कह दिया जाय कि मध्ययुग के सामन्ती संगठन की शक्ति का एक कारण यह भी था कि वह जमाना बड़ा उथल-पुथलवाला था और सामंत की रियासत में जो गरीब काश्तकार रहता था वह यह सोचता था कि यहाँ सामंत बना रहे, दूसरा न आवे, वही हमारे हितों के लिए अच्छा होगा। अर्थात्, उसका दृष्टिकोण उस अंग्रेजी कहावत के अनुरूप था, जिसमें कहा गया है 'जिस दैत्य को तुम जानते हो वह दैत्य उस दैत्य से भला है, जिसे तुम नहीं जानते।' धीरे-धीरे यह अर्द्धदास प्रथा भी

भूमिल अथवा लुप्त होने लगी पर तो भी भूमि का स्वामित्व बड़े-बड़े सामन्ती अमीर-उमराओ के हाथों में ही रहा। कभी-कभी ऐसा भी हुआ कि जब अमीर-उमरा अपनी फिजूलखर्ची अथवा दूसरे कारणों से बरवाद हुए तो उन्होंने अपनी सम्पत्ति को बड़े-बड़े व्यापारियों और महानजनों के यहाँ गिरवी रखकर उनसे उधार लिया। कुछ दिनों के बाद उनकी भूमि की मिलिकयत, उधार न दे पाने पर, उन व्यापारियों के हाथों में पहुँच गई। इस प्रकार मूल ही भूमि का स्वामित्व एक के हाथ से हटकर दूसरे के हाथ में पहुँचा हो, पर वास्तविक खेती करनेवाले वे लोग ही रहे, जिनका जमीन पर कोई भी अधिकार न था। ऐसी स्थिति पहली मर्तवा फ्रांस की सन् १७८६ की ऐतिहासिक महान राज्य क्रान्ति में ही बदली और यूरोप के अन्य देशों में उसके कुछ वाद।

### लगान के रूप

श्रौद्योगिक युग के पूर्व के युग में लगान के निम्न तीन रूप स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं :

१. श्रम द्वारा लगान की अदायगी।
२. जिन्सों में लगान की अदायगी।
३. सिक्कों में लगान की अदायगी।

श्रम द्वारा लगान इस प्रकार अदा किया जाता था कि किसान कुछ समय अपनी निजी भूमि पर कार्य करता था और उसके द्वारा अपनी और अपने परिवार की आवश्यकता पूर्ति करता था और बाकी समय वह स्वामी की भूमि पर काम करता था और उसके द्वारा स्वामी को फायदा होता था।

जिन्सों में लगान की अदायगी सच में श्रम द्वारा अदा किये जानेवाले लगान का ही एक रूप है। इसके अन्तर्गत किसान भूस्वामी को लगान की अदायगी, उसके खेतों पर सीधे-सीधे श्रम करने के वजाय अपने ही खेत पर किये गये श्रम से तैयार होनेवाले सामानों द्वारा करने लगा। कहा जा सकता है कि जिन्सों में अदायगी उत्पादन के साधनों और उच्च विकास-स्तर को व्यक्त करता है, कारण यह इस बात को इंगित करता है कि श्रव अर्द्धदास अपनी अर्द्धदासता से मुक्ति की दिशा की ओर पहुँच गया है और श्रव स्वामी के लिए यह आवश्यक नहीं रहा कि वह अर्द्धदास पर, खेतों पर काम करते समय निगरानी रखे। श्रव किसान अपने खेत पर बिना स्वामी की तेज-तरारि निगाहों के नीचे रहता हुआ स्वच्छन्द रूप से काम कर सकता था।

सिक्कों में लगान की अदायगी जिन्सों में लगान की अदायगी का ही एक बदला हुआ रूप है। यहाँ मालिक को लगान खेत की पैदावार के रूप में नहीं, बरन् एक निश्चित रकम में अदा किया जाता है। स्पष्ट है कि सिक्कों में लगान की अदायगी इस बात को सिद्ध करती है कि काश्तकार के पास कुछ अतिरिक्त अनाज भी बचता है और वह उस अनाज को बाजार में बेचकर कुछ पैसा भी पा जाता है। यह तभी सम्भव हुआ होगा जब समाज में व्यापार बढा होगा और बाजारों में विनिमय सम्बन्ध विकसित हुआ होगा। इस प्रकार सिक्कों में लगान की अदायगी इस बात को स्पष्ट करती है कि सामन्ती प्रथा या, दूसरे शब्दों में, पूँजीवादी युग के

ठीक पहले की लगान प्रथा, नष्ट-भ्रष्ट होने लगी थी। इसी सिक्कों में अदायगी के और अधिक विकसित होने पर किसान सामन्ती दवावों से मुक्त होकर भूमि पर अपना व्यक्तिगत स्वामित्व प्राप्त करता है।

### भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व

सच बात तो यह है कि किसान के व्यक्तित्व का विकास और उसकी परिश्रम-शक्ति और उसकी कृषि-वृद्धि का प्रकाश तब ही सम्भव हुआ जब उसे जमीन पर मिलिकयत प्राप्त हुई और वह स्वच्छन्द रूप से अपने खेत पर खेती करने लगा। जैसा सर्वविदित है, प्रारम्भिक काल में भूमि का उपयोग सामाजिक रूप से ही हुआ करता था। भले ही उस प्रारम्भिक अथवा आदिम साम्यवाद के युग में भूमि का मालिक कबीले का सरगना समझा जाता रहा हो, पर वास्तव में मिलिकयत पूरे समाज की हुआ करती है और खेतों में काम तथा खेतों की पैदावार का हिस्सा बनी-बनाई प्रणालियों और रिवाजों के आधार पर किया जाता था। समाज के किसी भी व्यक्ति को उन रीति-रिवाजों से परे भूमि पर कोई अधिकार नहीं हुआ करता था। उस समय हर नए वर्ष या तो कमीलेवाले एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते थे या उसी भूमि पर नये सिरे से काश्त हुआ करती, जिसके फलस्वरूप यह स्वाभाविक ही था कि किसी भी जमीन के किसी टुकड़े पर कोई स्थायी हित न पैदा होता था। वास्तव में उस समय एक ही कृषक को दूर-दूर हट्टी हुई भूमि की कई पट्टियाँ काश्त के लिए दी जाती थी, जिसके कारण उसका काफी समय एक टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक पहुँचने में ही खर्च हो जाता था। मध्ययुग में पश्चिमी यूरोप में यही स्थिति रही। अतः जब किसी एक व्यक्ति को भूमि की एक ऐसी टुकड़ी मिली जिसपर वह बराबर काबिज रहे तो वही काश्तकार की प्रगति की ओर पहला कदम कहा जा सकता है, और वहाँ से ही अच्छी कृषि की शुरुआत कही जा सकती है।

### फसलों की बदल-बदल कर बोआई

कृषि के विकास में दूसरा बड़ा महत्त्वपूर्ण कदम तब उठाया गया जब कृषकों को अच्छी खेतों के लिए फसलों की बदल-बदल कर बोनो का ज्ञान प्राप्त हुआ। अतीत काल में जब भूमि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी, खेतों का तरीका यही रहा करता था कि एक वर्ष यदि एक टुकड़े पर खेती की जाती है तो दूसरे वर्ष किसी दूसरे टुकड़े पर खेती की जाती थी। जब खानाबदोशी कम हुई और लोग एक स्थान पर रहने लगे तब यह तरीका प्रारम्भ हुआ कि एक वर्ष एक खेत पर फसल बो कर और काट कर दूसरे वर्ष उस खेत को खाली रहने दिया जाता और फिर तीसरे वर्ष उस पर पुनः खेती की जाती। कभी-कभी ऐसा भी होता था कि तीन वर्षों में एक खेत पर एक ही बार फसल उगाई जाती। कहा जाता है कि फसलों की बदल-बदली कर कृषि के उत्पादन को बढ़ानेका तरीका पहली बार कुछ अंग्रेज कृषकों ने १७वीं और १८वीं शताब्दी में ढूँढा था और यह बताया था कि क्रमानुसार अलग-अलग फसलों को बो कर भूमिको स्वस्थ रखा जा सकता है और उर्वरा शक्ति स्थापित रखी जा सकती है। निश्चय ही इस खोज के फलस्वरूप एक ही भूमि से पहले के अनुपात में कहीं अधिक अनाज, उगाया जाने लगा।

## मध्ययुग के कृषक-विद्रोह

ऊपर हमने भूमि पर किसानों को जो कुछ स्वत्व प्राप्त हुए और कृषि में जो विकास हुआ उसका संक्षेप में वर्णन किया है, पर इससे पाठकों को यह भ्रान्त धारणा नहीं होनी चाहिये कि उस काल में किसानों को सब अधिकार प्राप्त हो गए थे और उनके घरों में सुख और चैन की बसी बजने लगी थी। किसी भी ऐतिहासिक समीक्षा में इन बातों की चर्चा आवश्यक है, पर स्मरण रहे कि उस जमाने में भी सामन्तियों के महलों में, धनिकों की गगनचुम्बी अट्टालिकाओं में रास और रंग का वैभव था, मदिरा और कामिनी की अठखेलियाँ होती थी, ऐंशी-इशरत के ठाट थे, दौलत के दस्तरखान विछे रहा करते थे। और उस जमाने के बड़े-बड़े राजाओं, महाराजाओं, अमीर-उमराओं, बड़े-बड़े महन्तों, पादरियों और पोपों तथा शहरो के धनिकों इत्यादि के ठाठ-बाट और रास-रंग किसानों के ही कन्धों पर सम्भले हुए थे, किसानों के ही खून से वे सींचे जाते थे। संक्षेप में केवल यह समझना चाहिये कि सामन्ती युग में कृषक एक बोझा ढोनेवाले जानवर के तुल्य ही थे। उसकी श्रमशक्ति धनवानों की ही एक वस्तु थी, जिसे वे क्रय-विक्रय करते थे। कृषक को मानव नहीं समझा जाता था। उसके साथ हृदयहीन, निरंकुश व्यवहार किया जाता था। अतः आश्चर्य ही क्या कि उनके अन्दर घोर असन्तोष व्याप्त था। प्रतिहिंसा की ज्वाला से वे जला करते थे और तब यदि यदा-कदा कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी एक देश के इस क्षेत्र में और कभी उस क्षेत्र में, उनकी विद्रोहाग्नि ज्वाला के समान घघकी और खून की नदियाँ बही तो आश्चर्य ही क्या ?

सच तो यह है कि ससार के प्रत्येक देश के किसानों की विशेषता रही है कि वे बड़े ही धैर्यवान होते हैं और लम्बे अर्से तक चुपचाप बिना मीन-मेष किए सभी मुसीबतों को बर्दाश्त करते जाते हैं। रहन-सहन की अति कठिन और अवर्णनीय स्थितियों में भी, पुरखों के जमाने से अपमान, अन्याय व अत्याचार को सहते हुए समाज की सभी श्रेणियों के बोझ को अपनी कमजोर पीठ पर ढोते हुए भी वे शताब्दियों तक शांत रहे, आज्ञाकारी बने रहे। पर ऐसे धैर्यवान कृषक समूहों का भी धैर्य-बान्ध कभी-न-कभी टूट ही पड़ा। जब स्थितियाँ उनके बर्दाश्त के बाहर हो गईं तब एक-व-एक, बिना किसी तैयारी के, उनका क्रोध भभका, भयकर रूप से भभका और तब उनके विद्रोहों में प्रलय-काल की विध्वसात्मक शक्ति दिखाई पड़ती थी। इतिहासकारों और राजनीतिज्ञों ने एक-व-एक प्रस्फुटित होनेवाले विद्रोहों की प्रायः ऐसी परिभाषा दी है कि वे ऐसे विद्रोह होते हैं, जिनके अन्तर्गत स्थापित शासन-व्यवस्था एवं शासकों के विरुद्ध जनता में व्याप्त क्रोधाग्नि और घृणा भभक उठती है, परन्तु उनका कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता, उनकी लड़ाई के तौर-तरीके भी निश्चित क्रमानुसार नहीं रहते और न उनका नेतृत्व ही ऐसा होता है जो उनको सजग रूप से विजय की ओर ले जाय। और बहुधा इतिहासकारों ने ऐसे एक-व-एक होनेवाले विद्रोहों को एक अनिवार्य दुर्घा के रूप में स्वीकार किया है, जिसका दायित्व अन्ततोगत्वा स्थापित शासक वर्गों की अमानुषिकता एवं हृदयहीनता के सर पर ही मढ़ा जा सकता है। यूरोपीय देशों में ऐसे किसान विद्रोह, सबसे अधिक

सख्या में और अति व्यापक रूप से, सामन्ती शासनों के अन्तर्गत मध्ययुग में बड़े ही हिंसात्मक और खूखार होते थे। रोम साम्राज्य के पतन के बाद यूरोपीय देशों में जो शासन और व्यवस्था जमी हुई थी, उसका खात्मा हो गया। सर्वत्र अव्यवस्था, अराजकता, हिंसा और पाशविक शक्ति का ही दौर-दौरा हो गया। जो शक्तिवान थे, उन्होंने जो कुछ पाया उसे हस्तगत किया और तब तक उसके स्वामी बने रहे, जब तक कि कोई उनसे भी अधिक शक्तिशाली व्यक्ति ने आकर उनको दबा कर उनकी सम्पत्ति अपने हाथों में ले ली। इस समय सारे यूरप में बड़े-बड़े मजबूत किले बनाए गए और उन किलों के लाटों ने अपनी छोटी-मोटी सैन्य टुकड़ियों का संगठन किया और उनकी सहायता से चारों तरफ देहातों में अपना आतंक जमाया, मनमानी वसूलयाविया की और पास-पड़ोस के अपने ही समान दूसरे किलों के सामन्तों से युद्ध किया। इस अराजकता और हिंसा के दौर में गरीब किसान और निर्धन कृषि मजदूर ही सबसे अधिक पैसे। इसी व्यापक अव्यवस्था, हिंसा और अराजकता से मध्ययुगीन सामन्ती युग पैदा हुआ।

### मध्ययुगीन सामन्ती ढांचा

कृषक उस समय असंगठित थे और उन डाकू लाटों के खिलाफ वे अपनी रक्षा नहीं कर सकते थे। फिर उस समय कोई ऐसी शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार न थी जो कृषकों की सुरक्षा कर सके। अतः मजबूर होकर कृषकों को किले के लाट से समझौते करने पड़े, जिनके फलस्वरूप उनको उसे अपनी पैदावार का कुछ निश्चित अनाज देने के लिए बाध्य होना पड़ा, और दूसरे प्रकार से भी उनकी सेवा करने के लिए वे मजबूर हुए। इसके बदले में किले के लाट ने आश्वासन दिया कि वह उनकी लूट बन्द करा देगा और पास-पड़ोस के किले के सामन्ती लाट की लूट से उनकी रक्षा करेगा। इसी प्रकार छोटी गड्डियों के मालिक पास-पड़ोस के बड़े किलों के लाटों से समझौता करने लगे और उनको यह विश्वास दिलाया कि वक्त पड़ने पर वे बड़े लाट को सैन्य सहायता प्रदान करेंगे और जब कभी जरूरत पड़ेगी उसके पक्ष में युद्ध करेंगे। इस आश्वासन के बदले में बड़े लाट ने छोटी गड्डी के मालिक की रक्षा का वचन दिया। इस प्रकार छोटे लाटों के ऊपर बड़े लाट, उन बड़े लाटों के ऊपर और भी बड़े लाट और नोबलमनों का एक सामन्ती ढाँचा खड़ा हो गया, और इस ढाँचे के सर्वोच्च शिखर पर सम्राट या शाहशाह था, जिसने यह दावा किया कि उसको राज्य करने की दैवी शक्ति सीधे भगवान से प्रदत्त हुई है।

सामन्तों के ऊपर बड़े सामन्त और उन बड़े सामन्तों पर भी और बड़े सामन्तों का जो ढाँचा इस प्रकार बना उसका सुन्दर चित्र सन् १२७६ के एक अंग्रेजी न्यायालय के निम्न वर्णन से पता लगता है "सेंट जर्मेन के रोजर्स को भूमि का एक टुकड़ा ब्रैंडफोर्ड के राबर्ट से इस शर्त पर मिला कि वह उपर्युक्त राबर्ट को तीन पेंस अदा करेगा और छ पेंस रिचर्ड मिलचैस्टर को देगा, जिससे राबर्ट को जमीन मिली हुई है। और इस रिचर्ड को भूमि अलन डी चारट्री से मिली है और उसके लिए रिचर्ड को २ पेंस एक वर्ष में देने पड़ते हैं। फिर इस अलन को जमीन विलियम से मिली है, और इस विलियम को जमीन लार्ड गिलवर्ड डी

नर्वेल से मिली है और इस गिलबर्ड को जमीन लेडी डिवोरगिला दी व लोर्ड से मिली है, और इस डिवोरगिला को भूमि स्काटलैंड के वादशाह से मिली है और स्काटलैंड के वादशाह को यह भूमि इंग्लैंड के वादशाह से प्राप्त हुई है।”

गिरजे घर और पादरी इस सामन्ती प्रथा के आवश्यक अंग थे। उस जमाने में जो बड़े-बड़े ईसाई महन्त और पादरी होते थे, वे स्वयं बड़े-बड़े सामन्त थे। उदाहरणार्थ, जर्मनी में लगभग आधी भूमि और देश की लगभग आधी सम्पदा बड़े-बड़े विशपों और एवटी के हाथों में थी। पोप स्वयं बहुत बड़ा सामन्त हुआ करता था। इस प्रकार यह पूरी व्यवस्था श्रेणियों और ऊँचे दर्जों और ऊपर के दर्जों में विभक्त थी। इस ढङ्ग की सबसे निचली सीढी पर अर्द्धदास थे, और इन दु खितों की पीठ पर ही सारे सामाजिक ढाँचे का, छोटे और बड़े लाटो का, राजाओं और सम्राटों का और गिरजेघरों के पूरे ढङ्ग का बोझ था। ये बड़े-बड़े लाट और नवाब कोई भी लाभप्रद उत्पादक कार्य नहीं करते थे। उनका काम केवल एक दूसरे से युद्ध करना और बड़े-बड़े शिकार खेलना और खूब रास-रग में मस्त रहना होता था। ये बेचारे कृषक और दस्तकार ही थे जो अनाज उत्पादन करते थे और जीवन की अन्य आवश्यकताओं को भी पैदा करते थे।

### “सब्र भूमि सामन्ती लाट की”

इस काल में लगभग १० शताब्दी पूर्व, यूरप की जनसंख्या कम थी और बड़े-बड़े भूस्वामी भूमि-मजदूरों को जबरदस्ती अपनी जमीन पर बाध कर रखते थे। उस समय भूमि का मूल्य नहीं था, मूल्य था मनुष्य का जो भूमि को जोतता था। उस जमाने के भूमि-बन्दोवस्त के जो कुछ कागजात मिलते हैं, उनमें भूमि का क्षेत्रफल बड़े ही मोटे ढंग से इंगित किया गया दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ, किसी की भूमि का क्षेत्र इस प्रकार बताया गया है—अमुक नदी से अमुक पहाड़ी तक। पर इसके विपरीत, प्रत्येक भूमि-सम्पत्ति के अन्तर्गत प्रत्येक कृषक और दस्तकार का और उनकी दक्षता का विस्तृत वर्णन मिलता है। यह भी उन वर्णनों में सूक्ष्म रूप से दिखाया गया है कि अमुक व्यक्ति किस काम को करने योग्य है और यह भी विशेष रूप से बताया गया है कि वह अपने मालिक के लिए साल में क्या-क्या काम करेगा। ऐसे अनोखे भूमि-बन्दोवस्त के कारण स्पष्ट है। उस समय भूमि पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। खतरा रहता था कि अर्द्ध दास अपने स्वामी की भूमि से विलग होकर कहीं अन्यत्र जाकर भूमि को जोतने-बोने लगे और भूस्वामी की सम्पत्ति में एक मनुष्य कम हो जाये। इस खतरे से बचने के लिए उस समय यह घोषित कर दिया गया था कि सम्पूर्ण भूमि सम्पत्तिवान लाटो की है। वास्तव में उस समय सामन्ती का एक निहित मन्त्र था, वह लैटिन भाषा का था जिसका अनुवाद हो सकता है—“सब्र भूमि सामन्ती लाट की।”

कायदे से, सरकारी नियमों के अनुसार, लाटो का यह कर्तव्य था कि वे अपने अर्द्धदासों और चाकरो की रक्षा करें। पर वास्तविक जीवन में यह नियम ताक पर ही रखे रहते थे और सदा लाटों की मनमानी ही चला करती थी। सम्राट लोग कभी भी अपने अन्तर्गत सामन्तों की कार्य-

वाहियोंको नहीं देखा करते थे, और किसान स्वयं इतने दुर्बल और सकट-प्रस्त थे कि उनके पास सामन्तों की मनमानी के समक्ष झुकने के अलावा दूसरा कोई चारा न था। बेचारे अर्द्धदासों को अपने दकियानूसी कृषि यन्त्रों द्वारा सामन्तों की निजी भूमि पर जाकर काश्त ही नहीं करनी पड़ती थी, अपितु उन्हें सामन्तों और गिरजेघरों को अपनी निजी खेती की पैदावार का काफी बड़ा हिस्सा देना पड़ता था। वास्तव में सारी सामन्ती-समाज व्यवस्था ही व्यक्तिगत चाकरी तथा भूमि से कृषक के व्यक्तिगत लगाव पर ही आधारित थी। किसान तो सच पूछिये, भूमि से ही नया हुआ एक जीवात्मा था, उसीका एक अविभाज्य अंग था। गिरजेघर और सामन्ती लाट उस समय बड़े ही शक्तिशाली थे और वे जो चाहते मनमाना किसानों से वसूल करते थे, और उसके पास केवल इतना ही छोड़ते थे, जिससे वह वमुश्किल तमाम अपने अति दु खित अस्तित्व को स्थापित रख पाता था। सच पूछा जाय तो भूमि स्वामियों का यह क्रम सर्वत्र, सभी देशों में रहा है।

इस प्रकार प्रत्यक्ष हो जाता है कि उस समय की सामन्ती व्यवस्था में समानता अथवा स्वतन्त्रता के विचारों तक का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था। शासक सामन्तवर्ग केवल अपने अधिकारों और शोषित किसानों के दायित्वों को ही जानता था। सामन्ती लाट किसानों से मुफ्त सेवा तथा किसान के उत्पादन का कुछ भाग पाना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझता था तथा इसके बदले में उन किसानों की रक्षा करना उनका दायित्व माना गया था। पर वास्तविक जीवन में सामन्त अपना यह उत्तरदायित्व भुला ही देते थे, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमारे देश में भी जमीन्दार अपनी रकम वसूल करने में तो बहुत कठोर रहे हैं, पर किसानों के प्रति अपने दायित्वों को बड़ी सरलता से भुला देना उनके लिए मामूली सी बात रही है। अतः जनता परेशान थी और उसे अपनी आपत्तियों से छुटकारा पाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखाई पड़ता था। इनके जीवन का आवार ही था आशाशून्य श्रम-जीवन भर आशाशून्य श्रम। रोमन कैथलिक पादरी वर्ग भी सामन्ती लाटों के ही चट्टे-बट्टे थे और घर्मभीरु कृषकों के मस्तिष्क में बराबर यह विचार भरते रहते थे कि सामन्तों की सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना ही उनका चरम कर्तव्य है। लाटों के विशाल और भव्य दुर्गों की चारों ओर अर्द्धदासों की मिट्टी तथा लकड़ी की शोपडिया होती थी, और यह निरीह मानव इन लाटों की दृष्टि में पशुओं से केवल कुछ मात्रा में ही ऊपर थे।

### विनिमय तथा व्यापार के विकास का क्रान्तिकारी प्रभाव

परन्तु तेरहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में एक परिवर्तन आया। विनिमय तथा व्यापार के जन्म तथा विकास के फलस्वरूप सामन्ती व्यवस्था के अन्तर्गत स्थापित सम्बन्धों तथा समाज के नव विकसित आर्थिक आवारों के बीच विरोध होना स्वाभाविक था। उस समय लाटों तथा उनके अर्द्धदासों के अलावा शिल्पकारों तथा व्यापारियों का एक नया वर्ग समाज में बलशाली होने लगा। यह नया वर्ग सामन्ती व्यवस्था का निहित अंग न था, वरन् उसके विरोध में, उसके वावजूद पैदा हुआ और बढ़ा था। अराजकता एवं अशान्ति के समय तो व्यापार को बहुत ही कम, तथा



दस्तकारी को तो प्रगति करने का बिल्कुल ही अवसर नहीं रहता था। परन्तु ज्यों ही गुलामों के विद्रोहों के खतम होने के बाद कानून तथा व्यवस्था की स्थापना हुई और सामन्ती प्रथा जमी, वैसे ही व्यापार ने उन्नति की, जिसके परिणामस्वरूप व्यापारियों तथा दस्तकारों का भी महत्त्व बढ़ा। अब वे धनवान् हो गए तथा सामन्ती लाट व अमीर-उमरा तक्ष रूपया उधार लेने के लिए उनके पास जाने लगे। वे धन तो उधार देते ही थे, साथ ही बदले में कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त कर लेते, जिसका परिणाम यह हुआ कि वे शर्त शर्त और अधिक शक्तिशाली होने लगे। व्यापारियों तथा शिल्पियों ने मिल कर श्रमों अथवा समुदायों का सगठन प्रारम्भ किया तथा जहाँ इनके मुख्य कार्यालय होते थे वहाँ श्रम-भवनो अथवा नगर-भवनो का भी विकास होता गया। यह भवन धीरे-धीरे निकटस्थ सामन्ती लाट की गद्दी या किले द्वारा प्रतिबिम्बित एकक्षत्र निरकुश सत्ता को चुनौती देने लगे।

व्यापार की इस उन्नति तथा विनिमय-प्रणाली के इस विकास के कारण, सामन्ती लाटों तथा उनके अर्द्धदासों के पारस्परिक सम्बन्धों में भी परिवर्तन आया। जब तक कृषक के उत्पादन का उपभोग भूस्वामियों तथा उनके आश्रितों एव गुणों तक ही सीमित रहा, उस समय तक सामन्ती शोषण की सीमा भी, तुलनात्मक रूप से, सकुचित आर्थिक दायरों तक ही सीमित थी। यह तो स्पष्ट अर्थहीन होता कि सामन्ती लाट अपने कृषकों से अपने उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं से अधिक ले लेते। परन्तु विनिमय-प्रणाली के जन्म के साथ-ही-साथ यह सीमा समाप्त हो गई, कारण अब कृषि उत्पादन के बदले सामन्ती लाट किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकता था। अतः अब लाट ने किसान से उसके श्रम के उत्पादन का अधिक-से-अधिक भाग नीचना प्रारम्भ कर दिया। अर्द्धदासों की अवस्था और भी बदतर होने लगी। कृषकों के लिए सचमुच सामन्ती जुए का भार असह्य हो चला।

### जब फट्ट एवं शोषण का धक्का लावा ज्वालामुखी बन फटा

अब १३४८ में यूरोप में प्लेग की जो भयंकर महामारी फैली, उसने स्थिति को चरम सीमा पर पहुँचा दिया। महामारी ने अपनी भयावनी भुजाओं में लघु एशिया (एशिया माइनर) से लेकर इंग्लैंड तक सम्पूर्ण यूरोप को दबोच लिया। लाखों लाख मानव काल के कराल गाल में चले गए और सही ही इसे इतिहास में 'काली मृत्यु' के नाम से पुकारा गया है। इस भयंकर दुर्घटना के कारण जनसंख्या बहुत घट गई और हालत यहाँ तक पहुँची कि भूमि जोतने के लिए पर्याप्त आदमियों का मिलना भी कठिन हो गया। मनुष्यों की कमी के कारण श्रमिकों की मजदूरी अपनी बहुत नीची सतह से अब ऊपर उठनी प्रारम्भ हो गई। पर शासनयन्त्र तो भूपतियों तथा धनिकों के हाथों में था, और उन्होंने ऐसे नियम बनाये, जिनमें कृषकों को अपने-उनी पुराने कष्टपूर्ण स्तर पर कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ा। अन्ततोगत्वा कष्ट एव शोषण का धक्का लावा ज्वालामुखी के रूप में फट ही तो पड़ा। किमान अपनी युगो-युगो पुरानी जमीनों को जोतने के लिए उठ खड़े हुए। कभी यहाँ और कभी वहाँ उनके विद्रोहों की ज्वाला गहना, बिना किसी पूर्व तैयारी के, पर घोर हिंसक रूप में

जल उठने लगी। तेरहवीं शताब्दी से लेकर १६वीं शताब्दी तक इस प्रकार सहसा फूट पड़नेवाले हिंसात्मक किसान विद्रोहों की एक श्रृंखला-सी यूरोप में, विशेषतया पश्चिमी यूरोप में, दिखाई पड़ती है। बराबर इन विद्रोहों को प्रबल पार्श्विक शक्ति द्वारा कुचला गया, उन्हें खून की नदियों में डुबो दिया गया, फिर भी, बार-बार वे और अधिक शक्ति से, और भी हिंसात्मक रूप में उभरे।

इन विद्रोहों का अधिकतर स्थानीय रूप हुआ करता था। केवल जर्मनी में १६वीं शताब्दी में तथा महान फ्रांसीसी क्रान्ति के अवसर पर फ्रांस में, इन क्रान्तियों ने अति व्यापक राष्ट्रीय क्रान्ति का रूप धारण किया। फ्रांस को छोड़ कर और कहीं भी इन क्रान्तियों को कोई उल्लेखनीय सफलता नहीं प्राप्त हुई, और अधिकांशतः वे असफल ही रही। अधिक-से-अधिक यह हुआ कि विद्रोहों को कुचलने के बाद सामन्ती शासकों ने कुछ ऐसे न्यूनतम सुधार किये या ऐसी न्यूनतम सुविधाएँ प्रदान की, जो देश के कानूनों पर और सरकार पर किसानों का पुनः विश्वास करने के लिए निश्चिन्त रूप से आवश्यक समझी गई। पर मूलतः ऐसी प्रत्येक क्रान्ति के पश्चात् किसानों के भयंकर कष्टों और दुःखों में वृद्धि ही होती थी, कारण विद्रोहों के फलस्वरूप सामन्ती लाटों तथा उनके किलों को होनेवाली गहरी क्षति की पूर्ति के लिए मुआवजा कृषकों से ही, उनके करों को बहुत ही अधिक बढ़ा कर वसूल किया जाता था। विद्रोहों के पश्चात् और इन निर्दयों प्रहारों के बाद भी जो किसी भाँति जीवित रह सके, उनमें कटुता, क्रोध व प्रतिहिंसा की ज्वाला धधकती रही, वह अमिट बन गई। सच तो यह है कि जिस प्रकार गुलामों के भयंकर विद्रोहों ने यूरोप की दास प्रथा को खोखला बना कर अन्ततोगत्वा उसे समाप्त किया, उसी प्रकार इन व्यापक कृषक-विद्रोहों ने सामन्ती प्रथा की नींव को खोखला कर दिया। वास्तव में बहुत से यूरोपीय देशों से सामन्ती व्यवस्था के अन्त होने का श्रेय बड़ी सीमा तक इन्हीं विद्रोहों को दिया जायगा।

जैसा ऊपर कहा गया है, तमाम पश्चिमी यूरोप में एक के बाद दूसरी ऐसी किसान-क्रान्तियाँ हुईं। १३५६ में इटली में 'डलसिनो विद्रोह' और १३५८ में फ्रांस में 'जैक्वेरी विद्रोह' हुआ। इंग्लैंड में १३८१ में 'वैट टायलर विद्रोह' हुआ जिसके दमन के बाद इंग्लैंड के तत्कालीन बादशाह के सम्मुख टायलर को मृत्यु के घाट उतारा गया। इसी प्रकार १४३७ में हंगरी में 'जान बाडीशी विद्रोह' और १५५४ में 'सियोगी डोररा' विद्रोह हुआ।

### सोलहवीं शताब्दी का जर्मन कृषक युद्ध

यह तमाम जो कृषक विद्रोह थे सो तो थे ही, उनका सबसे अधिक भयानक, हिंसात्मक व रक्तितम रूप सन् १५२५ के लगभग जर्मनी में देखा गया। वास्तव में जर्मन कृषकों के इस विद्रोह ने एक विराट किसान युद्ध का रूप धारण कर लिया और इतिहास में वह जर्मन कृषक युद्ध के नाम से ही प्रसिद्ध है। चौदहवीं व पंद्रहवीं शताब्दी में जर्मनी में मशीन उद्योगों का जो विकास हुआ, तथा व्यापार की जो उन्नति हुई और नए व्यापारी वर्ग का व नगरों का जो उदय हुआ तथा अन्य अनेक कारणों से भी मध्य-युगीन समय से चले आनेवाले वर्गों की स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया। अतः १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जर्मनी की स्थिति कुछ बदली

हुई सी ही थी। पुराने वर्गों के अलावा नए वर्गों का भी जन्म हो चुका था। जर्मनी में कृषक-युद्ध की प्रचण्डता को समझने के लिए इन नयी श्रेणियों की स्थिति का सक्षिप्त वर्णन आवश्यक है। पुराने सामन्ती लाटो नोबलमैनो में से ही जर्मन प्रिन्सो का (जिन्हें नोबलमैनो से कही अधिक शक्तिशाली सामन्त कह सकते हैं—प्रिन्स का हिन्दी अनुवाद राजकुमार है पर उन्हें नए जर्मन राजकुमार कहना शुद्ध न होगा) उदय हो चुका था। यह जर्मन प्रिन्स जर्मन सम्राट के अन्तर्गत नहीं थे, वरन् स्वतंत्र थे, अपने छोटे-छोटे राज्यों में सम्पूर्ण सत्ता उन्हीं के हाथों में थी। वे सेना रखते थे, कर लगाते थे तथा युद्धो एव सधियों की घोषणा करते थे। अपने-अपने शासन-क्षेत्रों में उनका शासन पूर्णतः निरकुश होता था। जैसे-जैसे इन जर्मन प्रिन्सो की विलासप्रियता बढ़ी, और उनके राज दर-वारो, उनकी सेनाओ और उनके शासन का आकार विस्तृत हुआ, वैसे-ही-वैसे उनको धन, और अधिक धन की जरूरत होने लगी। अतः अन्धा-धुन्ध नए कर किसानो पर लगाए जाने लगे और निर्दयता से उनकी वसूल-यावी की जाने लगी। इन नए करो से नए पैदा होनेवाले नगरो और उनमें रहनेवाले व्यापारी लोग बच गए, कारण उनके पास धन की शक्ति थी, वे वैसे भी शक्तिवान हो गए थे और कुछ विशेषाधिकार प्राप्त कर चुके थे, और उन्होने सामन्ती लाटो व अमीर-उमराओ को रूपया भी उधार दिया था।

अतः करो का पूरा भार उन किसानो पर पड़ा जो सीधे इन जर्मन प्रिन्सो के आधीन थे। इस समय तक, मध्ययुग के प्रारम्भिक काल में जो अमीर-उमरा और लाट थे वे पूर्णतः अपनी पुरानी स्वतन्त्रता खो चुके थे और इन प्रिन्सो को अपना स्वामी मान चुके थे। इनके करका बोझ भी अर्द्धदासो पर ही पड़ा। कह दिया जाय कि मध्ययुग के प्रारम्भिक काल में जो सामन्ती लाट और अमीर-उमरा थे, उनमें सोलहवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक, जर्मन प्रिन्सो के शक्तिशाली होने के दौरान में ही, गहरी तब्दीलिया हो चुकी थी। वे या तो बड़े-बड़े कर स्वतंत्र प्रिन्स हो गए थे अथवा नीचे गिर कर निम्न स्तर के नोबलमैन मात्र रह गए थे। उनका दिवाला खिसक चुका था, उनके पास धन नहीं रह गया था, वे प्रिन्सो की सेवा और खुशामद पर ही आश्रित रहने लगे तथा धीरे-धीरे मृतप्राय होते जा रहे थे। जब प्रत्यक्ष करो से जर्मन प्रिन्सो की धन की क्षुधा तृप्त न हुई तब उन्होने अप्रत्यक्ष कर लगाना प्रारम्भ कर दिया। कर उगाहने के लिए सब तिकडमो का सहारा लिया गया और वित्तीय क्रमो की किसी भी चालवाजी को न छोड़ी गयी। प्रचलित मुद्राओ की भयकर फेराफेरी की गई। जितना चाहा, जैसा चाहा, वैसा मुद्राओ का अवमूल्यन किया गया तथा स्वैच्छापूर्वक, प्रिन्सो के हितानुसार, मुद्रा-चलन की सीमा का ऊंचा व नीचा स्तर निर्धारित किया गया। धन, और अधिक धन की लालसा में जो कुछ भी तत्कालीन न्याय-व्यवस्था थी, वह भी म्रष्ट बना दी गई, उसे भी न्याय का एक मुख्य तथा स्थायी साधन बना दिया गया। न्याय वस्तुतः विकने लगा और न्यायाधीशो व अन्य अदालती व्यक्तियो ने भी अपनी जेब खूब गर्म किए।

फिर, केवल जर्मन प्रिन्सो की लूट से ही जर्मनी का किसान नहीं कुचला जा रहा था। हमने ऊपर कहा है कि पुराने सामन्ती लाट व अमीर-उमरा

वुरी अवस्था को प्राप्त हो गए थे, परन्तु इसका अर्थ तुलनात्मक रूप में ही लिया जाना चाहिये। वे निम्न स्तर के नोबलमैन के दर्जे को अवश्य पहुँच गए थे, पर हाथी दुबलाएगा तो ऊट ही तो होगा वाली लोकोक्ति के अनुसार अपनी-अपनी गडियो और किलो में अब भी वे जबरजग घन्ना-सेठ बने थे, और वहा उनका विलासपूर्ण जीवन पहले जैसा ही चलता था। उनके किलो में होनेवाली बडी ही खर्चीली खिलाडियोकी प्रतियोगिता, उनके अधिक रूपये खानेवाले वृहद आखेट अभी भी केवल पूर्ववत् स्थापित ही न थे, वरन् पहले से भी अधिक बड़े और खर्चीले हो गए थे। पर उनकी आय घट गई थी, आय प्राप्त करने के उनके साधन, उनका क्षेत्र और उनकी शक्ति सकुचित हो गई थी। अतः इन्ही सकुचित साधनो और क्षेत्रो से ही वे अपना पूरा खर्च पूरा करने का प्रयास करते थे। अतः किसानो एव अर्द्धदासो की रक्त का आखिरी वृन्द तक चूसने में कोई कमी न उठा रखी गई।

किसानो की लूट-खसोट वर्ष-प्रति-वर्ष तीव्रतम होती गई। अर्द्धदासो का रक्त शोषण होते-होते वह सूखने लगे। हर मूमकिन मौके पर सामन्त अनेकानेक प्रकार का बोझ किसानो पर लादते रहे और उनसे तरह-तरह की नई रकम उगाहते थे। पुराने सब सम्झौतो को भग कर अर्द्धदासो से मुफ्त श्रम तो करवाया ही जाता रहा, उसके साथ तरह-तरह के और कर जैसे मृत्यु कर, भूमि कर, भूमि उत्पादन कर, सुरक्षा प्रदान करने का कर इत्यादि, वसूल किये जाते रहे।

### जर्मनी के पादरियो और गिरजाघरो का सामन्ती ढांचा

फिर पादरियो और गिरजाघरो के मठाधीशो का भी एक शक्ति-शाली शोषक वर्ग था। गिरजे के बड़े-बड़े पदाधिकारी जैसे विशप, आर्क विशप, एबट, फायर और टूमरे प्रेलेट, ये सब अपने किसानों तथा अर्द्ध-दासो और अन्य व्यक्तियो का न केवल उतना ही भयकर शोषण करते थे जितना कि बड़े-बड़े सामन्ती अमीर-उमरा और सरदार लोग करते थे वरन् उनका शोषण और भी वीभत्स और शर्मनाक हुआ करता था। पाश-विक शक्ति का प्रयोग तो वे करते ही थे, पर उसके साथ ही तमाम धार्मिक पाखण्डो का भी वे प्रचुर मात्रा में प्रयोग कर अपने आसामियो से धन खसोटते थे—उदाहरणार्थ, किसानो को धमकी दी जाती थी कि अगर वे पैसा नहीं अदा करेंगे तो उन्हें पदच्युत कर दिया जायगा व मरते समय ईसाई धर्म के अनुसार आखिरी प्रार्थना करने के लिए उनके पास पादरी नहीं जाएंगे। वास्तव में पादरियो ने उस समय धर्म को धन उगाहने के लिए एक व्यवसाय-सा बना लिया था जनता से अधिकाधिक रकम निचो-डने के लिए गिरजाघरो के पादरियो ने दस्तावेजो की जानसाजी शुरू की, सतो की ऐसी मूर्च्छिया बना कर बेचनी शुरू की, जिनके बारे में यह धारणा चलाई गई कि वे जादू-मन्तर कर सकती है, तांत्रिज बना कर बेचनी शुरू की, पापोसे मुक्ति पाने के लिये बने-बनाये क्षमापत्र अच्छी रकम लेकर देने लगे और इस प्रकार अन्य अनेक हथकंडे चलाने लगे।

गिरजाघरो और पादरियो के इस ढङ्ढे के शिखर पर पोप प्रतिष्ठित था। बड़े-बड़े सामन्ती अमीर-उमराओ के शिखर पर जो स्थिति और

प्रभुता तत्कालीन सम्राटो की हुआ करती थी, गिरजेधरो और पादरियों के ढड़ढे के शिखर पर वही स्थान पोप का होता था। सम्राट को सामन्तो से साम्राज्यी कर मिला करता था, उसी प्रकार पोप को भी तमाम गिरजेधरो से कर पहुँचाया जाता था। इस प्रकार पोप के पास जो अतुलित धन पहुँचता था, उसके आधार पर वह अपने रोमन दरवार की बड़ी जवरदस्त शान-शौकत और ऐशो-इशरत कायम रखता था। जर्मनी में गिरजाधरो की शक्ति बहुत प्रबल थी और वहाँ पादरियों की सख्या भी बहुत अधिक थी। इसी कारण वहाँ पोप को दिये जानेवाले करो की वसूलयाबी किसी और देश से अधिक कड़ाई से की जाती थी। जैसे-जैसे पोप के दरवार से धन की माग बढ़ती गई वैसे-ही-वैसे जर्मनी से वहाँ के किसानो से अधिकाधिक रकम वसूल कर रोम पहुँचायी जाने लगी। इन सब बातों के कारण किसानो में पादरियों के खिलाफ भयकर घृणा और क्रोध व्याप्त हो गया।

### जर्मन कृषको के भयंकर शोषण का एक चित्र

कई और कारणों से भी किसानो की दशा खराब होती रही, जैसे सामन्ती अमीर-उमराओ में वक्तन-फवक्तन चलनेवाले छोटे-मोटे युद्ध, फिर कभी यदा-कदा किसी सामन्ती उमरा और सम्राट के बीच छोटे-मोटे युद्ध, इत्यादि। इसीके साथ देश की अर्थ-अवस्था पर शहरो में पैदा होनेवाले नए पूजीपति वर्ग का, व्यापारियों और व्यवसायियों का प्रभाव भी बढ़ने लगा और वे भी प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसानो के शोषण के भागीदार बनने लगे।

इस प्रकार राष्ट्र के बहुसंख्यक शोषित कृषक, समाज के अन्य सब वर्गों का बोझ अपनी पीठ पर ढोने लगे। उनकी पीठ पर सामन्ती अमीर-उमराओ का, सरकारी अफसरो का, नौबलमैनो का, पादरियों का और रईसो का बोझ आ पडा, बहुत कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार भारतीय कृषक सदियों तक समाज के सब ही शोषक वर्गों का बोझ अपनी पीठ पर ढोता रहा। कार्लमार्क्स के सुप्रसिद्ध सहयोगी फ्रैंडरिक एन्जिल्स ने अपनी पुस्तक 'दी पीजेन्ट वार इन जर्मनी' (जर्मन कृषक युद्ध) में जर्मनीके महान् किसान विद्रोह के पूर्व वहाँ की स्थिति का वर्णन निम्न शब्दों में किया है

“किसान चाहे किसी सामन्ती अमीर-उमरा का आसामी रहा हो या चाहे सम्राट के किमी निकट सम्बन्धी बड़े भूपति का आसामी रहा हो, चाहे वह किसी मठ के अन्तर्गत रहा हो और चाहे किसी शहरो रईस के यहा, सर्वत्र उससे बोझा ढोनेवाले जानवर से भी बदतर व्यवहार किया जाना था। यदि वह अर्द्ध दास था तो वह पूर्णरूप से अपने स्वामी की दया पर आश्रित था। यदि वह इस शर्त पर भूमि को पाए हुए थे कि उसे कुछ निश्चित कर, जिन्तो में या नकद, अदा करना होगा तो यह निश्चित था कि वह समझौता ऐसा होता था जो उसको कुचल देने के लिए काफी था, और तिगपर उनमें उत्तरोत्तर इजाफा होता रहता था। अविफास तन्मय तो गिनान को अपने स्वामी के खेतों पर ही काम करना पडता था। न्यामी के खेतों पर काम करने के बाद जो कुछ घंटों की फुरमत उसे मिलनी थी और जिनमें वह अपने निजी खेतों पर काम करता था, उससे उमरा जो प्राप्त होनी थी, उनमें से उसे सम्राट का कर, पोप का कर,

युद्ध कर, भूमि कर तथा अनेको और कर अदा करने पडते थे ; अपने मालिक को कर दिए बिना न तो वह विवाह ही कर सकता था और न वह मर ही सकता था। अपने मालिक के खेतों पर और अपने खेतों पर काम करने के अलावा उसे मालिक के लिए वागानो से फलो को तोडना पडता था, शख बिनना पडता था, मालिक के शिकार के समय उसे शिकारी जानवरो को हाकना पडता था, जगलो से मालिक के लिए लकडी काटनी पडती थी, इत्यादि। इस जमाने में मछली मारने का अधिकार और शिकार खेलने का अधिकार सामन्तो को ही हुआ करता था। बहुधा शिकार खेलने में मस्त स्वामी किसान की खडी फसलो को ही अपने घोड़े दौडा कर बिनष्ट कर दिया करते थे। प्राय सभी ग्रामों में जो सामान्य उपयोग के बागीचे व वन थे वे सब ही स्वामियों ने जवरदस्ती अपने अधिकार में ले लिए थे। जिस प्रकार सामन्ती स्वामी का पूर्ण प्रभाव कृषक की सम्पदा पर हुआ करता था, उसी प्रकार स्वामी कृषक के व्यक्तित्व पर, और उसकी स्त्री और बच्चों के व्यक्तित्व पर भी अपना अधिकार चलाता था। उसे प्रथम रात्रि का अधिकार प्राप्त था। जब कभी उसे मौज हो जाती, वह किसान को गढी के भयंकर कारगार में डलवा देता, जहाँ बेचारे किसान की शामत आती और उसकी वहाँ मौत भी हो जाया करती थी। जब कभी स्वामी की इच्छा होती तब वह किसान को मरवा डालता अथवा उसका सिर उसके घड से अलग करवा देता।”

इसी पुस्तक में एन्जिल्स ने आगे मध्ययुग में प्रचलित 'कैरोलीना' नामक एक कानूनी नियमो की पुस्तक की चर्चा की है। कहा जाता है कि यह १६वीं शताब्दी में सन् १५३२ में, सम्राट चार्ल्स प्रथम द्वारा प्रकाशित करवाई गई थी और बाद में वह सम्राट चार्ल्स प्रथम और पवित्र रोमन साम्राज्य के जाव्ता फौजदारी कानून के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। वह किसी-न-किसी रूप में १५वीं शताब्दी में थी, और उसके पहले भी, विद्यमान थी, परन्तु सन् १५३२ में उसका और नियमित संस्करण छापा गया। उसमें अभियुक्तो को यातना देकर उनकी परीक्षा करना जायज कहा गया था। इस कानून की बड़ी अहमियत १८वीं शताब्दी तक बनी रही।

एन्जिल्स ने कहा है “कैरोलीना” के प्राय सभी शिक्षाप्रद अध्यायो पर, जैसे कान का काटना, नाक का काटना, अन्धा कर देना, अंगुलियों का काट देना, सिर से घड अलग कर देना, पहियों के नीचे कुचल देना, जला देना, जलते लोहे से दाग देना, इत्यादि सभी पर सामन्ती-उमरा महोदय अपनी खुशी और रहमान के मुताबिक अमल किया करते थे। विरला ही कोई अध्याय वे अमल रह जाता होगा, और बेचारे किसान को कौन रक्षा करता ? अदालतो का प्रबन्ध बड़े रईसों, पादरियों, शहर के धनिकों और न्यायशास्त्रियों के हाथों में था, और वे बखूबी जानते थे कि उनको किस बात के लिए तनह्दाह मिलती थी।”

### मार्टिन लूथर और मुएनशर

इस प्रकार किसानों में असतोषकी ज्वाला विस्फोट की स्थिति पर पहुँच गई। इस अन्तर पर महान् प्रोटेस्टेन्ट ईसाई नेता मार्टिन लूथर ने अपने माथियों के साथ रोम की पोपशाही का विरोध किया। पोप की निरकुशता के इस विरोध में उसे रोमन कैथोलिक गिरजाधरो से बँसे

ही भीषण रूप से त्रसित किसानों के विशाल समूहों से बड़ा समर्थन प्राप्त हुआ। बाद में जब किसान हिंसा पर उतर आए और बड़े-बड़े सामन्ती लाटों के महलों को जलाने लगे और हत्या करने लगे, तब मार्टिन लूथर किसानों का विरोधी हो गया। पर टामस मुएनशर नामक एक दूसरे पादरी ने किसानों के विद्रोह का नेतृत्व किया। आश्चर्यजनक उत्साह और क्षमता के साथ उस व्यक्ति ने किसानों का संगठन किया और किसानों के विद्रोह को व्यापक बनाया। उस समय उसने जो पत्र इधर-उधर भेजे और उसने जो धार्मिक व्याख्यान दिए, उनमें अनोखी प्रकार की क्रान्तिकारी आग धक्कती दिखाई पड़ती थी। अनवरत रूप से उसने शासक वर्गों के विरुद्ध घृणा की अग्नि प्रज्वलित की। बाद में वह गिरफ्तार किया गया और उसका सर घड़ से अलग कर दिया गया। जिस समय उसे फासी हुई, उसकी अवस्था केवल २८ वर्ष की ही थी और अपनी मृत्यु का सामना भी उसने उस वीरता से किया जिस वीरता से वह किसानों के क्रान्तिकारी आन्दोलन का नेतृत्व करता था।

जिस वक्त से मार्टिन लूथर ने रोमन कैथलिक पादरी डब्लू के विरुद्ध अपनी घोषणा की, तब से ही जर्मनी में सभी विरोधी शक्तियों ने बल प्राप्त किया और तब से कोई ऐसा वर्ष नहीं बीता, जब जर्मनी का कृषक अपनी मांगों को बुलन्द करता हुआ आगे न आया हो। उन्होंने अपनी १६ मांगें रखी और उनकी पूर्ति चाहने लगे। यह मांगें, यदि सच पूछा जाय तो कोई भी ऊँची मांगें नहीं थीं, वरन् छोटी मांगें ही थीं। उदाहरणार्थ, वे चाहते थे कि सामन्तों को कही भी शिकार खेलने का अधिकार समाप्त हो जाए, अर्द्धदास प्रथा समाप्त हो जाए, अत्यधिक करों को खतम किया जाए, मालिकों के निरकुश अधिकारों में कमी की जाए, जवरियन नाजायज गिरफ्तारियों से उनकी सुरक्षा की जाय और सामन्तों का पक्षपात करने वाली अदालतों से भी उनको बचाया जाए। वस ये उनकी मांगें थीं। सन् १५१८ से १५२३ के बीच जर्मनी के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों का विद्रोह होता रहा, कभी वहाँ के ब्लैक फारेस्ट में, तो कभी अपर साइलेशिया में। १५२४ में इधर-उधर छितरे हुए विद्रोहों ने एक नियमित रूप अस्तित्वार कर लिया। वास्तव में इसी वर्ष को महान जर्मन कृषक युद्ध की शुरुआत का वर्ष कहा जा सकता है।

### जर्मन कृषक-विद्रोह का दमन

पर अति शक्तिवान नौवलमैनो और पादरियों और बड़े-बड़े सामन्तों के लिए उन किसानों के विद्रोहों को कुचल देना कठिन न हुआ। बड़ी ही निर्दयता के साथ जर्मनी के किसानों का यह विद्रोह कुचल दिया गया। सभी जगह किसान पुन पादरियों, नौवलमैनो और अन्य सामन्तों के दबाव में आ गए। यदा-कदा विद्रोही किसानों के साथ सामन्तों ने जो कुछ तयाकथित समझौते किये भी थे, उनको भंग किया गया। असह्य किसानों को पुन अर्द्धदास बनाया गया और ग्रामीण समाज के कब्जे के विशाल भूमिक्षेत्र जप्त कर लिए गए। इस प्रकार जो अव्यवस्था चली और असह्य किसान जब इस प्रकार नष्ट हुए तो बहुत बड़ी संख्या में जर्मनी के किसान खानाबदोशों की तरह इधर-से-उधर घूमने लगे। किसानों पर जो बोझ था वह और भी गहरा इस कारण हो गया कि

विजेता सामन्तों ने उनसे बड़ी निर्दयता के साथ हर्जाना वसूल करना शुरू किया।

स्मरण रहे कि पादरी वर्ग ही जर्मनी का सबसे बड़ा भू-स्वामी था, और 'जर्मन कृषक-युद्ध' से सबसे अधिक नुकसान उनको ही हुआ। उनके बड़े-बड़े मुन्दर मठ और उनकी जायदादें जला दी गईं, धूल-धूसरित हो गईं। इन मठों के बड़े-बड़े मूल्यवान सामानों की चोरी हो गई। उन्हें विदेशों में बेच दिया गया अथवा उन्हें गला कर छिपा लिया गया। उनके गोदामों के सामानों को लूट कर बांट दिया गया। पादरियों के पास अपनी सुरक्षा के लिए ऐसी कोई विशाल और वृहद् पलटनें तो थी नहीं, और उनके पास किसानों के विद्रोहों को तत्काल दबा देने के लिए आवश्यक अस्त्र-शस्त्र तो थे नहीं, अतः किसानों के सचित शोध एव घृणा का सबसे गहरा और भीषण प्रहार गिरजेधरो पर ही पड़ा। नौवलमैनो की भी गहरी क्षति हुई। उनकी अघिकाश गडिया, किले और महल नष्ट कर दिये गए। कुछ बड़े ही प्रतिष्ठित सामन्तों के खानदान विल्कुल वरवाद और तहस-नहस हो गए और उनको अपने जीवन-यापन के लिए अन्य सामन्तों के यहाँ नोकरी करनी पड़ी। वास्तव में कुछ बड़े सामन्तों और बड़े प्रिंसों की पलटनों ने ही किसानों को कुचला और दबाया। इस प्रकार ससार के एक सबसे खूबार और खूनी किसान विद्रोह का खात्मा हुआ।

### मार्टिन लूथर द्वारा कृषक विद्रोह का विरोध

हमने ऊपर कहा है कि पोपशाही और रोमन कैथलिक गिरजेधरो के विरुद्ध मार्टिन लूथर ने जो आन्दोलन उठाया वही जर्मनी में किसानों के विद्रोह के लिए हरी झंडी का काम कर गया। उन विद्रोहों ने मार्टिन लूथर और प्रोटेस्टेन्टों को भी बड़ी सहायता दी। मार्टिन लूथर के पहले भी कुछ धर्म-सुधारकों ने, उदाहरणार्थ, इग्लैन्ड के वाइकिलफ ने, तथा कुछ अन्य व्यक्तियों ने रोम की पोपशाही के विरुद्ध आवाज ही नहीं उठाई, वरन् नौवलमैनो के खिलाफ किसानों के आन्दोलनों को बढ़ावा दिया। मार्को की बात यह है कि प्रारम्भ में विद्रोही सिद्धान्तों का प्रचार करने के बाद भी मार्टिन लूथर को शासन वर्गों का समर्थन प्राप्त होता रहा। उसका कारण यह था कि मार्टिन लूथर ने बड़ी होशियारी के साथ जर्मनी के सामन्तों को यह सुझाया कि यदि विदेशों (अर्थात् पोप और रोम के गिरजा) का प्रभाव समाप्त हो गया तो उसके बाद जर्मनी के नौवलमैन जर्मनी-स्थित गिरजों की भूमि और खजानों को हस्तगत कर लेंगे। जहाँ तक किसानों की यह मांग थी कि अर्द्धदास-प्रथा समाप्त हो, उसके सत्रव में मार्टिन लूथर ने कहा, "इस मांग के स्वीकृत हो जाने से सभी मनुष्य समान हो जाएंगे और उसके फलस्वरूप प्रभु ईशु की कल्पना का आध्यात्मिक राज्य, बाहरी, दुनियावी, भौतिक राज्य ही जायगा, यह असम्भव है। सांसारिक राज्य तो बिना असमानता के रह ही नहीं सकते। वहाँ तो कुछ को स्वतंत्र होना पड़ेगा, कुछ को अर्द्धदास होना पड़ेगा, कुछको शासक होना होगा और कुछ को शासित होना होगा।" वास्तव में लूथर तो इससे भी आगे गया। उसने किसानों को शाय तक दिया और उनको विद्वन्स करने की मांग तक की। उसने कहा, "अतः यह जरूरी है कि जो लोग शक्तिवान हैं वे किसानों को काटे, उनको मारें और उनको छुरी भोंकें,

चाहे खुले में चाहे छिपे रूप से, और सब इसको याद रखें कि विद्रोह से बढकर जहरीली, घृणित और भयकर वस्तु कोई दूसरी नहीं होती। आप उसको उस रूप से मारिए जैसे आप एक पागल कुत्ते को मारते हैं। यदि आप उसको नहीं मारते तो निश्चय ही वह आपको मारेगा और सारे देश को मारेगा।” और अन्त में लूथर ने नोबलमैनो और सामन्तो को यह आश्वासन दिया कि “यदि इस युद्ध में तुम मारे गए तो निश्चय ही तुम्हें बचाई मिलेगी, कारण इससे और मुन्दर मृत्यु दूसरी नहीं हो सकती।”

### सामन्तवाद से पूंजीवाद की ओर

इस प्रकार यद्यपि किसानो का विद्रोह कुचल दिया गया तब भी असंतोष और विद्रोहाग्नि धीरे-धीरे सुलगती रही। यह अग्नि १६वीं और १७वीं शताब्दी में तो सुलगी ही, उनका चरम परिपाक सन् १७७६ की महान फ्रांसीसी क्रान्ति में हुआ। इस प्रकार सामन्तशाही का जो ढाचा अपने अन्दर यूरप को बन्द किए हुए था, टूटने लगा। इसी मध्ययुग में कोलम्बस और वासकोडिगामा ने अमरीका और भारत के समुद्री रास्तो को ढूँढ कर, अपनी ऐतिहासिक खोजो के द्वारा जो महान कार्य किया, उसने भी इस सामन्तशाही के विघटन के क्रम में अपना बड़ा योग प्रदान किया। स्पेन और पुर्तगाल को जो अतुलित सम्पदा अमरीका से और पूर्व से प्राप्त हुई, उससे सारा यूरप चकाचौध हो गया और उसके कारण यूरपमें परिवर्तन-क्रम तेज हो उठा। ससार में व्यापार बढाने की और दूसरे देशो को गुलाम बनाने की बड़ी सम्भावनाएँ यूरोपीयो पर प्रकट हुईं। शहरो में उस समय जो मध्यम वर्ग था, वह धनवान् होता जा रहा था। व्यापारियो और पूजीपतियो की जो नई श्रेणी उस समय खडी हो रही थी, वह और भी शक्तिशाली हुई। धीरे-धीरे इस नए उभडते हुए वर्ग ने यह महसूस किया कि यूरप में स्थापित सामन्ती ढाचा व्यापार एव समृद्धि के विकास में एक गहरा रोडा है। सामन्तवाद स्पष्टतः प्रगति विरोधी और समय से पिछडा हुआ प्रतीत होने लगा। वास्तव में सामन्तवादी ढाचा किसानो के हृदयहीन, शर्मनाक शोषण पर, जबरियन बेगार पर और अनेकानेक प्रकार के नाजायज करो और वसूलवादियो पर निर्भर था, और तिसपर से मजा यह कि इन सब कार्यवाहियो के अन्तिम भाग्य-विधाता वे ही सामन्ती लाट थे जो स्वयं इन अमानुषिक कृत्यों द्वारा गुलछरें उडाया करते थे। अतः किसानोके विद्रोह हुए, और उनके युद्ध फँले तथा व्यापक हुए, अधिकाधिक होने लगे और उसीके साथ यूरप के विभिन्न भागोमें जो आर्थिक तब्दालिया हुईं, उनके फलस्वरूप सामन्ती ढाचा तहसनहम हो गया और यूरप पर नए मध्यम वर्ग का, या यो कहिए कि नए पूजीपति वर्ग का आधिपत्य स्थापित हुआ। निश्चय ही इस आधिपत्य की स्थापना में उन महान कृषि-क्रान्तियो का बड़ा हाथ था।

एक बार जब समाज में पूंजीवादी पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित हुआ, बडा और विकसित हुआ तब यह देखा गया कि यदि कृषक का भूमि से पूर्णस्वेषण लगाव बना रह गया और कृषक यदि भूमि से अलग न किया गया तो यह नव-विकसित उत्पादक साधनोके विकास में रोडा हो जाएगा। फलस्वरूप धीरे-धीरे एक के बाद दूसरे देश में किसानो का भूमिसामियों पर आश्रित रहना और भूमि से विनानो के बंधे रहने के क्रम का खात्मा

होना स्वभाविक है। पर इस नए क्रमानुसार किसान आर्थिक एव राज-नैतिक रूप से वहा ही स्वतन्त्र हुए, जहा पर सामन्ती अधिनायकवाद के खात्मे के साथ-ही-साथ बडी-बडी सामन्ती रियासतो को भी जन्त कर लिया गया अथवा उनको तोड कर उनके अर्गत भूमि का वितरण किया गया। सन् १७७६ की महान् फ्रांसीसी क्रान्ति में ऐसा ही हुआ, जिसके फलस्वरूप फ्रांस का किसान स्वतन्त्र हुआ।

### महान फ्रांसीसी क्रान्ति

महान फ्रांसीसी क्रान्ति के समय किसानो की आर्थिक दशा का और देश के कानूनो में उनकी स्थिति का सक्षेप में हम इस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। कुछ जिलो में अमीर-उमरा और पादरी कुल जोती हुई भूमि के ५१ प्रतिशत तक के मालिक थे। कुछ अन्य स्थानो पर उनकी मिल्कियत केवल १३ प्रतिशत ही थी। किसान जोती हुई भूमि के केवल २० से ६० प्रतिशत तक के मालिक थे। अतः किसानो में भूमि के लिए स्वभावतः भूख थी। ग्रामीण जनसख्या का एक काफी बडा भाग भूमिरहित था। कुछ स्थानो पर ऐसे लोगो की सख्या कुल आबादी की लगभग ८६ प्रतिशत थी। लिअन्स में लगभग ४५ प्रतिशत किसानो के पास आधा एकड या इससे भी कम भूमि थी। ब्रिटानी में लगभग ४६ प्रतिशत किसान घरानो में प्रत्येक घराने के पास केवल २ हेक्टेयर (१ हेक्टेयर लगभग २.६ एकड) भूमि थी।

अतः जब किसानो के पास पर्याप्त भूमि नहीं थी तो उन्हें अत्यधिक दरो पर जमीन्दारों से लगान पर भूमि लेना पडता था। इस प्रकार उनको जो भूमि मिली, यदि उसके मालिक में उसका बँटवारा हुआ अथवा खान्दान के बडे की मृत्यु के बाद वह भूमि सन्तानो को मिली तो उसके लिए भी एक कर देना पडता था। मडी में बेचने के लिये अनाज ले जाने के वास्ते भी उसे चुगी देनी पडती थी। किसानो के लिए स्वामियो की चक्की में आटा पिसवाना आवश्यक था। अदालतें पूर्णतया सामन्ती लाटो के हाथो में थी। शिकार खेलने का एक मात्र उन्ही को अधिकार था। फसल इकट्ठी होने से पूर्व भी गिरजे के अबवाब के रूप में उन्हें एक विशेष कर देना पडता था। इनके अलावा राज्य द्वारा किसानों से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एकत्र किये जानेवाले करो का भी बडा गहरा बोझा था। प्रत्येक कर ही किसान की कुल आय का ५० प्रतिशत खा जाते थे। प्रत्येक किसान को सडक बनाने या मरम्मत करने के लिए अनिवार्य रूप से साल में १२ दिन देने पडते थे।

ऐसी दशा में आश्चर्य ही क्या कि फ्रांस में भिखारियो की सख्या १२ लाख थी और दुर्दिनो में लगभग एक चौथाई जनसख्या भोख माग कर निवाह करती थी।

ऐसी दुर्दशा में किसान अपना असन्तोष प्रकट करने लगे। उन्होने माग को कि —

- (१) बेगार बन्द हो।
- (२) करो में कमी हो तथा उन्हें समान रूप से लगाया जाय।
- (३) अबवाब खत्म हो।
- (४) ग्रामो के सामान्य उपयोग की जितनी भूमि पर जमीन्दारो ने कब्जा कर लिया था, वह जमीन वे छोड दें, इत्यादि।

एलिजाबेथ प्रथम (१६०२ ईसवी) के राज्यकाल तक इंग्लैंड का कोई महत्त्व नहीं था। वहाँ की जनसंख्या ६ लाख से अधिक नहीं थी जो आजकल लन्दन की आवादी से भी बहुत कम थी। आरम्भ से ही इंग्लैंड के सामन्तो ने बादशाह की शक्ति को सीमित रखने की कोशिशें कीं। १२१५में ही वहाँ मैग्नाकार्टा नामका सुप्रसिद्ध अधिकार-पत्र स्वीकार किया गया, जिसके कारण अठारहवीं शताब्दी तक जर्मनी में कैरोलिना विमान के अन्तर्गत जो पाशाविक दमन होता रहा वह न हो पाया। कुछ काल बाद हमें इंग्लैंड में संसद की उत्पत्ति होती हुई दिखाई पड़ती है। बड़े-बड़े दिग्गज अमीर-उमराओं और पादरियों का हाऊस आफ्लार्ड्स बन गया, और उनके छोटे दर्जे के सामन्तो को चुनी हुई परिषद हाऊस आफ कामन्स में परिणत हो गई। दोनों सदनों के सदस्य मूलतः धनाढ्य भूपति और अमीर व्यापारी थे। परन्तु उस समय संसद बहुत दुर्बल थी। बादशाह ही, विशेषरूप से ट्यूडर वंश के बादशाह, निरंकुश शासक हुआ करते थे। संसद को केवल इतनी ही शक्ति प्राप्त थी कि वह जनता पर लगाये जाने वाले करों में कुछ दखलन्दाजी कर सकती थी। बिना संसद की आज्ञा के न तो नये कर लगाये जा सकते थे और न इकट्ठे किये जा सकते थे और इसलिए ही बादशाह को नए कर सम्बन्धी प्रस्तावों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिये संसद को बुलाना पड़ता था।

साम्राज्यी एलिजाबेथ के शासन काल में अमरीका और पूर्वीय देशों में जाने के समुद्री मार्ग ढूँढे गए और व्यापार के नए अवसर प्राप्त हुए, जिनसे आकर्षित होकर देश के लोग उन दिशाओं में जाने लगे। फल-स्वरूप व्यापारियों का एक नया, उन्नति करता हुआ वर्ग पैदा हो गया। एलिजाबेथ के बाद स्कॉटलैंड का बादशाह जेम्स प्रथम राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ, और उसके बाद उसका लडका चार्ल्स प्रथम १६२५ में गद्दी पर बैठा। जेम्स प्रथम का विश्वास था कि बादशाहों को शासन करने का ईश्वर प्रदत्त अधिकार प्राप्त है और उसने संसद की जरा भी परवाह नहीं की। उसके लडके ने भी वही क्रम अपनाया। अतः बादशाह और संसद में झगड़े बढने लगे, और यह झगड़े सन् १६२८ में बहुत गम्भीर हो गए जब संसद ने अपना सुप्रसिद्ध 'अधिकार-प्रार्थनापत्र' पेश किया। इस प्रार्थनापत्र में बादशाह को कहा गया कि वह निरंकुश शासक कदापि नहीं है और उसे मनमाने तरीके से कर लगाने का अथवा लोगों को जेल भेजने का अधिकार नहीं है। इस प्रार्थनापत्र से क्रुद्ध होकर चार्ल्स प्रथम ने संसद को भग कर दिया और कई वर्षों तक बिना संसद के शासन चलाता रहा। पर कुछ वर्षों के बाद जब उसे पैसे की तंगी हुई तो उसने पुनः दूसरी संसद बुलाई। उस समय चार्ल्स प्रथम की हरकतों से देश में बड़ा भयंकर अप-तोष व्याप्त हो गया था और जो नए सदस्य एकत्र हुए, वे बड़े क्रोध में थे और लडके के लिए उतावले हो रहे थे। अतः सन् १६४२ में इंग्लैंड में बादशाह और संसद के बीच सुप्रसिद्ध गृहयुद्ध आरम्भ हुआ। बादशाह के पीछे अमीर-उमरा और नोबलमैन थे और फौज का भी बड़ा हिस्सा उसके साथ था। संसद के पीछे नए घनों व्यापारियों की शक्ति थी और लंदन शहर भी संसद के ही पीछे था। अन्ततोगत्वा आलिबर क्रामवेल के नेतृत्व में सन् १६४६ में संसद की विजय हुई। यद्यपि ब्रिटिश संसद के

उच्च सदन, हाऊस आफ लार्ड्स ने एतराज किया तो भी हाऊस आफ कामन्स के सदस्यों ने आलिबर क्रामवेल के नेतृत्व में चार्ल्स प्रथम पर "आततायी, गद्दार, हत्यारा और देश का दुश्मन" होने के आरोप में मुकदमा चलाया। उसे फासी की सजा दी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया गया। अब इंग्लैंड बिना किसी बादशाह के हो गया, और 'लार्ड प्रोटेक्टर' की पदवी अस्तित्वात् कर क्रामवेल ने देश का शासन चलाया। १६५८ में क्रामवेल की मृत्यु हो गई और तब चार्ल्स प्रथम के लडके चार्ल्स द्वितीय को गद्दी पर बैठाया गया और इस प्रकार इंग्लैंड में पुनः अमीर-उमराओं की प्रथा जीवित हो गई। पर यह अमीर-उमरा उर्ध्वरूढ़ क्रान्ति के बाद कभी भी अपनी पुरानी शक्ति नहीं प्राप्त कर सके, ब्रिटिश संसद की शक्ति दिनोदिन बढती ही गई, ब्रिटेन के शासन पर उसका अधिकार उत्तरोत्तर प्रबल होता गया, और अन्ततोगत्वा ब्रिटेन का बादशाह महज एक सविधानीय चिह्नस्वरूप ही रह गया।

### अंग्रेजी और फ्रान्सीसी क्रान्ति का एक मौलिक अन्तर

ब्रिटेन को यह स्थिति यूरोप महाद्वीप के अन्य देशों की स्थिति से सर्वथा विभिन्न थी। यूरोप महाद्वीप के देशों में बादशाह इसके लिए भी निरंकुश शासक और आततायी बने रहे और बाद की शताब्दियों में भी किसानों का भयंकर शोषण होता रहा। इंगलिस्तान में बादशाहों की निरंकुशता समाप्त हो जाने का एक सीधा फल तो यह हुआ कि वहाँ के किसानों का शोषण उस स्तर पर या उसके निकट भी नहीं पहुँचा, जिस स्तर पर यूरोपीय किसानों का शोषण होता रहा। निश्चय ही किसानों के भयंकर शोषण के फलस्वरूप विद्रोहाग्नि यूरोपीय देशों में सुलगती रही और उसकी चरम सीमा ब्रिटेन की क्रान्ति के एक शताब्दी के बाद फ्रांस में देखी गयी, जहाँ पर फ्रांस के सम्राट को भी गिलोटिन द्वारा मौत के घाट उतारा गया। पर यहाँ एक अत्यावश्यक बात हमें नहीं भूलनी चाहिये। इंग्लैंड और फ्रांस की इन क्रान्तियों में एक मौलिक अन्तर देखा गया। फ्रांस में नए उभरनेवाले पूँजीपति वर्ग का सामन्ती प्रथा पर और अमीर-उमराओं पर एक भयंकर सहारकारी प्रहार कर उनका खात्मा करना पड़ा, कारण उस देश के सामन्त और अमीर-उमरा फ्रांस के उत्पादन-साधनों के विकास के रास्ते में गहरे रोड़े बन गए और उन्होंने नए उभरे पूँजीपतियों से किसी भी प्रकार का समझौता करने से इन्कार कर दिया। इसके विपरीत इंग्लैंड में चार्ल्स प्रथम के कत्ल के बाद वहाँ अमीर-उमराओं ने अपने में समयानुसार परिवर्तन किया। नयी स्थिति के अनुरूप उन्होंने अपने को बदला और उसके फलस्वरूप इंग्लैंड में पुराने सामन्तो और नए पूँजीपतियों में पारस्परिक सम्बन्ध मृदुल हुए और दोनों एक दूसरे की दिक्कतों को समझते हुए आगे बढ़े। यद्यपि यह निर्विवाद है कि इंग्लैंड की नयी व्यवस्था में नए पूँजीपतियों का ही हाथ ऊपर था। इस नयी व्यवस्था में लंदन नगर के व्यापारी बड़े-बड़े भूपति बन सकते थे और बने और बड़े-बड़े सामन्त और भूपति व्यापार में हिस्सा लेने लगे।

इंग्लैंड की क्रान्ति ने अमीर-उमराओं और किसानों के बीच का तनाव बहुत हद तक खत्म किया, फिर भी सामन्तो को काफी

विशेषाधिकार प्राप्त रहे। निश्चय ही ससद अब ब्रिटेन में सार्वभौम हो गई थी, परन्तु हाऊस आफ कामस के सदस्य ऊँचे वर्गवाले ही होते थे, जो या तो बड़े-बड़े व्यापारी थे या बड़े भूस्वामी थे। ब्रिटेन की बहुत थोड़ी जनता को मताधिकार प्राप्त था और बहुत से तो ऐसे चुनाव क्षेत्र थे, जिन्हें 'जेवी चुनाव क्षेत्र' कहा जाता था। प्रसिद्ध है कि सन् १७६३ में हाऊस आफ कामस के ३०६ सदस्यों को कुल १६० व्यक्तियों ने चुना था। पर इसी समय एक तरफ तो इंग्लिस्तान में उद्योगों का वृहद विकास प्रारम्भ हुआ और दूसरी तरफ अमरीका में और भारत में अपने साम्राज्य-विस्तार के सिलसिले में ब्रिटेन नई इलाकों में फसा, और इन सब बातों में अंग्रेज मस्तिष्क व्यस्त रहा तथा उपर्युक्त अनीतिसंगत बातों की ओर उसका ध्यान नहीं गया। वैसे जब कभी समाज में तनातनी कुछ प्रबल होती थी तो तुरन्त शासक वर्ग कोई-न-कोई समझौता कर लिया करते, जिससे तनातनी खत्म हो जाती थी और अव्यवस्था एव हिंसा का खतरा खत्म हो जाता था। वास्तव में ब्रिटेन के शासक वर्गों, और शासक वर्ग ही क्या, समस्त ब्रिटिश जनता के चरित्र की यह बड़ी विशेषता रही है कि वे अन्ततोगत्वा जो होनी होने की होती है, और जो पराजित न हो सकनेवाली शक्तियाँ उनके विरोध में प्रबल हो जाती हैं, उनके आगे वह तुरन्त सिर झुका देते हैं और समझौता कर लेते हैं। इतिहास सदैव अंग्रेजों की इस विशेषता को देखता आया है। यह विशेषता ही इस विचित्र बात का कारण है कि जहाँ एक तरफ ब्रिटेन आज ससार के सामने परम्परागत रूप से जनतन्त्रवादी देश के रूप में सामने आता है, वहीं दूसरी तरफ वहाँ आज भी जमींदारी प्रथा स्थापित है, बड़े-बड़े भूस्वामी और लाट और नोबलमैन आज भी वहाँ पाये जाते हैं, बड़े-बड़े पूँजीपतियों के साथ उनका घनिष्ठ सम्बन्ध है, और उनका आज भी काफी राजनीतिक प्रभाव है लगभग १०० वर्ष पूर्व सुप्रसिद्ध ब्रिटिश राजनीतिज्ञ ग्लेडस्टन ने कहा था "हाऊस आफ कामस तो वास्तव में हाऊस आफ लार्ड्स है।" सन् १९३६ में ब्रिटेन में एक बड़ी प्रसिद्ध पुस्तिका प्रकाशित हुई, जिसका नाम था "टोरी एम० पी०"। इस पुस्तिका में ब्रिटेन के अनुदार दल के सदस्यों की सामाजिक स्थिति और उनकी राजनीतिक विशेषता का विवेचन है। इसमें लेखक ने बड़े ही सुन्दर ढंग से यह सावित किया है कि अनुदार दल पर कुछ पीछे से ब्रिटिश खानदानों का प्रभाव है, जिनमें से अधिकांश बड़े-बड़े भूपति और अमीर-उमरा हैं। सुप्रसिद्ध स्वर्गीय प्रो० हैरल्ड लास्की ने अपनी पुस्तिका १८०१ से १९२४ के बीच ब्रिटिश मन्त्रिमंडलों के व्यक्तित्व में दिखलाया है कि १९०६ से लेकर १९१५ के दस वर्षों में ब्रिटिश मन्त्रिमंडलों के कुल ५१ मन्त्रियों में २५ बड़े अमीर-उमरा और सामन्त थे।

वाम्त्व में इस शताब्दी के प्रथम २५ वर्षों के बाद ब्रिटेन में जो मजदूर दल का प्रभाव बढ़ा तथा चुनावों में विजयी होकर मजदूरदलीय सरकारें बनने लगीं तो उसका कारण यही बताया गया कि अब ब्रिटिश जनता राजनीति जाग्रत हो गई है कि वह नहीं चाहती कि देश की राजनीतिक सत्ता कुछ ऐसे बड़े मान्दानों और अमीर-उमराओं के हाथों में रहे, जो वास्तव

में ब्रिटेन में बहुत थोड़े हैं और जिनके रहन-सहन का तरीका और क्रम ब्रिटेन की विशाल जनता के सर्वथा विभिन्न है।

### सामन्त विरोधी संघर्ष के तीन मुख्य अध्याय

जैसा कि सभी जानते हैं, कि इंग्लैंड एक ऐसा देश है, जहाँ सबसे पहले औद्योगिक विकास प्रारम्भ हुआ और जहाँ धीरे-धीरे कृषि का स्थान गीण होता गया। वहाँ के सामाजिक सम्बन्धों के विकास की जो विशेषता रही और जिस प्रकार वहाँ के शासक वर्ग ने अपने को समयानुसार परिवर्तित किया, उसी कारण से ही वहाँ सन् १६४२ की क्रान्ति के बाद कभी भी अशान्ति-अव्यवस्था, खून-खराबी और हिंसा नहीं हुई, यद्यपि यह बातें प्रायः अन्य सब ही यूरोपीय देशों में दृष्टिगोचर होती हैं। तथापि इतिहास की अनवरत प्रगति ने इंग्लैंड को, जैसे अन्य देशों को भी, अछूता नहीं छोड़ा। सामन्ती ढाँचे के अन्तर्गत एक मध्यम वर्ग सब जगह उभरा और जैसे-जैसे व्यापार का विकास हुआ, वैसे-वैसे यह नया उभरा मध्यम वर्ग शक्तिशाली होता गया। धीरे-धीरे यह मध्यम वर्ग सामन्ती शासकों से, अमीर-उमराओं से और बादशाहों से संघर्ष में आया और उसने अशान्ति की अग्नि में जलनेवाले असह्य किसानों का नेतृत्व किया। इस नए वर्ग ने सामन्ती ढाँचे के विरुद्ध जो लम्बी लड़ाई लड़ी उसके इतिहास में तीन निर्णायक अध्याय कहे जा सकते हैं। प्रथम, प्रोटेस्टेन्टों के नेतृत्व में रोमन कैथलिक गिरजेधरों और पोपशाही के विरुद्ध विद्रोह हुआ। दूसरे, इंग्लिस्तान की शानदार क्रान्ति, और तीसरे, फ्रांस की महान क्रान्ति। महान फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद यूरोप में और सारे ससार में सामन्तवाद का प्रभुत्व समाप्त-सा हो गया और सामन्ती प्रभाव ससार में घटने लगा। उसके स्थान पर नयी पूँजीवादी सभ्यता आई, जो वस्तुओं के स्वतन्त्र व्यापार पर आधारित थी, जिसमें उत्पादन के तरीके बहुत विकसित थे और जिसका मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना था। यह पूँजीवादी प्रथा के नाम से ससार में प्रसिद्ध हुई। इस प्रथा ने किसी समय ससार में बड़ा प्रगतिशील कार्य किया, परन्तु कालान्तर में यह प्रथा भी शोषक और गलित सिद्ध हुई और आज इसके भी खात्म के दिन आ गए हैं। अस्तु।

यद्यपि यह सत्य है कि महान फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद ससार के सामाजिक सगठन में सामन्ती प्रथा का महत्त्व बहुत कम हो गया, और धीरे-धीरे पुराने जमाने के अमीर-उमरा और नवाब और लाट और उनकी बड़ी-बड़ी सुरक्षित गढ़ियाँ और महल लुप्तप्राय हो गए, तथापि यह भी निर्विवाद है कि जहाँ कहीं सामन्तशाही के खात्म के साथ जमीन्दारी प्रथा का भी खात्मा नहीं किया गया, वहाँ पर राजनीतिक सत्ता बहुत कुछ भूस्वामियों और जमीन्दारों के हाथों में ही रही। यह बात आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़े देशों के लिए विशेष रूप से सत्य है। उन देशों में कृषि ही आवादी की अपार सख्या के जीवन-यापन का साधन थी। अतः आश्चर्य ही क्या कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर बड़े-बड़े भूस्वामियों का ही प्रभुत्व निर्णायक बना रहा, और ऐसे देश अन्ततोगत्वा प्रतिक्रियावादी गढ़ सिद्ध हुए। जहाँ सामन्तों की शक्ति का खात्मा होने के साथ ही जमीन्दारी प्रथा का खात्मा नहीं हुआ, वहाँ एक अदृश्य रूप

से बड़े-बड़े सामन्ती लाटो और अमीर-उमराओं तथा नए उभरे पूजीवादी धनपतियों में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो गया, और इस वर्ग से ही राज-दरबारों के बड़े-बड़े अधिकारी, राज्य मंत्री, बड़े-बड़े फौजी जनरल और सरकारी नौकरियों में ये बड़े-बड़े अफसर होने लगे। देहातो में स्थानीय अधिकारी और पुलिस और स्कूलों के अध्यापक इत्यादि भी भूस्वामियों की ही सहायता करते रहे। सारांश यह कि समाज के अन्दर जो भी व्यक्ति किसी जिम्मेदार शासकीय पद पर रहे, वे सब-के-सब या तो भूस्वामियों के वर्ग से घनिष्ठ रूप से सम्बन्धित थे अथवा उन पर आश्रित थे। ऐसी स्थितियों में जो जनतान्त्रिक अधिकार नए सविधानों के अन्तर्गत जनता को प्रदत्त किए गए, वे बहुत हद तक कागजी ही बने रहे। कई देशों में बालिग मताधिकार सविधान द्वारा तो स्वीकार हो गया, परन्तु एक तो ग्रामीण जनता अशिक्षित और पिछड़ी थी और दूसरे प्रशासनिक ढांचे में पुराने शासक वर्गों का प्रभाव वदस्तूर कायम था। अतः उन नए अधिकारों का लाभ गरीब जनता न उठा सकी। ऐसे स्थानों पर कृषकों और कृषि-मजदूरों को उसी प्रकार अपना मत प्रदान करने पर बाध्य होना पड़ता था, जैसा उनके भूस्वामी चाहते थे। यह बातें उदाहरणार्थ इटली, एशिया, पोलैन्ड, हंगरी, रूमानिया और सब से ऊपर जारशाही जमाने के रूस के लिए सत्य रही।

### यूरोपीय भूमि-प्रश्न के विकास के दो निश्चित सुझाव

इस कारण से ही हम यह देखते हैं कि यूरोप के भूमि सम्बन्धी प्रश्नों में दो निश्चित रुझान दिखाई पड़ते हैं। पश्चिमी यूरोप की औद्योगिक क्रान्ति द्वारा पैदा हुई स्थितियों के प्रभाव से और एक नये शक्तिशाली पूजीपति वर्ग के उद्भव के फलस्वरूप कृषि उत्तरोत्तर व्यापारिक दायरे के अन्तर्गत आने लगी और उसका आधुनिकीकरण होने लगा। भूमि पर सामन्ती तथा अन्य स्थिर स्वार्थों के खत्म किये जाने का यह एक अवश्य-म्भावी नतीजा था। पर स्मरण रहे कि इस क्रम से इंग्लैंड और जर्मनी की दशा कुछ विभिन्न-सी रही। इंगलिस्तान में वशानुगत रूप से जायदाद की प्राप्ति के सिलसिले के कानून से कोई भी दखलअन्दाजी न की गई। वहां पर कोई सामाजिक क्रान्ति भी न हुई और वहां की अधिकांश भूमि बड़ी-बड़ी रियासतों के कब्जे में ही बनी रही, जिन पर बड़े-बड़े लाटो और नोबलमैनो का अधिकार स्थापित रहा। ऐसी रियासती भूमि विभिन्न-विभिन्न आकार के खेतों में विभाजित कर दी गयी और उन्हें नकद लगान पर किसानों को उठा दिया गया। पर यहा यह कह देना चाहिये कि ब्रिटेन में जिस प्रकार की खेती अब प्रमुख हुई वह किसान परिवारों को लगान कर उठाये जानेवाले वह छोटे-छोटे खेत न थे जिनसे सम्भवतः परिवारों की गुजर-बसर न हो पाती हो। वास्तव में ब्रिटेन में एक नये तरीके की खेती की प्रणाली शुरू हुई जिसमें कुछ लोगों ने एकत्र होकर कुछ पूजी इकट्ठी की और कृषि मजदूरों को निश्चित वेतन पर नौकर रखा और एक दर्जन या उससे अधिक आदमियों को प्रवन्वकर्त्तियों के रूप में मुलाजिम रखा। इस प्रकार लगभग ५०० एकड़ या इससे बड़े चकों पर वाकायदा व्यापारिक ढंग से सुधरे तौर पर खेती शुरू करवाई गई।

जर्मनी के पूर्वी हिस्सों पर बड़ी-बड़ी रियासतें बड़े-बड़े नोबलमैनो, काउंटो और अमीर उमराओं के पास बनी रहीं। सन् १८४८ में जर्मनी में अवश्य एक क्रान्ति हुई थी पर वह बहुत ही अल्पकालीन थी और उसमें जर्मनी के कृषकों को इतना अवसर न प्राप्त हुआ कि वह फ्रांसीसी किसानों के समान अपना दवाव डाल कर और शक्ति लगा कर सामन्ती प्रथा का खात्मा करवा दें। तथापि सन् १८४९ की क्रान्ति के फलस्वरूप जर्मनी के किसानों ने, कम-से-कम जर्मनी के पश्चिमी हिस्सों में बहुत हद तक अनेकानेक सामन्ती शोषणों और नाजायज वसूलयावियों को समाप्त करवा दिया। फिर फ्रांस के सामन्ती, अमीर-उमराओं और नोबलमैनो के समान जर्मनी के सामन्तों ने हठधर्मी न अपनायी और उन्होंने सन् १८४८ की क्रान्ति के नेताओं के साथ समझौता किया और झुकने को तैयार हो गये। फिर एक बात यह भी स्मरण रखने योग्य है कि जर्मन अमीर-उमराओं और काउंटों के पास जो बड़ी-बड़ी रियासतें थी उनमें खेती बड़े ही आयोजित रूप से, बड़े ही मुवर ढंग से की जाती थी। वहां के सामन्त इंग्लैंड के सामन्तों की तरह अपनी रियासती जमीनों को लगान पर नहीं उठाते थे, वरन् स्वयं उनकी जुताई-बुआई अपनी देखरेख में करवाते थे और अपनी खेती-बारी के काम में विश्वविद्यालयों में शिक्षित कृषि-विशेषज्ञों की सहायता लेते थे। बहुत कुछ उनके बड़े-बड़े खेतों का सगठन क्रम बही हुआ करता था जो कि उस समय जर्मनी में विकसित होने-वाले औद्योगिक कारखानों में पाया जाता था। वास्तव में पूर्वी जर्मनी की यह सुप्रसिद्ध प्रशियन युकर रियासतें विश्व के इतिहास में निराली ही चीजें रही हैं, और उनमें से एक-से-एक दिग्गज विद्वान और एक-से-एक महान सैन्य विशेषज्ञ और फौजी जनरल पैदा हुए। वास्तव में इनका प्रभाव शताब्दियों तक पूरे जर्मनी के शासन पर अक्राद्य-सा रहा और इनके लोग ही जर्मनी की अति सुघर और विशाल सेना के निर्देशक रहे। जर्मनी में चाहे समाजवादी ब्रूनिंग अथवा फासिस्त हिटलर का शासन रहा हो, अन्तिम रूप से जर्मन नीति के निर्देशन इन्हीं प्रशियन युंकरों द्वारा ही होता रहा। वास्तव में यह प्रशियन युकर सारे यूरोप के देशों द्वारा बड़े भय से और मद्दिग्व दृष्टि से देखे जाते रहे। उनका खात्मा अन्तिम रूप से सन् १९४५ में रूस की लाल सेना द्वारा तब हुआ जब पराजित हिटलरों सेनाओं का पीछा करती हुई रूसी सेना जर्मनी पहुंची। उसने इन प्रशियन युंकरों की बड़ी-बड़ी रियासतों को ज्वल करके वहां के किसानों में बांट दिया।

### पूर्वीय यूरोप में

अब रहा यूरोप के पूर्वी देशों का सवाल। यूरोप के पूर्वी देशों में कृषकों के लिये खेती लाभकर नहीं रही है। छोटे-छोटे अलाभकर खेतों की संख्या अधिक रही और बड़े-बड़े मुफ्तखोर जमीन्दार निरकुशता से शोषण करते रहे। यह सही है कि बड़े-बड़े लम्बे अरसे तक बालकन प्रायद्वीप पर तुर्कों के सुलतानों के साम्राज्य स्थापित रहने से अथवा बड़े लम्बे अरसे तक पोलैन्ड का रूसी जारशाही के पदों के नीचे पददलित होने से बालकन देशों की और पोलैन्ड की प्रगति अवरोध रही। इसके कारण ही पश्चिमी यूरोप का विकास जिस क्रमनुसार हुआ और



जिस प्रकार औद्योगीकरण के पश्चात् वे बड़े शक्तिशाली राष्ट्रवादी देश बन गये वह क्रम पूर्वी यूरोप के देशों में अनुपस्थित रहा। वास्तव में इन पूर्वी देशों में देश के अन्दर की ही विभिन्न श्रेणियों में पारस्परिक संघर्ष तबतक न प्रारम्भ हुआ जबतक वहाँ तुर्की का शासन रहा। जिस समय यूरोप के पूर्वी देशों पर तुर्की का आधिपत्य क्षीण होने लगा उसी समय सस्यार में व्यापार का विकास बृहद रूप में प्रारम्भ हुआ और तब इस बात की सम्भावना दृष्टिगोचर हुई कि बालकन प्रायद्वीप के देशों में उत्पन्न अनाज का निर्यात कर के काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। अतः जो लोग उस समय वहाँ भूमि के स्वामी थे उन्होंने किसानों द्वारा उत्पादित अनाज को हस्तगत करने के लिए किसानों का शोषण और गहरा किया। इसके फलस्वरूप किसानों में असंतोष व्यापक रूप से फैला। कभी-कदा किसानों की विद्रोहाग्नि प्रज्वलित हुई पर उसे बड़ी ही निर्दयता के साथ कुचल दिया गया। साराश में पूर्वी यूरोप के देशों में सदैव ही किसानों की समस्याएँ गम्भीर रूप में विद्यमान रही।

### उपसंहार

शासक वर्गों के दूरन्देश राजनीतिज्ञों ने सदैव ही किसानों के व्यापक असंतोष के रूप में विद्यमान ज्वालामुखी को पहचान कर समय-समय पर कुछ ऐसे कानून बनाने का प्रयास किया, कुछ ऐसा भूमि सुधार करना चाहा जिसे किसानों का प्रश्न कुछ कम गम्भीर हो सके और किसानों की विद्रोहाग्नि ज्वालामुखी के रूप में प्रलयकारी ढग से फटने न पावे। इस कारण ही कभी-कदा विशेष रूप से १८वीं और १९वीं शताब्दियों में, हम कुछ भूमि सुधारों की चर्चा पाते हैं। ऐसे भूमि-सुधारों पर तब विशेष ध्यान दिया गया जबकि देश किसी रुद्ध अथवा किसी राष्ट्रीय सकट में फसा। इन छिटपुट भूमि-सुधारों का विवरण इस संक्षिप्त लेख के अन्दर सम्भव नहीं है, पर एक बात तो कही ही जा सकती है। यह छिटपुट भूमि-सुधार हुए वह यह तो दर्शाते हैं ही कि उस समय किसानों को किन-किन बातों की सबसे अधिक तकलीफ थी तथा कृषकों और कृषि मजदूरों को किस प्रकार से शोषित किया जाता था। यह कानून इस बात को निश्चित करने का प्रयत्न करते थे कि बड़े-बड़े रियासती

खेतों पर काम करनेवाले कृषि-मजदूरों को वेतन निश्चित कर दिया जाय। वे यह भी प्रयास करते थे कि काम करने के लिए मजदूरों के साथ जो ठेके किये जाय वह किस प्रकार के हों। यह कानून इस बात का भी प्रयास करता था कि साल के कुछ दिन निश्चित रूपसे इस बात को छूट रहे कि वे मालिकों के खेतों से हट कर अपने छोटे-मोटे अलाभकारी निजी खेतों पर जाकर उसकी फसल काट सकें। इसी प्रकार से कुछ अन्य छोटी-मोटी सुरक्षा कृषकों को प्रदान करने की कोशिश इन कानूनों द्वारा की जाती थी।

यह सब जो था सो था ही, पर यूरोपीय किसानों के अन्दर भूमि की भूख ही उनकी मूल समस्या बनी रही। हम भारतवासी किसानों की भूमि के लिए गहरी भूख से सुपरिचित हैं और इसलिए हमको यूरोपीय किसानों की इस भूख को समझने में दिक्कत नहीं होती। मध्ययुगीन इतिहास की लम्बी-लम्बी शताब्दियों में यूरोपीय किसान परम्परागत रूप से भूमि के याचक बने रहे। किसान चाहता था कि उसे निजी भूमि मिले जिस पर वह काबिज रहे, जिसको वह सुधरे तरीके से जोते-बोये और जिस पर उसके अधिकारों को छीननेवाला कोई न हो और जिसके द्वारा कठिन परिश्रम कर वह अपने परिवार को पाल सके। पर सामन्ती शोषणों से पोंडित सस्यार के सभी देशों के किसानों के समान ही यूरोपीय किसानों को यह तृष्णा कभी भी मध्ययुगीन इतिहास की लम्बी शताब्दियों में तृप्त नहीं हुई।

और जब २०वीं शताब्दी प्रारम्भ हुई, पूँजीवाद विकसित होते-होते अपनी अन्तिम मजिल साम्राज्यवाद के युग में दाखिल हुआ, जब साम्राज्यवादी शक्तियाँ विश्व के पुनर्विभाजन के वास्ते विश्व महायुद्ध में जुट गयीं और इस प्रकार जब आधुनिक पूँजीवाद साम्राज्यवाद का गलित, कुठित ढाँचा नग्नरूप में विश्व में ताण्डव करने लगा तब किसानों की युगो-युगो की सचित यह भूमि की भूख पुनः एक नये ज्वालामुखी के रूप में घघक उठी। तब पुनः क्रान्तियों का दौर आया, रूस में क्रान्ति हुई, पूर्वी यूरोप में क्रान्तियाँ हुईं और इस क्रान्ति की ज्वाला में सारा सस्यार धू-धूकर के जल उठा। पर वह तो दूसरा अध्याय है। हमें अपने इस आख्यान को यही समाप्त करते हैं।



# वेदों में कृषि का उल्लेख

## श्री वीरेन्द्र श्रीवास्तव, विद्यावाचस्पति

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है यह कथन हम अपने देश के परिचय में बराबर सुनते चले आये हैं। वैदिक युग में कृषि का क्या रूप था और साक्षात्कृतवर्मा ऋषि अपने मंत्रों में उसके विषय में क्या प्रतिपादन करते हैं इसका विवेचन अपने अतीत गौरवमय इतिहास और सस्कृति के ज्ञान के लिए आवश्यक है।

### अन्न और उनके नाम

जीवन धारण के लिए अन्न अपरिहार्य है और उस अन्न का उपजाना मानव जाति का कर्तव्य है। इसे वैदिक ऋषि खूब अच्छी तरह समझते थे। “अन्न वै प्राणा” यह उपनिषद् वाक्य उसीका समाहार है। अन्न की प्राप्ति और उसकी समृद्धि के लिये प्रार्थना अनेक सूक्तों में की गई है। यजुर्वेद का १२वा अध्याय और १८ अध्याय विशेष द्रष्टव्य है। वैदिक संस्कृत में अन्न और अन्नरस के लिए वाज और अर्क शब्द प्रयुक्त है। यजमान यज्ञ करके प्रार्थना करता है

वाजो न अद्य प्रमुवाति दान वाजो देवान् ऋतुभि कल्पयाति।

वाजो हि मा सर्ववीर जजान विश्वा आशा वाजर्पाजियेयम् ॥

यजु १८।३३

“अन्न ही आज दान को प्रेरित कर रहा है, अन्न ही ऋतुओं से देवों को सामर्थ्ययुक्त करता है। अन्न ने ही मुझे सबसे वीर बनाया, मैं “वाजपति” सब दिशाओं और आशाओं को जीतू। गृहपति बिना वाजपति (अन्नपति) वन कैसे निरन्तर दान कर सकता है, भिन्न-भिन्न ऋतुओं में इष्टि और दाग से देवों को तृप्त कर सकता है, और वीर तथा अर्जस्वी बन सकता है ?

वैदिक ऋषि विभिन्न अन्नो की प्राप्ति निम्नरूप में चाहता है।

“त्रीह्यश्च में यावश्च में मापाश्च में तिलाश्च में मुद्वाश्च में खल्वाश्च में प्रिंगवश्च में ठावश्च में श्यामकाश्च में नीवाराश्च में गोमाश्च में मसूराश्च में यज्ञेन कल्पताम् ।” यजु १८।१२

यज्ञ से मुझे घान, जौ, माप, उडद, तिल, मूंग, खाल्व, प्रियगु, अणु, सावा, नीवार, गेहूँ और मसूर सम्पन्न हो। छ प्रकार के चावल, जौ, गेहूँ, उडद, मूंग और मसूर जैसी दालों और तेल के लिए तिल की याचना है। ये सब धान्य वैदिक युग में उत्पन्न होते थे।

### अन्न यज्ञ अर्थात् गोमेध

इन अन्नो की उत्पत्ति के लिए जो अन्न यज्ञ किया जाता था उमका ही दूसरा नाम गोमेध था। “अन्न हि गो” शतपथ ४।३ अर्थात् अन्न ही गो है और उससे सम्बद्ध ‘मेध’ अर्थात् यज्ञ गोमेध है। वैदिक शब्द कोप में सबसे प्रधान निषट्टु और उसीकी व्याख्या निरुक्त है। निषट्टु में सर्व प्रथम भूमिवाची शब्दों की गणना की गई है। भूमि में अन्न प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया जाय वह ‘गोमेध’ है। वैदिक छन्दों का अनुकरणवाले पारसी धर्मग्रन्थ जिन्दावेस्ता में इसी को ‘गोमेज’ कहा गया है। ‘घ’ का वर्ण विकार के नियमों से ‘ज’ उच्चारण हो गया है। ‘गोमेज’ में हल से जमीन जोतने का विधान किया गया है। प्राचीन काल में विदेह जनको की प्रथा थी कि राज्य में सर्व प्रथम सुवर्णमय हल का संचालन करके कृषि पर्व का प्रारम्भ किया करते थे। जनता उनका अनुसरण करती थी। यही गोमेध यज्ञ है। सीवें शब्दों में कृषक अपने श्रम सीकरो को गिराकर हल और बल के साथ भूमि पर जो तपस्या अन्न प्राप्ति के लिए करता है वह गोमेध यज्ञ है। यजुर्वेद के विभिन्न मंत्रों का विनियोग ‘गोमेध’ में गाय के अंगों को काटकर डालने के लिए जिन भाष्यकारों की कल्पना है वह सर्वथा अनर्थ प्रसूत है। गोमेध, नरमेध, अश्वमेध में वे नव जगह ‘मेध का अर्थ मेधृ हिंसायाम्’ से काटना करके सब का काटना ही यज्ञ समझ बैठते हैं। वेद में ‘गो प्राणी अन्न्या’ अहन्तव्य कही गई है इसका उन्हें ध्यान ही नहीं। वे व्याख्याकार शायद रघुवश के ‘प्रजाये गृहमेधिनाम्’ का अर्थ घर की हिंसा करनेवाले रघुवशी कर देंगे। वे यज्ञवाची मेध शब्द को भूल जाते हैं।

## कृषि और उसके उपकरण

गोमेघ यज्ञ का सीवे शब्दों में वर्णन यजुर्वेद के १६ वें अध्याय में ६७।१७ मंत्रों में है। उसी का अथर्व वेद में पृथक सूक्त के रूप में ३।७८ में कथन है कि इन मंत्रों का देवता अर्थात् प्रतिपाद्य विषय “कृषि बला” है। खेती को ही अपना बल समझने वाले किसान “कृषीबल” है। उनके लिए मंत्र में “कीनाश” शब्द जो भाषा विज्ञान के वर्ण व्युत्पत्ति नियम और ध्वनि विकार का अनुसरण कर हिन्दी ‘किसान’ बन गया है। इन किसानों के विषय में कहा गया है कि ‘वे धीर क्रान्तिदर्शी हलो को जोतते हैं। उनमें जुआ को पृथक बँलों के लिए नियोजित करते हैं। भूमि योनि में बीज वपन करते हैं और जब शस्य समृद्ध हो जाता है तो पके अनाज को दराती से काट लेते हैं। अच्छे फलों से किसान जमीन को जोतते हैं, वे बँलों का अनुगमन करते हैं और उत्तम फल्युक्त परिपक्व औषधि को अर्थात् धान, जौ आदि को प्राप्त करते हैं। सुन्दर “सीता” अर्थात् क्यारी को तैयार करके उसे देवों की अनुमति से ‘पयस्’ ( जल ) से तृप्त कर पुष्ट करते हैं। काम दुधा गाय से ‘पयस्’ की तरह उससे अन्न का दोहन करते हैं।” कृषि के साधनों में हल सबसे प्रधान है उसके लिए सीर और लागल शब्द प्रयुक्त हैं। हल में सुन्दर फाल की योजना की गई है और युग जुआठ बाहो (बँलों) के लिए लगाया गया है। जमीन में ‘सीता’ क्यारी बनाई गई है, उस ‘भूमियुनि’ में ‘बीज वपन’ किया गया है और सब उस सब साधन को करके किसान अन्न प्राप्त करता है। मंत्र इस प्रकार है

“सीरा युज्जन्ति कवयो युगा वितन्वेत पृथक । धीरा पेवेषु  
सुम्नया ॥ युनक्त सीरा वि युगा तनुव्यम कृते योनी वपतेह बीजम् ॥”  
गिराच श्रुष्टि सभरा असन्नेदीय इत्सून्य पक्वेमेयात् ॥  
शुन सुफाला विकृषन्तु भूमि, शुन कीनाशा अभियन्तु वाहे ।  
शुनासीरा हविषा तोषमाना सुपिप्यलम औषधी पकतनास्मे ॥  
धूते न सीता मधुना समज्यात् विश्वदैव रनुमत्गमत्गमश्दिभि ।  
ऊर्जस्वती पयसा पिन्वमाना स्तस्मात् सीते पयसा श्वाववृत्स्व ॥  
लागल पवीरवत्सुशेवम् ६७।७१

ये शब्द कृषि शास्त्र में अति प्रचलित हैं, मंत्रों में प्रयुक्त फ़िराएँ भी साभिप्राय हैं। अथर्व में ‘सीता’ की विशेष वन्दना की गई है।

“सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । यथा न सुभना असो यथा न सुफना भुव”

एसे, सुभग सीता तुम्हारी वन्दना करते हैं, तुम नीचे की तरफ अचञ्ची तरह जाओ जिसे प्रसन्न होकर उत्तम फल देनेवाली हो।” इसमें सीता के चूब गहरा बनाने से फल की प्राप्ति कही गई है। गोमेघ के जनक और इस नीता का मन्त्रव्य करके विदेह नन्दिनी सीता की प्राप्ति हल

चलाते जनक को हुई थी यह प्रतीकात्मक गाथा चल पड़ी है। अन्न यज्ञ का जनक तो किसान या पर्जन्य है और सीता खेत की क्यारी या फाली है। अथर्ववेद के ऋष्वी सूक्त १२ में पृथ्वी में कर्षक अन्न उत्पन्न करते हैं। १२।३ में यह कहा गया है। उसी सूक्त में पृथ्वी को माता अपने को पुत्र और पर्जन्य मेघ को पिता कहा गया है।

माता भूमि पुत्रो अहपृथ्व्या, पर्जन्य पिता स उन विपतुं

१२।१२

खेती में भूमि माता का काम करती है जिसकी योनि से अन्न उत्पन्न होता है और मेघ सेचन का काम करके पिता बनता है।

समृद्ध राष्ट्र में समय-समय पर मेघ की वृष्टि और सफल औषधि के पकने की प्रार्थना है “निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, फलवत्यो न औषधय पञ्चन्ताम्।”

परन्तु वैदिक कवि क्रान्तदर्शी किसान केवल मेघ की ही आशा लगाये नहीं बैठा करता था। वह अपनी भूमि को अतिव मातृक “अर्थात् ‘नदी मातृक’ भी बनाना जानता था। नदियों तक अन्य जलाशयों से वह पानी लेकर खेत सींचता था। वह नदियों की “सुखरथ योजना” भी जानता था और उन्हें “वाजिनी वती” (अन्न प्रदायिनी —) कर डालता था। ऋग्वेद १०।७५ में गगा, यमुना, सरस्वती और सप्त सिन्धु देश की नदियों की प्रशंसा करके उन्हें ‘वाजिनीवती’ भी कहा गया है।

## कृषि प्रशंसा

ऋग्वेद में दशम मण्डल के ३४वें सूक्त में जुआ खेलने का क्या दुष्परिणाम है और जुआरी की क्या मनोवैज्ञानिक स्थिति होती है इसका बड़ा सुन्दर चित्रण किया गया है। जुआरी को सम्बोधन करके ऋषि कहता है:

अक्षे मा दीव्य कृषिमित्कृषस्व विचे रमस्व बहुमन्यमान ।  
तत्र गाव कितव तत्र जाया तमे विचष्टे सवितायमर्यं ॥

“पासो से जुआ मत खेलो, खेती करो और उससे प्राप्त धन को बहुत मानते हुए उसमें आनन्द लो। ऐ कितव (जुआरी) उसीमें गौवे है, उसी में पत्नी है यह मुझे श्रेष्ठ सविता ने कहा है।” वेद की दृष्टि में खेती ही सब समृद्धि का साधन है। दुर्व्यसनो को छोड़कर मन से खेती करने से धर का सब आराम सुलभ होता है।

इस प्रकार हमने देखा कि जीवन के साधन तरह-तरह के अनार्यों की प्राप्ति के लिए वेद अन्न यज्ञ (गोमेघ) का विधान करता है। किसान तरह-तरह के कृषि के विभिन्न साधनों का मनोयोगपूर्वक उपयोग करके धन-धान्य से समृद्ध हो सकता है इसका वेद ने भली-भाँति प्रतिपादन किया है। कृषि वैदिक युग से भारतीय जीवन का प्रधान अंग बनी रही है और उसी के साथ गोपालन आदि अन्य व्यवसाय भी जुड़े हुए हैं।

# आधुनिक

## हिन्दी

### साहित्य

#### में

## किसान

श्री मन्मथ नाथ गुप्त

आधुनिक हिन्दी साहित्य की परिभाषा धरावर बदलती चली जा रही है। ज्यो-ज्यो समय बीतता जा रहा है, त्यो-त्यो आधुनिक हिन्दी साहित्य की परिधि इधर की ओर आ रही है। प्रेमचन्द के प्रारम्भिक युग में राजा शिव प्रसाद (१८२३-१८६३), भारतेन्दु हरिश्चन्द्र (१८५०-१८८४) बालकृष्ण भट्ट (१८४४-१९१४), लाला श्रीनिवास दास (१८५१-१८८७), राधाचरण गोस्वामी (१८५८-१९२५) आदि लेखक आधुनिक समझे जाते थे, पर अब शायद प्रेमचन्द और प्रसाद के पीछे आधुनिक हिन्दी साहित्य को ले जाना सम्भव न होगा। बात यह है कि इस प्रकार सीमित कर देने पर भी आधुनिक हिन्दी साहित्य का क्षेत्र काफी बड़ा हो जाता है।

हम प्रेमचन्द से ही अपना विवेचन शुरू करें, तो हमारे पास इतना मसाला हो जायगा कि उस पर एक लेख में विचार करना असम्भव है। प्रेमचन्द का जन्म गाव में हुआ था, और वे काफी उम्र तक गाव में ही रहे। उनके पिता अजायबराय एक बहुत साधारण व्यक्ति थे, और गरीबी इतनी थी कि मुश्किल से गुजर होती थी। उनकी गरीबी का वर्णन उनके मुह से ही सुन लिया जाय।

“अधरा के पुल का चमरोधा जूता मने बहुत दिन तक पहिना है। जबतक मेरे पिताजी जीवित रहे, तब तक उन्होंने मेरे लिये वारह आने से ज्यादा का जूता कभी नहीं खरीदा और न चार आने गज से ज्यादा का कपडा मेरे लिये खरीदा गया।”

उन्होंने अपनी गरीबी के बहुत से उदाहरण लिखे हैं, जिनमें एक घटना यह है कि खाने-पीने की आफत के कारण उन्होंने अपने गरमकोट

को दो रूपये में बेच दिया था। दूसरी घटना यह है कि एक बार उनके पिता के एक मित्र उनसे मिलने आये। उन्होंने देखा कि वे बहुत दुबले हैं, इस पर उन्होंने यो ही कह दिया—तू दुबला क्यों है? क्या तुझे दूध-धी नहीं मिलता?

सचमुच उन्हें दूध-धी नहीं मिलता था।

एक घटना और ली जाय। उनकी शादी के लिए क्या तैयारी हुई थी, यह उनकी गरीबी को प्रकट कर देती है। शादी के लिए पाच रूपये का गुड खरीदा गया था। इसके अतिरिक्त शादी के लिए जो मंडप बनना था, उसके लिए उन्होंने स्वयं वास काटे। मंडप को छाने के लिए वासो की आवश्यकता थी।

इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि प्रेमचन्द का हृदय गरीबी और किसानों के लिये हमेशा रोया करता था। उनके उपन्यासों में हम यह देखते हैं कि जहा वे ग्राम-जीवन या किसान-जीवन का वर्णन करते हैं, वही पर वे सबसे अधिक शक्ति का परिचय देते हैं। इसका कारण यह है कि जिम जीवन को उन्होंने स्वयं जिंदा था, जिस जीवन की समस्याओं से वे अच्छी तरह परिचित थे, उसीको वे अच्छी तरह चित्रित कर सकते थे। यदि उनके उपन्यासों की मूची को ध्यान से देखा जाय, तो यह ज्ञात होगा कि एक आधुनिक पुस्तक के अतिरिक्त बाकी सभी पुस्तकों में उन्होंने ग्राम्य-जीवन का चित्र ही चित्रित किया है। प्रेमश्रम, रगभूमि, कायाकल्प, कर्म-भूमि, गोदान, ग्राम-जीवन सम्बन्धी पुस्तकें हैं और इन्हीं में से दो यानी गोदान और रगभूमि उनकी सर्वश्रेष्ठ कृतियां हैं।

प्रेमचन्द केवल गाव में पैदा हुये और पले ऐसी बात नहीं, बल्कि जब वे अच्छे उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हो गये, तब भी वे बराबर अपने गाव में जाते थे, और जैसे हुक्का ताजा किया जाता है, वैसे वे गाव में रहकर अपने तजर्बों को ताजा कर लेते थे। उनकी पत्नी श्रीमती शिवरानी देवी ने उनकी ग्रामयात्रा के सम्बन्ध में लम्बे स्मरण लिखे हैं, उसमें से कुछ पकितया यो है।

“जब गाव के काश्तकार इकट्ठा होते तो वे उनसे बातें करते, झगडा निवटाते, और बच्चों से खेलते भी जाते थे। कोई नए कायदे-कानून बनते तो काश्तकारों को समझाते। उन सबों के साथ तो वे बिल्कुल काश्तकार ही जाते थे।”

इसी प्रकार घुलमिल जाने के कारण ही वे ग्रामजीवन के इतने सफल चित्रकार बन सके। हमने अपनी ‘कयाकार प्रेमचन्द’ नामक सुवृहत पुस्तक में प्रेमचन्द के सब उपन्यासों का ब्यौरेवार विवेचन किया है। हम केवल ‘गोदान’ उपन्यास के सम्बन्ध में ही इस अवसर पर कुछ कह कर आगे बढ़ जायेंगे।

‘गोदान’ का नायक होरी एक मामूली किसान है। चार-पाच बीघे जमीन जोलता है। पुस्तक के द्वितीय पृष्ठ में ही प्रेमचन्द किसान जीवन की सबसे बड़ी परेशानी को स्पष्ट कर देते हैं। “चाहे जितनी ही कतर-ब्योत करो, कितना पेट-तन काटो, चाहे एक-एक कौड़ी को दात से पकडो, मगर लगान वंवाक होना मुश्किल है।”

होरी में मामूली किसान के सब दोष-गुण दिखाये गये हैं। वह समय-समय पर एक व्यर्थ आशा के बशवर्ती होकर अपने जमींदार राय साहब के यहा सलाम बजाने चला जाता है। होरी के मन में एकही उच्चाकाक्षा थी कि दरवाजे पर एक गाय बध जाय। इसमें भी वह एक साधारण भारतीय किसान, बल्कि सभी देशों के किसानों की मनोवृत्ति को अभिव्यक्त करता है। “गऊ से ही तो द्वार की शोभा है। सबेरे-सबेरे गऊ के दर्शन ही जाय तो क्या कहना। न जाने कब यह साध पूरी होगी।”

होरी कोई दूध का घुला नहीं है। वह चन्द रूखों के लिए अपने भाई को धोखा देने के लिए तैयार हो जाता है, पर वह अपने शोषकों से फही अच्छा है। जिसको उसने धोखा दिया था, उसी भाई पर जब एक विपत्ति आती है, तो वह जान देकर उसकी रक्षा के लिए तैयार हो जाता है। होरी अपने छोटे-मोटे झूठ, ठकुरसुहाती, खुशामदीपन के वाबजूद हमारे नामने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में आता है, जो ‘गोदान’ के रायसाहब, मिस्टर मेहता आदि से कही अच्छा है।

होरी भारतीय किसान वर्ग का प्रतीक है, एक तो यो ही तरंगों से उमे लडना पडता है, तिम पर सर्वत्र न मालूम कितने बड़े-बड़े जहाज, मगरमच्छ और न मालूम क्या-क्या विपदायें इम सागर में हैं। इन विपत्तियों के बीच से होकर वह अपनी छोटी-सी डोंगी खेता हुआ चलता है। हर समय उनके डूबने का भय रहता है। न मालूम कब किससे टक्कर नग जायें, और डोंगी की भदलीला समाप्त हो जाय। इसलिए ‘गोदान’ एक व्यक्ति के, और चूंकि यह व्यक्ति भारत के वृहत्तवर्ग का है, इसलिए चारे किसान वर्ग के जीवन-नयाम का इतिहास है। किस प्रकार होरी इतनी

विपत्तियों और इतने शत्रुओं के बीच से होता हुआ चलता है, इसीकी महाकाव्यमय कहानी ‘गोदान’ में कही गई है। होरी को हमने भारतीय किसानवर्ग का प्रतिनिधि पात्र या प्रतीक कहा है, किन्तु यह स्मरण रहे कि होरी के पास चार-पाच बीघे जमीन है, इसलिए वह उन लाखों खेतिहर मजदूरों से खुशहाल है, जिनके पास कोई जमीन नहीं है और जिनको दूसरों की जमीन पर मजदूरी करते हुए जीवन के दिन काट देने पडते हैं। चार-पाच बीघे जमीन के तथा हल-बैल के मालिक होते हुए भी होरी पर जैसी-जैसी मुसीबतें आती हैं, इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि उन किसानों की क्या हालत होगी जिनके पास जमीन नहीं है। अवश्य होरी स्वयं खेतिहर मजदूर होने पर मजबूर हो गया है, यह इस उपन्यास में दिखा दिया गया है। इस प्रकार हम यह भी देखते हैं कि किस प्रकार बराबर मामूली किसान सर्वहारा वर्ग में गिरते चले जा रहे हैं।

खुद है कि प्रेमचन्द भारत की स्वतंत्रता देख नहीं जा सके और यह नहीं देख पाये कि जमीन्दारी प्रथा के उच्छेद आदि उपायों से किसानों की समस्या के आंशिक समाधान करने की चेष्टा की जा रही है। ‘गोदान’ अब भी किसान सम्बन्धी साहित्य के रूप में अद्वितीय है।

‘गोदान’ में प्रेमचन्द सम्पूर्ण रूप से अपने पहले के सस्कारों से मुक्त होकर एक शुद्ध वस्तुवादी कलाकार के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। गोदान में ग्राम समाज का जो चित्र है, वह कवित्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अत्यन्त वस्तुवादी है। दातादीन, पटेश्वरी, झिगुरी सिंह, अनोखे राम ये ग्राम्य-समाज के स्तम्भ हैं, किन्तु कितने सड़े-गले स्तम्भ हैं। इन्स ने समाज के स्तम्भ नामक नाटक लिखा है, उसे वस्तुवादी होने के नाते बहुत सराहा गया है, किन्तु ग्राम-समाज का जो चित्र प्रेमचन्द गोदान में हमें देते हैं, वह उससे कुछ कम प्रशंसनीय नहीं है। शरत बाबू ने अपने ‘पल्लि समाज’ में ग्राम्य जीवनके इस पहलू को सरलता के साथ चित्रित किया है। गोदान में यह स्पष्ट हो जाता है कि गाववालों की मुसीबत यदि जमीन्दार और उनके कारिन्दों के कारण है, तो साथ ही उनके जीवन को नरक बनाने में पुलिस का भी बड़ा भारी हाथ है।

प्रेमचन्द के वाद हिन्दी उपन्यास बहुत आगे बढ़ गया है, पर जहा तक ग्राम और ग्रामीणों की समस्याओं का सम्बन्ध है, बाद के किसी भी उपन्यासकार ने इन बातों पर न तो उसे विस्तार से लिखा, और न वह दृष्टिकोण ही लिया। जनेन्द्र, अज्ञेय, यशपाल, वृन्दावनलाल वर्मा आदि कई उपन्यासकार हिन्दी में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, पर इनमें से केवल वृन्दावनलाल वर्मा ने ग्राम्य जीवन को उसी प्यार से देखा है, जिस प्यार से प्रेमचन्द ने अपनाया था, पर उनके प्यार में यद्यपि कमी नहीं है, फिर भी वे उस आत्मा से ग्रामीणों के जीवन को नहीं देखते, जिस आत्मा से प्रेमचन्द देखते थे। शोपक और शोपित सम्बन्ध के कारण ग्राम जीवन हेय और गन्दा बना हुआ है, वहा के लोगों को न तो पेट भर रोटी मिलती है, और न सस्कृति के कोई साधन प्राप्त है। हमारे कुछ लेखक ग्राम-जीवन की ओर झुके हैं, जैसे यशपाल ने कागडा के जीवन का जहा-तहा वर्णन किया है, पर देहात की ओर यह यात्रा केवल नये वातावरण में रोमान्स की खोज के कारण है, न कि ग्रामवासियों की समस्याओं के समाधान के

लिये है। हां यो चित्रण करते समय वृन्दावनलाल तथा यशपाल की कृति में कुछ समस्याएँ आ गई हैं, यह और बात है। बिहार में राजा राधिका-रमण ने ग्राम-जीवन पर बहुत कुछ लिखा है, पर पाच रूपयों के गुड से शादी करने वाले तथा फीस जमा न कर सकने के कारण वर्षों तक वी० ए० की डिग्री प्राप्त करने में असमर्थ प्रेमचन्द के दृष्टिकोण और राजा साँहव के दृष्टिकोण में बड़ा फर्क है।

ग्राम-जीवन पर उपन्यास लिखने की परम्परा को बिहार के ही एक लेखक श्री नागार्जुन ने 'बलचनमा' नामक उपन्यास लिखकर आगे बढ़ाया है। ग्रामीणों के साथ सहानुभूति में उनकी समस्याओं के सम्बन्ध में अपनी दृष्टि में साथ ही कलामय चित्रण में वे प्रेमचन्द से सचमुच आगे बढ़ गये हैं, ऐसा कहा जाय तो कोई अत्युक्ति न होगी। इस उपन्यास में दर-भंगा जिले का चित्र है, और वह १९३७ तक समाप्त हो जाता है। लेखक ने खड़ी बोली में वही के शब्दों को यत्रतत्र लाकर एक ऐसा स्थानीय रंग पैदा कर दिया है, जो न केवल गुदगुदी उत्पन्न करता है, बल्कि गाव के जीवन का एक मजबूत चित्र उपस्थित कर देता है। सामन्तवाद का इन-सेक्शन दिखाने के साथ-ही-साथ कांग्रेस ने किस प्रकार इसको तोड़ने में तथा उसे बचाने में किस प्रकार का काम किया है, इस द्वन्द्ववादी चित्र को लेखक ने व्याख्यानोंसे नहीं, बल्कि अपनी कहानीसे स्पष्ट किया है। पुस्तक को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि इसके कई भाग निकलेंगे। यह दुख की बात है कि आर्थिक कठिनाइयों के कारण बिहार के इस परम प्रतिभा-वान लेखक को अपनी कलाकृतियाँ तैयार करने के लिए समय नहीं मिल रहा है, और ऐसे कामों में समय व्यतीत करना पड़ रहा है, जो शायद उनकी प्रकृति के अनुकूल नहीं है, और साहित्य की दृष्टि से कोई महत्त्व नहीं रखता। स्मरण रहे कि यहाँ हम नागार्जुन के विचारों के लिये नहीं, बल्कि उनकी कला के लिए उनकी सराहना कर रहे हैं। साहित्य में विचार बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है, पर यदि विचार कला के जरिये से आ पाते हैं, तो वह साहित्य सार्थक होता है, नहीं तो वह दो कौड़ी का होता है। हम यह आशा करते हैं कि नागार्जुन मिथिला के ग्राम जीवन पर हमें और सुन्दर कृतियाँ प्रदान करेगा।

अब हम कविता के क्षेत्र में पदार्पण करते हैं, तो वहाँ हमें यह देखकर आश्चर्य होता है कि यद्यपि आधुनिक कवियों में से बहुतेरे गाव में पैदा हुए फिर भी उनमें से बहुत कम लोगो ने किसानों पर कविताएँ लिखी। श्री महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बलीवर्द नाम से एक कविता में हमारी कृषि पद्धति के केन्द्र-स्थल बँल पर यह कविता लिखी है —

तुम्हीं अन्नदाता भारत के सचमुच बँल महाराज,  
बिना तुम्हारे ही जाते हम दाना-दाना को मुहताज।

उसी युग के केशव प्रसाद मिश्र ने किसान की पीड़ा के सम्बन्ध में लिखा —

जो करता था पेट काटकर सरकारी कर दान,  
रहता था प्रस्तुत करने की श्रम्यागत का भान।  
नहीं हुआ था जिसे धैर्यवश कभी दुख का भान,  
आज वही भूखो भरता है मातादीन किसान।

श्री मैथिलीशरण गुप्त ने "भारत भारती" में कृषि और कृषक पर कुछ छन्द लिखे। कृषको में फँले हुए आलस्य का दोष वे उनके शोषण पर मढ़ते हैं।

करते नहीं कृषक परिश्रम और वे कैसे करें,  
कर वृद्धि जब है साथ तब वे क्यों वृथा श्रम कर मरें।  
वे आगे लिखते हैं —

बरसा रहा है रवि अनल भूतल तथा सा जल रहा,  
है चल रहा सन-सन पवन तन से पमीना ढल रहा।  
देखो कृषक शोणित सुखा कर हँसतयापि चला रहे,  
किस लोभ से इस आच में वे निज शरीर जला रहे।  
मध्याह्न है, उनकी स्त्रियाँ ले रोटियाँ पहुँची वहीं,  
हैं रोटियाँ रूखी खबर है, शाक की हमको नहीं।  
सतोष से खाकर उन्हें वे काम में फिर लग गये,  
भर पेट भोजन पा गये तो भाग्य मानो जग गये।

मैथिलीशरण जी ने 'किसान' नाम से एक लघु काव्य भी लिखा है। श्री केशव प्रसाद मिश्र ने फरवरी १९१५ की सरस्वती में लिखा था—  
एक दरिद्र कृषक है जिसने किया खेत में दिन भर काम,  
किन्तु पेट भर रोटी मिलना, उसको है जय सीताराम।

गिरिवर शर्मा किसान को कर्मयोगी रूप में देखते हुए कृषक 'कीर्ति-गान' कविता में लिखते हैं —

है गीता का गूढ ज्ञान,  
इस पर तू चलता सुजान।  
गिरिवर जो जन है महान,  
करते तेरा कीर्तिगान।

सनेही जी ने रवीन्द्र के एक प्रसिद्ध गीत का अनुवाद किया, जिसकी प्रथम दो पक्तियाँ यों हैं —

आखें खोल देख तू सम्मुख तेरा पूज्य वहाँ न,  
वह है वहाँ जोतता धरणी जहाँ गरीब किसान। इत्यादि

पर किसानों के सम्बन्ध में उन दिनों सबसे अच्छा मैथिलीशरण जी ने ही लिखा —

पहला ही ऋण नहीं चुका है, रहटी बीज खवाई का,  
कैसे चुके लगा है क्षण्डा सबके साथ सवाई का।  
खेती में क्या सार रहा अब कर देकर जो बचता है,  
कडे व्याज के बडे पेट में सभी फलों में पचता है।  
जमीन्दार ने कहा कि सुनलो कहते हैं हम साफ-  
भवकी वार फसल फिर विगडे या लगान हो माफ,  
पर हम जिम्मेदार नहीं हैं छोड़ेंगे न छदाम।

हम आगे कृषक सम्बन्धी कुछ कविताएँ उद्धृत करते हैं। श्री सुमित्रा-नन्दन पन्त ने १९३६ के लगभग लिखा —

युग-युग का वह भारवाह, आकटि नत मस्तक,  
निखिल सम्य ससार पीठ का उनके स्फोटक।  
वज्र मूढ, जड भूत, हठी, वृष वाचक कर्षक,

घ्रुव, ममत्व की मूर्ति, रूढियों का चिर रक्षक ।  
 कर-जर्जर, ऋण-ग्रस्त, स्वल्प पैत्रिक स्मृति भूषण,  
 निखिल दैन्य, दुर्भाग्य, दुरित, दुख का जो कारण,  
 वह कुबेर निधि उसे, स्वेद सिंचित उसके कण,  
 हर्ष-शोक की स्मृति के बीते जहा वर्ष क्षण !  
 विश्व विवर्तनशील, अपरिवर्तित वह निश्चल,  
 वही खेत, गृहद्वार, वही वृष, हसिया औ हल ।  
 स्यावर स्थितियों का शिशु स्यावर स्थाणु कृषीवल,  
 दीर्घसूत्र, अति दुराग्रही, सशक औ वृषल ।  
 है पुनीत सपत्ति उसे दैवी निधि निश्चित,  
 सततिवत् गो वृषभ, गुल्म, तृण, तरु चिर परिचित ।  
 वह सकीर्ण, समूह-कृपण, स्वाश्रित, पर-पीडित,  
 अति निजस्त्र-प्रिय, शोषित, लुठित, दलित, क्षुधादित ।  
 युग-युग से नि सग स्वीय श्रमबल से जीवित,  
 विश्व-प्रगति-अनभिज्ञ, कूप तम में निज सीमित,  
 कृषक का उद्धार पुण्य इच्छा है कल्पित,  
 सामूहिक कृषि काय-कल्प, अन्यथा कृषक मृत ।

यदि देखा जाय तो पत जी की यह कविता किसी भी अर्थ में न तो मयिली शरण जी की कविता से सुन्दर है, और न उनकी समस्याओं की गहराई में जाता है। शब्द जाल अधिक है, और किसानों की समस्याओं के सम्बन्ध में समझ बहुत थोड़ी। हा, अन्त में यह जो कहा है कि “कृषक का द्वार पुण्य इच्छा है कल्पित, सामूहिक कृषि कायकल्प, अन्यथा कृषक मृत”, इन पक्तियों में यह बताया गया है कि किसानों का उद्धार सामूहिक खेती से ही होगा। मुझे तो इस कविता में कृषको के प्रति प्रेम का एक बिन्दु भी दिखाई नहीं पड़ता, जैसा कि पहले उद्धृत कविताओं में दिखाई देता है। यह तो एक दिमागी कसरत-सी मालूम पड़ती है।

प्रलयवीणा के कवि स्वर्गीय डाक्टर सुधीन्द्र की ‘किसान’ नामक कविता में बलिक अधिक ऐतिहासिक गहराई और किसानों के प्रति प्रेम दिखाई पड़ता है, पर इसमें किसान के शोषण को एक दिव्य रूप देकर उसके पिशाचत्व को उभरने नहीं दिया गया। कविता यो है।

तुम तपोपूत, तुम देवदूत ।  
 तुम अवातीत, तुम पुण्य प्राण ।  
 विभु वह तुममें अवतरित हुआ  
 लेकर अपना मानव महान ।

करते अपने श्रम-सीकर से  
 तुम ससृति-हित मधु का विधान ।  
 निज रक्ताहुति देकर जग को  
 तुम करा रहे पोषण-पान

जग की वर्वर्ता को तुमने  
 पहनाया मन्कृति-मुपरिधान  
 तुम गत्य-मृष्टि-घाता किसान ।  
 मृम आदि-अन्नदाता किसान ।

पट से वितान निस्सीम तान  
 तुमने इस भव का किया त्राण  
 जग पर अपनी कर-छाया कर  
 तुम हुए स्वयम् छाया-समान

शिवि, दे-देकर अपना शरीर  
 तुम स्वयम् बने हो शीर्ण-क्षीण  
 जिससे न तुम्हें पहचान सकी  
 आत्मा जग की सकलुष-मलीन

लेकर आत्मा का अमृत-त्याग,  
 ले तप-मानवता का पराग,  
 शीशस्य आग को बना फूल  
 खेला तुमने बलिदान-फाग

गोपाल । तुम्हारे जीवन में  
 उतरा आकर विभु निर्विकार  
 जग पूत हुआ तुमसे पुनीत  
 ओ पुण्य सत्र के सूत्रधार ।

हलवर ! तुमने शिर घरा अहो !  
 गुस्तम यह ससृति त्राण-भार  
 सस्कृति होती क्षुन्मग्र नग्न  
 तुम बिना आज धमवितार !

इस कविता में किसान को शस्य सृष्टि घाता आदि अन्नदाता, शिवि, गोपाल आदि कह कर किसान की मर्यादा बहुत अधिक बढ़ा दी गई है, पर उसकी वर्तमान गिरी हुई अवस्था से उसका किसी प्रकार परित्राण हो सकता है या होना चाहिये, इसका कहीं जरा सा भी संकेत इस कविता में नहीं है। तपोपूत, देवदूत, अवातीत, पुण्यप्राण कहने से किसान की काल्पनिक मर्यादा में भले ही वृद्धि हो, पर इससे कुछ आता-जाता नहीं। इस दृष्टि से देखने पर सुमित्रानन्दन पत की ‘कृषक’ कविता अच्छी थी क्योंकि उसमें अत्यन्त सूत्ररूप में ही सही सामूहिक कृषि कायाकल्प से किसान के उद्धार की बात कही गई है।

‘ग्राम्या’ (१९४०) में चलकर सुमित्रानन्दन पत ने कवि किसान नाम से एक कविता लिखी है, जिसमें कवि की तुलना किसान से करते हुए उससे नव मानवता का स्वर्णशस्य उगाने के लिए कहा गया है। यद्यपि सच पूछा जाय तो यह कविता कवि पर है न कि किसान पर, फिर भी इसमें किसान के प्रति जो सम्मान की भावना है, उसके कारण वह कविता इस प्रसंग में उद्धृत करने योग्य है —

जोती है कवि, निज प्रतिभा के  
 फल से निष्ठुर मानव अन्तर,  
 चिर जीर्ण विगत की खाद डाल,  
 जन-भूमि बनाओ सम सुन्दर ।  
 वोओ, फिर जन-मन में वोओ,  
 तुम ज्योति पख नव बीज अमर,  
 जग जीवन के अकुर हस-हस  
 भू को हरीक्षिमा से दें भर ।

पृथ्वी से खोद निराओ, कवि,  
मिथ्या विश्वासों के तूण खर,  
मीचो अमृतोपम वाणी की  
धारा से मन, भव हो उर्वर !  
नव मानवता का स्वर्ण-शस्य—  
सौन्दर्य लवाओ जन-सुखकर,  
तुम जग-गृहिणी, जीवन किसान,  
जन हित भडार भरो निर्भर ।

श्री गोपाल सिंह नेपाली ने 'जल रहा है गाव' शीर्षक से एक कविता लिखी है, जो बहुत ही सुन्दर है। यद्यपि इसमें किसान के उद्धार का न तो कोई संकेत है, और न इसमें भविष्य का कोई इंगित है, फिर भी इसमें किसान की समस्या बड़े ही कवित्वमय रूप से सामने आ जाती है। इस कविता में उदी, उदी, गँल, धरम-करम, दुन्द, उयला-उयला आदि शब्दों के कारण जो वातावरण बनता है, वह पत जी की 'कृषक' कविता में विल्कुल बन नहीं पाता। पत जी की 'कृषक' कविता की भाषा विल्कुल संस्कृत मूलक है, और उसमें गाव की सोबी-सोबी महक विल्कुल आ नहीं पाती। पर 'जल रहा है गाव' कविता में यह बात नहीं है। वह कविता यों है—

झुरमुटो के पास में यह धुआ उठा है जो  
जल रहा है गाव  
जल रहा है गाव  
उदी-उदी झोपडी सूनी-पूनी गँल  
बाजरे के खेत में जुत रहे थे वँल  
रोटियों के बास्ते पिल रहे किसान  
खडी फसल की याद में खिल रहे किसान  
पल कराल मेघ बन  
लाल-लाल मेघ बन  
चँत के आकाश में यह धुआ उठा है जो  
जल रहा है गाव  
जल रहा है गाव  
यह किसी किसान की नहीं चिलम की आग  
नहीं किमी फकीर के धरम-करम की आग  
यह कहीं से आग की आई चिनगारिया  
घबक रही है झोपडी, सुलग रही है ब्यारिया  
आज दुन्द बाघकर  
वस्तिया बरबाद कर  
पश्चिमी वतास में यह धुआ उठा है जो  
जल रहा है गाव  
जल रहा है गाव  
उयला-उयला हो गया है गाव का कुभा  
सारा पानी पी गया है आग का धुआ  
ठोकरो के सामने लुढ़क रहे हैं डोल  
कोयला श्री' राख में जिन्दगी का मोल

आखें लाल-लाल कर  
आधियों की ताल पर  
शान्ति के निवास में यह धुआ उठा है जो  
जल रहा है गाव  
जल रहा है गाव

न जाने इस कविता को पढ़कर रगभूमि का वह अन्तिम प्रसंग क्यों याद आ जाता है, जिसमें पाडेपुर गाव के धू-धू करके जलने का वर्णन है। नरेन्द्र ने पत के ही ढग पर 'कवि किमान' नाम से एक कविता लिखी है। कविता का नाम भी वही है पर मुख्य विचार एक होने पर भी कुछ अर्थों में यह कविता यथेष्ट मौलिकता लिये हुए है पर कविता को पढ़ने से यह ज्ञात होता है कि यह विना किसी अनुप्रेरणा के लिखी गई है। वह कविता यों है—

हम किमान हैं ।  
मनोभूमि में ज्योति बीज बोनेवाले हम  
कवि किमान हैं ।  
हम किसान हैं ।  
योद्धा को तलवार  
श्रमिक को मिलती छेनी.  
कृषकों को हल कवि को  
मिली लेखनी पंती ।  
कहीं शस्ययुत क्षेत्र  
कहीं उद्ग्रीव दान है !  
हम किसान हैं !  
पगु न्याय विन शक्ति  
वस्तु विन विश्व अविकसित !  
पतित अहल्या-भूमि  
गीत के विना रिक्त चित्त ।  
जोतेंगे भव-तिमिर  
ज्योति-जिहवा समान है ।  
हम किसान हैं !

इस कविता में कहीं अधिक सहानुभूति उन कविता में पाई जाती है जो 'मिट्टी और फूल' शीर्षक से १९४२ में प्रकाशित हुई थी। "मिट्टी और फूल" नामक कविता किसान पर नहीं है, क्योंकि सारी कविता मिट्टी की जवानी कहलाई गई है, फिर भी यह प्रासंगिक है और मिट्टी के प्रेम से अत-प्रोत है, जो कृषक जीवन की आत्मा है। वह कविता यों है—

वह कहती है, 'हैं तूण-तर-प्राणी  
जितने, मेरे बेटा-बेटो' !  
ऊपर नीला आकाश और  
नीचे सोना-माटी लेंटी ।  
"मेँ सब कुछ सहती रहती हूँ,  
हो धूप-ताप चर्पा-माला,  
पर मेरे भीतर छिपी हुई



बिन बुझी एक भीषण ज्वाला ।  
 मैं मिट्टी हूँ, मैं सब कुछ  
 सहती रहती हूँ चुपचाप पड़ी,  
 हिम श्रातप में गल और सूख  
 पर नहीं आज तक गली-सड़ी ।  
 मैं मिट्टी हूँ, मेरे भीतर  
 सोना-रूपा, नौरत्न भरे ।  
 मैं सूखी हूँ पर मुझसे ही  
 फल-फूल और वन-बाग हरे ।  
 मैं पावो के नीचे, मैं ही हूँ  
 पर पर्वत पर की चोटी !  
 मेरी छाती पर शत पर्वत,  
 मैं मिट्टी हूँ सबसे छोटी ।  
 मैं मिट्टी हूँ, अभी मिट्टी,  
 पर मुकुल-फूल मेरी आखें ।  
 मैं मिट्टी हूँ—जड़ मिट्टी हूँ,  
 पर पत्रों में मेरी पाखें ।  
 मैं मिट्टी हूँ—मैं वर्णहीन,  
 पर निकले मुझसे वर्ण सकल ।  
 मेरे रस से रजित-प्रसून  
 रजित नव अंकुर, पल्लव-दल ।  
 मैं गन्धहीन, मुझसे करते  
 फल-फूल-मूल पर गघ ग्रहण,  
 जलवायु व्योम जो गघरहित  
 करते वे किसकी गघ वहन ?  
 मैं शव की शैया, मुझसे ही  
 उगते हैं नवजीवन-अंकुर,  
 नभ में कैसे खेती करता  
 सब जीवों में जो जीव चतुर ?  
 श्राती है मेरे पास खगी  
 दाने-दाने को चोंच खोल,  
 तिन दवा चटुल उड जाती वह  
 मेरे पेंडों पर जो अबोल ।  
 मुझसे वनते हैं महल और  
 ये खड़ी मुझी पर मीनारें,  
 मैं करवट लेती—डह जाते हैं  
 दुर्ग, चीन की दीवारें ।  
 हा, बुद्धिजीवि, आदर्श-मुग्ध  
 मानव भी मेरी ही कृति है,  
 पैगम्बर और निकन्दर का  
 मुझसे श्रय है, मुझमें इति है ।  
 मेरे कन-कान पर उडगन भी  
 वारा करते हिमकन-मोती,

जिनकी सतरगी गोदी में  
 सिर धर सूरज किरणों सोनी ।  
 मैं मर्त्यलोक की मिट्टी हूँ,  
 मैं सूर्यलोक का एक अश,  
 श्राती है जिस धर से किरणें  
 है मेरा भी तो वही वश ।

( २ )

इतने में आया हस वसन्त,  
 मिट्टी को चूमा—खिला फूल ।  
 थल का बुलबुला फूल जैसे  
 हसता समीर में झूल-झूल ।  
 जिस मिट्टी से जीवन पाया,  
 वह उस मिट्टी को गया भूल,  
 थल का बुलबुला फूल जैसे  
 हसता समीर में झूल-झूल ।  
 देखा जो तारों को, सोचा—  
 मैं भी उड जाऊ बहुत दूर,  
 है जहां जल रहा नीलम के  
 मंदिर में वह कूर्म चूर ।'  
 तितली को देखा और कहा—  
 मुझको दे दो, दो चटुल पख,  
 मैंना आई तो उससे भी  
 उडने को मागे चटुल पख ।  
 फिर आ निकली वन की चिडिया  
 तिनके चुगने, चुग्गा लेने  
 'ले चलो मुझे भी उडा कहीं'  
 यों भूल लगा उससे कहने ।  
 चिडिया की चोच वसन्ती थी,  
 था फूल गुलाबी रंग भरा,  
 बस पल में दीखा चिडिया के  
 मुह में वह डठल हरा-भरा ।  
 ऊपर था नीला आसमान,  
 दीखी नीचे सोना धरती,  
 थल का बुलबुला फूल, टूटा !  
 पर मिट्टी इसमें क्या करती ?  
 आ गिरा धरा पर फूल, मिला  
 मिट्टी में, छिन में हुआ धूल !  
 जिस मिट्टी से जीवन पाया,  
 था उस मिट्टी को गया भूल ।  
 मिट्टी कहती—“मैं सब कुछ  
 सहती रहती हूँ चुपचाप पड़ी,  
 हिम श्रातप में गल और सूख  
 पर नहीं आज तक गली-सड़ी ।”

कवि मिलिन्द ने 'घरती की पुकार' नाम से एक बहुत अच्छी कविता लिखी है। कविता की दृष्टि से यह कविता उसी श्रेणी में आती है, जिसमें गोपाल सिंह नेपाली की कविता रखी गई, यानी इसमें वातावरण का सृजन बहुत सुन्दर रूप से हुआ है। साथ ही घरती के प्रति अपरिमित बल्कि अपरिमेय प्रेम दृष्टिगोचर होता है। कविता यो है—

केवल सहृदय सुन पाते हैं  
घरती के अन्तर की पुकार ।

जिसके प्राणों में पलता है  
ज्वालागिरि का उच्चाप प्रखर,  
पर, जग को देती रहती है  
जो शीतल सरिता, सर, निर्झर,  
उठती है जिसके कण-कण से  
क्षण-क्षण जीवन-रस की फुहार  
केवल सहृदय सुन पाते हैं  
घरती के अन्तर की पुकार ।

संस्कृति का प्रहरी तपोनिष्ठ  
हिमगिरि विकास जिस रजकण का,  
वह लघु कण है वास्तव्यपात्र  
शिशु, मानो, जिसके आगन का,  
मातृत्व-प्रेरणा नारी की  
जिसकी अनन्त है स्नेहवार ।  
केवल सहृदय सुन पाते हैं  
घरती के अन्तर की पुकार ।

उत्सर्ग सिखाया नारी को,  
है प्रेम पुरुष को सिखलाया,  
उनके जीवनपथ पर जिसने  
सचित श्री-सौरभ विखराया  
दे दिया खुले हाथों अपना  
नन्दन बन करने को विहार ।  
केवल सहृदय सुन पाते हैं  
घरती के अन्तर की पुकार ।

जिसकी पुकार है शान्ति, क्षमा,  
कहणा, मानवता, ममता की  
जिसकी पुकार है त्याग, न्याय,  
शुचिता, उदारता, समता की,  
उम पृथ्वी का स्वर सुनने को  
अनुभूति चाहिये निर्विकार ।  
केवल सहृदय सुन पाते हैं  
घरती के अन्तर की पुकार ।

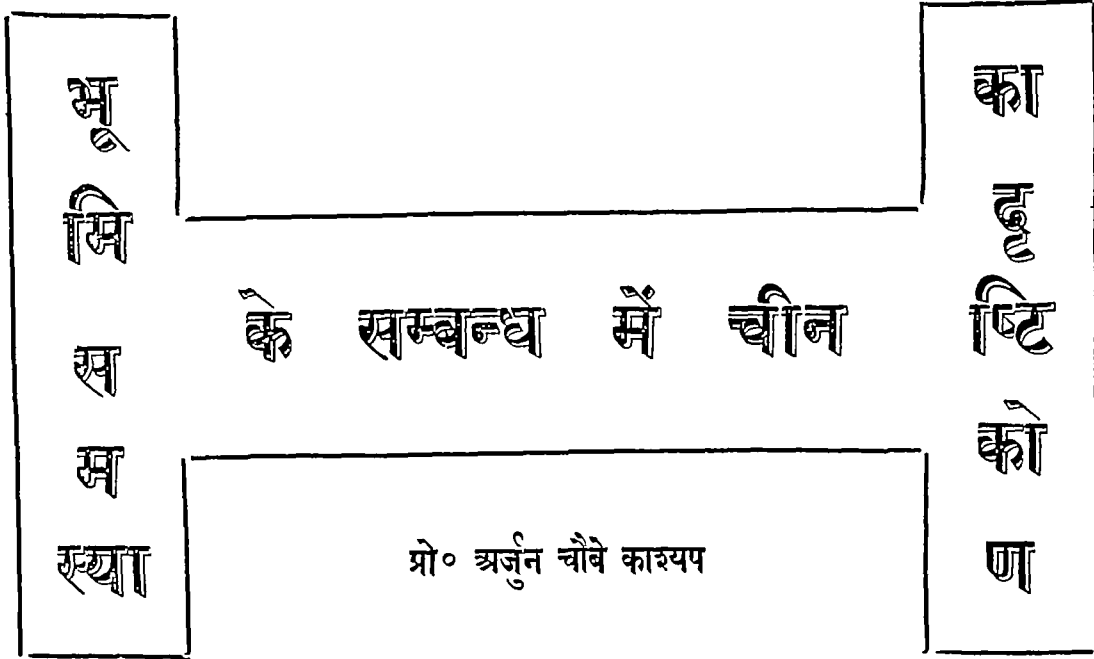
आकाश शून्य है, सूर्य आग,  
विस्तार मात्र, खारा सागर  
पर चित्र विचित्र और गतिमय  
पृथ्वी सुन्दरता की आकर ।  
है मौन गीत इसका, इसके  
कण-कण में है असय डुलार ।  
केवल सहृदय सुन पाते हैं  
घरती के अन्तर की पुकार ।

वज्राहत, भूकपादोलित  
होकर भी अविचल रहती है,  
पहुँचाती क्षति न किमी को भी  
सबके प्रहार यह सहती है ।  
तप करती है, रस देती है,  
है सृजन-शक्ति इसकी अपार ।  
केवल सहृदय सुन पाते हैं  
घरती के अन्तर की पुकार ।

जिस दिन इसने आरम्भ किया  
इस जग पर स्नेह लुटाना है,  
उस दिन से केवल देना ही  
इस तपस्विनी ने जाना है ।  
प्रतिदान प्रेम का इसने कब  
किससे है मागा कर पनार ?  
केवल सहृदय सुन पाते हैं  
घरती के अन्तर की पुकार ।

जो केवल लेता रहता है  
जो अस्थिर स्वार्थी और मुखर,  
जो बिना साधना मिलता है  
मानव को जीवन के पथ पर  
आदर्श नहीं वह वसुधा का,  
यह इसके उसका नहीं प्यार ।  
केवल सहृदय सुन पाते हैं  
घरती के अन्तर की पुकार ।

इस लेख में हमने कितान सम्बन्धी कुछ ही साहित्य का उल्लेख किया है। यह दावा नहीं किया जा सकता कि सबका उल्लेख कर ही दिया गया, ऐसी बात नहीं, पर सभी ढंग का कुछ प्रतिनिधित्व प्राप्त गया, इसमें नन्देह नहीं ।



“नया चीन” अर्वाचीन साम्यवाद की सुखद प्रवृत्तियों से प्रचालित एव व्यवहार द्वारा स्थापित प्रक्रियाओं एव योजनाओं का एक उज्वलत उदाहरण है। अपने गत आठ वर्षों में उसने युगो से प्रताडित एव विषम रूढियों से कराहती सामान्य जनता को जिस आर्थिक स्तर पर उठा दिया है वह उसकी सकल योजनाओं तथा पुनर्निर्माण के सकेतो का उज्ज्वल प्रतीक है। माओ-त्सेतुंग की अध्यक्षता एव उनके व्यावहारिक दृष्टिकोण से अनुप्राणित हो नये चीन के नियामको ने राष्ट्रीय योजनाओं को इतनी व्यापकता दी जिसे देख लोग दातो तले उ गली दवा रहे हैं।

आज का चीन, जिसे “नया चीन” की उपाधि से विभूषित किया जाता है, युगो से चली आती हुई गहिर समाज-नीति, धर्म-नीति, अर्थ-नीति, राजनीति तथा अन्य विषमतापूर्ण एव घृणित जीवन थापन की नीतियों तथा रूढियों को दूर फेंक चुका है और इस प्रकार उसने परम्परा से चले आये हुए समाज-शोषण एव जन-जन के दोहन को कुत्रवृत्तियों से सचालित विषमताओं तथा विभेदो को उत्पाटित कर आश्चर्य में डालनेवाली यथार्थवादी परम्पराओं का निर्माण किया है। निस्सन्देह, “नया चीन” सुवरो एव योजनाओं के क्षेत्र में नए रूप को छोड विश्व के अन्य राष्ट्रों से आगे है। इन नेत्रों में हम भूमि समस्या से सम्बन्ध रखनेवाले चीनी दृष्टिकोण का पर्यवेक्षण करेंगे और इसके सभी पहलुओं पर वैज्ञानिक एव अनुभूतिजन्य प्रयोगों का लेनाजोखा उपस्थित कर नवीन भारत के समक्ष नई उदाहरण रचेंगे, जिनसे हम भी, यदि सम्भव हो सके तो, तदनुरूप न उठा सकें।

२ “नया चीन” पुनर्निर्माण के पुनीत पथ पर शीघ्रतम गति से अग्रसर हो रहा है। वहा की सर्वतोमुखी उन्नति, सवमुच, हमें चकित करने वाली है। हम जिस क्षेत्र और जिस विषय का भी अव्ययन करने की ओर मुडते हैं तो ऐसा लगता है, मानो चीन की सारी शक्ति उसी क्षेत्र या विषय के सुधार और उन्नति की ओर लगी हुई है। परन्तु वास्तविकता इससे सर्वथा भिन्न है, और यह वह है कि आज चीन हर क्षेत्र में हर विषय की ओर तूफानी गति से सुधार, उन्नति और प्रगति के लिये जुटा हुआ है। चीनी सरकार, चीनी नेता, चीन के कार्यकर्ता और थोडी भी समझदारी तथा विवेक-बुद्धि रखनेवाला एक-एक चीनी आज अपना सबसे पहला और सबसे बडा कर्तव्य राष्ट्रनिर्माण के कार्य में पूरा योग देना और उसके लिए अपनी सारी शक्ति लगा देना मानता है। आज वहा के विवेकशील व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ एव हानि की अपेक्षा देशके लाभ एव हानि की बात अधिक सोचते हैं और इस सिद्धान्त को सामने रख कर ही सारा काम करते हैं। “माओ के चीन में” के लेखक श्री देवव्रत के ये शब्द “नया चीन” के पुनर्निर्माण की मनोवैज्ञानिकता के द्योतक हैं। वास्तव में, चीनी, सन्नष्टिवादी एव राष्ट्रवादी हो गए हैं। राष्ट्रहित के सामने व्यक्तिगत स्वार्थों को तिलाजलि देते जा रहे हैं।” समस्त चीन की मुक्ति और स्वराज्य स्थापना के वाद वे आज भी राष्ट्र निर्माण के लिये अधिक-से-अधिक त्याग और बलिदान करके अधिक-से-अधिक सेवा और परिश्रम करके आदर्शरूप में अपना आचरण और अपना कार्य देश और समाज के सामने रखते हैं। यह है साराश श्री देवव्रत के उन प्रत्यक्ष अनुभवों का जिन्हें

उन्होंने चीन में धूम-धूम कर प्राप्त किया था। इस प्रकार हम देखने हैं कि नया चीन अपने पुनर्निर्माण की योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए प्राण-पण से लगा हुआ है और अपनी सम्पूर्ण शक्ति, बुद्धि एवं विवेक, गलित पुरातन रूढ़ियों को नष्ट करने तथा स्वस्थ समाजनीति, अर्थनीति के प्रतिष्ठापन में लगा रहा है। उसकी बलशाली योजनाओं में एक अन्यतम योजना थी भूमि-समस्या का समाधान। इस समाधान को हृदयगम करने के पूर्व हमें, बहुत ही संक्षेप में, साम्यवादी दृष्टिकोण पर ध्यान देना होगा, क्योंकि "नया चीन" के प्रमुख नियामक एवं विधायक माओत्सेतुंग साम्यवादी हैं। यद्यपि "नया चीन" बहुत सी बातों में नये मार्गों का निर्माता कहा जाता है किन्तु मौलिक रूप से उसकी योजनाओं की प्रतिष्ठा मार्क्सवादी एवं साम्यवादी आचारों पर आधारित है।

(३) मार्क्सवाद मानवी रचनात्मक एवं उत्पादन क्रिया को सर्वोच्च मौलिक व्यावहारिक क्रिया मानता है और उसे सभी प्रकार की क्रियाओं का निर्धारक समझता है। मानव अपनी सचेतता या जानकारी में भौतिक उत्पादन की क्रिया पर आधारित होता है। क्रमशः प्रकृति के तत्त्वों को, उसकी विशिष्टताओं को, उसके नियमों को तथा मानव एवं प्रकृति के सम्बन्धों को समझता है और उत्पादन एवं रचनात्मक क्रिया के द्वारा वह क्रमशः पारस्परिक मानवी सम्बन्धों के विषय में तदनुकूल मात्रा में ज्ञान ग्रहण करता है। उत्पादन क्रिया से दूर हो इस प्रकार का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। वर्गहीन समाज में प्रत्येक व्यक्ति समाज की सदस्यता के साथ-साथ अन्य सदस्यों से सहयोग करता है, उनके साथ उत्पादन सम्बन्ध स्थापित करता है और भौतिक समस्या के समाधान के लिए उत्पादन क्रिया में सलग्न होता है। मार्क्सवाद की यह धारणा है कि मानव समाज में उत्पादन क्रिया निम्नतर स्तर से उच्चतर स्तर की ओर क्रमशः उभरती है और परिणामतः समाज एवं प्रकृति सम्बन्धी मानव-ज्ञान निम्नतर स्तर से उच्चतर स्तर की ओर क्रमशः उन्मुख होता है, अर्थात् छिछले स्तर से गम्भीर स्तर की ओर तथा व्यष्टि से समष्टि की ओर। युगों तक मानव समाज इतिहास को विचित्र ढंग से पढ़ता आया है, उसने शोषक वर्गों की एकपक्षीय धारणाओं में ही विश्वास किया है और फलतः समाज का इतिहास विकृत रूप में ही उपस्थित हो सका है। आज जब अर्वाचीन मजदूर-किसान या सर्वहारा अपने विशाल उत्पादन को लेकर उपस्थित हुआ तभी मानव ने सर्वांगीण रूप से मानव-समाज के विकास का ज्ञान प्राप्त किया।

बहुत ही संक्षेप में हमने मार्क्सवादी दृष्टिकोण का परिचय दिया, किन्तु इस लेख की भूमिका के रूप में इतना ही पर्याप्त है। "नया चीन" को राष्ट्रीय योजनाएँ मार्क्सवादी दृष्टिकोणों पर ही आधारित हैं।

(४) प्राचीन चीन अर्द्ध-सामन्ती एवं अर्द्ध-औपनिवेशिक देश था। सामन्ती शासकों, देशीय शोषकों तथा विदेशी साम्राज्यवादी आक्रमकों की अनगिनत पीढ़ियों ने निर्मम व्यवहारों, शोषण एवं लोभहर्षक अत्याचारों से चीनी जनता को पीस डाला था। चीनी जनता अपने अधिकारों से पूर्णरूपेण वंचित थी और उसे अधकार एवं अभाव के गर्त में रखा गया था। वह दारिद्र्य एवं परतंत्रता की बँडियों में युगों से ब्राहि-ब्राहि कर रही थी। किन्तु "चीनी जनता के स्वातन्त्र्य युद्ध" तथा "जनक्रान्ति" की

विजयों ने सामन्त प्रथा, साम्राज्यवाद एवं नौकरशाही, पूँजीवाद के शासन को सदा के लिए मिटा दिया है। "नया चीन" ने जन्म लिया है। चीन के लम्बे इतिहास में प्रथम बार स्वस्थ, शान्तिप्रिय एवं समृद्धिशाली जीवन के वातायन खुले हैं। लगभग तीन दशकों तक चीनी जनता ने साम्यवादी दल की अग्रगण्यता में बड़ा धैर्य एवं हठवादिता के साथ शत्रुओं से लोहा लिया। जनता की मुक्ति सेना ने जनक्रान्ति की सफलता के साथ साम्राज्यवादी, सामन्तवादी एवं नौकरशाही पूँजीवादी शासक का अन्त किया। इस प्रकार जनक्रान्ति सफल हुई और तत्पश्चात् साम्यवादी दृष्टिकोणों के आधार पर जन-जन के कल्याण के लिए योजनाएँ बननी आरम्भ हो गयीं। जनक्रान्ति से ही भूमि-समस्या का समुचित समाधान हो सका।

(५) "नया चीन" जनक्रान्ति के उपरान्त ही भूमि-समस्या के समाधान में सलग्न हो गया। सामन्ती शोषण के अन्त के लिए एक बड़े संघान्तिक युद्ध की अनिवार्यता स्पष्ट हो गयी और साम्यवादी दृष्टिकोण से ही भूमि-समस्या का समाधान किया गया। "नव कृषक दल" ने एक सम्मिलित मोर्चा स्थापित किया। सामन्त प्रथा से युद्ध लेना नवयुवक कृषक दल का ही कार्य था। फलतः इस दल ने इस विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त की। युगों से चली आती हुई भूपति शक्ति अपरिमित थी। भूपतियों ने कृषकों को अपने दृढ़ पैरों के नीचे बड़ी निर्दयतापूर्वक दबा रखा था। नवयुवकों को ही इस विषय में उभारा गया और उन्होंने "मिया का जूता मिया का सर" वाली कहावत चरितार्थ की। कृषकों के दल स्थापित किए गए। "जब तक कृषक स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक नया चीन का निर्माण नहीं हो सकता" का नारा बुलन्द किया गया और चीनी क्रान्ति की यही प्रमुख समस्या मानी गयी। आज चीनी क्रान्ति इस विषय में विजयोल्लास से मच्च है। यह समस्या एक लोकसत्तात्मक आन्दोलन के रूप में ली गयी और भूमि-मुक्ति के रूप में परिणत हो गयी। चीन के वर्तमान इतिहास में यह एक सर्वोच्च आन्दोलन माना जाता है। इसके द्वारा करोड़ों-करोड़ कृषकों को स्वतंत्रता मिली और मिला उन्हें नया जीवन और नया उन्नयन-उत्सव।

(६) चीन की जनसंख्या लगभग ५० करोड़ है। इसका क्षेत्रफल ९५ लाख ९७ वर्ग किलोमीटर है, जो यूरोप के पूरे क्षेत्रफल से भी अधिक है। जनक्रान्ति के पूर्व केवल १० प्रतिशत चीनियों के पास, जिनमें मुट्ठी भर भूपति एवं घनी कृषक थे, लगभग ८०-९० प्रतिशत भूमि थी। जनसंकुल चीन में इसका तात्पर्य यह था कि करोड़ों कृषक निस्सहाय थे, वे या तो कट्टे-दो कट्टे भूमि खण्डों पर जीवित थे या उनके पास कुछ भी भूमि नहीं थी, वे या तो भूपतियों के ऋणी थे या 'महाजनो' के वश में थे। भूपतियों की शक्ति विशाल थी, वे बेगारी लेते थे और अपनी कोठी में ऋणी कृषकों को बंदी बनाके रखते थे और ग्रामीणों के जीवन-मरण के नियामक थे। कृषकों से भूमि छीनने के लिए जमीन्दार उन्हें मार डालते थे अथवा उनकी असहाय अवस्था से लाभ उठा उनकी जमीनें छीन लेते थे। इस कुत्सित एवं अमानुषिक भूमि-प्रणाली के विरुद्ध चीन के साम्यवादी दल ने सर्वत्र लेना आरम्भ कर दिया। इस दल ने जनता की सामूहिक शक्ति को उकसाया और उसे भूपतियों की शक्ति को तोड़ने एवं सामन्ती भूमि-व्यवस्था को नष्ट करने के लिए भरपूर उभाड़ा। "खेतियार की भूमि मिले" का तुमुलोद्घोष किया गया। कृषकों को

प्रथम वर्ष में निर्धारित उपज का ही उपयुक्त प्रतिशत देना पड़ता है। मुक्ति मिलने के पूर्व किसानों को अपनी उपज का लगभग ७० प्रतिशत गलना जमीन्दारों को दे देना पड़ता था। क्या पूछना था, भारत के जमीन्दारों की भाँति चीनी सामन्तो, जमीन्दारों और बड़े किसानों के घरो और बाजारों में लाखों मन अन्न चला जाता था। आज स्थिति बिल्कुल पलट गयी है। सारा-का-सारा अनाज किसानों के घरो में रह जाता है। आज भूमि किसानों की अपनी है। अतः भरपूर परिश्रम करके वे उपज बढ़ाते जा रहे हैं।

आज चीन सप्ताह का सबसे अधिक अनाज उत्पन्न करनेवाला देश है। गत वर्ष यहाँ कुल १६३,७५०,००० टन अनाज उत्पन्न किया गया। चावल की वार्षिक उपज यहाँ ५ करोड़ से ६ करोड़ टन तक है, अर्थात् विश्व का एक तिहाई से भी अधिक चावल वही उत्पन्न होता है। गेहूँ उत्पन्न करनेवाले देशों में इसका तीसरा स्थान है और विश्व की आधी चरी और ज्वार भी यही उत्पन्न होता है। किन्तु इतना होते हुए भी, १७२१ से १९४९ तक इसे अपनी आवश्यकताएँ प्रतिवर्ष बाहर से अन्न मगाकर पूरी करनी पड़ती थी।

केन्द्रीय लोक सरकार ने अपनी पूरी शक्ति को पुनः सुव्यवस्थित एवं विकसित करने में तथा अनाज की उपज बढ़ाने में लगायी है। भूमि सुधार, परस्पर सहायता और कृषि सहकारिता का विकास, विशाल जल सुरक्षा योजनाएँ, भारी-भारी ऋण तथा लोक सरकार से सीवी किसानों को दे दी गयी। अन्य सहायताएँ आदि से अनाज की उपज बहुत बढ़ गयी है।

भूमि सुधार ने लगभग ४० करोड़ से भी अधिक किसानों का उद्धार किया और उन्हें कृषि में एक बहुत ही क्रियात्मक और प्रभावशाली भूमिका अदा करने का अवसर दिया। इससे वह ३ करोड़ टन अनाज भी उनके पास ही बचा रह गया जो पहले वार्षिक लगान के रूप में बन्द हो जाता था। पुराने समय में उसका अधिकतर भाग सट्टेबाजी के काम आता था। भूमि सुधार के पश्चात् आज किसानों के पास न केवल अपनी आवश्यकताओं के योग्य अनाज है, बल्कि उससे कहीं अधिक है। वे उसे नफ़ेदारों पर बेच सकते हैं और उस रकम से अपने खेतों की काफी उन्नति कर सकते हैं।

चीन अपनी खाद्य समस्या को आखिरी तीर पर और निश्चित रूप से समाधान दे देगा। वह पूरे विश्वास के साथ उस दिशा की ओर बराबर आगे बढ़ रहा है। इसके लिए वह आज भूमि-सुधार, परस्पर सहायता और सहकारिता का विकास, खेती के नवीनतम तरीकों का उपयोग, मशीनों द्वारा खेती और उसके लिए आवश्यक औद्योगिकरण तथा नए सिरे से सोच-समझकर योजनानुसार बटवारा आदि तरीकों को अपना रहा है। ये वे तरीके हैं जिनका विकास मोवियत सब के सफल अनुभवों के आधार पर हुआ है।

(१०) "नय चीन" सैद्धान्तिक रूप से साम्यवादी दृष्टिकोण रखता है, किन्तु अपनी समस्याओं के समाधान में वह लकीर का फकीर ही है। समयानुसार व्यवस्था तथा पुनः उसका परिवर्तन जन-कल्याण की दृष्टि में रचकर किया जाता है। चीनी सरकार और साम्यवादी दल

ने यह समझा कि व्यक्तिगत छोटी खेती से उत्पन्न होनेवाली कठिनाइयों पर अधिकार पा लेने के लिए, जिससे कि उद्योगों के शोचगामी विकास के लिये कच्चा माल मिल सके और किसानों की आमदनी या ऋण-शक्ति में बढ़ती हो, जिससे औद्योगिक माल की खपत के लिए आन्तरिक बाजार का विकास और प्रसार हो, किसानों में "संगठित हो" का सिद्धान्त कार्यान्वित किया जाय। अतः "संगठित हो" के सिद्धान्त को खूब बढ़ावा दिया गया और किसानों को परस्पर लाभ के आधार पर सहकारिता या परस्पर सहायता के लिए प्रोत्साहित किया गया। वर्तमान स्थिति में इसका अर्थ है निजी सम्पत्ति के आधार पर सहकारिता और सहयोगी-श्रम जो कालान्तर में सामूहिक तथा समाजवादी खेती का रूप पकड़ लेगा।

(११) ऊपर के प्रकरणों में हमने देखा कि चीन के साम्यवादी दल के अध्यक्ष तथा महान नेता माओ त्से-तुंग के नेतृत्व में चीन के किसानों ने भूमि समस्या का समाधान कर लिया और सामन्त प्रथा का पूर्णतः विनाश कर दिया है। इस सफलता के आधार पर उन्होंने अपने नेताओं की पुकार पर कृषि उत्पादन के विकास के लिए तथा भूमि समस्या के वास्तविक समाधान के लिए तीन प्रकार की सहकारिता के आन्दोलन का सहारा लिया है। (१) प्रथम प्रकार की सहकारिता का स्वरूप है एक सीवी-सर्वी अस्थायी मौसमी परस्पर सहायता दल की योजना, (२) द्वितीय प्रकार की सहकारिता वर्ष भर चलनेवाले सहायता दलों की योजना तथा (३) तृतीय और सबसे अधिक विकसित सहकारिता का स्वरूप है कृषि उत्पादकों की सहकारी संस्थाओं की योजना।

परस्पर सहायता तथा सहकारिता का आन्दोलन सर्वप्रथम सन् १९४९ ई० में उत्तरी चीन में आरम्भ हुआ। परस्पर लाभ के लिए निजी सिद्धान्त के आधार पर इस प्रकार की योजनाएँ बनायी गयीं। भूमि के निजी स्वत्व के आधार पर मिलजुल कर पारस्परिक सहयोग से श्रमदान की क्रिया ही इस प्रकार के आन्दोलन के मूल में है। इस प्रकार की योजनाओं का स्वरूप, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, त्रिधा है। प्रथम कोटि में मौसमी परस्पर सहायता दल आते हैं। जुलाई-बुनाई या कटाई के समय आपस में दल बनाकर एक दूसरे के काम में सहायता का यह ढंग सहकारिता की प्रथम मजिल है। एक पड़ोसी के सहायतार्थ अन्य पड़ोसी कुछ दिनों तक काम करते हैं और बाद को वह पड़ोसी अन्य पड़ोसियों की सहायता करता है। इस योजना से सबका काम चल जाता है और सहकारिता का मूल्यांकन भी हो जाता है। इससे श्रमदान का मूल्य एक तिहाई और बढ़ जाता है।

द्वितीय कोटि में वर्ष भर चलनेवाले सहकारी दल आ जाते हैं। इन दलों की सदस्यता स्थायी होती है। सभी सदस्य वर्ष भर एक दूसरे की सहायता के लिए सन्नद्ध रहते हैं। श्रम विभाजन से श्रम की योग्यता बढ़ जाती है। कुछ सदस्य अन्य काम करके सदस्यों की कमायी बढ़ा देते हैं। कुछ सदस्य इस प्रकार वाहरी धन कमा कर कृषि-यन्त्र तथा अकाल के समय के लिए पशु आदि खरीद लेते हैं और इस प्रकार आर्थिक सहकारिता का रूप निर्धारित करते जाते हैं। व्यक्तिगत कृषि से परस्पर सहयोग दल की योजना कहीं बढ़कर उपादेय होती है। इससे उत्पादन बढ़ जाता है और कृषकों की रहन-सहन का माप दंड बढ़ जाता है।

तृतीय कोटि है कृषि उत्पादको की सहकारी संस्थाओं की जो सह-कारिता आन्दोलन का सबसे विकसित स्वरूप है। इसमें कृषक अपनी भूमि को हिस्से के रूप में देकर सहकारी संस्थाओं में सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार इसका नाम है कृषि सहकारी समितिया। कृषि के साथ-ही-साथ अन्य धन्वों का विकास, एक सीमा तक योजना बना कर उत्पादन में उन्नति, श्रम-विभाजन और कुछ उन्नत कृषि यन्त्रों, पशुओं या अन्य सम्पत्ति की सम्मिलित मिल्कित आदि कुछ कृषि सहकारी समितियों की विशिष्टताएँ हैं। इसके अतिरिक्त मजदूरी या वेतन काम किये गये दिनों के हिसाब से दिया जाता है और मेहनत के अनुसार वोनस दिया जाता है। चीन के समाज शास्त्री इन विशेषताओं और खासकर सम्पत्ति के सामूहिक स्वामित्व में समाजवादी तत्त्व देखते हैं। अब हम नीचे भूमि समस्या के समाधान के निमित्त उत्पन्न भूमि सुधार एवं तज्जन्य योजनाओं के लाभों पर संक्षेप में दृष्टिपात करेंगे।

(१२) परस्पर सहायता तथा सहकारिता के आन्दोलन ने कृषि उत्पादन तथा देहाती जीवन पर बड़े ही क्रान्तिकारी प्रभाव डाले हैं। इन प्रभावों को हम तीन विशिष्ट प्रभावों में बाट सकते हैं। प्रथम विशिष्ट प्रभाव है कृषि उत्पादन तथा कृषकों की कमायी में वृद्धि। सन् १९५२ में उत्तरी चीपू के सगठित कृषकों ने कृषि उत्पादन की वृद्धि, कृषि यंत्रों के संग्रह, जोतने की प्रक्रिया में सुधार, कृषि सम्पत्ति के निर्माण तथा प्राकृतिक आपदाओं से रक्षा के लिए विस्तार के साथ सक्रियता प्रदर्शित की। इसके परिणामस्वरूप कृषि उत्पादन बड़ी तेजी से बढ़ा, जैसा कि हमने प्रकरण ९ में देख लिया है। अनुभवों से यह व्यक्त हो गया है कि परस्पर सहयोग एवं सहायता दलों तथा सहकारिता से उत्पादन की शक्ति कई गुनी बढ़ जाती है।

दूसरा शक्तिशाली विशिष्ट प्रभाव है गरीबी का दूर हो जाना तथा दिवालियापन का अभाव। जब से भूमि सुधार हुआ है शोषण का कहीं भी कोई चिह्न दृष्टिगोचर नहीं हुआ और न किसी प्रकार की बेगारी देखने में आयी। जिन भू मागों में अभी सहकारिता का आन्दोलन नहीं चल सका है, वहाँ की जनता सहकारिता से सुव्यवस्थित स्थानों की जनता से बहुत ही सुखी है। इससे स्पष्ट है कि केवल भूमि सुधार से भूमि समस्या का समाधान नहीं हो सकता, प्रत्युत, भूमि सुधार के पश्चात् सक्रिय सहकारी योजनाओं का प्रचलन अति आवश्यक है।

तीसरा विशिष्ट प्रभाव है कृषकों की विचारधारा में परिवर्तन। अब कृषकों की जीवन-सम्बन्धी सुविधाओं से उनके जीवन-यापन के उपकरणों में परिवर्तन हो गया है। गावों में राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक जीवन का स्तर बहुत ऊँचा हो गया है। पुस्तकालयों की स्थापना हुई है। पत्र-पत्रिकाओं का पठन-पाठन आरम्भ हो गया है। इस प्रकार सहकारिता आन्दोलन से देहाती जीवन से अज्ञानता का अन्वकार दूर होता जा रहा है।

सामाजिक चेतना बढ़ती जा रही है। पहले आवश्यकता पड़ने पर एक कृषक अपने नातेदारों अथवा पड़ोसियों के सामने हाथ पसारता था किन्तु अब परस्पर सहायता के दलों एवं सहकारी संस्थाओं से सहायता

लेना सरल हो गया है। नर-नारियों में श्रम सम्बन्धी किसी भी प्रकार का विभेद नहीं रह गया है। स्त्रियों का सामाजिक उन्नयन हो गया है। अब माओत्सेतुंग के निम्न शब्द अक्षरशः सत्य जचते हैं।

जब एक वार सगठन सम्पूर्ण कृषक मंडल द्वारा आचरणजन्य मान्य लिया जायगा तो न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी, प्रत्युत कृषकों के राजनीतिक जीवन का स्तर ऊँचा उठ जायगा। तब वे अपने स्वास्थ्य की अधिक चिन्ता करेंगे। आवागमन का नाश होगा और सदाचारों में नयी प्रवृत्तियाँ आएंगी वास्तव में, भूमि-समस्या के समाधान का यही अन्तिम स्वरूप है।

(१३) भूमि समस्या के सम्बन्ध में चीनी दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया। ऊपर के प्रकरणों में इस समस्या के समाधान के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। अब हम कुछ सामान्य कठिनाइयों का उद्घाटन करते हैं। इस सिलसिले में हम यह भी देखेंगे कि "नया चीन" ने इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया।

भूमि सुधार के पश्चात् परस्पर सहायता की योजना तथा सहकारिता के आन्दोलन के स्थापन में कई प्रकार की कठिनाइयाँ थीं और साथ-ही-साथ स्पष्ट है कि कृषकों की वैयक्तिक सम्पत्ति की जो सामयिक स्वीकृति प्रदान की गयी वह कालान्तर में परिवर्तित होगी ही, किन्तु सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण के पूर्व व्यक्तिगत सम्पत्ति की स्वीकृति कई कारणों और कठिनाइयों को सामने रखकर हुई। चीन में जो भूमि समस्या का समाधान हुआ है तथा जिस प्रकार भूमि सुधार की योजनाएँ कार्यान्वित हुई हैं वे केवल सामन्ती प्रथा को दूर कर कृषक भूमि स्वामित्व के रूप में उपस्थित हैं। यह मान लिया गया है कि वर्तमान चीन की आर्थिक दशाओं में व्यक्तिगत छोटी-मोटी कृषक सम्पत्ति बहुत दिनों तक चलती रहेगी और यह भावात्मक रूप में ही उपस्थित रहेगी, किन्तु यह वास्तविक भूमि प्रवन्ध में एक प्रकार की कठिनाई के समान है। भूमि सुधार के पश्चात् मध्य कोटि के कृषक अधिक संख्या में बढ़ गए अतः उनके बीच एकता का स्थापन अनिवार्य हो गया। यदि सगठन में कृषक नहीं आते अथवा वे सहकारी समितियों के द्वारा कार्यशील नहीं होते तो यह सम्भव था कि अब भी कुछ बड़े कृषक शोषण की प्रवृत्ति में सलग्न हो जाते। अतः माओत्सेतुंग के कथनानुसार सगठन में आना अत्यन्त आवश्यक हो गया। इसलिए सगठन की नीति को प्रसारित किया गया। इसके उपरान्त कृषिगोली को विकसित की गयी। किन्तु प्राचीन शैली से मोह रखनेवाले कृषकों के ममक्ष नयी शैली का विकास दुष्कर सा था, अतः उन्हें कई प्रकार से शिक्षित किया गया। जब सर्व प्रथम कपास के बीज को गर्म पानी में डाल कर बोने, मक्के को अत्राकृतिक ढंग से परागित करने तथा रासायनिक ढंग से बीज बढ़ाने की शैली प्रसारित की गयी तो कृषकों को यह सब अमान्य था। जब कुछ विशिष्ट कृषक सदस्यों ने नयी शैली में कृषि उत्पादन बढ़ाया तो अन्य कृषक दल भी तैयार हो गए। इस प्रकार क्रमशः भूमि समस्या को भूमि सुधार सम्बन्धी कानूनी, परस्पर सहयोग, सहकारिता आन्दोलन तथा अन्य वैज्ञानिक, प्रक्रियाओं में हल किया गया।

# आर्यों की ग्राम पंचायतें और उनकी चुनाव व्यवस्था

श्री प्रभाकर माचवे

प्राचीन भारतीय आर्य गणराज्यों में निम्न प्रकार से प्रातिनिधिक सस्याएँ हुआ करती थी

क्र. सं.	घटना	मिट्टी का हिस्सा	राज्य का नाम	राज प्रतिनिधि	प्रजा प्रतिनिधि
१	५ से १० इन्द्रिय	शरीर	स्वामी	आत्मा	बुद्धि
२	५ से १० शरीर	कुटुम्ब	गृह घर	गृहपति	गृहिणी
३	५ से १० कुटुम्ब	कुल	वाटी वाडी	कुलपति	पुरएता
४	५ से १० कुल	पेठ जाति	खेट खेडा	ग्रामाधिप	ग्रामणी
५	५ से १० पेठ	गाव	ग्राम मडल	गोप	नेता
६	५ से १० गाव	शहर	नगर	नगराधिप	नगरप्रणिधि
७	५ से १० शहर	जिला	जनपद	समाहर्ता	माडलिक
८	५ से १० जिले	प्रान्त	राज्य	राजा	ग्रामात्य
९	५ से १० प्रान्त	देश	महाराज्य	महाराजा	सभासद
१०	५ से १० देश	पृथ्वी	पारमेष्ठ्य	सावभौम	मन्त्री
११	५ से १० पृथ्वी गृह	जगत्	स्वराज्य	प्रजापति	सावित्री
१२	५ से १० जगत्	मृष्टि या विश्व	त्रैराज्य	विष्णु पुरुष	प्रकृति

मानव देह से विराट् स्वरूपी परमेश्वर तक इस प्रकार का विभाजन था। नुविधानुसार राज प्रतिनिधि एक अकेला अधिकारी होता और प्रजा प्रतिनिधि एक या अनेक हो सकते थे। कार्य भेदानुसार प्रजाप्रतिनिधि अधिक हुआ करते थे। उनके सघों के नाम अलग-अलग हुआ करते थे।

१ कुल	एक आचार-विचार के लोगो का समूह	अगरेजी फँमिली
२ जाति	वश परंपरा से एक पेशा करनेवालो का समूह	गिल्ड या कास्ट
३ वर्ग	एक व्यवसाय में लगे लोगो का समूह	क्लास
४ सघ	कार्य-विशेष के लिए की हुई एकता	यूनियन
५ समिति	खास काम करने के लिए चुनी हुई मडली	कमेटी
६ मडल	गाव-गाव घूमनेवालो समिति	बोर्ड या कमीशन
७ परिषद	साधारण विचार-विनिमय के लिए जुटी मडली	असेम्बली
८ सदस्य	एक विषय की चर्चा करनेवालो मडली	असोसियेशन
९ सभा	कार्यकार्य निश्चित करनेवाली मडली	काउन्सिल
१० सत्र	सावदेशीय कानून बनानेवाली सस्या प्रतिनिधि के सामान्य लक्षण है, 'तद्वर्भास्याद्'। असत्ति सिद्धश्च'। इस सूत्र का स्पष्टीकरण प्रजापति स्मृति में इस प्रकार से किया गया है 'निधोजस्यस्य तुय कार्यं स्वात्मभावेन पश्यति।' इसका अर्थ है जो व्यक्ति अपने को चुननेवाले आदमियो का काम अपना ही काम मानता है वह सच्चा प्रतिनिधि है। आजकल चुननेवाले और चुने गये एक ही सी योग्यता के होते हैं। यह बात तब नहीं मानी जाती थी। चुना गया व्यक्ति अधिक योग्यतावाला व्यक्ति अवश्य ही होता था। नियम-अधिनियम बनाने का काम श्रेष्ठ लोक प्रतिनिधियो के पास, उन्हें कार्य में उतारने का काम राज-प्रतिनिधियो के हाथ और राज्य कार्य के लिये आवश्यक पैसे मजूर करने का और देने का काम सामान्य जनता के हाथों में था। इस त्रैवर्णिक व्यवस्थामें कोई भी एक वर्ग सिर पर नहीं चढ़ सकता था और सबको यथोचित सुविधा मिलती थी।	कांग्रेस

मुख्य बात है सही आदमी का चुनाव। आदमी की योग्यता निश्चित करने के लिए प्राचीन ग्रन्थकारो ने ये नियम रखे थे

“वित्त बधु कर्मजाति विद्यावयासिमान्यानि । धर्मसूत्राणि अ० ६. श्रुततु सर्वभ्यो गरीय । पदपेक्षस्तद्वृत्ति । धर्मसूत्राणि अ० ८ वित्त बधुर्वय कर्म विद्या भवति पचमी ।

एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यद्यदुत्तर ॥ मनुस्मृति २।१३६ ।

वयोवधुश्च वित्तच विद्याधारण तथा ।

एतानि मान्यस्थानानानि गरीयो यद्यदुत्तर ॥ भृगुसहिता

वय का अर्थ है जन्म के बाद बीती हुई आयु। वधु का अर्थ है मनुष्य की सहायता के लिए आनेवाला व्यक्ति। वित्त अधिकार में जो संपत्ति है उसे कहते हैं। विद्या उपलब्ध ज्ञान को कहते हैं और आचरण में आदतें शुमार होती हैं। इन पांच बातों पर आदमी की योग्यता अवलंबित थी। और इनमें तारतम्य है। आयु से जो बड़प्पन मिलता है वह तो स्वाभाविक है, अतः वह सबसे हलका है, उससे बड़ा वह है जो उच्च कुल का हो, उससे भी बड़ा वह है जो पैसेवाला हो। परन्तु पैसे से ज्यादा बड़ा विद्यावाला है, यह स्पष्ट है। अन्त में आचरण की श्रेष्ठता को सबसे बड़ी योग्यता माना गया है, यह बात ध्यान में रखने लायक है। इन पांच बातों को विस्तार में चर्चा यहाँ की जाती है।

आयुर्वेद के अनुसार 'आषोडशाद्बृद्धि' है। कौटिल्य के अनुसार बारह वर्ष की लड़की और सोलह वर्ष का लड़का सज्ञान माना जाता है। द्वादश वर्षा स्त्री प्राप्त व्यवहारा भवति। षोडशवर्ष पुमान्। षोडशाब्दा च या स्त्रोस्यात्त्वर्चविंशतिक पुमान्। वाग्भट्ट आदि अन्य शास्त्रकारों के अनुसार सोलह वर्ष की स्त्री और बीस वर्ष का लड़का स्वतंत्राचरण के योग्य माने गये हैं। मतदान की आयु-मर्यादा भी इसीके अनुसार रखी जाती थी। उपनयन में १६ से २४ तक वय सही माना जाता था, बाद में वह "व्रात्य" होने के लायक नहीं रहता था। ग्राम पचायत में १६ वर्ष और राजकीय कार्य में २४ वर्ष की वयोमर्यादा मतदान के लिए मानी जाय, ऐसा अलिखित नियम था।

किसी भी काम के करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को कम-से-कम वधु आवश्यक थे, एक पुरस्कृता, एक अनुभन्ता। वधु का अर्थ था उस काम से बड़ा हुआ, जिसमें उसके हाथ गुंथे हैं ऐसा सहायक। प्रत्येक मतदाता को कम-से-कम दो वधु थे, मा और बाप। काण्व स्मृति में कहा गया "भातृमान् पितृमान् आचार्यवान् पुरुषोवेद।" इस स्मृति के अनुसार मा काम-पुरुषार्थ की गुरु, बाप अर्थ-पुरुषार्थ का गुरु और आचार्य धर्म-पुरुषार्थ का गुरु है। क्या खायें, क्या पियें, कितना उपयोग लें यह काम पुरुषार्थ के अन्दर आता है, यह मा सिखाती है। पैसे कमाने की अक्ल बाप सिखाता है इस प्रकार से जिसे अधिक वधु हो वह अधिक मान्य है, ऐसा माना जाता था।

वित्त के सम्बन्ध में हवा, पानी तो परमात्मा की देन थी। आज की तरह जल कर (वाटर टैक्स) और शुद्ध हवा के लिए भी उच्च वाटिका होना जरूरी नहीं था। अन्न, वस्त्र और गृह कष्ट से अजित करना पड़ता था। जिसे किसी भी चीज की अपेक्षा नहीं है ऐसा विरक्त अथवा पशुतुल्य मनुष्य मतदाता नहीं हो सकता था।

चतुर्यमायुषा भोग त्यक्त्वा सगान् परिव्रजेन् ॥ मनुस्मृति ६।३३

७५ वर्ष की आयु के बाद सन्यास लेना आवश्यक था। ७५ वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति को मतधिकार भी नहीं था।

भृगुसंहिता में पहले अध्याय में विद्या की परिभाषा इस प्रकार से दी गयी है।

शक्नोमूकोऽपि यत्कर्तुं कलामन्न तु तत्स्मृतं।

यद्यत्-तद्वाचिक सम्यक्कर्म विवेति सज्ञेन ॥

जो काम गूगा भी कर सकता है उसे कला या कारीगरी कहा जाय और जो काम अच्छी तरह से करने के बाद उमकी उत्पत्ति मूँह से ठीक सपसा दी जा सकती है उसे विद्या कहते हैं। कम-से-कम लिखना-पढ़ना आना मतदाता के लिए आवश्यक है। अथर्ववेद में प्राचीन राजाओं का उल्लेख है जो बड़े अभिमान से कहते थे कि मेरे राज्य में विद्वान न हो ऐसा एक भी आदमी नहीं है।

न स्तेवो म जनपदे न कदर्यो न मद्यपी।

नाना हिताग्निविद्वान् न स्वैरी स्वैरिणीकुत ॥

मतदाता अच्छे आचरणवाला होना चाहिये। मतदाता समाज विध्वंसक, समाज के बधन न माननेवाला, समाजवहिष्कृत व्यक्ति नहीं हो सकता। समाज की सुव्यवस्था का निर्माण करनेवाले प्रतिनिधि चुनने का जिन्हें अधिकार हो वह व्यक्ति समाज द्वेषी हो ही नहीं सकता। इस प्रकार से मतदाताओं के वय, वधु, वित्त, विद्या, व्यवहार की चर्चा हो गई।

अब ग्राम पचायत के प्रतिनिधियों के बारे में भी वही पांच साधन देखें तो प्रतिनिधि होने के लिए तीस वर्षों से ऊपर वय होना चाहिये। आयुर्वेद में कहा गया है कि आपचविंशतेषां वन आचत्वारिंशत संपूर्णता। पच्चीस वर्ष तक मनुष्य का मन चल और अस्थिर होता है। चालीस में जाकर वह प्रगल्भ हो जाता है। राजनीति में कूदने से पहले मनुष्य को १ साला में योग्य शिक्षा मिलनी चाहिये २ योग्य रीति से पारिवारिक जीवन वित्ताना आना चाहिये और ३ जहा तक समझ हो दूसरों के लिए कष्ट सहने की और काम करने की शिक्षा मिलनी चाहिये। ग्राम पचायत का प्रतिनिधि बननेवाले की आयु ३० वर्ष, जिला मंडल में पैंतीस और राज-सभा के प्रतिनिधि की आयु चालीस होनी चाहिये। राज सभा में ६० वर्ष से ऊपर आयुवाला कोई सदस्य न हो ऐसा प्राचीन आयु का नियम था।

वधुओं के बारे में कहा गया था कि वधु समवयस्क हो। एक ही गाव में एक ही पेशा करनेवालों में १० वर्ष से वयस्क बड़ा कहा जाता है, उसके अन्दर के सब एक समान, एक-सी कारीगरी में पांच वर्ष के अनुभववाला बड़ा, एक-सी विद्या-सपन्नो में तीन वर्ष से अधिक आयुवाला बड़ा और एक-सा मान प्राप्त करनेवालों में पहले मान प्राप्त व्यक्ति अधिक श्रेष्ठ माना जाय। धर्मसूत्रों के छठे अध्याय में सूत्र है

दशवर्ष वृद्ध पौर। पञ्चभि कलाभर ॥

श्रोत्रियश्चारणास्त्रिभि दीक्षितस्य प्राक्क्रमाद् ॥

और मनु स्मृति के दूसरे अध्याय में १३४वा श्लोक है।

दशावदारथ पौरसद्य पचावदारुण कला भृता।

त्र्यब्द पूर्ण श्रोत्रियाणा स्त्रलेपेनापि स्वयोनिपु ॥

विद्या के सम्बन्ध में कौटिल्य ने चार प्रकार माने हैं। आत्वीक्षिकी, अग्नी, वार्ता और दडनीति चार विद्या हैं। सबल और निर्बल पक्षों का अंतर हेतुओं से जाना जा सकता है और यह हेतु ज्ञान आन्वीक्षिकी विद्या से जाना जा सकता है। धर्मानुविवे चरी विद्या से, अर्थ और अर्थका, अन्तर वार्ता विद्या से और न्याय-अन्याय का भेद दडनीति से जाना जा सकता है। मूल इस प्रकार के हैं



आन्वीक्षिकी त्रयो वार्ता दडनीतिश्चेति चतस्रे विद्या ।  
वलावले आन्वीक्षिक्या, धर्मावर्मात्रैश्च अर्थानधौ वार्ताया,  
नयानमी दडनीत्या । तामिप्रमायोश्च विद्यात्द्विद्याना विद्यात् ।

वित्त के सत्रध में साधारणत यह माना जाता था कि जिस कार्य में जो पैसे देता है उसका मत अत्रय ध्यान में लिया जाय। समाज में सब व्यक्तियों की एक दूसरे से और सबकी पराक्रम-सुरक्षा के निमित्त खेती का काम लिया जाता है और उसका विनियोग न्याय और सैनिक व्यवस्था में किया जाय। इन विषयों में सब व्यक्ति प्रतिनिधित्व के योग्य है यह स्पष्ट ही है। कौटिल्य कहते हैं।

परचक्राट वीभृत तु प्रत्यानीय राजा यथास्व प्रयच्छेत् ।

चोरहृतमविद्यमान स्वव्यभ्य, प्रयच्छेद ।

प्रत्यानेतु अशक्तो वा स्वयग्रहिणाहृत प्रत्यानीय तन्निकय वा प्रयच्छेद ॥ कौटिल्य ३।१६।७०

चोरहृतमपजित्य यथा स्थान गमयेद ।

कोशाद्वा दद्यात् ॥ धर्मसूत्राणि १०।४६।४७ ।

स्नेनाना निग्रहादस्य यशो राष्ट्रच वर्धते । मनुस्मृति ८।३०२ ।

विदेशी आक्रमण के कारण अथवा अन्य तस्करो के कारण किसी का कुछ लुट गया तो राजा वह उसे वापिस लाकर दे। चोर यदि कोई माल ले जाय और वह वापिस न मिल सके तो राजा अपने खर्च से कीमत भरकर दे। जबरदस्ती से जो माल ले जाया जाय उसकी भी व्यवस्था इसी प्रकार से हो। चोर से जेल में काम कराने की जो प्रथा चल पड़ी उसके मूल में भी यही भावना थी कि चोरी की हुई चीज के दाम वसूल किये जाय। कौटिल्य ने यहा तक लिखा है कि "सस्य भक्षणे सस्योपघात निष्पत्तित्। परिसख्याय द्विगुण द्वापयेद ३।१०।६२।" अर्थात् जानवर जितना अनाज फल खा गये है वह नाप-तौल कर उससे दुगुने दाम जानवर के मालिक से वसूल किया जाय।

मतदाता के आचरण पर उलना निर्बंध नहीं है, जितना कि प्रतिनिधि के आचरण पर है। प्रतिनिधि बहुत योग्य व्यक्ति होना चाहिये। वह 'सप्त व्यसन वजित' चाहिये। व्यसन का अर्थ कौटिल्य के अनुसार यह है कि "श्रेयमे, कल्याणकारो, सन्मार्गं से जो किमी को फेंक देता है वह व्यसन कहलाता है" व्यस्यति एत श्रेयसस्तदमद् ८।१।१२७ आगे चलकर कौटिल्य ने बताया है कि प्रतिनिधि किन किन दुर्गुणों से मुक्त हो

१ गाली-गलीज वहन करे,

२ द्रव्य का दुर्हयोग न करे,

३ वह मारपीट न करे, इस प्रकार से यह तीनों बातें कोप या क्रोध से जो उत्पन्न है उनसे बचे और

४ शिकार

५ जूआ

६ वेध्यागमन और

७ शरापत्तरी या अन्य नगार्वारी यह काम से उत्पन्न चार व्यसन उनमें न हो। वह 'परतन तरुगो निम्नुह' हो, यानी दूसरे की स्त्री और धन के प्रति उनमें कोई मोह नहीं होना चाहिये। जब प्रतिनिधि चुना

जाय तब उसके अडोसी-पडोसी से पूछकर उसका शील, बल, स्वास्थ्य सात्विकता जाच ली जाय

"सवासिभ्य शीलबलारोग्य सत्यसत्वयोग परीक्षेत् ।"

ग्राम प्रचायत के काम नीचे लिखे हुआ करते थे

१ गाव में पीने के पानी का इन्तजाम करना।

२ गाव के बच्चों की पढाई की व्यवस्था करना

३ गाव के झगड़े-टटों का फैसला करना

४ गाव से दूसरे गाव को जानेवाले रास्ते ठीक रखना, और

५ गाव के देवालय आदि धार्मिक मामलों का प्रबन्ध रखना ।

इन कामों में पहले और चीथे कामों के लिये गाव का हर आदमी महीने में एक दिन दे या एक दिन की मजदूरी एक मजदूर को दे, इस प्रकार का नियम था। मनु के अनुसार, 'एकैक कार्यैत्कर्म मासि मासि महीपति' ७।१३८ और धर्मसूत्रों के अनुसार "शिल्पिनो मासि मास्ये-कैक अह कर्मकुर्यु नौ चश्रीवतश्च, भक्त तेभ्यो दद्यात् ।" १०।३० से ३६ और बृहस्पति स्मृति में है

'शुल्क दद्यात्तनो मासमेकैक पन्थमेववा ।

अवधिविर मूल्येन वणिजस्ते पृथक-पृथक ॥

कमकर लोग गाव के लिए माह में एक-एक दिन काम करें। नाव-वाले और गाड़ीवाले भी वंसा ही करें। उस दिन उन्हें मुफ्त भोजन मिले। और लोग बिना मजदूरी लिए मजदूरी दें। इसी तरह से पहले बड़े-बड़े काम होते थे। और कामों के लिए प्रत्येक परिवार अपने निर्वाह के बाद बचे रहनेवाले द्रव्य का पाचवा हिस्सा दें ऐसा नियम था।

"पचाशद् भाग आदेयो राज्ञा पशु हिरण्ययो" मनुस्मृति ७।१३०

"पशु हिरण्ययो पचाशद् भाग" धर्मसूत्राणि ३।१० सू० २४

"कुटुम्ब पोषण कुर्यान्नित्य कोशाच वर्धयेद् ।"

अन्यत्रापत्तित कोशादेव ग्राह्य च नेतेराद् ॥" व्याघ्र स्मृति ।

कुटुम्ब पोषण के बाद बचनेवाले द्रव्य पर यह कर था। अकाल इत्यादि की स्थिति में यह कर माफ कर दिया जाता था। खेती की उपज बेचकर पशु या सोना मोल लेते थे उस पर यह कर था।

गाव के लडाई-झगड़े के निबटारे का काम पंच नि शुल्क करते। उनके काम में व्यवहार की रीति समझानेवाले सहायक लोग हुआ करते थे। धर्मसूत्रों के ग्यारहवें अध्याय में लिखा है कि किसान-व्यापारी, गडेरिए, सर्राफ, कारीगर आदि अपनी मदद के लिए अपने-अपने वर्ग से व्यक्ति लें। यह सहायक सख्या में तीन से अधिक न हो। इनसे पद्धति या रुढि पूछकर उसके अनुसार निर्गम दिया जाय। न्याय देते समय अनुमान पर भी अधिक ध्यान दिया जाता था।

कर्षक वणिक्पशुपाल कुरीदि कारव स्वैस्वैवर्गो ।

स्ववर्गो अथवराधर्मान्प्रशुन्यायात्रिग में तर्कोभ्युपाय

तेभ्यो यथाधिकारमयन्प्रित्यवहृत्य धर्म व्यवस्था ।

राजा जब तक प्रजा को गुणवत्ता का पूर्ण प्रबन्ध न करे, तब तक वह कर लेने का अधिकारी नहीं था।

# भारतीय कृषि का एक महान रोग

## श्री अरुनींद्र कुमार विद्यालंकार खेतों का विभक्तिकरण

विश्व की दो तिहाई आबादी आर्थिक दृष्टि से पिछड़े प्रदेशों और इलाकों में रहती है। इन प्रदेशों की मुख्य समस्या गरीबी है। गरीबी का मुख्य कारण है कि इन प्रदेशों के किसान गरीब हैं। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों की अधिकांश आबादी के जीवन का सहारा खेती है। इनके आर्थिक तंत्र का आधार खेती है। किस महादेश में जनसंख्या का कितना बड़ा भाग खेती में लगा हुआ है, यह निम्न तालिका से स्पष्ट है :

### खेती में विश्व आबादी का अनुपात १९४९

क्षेत्र	कुल आबादी लाखों में	खेतिहर आबादी लाखों में	खेतिहर आबादी कुल आबादी के अनुपात में
उत्तरी अमेरिका	१६३०	३३०	२०
यूरोप	{ २६१० १२०	{ १२६० ४०	{ ३३ ३३
दक्षिण अमेरिका	१०७०	६४०	६०
मध्य अमेरिका	५००	३३०	६७
एशिया	१२५५०	८७८०	७०
अफ्रीका	१६८०	१४६०	७४
विश्व का कुल	२०७६०	१२८७०	३५७

विश्व की कुल आबादी का ६० प्रतिशत या लगभग १३० करोड़ लोग खेती पर आश्रित हैं। इनमें से एक अरब से अधिक एशिया, अफ्रीका, मध्य और दक्षिण अमेरिका में रहते हैं। इसके विपरीत यूरोप में तीन के

पीछे एक, उत्तरीय अमेरिका में ५ के पीछे केवल एक व्यक्ति अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है और एशिया और अफ्रीका के प्रति चार व्यक्तियों में से तीन खेती से गुजारा कर रहे हैं।

कृषि-जीवी देश में प्रति एकड़ पैदावार कम है। औद्योगिक देशों में प्रति एकड़ उत्पादन अधिक है। क्षेत्र, आबादी की घनता के कारण प्रति व्यक्ति उत्पादन भी कम है। इन अन्तरो का उत्पादन पर भी प्रभाव पड़ता है। खेतिहर और औद्योगिक देशों के मध्य उत्पादन का अन्तर निम्न सारिणी से प्रकट है।

महादेश	प्रति हेक्टर पैदावार		खेती में प्रति व्यक्ति उत्पादन	
	१९४७-४८ मेट्रिक टनो में	१९४७-४८ युद्ध पूर्व का प्रतिशत	१९४७-४८ मेट्रिक टनो में	१९४७-४८ युद्ध पूर्व का प्रतिशत
विश्व का औसत	१२४	१३०	१०५	०४२
उत्तर और मध्य अमेरिका	१०७	१५०	१८०	२५७
यूरोप	१५१	१३४	८६	१०४
ओसेनिया	१००६	१२०	११३	१६४
एशिया	१२६	१२०	६५	०२४
अफ्रीका	०७७	०७३	६५	०१२

खेती में प्रति व्यक्ति उत्पत्ति का अन्तर इस बात का सूचक है कि विभिन्न देशों के गावों और किसानों के जीवन मान में कितना अन्तर है। उत्तरी अमरीका में प्रति किसान पँदावार लगभग ८॥ टन है। वहाँ जीवन मान ऊँचा होना स्वाभाविक है। इसके विपरीत एशिया में ४। टन और अफ्रीका में १॥ टन है।

खेती के अन्दर कम पँदावार होने के अनेक कारण हैं। भूमि का कमजोर होना, प्रतिकूल आबहवा, पुराना तरीका और टेकनीक, उपकरण, साज-सामान, देहाती आबादी की अत्यधिक घनता, खेत की पँदावार का कम कीमत मिलना, आदि। ये सब बातें विभिन्न अर्थों में महत्त्वपूर्ण हैं। लेकिन इनमें सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण कारण है, कृषिका ढाँचा, जिसका ग्राम्य-जीवन-मान पर प्रभाव पड़ता है। खेती का ढाँचा जब हम कहते हैं तो इसके अन्तर्भेद भू-धरण, भूस्वामित्व रिवाजी या कानूनी, क्षेत्र स्वामित्व की बड़ी स्टेटों और किसान प्रक्षेत्रों, या किसानों के मध्य विभिन्न प्रकार-प्रमाणों के प्रदेशों का वितरण, भूकाश्त-कारी, भू-प्रणाली, जिसमें भूमि जोती जाती है और पँदावार बाटा जाता है, प्रत्येक सगठन, उत्पादन और भूमि-व्यवस्था खेती की वित्तीय मशीनरी, सरकार द्वारा करो के रूप में देहाती समाज पर डाला जाना और ग्राम्य जनता को सरकार द्वारा की जानेवाली सेवा में, यथा यात्रिक परामर्श, शिक्षा सुविधा, स्वास्थ्य सेवा, जलपूर्ति और यातायात का संचार।

समाज का आर्थिक विकास हरेक देश के अन्दर एक ही रीति और ढंग से नहीं हुआ। विदेशी सस्याओं का प्रभाव भी हरेक पर अलग-अलग पड़ा है। फलतः हरेक का धरण भी अलग-अलग है। खेती के ढाँचे की मुख्य बात जो हमारे सामने सर्व प्रथम आती है वह है खेती का बहुत छोटे-छोटे टुकड़ों में विभक्त होना। छोटे आकार परिमाण का खेत कौन सा है इसका लक्षण करना या इसकी परिभाषा देना सरल नहीं, क्योंकि प्रत्येक देश में यह अलग-अलग है। संयुक्त राज्य अमेरिका और इंग्लैंड के कुछ भागों में ३० हेक्टर ७५ एकड़ का प्रक्षेत्र छोटा माना जाता है। इसके मुकाबले पूर्वीय यूरोप में जहाँ औसतन परिमाण का प्रक्षेत्र रकबा ५ हेक्टर साठे बारह एकड़ है, यह एशियाई देशों में एक हेक्टर ढाई एकड़ का प्रक्षेत्र बड़ा माना जायगा। आर्थिक दृष्टि से न्यूनतम परिमाण बताना भी सरल नहीं, क्योंकि हरेक देश में खेती का तरीका और उसका उपयोग अलग-अलग है। यदि बँलो द्वारा खेती की जाती है, ट्रेक्टरों से नहीं तो स्वभावतः खेती का परिमाण छोटा होगा।

लेकिन यह प्रश्न बना रहता है कि आर्थिक दृष्टियों से लाभजनक खेती के लिए न्यूनतम रकबा कितने का होना चाहिये। इसका विचार और निर्णय करने की भी दो कमीटियाँ हैं। एक है कि किसान के खेती-उपकरण कितनी भूमि का पूरा-पूरा उपयोग कर सकने में समर्थ हैं और दूसरी कमीटी है एक-एक किसान परिवार के जीवन-निर्वाह, भरण-पोषण के वास्ते कितनी न्यूनतम जमीन की जरूरत है। इसका मान प्रति व्यक्ति मान-मान जमीन के अनुसार तय होगा। आहार स्वास्थ्य-

वर्द्धक पीष्टक एवं रोग प्रतिबन्धक होना चाहिये। पर इसके आघार पर टुकड़ों का निर्णय नहीं किया जा सकता, क्योंकि जोत की सारी जमीन एक जैसी नहीं है। फिर खेती करने और जुताई का ढंग भी अलग-अलग है। जुताई कितनी गहरी होती है इस पर उत्पादन निर्भर है। फिर सिंचाई की सुविधा से भी पँदावार में अन्तर आता है। भारत के अन्दर नदी-घाटी में सिंचन दोहरी फसल की जमीनों में अतिरिक्त एकल फसल की जमीन को तुलना में छ गुणा पँदावार होती है।

इन सब भेदों के बावजूद यह सत्य है कि अधिकांश देशों में बड़े फार्म प्रक्षेत्र बहुत थोड़े हैं। जनसंख्या के बढ़ने पर और उत्तराधिकार के कानूनों के कारण खेती की जमीन का विभक्तिकरण सदियों से हो रहा है। जिस देश के अन्दर जितनी पुरानी आबादी है उसमें जमीन का बटवारा भी उतना ही अधिक हुआ है। प्रक्षेत्र इतने अधिक छोटे हैं कि वे किसान परिवार का भली प्रकार पालन-पोषण करने में असमर्थ हैं। प्रक्षेत्र के अत्यधिक विभक्तिकरण होने के कारण स्वामित्व केन्द्रित हो जाता है और इससे सम्पत्ति के विषम वितरण होने में वृद्धि होती है। छोटे-छोटे प्रक्षेत्र किसान का पेट नहीं भर सकते थे और वह बड़े भूस्वामी और महाजन से कर्ज लेने को बाध्य होता है और कर्ज न चुकाने की अवस्था में अपनी जमीन उनके हवाले करने को बाध्य होता है। आबादी की घनता जहाँ अधिक है वहाँ फार्म भी उसी अनुपात में छोटे हैं। पहले दी गई सारिणी की तरह भारत के विषय में भी आगे दी जा रही है। सारिणी से प्रकट है कि खेती योग्य भूमि के अनुपात में जहाँ आबादी अधिक है वहाँ फार्म आबादी की घनता भी अधिक है। प्रक्षेत्र आबादी की घनता का क्रम है, जापान, मिश्र, कोरिया, हिन्देशिया, हिन्दचीन, सीलोन, चीन और भारत। लेकिन अमेरिका के बोलिविया, कोलम्बिया और पेरू भी इसी वर्ग में हैं। लेकिन प्रति व्यक्ति खेती योग्य भूमि के फार्म आबादी की घनता का यथार्थ छोटका नहीं है। क्योंकि खेती योग्य सारी भूमि को जोतने योग्य जमीन में नहीं सम्मिलित किया गया है। इन देशों में प्रति व्यक्ति जोत की जमीन १।३ हेक्टर एक एकड़से अधिक है। जापान की फार्म प्रक्षेत्र आबादी ३४५ लाख है और वह ५६ लाख हेक्टर जमीन पर गुजारा करती है। मिश्र की मुख्य जनसंख्या १४० और १५० लाख के मध्य है और यह २५० लाख हेक्टर पर जोती है। हिन्देशिया, जावा और मलाया की देहाती आबादी ४५० और ५०० लाख के बीच है और १०० लाख हेक्टर जुते खेत पर बसर करती है। १६३८ में औसतन ०.८६ हेक्टर था। भारत में देहाती आबादी २८५० लाख है और ६८० लाख हेक्टर खेती योग्य जमीन है। यद्यपि उपर्युक्त तीनों देशों की अपेक्षा प्रति हेक्टर आबादी कम है, पर जीवन मान पर आबादी की घनता का प्रभाव अत्यधिक है क्योंकि प्रति एकड़ उत्पादन कम है, फसल की पँदावार कम है और दोहरी फसल एक सीमित क्षेत्र में ही बोई जाती है। मिश्र, जापान और जावा में प्रति एकड़ पँदावार भारत की तुलना में ज्यादा है। भारत के विभिन्न राज्यों में प्रति परिवार जोत की जमीन कितनी है यह निम्न सारिणी से प्रकट है। यह कांग्रेस द्वारा नियुक्त कुमारप्पा कमीटी की रिपोर्ट से ली गई है।

## विभिन्न परिमाण के खेतों के साथ परिवार का प्रतिशत

## बोरसाब ताल्लुका कैरा जिला, गुजरात में रकबों का आकार

प्रान्त	१ से कम	२ से ५	५ से १०	१० और अधिक
आसाम	३८६	२७४	२११	१२६
गुजरात	२७५	२५७	२३३	२४५
दक्खिन	१६८	१६७	१८८	४७७
कर्णाटक	१२२	१६२	२१७	४६६
पश्चिमी बंगाल	३४७	२८७	२००	१६६
मध्य प्रदेश	२८३	४६०	२१०	३००
उड़ीसा	५००	२७०	१२०	१००
मद्रास	५१०	३१०	७००	११०
उत्तर प्रदेश	५५८	२५४	१२८	६०
पंजाब	३७६	१७६	२०५	२३७

आकार	१९०१		१९२१		१९०१ से रकबों में वृद्धि कमी
	सख्या	प्रतिशत	सख्या	प्रतिशत	
५ एकड़ से कम	७७४०	५८	१६७४०	८२	१२५
६ से २५ एकड़ तक	५१०७	२८	३६१६	१६	२३
२६ से १०० के बीच	५७०	४	४३२	२	३
१०० से ५०० के बीच	३०		२६		
जोड़	१३४४७	६०	८४११७	१००	१५१
	१९०१		१९२१		
कुल क्षेत्र एकड़	६४६६०		६२६३६		
औसतन रकबा एकड़ में	७		३८		

भारत की देहाती आबादी के जीवन मान पर यह सारिणी अच्छा प्रकाश डालती है। चीन के गावों में भी बहुत सघन आबादी है। वारह प्रान्तों के १७००० फार्मों की जाच की गयी थी। इससे मालूम हुआ कि १५०० व्यक्ति प्रति वर्ग मील रहते हैं, या प्रक्षेत्र फार्म पर प्रति व्यक्ति को आधा एकड़ जमीन है। इससे जाहिर है कि इन गावों की आबादी की घनता भारत की अपेक्षा दुगुणी है। लेकिन प्रति एकड़ औसतन फसल भी भारत से चीन में दुगुणी है।

सघन वस्ती के प्रदेशों में, औसतन प्रक्षेत्र रकबा छोटा होगा, यदि जमीन समान रूप से बांटी भी जाय तब भी स्थिति में अन्तर न आयगा। जब औसतन रकबे छोटे होंगे, तब प्रक्षेत्र रकबों के आकार परिमाण में अत्यधिक असमानता होगी, अधिक सख्या के प्रक्षेत्र घटकर औसतन आकार से कम के होंगे और इस कारण अधिकतर सख्या में रकबे भरण-पोषण के न्यूनतम मान से भी कम के होंगे। जैसे जापान के पजम का औसतन आकार एक हेक्टर या ढाई एकड़ है। हाल के सुधार ने फार्मों का परिमाण अपेक्षाकृत कम कर दिया है। फिर भी ४१ प्रतिशत प्रक्षेत्र रकबे १२ एकड़ से कम के हैं।

भारत में अलाभजनक रकबे अनुपातत बड़ी सख्या में हैं। अधिकांश राज्यों में रकबे का आकार ४ और ५ एकड़ के मध्य है। भारत के लिए आर्थिक दृष्टि से लाभजनक रकबा ५ एकड़ का माना जाता है जिसमें २३ एकड़ जमीन सुसिंचित होनी चाहिये। लेकिन भारत के कुछ बारिश क्षेत्रों को कुल एक तिहाई जमीन ऐसी है जिसमें अच्छी वर्षा होती है या सिंचाई की अच्छी व्यवस्था है। प्रति औसत रकबे के साथ २ एकड़ सुसिंचित जमीन भी नहीं है। इसके बदले और सूखी ४ एकड़ जमीन कमी को पूरा करने के लिए चाहिए। इस प्रकार औसतन प्रक्षेत्र एकड़ भी न्यूनतम भरण-पोषण योग्य मान से कम है और अधिकांश रकबे औसतन प्रक्षेत्र रकबे से कम है।

बढती जनसख्या का खेती पर कितना भारी दबाव पड रहा है यह निम्न सारिणी प्रकट है।

यह है ७२ गावों की जाच का परिणाम। बीस साल के अन्दर कुल रकबों की सख्या ७६ प्रतिशत बढ़ गई, लेकिन १९१० में जहाँ औसतन रकबा ७ एकड़ का था वहाँ १९२१ में केवल ३.८ एकड़ का रह गया।

एक जोड़ी बैल साल में औसतन २५ एकड़ जोतते हैं और वम-फील्ड थोरी के अनुसार यह आर्थिक दृष्टि से लाभजनक रकबा है। १९२१-२२ में २१००० रकबा में से केवल ३४०० रकबे या २ प्रतिशत से भी कम, २५ एकड़ से अधिक के थे। बोरसाद ताल्लुका के लोगों के लिए यह मान बहुत ऊँचा है। इसलिए "इंडियन एग्रीकल्चरल इकनामिक्स" के लेखक श्री ए० डी० पटेल का कहना है

इसलिए ताल्लुका के लोगों के जीवन मान के अनुसार हम लाभजनक रकबे के परिमाण करने का यत्न करते हैं। हमारे ताल्लुके में रकबे का आकार प्रति परिवार साठे १२ एकड़ होना चाहिये। पर लाभजनक रकबे के हमारे परिमाण का दो तिहाई ही वस्तुतः प्रति परिवार जोत है।

सूरत जिले के बोरसाद ताल्लुके के बारे में १९२१-३० में "लाइफ एन्ड लेबर इन गुजरात ताल्लुकाज" के लेखक जे० बी० शुक्ल के लिखा था कि इसके लिए लाभजनक रकबे का परिमाण २० एकड़ होना चाहिये। पर स्थिति क्या थी

## ग्राम समूहों के अनुसार रकबों की सारिणी

समूह	रकबों की कुल सख्या	लाभजनक या उससे ऊपर के रकबों की सख्या	अलाभजनक रकबों की सख्या	कुल रकबों में अलाभजनक रकबों का प्रतिशत।
१	६२	१८	७३	७६३
२	१२८	७	१२१	६४५
३	७६	६	६७	८८१
४	६२	३	६८	६६७
५	२०३	८	१९६	६६०
योग	५६१	४५	५४५	४५४६

बम्बई प्रान्त के एग्रीकल्चर डाइरेक्टर डा० हेरल्ड मान ने १९१७ में पूना जिले के एक गाव की जाच कर बताया था कि १७७१ में औसतन रकबा ४० एकड़ का था, १८२०/४० में १४ एकड़ का था, और १९१४/१५ में वह घट कर ७ एकड़ का रह गया। ८१ प्रतिशत रकबे, अत्यधिक अनुकूल परिस्थिति में भी अपने स्वामी का भरण-बोषण नहीं कर पाते, डा० मान इस निष्कर्ष पर पहुँचे थे। इससे यह स्पष्ट है कि पिछले ७० वर्षों में रकबो के अन्दर बड़ा परिवर्तन हुआ है। ब्रिटिश काल से पहले और ब्रिटिश शासन के आरम्भ में साधारणत रकबे उचित आकार के थे, अधिकतर ६ से १० एकड़ के थे और दो एकड़ से कम के वैयक्तिक रकबे अज्ञात ही थे। अब रकबो की संख्या बढ़ गई है और लगभग दुगुणी हो गई है और ८१ प्रतिशत रकबे आकार में २० एकड़ से कम है और ६० प्रतिशत से अन्यान्य ६ एकड़ से भी कम है।

डा० मान ने बम्बई के ठाणा जिले के भिकाडी ताल्लुके की जाच की थी। आपने ६५८४ खातेदारो की जाचकर निम्न परिमाण सबद्ध किया है \*

बुलसार ताल्लुका सूरत जिला के आजाम की जाच श्री मुस्तार ने १९२७/२८ में की थी। गाव में ४६१ परिवार थे जिनमें २४६ या ५४ प्रतिशत किसान थे। खेत कितने छोटे-छोटे टुकडो में विभक्त हो गए थे यह उन्होंने इस प्रकार बताया है।

### उपविभाग

रकबो की संख्या	१९००/०१	१९१७/१८	१९२६/२७
१०० एकड़ से अधिक के	१	१	१
७१ से १०० एकड़	५	३	
५१ से ७० एकड़	८	६	८
३१ से ५० एकड़	२१	९	७
१५ से ३० एकड़	३४	३७	३७
६ से १५ एकड़	३९	१०७	९५
१ से ५ एकड़	६४	१३२	१३३
१ एकड़ से नीचे	४४	१०९	२४३
योग	२१६	४०४	५२४

* रकबे	१८८६		१९०३		१९३१		१९३७	
	संख्या	प्र०श०	संख्या	प्रति शत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रति शत
५ से कम	३७३१	४९७	६४१६	६२६	१०५५८	७४२	६६३८	६९१
५ से २५ एकड़	३०४१	४०३	३२०६	३१६	३४०४	२४१	२४२६	२५५
२५ से १०० एकड़	६९४	९३	५५६	५४	२०६	१४	४३८	४५
१०० से ५०० एकड़	३९	५	४१	४	३०	३	७९०	९
५०० से ऊपर								
योग	७५०५	९९८	१०२१९	१०००	१४१९८	१०००	१०२९२	१०००

### खंड खंड होना

खंड की संख्या की संख्या के साथ रकबे	निश्चित रकबो की संख्या के साथ	खंडों की संख्या	निश्चित खंडों की संख्या के साथ रकबो की सं०
१ से ५	२८६	२१/२५	७
६ से १०	६२	२६/३०	८
११ से १५	४२	३१/४०	६
१६ से २०	२२	४० से अधिक	३

### एक एकड़ से कम के प्लाटों का परिणाम और संख्या

३०/४० भुज	२०१	१०/१५ भुज	३३९
२०/३० भुज	३११	५/१० भुज	३३९
१५/२६ भुज	२१५	५/१० भुज	३३९
१५/२६ भुज	२१६	५ भुज से नीचे	३०५

( १ भुज बराबर है १/४० एकड़ )

दक्षिण भारत की स्थिति इससे भिन्न नहीं। डा० गिलवर्ट ने १११६ में कुछ गावो की जाच की थी। १९३६ में इन्हीं गावों की पुन जाच की गई, इन जाचो का परिणाम इस प्रकार है

रकबो का परिमाण	१९२६		१९३६	
	रकबो की संख्या	मात्रा एकड़ में	खेतो की संख्या	मात्रा एकड़ में
१ से १० एकड़ के मध्य	३८	२५०	१२१	५३५
१० से २५ "	३८	६४९	३७	५९४
२५ से ५० "	१२	४६९	८	२६४
५० से १०० "	३	४७१	१	१०५
१०० से २५० "	३	२११	३	१६०
योग	९४	२०५०	१७०	१६५८

कुछ क्षेत्र में कमी होने के साथ रकबों की संख्या में वृद्धि होती गई। १९१६ में रकबों का जो परिमाण था उससे २० वर्ष के बाद १९३६ में आधा ही रह गया। एक और भी उल्लेख योग्य बात यह है कि १ से २० एकड़के रकबों और अभी अधिक उपविभाग हुआ है।

रकबों के खंड-खंड होने की प्रक्रिया सारे देश में जारी है। मालाबार जिले के मुल्लयूर गांव की १९३६ में जाच की गई थी। उसका परिणाम इस प्रकार रहा

आकार	संख्या	एकड़ों में विस्तार
चौथाई एकड़ से कम	१०६	१८ १०
चौथाई से आधा एकड़	१२५	४४ ६८
आधा से एक एकड़	१५२	१०० ४९
एक से २ एकड़	६९	९५ ७३
२ एकड़ से ५	६२	१९२ ७८
५ से १० एकड़	२४	१६९ ७८
१० से २० एकड़	११	१४५ ८२
२० एकड़ से ऊपर	७	३९० ९९
योग	५५६	११५८३७

इस गांव में रकबों का औसतन परिणाम २ १ एकड़ है। नारियल क्षेत्र में यदि गहरी खेती की जाय तो २ १ एकड़ का रकबा आर्थिक दृष्टि से अलाभजनक नहीं कहा जा सकता। परन्तु कुल रकबों का प्रतिशत एक एकड़ से भी कम है और ४२ प्रतिशत रकबों तो आधे एकड़ से भी कम के हैं।

“साउथ इंडियन विलेज” के अनुसार गंगेककोडम तिननेवली जिला गांव के अन्दर “पिछले १५ और २० वर्षों के अन्दर काश्तकारों की बहुत वृद्धि हुई है। इनमें से बहुत से काश्तकार खाली समय में खेतिहर मजदूर भी हैं। नीचे की तालिका से मालूम होगा कि मू-स्वामियों की संख्या में कमी हुई है और बड़े जमीन्दारों के हाथ में जमीन के केंद्रीकरण हुआ है। यथा

### गंगेक कोडम गांव तिननेवली जिला

आकार	मूस्वामियों की संख्या	
	१९१६	१९३४
१ एकड़ से कम	१०५	१००
१ एकड़ से ५ एकड़	२२०	६००
५ एकड़ से २० एकड़	२५०	५०
१० एकड़ से २० एकड़	१००	३०
२० एकड़ से ५० एकड़	१६०	५०
५० एकड़ से १०० एकड़	९	३
योग	८४४	८३३

१९३६ में लैंड रेवेन्यू कमीशन नियुक्त किया था। इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, यह मानते हुए कि १९३१ में ७० प्रतिशत आवादी काश्तकार थे तो खेती करनेवालों की कुल संख्या ३२७ लाख होती है। जोत में कुल जमीन है लगभग ३१७ लाख एकड़ है, अतः औसतन प्रतिशत एक एकड़ से कुछ कम है। क्लाउड कमीशन ने यह भी लिखा कि कमीशन खेत के लिये डाइरेक्टर आफ लैंड रेकॉर्ड द्वारा की गई जाच की एक अत्यन्त उद्वेगजनक बात यह है कि ४१ ९ प्रतिशत परिवारों के पास २ एकड़ या इससे भी कम जमीन है और जिनके पास २ और ४ एकड़ के बीच जमीन है वे २० ६ प्रतिशत हैं। इसका अर्थ है कि खेतिहर परिवारों में से २।५ भाग के पास २ एकड़ से भी कम जमीन है और वह उनके जीवन निर्वाह के लिए कम है और वे बिना किसी कानूनी अधिकार के दारमदार के रूप में जमीन लेने को बाध्य होते हैं या दिन में दूसरों के खेत पर मजदूरी करने के लिए लाचार हैं।

डोरवा, दानापुर सबडिवीजन पटना एक जमीन्दारी गांव है। १९४९ में इसकी भारत सरकार ने जाच करवाई थी, इस जाच के अनुसार औसतन रकबा ६ एकड़ ही है। गांव में ६३ काश्तकार परिवार थे, उनके पास जमीन इस प्रकार थी

	परिवारों की संख्या
२ एकड़ से कम	१६
२ से ५ एकड़	२१
५ से १० एकड़	१४
२० एकड़ से ऊपर	१२

रिपोर्ट लेखकों का कहना है कि लगभग ४४ प्रतिशत के पास २ एकड़ से भी कम जमीन है। २५ प्रतिशत के पास २ से ५ एकड़ है। १७ प्रतिशत के पास ५ से १० एकड़ और केवल १४ प्रतिशत के पास १९ एकड़ जमीन है।

मध्य प्रदेश के एक गांव रकपरी नामक ताल्लुक, नागपुर से ८ मील दूर, की भी १९४९ में जाच की गयी थी। भारत सरकार द्वारा की गई जाच का परिणाम इस प्रकार है

आकार	प्रतिशत
२ एकड़ से कम	००
२ से ५ एकड़	६.९
५ से १० एकड़	२४ २
१० से १५ एकड़	२५ ८
१५ से २० एकड़	१० ४
२० से ३० एकड़	१७ २
३० से ४० एकड़	५.२
४० से ऊपर	१० ३

आसाम राज्य के कामरूप जिला के अन्तर्गत भडारी सबडिवीजन में भम्रपारा नामक एक गाव है। इस गाव की जाच भी १९४९ में की गई थी। रकबो के आकार के सम्बन्ध में इसकी जाच की रिपोर्ट में कहा गया है

आकार	रकबों की कुल सख्या
२ एकड से न्यून	१३८
२ एकड से ५ एकड से न्यून	३६२
५ एकड और १० एकड से न्यून	४४२
१० एकड और उससे ऊपर	५२

इससे स्पष्ट है कि ५० प्रतिशत रकबे ५ एकड से भी कम है और केवल २२ प्रतिशत के पास १० एकड या इससे अधिक जमीन है।

उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के एक गाव का नाम रक्सौलपुरा है। इस गाव की भी १९४९ में जाच की गई थी। इस गाव में २०२ परिवार खेती करते आते थे। ५५ एकड जमीन जोत में थी। यह इस प्रकार वटी थी

रकबे का आकार	काश्तकारों की सख्या
२ एकड से कम	१४४
२ एकड से ५ एकड तक	२६
५ एकड से १० एकड तक	१६
१० एकड और उससे ऊपर	८
रकबे का औसतन आकार	३०

उड़ीसा की हालत भारत के अन्य राज्यों से भिन्न नहीं है। कटक जिले के सदर सबडिवीजन में खूटनी गाव है। गाव से रेलवे स्टेशन केवल एक मील दूर है। इस गाव में खेती का विभाग उपविभाग इस प्रकार है

रकबो का आकार	काश्तकारों की सख्या
२ एकड से कम	२४
२ से ५ एकड	२८
५ एकड से १० एकड	३
१० एकड और उससे ऊपर	००

रकबो का टुकड़ा होना बराबर जारी है। इससे कोई अभी खास परिवर्तन नहीं हुआ। मद्रास राज्य के चिन्नर जिले में एक गाव बगलोर है। १९४९ में इसकी जाच की गई थी। जाच से मालूम हुआ कि काश्तकारों की सख्या १४७ है। रकबो की आकार इस प्रकार था

रकबो का आकार	काश्तकारों की सख्या
२ एकड से कम	८२
२ एकड से ५ एकड	४९
५ से १० एकड	२०
१० एकड और उससे ऊपर	६
	१५७

भारत के समान मिश्र में भी रकबे बहुत छोटे-छोटे हैं। आवादी-आकार भी बहुत है। यथा .

### मिस्र में भूस्वामित्व का वितरण १९४७

रकबो का आकार	स्वामियों की सख्या	कुल क्षेत्र फोड्डन	स्वामित्व फोड्डन	कुलका प्रतिशत
१ फोड्डन और निम्न	१९२१०००	७२१	७८५०००	१३.१
१ से ५ फोड्डन	५८७०००	२२१	१२१९०००	२०.३
५ से ५० फोड्डन	१४३०००	५४	१७७४०००	२९.७
५० से ऊपर फोड्डन	११०००	४	२२०००००	३६.८
योग	२६६२०००	१०००	५९७८०००	१००.०

१ फोड्डन = १.०३८ एकड या ०.४२ हैक्टर

भारतीय अकाल कमीशन के अनुसार प्रति रकबा औसतन पैदावार मद्रास, बंगाल और उत्तर प्रदेश में २ टन है तथा पंजाब में ३ टन है। ऊपर ऐसे भी रकबे हैं जहां पैदावार दो टन से भी कम है। अकाल कमीशन के अनुसार ये इस प्रकार हैं।

### एकड़ टन से कम पैदा करने वाले रकबों का प्रतिशत

नाम राज्य	प्रतिशत सख्या
मद्रास	७४
बंगाल	५०
बम्बई	५०
उत्तर प्रदेश डेढ़ टन से कम	५०

अलाभजनक रकबो की औसत समस्या का महत्व उस समय प्रकट होता है, जब यह मालूम होता है कि खेती करनेवालों में से अधिकांश को जोत की जमीन में स्वामित्व नहीं होता न वे उसके मालिक होते हैं और न वे काश्तकार। छोटे प्रक्षेत्रों की समस्या मुख्यतः भारत, चीन के कुछ भागों और बर्मा को छोड़कर सम्पूर्ण एशिया में है। कैरिबियन प्रदेश में, मिस्र और जापान में भी यह उग्र सीमा पर पहुँची हुई है। आवादी की सघनता इसका एक मुख्य कारण है। अतः खेती का ढाँचा बदलने मात्र से यह समस्या हल न होगी।

छोटे क्षेत्रों के होने का एक बड़ा कारण देहाती आवादी की बड़ी सख्या में होना है, पर अलाभजनक फार्म उन देशों में भी पाए जाते हैं जो देहाती आवादी में सख्या की समस्या से परेशान नहीं है। फिलीपीन में औसतन रकबा ४ हैक्टर १० एकड का है। लेकिन आधे से अधिक फार्म दो हैक्टर का है। इसके दो कारण हैं। भूस्वामित्व का विषम वितरण हुआ है और लू जान और वीसायन द्वीपों में आवादी केन्द्रित हो गई है।

दक्षिण अमरीका में इसके विपरीत ऐसे देश हैं जिनमें रकबे बहुत बड़े हैं और आर्थिक दृष्टि से इसी कारण लाभजनक नहीं। अर्जेंटीना में निजी खेती की जमीनो में ८५ प्रतिशत ५०० हेक्टर से बड़े स्टेट है। इसके साथ ही फार्म आवादी में से ८० प्रतिशत के पास एक एकड़ भी जमीन नहीं है। ब्राजील में भी यही बात है। लगभग आधी जमीन १००० हेक्टर से अधिक की स्टेट है और आधे फार्म २० हेक्टर से कम के हैं और ये कुल जमीन केवल २० प्रतिशत से भी कम है। लेकिन अमरीका में बड़े-बड़े चारागाह हैं और फार्मों के बड़े होने का एक यह भी कारण है।

रकबे भी अनेक खडो और टुकडो में होते हैं और ये दूर-दूर बिखरे होते हैं। यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशो तक ही सीमित नहीं। यह स्विटजरलैंड, फ्रांस और दक्षिण जर्मनी में भी है। दक्षिण यूरोप के विशेषतः पोलैंड और वाल्कन प्रदेशो में यह प्रक्रिया दूर तक गई हुई है। मसलन यूगोस्लेविया में १२ एकड़ का फार्म अलग-अलग ३० खडो या प्लाटो में बटा होता है। खडीकरण का कारण भी प्रक्षेत्रो की आवादी का बढ़ना और उत्तराधिकार कानून असम होना है।

छोटे रकबो का होना और फिर उनका खड-खड में बटना और फिर उनका बिखरा होना एक औसत और उग्र समस्या है, यह असन्दिग्ध है। प्रश्न यह है कि इसे कैसे हल किया जाय ?

अब तक इसके दो रास्ते बताए गए हैं। एक है सामूहिक खेती और दूसरा है सहकारी खेती का। सामूहिक खेती उस जैसे देशों में सुरुज हो सकती है जहा बड़ी मात्रा में जमीन परती पडी है। परन्तु जहा जमीन की भूख बढी हुई है और हरेक व्यक्ति जमीन पर स्वत्व पाने को उत्सुक है और पूर्वजो की जमीन के प्रति जहा लोगो को मोह है वहा सहकारी खेती की प्रणाली ही उचित और सफल हो सकती है।

मेक्सिको में सामूहिक खेती का परिश्रम इस कारण सफल हुआ क्योंकि वहा परती जमीन बहुत थी। 'एजीडोज' नवीन जमीन बन्दोवस्त, १९१५ में नवीन कृषि सुधार के अन्दर हुआ। १९३६ में प्रेजिडेन्ट लाजोर काडेनाज ने २२१ 'एजीडोज' बनाये। अकेले लेमूना प्रदेश में ही प्रक्षेत्र की ३ लाख एकड़ जमीन, और ५ लाख एकड़ वर्ग सुवरी जमीन ३२००० किसानो में बाँटी गई। १९४० में जीगेजो की सख्या १५००० हो गई। कुल जमीन ६२४ लाख एकड़ थी और उस पर १४ लाख किसान बसे हुए थे। अनुमान है कि एक तिहाई 'एजीडोज' अर्थात् ५००० सामूहिक हैं और शेष वैधानिक रकबे हैं। लेकिन हरेक वर्ग की जमीन सामान्य अधिकार में है।

'एजीडोज' का निर्माण स्वेच्छा के आधार पर हुआ है। कम-से-कम अधिकारी २० किसानो द्वारा एक समूह बनाना और जमीन के लिए आवेदन पत्र देना आवश्यक है। जमीन की प्राप्ति और उस पर बसना सामूहिक है पर वैधानिक या सामूहिक सबसे खेती करने के विषय में वे निर्णय कर सकते हैं। प्रशासन चुनी हुई दो कमिटियो के हाथ में होता है। कमिटी में तीन सदस्य और तीन उसके एक्जी होते हैं। इनमें से एक कमिटी कार्यपालिका होती है और वह भी सदस्यो में से चुनी जाती है। दूसरी कमिटी का काम आय निरीक्षण होता है। साधारणतः समा द्वारा प्रमुख अधिकारी चुने जाते हैं। 'एजीडोज' का निरीक्षण ऊची एजेंन्सिया

करती है क्योंकि 'एजीडोज' के ७० प्रतिशत सदस्य निरक्षर हैं। इसकी आय बेटन के रूप में बाँटी जाती है। बेटन का निर्णय आय की मात्रा और आय की स्थिति की पर निर्भर है। जहा सामूहिक रूप से उत्पादन किया जाता है वहा भी जमीन वैधानिक रहती है।

बड़े परिमाण में परती पडी जमीनो को बसाने में ही सामूहिक खेती का परीक्षण किया जा सकता है और इस प्रकार जमीन इस देश में अधिक नहीं है।

सोवियत सामूहिक खेती के परिणाम की अपेक्षा फिनीस्तीन में 'कुवट्जा' या यहूदी सामूदायिक प्रक्षेत्र अधिक महत्त्वपूर्ण एक सामाजिक जरिया है—यह जातीय और साम्प्रदायिक सगठन है और सोवियत 'कम्पून से बहुत मिलता-जुलता है। जमीन वैयक्तिक सम्पत्ति का नाम नहीं। 'कुवट्जा' खुद नेशनल फंड से जमीन पर कर्ज लेता है। इसका इन्तजाम प्रति वर्ष चुनी एक प्रबन्ध कमिटी करती है सोवियत 'कम्पून' से इसका अन्तर यह है कि यह मुख्यतः पूजीवादी समाज के ढाँचे के अन्दर काम करती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सस्कृति और काम के वितरण के लिए अलग-अलग कमिटियाँ हैं। इसमें वैयक्तिक पुरस्कार का सर्वथा अभाव है।

कुवट्जा किमी अंश में एक नूतन आदर्श का सूचक है और भारत में इसके समानान्तर कोई दूसरी चीज नहीं है। सब जगह से सताये और भगाये जाकर यहूदियो ने इसराइल को जीओनिज्म का घाम बनाया है। हमारे किसान की ऐसी स्थिति नहीं। इसके लिए जिस प्रेरणा और लक्ष्य की जरूरत है, उसका हमारे देश के किसानो में अभाव है।

उत्पादन की विशाल वृद्धि के लिए पूजीवादी खेती और सामूहिक खेती की प्रणाली उपयोगी है। किन्तु भारत में साधारणतः इसके लिए उपर्युक्त अवस्था नहीं है। इनके मुकाबले हालैंड और डेनमार्क में प्रचलित सहकारी खेती की प्रणाली इस देश की हालतो एवं परिस्थितियो के अनुकूल है और किसान का व्यक्तित्व भी स्वतंत्र रूप से विकास करने का अवसर पाता है। इस प्रणाली में वैयक्तिक खेती करने के सब लाभ शामिल हैं, अर्थात् किसान का वैयक्तिक उत्पादन-क्षमता और उपक्रम का पूरा-पूरा लाभ इसको मिलता है। इसके साथ वह सहकारी प्रक्षेत्र सस्या के सदस्य होने के नाते विशाल परिमाण की खेती का भी लाभ उठाता है। अर्थात् यह भी आधुनिक मशीनो, विशेषज्ञो का परामर्श, कच्चे माल की खरीद और उत्पादन माल की विक्री आदि में सहकारी प्रक्षेत्र सस्या का लाभ पाता है।

हम अपने देश भारत में नवीन कृषि या आर्थिक तंत्र की स्थापना कर रहे हैं। जिसकी निम्न विशेषताएँ हैं —

- (१) प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर प्राप्त हो।
- (२) शोषण और विद्रोह सर्वथा न हो,
- (३) उत्पादन की अधिकतम कार्य क्षमता हो, और
- (४) खेती-योजना और प्रणाली वैधानिक हो।



भारतीय किसान समाज एक ही अवस्था में नहीं है। प्रत्येक राज्य के अन्दर ही किसान विभिन्न सामाजिक अवस्थाओं में हैं। अतः एक की खेती की प्रणाली सबके लिए उपयुक्त न होगी। इसलिए यदि २० जोत का रकबा आर्थिक दृष्टि से लाभजनक हो तो किसान का वैयक्तिक रूप से खेती करने की व्यवस्था आज के समान भविष्य में भी रहनी चाहिये। सहकारी खेती में सम्मिलित होना उसकी इच्छा पर छोड़ना चाहिये।

इस सम्बन्ध में मुख्य प्रश्न यह है कि आर्थिक दृष्टि से लाभजनक रकबा किसको माना जाय। इसका निर्णय और देश के लिए एक ही नहीं हो सकता। एक राज्य के लिये भी एक नहीं हो सकता। क्योंकि अवस्थाएँ एक नहीं। वृष्टि, आर्थिक तंत्र, खेती करने की प्रणाली और उसका तंत्र किसानों का जीवन-मान ये कुछ आधारभूत तत्त्व हैं जिनके आधार पर आर्थिक दृष्टि से लाभजनक रकबा का निर्णय किया जाना चाहिये। इसका उद्देश्य यह होना चाहिये।

(१) यह जीवन-निर्वाह का उचित मान प्रदान करे।

(२) साधारण आकार के परिवार के सब सदस्यों को पूरा रोजगार दे और कम-से-कम एक जोड़ी बैलों के लायक हो।

(३) प्रादेशिक और क्षेत्रीय आर्थिक तंत्र की व्यवस्था किसान के अनुकूल हो।

बुनियादी रकबा कितना बड़ा होना चाहिये, जो आर्थिक दृष्टि से लाभजनक हो, यह निर्णय करना सरल नहीं। अकेली सिंचाई सुविधा ही खेती का रूप बदल देती है। अतः बुनियादी रकबों का निर्णय हरेक क्षेत्र की अवस्था के अनुसार होना चाहिये। बुनियादी रकबों का निर्णय करने के साथ अधिकतम बड़े रकबों की भी सीमा निश्चित करना आवश्यक है। नियोजन कमीशन ने इसकी आवश्यकता स्वीकार की है।

भारत में १९२१ से सहकारी खेती का प्रचलन करने का मान किया जा रहा है। पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में यह प्रयोग उस समय से

चालू है। कानून ने सहकारी खेती को सर्वथा स्वच्छा पर नहीं छोड़ा है। उसमें कुछ बाधयता भी है। मसलन यदि एक इलाके के दो तिहाई किसान सहकारी खेती के लिए तैयार होते हैं तो शेष एक तिहाई किसान को भी उनके साथ मिलकर सहकारी खेती में योग देना होता है।

१९४६ तक पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग १६००००० एकड़ जमीन का एकीकरण कन्सोलिडेशन किया गया। फलतः ४२५०००० खेत के प्लाट ६४६००० प्लाटों में बदल गए। एकीकरण का पंजाब में यह लाभ हुआ है कि मूस्वामियों ने अपने रकबों की सिंचाई के लिए कुआँ बना लिया है। बाध बाधना, जमीन को समतल बनाना, जल की बचत करना और खाद के लिए गड्ढे खोदना इसके कारण सम्भव हो गया है। कुछ गावों में वेंटर लिविंग कोऑपरेटिव सुन्दरतर सहकारिता संस्था की अच्छी सफलता मिली है।

रकबों को खड-खड होने से बचाने के लिए वम्बई सरकार ने फ्रैगमेंटेशन एन्ड कन्सोलिडेशन आफ होल्डिंग ऐक्ट १९४७ बनाया और पंजाब सरकार ने ईस्ट पंजाब होल्डिंग कन्सोलिडेशन एन्ड प्रीवेंशन आफ फ्रैगमेंटेशन ऐक्ट १९४८ बनाया है। इन कानूनों से राज्य सरकारों को एक इलाके के वास्ते प्लाट का न्यूनतम आकार निश्चय करने, जमीन को हस्तान्तरित करने या विभाजन करने को रोकना और जमीन्दारों को अनुमति के बगैर भूमि एकीकरण को योजना लागू करने का अधिकार प्राप्त हुआ है।

खेतों के एकीकरण और उनको खड-खड होने से बचाने की ओर सरकार और जनता दोनों का ध्यान है। कुछ प्रदेशों को छोड़कर जहाँ सामूहिक खेती के लिए पर्याप्त जमीन है और अभी तक गैर आबाद है, शेष देश के लिए सहकारी खेती का हालैंड और डेनमार्क में प्रचलित रूप को हमारे देश ने चुना है।



# वन-सम्पदा का महत्व

“आर्य जब सर्व प्रथम भारतवर्ष में आये मने ही उन्हें अपनी गोद में आश्रय दिया और फल-मूल खिलाया। मेरे ही अनुपम साज को पहन प्रकृति इतनी रूपसी बन गई कि उसने आर्यों के कोमल भावुक मन को मयकर वेद का प्रथम मन्त्र निकाला।”  
—वन की आत्मकथा

वन मानव के सांस्कृतिक, बौद्धिक, औद्योगिक और आर्थिक विकास का उद्गम है। मानव का कोई भी कार्यक्रम वन की वस्तु के बिना सफल नहीं हो सकता। मानव समाज को सुखी और ऐश्वर्य सम्पन्न रखने में वन का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जीवन की मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति के आधार वन और वन-पदार्थ हैं। कृषि का वन से बहुत गहरा सम्बन्ध है तथा मानव के सांस्कृतिक विकास के लिए वन का वातावरण विशेष उपयुक्त है। वन हमारे लिये सदा से सादगी, सच्चाई और मनुष्यत्व के उचित पाठ पढ़ाने तथा तज्जनित गुण ग्रहण कराने के केन्द्र रहे हैं।

वन के आध्यात्मिक सौन्दर्य ने आदिकाल से मनुष्य के अन्तःकरण को आकर्षित किया है। जितने प्राचीन ऋषि-महात्मा भारतवर्ष में हुए हैं, प्रायः सभी ने वन-भूमि में तपस्या कर ज्ञान प्राप्त किया था। महात्मा बुद्ध ने महल छोड़ वट-वृक्ष के नीचे बैठकर दिव्य-दृष्टि पायी। वेद, उपनिषद्, आदि अद्वितीय ग्रन्थों की आत्मा वन के वातावरण से ही आयी थी। मानव-मन ससार की कपट-क्रूरताओं से ऊबकर आत्मा की शांति के लिये वन की ओर अग्रसर होता है।

## वन और संस्कृति

प्राचीन काल में विद्याध्ययन भी वन के शान्त और मनोहर वायु-मण्डल में हुआ करता था। इस वैज्ञानिक और विलासप्रिय युगमें फिर हमारा अशान्त हृदय आलीशान इमारतों से विमुख हो वन के आह्वान को सुनने लगा है। अमेरिका आधुनिक युग में भौतिक सुखों का सर्वश्रेष्ठ केन्द्र है, वहाँ विज्ञान और उद्योग के मधुर फल लोगों के हाथ में रखे हुए हैं, ऐश्वर्य और सुख साधन की कोई कमी नहीं है। ससार में कोई भी देश अवतक इतना सुखी नहीं हो सका है, फिर भी इस सुख-विलास में तर लोग महसूस करते हैं कि उनकी अन्तरात्मा में कोई ऐसी कमी रह गई है जो उन्हें अशान्त कर रही है। वे अनुभव कर रहे हैं कि सब होते हुए भी वे सुखी नहीं हैं। सुख की ये सामग्रियाँ उन्हें सुखी नहीं कर पाती। उनकी आत्मा की एक अज्ञात क्षुधा भौतिक सम्पदाओं से तृप्त नहीं हो रही है, यही कारण है कि भारतवर्ष से जानेवाले किमी भी सावु-महात्मा की अमेरिका में बड़ी कद्र होती है। उनकी अज्ञात प्रेरणा की ओर लोग अग्रसर होते हैं कि शायद उनकी आन्तरिक अशान्ति का समाधान इन महात्माओं की ज्ञान-शिक्षा से हो जाय। ये सावु-महात्मा वाहर भारतवर्ष की वही सांस्कृतिक सम्पदा अपने साथ लेकर जाते हैं जिसमें आत्मा प्रघान मानी गयी

है शरीर गौण। यदि यह उन्मत्त ससार वैज्ञानिक और औद्योगिक आविष्कारों से यह समझ बँठा है कि सम्यता और सुख की चरम सीमा यही है तो यह उसकी भारी भूल है। यदि वह सच्चा सुख प्राप्त करना चाहता है और एक दूसरे से प्रेम निरर्ह के साथ शान्ति से रहना चाहता है तो उसे इसी सम्यता की शरण लेनी पड़ेगी जिसका आधार और जन्म-भूमि वन है। हम जब ध्यान और ज्ञान की चर्चा करते हैं, सत्य और अहिंसा का विषय उठाते हैं तब अनायास ही हमें हिमालय याद आता है। ईश्वर का ध्यान तो हम कलकत्ते की चौरागी सड़क के किनारे या दि ली के कन्न ट पथ पर भी कर सकते हैं क्योंकि हमारे ऋषि-मुनियों ने सिखाया है कि ईश्वर सर्वत्र है, हर प्राणी में है, प्रत्येक अणु में है। किन्तु यह सर्व विदित है कि ज्ञान और ध्यान हल-चलके बीच नहीं हो सकता, इसके लिये तो वन का आश्रय आवश्यक है। विलास-सृष्टि और मन के गठन में वातावरण का प्रमुख हाथ है। हमारी जो विचार-धारा मशीन के चीत्कारों के बीच उत्पन्न होगी वह अन्तर के उस प्यास की नहीं बुझा सकती जो सर्व सम्पन्न अमेरिका निवासी अशान्त उद्विग्न हो अनुभव करने लगे हैं। सत्य और अहिंसा के दूत महात्मा गांधी वन में तपस्या करने लगे थे पर उन्होंने राम और दधीचि के जीवन से ही शिक्षा पायी जिनकी आत्मा को वन-प्रकृति से इस मूल-धर्म का सन्देश मिला था।

आदिकवि वाल्मीकि ने “पृथ्वीच सकानना” शब्द का व्यवहार किया है, जिससे स्पष्ट है कि पृथ्वी को उसके वन-सखा से पृथक वे कल्पना ही नहीं कर सकते थे। महाकवि कालिदास की शकुन्तला वन में ही पली थी। अब हम झूठी सम्यता के फरेव में पड़कर वन को सम्यता का विपक्षी समझने लगे हैं। परन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि भारतवर्ष की सांस्कृतिक गरिमा गंगा की तरह वन से ही बहकर आयी है और हमारी अद्वितीय आध्यात्मिक सम्यता को अक्षय बनाये रखने के लिए वन का अस्तित्व अनिवार्य है। वैविलन, मिश्र आदि सम्यता के उच्च शिखर पर पहुँचकर भी वन-सम्पदा खो-देने से मरुभूमि बन गए।

## वन और समाज

वन पदार्थ पर मानव-समाज को बहु कुछ निर्भर करना पड़ता है, पहले लकड़ी की ही बात लीजिए। घर बनाने के लिए तथा कुर्सी, टेबुल, खाट इत्यादि के बनाने में कृषि की सामग्री, रेल के स्लीपर, नाव, रेल के डब्बे, पुल इत्यादि के लिए लकड़ी की विगोप आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि लोहे का शहतीर देकर मकान बना लेंगे। कुर्सी, टेबुल इत्यादि भी लोहे के बनते हैं। रेल के स्लीपर भी लोहे के बनने लगे हैं। किन्तु उपर्युक्त वस्तु के बनाने में कुछ अश तक लकड़ी की जरूरत पड़ेगी ही। फिर घर के लिये लोहे का शहतीर कितने को मयस्सर है? धनी लोग

श्री योगेन्द्रनाथ सिन्हा

तथा

श्री सच्चिदानन्द सिंह

मले ही उसे प्राप्त कर ले, पर गाव के साधारण लोग यदि घर इत्यादि के निर्माण में लोहे पर निर्भर होना चाहें तो यह असम्भव सा है। एक तो उनके कच्चे घर लोहे के शहतीर इत्यादि का भार समझल नहीं सकते और न वल ही लोहे का हल-जुआठ खींच सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इतना लोहा आयागा कहा से ? हमारे देश में इतना लोहा बनने में अभी सदिया लगेगी कि वह लकड़ी की जगह ले सके। फिर लोहे का दाम इतना ज्यादा पड़ेगा कि वह साधारण जनता की शक्ति और पहुच के बाहर ही रहेगा। हमारे यहा लोहे की तो कमी है ही, लेकिन वन की मात्रा भी कम होने के कारण सबको पूरी लकड़ी नहीं मिल सकती। तुलनात्मक दृष्टि से हम घर बनाने इत्यादि की लकड़ी, जलाने की लकड़ी, लकड़ी से कागज बनाने का जो पल्प ( Pulp ) निकलता है, इन सभी के खर्च में दूसरे देशो की अपेक्षा तकलीफ सहकर ही करते हैं। हमारे और दूसरे देशो में प्रत्येक व्यक्ति को कितना वन-पदार्थ सालाना खर्च करने को मिलता है उसका हिसाब यो है —

वन पदार्थ का विवरण	सालाना खर्च व्यक्ति पीछे		
	अमेरिकामें	स्वीडनमें	भारतवर्ष में
१ घर बनाने, कृषि के लिये तथा कुर्सी, टेबुल इत्यादि के लिये लकड़ी	३० मन	२८ मन	६ सेर
२ जलाने की लकड़ी	५॥ मन	२७ मन	१६ सेर
३ कागज बनाने का पल्प	३ मन	२ मन	आधा सेर

अब जलावन की लकड़ी का विषय लीजिये। लोग कह सकते हैं कि लकड़ी न मिले तो हम कोयला जलायेंगे या बिजली में खाना पका लेंगे। भू-गर्भ इतिहास से पता चलता है कि कोयला भी वन की लकड़ी से ही बना हुआ है जो लकड़ी अति प्राचीन युग में जमीन के नीचे भूचाल इत्यादि से गड गयी थी। कोयले की मात्रा भी सीमित है, वह रोज घटती है, बटती नहीं। यदि इस कोयले पर ही मनुष्य निर्भर करे तो एक-न-एक दिन कोयले की कमी के कारण उसे भीषण विपत्ति का सामना करना पड़ेगा। फिर दूर-दूर देहातो में कोयला भेजने का जितना खर्च पड़ेगा, उसका बोझ साधारण किसान सह नहीं सकते। सभी कोयला खर्च भी करने लगे तो कारखानो को—जिनका काम लकड़ी से नहीं चल सकता बडा भारी धक्का लगेगा। अभी तो भारतवर्ष में कारखाना की काफी कमी है, ज्यो-ज्यो कारखानो की मरया बढेगी, कोयले की खपत भी त्यो-त्यो बढती जायगी। इसलिए उचित है कि हम घर में लकड़ी ही जलावें और कोयले को कारखाने के लिए बचावे। यदि हम वन की रक्षा पर ध्यान रखे तो लकड़ी का भंडार कभी भी खत्म न होगा यद्यपि कोयले की खान शोष हो जायेंगी।

गिना, जो नन्धना का मुख्य ग्रग है, उसकी भी नामग्री वन से ही निर्माण हुई है। प्राचीन काल में भोज-पत्र या ताल-पत्र पर लिखा जाता था। अब कागज पर लिखा जाता है और कागज पर ही समाचार

छपते हैं। लेकिन कागज किस वस्तु से बनता है ? कागज भारतवर्ष में विशेष कर बास और सबई घास से बनता है तथा दूसरे देशो में पाइन स्पूस इत्यादि लकड़ी से। इससे स्पष्ट है कि वन न रहे तो शिक्षा और सभ्यता का स्रोत ही सूख जाय।

वन जडी-बूटियो की खान है, औषधि आयुर्वेदिक हो या एलोपैथि सभी का आधार मुख्यत वन की जडी-बूटी ही है।

शत्रुओ के आक्रमण में भी वन हमारी सहायता करता है। गत विश्व युद्ध में देखा गया कि गोला बारूद, हवाई जहाज इत्यादि रखने में जगह जगलो में ही खोजी गई। वन में छिपे रहने से हवाई जहाज के आक्रमण में इनकी रक्षा होती है। युद्ध के समय ऐसे देशो में भी जहा लोहा काफी है, लकड़ी की विशेष आवश्यकता आ पहुचती है। सेना के लिए जहा-तहा छोटी-छोटी छावनी बनाने में, जल्दीबाजी के पुल बनाने में खाना पकाने में लकड़ी के बिना काम नहीं चल सकता। इंग्लैंड ने १९१४-१९१८ तक की लडाई में अपने यहा जगल की कमी का कटु अनुभव किया था और तभी से एक फौरस्ट्री कमीशन (forestry commission) स्थापित हुआ जिसका काम था उत्तर खड में वृक्ष रोपकर वन बढाना पिछली लडाई में हम भारतवर्ष में ही देख चुके हैं कि तरह-तरह की लकड़ी किस अपरिमित मात्रा में लडाई के काम में लगी थी। बल्कि इस आवश्यकता की पूर्ति में इस देश के कई भागो में वनो की बुरी दशा आई। इससे ज्ञात होता है कि देश-रक्षा के लिए जितनी आवश्यकता सेना की है उतनी ही आवश्यकता वन और वन-पदार्थो की है।

दुर्भिक्ष के समय वन के कन्द-मूल तथा फल सहायक होते हैं। जि अचलो में वन है वहा भुखमरी कभी सुनी नहीं जाती। केन्द, पियार, वे महुआ इत्यादि के फल साधारणतया खाये जाते हैं। वन के निकट रहने वाले कुछ समय तक प्रधानत इन फलो पर निर्वाह भी कर लेते हैं। कई तरह के कन्दे, वन-आलू इत्यादि भी खोद कर खाने के लिये लाये जाते हैं। हिमालय पर अखरोट, स्ट्राबेरी, जगली अनार इत्यादि बहुतायत मिलते हैं। कोयनार के पत्ते का साग होता है और इण्डोफेरा सेलो की भाजी भी बनती है। वन के निकट रहनेवाले लोगो के लिए ख.द्य-समस्या उतनी विकट नहीं है जितनी अन्य लोगो के लिए।

मवेशी के चरने के लिए घास पर्याप्त मात्रा में वन में ही मिल सकती है। भारतवर्ष में प्राय २८ करोड मवेशी है और इनके लिए वन सरी प्राकृतिक चारागाह न मिलें तो चारा पैदा करके इन्हें पालना बडा कठिन प्रश्न हो जायगा। हमारे देश में जो ब्रजभूमि कभी वनो, उपवनो, लता कुजो, फल-फूलो से आच्छादित तथा झरनो के कल-कल और मयूरा पक्षियो के कल-कूजन से गुजित रहती थी, वह आज उजडा हो गई है। जहा बटे-बडे चरागाहो में गो-समूह चरा करते थे और घी-दूध का नदिया बहती थी वहा अब दूध के लाले पड गये हैं। यमुना के किनारे सुरम्य तट पर कृष्ण की मुरली के मधुर स्वर का साम्राज्य था, वनस्पति के अभाव से उसकी भूमि कट गई है। जिस गोवर्द्धन पर लता-कुज फूल-फल के सुन्दर वृक्ष शोभायमान थे, अब उसका सौन्दर्य नष्ट हो गया है और वृक्षो तथा वनो के अभाव में राजस्थान का रेगिस्तान तीव्र रूप से इस पुण्यभूमि को निगलता जा रहा है। किन्तु हर्ष का वात है

संरंकार का ध्यान ब्रजभूमि की इस हीनावस्था की ओर विशेष रूप से आकर्षित हुआ है और उसके पुनरुद्धार के लिये सरकार की ओर से इस भूमि में विभिन्न उपर्युक्त स्थलों पर वृक्षारोपण की विस्तृत योजना तैयार की गई है और कार्यारम्भ हो चुका है। आशा की जाती है कि निकट भविष्य में इसकी स्थिति बहुत कुछ सुधर जायगी।

### वन और व्यवसाय

वन कई तरह के व्यवसाय तथा उद्योग-घघो का केन्द्र या आधार है। वन तथा वन के इर्द-गिर्द शहरों में लकड़ी के कई कारखाने चलते हैं जिनमें बहुसंख्यक व्यक्ति रोजी पाते हैं। जंगलों में लकड़ी की कटाई, ढोलाई इत्यादि में लाखोंलाख आदमी जीविकोपार्जन करते हैं। लकड़ी के तरह-तरह के खिलौने बनते हैं, पेड़ और लताओं के छिलके से रस्सी बनती है और बास की टोकरी इत्यादि। इसी तरह बहुतेरे कुटीर शिल्प वन-पदार्थ पर निर्भर हैं।

विहार तथा मध्य प्रदेश में लाह की उपज कुसुम, पलास और बेर के वृक्षों पर होती है। अन्तःराष्ट्रीय व्यवसाय में लाह का मुख्य स्थान है। देश में चपड़े के कई कारखाने भी हैं जिनमें बहुत लोगों का भरण-पोषण होता है। रेशम और तसर, जिनका भारतवर्ष में काफी बड़ा उद्योग है, वन के ही पदार्थ हैं, क्योंकि इनके कोये तूत और आसन के पेड़ों पर लगते हैं। उत्तर प्रदेश में पाइन के पेड़ों से तारपीन बनता है, जिनके बड़े-बड़े कारखाने भी हैं। खैर के वृक्षों से कई प्रदेशों में कथ बनता है जिसका व्यवसाय भी काफी बड़ा है।

हरा का फल चमड़ा पकाने के काम में आता है और काफी मात्रा में विदेश भेजा जाता है। इसी तरह कई तरह के छिलके या पत्तों चमड़ा पकाने के काम में लाये जाते हैं। सेमल की लकड़ी से दियासलाई बनती है। वन पदार्थ बास या सबई घास से जो कागज बनता है उसका भी हमारे देश में बहुत बड़ा उद्योग है जिससे आर्थिक लाभ होता है और श्रमजीवियों को रोजी मिलती है। पकिंग बक्स, शस्त्र और औजार के मूठ आदि का भी व्यवसाय होता है।

भारतवर्ष में जितना वन चाहिये उससे कम है जिसके कारण कई वन-पदार्थ हमें विदेशों से मगाने पड़ते हैं। जो वन पदार्थ विदेशों से आते हैं उनका व्योरा यो है —

१ चीरी हुई लकड़ी	३,००,००० घनफुट
२ जलावन की लकड़ी	१००० घनफुट
३ कागज बनाने का पल्प	२१,००० घनफुट
४ अखवार का कागज	२,८७,००० घनफुट
५ दूसरे तरह का कागज या कूट	१,७१,००० घनफुट
६ फाइबर बोर्ड	३१,५०० घनफुट

रूपयों के हिमाव से वन-पदार्थों के आयात और निर्यात का आकड़ा यो है —

आयात	१९,६८,५०,००० रूपयें
निर्यात	७३,३०,००० रूपयें

अर्थात् लगभग १९ करोड़ रूपया हमारे देश का खर्च होता है बाहर से वन-पदार्थ खरीदकर मगाने में। इसके वितरित कनाडा देश को लकड़ी

इत्यादि बँचकर ३ अरब ३ करोड़ रूपया सालाना मुनाफा होता है और फिनलैंड को जो भारतवर्ष के एक प्रदेश के बराबर है, १ अरब ३४ करोड़ रूपयें की बचत होती है। यदि हम अपने वनों का क्षेत्रफल बढ़ाकर तथा उसकी स्थिति सुधारकर इस १९ करोड़ के आयात खर्च को बचा लें तो उनसे हम देश के कई कल्याणकारी कार्य आसानी से करके समाज को महान लाभ पहुँचा सकते हैं।

### वन का वैज्ञानिक प्रबन्ध

लोग कहते हैं, वन का प्रबन्ध क्या? पेड़ तो खुद बढ़ता है, आप उसे खींचकर तो बढ़ाते नहीं, तो प्रबन्ध किस लिये? वन की रक्षा ही करनी है तो उसे काटिये मत। लेकिन हम यहाँ बताना चाहते हैं कि वन में पेड़ काटे भी जा सकते हैं और साथ-साथ वन की रक्षा भी हो सकती है। यह कैसे?

वन एक सम्पत्ति है, जिस तरह हर सम्पत्ति से हमें आमदनी प्राप्त करने का हक है, गाय से दूध लेने का, खेत से उपज लेने का, घर से किराया लेने का और बैंक से अपने जमा रूपयों के मूद लेने का, उसी तरह वन-सम्पत्ति से भी लाभ उठाने का हमें अधिकार है। यह नियम हर सम्पत्ति पर लागू है कि उसका व्याज लिया जाय और मूलधन को सुरक्षित रखा जाय, तभी उस सम्पत्ति का कोई हानि न होगी। तो वन-सम्पत्ति का व्याज क्या है? इसका व्याज है उसके वृक्षों की सामूहिक वृद्धि। हर पेड़ पर हर रोज कुछ न-कुछ बढ़ता है। किमी भी वन के हरेक पेड़ की वार्षिक वृद्धि जोड़ी जाय तो वही उसका वार्षिक व्याज हुआ। यह तो सम्भव नहीं कि प्रत्येक पेड़को छीलकर उसकी वार्षिक वृद्धि निकाल ली जाय। इसलिए उस वृद्धि को वृक्षों की संख्या में परिणत करते हैं और उसी को कूप (Coupe) बनाकर निकालते हैं। कूप वन की वार्षिक वृद्धि हुई। ध्यान रखा जाता है कि काटने से कोई जगह खाली न हो जाय, बल्कि जहाँ पेड़ घने हैं वहाँ दो-चार पेड़ निकाल लेने से जो पेड़ बचें उन्हें बढ़ने में और भी सुविधा होगी। इससे आप समझ सकते हैं कि वैज्ञानिक रीति से वन काटने पर नुकसान नहीं हो सकता, बल्कि उसकी उन्नति होती है।

उसके व्याज का भी कुछ हिस्सा छोड़ दिया जाता है। वैज्ञानिक प्रबन्ध में अधिक लकड़ी काटने से भी जहाँ क्षति नहीं होती वहाँ बेनियम उसके आघात भी काटने से जगल नष्ट हो जा सकता है। यही कारण है कि जमीन्दारी जगल बहुत कुछ बरबाद हो गये लेकिन सरकार की देख-रेखवाले जगल दिन-दिन उन्नति पर हैं। वैज्ञानिक प्रबन्ध में वन को एक बड़ा वाग समझा जाता है। जिस तरह माली अपने वाग के हर पौधे की रक्षा करता है उसी तरह वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारीगण अपने वृक्षों की देख-रेख करते हैं। हमारे देश में वैज्ञानिक प्रबन्ध अभी कुछ नीचे स्तर पर ही है। यूरोप में फी एकड़ ३५ घनफुट लकड़ी हर साल निकाली जाती है लेकिन भारतवर्ष में अभी तक केवल २५ घनफुट लकड़ी प्रति एकड़ निकाली जाती है।

### वन और जल विद्युत

जल विद्युत संचार के लिये यह आवश्यक है कि नदियों में साल भर पानी बहा करे। स्वीटजरलैंड में कोयला नहीं है। वहाँ की रेल विजली से चलती है, कारखाने विजली से काम करते हैं और सड़क के किनारे लोहार

की भट्टी भी बिजली से गरम होती है। उन लोगो ने अनुभव से सीखा कि जल-विद्युत पैदा करने के लिये जिस जल की आवश्यकता है वह पहाडो के वनाच्छादित रहने पर ही नदियो से बराबर आता रहेगा। इसीलिए स्वीटजरलैंड में छोटी पहाडी भी वनहीन नहीं है, नीचे से तिहाई भाग तक पहाडी पर खेती या बागवानी की जा सकती है, पर इसके ऊपर के जगलो को काटने की कानूनन शक्त मनाही है। इटली में भी युगो के वीरान पहाड फिर से वृक्ष लगाकर ढके जा रहे हैं, बाढ को रोकने के लिये। अमेरिका में प्रतिवर्ष कई करोड डालर वीरान भूमि को वृक्षो से ढककर उर्वर मिट्टी बचाने में खर्च किये जाते हैं। कारण यह है कि जहा वन नष्ट हो गया है वहा की पैदावार कम होती जा रही है।

भारतवर्ष में कोयले की उतनी कमी नहीं है पर कोयले के खर्च में मितव्ययिता आवश्यक है। देश के प्रत्येक भाग में कोयला है भी नहीं, और जगह-जगह ले जाने में खर्च भी पडता है। इन कारणों से तथा बिजली को सस्ती करने के लिए अन्य देशो की तरह यहा भी जल-विद्युत संचार की व्यवस्था जोरो से की जा रही है। बड़े-बड़े बाघ (dam) बन रहे हैं, जैसे—भाखरा और नागल, दामोदर घाटी, हीराकुड इत्यादि। यहा इन्जिनियरो ने बड़े-बड़े बाघ (dams) बनाये गये हैं और बनाये जा रहे हैं। उद्देश्य यह है कि वर्षा जल का अधिक हिस्सा बाघ द्वारा निर्मित झीलो में सरक्षित कर लिया जाय और उसी जल के क्रमिक प्रवाह से जल-विद्युत का संचार साल भर होता रहे। अभाग्यवश इन इन्जिनियरो ने इस काम में वन के महत्त्व पर समुचित ध्यान नहीं दिया है। ऊपर 'वन और बाढ' के सम्बन्ध में बताया गया है कि किस तरह नग्न भूमि से वर्षा का जल मिट्टी काटकर बहाता है। जितने वर्गमील क्षेत्र से किसी झील में पानी आता है, उतने की मारी घुली मिट्टी आकर झील में विशेषकर बाघ के पीछे आकर जमा होगी और कुछ वर्षों के बाद झील का सतह उठ जागा और उसमें पानी जमा होने की जगह हर साल कम होती जायगी। यह निश्चित है कि यदि इन बाघो या झीलो के ऊपर वन का समुचित आच्छादन न हो तो ये उनके बहुत पहले आहत-सूची में आ जायेंगे जिस भय का इन्जिनियरो ने वन-महत्ता की अज्ञानता में अन्दाज कर रक्खा है।

ऊपर कहा गया है कि जहा समुचित रूप से वन है वहा वर्ष के विविध महीनो में वर्षा का विभाजन अधिक उपयोगी रूप से होता है। यह भी बतला देने की चेष्टा की गई है कि पहाडी अचलो में यदि वन न रहे तो सारी उर्वरा मिट्टी धुलकर बह जाय और खेती की जमीन ऊसर वीरान या धीरे-धीरे खन्दक वन जाय, इसलिए ऐसे इलाको में तो वन कृषि का सहयोगी ही नहीं, बल्कि प्राण है। 'वन और बाढ' शीर्षक के नीचे कहा गया है कि वन-मम्पन्न अचलो में वर्षा-जल को जमीन स्याही-सोख की तरह सोख लेती है और उसे मरक्षित कर बरसात के बाद कई महीनो तक झरना के रूप में बहाती रहती है जिसमें मिचाई में सुविधा होती है। इससे स्पष्ट है कि कृषि को वन ने बड़ी महायता मिलती है। पहाडो के ठीक नीचे जो नेत है वे तो एक ही वर्ष में मिट्टी, बालू, पत्थर से भर कर पैदा हो जाय यदि पेड की जड़े पहाड की मिट्टी को बाध कर न रक्खे।

वन में डंके पहाडो ने जो वर्षा-जल आता है वह अपने साथ सडी पत्तियो की मार लाता है जिसमें फसल को लाभ पहुँचाता है।

हल-जुआठ आदि खेती के समान वन के आस-पास किसानो को सस्ते दाम में सुगमता से मिल सकते हैं।

लकडी के अभाव से गोबर के कण्डे बनाकर जलाये जाते हैं। यदि लकडी काफी मिले तो यह गोबर खाद के काम में लाया जाता जिससे फसल में काफी वृद्धि होती। अन्दाज लगाया जाता है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग ४० करोड बँलगाडी गोबर इसी तरह जला दिया जाता है। यदि यह सारा गोबर खाद बनाकर खेत में डाला जाता दो अनुमानत ४० करोड मन खाद्य पदार्थ और अधिक पैदा होता।

### वन और वृष्टि

वन से वृष्टि का घनिष्ठ सम्बन्ध है। यो तो वृष्टि के अनेक कारण हैं और हो सकता है कि वनहीन जगह में कभी मूसलाधार वृष्टि हो और वनाच्छादित अचल सूखा रह जाय। परन्तु मूसलाधार वृष्टि से क्या लाभ? हमें तो थोडा-थोडा पानी साल भर या वर्ष के अधिकांश समय तक मिलता रहे तो खेती का काम ठीक से चले। यदि ५० इंच वर्षा हो या तीन महीनो में हो जाय तो उससे उतना लाभ नहीं होगा जितना कि इसकी आधी वर्षा बारह महीनो में बट कर हो। वन का हाथ इसी में है कि वर्षा को थोडा-थोडा करके बरसाता है। बिहार के पटना, शाहाबाद इत्यादि में जाड़े प्रौर बरसात के बीच बहुत कम वर्षा होती है किन्तु छोटानागपुर में बहुधा थोडा-थोडा पानी बरसा करता है, फलत टेवाघान की एक फसल बरसात के पहले ही लोग कही-कही उपजा लेते हैं। इस तरह की खेती वन के इलाको में ही सम्भव है। इसके अतिरिक्त वन हवा की गर्मी को घटाकर तथा उसे नमी प्रदान कर शीतल बनाता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में गया और पटने की अपेक्षा हजारीबाग और राची में गर्मी का प्रकोप कम रहता है। इसी तरह के उदाहरण अन्य प्रदेशो के सम्बन्ध में भी दिये जा सकते हैं।

### वन और बाढ

लोग कहा करते हैं कि लकडो इत्यादि की बात तो मानी जा सकती है पर जब आप यह समझाने लगते हैं कि पहाडो पर जगल हो तो नदियो में बाढ न आये, यह चन्द्रखाने का गप सा लगता है। कहा हिमालय और विन्ध्य पर्वत और कहा गंगा और सोन में बाढ? कहा छोटानागपुर की पहाडिया और कहा बगाल की बाढ। यह तो होमियोपैथी के मजाक सा दीखता है कि हरद्वार की गंगा में एक बूद दवा डाल दो और पटने में पी लो तो रोग अच्छा हो जाय।

वात कुछ अजीब सी लगती है जरूर, फिर भी सच्ची है। वन की अदृश्य उपयोगिताओ के समझाने में उन्ही कठिनाइयो का सामना करना पडता है जो यह प्रमाणित करने में कि पृथ्वी चिपटी नहीं, गोल है, हम ऊगली रखकर नहीं बता सकते कि पृथ्वी यहा गोल है, उसी तरह हम उ गली रखकर यह भी नहीं बता सकते कि देखिये वन-रक्षा की गई तो अमुक लाभ तुन्तर हो गया और वन-विनाश से अमुक हानि हो गई। वन रक्षा से जो लाभ होता है उसके होने में समय लगता है और उसके दुष्पयोग से जो हानि होती है उसमें भी समय लगता है। इसीलिए वन-बैज्ञानिक की वातो पर सहज में विश्वास नहीं किया जाता। परिणाम का दृष्टान्त देकर ही हम हानि या लाभ समझा सकते हैं।

बाढ का विषय ही लिया जाय। दो पहाडियो का मानसिक चित्रण कीजिए। दोनो एक दूसरे के समीप हैं पर एक पहाडी वन से पूर्ण आच्छादित है और दूसरी नग्न, वीरान। वर्षा हो रही है। देखा जाय दोनो पर वर्षा का क्या असर पड रहा है। पहले नग्न वीरान पहाड को लीजिये। वृन्दें सीधे जमीन पर आ पडती हैं और मिट्टी को कुदेद डालती हैं। मिट्टी के अच्छी तरह भीग जाने के बाद पानी पहाड के उतार पर बहने लगता है। पानी जितने नीचे बढता है उसकी गति उतनी ही तीव्र होती जाती है और उसमें मिट्टी-ककड, बालू बहाकर ले जाने की शक्ति भी उसी अनुपात से बढती जाती है। इसीलिए वीरान पहाड से जो वर्षा-जल नीचे छलाग मारता हुआ उतरता है, वह लाल होता है और उसमें मिट्टी, ककड भरा रहता है। ऐसे पहाड पर छाया तो है ही नहीं, जमीन धूप में सूखकर कडी हो गई है इसलिए पहाड की भूमि पानी को सोख भी नहीं सकती। अतः वर्षा का सारा जल गडगडाता हुआ और मिट्टी को धोकर बहाता हुआ नीचे चला आता है। वर्षा के दो-चार घटो के बाद उस पहाड को सूखा ही पाइयेगा। पहाड से जो पानी उतरा, वह छोटे नालो में गया, फिर बडे नालों में, और अन्त में नदी में। अब अनुमान कीजिए एक पहाडी जिला, जिसका क्षेत्रफल पाच हजार वर्गमील है और जिसमें जगल बरवाद होने के बाद इसी प्रकार नग्न, वीरान पहाड और पहाडिया हैं वर्षा तमाम हो रही है। अब इन सारे पाच हजार वर्गमील का वर्षा-जल एक ही साथ उतर कर यदि नदियो में एकाएक पहुच जाय तो बाढ को कौन रोक सकता है? इधर समतल में बाढ हुई और उधर पहाडी इलाके में उर्वरा मिट्टी बह जाने से फसल में कमी होने लगी। ऐसे इलाको में बरसात के कुछ दिनों के बाद ही नदी, नाले सभी सूखे मिलते हैं। सिंचाई के लिए पानी की तो बात ही न पूछिये, यहा तो मवेशी बरसात के बाद प्यासे फिरते हैं। ऐसे वीरान पहाड-वाले जिले में कितना भी पानी बरसे, बरसात के बाद पानी नहीं मिल सकता। बल्कि जितनी ही वर्षा अधिक हो, उतनी ही खराबी पहुचती है क्योंकि उसी मात्रा में मिट्टी भी धुलेगी और समतल में बाढ भी आयेगी।

अब देखा जाय उस पहाडी की हालत, जो वन के पेड, पौधो और लताओ से आच्छादित है। यहा वर्षा की वृन्दें पहले तो पत्तो पर पडनी हैं और यही उनकी ताकत खत्म हो जाती है। कुछ देर के बाद पत्तो से चूकर वर्षा-जल जमीन पर आता है। यह तो अनुभव सभी को है कि वर्षा आ जाय तो पहले लोग किसी पेड के नीचे पानी से बचने के लिए आश्रय लेते हैं। हल्की वर्षा हुई तो आदमी भंगने से बच भी जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि वन की जमीन पर जो वर्षा-जल पहुचता है, उसमें मिट्टी काटने की ताकत नहीं रहती है। जगल के भीतर की जमीन सूखी अत्रसडी पत्तियो से ढकी रहती है। वर्षा-जल उसके भीतर से होकर मिट्टी तक पहुचता है। यहा की मिट्टी मुलायम होती है और उसके साथ सडे पत्तो का खाद मिश्रित रहता है। यहा की जमीन वर्षा-जल का एक पूरा अग्र स्थाही सोख की तरह सोख लेती है और यही पानी पीछे झरना बनकर निकलता है। जो पानी बचा, वही पहाड के नीचे उतरता है। उसके उतरने में इतनी बाधाएं हैं कि पानी तेजी से नहीं बह सकता इसलिए

मिट्टी भी नहीं धुलती। पानी एक साथ नहीं बहकर धीरे-धीरे नाले और नदियो में पहुचता है। इसीलिए बाढ की सम्भावना नहीं रहती और उपजाऊ मिट्टी भी जहा की तहा बचकर रह जाती है। बरसात के बाद यही संचित वर्षा-जल नालो और नदियो में झरना बनकर आता है जिससे सिंचाई का काम हो सकता है। इस तह देखते हैं कि पार्वत्य अचलो में वन के अस्तित्व का कितना बडा महत्त्व है। कोसी की बाढ को जो भारत की समस्या हो गई है साधारण लोग दैवी प्रकोप समझते हैं पर उसका दायित्व तो मुद्दूर हिमालय के उस वनहीन हिस्से को है जहा से वह बहकर आती है।

### वन-प्रबन्ध का सक्षिप्त इतिहास

जब जगल जरूरत से ज्यादा था तब जगल काटकर आवाद करना ही धर्म समझा जाता था। यद्यपि यूरोप में सैंकडो वर्ष पहले से वैज्ञानिक वन-प्रबन्ध की व्यवस्था चल रही थी, पर भारतवर्ष में सर्व प्रथम सन् १८५६ ई० में वन-रक्षा की ओर ध्यान गया। जमीन्दारी जगलो को कानून के अन्दर लाने और उनको वैज्ञानिक प्रबन्ध की परिधि में दे डालने में बिहार ने सबसे पहले कदम उठाया और इसका श्रेय बिहार के राजस्व-मन्त्री श्री कृष्ण वल्लभ सहाय जी को है।

१९४६ ई० तक यहा करीब २५०० वर्गमील वन सरकारी प्रबन्ध में था पर उसके विपरीत करीब १० हजार वर्गमील वन जमीन्दारोंके हाथ नष्ट-भ्रष्ट हो रहा था। १९४६ में बिहार प्राइवेट फॉरेस्ट्स ऐक्ट (Bihar Private Forests Act) बना जिसके अनुसार प्राय सभी जमीन्दारी वन सरकार के प्रबन्ध में लाये गये। इसके बाद दूसरे-दूसरे प्रदेशो ने भी जमीन्दारी वनो को प्रबन्ध में लेने का कार्य आरम्भ किया।

किसी भी देश में जमीन का २० मे २५ प्रतिशत हिस्सा वन से आच्छादित रहना चाहिये जिसमें उपर्युक्त सभी पहलुओ से जनता का कल्याण हो। भारतवर्ष में भूमि का क्षेत्रफल ११,७६,८६४ वर्गमील है पर वन का रकबा १,७१, ३२८ वर्गमील ही है अर्थात् जगल जमीन का १४ प्रतिशत है, जबकि फिनलैंड में ७४ प्रतिशत, स्वीटजरलैंड में ५५ प्रतिशत, रूस में ४४ प्रतिशत, फ्रांस में २४ प्रतिशत और इटली में २० प्रतिशत वन है। इसलिए हमारे यहा वीरान जगहो में वन रोपकर बढाने की आवश्यकता है और जो वन बचा हुआ है उसकी भी वैज्ञानिक प्रबन्ध द्वारा उन्नति करनी है क्योंकि जहा यूरोप में एकड पीछे ३५ घनफुट लकडी की सालाना आमदनी होती है वहा भारतवर्ष में २५ घनफुट से भी कम।

वन रक्षा में सभी का गहरा सम्बन्ध है। कपडा, तेल, सिमेन्ट या गल्ला भी कम हो जाय तब विदेशो से मगा लिया जा सकता है, खेती एक साल उजड जाय तो दूसरे साल उममें पर्याप्त मात्रा में खाद देकर अच्छी फसल उपजायी जा सकती है, पर वन एक बार नष्ट हो जाय तो उसे न दूसरे देश से मगा सकते हैं या न एक-दो साल में तैयार ही कर सकते हैं। सखुआ या सागवान का पेड आज लगाया जाय तो एक सौ बीस बरस के बाद उससे काम की लकडी मिल सकती है। अतः वन-सम्पदा से लाभ उठाने के लिए काफी धैर्य और समय में काम लेने की आवश्यकता है।

# बिहार में कृषि का पुनरुसंधान

प्रो० केदारनाथ प्रसाद, एम० ए०

बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अति प्राचीन काल से कृषि, बिहारियों के प्रमुख पेशों में से एक रही है। राज्य की आर्थिक अवस्था मुख्यतः कृषि पर ही आधारित है, क्योंकि यहाँ की ८६ प्रतिशत आबादी कृषि पर ही प्रत्यक्षत निर्भर करती है। गावों के शिल्पी और मिलों में काम करनेवाले मजदूरों का भी कृषि से गहरा सम्पर्क है।

एक शब्द में, केवल अतः त में ही नहीं वरन् वर्तमान में भी राज्य का सम्पूर्ण आर्थिक सगठन कृषि के द्वारा ही निश्चित होता है। यह अनुमान किया गया है कि प्रतिवर्ष राज्य की कुल आय का ६७ प्रतिशत केवल कृषि से आता है। इस प्रकार बिहार में कृषि के महत्त्व को किसी प्रकार अस्वीकार नहीं किया जा सकता। निर्धन प्रजा, निर्धन राजा, निर्धन देशवाली पुरानी किंवदन्ती बिहार जैसे राज्य के लिए बिलकुल सत्य उतरती है।

मौसमी फसल के नष्ट होते ही समूची आर्थिक प्रणाली अव्यवस्थित और जोचनीय हो जाती है। कृषि के उत्पादन से ही हमारे बहुत से उद्योगों को कच्चा माल मिलता है। अनेकों व्यक्ति अन्य व्यापार में लगे हुए हैं। राज्य सरकार को कृषि के जरिये मालगुजारी और कृषि कर के रूप में खासी आमदनी होती है। बहुत अंश में कृषकों को अल्प क्रय-शक्ति के कारण कुछ उद्योगों में बनी वस्तुओं का उपभोग सीमित हो जाता है। कृषि की प्रगति से ही वनोन्नति भी होती है तथा इसी के द्वारा अन्तर्देशीय व्यापार का मतुलन निर्णीत होता है।

राज्य की निरन्तर बढ़ती हुई आबादी का एकमात्र सहारा भूमि ही है इसमें इन्कार नहीं किया जा सकता। पिछले तीन दशकों में भूमि पर जनसंख्या का भार बहुत अधिक बढ़ा है जिसके फलस्वरूप ग्रामीण आर्थिक प्रणाली में भयंकर गत्यरोध उपस्थित हो गया है। १९२१ और १९५१ के बीच जबकि जनसंख्या में ११० लाख की वृद्धि हुई है, कृषि योग्य भूमि में केवल २० लाख एकड़ की वृद्धि हुई है। प्रति वर्ष जन वृद्धि की दर १३ प्र० ६० रही है। प्रतिवर्ष ४ से ५ लाख तक नये मुह वढ जाते हैं। ग्रामीण जनसंख्या जिसके जीवन का मुख्य आधार कृषि है, प्रति दिन १२५ हजार ली दर में घटती है।

कृषि, जो बिहार की जानमा है, आज दयनीय स्थिति में गुजर रही है। हम जिन दृष्टिकोण में देखें, कृषि की ईकाई, श्रमिकों का उपयोग, परिवहन, आधुनिक तरीकों में फसल वृद्धि, बिहार की कृषि बहुत

ही पिछड़ी दशा में है। पशु पालन तथा कृषि से सम्बन्धित अन्य पेशों भी अभी तक अनिश्चित स्थिति में है।

प्रति एकड़ उत्पादन से जो आय हमें प्राप्त होती है, वह भी कृषि-जनक ही है। बिहार में प्रति एकड़ धान की उपज से ८८, गेहूँ से १८४, जौ से ७४, मकई से ६०, चना से ८२, तीसी से ३०, सरसो से ८२, ईख से २७३ और तम्बाकू से ८६० रूपयों की आय होती है। धान, जौ, गेहूँ, मकई और चना की प्रति एकड़ उपज क्रमशः ६२७, ६१७, ७७७, ६७२ और ६४४ पौंड है। यह तनिक चौंका देनेवाली बात है कि जहाँ भारत में प्रति एकड़ धान की उपज १०४५ पौंड है वहाँ बिहार में यह सिर्फ ६८७ पौंड है।

हमारी कृषि की सबसे बड़ी कठिनाई है, प्रति एकड़ उत्पादन की निम्न दर। खाद्य पदार्थ का कुल उत्पादन कम नहीं, प्रति एकड़ उपज भी अत्यन्त अल्प है। इसके बहुत से कारण हैं। बिहार में सिंचाई की व्यवस्था बहुत कम है। सभी सिंचाई के साधनों के बाद भी कुल बोई जानेवाली भूमि का केवल २३ ४ प्रतिशत ही सिंचाई की सुविधा से युक्त है। इस प्रकार यहाँ की कृषि पूर्णतया वर्षा पर आधारित रहने को बाध्य है। वर्षा की अपूर्णता और अनियमितता के कारण बहुत सी फसल मारी जाती है। कृषक अच्छे बीज का प्रबन्ध नहीं कर पाते, बीज को सुरक्षित रखने का उनका ढग भी अच्छा नहीं है। खेतों में खाद डालने की प्रथा अपूर्ण होने के साथ-साथ अर्धज्ञानिक भी है। खेती के पुराने तरीके और अज्ञानमयक हैं। पशु सहायक होने के बजाय बोझ बने हुए हैं। कृषक अनपढ़, रूढ़िवादी, भाग्य पर जीनेवाले और गरीब हैं। खेतों का विभाजन इतने बड़े पैमाने पर हुआ है कि एक खेत का औसत क्षेत्रफल ३५ एकड़ रह गया है। बिहार में प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि ३ एकड़ पड़ती है। अनाधिक चकलों के वावजूद भूमि ह्रास, फसल परिवर्तन का अज्ञान और सम्मिलित खेती के अभाव में भूमि का उचित उपयोग नहीं हो पाता। जंगली जानवरों, कीड़ों और टिड्डियों के चलते फसल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाता है। अधिकांश आबादी के कृषि पर आधारित रहने के कारण कृषि लाभदायक पेशा नहीं रह गई है। हमारी कृषि में अन्य भी कई न्यूनतायें हैं।

प्रथमतः यहाँ पूँजी का अभाव है। सहयोग समितियों का कार्य बहुत आशाजनक नहीं रहा है। कृषकों की गरीबी भी एक महान बाधा है। वे गरीबी में ही जनमते हैं, गरीबी में ही पलते और गरीबी में ही मर जाते

है। साहुकार और वनिये बिना किसी बाधा के उनका शोषण करते हैं। बाजार का सगठन पुराने तरीके पर होने के कारण भी उन्हें अधिक लाभ नहीं हो पाता। जीवन के आवश्यक साधनों को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार की रोजियों का सर्वथा अभाव है। ग्रामीण आर्थिक प्रणालियों में मौसमी और अपूर्ण रोजी ही लोगों के जीने का एकमात्र साधन है। भूमिहीन किसान किसी प्रकार अपने को जिन्दा रखने में समर्थ होते हैं। अधिक लगान तथा भयकर तगी के चलते उनके जीवन की सारी प्रफुल्लता लुप्त हो जाती है। उनको खेती जैसे मनहूस काम में लगा रहना पड़ता है, जिससे कि उनके जीवन में किसी प्रकार की विकास की समावना नहीं रहती है। इसके अतिरिक्त बाढ़ के भयकर प्रकोप से विहार की कृषि को भयकर धक्का लगा है। स्वतंत्रता प्राप्त के पहले अंग्रेजों की इस ओर से उदासीनता, निश्चय ही कृषि की दयनीय दशा के मूल में है।

यह कहना निष्प्रयोजन ही है कि राज्य तथा देश के कल्याण के लिये कृषि सगठन अत्यावश्यक है। आखिर किस प्रकार हम इस महान कार्य की पूर्ति कर सकते हैं? निश्चय ही सफल कृषि के मार्ग की सभी बाधाओं को हटाकर हम इस कार्य में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज की मजसे बड़ी आवश्यकता यह है कि कृषि के अधिकाधिक साधन हमारे पास हों। मिर्चाई के निम्न साधनों पर हमें निश्चय ही अधिक जोर देना चाहिये। सिंचाई के सम्बन्धित साधनों के जरिये कृषि में ५० से १०० प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है।

बीज के सुधार के फलस्वरूप भी उत्पादन में ५ से ६ प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। तीसरा स्थान खाद का है। उनके जरिये २० से ४० प्रतिशत उत्पादन बढ़ सकता है। सहयोग समितियों तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से सरकार को पर्याप्त जलावन का प्रवन्ध करना चाहिये जिससे गोबर का दुष्प्रयोग न हो सके। मिर्चाई की सुविधा, अच्छे बीज और उत्तम खाद के जरिये कृषि उत्पादन में २५ प्रतिशत वृद्धि हो सकती है।

खेती के वर्तमान तरीके में आज आवश्यक परिवर्तन जरूरी है। सरकार का कर्तव्य है कि वह कम दाम में खेती के आधुनिक औजार किसानों को दे। मानव श्रम के अधिकाधिक उपयोग को ध्यान में रखते हुए खेती के तरीकों का आधुनीकीकरण जरूरी है। बैलगाड़ियों की बनावट और आकार-प्रकार में भी सुधार अपेक्षित है। पशु पालन पर भी अधिक ध्यान देना होगा। अधिकाधिक पशु चिकित्सालयों, चारों को वृद्धि और नल सुधार के जरिये आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सकता है।

वयस्क मनाधिकार पर आधारित किसी भी गणराज्य के लिये यह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि वहां के किमान स्वयं अपने पथ का निर्माण करे। चाहे वह आर्थिक क्षेत्र हो या सामाजिक, राजन तिक क्षेत्र ही या सांस्कृतिक, सभी जगह उन देहातियों द्वारा उन्नति का पथ निर्मित हो सकता है। युग-युग से उपेक्षित किसानों और मजदूरों के प्रति हमें अपनी दृष्टि बदलनी होगी। उन्हें उचित शिक्षा देकर इन योग्य बनाना होगा कि वे आधुनिक विचार धारा से परिचित हो सकें। इसके लिए यह जरूरी है कि व्यावहारिक प्रदर्शन द्वारा उन्हें शिक्षा दी जाय। आधुनिक ङग को शिक्षा उनके लिए किसी काम की नहीं। खेतों को चक्रवन्दी का काम भी ईमानदारी से करना होगा।

अब जब कि जमीन्दारी प्रथा का उन्मूलन हो गया है उन क्षेत्रों में सहयोगी खेती अच्छी तरह हो सकती है।

खेती के तरीकों का राष्ट्रीकरण करके भूमि पर वर्तमान जनभार को कम करना होगा। कृषि में लगे हुए अतिरिक्त व्यक्तियों को लाभदायक रोजी के साधनों का विस्तार कर उन्हें इन योग्य बनाना होगा कि वे न्यूनतम आर्थिक सुविधा प्राप्त कर सकें। भूमि बन्धक, बैंको और सहयोग समितियों के विस्तार के द्वारा उन्हें सस्ती साख और कम दाम पर कृषि के औजारों का प्रवन्ध करना होगा। कर्ज देने के व्यवसाय को निश्चय ही स्वस्थ और सगठित होना होगा। कृषि बाजार का पुनर्निर्माण आज की अत्यन्त तीव्र आवश्यकता है और राज्य को उसके त्वरित विकास के लिए सन्नद्ध होना अत्यावश्यक है। बाजारों में फँसी बुराइयों को समूल विनष्ट करने में सरकारी दूकानें और सहयोग समितियाँ ही सफल हो सकती हैं। यदि आवागमन के साधनों तथा वहन सुविधाओं का सुचारु प्रवन्ध जल्द-से-जल्द किया जाय तो देहाती जीवन में एक महान परिवर्तन होगा और गांव तुन्तर ही आर्थिक कार्य के आकर्षक अखाड़े बन जायेंगे।

दस्तकारी और कुटीर उद्योगों का पुनर्वास आज कितना आवश्यक है, सम्भवतः उतना कभी नहीं था। अतिरिक्त जनशक्ति और कर्महीन अवकाश में आवश्यक सन्तुलन आज की तीव्र आवश्यकता हो गई है। कृषक में सुधार आज अत्यावश्यक है। अधिकाधिक वेकार पड़ी हुई जमीन कृषि के अन्तर्गत लाना होगा। इस प्रकार हम खाद्य की भयकर कमी जो आज समूचे आर्थिक निर्माण को उलटने पर तुली हुई है, को दूर कर सकते हैं। कृषि सम्बन्धी शिक्षा और खोज की निरन्तर वृद्धि होनी चाहिये। इसके लिये कालेजों को ग्र.मो में अधिकाधिक महत्ता में खोलना आवश्यक है। कृषि सम्बन्धी बीमा कम्पनियों को भी आज जरूरत कम नहीं। ग्राम बैंक भी इस दिशा में काफ़ी सहायता प्रदान कर सकेंगे और इनके जरिये अदूर-दर्शिता की समाप्ति तथा लोगों का भूमि, रूपया, मोना आदि के प्रति जो अत्यधिक मोह है उसका अन्त होगा। ये ग्राम सुधार के पथ की महान बाधाएँ हैं।

इन कृषि सम्बन्धी समस्याओं की भूमिका में पिछले वर्षों में सरकार द्वारा किये गये प्रयत्नों का अवलोकन लाभदायक होगा। हम कह सकते हैं कि सरकार ने इन सम्बन्ध में नात काम किये हैं १ मूद पर कर्ज देने की व्यवसाय के नियंत्रण का कानून, २ भूमि की मालगुजारी प्रथा में सुधार, ३ अधिक अन्न उपजाओं योजना की मृष्टि और उसकी सफलता के लिये सभी प्रकार की सहायता देने का कार्य ४ मिचन साधनों का निर्माण, ५ कृषकों को खाद, बीज और कृषि औजार आदि प्रदान करना, ६ पशुओं के स्नास्थ्य में सुधार और ७ फल तरकारियों के अधिकाधिक उत्पादन, ताः। दूध, मद्य आदि को अधिकाधिक मात्रा में नैयार करने की योजना।

१९४६ में विहार सरकार ने राज्य को खाद्य वस्तुओं के विषय में आत्म-निर्भर बनाने के विचार ने एक पंचवर्षीय योजना में ३,३३,०६,१६० रूपयों का अनावर्तक व्यय और १,३६,४४,६६२ रूपयों का आवर्तक व्यय करने का निश्चय किया गया। कार्यक्रम को सात भागों में विभक्त किया गया (१) कुएँ खोदना, (२) अल्प मिचन योजनाओं



का निर्माण, (३) ट्यूबवेल का प्रबन्ध, (४) सिंचाई की वृहद् योजनाओं का विकास, (५) चौरों का उद्धार, (६) बजर भूमि कर्षण तथा (७) खाद का प्रबन्ध ।

पिछले आर्थिक वर्ष तक करीब-करीब सभी क्षेत्रों में प्रगति रही । नीचे दिये गये लक्ष्य प्राप्त किये गये, मध्यम आकार की नहरें, पईन और वाघ ९०, कुए ४००१, ट्यूब पंप २०९७, लिफ्ट पट २३४७, ट्यूब पंप वेल १५, रहट १०५३, नहर कम्पोस्ट ४५७४ टन, खाद्यान्न क्रीत बीज ९४७२ मन, तरकारियों का बिका बीज ३०९ मन और कृषि सम्बन्धी साहित्य की ५००० प्रतियों का मुफ्त वितरण । १९५१-५२ में कृषि विभाग की खोज विभाग द्वारा खास कर ईख, खाद और आलू की खेती के सम्बन्ध में काफी काम किया गया । जगली जानवरों को मारने के लिए एक हथियार से लैस टुकड़ी का प्रबन्ध किया गया है । तरकारियों के बीज के विक्रय के लिए एक अर्थ के सम्बन्ध में आत्म निर्भर रखनेवाले उपाय का प्रबन्ध किया जा रहा है और फलों तथा तरकारियों की कृषि में सुधार लाने के लिये कृषि विभाग सन्नद्ध है । भूमि विकास कर्ज के जरिये बजर भूमि कर्षण के लिए २५ से २८ लाख रुपये प्रति वर्ष वितरित किये जाते हैं । लाखों की संख्या में कृषि योग्य बेकार भूमि जोती और बोयी जा रही है । प्राकृतिक विपत्तियों और विनाश के अवसर पर लोगों को सहायता दी जाती है ।

केन्द्रीय सरकार के जरिये सिन्दरी के खाद का कारखाना और राची में लाख अनुसंधान केन्द्र चलाये जा रहे हैं । कृषि की उन्नति में दोनों का महत्त्व अपूर्व है । लाल मिर्च, आलू, धान, गेहूँ, मकई और आम की बीमारियों को दूर करने के लिए कल्याणकर प्रयत्न सरकार द्वारा किये गये हैं । धान, गेहूँ, जौ, अरहर, चना, खेसारी, तीसी, सरसो, ईख और चीना वादाम के उत्तम प्रकारों की खोज हुई है । कृषकों को अच्छी फसल उपजाने के लिए उत्साहित करने के हेतु समय-समय पर फसल प्रतियोगिता सगठित की जाती है । इन प्रतियोगिताओं में जो प्रथम आते हैं उन्हें सरकार कृषि पडित की उपाधि प्रदान करती है । उन्हें ट्रेक्टर तथा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है । कुल राज्यों में करीब १० सरकारी फार्म हैं और उनमें से कुछ में पशुओं की नस्ल सुधार का काम बहुत सफल-पूर्वक हुआ है । इन फार्मों में अच्छे बीज, खेती के औजार तथा पशु सस्ते दर पर विक्रय के लिए रखे जाते हैं ।

पंचवर्षीय योजना में यह स्वीकार किया गया है कि किसी भी सगठित आर्थिक उन्नति की योजना में कृषि का पुनर्सगठन और सुधार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । हाल ही में खाद्य पदार्थ और कच्चे माल की बढ़ती हुई आवश्यकता के चलते समाज के सभी क्षेत्रों में इसके महत्त्व का अनुभव किया गया है । खेती में लगे हुए भूमि तथा श्रम के साधनों का उचित उपयोग करके ही पंचवर्षीय योजना पूर्ण रूप में सफल हो सकेगी । कृषि का विस्तार होने के माय ही-माय गहरी खेती भी अत्यन्त आवश्यक है । ग्रामीण आर्थिक प्रगति का आज निवमित रूप में सुधार करना आवश्यक है । आज एक नई और हमारी आवश्यकताओं के अनुरूप भूमि प्रथा की जरूरत है । खाद्य पदार्थों के माय ही व्यावसायिक दम्तुओं की पैदावार बढ़ाना आवश्यक है ।

अगर मकई, वाजरा, चीना वादाम, सावा, कोदो, महुआ का फूल आदि मोटे पदार्थों के उत्पादन को बढ़ाया जाय तो इससे सम्भवत खाद्य सकट की विकरालता कम होगी और जब तक कटनी नहीं होती या वर्षों के अभाव में बेकार पड़ी रहनेवाली जनता को रोजी प्रदान करने में तथा जीवित रखने के लिए इससे अच्छा उपाय नहीं हो सकता है ।

सिंचाई के दीर्घ और अल्प साधनों का विकास भी कृषि उत्पादन में सहायक होगा । जीवन और जगलो की रक्षा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । दुग्धशाला विकास, उद्योग और वागवानी के विकास के जरिये ग्रामीणों को रोजी का लाभदायक जरिया प्रदान कर सकते हैं । इसके लिये उन्हें सस्ते और हल्के शक्ति-यंत्रों और औजारों को प्रदान करना जरूरी है । नदी की सुविधाओं के विकास के साथ-साथ मत्स्य उद्योग भी विकसित होगा । कृषकों को आर्थिक सुविधा देकर आर्थिक निर्माण का काम सरल किया जा सकता है । सामूहिक विकास और ग्राम विस्तार योजना के जरिये ग्रामों में नवजीवन का संचार होगा ।

बिहार में १९५१-५२ के बीच ऐसा अनुमान किया गया है कि खेती पर १२ करोड़ ८४ लाख ३० हजार रुपये खर्च किये जायेंगे । राज्य सरकार ने ७७५९०० टन अधिक खाद्यान्न उत्पादन की योजना बनाई है जिसमें १२३००० टन का उत्पादन सिंचाई की बड़ी योजनाओं के और ३५३३०० सिंचाई के छोटी योजनाओं के फलस्वरूप होगा । बजर भूमि कर्षण के जरिये १६६३०० टन उत्पादन बढ़ेगा तथा अन्य विविध कार्यों से भी १३२३००० टन उत्पादन की वृद्धि होगी । ३००० गाठ अधिक रूई, १७४८००० गाठ अधिक जूट, ३५९००० टन अधिक ईख, ६०००० टन अधिक तेलहन का लक्ष्य भी अपनी पंच वर्षीय योजना में राज्य सरकार ने रखा है और इसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है । इस बीच २२५००० एकड़ बजर भूमि में कृषि होगी और ३६९००० एकड़ भूमि का सुधार किया जायगा ।

इसमें सदेह नहीं कि लोगों में उत्तम बीज का प्रचार किया जायगा । पर निरन्तर अच्छे प्रकार के बीज के प्रवेश से कहीं कृषकों को विश्वास न डिग जाय यह भी देखना होगा । खाद, पंचन, अनुसंधान, अन्नकर, कृषि शिक्षा आदि के अन्य पक्षों पर भी जोर देना होगा और उसके अनुसार काम भी किया जा रहा है, पर स्थानाभाव के कारण सबों पर विस्तृत विचार प्रस्तुत करना मेरे लिये संभव नहीं । अन्तिम महत्त्वपूर्ण बात यह है कि गावों का सहयोग के आधार पर प्रबन्ध कृषि के लिए अत्यन्त आवश्यक माना गया है । इस सिद्धान्त के अनुसार गाव की समस्त भूमि पर सम्मिलित खेती की जायेगी और समूची उपज को मिश्रित श्रम और अधिकार के सिद्धान्तानुसार गाव के व्यक्तियों में वितरित कर दिया जायगा । जब तक यह प्रबन्ध पूरा होगा तब तक उपज समिति, रजिस्टर्ड कृषि फार्म तथा कृषि सहयोग समितियां कायम कर काम चलाया जायगा ।

ऐसी आशा की जाती है कि इन साधनों के जरिये बिहार, जिसे भारत का हृदय कहा जाता है, अपने चिर गौरव को पुनर्लाभ करने में सफल हो सकेगा ।

भूदान यज्ञ के भगीरथ,

सन्त विनोबा ने यह सकल्प कर लिया है कि अब भारत में कोई भी व्यक्ति भूमि-हीन नहीं रहेगा। हर किमी के मन में भूदान यज्ञ के इस आन्दोलन के आधार को खोजने

## भूदान आन्दोलन का आधार

डा० श्रीमप्रकाश गुप्त, एम० ए०, एल० एल० बी०, डी० लिट्

की तीव्र उत्कठा होना स्वाभाविक ही है। जमीनो का वटवारा फिर से होना चाहिये इससे तो कोई भी व्यक्ति या दल असहमत नहीं हो सकता। सभी लोग इसकी आवश्यकता को मानते हैं और आज से नहीं वर्षों पहले से, अपनी-अपनी शक्ति और सगठन के अनुसार इसके लिए आवाज उठा रहे थे। हिन्दुस्तान आजाद हुआ। यदि आजाद हिन्दुस्तान की आजाद सरकार स्वयं ही जमीनो की इस समस्या को हल करने के लिये कोई कानून बना देती अथवा रूस और चीन की तरह यदि यहाँ भी तलवार के बल पर जबरदस्ती जमीनो पर कब्जा कर लिया गया होता तो शायद हिन्दुस्तान के प्रायः सारे राजनीतिक दल सन्तुष्ट हो जाते, किन्तु जरा सन्त विनोबा से तो पूछिये क्या वह भी चुपचाप अपने आश्रम में बैठे रहते? विनोबा चुप बैठनेवाले नहीं थे। उनके दिमाग में केवल जमीनो का फिर से वटवारा ही बात नहीं है इसीलिए तो जब कल्ल और कानून के रास्ते की बात आती है वह उसका विरोध करते हैं। विनोबा जी न तो कल्ल से भय खाते हैं और न कानून से ही उनको कोई घृणा है। दुनिया के सारे शान्तिवादी जन अपने सम्मेलन की दूसरी बैठक के लिए सेवाग्राम आकर रहे तो विनोबा जी ने उन सबको सम्बोधन करके बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं इन छोटे-छोटे घरेलू या आन्तरिक सघर्षों की अपेक्षा महायुद्ध को कहीं अधिक पसन्द करता हूँ। इसी प्रकार जब उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकार को भूदान-यज्ञ में मिली हुई जमीनो के सम्बन्ध में कानून बनाना था तो स्वयं विनोबा जी भी उस कानून के बनानेवालों में एक थे। विनोबा जी कल्ल और कानून के रास्तो को सिर्फ इसलिए नापसन्द करते हैं कि इन दोनों रास्तो से जमीने भले ही मिल जाए किन्तु जिस धर्म-विचार का प्रसार वह करना चाहते हैं वह इनसे हरगिज नहीं हो सकता।

बापू के स्वर्गवास के उपरान्त सेवाग्राम में एक सम्मेलन हुआ जिसमें गांधी विचार को समझनेवाले सभी बड़े-बड़े नेता तथा रचनात्मक कामों में लगे हुए अन्य बहुत से कार्यकर्ता उपस्थित थे। उस समय विनोबा जी ने सर्वोदय विचार को बड़े विस्तार के साथ लोगों के सामने रखा और साम्ययोग के आधार पर सर्वोदय समाज की रचना का कार्यक्रम देश के सामने आया। जो विनोबा दुनिया की दृष्टि ने मोझल होकर अबतक

अपनी प्रयोगशाला में बैठे हुए एक वैज्ञानिक की तरह अहिंसक समाज-रचना के प्रयोगों में डूबे हुए सर्वोदय शास्त्र के अनुसन्धान में निमग्न थे, अब बाहर आए। बापू के चले जाने के बाद सारे देश में जो एक

प्रकार की निराशा, जड़ता और किर्कतव्यविमूढता सी छा गई थी उसे दूर करने के लिए साम्ययोग का सबल लेकर उन्होंने अपनी पहली शान्ति यात्रा आरम्भ की। विनोबा जी की यह यात्रा मोटर और रेलगाडी के द्वारा हुई। इस यात्रा में जहाँ और बहुत से अनुभव हुए उन्होंने उपनिषदों के 'चरंवेति, चरंवेति' के इस मूल मन्त्र का प्रत्यक्ष दर्शन कर लिया। हैदराबाद की पंढरयात्रा को इसीलिए उन्होंने सर्वोदय यात्रा माना। इसी सर्वोदय यात्रा के सिलसिले में जब वह तैलंगाना में घूम रहे थे, एक दिन पोचमपल्ली नामके गाव में भगवान की ओर से उन्हें भूदान यज्ञ की प्रेरणा मिली। यदि पोचमपल्ली गाव के हरिजन ८० एकड़ जमीन की माग न करते और वहीं उनकी माग को पूरा करनेवाले श्री रामचन्द्र रेड्डी स्वेच्छा से खड़े होकर अपनी सौ एकड़ जमीन विनोबा जी को अर्पण न कर देते, यानी जहाँ जमीन मागनेवाले हैं वहाँ जमीन देनेवाले हैं इसका प्रत्यक्ष दर्शन विनोबा जी को न हो गया होता अथवा भूदान यज्ञ की यह प्रेरणा उन्हें न मिली होती तो क्या वह अपनी सर्वोदय यात्रा को समाप्त कर देते? कदापि नहीं। विनोबा जी ने शान्ति-सेना-काचन मुक्ति, शुद्ध व्यवहार तथा पूर्ण साम्य योग के जो प्रयोग अब तक किये, और कराये थे उनका व्यापक रूप अब वह देश में देखना चाहते थे और वास्तव में इसी विचार का प्रचार और प्रसार करने के लिए वह सारे देश में पंढर घूमना चाहते थे। इसका यह मतलब यह नहीं है कि भूमि की समस्या उनके सामने नहीं थी। भूमि की समस्या तो न मालूम कितने वर्ष पहले से उनके दिमाग में थी। सन १९३० में धूलिया जेल में जब किसी ने उनसे पूछा कि स्वराज्य प्राप्ति के बाद आप सबसे पहले कौन सा काम हाथ में लेंगे तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं सबसे पहले भूमि वितरण के काम को ही करूँगा।

विनोबा जी आज जब बार-बार कहते हैं कि भूदान यज्ञ बापू का ही काम है और जो मैं कर रहा हूँ बापू का ही काम कर रहा हूँ तो इसमें विनोबा की अपार विनम्रता और अगाध गुरुभक्ति तो है ही, किन्तु भूदान यज्ञ आन्दोलन की उम्र आधारशिला की थोर भी सकेत है जिसके बीज गांधी जी ने अपने जीवन काल में ही डाल दिया था। फरवरी सन १९३० के अपने साप्ताहिक 'यंग इंडिया' में बापू जी ने लिखा है:

“अहिंसा के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट पैसेवाले, स्टेटवाले, जमीन्दार, मिल मालिक वगैरा देशी स्वार्थ है। अंग्रेजी राज्य ही इनके जन्म का कारण है। यह इतना नहीं समझते कि जनता के खून पर इनका जीवन चल रहा है। जब समझमें आता भी है तो वे जिन अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली और दलाल बने हुए हैं उन्हीं की तरह बेरहम हो जाते हैं। उन्हें सहज ही यह समझ लेना चाहिये कि जब अपने लाखों-करोड़ों भाई-बहन दाने-दाने को तरसते हैं तो उन्हें दबाये रखना एक जुर्म है और इसलिए उन्हें अपनी दलाली छोड़ देनी चाहिए।”

जमीन्दारों को समझाते हुए कराची कांग्रेस के बाद बापू जी ने कहा था —

“मैं आपके दिल तक एक सत्य पहुँचाना चाहता हूँ। आपको बदल देना चाहता हूँ ताकि आपके पास जो कुछ अपनी निजी सम्पत्ति हो उसे आप अपनी प्रजा के लिए ट्रस्ट की तरह रखें और उन्हीं के हित में इसका इस्तेमाल करें। लेकिन मैं आपको सावधान भी कर देना चाहता हूँ। मैं आपको कहूँगा कि आपकी जमीन पर जितनी मालिकी आपकी है उतनी ही किसानों की भी है। आपको अपने माल को ऐशो आराम या फिजूलखर्ची में न उड़ाकर किसानों की भलाई के काम में लगाना चाहिये। जहाँ एक बार आपने अपने किसानों के साथ प्रेम का नाता जोड़ा और उन्हें लगा कि आप उनके हैं और वह आपके, एक परिवार की नाई उनके हित आपके साथ सुरक्षित हैं तो विश्वास रखिये उनमें और आपमें कभी टक्कर नहीं हो सकती।”

आदर्श जमीन्दार कैसा हो इस पर भी बापूजी ने स्पष्ट कहा है —

“आदर्श जमीन्दार को इस बात पर सन्तोष नहीं कर लेना चाहिये कि यदि गाववाले स्वास्थ्य और सफाई के नियमों का पालन नहीं करते तो वह क्या करे। किसान को उसके जीवन की जरूरी चीजें दिलाने के लिये वह खुद गरीब बन जाय, वह अपने इलाके के किसानों की आर्थिक स्थिति का अध्ययन करे, ऐसे स्कूल खोलें जहाँ किसानों के बच्चों के साथ ही उसके बच्चे भी पढ़ें। गाव के कुँआरों और तालावों की सफाई करे। किसानों को सड़क पर झाड़ू देना सिखाए और उसका मँला खुद ही उठाए। यदि वह समय की गति को पहचान जाय तो उसका यह ख्याल कि मेरे पास जो चीजें हैं उनपर ईश्वर की ओर से मुझे हक मिला हुआ है बदल जायगा और देखते-देखते हमारे देश के सात लाख घर जो आज गाव कहलाते हैं शान्ति, स्वस्थ और सुख-चैन के श्रोत बन जायेंगे।”

सन् १९३९ की गर्मियों में जब वह विहार आए हुए थे तो चम्पारण जिले के वृन्दावन नामक स्थान में किसानों से उन्होंने कहा था

“मैं मानता हूँ कि जिन जमीन को तुम जोतते हो वह तुम्हारी होनी चाहिये लेकिन वह एकदम तुम्हारी नहीं हो सकती। जमीन्दारों से तुम उसे छीन थोड़े ही सकते हो? अहिंसा ही एक रास्ता है, तुम अपनी खुद की शक्ति को पहचानो।”

अन्त में सन् १९३९ में ही उन्होंने कहा था —

‘मन्ना ममाजनाद तो हमें हमारे पुरखों ने विरामत में मिला है जिन्होंने पिताया “सुप्रभू भूमि गोपाल की” फिर इन भेद-भाव का सवाल

ही कहा पँदा होता है। मनुष्य ने ही इस भेद-भाव को बनाया है और इसलिये मनुष्य ही उसे मिटा सकता है।”

“मुझे पूरा विश्वास है कि हम अपने इस ध्येय की पूर्ति का उतना ही बढ़िया रास्ता निकाल सकते हैं जितना रूस हो चाहे कोई अन्य देश निकाल सकता है। हमारा रास्ता बिना हिंसा का होगा। जमीन और धन तथा जायदाद उसकी जो हो वह उस पर काम करे।”

सन् १९४२ में आगा खा जेल में मीरा बहन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बापू ने इस प्रश्न को और भी स्पष्ट करके कहा था .

“जमीन पर मालिकी सरकार की होगी। मेरा ख्याल है कि हुकूमत की बागडोर ऐसे लोगों के हाथ में होगी जिन्हें इस आदर्श में विश्वास है। ज्यादा जमीन्दार तो राजी से ही अपनी जमीन छोड़ देंगे और जो ऐसा नहीं करेंगे उन्हें कानून से करना होगा।”

जमीनों के बटवारे की समस्या सन् १९३० से ही विनोबा जी के मन में इतनी तीव्र थी और फिर बापू जी ने समय-समय पर इस मसले पर जितनी गहराई और स्पष्टता से प्रकाश डाला है इन सब चीजों को देखकर यदि लोग जमीनों के बटवारे को ही विनोबा जी के इस भूदान-यज्ञ आन्दोलन का उद्देश्य या आधार मान बैठें तो हम उन्हें अधिक दोष नहीं देंगे। हजारों जगह और हजारों तरह से इस युग के अध्ययन स्वयं विनोबा जी ने इस आन्दोलन के आधार के सम्बन्ध में पर्याप्त प्रकाश डाला है किन्तु फिर भी जब बार-बार लोग पूछते हैं क्या कानून का आश्रय लिए बिना जमीन की समस्या हल हो सकती है? आपके कार्यों की सफलता कब तक संभव है? “क्या जमीन जैसी महान समस्या युद्ध और हानि के बिना हल हो सकती है?” “भूदान यज्ञ से जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे, क्या आर्थिक दृष्टि से यह अपर्याप्त और अहितकर नहीं होगा? “गरीबों से जमीन लेकर क्या आप उन्हें और गरीब नहीं बनाते हैं?”, “हमारे देश की चारों सीमाओं पर कम्युनिज्म का प्रचार हो चुका है। ऐसी स्थिति में हमारी रचना टिकेगी या नहीं यह शका हो रही है। आप यह भूदान यज्ञ ही जारी रखनेवाले हैं या और कोई प्रोग्राम देश के सामने रखनेवाले हैं ताकि भारतीय समाज-रचना टिक सके?” तो हमें लगता है कि ये लोग अभी तक भूदान यज्ञ के इस आन्दोलन का उद्देश्य केवल जमीनों माग कर वंजमीनों को बाट देना मात्र ही समझते हैं। ऐसे लोगों से और उनके द्वारा सबको फिर एक बार हम बड़े जोरदार शब्दों में यह बतला देना चाहते हैं कि भूदान-यज्ञ के इस आन्दोलन का उद्देश्य केवल देश की जमीनों का बटवारा ही हरगिज नहीं है। हमने तो एक सभा में यहाँ तक कहा था कि यदि इसका उद्देश्य केवल जमीनों का बटवारा मात्र होता तो हम तो हरगिज इसमें शामिल नहीं होते, क्योंकि आज की विषमता-मूलक समाज व्यवस्था के रूते हुए इस तरह का कोई भी बटवारा टिकाऊ नहीं हो सकता। वास्तव में भूदान यज्ञ तो आज के हमारे समाज में स्थापित समस्त विषमताओं को दूर करके साम्य योग के आधार पर केवल बहुसंख्या का नहीं बल्कि सारे समाज का हित चाहनेवाले सर्वोदय समाज की स्थापना का एक साधन मात्र है। स्वयं विनोबा जी ने भूदान यज्ञ को धर्म-विचार के प्रचार का वाहक माना है। विनोबा जी का कहना है कि “मैं पहले विचार

परिवर्तन के द्वारा लोगों का हृदय परिवर्तन करूँगा, उसके बाद उनका जीवन बदलूँगा और अन्त में पूरे समाज का ही परिवर्तन करूँगा।” विचार सूक्ष्म होते हैं उनपर लोगो की दृष्टि आसानी से नहीं ठहरती। उनका प्रचार करने के लिए, अतएव, किसी स्थूल आधार या माध्यम की जरूरत होती है। “सर्व भूमि गोपाल की”, “सब सपति रघुपति के आही” “सर्वभूत हितैरत” तथा “तेन त्यक्तेन भुजीथा ” इत्यादि सूक्ष्म धर्म विचारो को समझाने के लिए वास्तव में भूदान यज्ञ का सहारा लिया गया है। एक कट्टा और दो कट्टा जमीन रखनेवाले से भी कुछ-न-कुछ दान में देते क्यो ? यदि जमीनो का वटवारा मात्र ही इस आन्दोलन का ध्येय होता तो फिर इन छोटी जमीनवालो से दान-पत्र भरवाने का कोई मतलब नहीं था, इन्हें तो उल्टे जमीन मिलने ही वाली है। वास्तव में भूदान यज्ञ में असली सकेत तो सम्पत्ति और स्वामित्व के विसर्जन का है और सम्पत्ति और स्वामित्व में परिमाण की कीमत नहीं होती, एक पैसा भी सम्पत्ति है उसका भी मोह होता है, एक कट्टे जमीन में भी स्वामित्व छिपा रहता है।

ऊपर हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन और अन्त में समाज परिवर्तन की बात आई है। इसी त्रिसूत्री परिवर्तन को धर्म विचार या साम्य योग समझना चाहिए। विनोबा जी ने भूदान यज्ञ को इसी विचार का वाहन माना है। सक्षेप में यह त्रिसूत्री परिवर्तन ही भूदान यज्ञ का आधार है। इसलिए अब अति सक्षेप में इस त्रिसूत्री परिवर्तन का ही विवेचन करेंगे। हृदय परिवर्तन, जीवन परिवर्तन और समाज परिवर्तन इन तीनों के पीछे हमारी क्या कल्पना है यह अच्छी तरह से समझने के लिए पहले हृदय जीवन और समाज की, प्रक्रियाओं तथा उनकी वर्तमान स्थिति पर विचार कर लेना आवश्यक है। ससार के अन्य प्राणियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो यह बात हृदय तय करता है, ससार की समस्त भोग्य वस्तुओं की ओर हमारा जैसा रुख रहता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है और प्रकृति या ईश्वर से मिली हुई योग्य वस्तुओं की व्यवस्था करना समाज का धर्म है।

ससार में अगर एक ही मनुष्य होता तो उसके सामने हृदय परिवर्तन का या समाज परिवर्तन का प्रश्न ही कभी नहीं आता। उसके सामने सिर्फ इतना ही सवाल होता कि अपना जीवन चलाने के लिए वह आस-पास की सृष्टि का कितना और कैसा उपयोग करे, किन्तु मनुष्यो का एक समूह या समाज विद्यमान है। इसलिए अब उसके सामने इस भौतिक प्रश्न के अतिरिक्त एक दूसरा सामाजिक प्रश्न भी आ जाता है अर्थात् इस प्रश्न के अतिरिक्त कि सृष्टि पर अधिकार कैसे किया जाय ये प्रश्न भी उसके सामने आते हैं कि एक दूसरे के प्रति कैसा व्यवहार करे, अर्थात् मनुष्य अपने पारस्परिक व्यवहार में समाज के मानमिक सुख-दुःख का सतुलन कैसे ममाले ? तथा उनमें आपस में व्यवस्था कैसे की जाय अर्थात् मनुष्य की मित्कयत, जिसमें जमीन, धन-दौलत, बल-बुद्धि इत्यादि मारे गुण सब शामिल हैं, आपस में कैसे बाँटी जाय। वास्तव में आज हमारे सामने ही नहीं पूरे मानव समाज के सामने केवल एक यही समस्या है यदि उसकी यह समस्या हल हो जाय तो सारी समस्याएँ हल हो जाय। सृष्टि के आदि

से यही समस्या मनुष्य को तग करती आ रही है। अबतक कितने युग बीत गये, कितनी सम्यताएँ आईं और खतम हो गईं, कितने राजनीतिक दल बने और बिगड़ गये और कितनी क्रान्तियाँ आईं और चली गईं, कितने सत-महात्मा और मुधारको ने इस समस्या को हाथ में लिया और आगे बढ़ाया किन्तु पूरी तरह से अभी इसका हल किसी को मिला नहीं।

आज के युग को विज्ञान का युग कहते हैं। प्रकृति को उन्होंने जीत लिया है ऐसा उनका दावा है। देग, काल और दूरी के बंधनों को भी आज के वैज्ञानिक ने तोड़ फेंका है। सुख और सुविधा की इतनी अधिक और ऐसी-ऐसी चीजें उन्होंने तैयार कर ली हैं जिनकी कुछ समय पहले मनुष्य को कल्पना भी नहीं थी। उत्पादन, कार्यक्षमता और आयातनिर्यात के साधनों में भी वेहद उन्नति उन्होंने कर डाली है, किन्तु फिर भी जब चारो ओर बढ़ती हुई बेकारी और भुखमरी को देखते हैं तो स्वभावतया यह प्रश्न मन में उठता है कि इतनी विपुलता में इसी विपन्नता क्यो ? दुनिया में भौतिक दूरी जितनी ही कम होती जाती है उतनी दिलो की दूरी बढ़ती जाती है ऐसा क्यो ? जितना हम एक दूसरे के पास आते जाते हैं उतना ही एक दूसरे के खून के प्यासे होते जाते हैं, ऐसा क्यो ? अभी पहले महायुद्ध का भय निकला नहीं था कि दूसरा उससे भी भयकर महायुद्ध आ गया और दूसरे के आसू अभी सूखे नहीं कि तीसरे की तैयारियाँ चल रही हैं। यह सब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। ऐसा क्यो हुआ इसका मुख्य कारण यही है कि भौतिक विज्ञान का अध्ययन तो हमने खूब आगे बढ़ाया किन्तु मानव विज्ञान या आत्म विज्ञान (नाइन्स और फ्रॉइड) को बिल्कुल भुला दिया। भौतिक प्रगति और आध्यात्मिक प्रगति के बीच में एक बड़ी खाई पड़ गई, एक बहुत तेज गति से आगे बढ़ती ही चली गई और दूसरी इतनी पीछे रह गई कि लोगो को इसका स्मरण ही नहीं रहा। वे भूल गये कि उसकी जरूरत है। भौतिक विज्ञान भोग की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा सकता है, जहाँ पहले एक छटाक पैदा होता था वहाँ तीन छटाक कर सकता है, जहाँ पहले एक गज कपडा तैयार हो सकता था वहाँ तीन गज तैयार कर सकता है और उमने ऐसा किया भी किन्तु विज्ञान गेहूँ को भूखों के पास और उस कपडे को नगों के पास ले जाने का काम तो नहीं कर सकता, यह काम तो मनुष्य को ही करना है। अब हम देखते हैं कि लाखों मन गल्ला जला दिया जाता है, हजारों गाँठ कपडे को बर्बाद कर दी जाती है और यह सब उचित और शास्त्रीय समझा जाता है तो हमें लगता है मनुष्य विज्ञान का गुलाम हो गया है। अर्थ के कोडों ने उसकी सारी मानवता को छीन लिया है, उसकी समझ में नहीं आता है कि अन्न का प्रथम और अन्तिम कार्य क्षुधा शान्ति है, कपडे का निर्माण शरीर की रक्षा के लिए हुआ है, तन ढकने में ही उसका उपयोग है और हरेक प्राणी को भूख लगती है तथा हरेक प्राणी को ही वस्त्र की आवश्यकता होती है। अतएव अन्न, वस्त्र आदि जीवन की जितनी भी उपयोगी और आवश्यक चीजें हैं उनपर सबका ही समान अधिकार है, जिसको जब और जितनी चीजों की जरूरत हो उमे तब और उतनी चीजें मिलनी चाहिये। घर में घर की मारी चीज पर जैसे घर के सभी लोगो का नामान अधिकार होता है उममें यह नहीं देखा जाता कि यह लडका तो बीमार रहता है, कोई काम ही इमने नहीं होता और वह लडका तो खूब काम करता है इसलिए

उसे अधिक मिलना चाहिये बल्कि प्राय ठीक उसका उल्टा ही होता है, जो वीमार है कम या विलकुल ही काम नहीं कर सकता उसे बहुत अधिक मिलता है और जो बहुत ज्यादा काम करता है उसे बहुत कम और कभी-कभी तो विलकुल नहीं मिलता। क्यों ? घर के सारे लोग जितनी उनमें शक्ति है उसे पूरी तरह से लगाकर घर को सम्पन्न और समृद्ध बनाते हैं। वे लोग व्यक्तियों के रूप में नहीं सोचते, पूरे घर के रूप में सोचते हैं। विचार कीजिए, यदि उस घर के लोग यह तय कर लें कि प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता को न देखकर उसकी योग्यता के अनुसार अथवा उसकी कार्य क्षमता के अनुसार कम या ज्यादा पारिश्रमिक अथवा जीवन की सुविधाएँ मिलनी चाहिये तो वह घर रह जायेगा या एक जीता जागता घुंघरुआ बन जायेगा ? जितने समर्थवान होंगे उन्हें ही सबसे अधिक सुख-सुविधाएँ मिलेंगी, उनका जीवन स्तर बहुत ऊँचा उठ जायेगा किन्तु जो किसी कारण से थोड़े असमर्थ या रोगी होंगे उनका जीवन विलकुल ख़ाई में गिर जायेगा। बच्चे और बूढ़ों की क्या दशा होगी इसकी पाठक लोग स्वयं कल्पना करें और देखें कि इस प्रकार की गृह-व्यवस्था कितने दिन तक टिकेगी। अब उसी घर का दूसरा चित्र देखिये, जहाँ घर के सारे लोग मिलकर प्रत्येक व्यक्ति को वोट का अधिकार दे देते हैं और सब काम वोट के बल पर चलता है तो घर में यदि १० व्यक्ति हैं और उनमें से मान लो एक दिन ६ व्यक्तियों ने तय कर लिया कि आज केवल मिर्चों का ही साग बनेगा तो जिन चार को मिर्च नुकसान देती है सोचिये उनकी दशा क्या होगी ? जब तक बहुत सख्या की राय से अल्प सख्या के हितों की रक्षा की जायेगी तब तक पारिवारिक वातावरण स्थापित नहीं हो सकता। मिर्च न खानेवाले मिर्च खानेवालों में से किसी को अपनी और फोड़ना चाहेंगे और मिर्च खानेवाले इसे सहन नहीं करेंगे, तब देखिये, घर का सा आखाडा बन जाता है। अब मान लीजिये घर के कुछ मनचलें लोग समता लाने का निश्चय करके यह तय कर लें कि जिन लोगों के हाथ में सत्ता है उन्हें खत्म किये वगैर समता नहीं आ सकती तो फिर सारा घर ईर्ष्या और द्वेष की भट्टी ही बन जायेगा। शान्ति नहीं आ सकती क्योंकि हिंसा में से प्रतिहिंसा का ही निर्माण होता है चाहे थोड़ी दशा तक शान्ति जमी दिखाई देती रहे। इतना ही नहीं उसके कारण मनुष्यता का मूल्य घट जाता है। उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है।

समाज घर का ही एक समष्टि रूप है, उसी का एक बड़ा आकार है। उन्नीके लिए जो चीज घर के मन्वन्व में है वही पूरे समाज के लिए भी लागू होती है। ऊपर की चर्चा में हमने देखा कि जब तक हम मनुष्य-मनुष्य में भेद करते रहेंगे मानव समाज में शान्ति नहीं आ सकती। शान्ति तो तभी आ सकती है जब हम यह अनुभव करने लग जाय कि हरेक मानव में एक ही आत्मा नगमान रूप में है। आत्मा की एकता का अनुभव जिस दिन मनुष्य को होने लगेगा वह उन्नीके आधार पर और भी गहराई में विचार करेगा। जब प्रत्येक मनुष्य में अपना और अपने में नवका दर्शन उसे होने लगेगा तो फिर उन्नीके आन्वयनाएँ भी नवकी आवश्यकताएँ बन जायेगी, वह उन्नीके ही आन्वयनाएँ या दुवका छिपा अथवा चोरी करके कोई चीज नहीं लगेगा। जे जब भूष लगेगी तो वह नोचेगा कि श्रीरो को भी भूष लग लगेगी, जे जब टड लगेगी तो वह मोचेगा कि श्रीरो को भी ठड लग

रही होगी और इसलिए अन्न और वस्त्र पर सबका उतना ही अधिकार है जितना उसका। वह सबको खिलाकर खाने में और सबको पहनाकर पहनने में ही आनन्द का अनुभव करने लगेगा।

जब हम एक दुनियादी आध्यात्मिक विचार ग्रहण करते हैं तो जीवन की अनेक शाखाओं, नैतिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इत्यादि में हमारा प्रवेश हो जाता है। हमारे पास जो कुछ भी जमीन जायदाद, सम्पत्ति, बुद्धि-शक्ति इत्यादि है सबका मालिक भगवान है हम नहीं। और चूँकि हमारे सभी गुण समाज के लिये हैं अतएव हमें चाहिये कि हमारे पास जो शक्तियाँ हैं उन्हें हम ईश्वर की देन मानें और समाज को अर्पण कर दें। इतना ही नहीं अन्त में तो वह अपने शरीर पर भी अपनी मालिकी नहीं मानेगा। हमने शुरू में ही किसी जगह कहा है कि भूमि दान यज्ञ का यह आन्दोलन सम्पत्ति और मालिकी के मोह को दूर करना चाहता है। गरीब और अमीर जब हमें अपनी सब प्रकार की सम्पत्ति का स्वच्छा से एक हिस्सा दरिद्रनारायण के लिए देते हैं तो उनके हृदय में एक बड़ा भारी परिवर्तन आता है। इस आन्दोलन का सिंहावलोकन करते हुए विनोबा ने एक जगह कहा है—

“भूदान यज्ञ से जो हवा बन रही है, नैतिक मूल्यों की जो प्रतिष्ठा लोगों के ध्यान में आ रही है, सामाजिक अन्याय न सहन करने की और मुक्त होने की जो तीव्र भावना पैदा हो रही है, जो सबसे पिछड़े हुए हैं उनकी और सबसे पहले ध्यान देना चाहिये यह बात जो लोगों की समझ में आ रही है जिसे मैंने प्रजा सूय यज्ञ कहा, धर्म प्रवर्तक चक्र कहा, बेजबान मजदूरों का उत्तर कहा, उसके मुकाबले भूमि का मसला हल होने की बात में विशेष महत्त्व को नहीं मानता। यह जो आबहवा फँली है, और इसमें जो प्राण है, इसका स्पर्श सबको हुआ तो न सिर्फ भूमि का मसला ही हल होगा बल्कि सारे मसले हल होंगे क्योंकि मानव समाज में जो-जो मसले पैदा हुए हैं उन सबके मूल में जो कुप्रवृत्ति और उद्वुद्धि है उसी पर इससे प्रहार होता है।”

मनुष्य के आचार-व्यवहार में ही उसके हृदय का सच्चा दर्शन होता है। इसको उलट कर यो भी कह सकते हैं कि जैसा उसका हृदय होता है वैसे ही उसके आचार व्यवहार भी बन जाते हैं। आज हमारे जीवन में जो नित्य नए-नए मसले पैदा होते चले जाते हैं तो उसका मूल कारण हमारे हृदय की वह कुप्रवृत्ति और उद्वुद्धि ही है जो “हम और हमारे ही लिए सब कुछ होना चाहिये” की अति सकुचित भावना को जाग्रत करके कम-से-कम या विलकुल ही श्रम न करके अधिक-से-अधिक प्राप्त कर लेने की जीवनाकाक्षा। आज हमें लाखों मन गल्ला बाहर से मगाना पडता है, क्यों ? इसलिए नहीं कि हम गल्ला नहीं उपजा सकते, या उपजाने के साधन हमारे पास नहीं हैं बल्कि इसलिए कि जिनके पास उपजाने की साधन हैं वे स्वयं उपजाने का श्रम नहीं करते और जो श्रम करते हैं या कर सकते हैं उनके पास साधन नहीं हैं। गरीब और अमीर सब कोई श्रम को टालने की ही चिन्ता में लगे रहते हैं। दूसरे शब्दों में हर कोई एक दूसरे को श्रमिक बनाकर, कमिया और गुलाम बनाकर उसके श्रम पर जीना चाहता है। अपनी इस कुप्रवृत्ति और कुचेष्टा को समाज के सामने न्याय और नैतिक सिद्ध करने के लिए उसने एक समाज-व्यवस्था कायम की जो हवा पानी और

रोशनी की तरह सबको और सबके लिए मिली हुई जमीन जैसे उत्पादन के बुनियादी साधन होने पर भी व्यक्ति को मालिकी का अधिकार देती है और इतना ही नहीं बल्कि उसे समाज में ऊचा स्थान भी देती है। अब आप सोचिए यदि वही मनुष्य जिसने अबतक अपनी सारी शक्ति लगाकर न्याय-अन्याय, झूठ-सच, सारे प्रपच करके उत्पादन के साधनों को एकत्र करना और बिना श्रम के उनके किराये पर ही मौज उड़ाना अपने जीवन का ध्येय बना रक्खा था, जिसने अपने कमियाँ और मजदूर को कुत्ते और विल्ली से भी निम्नतर मान रक्खा था आज यह मानने लगता है कि उसके पास न केवल जमीन है बल्कि और भी जितनी शक्तियाँ हैं वे सब समाज की सेवा के लिए हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ साधना के लिये नहीं। व्यक्तिगत स्वार्थ को समाज के चरणों में अर्पित कर देने में ही कल्याण है। हरेक आदमी जैसा अब तक प्रचलित था अपनी कमाई का जिम्मेदार और हकदार है। यह न मानकर यथाशक्ति कमाई करनेवाले किसी भी व्यक्ति को सम्मिलित कमाई का समान हकदार मानता है तो फिर उसके जीवन में स्त्री-पुरुष भेद, शरीर परिश्रम के उपभेद, शारीरिक और मानसिक परिश्रम का उपभेद इत्यादि वर्ग और इसलिए विषमता तथा विद्वेष उत्पन्न करनेवाली दीवारे कैसे रह सकती हैं। जब नैतिक और भौतिक वस्तुओं का भेद उसकी समझ में आ जाएगा और वह यह समझ लेगा कि कम या ज्यादा शक्ति के अनुसार पोषण में कमी या वृद्धि करने की कल्पना गलत है। से-1 जो नैतिक वस्तु है उसकी कीमत पोषण जो भौतिक वस्तु है उसमें नहीं हो सकती तो उसका सारा जीवन ही बदल जाये। उसका अर्थशास्त्रके क्रय-विक्रय की कुटिल नीति पर न खडा रहकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की दिव्य आधारशिला पर आधारित होगा। अब वह जो कुछ करेगा वह नफा कमाने के लिए नहीं, बल्कि सेवा के लिए करेगा। वणिक चर्चा के स्थान में भ्रातृ चर्चा उसके जीवन का लक्ष्य बन जायेगा, वह सम्पत्ति तो पैदा करेगा और यथाशक्ति खूब करेगा किन्तु धर्म के रास्ते से पैदा करेगा और मोक्ष दिलानेवाले कामों में यानी ऐसे कामों में जिसमें मैं और तू मेरा और तेरा का भेद भाव नहीं है उस सम्पत्ति का विनियोग करेगा। वापू के शब्दों में तब वह अपनी समस्त शक्तियों का समाज के हित के लिए दृष्टी बन जायगा। उपभोग से हटकर अब उसके जीवन का लक्ष्य सेवा में केन्द्रित हो जाएगा।

पाठक विचार करें कि उन्हें पैसे के बल पर चलनेवाला होटल चाहिये या सेवा निष्ठा की प्रेरणा पर चलनेवाला सुन्दर घर? उन्हें होटल व्याय की सर्विस पसन्द है या मा, बहन और भाई की सेवा? भूदान यज्ञ आन्दोलन के पास इसका जवाब है। स्वयं विनोबा जी इसे बुनियादी मसला मानते हुए लिखते हैं, "आजकल तो सर्विस की बात चली है। सिविल सर्विस, एडुकेशनल सर्विस, मेडिकल सर्विस यहा तक कि भोजन, मोटर और चर्चा की भी सर्विस होती है। सिविल सर्विस के जो नौकर हैं उन्हें हजार रूपया तनख्वाह मिलती है और उनके जो स्वामी हैं गरीब जनता, उनको आठ आना रोज मिलते हैं। वे लाखों कमाते हैं, वे सेवक होने का दावा करते हैं और जो सारे समाज के लिए अन्न पैदा करता है वह सोचता है कि मैं तो अपने पेट के लिए काम कर रहा हूँ। इस तरह की सर्विसों को क्या कहा जाय। हमारी भाषा में उसके लिए, डोग यही शब्द है। इस दम को

खतम करने के लिए ही मैंने यह विचार सामने रक्खा कि भूमि पर सब का समान अधिकार है, हमारे पास अपनी सतति, सम्पत्ति, भूमि और बुद्धि जो कुछ भी है वह सब समाज के लिए है। जैसा अपरिग्रह हम चाहते हैं, उसमें वैभव तो बढ़ेगा पर समाज का बढ़ेगा। समाज नारायण स्वरूप है, इसलिए लक्ष्मी तो उसके पास पडी रहेगी। वह वैरागी शकर है, पर कुबेर उसके हाथ में रहेगा। अपरिग्रह का आधार जल में एक भव्य और सुन्दर समाज का निर्माण करना है। उनी बुनियादी रूप में मैंने भूमि का मसला उठाया है।"

"आज जो धन कमाता है, वह उसके साथ रोग और चिन्ता भी कमाता है। धन कमाकर पुत्र मित्र और पडोसी के प्रेम को खोता है इसीसे वह दुखी भी है। आज समाज में श्रीमान और गरीब दोनों दुखी हैं, इसलिये यह समाज रचना बदलनी होगी।"

हम देखते हैं एक आदर्श परिवार में छोटे-बड़े, स्त्री-पुरुष, बालक बूढ़े, समर्थ अल्प समर्थवान और विलकुल समर्थ जितने भी प्राणी होते हैं सबको समान सरक्षण मिलता है, ऐसा नहीं होता कि छोटा बच्चा है या बहुत बूढा है जो कुछ नहीं कमाता उसे कम सरक्षण मिलता होगा। सरक्षण की समानता का परिवार में यह भी अर्थ नहीं होता कि सबको बराबर रूपया वाट दिया जाता हो बल्कि जिसकी जितनी आवश्यकता होती है उसको उतना मिलता है। और यह भी नहीं होता कि एक को तो खूब दूध, मलाई और मालपुआ मिले और दूसरे को सत्तू। यह भी कल्पना बहा नहीं आती कि जिसकी जैसी सेवा हो उसे वैसा ही पोषण मिले। घर में झाड़ू दुहारू करनेवाली एक छोटी विटिया को और आठ घंटे कस कर खेत में काम करनेवाले गृहपति को एक सा ही दाल-भात और तरकारी मिलती है। दोनों की भूख के परिमाण में दोनों को मिलता है। और जहा तक काम करने का मन्वन्ध है प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति के अनुसार ही काम करता है। गरज यह कि सबकी सम्मिलित सेवा का फल सबको सम्मिलितरूप से मिले। सरक्षण के साथ समान अनुपात होता है। संक्षेप में यही कहा जा सकता है कि समाज की व्यवस्था न तो 'कमाओ तो खाओ' अथवा "जितना लगाओ उतना पाओ" या "जितना काम उतना दाम" वाली पूजीवादी अथवा पूजी सापेक्ष व्यवस्था होती है और न व्यवस्थापक के दड पर ही परिवार का काम चलता है। पैसे में भी सब काम होते हैं अथवा दड के भय से ही लोग नीचे रास्ते पर रहते हैं यह विचार परिवार के अनुभव से गलत मात्रित होते हैं। घर में जो समर्थ लोग होते हैं वास्तव में असमर्थ और अल्प समर्थवानों की सेवा में ही अपनी शक्ति की शोभा मानते हैं।

परिवार में जो आर्थिक दुरवस्था थोड़े बहुत अश में सर्वत्र पायी जाती है उसे भी पूरे समाज पर लागू किया जा सकता है। आखिर समाज कुटुम्ब का ही तो एक बड़ा रूप है। जो चीजें या जिस प्रकार की व्यवस्था घर या कुटुम्ब में होना सम्भव है वह समाजमें भी बडो आसानी से लागू हो सकती है। आज यह मान लिया गया है कि राष्ट्र की कुशलता, प्रामाणिकता, उत्साह और जिम्मेदारी को तो प्रोत्साहन देने का एक मात्र मार्ग कम या अधिक वेतन देना है, किन्तु पारिवारिक व्यवस्था का अनुभव यह



भूदान यज्ञ का यह आन्दोलन इसलिए मनुष्य को नैतिक, आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सभी क्षेत्रों में परिवर्तन लाना चाहता है। इसी को क्रान्ति कहते हैं। आजकल हिंसा को ही क्रान्ति समझते हैं किन्तु जहाँ दुनियादी चीजों में क्रान्ति नहीं वहाँ ऊपर-ऊपर के परिवर्तन को क्रान्ति कहना गलत होगा। क्रान्ति तभी होती है जब हम अपने नैतिक जीवन में परिवर्तन करते हैं। यह भूदान तो एक पञ्चर है। आरम्भ में विचार को समझने और मोह-ममता से मुक्त होने का एक साधन है। ममता छूटे कैसे? जमीन की मालिकी का मोह छोड़ना तो इस मोह मुक्ति का पहला कदम है। दान देना किसी पर कृपा नहीं है। अन्त में हमारी कल्पना तो यह है कि गावों की जितनी भूमि है वह सब गाववालों की है। आगे जाकर हम तो कहेंगे कि यदि प्रान्त में भूमि कम है और मनुष्य

ज्यादा है तो दूसरे प्रान्तों में जाकर रहे। एक देश से दूसरे देश में भी लोग बसने के लिए जाने चाहिये। भूमाता सारी-की-सारी पूर्ण मुक्त है, जो जहाँ रहना चाहे रह सके। जहाँ सेवा करना चाहता हो, कर सके। हम इस प्रकार दुनिया के नागरिक बनना चाहते हैं और आर्थिक सामाजिक तथा राजनीतिक भेद रखना नहीं चाहते हैं। जमीन चाहे थोड़ी या बहुत छोटी हो या बड़ी हो सब परमेश्वर की देन है। हम उसके मालिक नहीं बन सकते। हिन्दुस्तान के लोग हिन्दुस्तान के मालिक, जर्मनी के लोग जर्मनी के मालिक, यह विचार ही गलत है। सारी दवा, सारा पानी, सारी रोगनी और सारी धरती, सारी-की-सारी सबकी है। वस, संक्षेप में यही भूदान यज्ञ आन्दोलन का मूलाधार है।





# ग्रामीण उद्योगों का विकास

श्री जयनारायण सिंह

किसी भी देश के आर्थिक विकास में प्रयत्नशील होने के पहले वहाँ के अर्थनीति विधायकों को उस देश के मूल आर्थिक तत्त्वों से पूर्ण परिचित हो जाना चाहिये। प्रत्येक देश की अपनी विशेष आर्थिक परिस्थितियाँ हुआ करती हैं। हमारा देश इसका अपवाद नहीं हो सकता। भारतीय आर्थिक तत्त्व की भी कई विशेषताएँ हैं। उनमें अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं, कृषि की प्रधानता, जन साधारण में फैला हुआ प्रचंड भाग्यवाद और तज्जनित आर्थिक प्रश्नों के प्रति शून्य उदासीनता, ग्रामीण जनमस्या का बाहुल्य और औद्योगिक मनोवृत्ति का सर्वथा अभाव, निम्न जीवन स्तर और बेकारी की समस्या आदि।

यूरोप से सम्बन्ध रखने पर भी भारत में या पूरब के अन्य देशों में उस पाश्चात्य आर्थिक दृष्टिकोण की अनुपस्थिति दीख पड़ती है। जो आर्थिक या भौतिक विकास का विन्दु माना जाता है। पूर्वीय आर्थिक चिन्तन धारा और उस पर आधारित पूर्वीय अर्थनीति पश्चिम के आर्थिक विचारों से कुछ भिन्न पड़ती है। इस कारण, अविकसित देशों की आर्थिक समस्याओं पर उनकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र रूप से चिन्तन करने की आवश्यकता है। ये विशेषताएँ भारत में भी काफी सशक्त हैं और प्रत्येक आर्थिक योजना में इन पर समुचित विचार अपेक्षित हैं। ये विशेषताएँ बम्बई और कलकत्ता जैसे व्यावसायिक नगरों और जमशेदपुर तथा डालमियानगर जैसे औद्योगिक केन्द्रों के बावजूद भी सशक्त हैं, इनका अनुमान तो गावों की दशा के निकटतम अध्ययन से ही लग सकता है। यह बात तब और भी महत्त्वपूर्ण हो जाती है जब हम गावों में या दिहातों में रहते हुए विशाल जन समुदाय का ध्यान करते हैं।

भारत में लगभग सात लाख गाव हैं और इनमें साठे २९ करोड़ लोग रहते हैं। इस प्रकार जन सख्या का प्राय ६६ प्रतिशत भाग ग्रामों में रहता है। इन अपार जन समूह की प्रवान जीविका कृषि है। कुछ ग्रह-उद्योग भी यत्र-तत्र हैं पर उनकी अवस्था अत्यन्त दयनीय है। इन प्रकार कृषि मात्र ही जीविकोपाजन का मुख्य साधन है। कृषि की समस्याएँ ग्रामों की मुख्य आर्थिक समस्या है। कृषि के प्रस्तुत व्यय की प्रमाणाँ में परिवर्तन की आवश्यकता, ऐंसे परिवर्तनों की सम्भावना आदि प्रश्न ग्रामों की आर्थिक प्रस्तावली में प्रमुख हैं।

भारत में कृषि के कार्य क्षेत्र गाव हैं। ग्रामीण जन समूह का बहुत बड़ा भाग अशिक्षित है और अभी तो उत्पादन के बड़े ही साधन काम

में लाये जाते हैं जो सदियों से प्रचलित थे। कृषि के नये साधन और नई प्रणालियाँ जिन्होंने पश्चिम के कृषि उत्पादन की काया पलट कर दी है, यहाँ केवल वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की जानकारी के विषय हैं। खेतों में काम करनेवाले कृषकों को इतनी खबरें तक नहीं हैं। एक ओर तो प्रयोगशालाओं में आधुनिकतम प्रणालियाँ एवं साधनों के अनुसंधान हो रहे हैं, दूसरी तरफ भारतीय कृषक पुरानी लकीर का फकीर बना हुआ है। प्रयोगशालाओं के कार्य भी महत्त्वपूर्ण हैं पर उनसे भी महत्त्वपूर्ण है जानी हुई बातों से उस व्यक्ति को अवगत कराना जो खेतों में वास्तविक उत्पादन का कार्य कर रहा है।

कृषि की समस्या हमारे यहाँ मुख्यतः सिंचाई की समस्या है अतः कृषि के विकास का मापदण्ड सिंचाई की व्यवस्था की प्रगति है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस सत्य को स्वीकार किया गया है और सिंचाई सम्बन्धी निर्माण कार्य को अत्यधिक महत्त्व दिया गया है। साथ ही कृषि कार्य में वृद्धि, बजरो को खेती लायक बनाने के प्रयत्न और शोध कार्य के नतीजों के प्रयोग की व्यवस्था है। ग्रामीण आर्थिक जीवन में बहुरूपता और विस्तार पर अधिक जोर दिया गया है और इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए डेरी, फल-फूलों के उत्पादन और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास का प्रस्ताव है। कृषि के लिए पूँजी की व्यवस्था के सम्बन्ध में भी कुछ सुझाव रखे गये हैं। इसी विचार से योजना में सहकारी संस्थाओं का बहुत बड़ा महत्त्व माना गया है। इस दिशा में रिजर्व बैंक की दिलचस्पी देखते हुए प्रगति की आशा भी की जा सकती है।

कृषि से सम्बन्धित सबसे मौलिक प्रश्न भूमि पर अधिकार का है। "भूमि कृषक की", यह नारा तो प्रायः स्वीकृत है पर इसके तार्किक निष्कर्ष पर पहुँचने में बड़ी-बड़ी अड़चनें आ जाती हैं। पर यह भी अत्यधिक स्पष्ट है कि इन्हें हल किये बिना भी काम चलने का नहीं। इसीलिए जहाँ एक तरफ योजना में लक्षित उत्पादन वृद्धि की ओर प्रयत्नशील होना आवश्यक है, दूसरी ओर भूमि सम्बन्धित नीति ऐसी होनी चाहिये जो सम्पत्ति और आय सम्बन्धित विषमता को दूर करे, शोषण का अन्त करे, कृषक और श्रमिक की सुरक्षा की व्यवस्था करे और ग्रामीण जन समूह के भिन्न भागों में पद और अवसर की समता के लिए आशा का संचार करे।

पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार के जो प्रस्ताव हैं उनका भूमि सम्बन्धी इन पाँच हितों से सम्बन्ध है, (१) मध्यवर्ती वर्ग, (२) बड़े

भूमिपति, (३) निम्न और मध्य वर्ग के भूमिपति, (४) भूमिहीन कृषक, (५) भूमिहीन मजदूर। पहली श्रेणी के लोगो का भूमि से सम्बन्ध विच्छेद कराया जा चुका है और भारत सरकार की एक विज्ञप्ति से यह ज्ञात होता है कि पश्चिमी बंगाल को छोड़कर 'ए' और 'बी' वर्ग के सभी राज्यों में इनके हकको को समाप्त कर दिया गया है।

एक व्यक्ति के पास कितनी जमीन रहनी चाहिये, इसकी ऊपरी सतह को निर्धारित करने के सिद्धान्त को योजना में स्वीकार कर लिया गया है। किन्तु, इसका निर्णय व्यक्तिगत अधिकार और कर्तव्य की विवेचना और भूमि वितरण के लिए उपलब्ध भूमि से नहीं बल्कि अर्थशास्त्र और उत्पादन सम्बन्धी साधारण दृष्टिकोण एवं सार्वजनिक हित की दृष्टि से होना चाहिये। इस आधार पर एक व्यक्ति के अधिकार में रहनेवाली और एक व्यक्ति के अधिकार में छोड़ी जानेवाली भूमि की ऊपरी सतह दो उद्देश्यों के लिये निश्चित की जा सकती है? (१) भविष्य में भूमि प्राप्ति और (२) व्यक्तिगत कृषि-कार्य के पुनरारम्भ के लिये।

पंचवर्षीय योजना में इस बात की भी चर्चा मिलती है कि प्रत्येक राज्य में ऐसे नियम बनें जिनके आधार पर कृषि कार्य और कृषि व्यवस्था में कार्य क्षमता का एक समुचित मानदंड निश्चित हो सके। इस मानदंड के अनुसार बड़े-बड़े फार्मों के दो भेद किये जा सकते हैं। (१) वे जिनकी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि उनको खड-खड करने से उत्पादन घटने का डर है, (२) वे जो इस मानदंड पर खरे नहीं उतरते हैं। इन दूसरी तरह के फार्मों पर ही भूमि सम्बन्धी प्रस्तावों को पहले कार्यान्वित करना चाहिये। इन्हें सहकारिता के आधार पर सगठित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिये, इस प्रकार के उनलोगों की भूमि का, जो बड़े पैमाने पर भूमि रखते हैं बहुत हद तक पुनर्वितरण हो जा सकेगा।

निम्न और मध्य श्रेणी के भूमिपतियों के विषय में नीति का उद्देश्य प्रोत्साहन और सहयोग दान होना चाहिये। साथ-ही-साथ सहकारी आन्दोलन को भी यथासंभव सहायता मिलनी चाहिये। छोटे-छोटे होल्डिंगों का एकीकरण और न्यूनतम होल्डिंग की सीमा के निर्धारण की भी व्यवस्था होनी चाहिये। भूमिहीन कृषकों के लिए एक निश्चित अवधि होनी चाहिये और उस अवधि के बाद कृषि कार्य के अधिकार की पुनर्प्राप्ति की भी गारंटी होनी चाहिये जस्तक कि भूमिपति स्वयं खेती करना नहीं चाहें।

भूमि वितरण के प्रस्तावों से मुख्यतः ऐसे लोगों को ही लाभ होता है जो किसी-न-किसी रूप में भूमि रखते हैं। इसीलिए भूमिहीन मजदूरों की दृष्टि से भूदान यज्ञ का विशेष महत्त्व है। इसके द्वारा भूमिहीनों को भूमि प्राप्त करने का अवसर मिलता है। भूदान यज्ञ प्रस्तुत आर्थिक तंत्र को चुनौती है जिसमें एक ओर तो कुल वश और जन्म की विशेषता से भूमि पर अधिकार मिलता है और दूसरी ओर इन्हीं कारणों से भूमि पर अधिकार में सन्निहित उन्नति और अभ्युदय के सुअवसर से वंचित रहना पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं भूमि सुधार की समस्या में तत्रात्मक परिवर्तन का प्रश्न प्रमुख हो जाता है।

छोटे और अनाथिक होल्डिंग कृषि विकास के मार्ग में प्रमुख व्यवधान हैं। अतः निम्न और मध्य श्रेणी के भूमिपतियों को सहकारिता के आधार पर सगठित करने का प्रयत्न करना चाहिये। 'भूमि कृषकों की' के सिद्धान्त को

इसी पथ पर कार्यान्वित किया जा सकता है। साथ-ही-साथ उन सुदूर और निर्दिष्ट उद्देश्यों की ओर भी दृष्टि रखनी चाहिये जिनकी प्राप्ति के बाद ही यह सिद्धान्त मूर्त रूप पा सकता है। इस निर्दिष्ट पथ पर ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था को गतिशील करना चाहिये। इसके लिए ग्राम्य स्तर पर ऐसे सगठन का आयोजन आवश्यक है जिसके अधिकार का श्रोत सम्पूर्ण ग्रामीण जन-समूह हो। इस सगठन को गांव के सम्पर्क-विकास के लिए उत्तरदायी होना चाहिये। कुछ इसी प्रकार के सगठन की ओर पंचवर्षीय योजना में सकेत है।

भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता जा रहा है और अन्य उद्योग विकसित नहीं हो पाए हैं। अतः गांव की सारी भूमि का सहयोग के आधार पर प्रबन्ध होना चाहिये तथा कृषि के अलावा अन्य उद्योग-वधो और सामाजिक सेवाओं का भी सगठन होना चाहिये। गावों में एक नवीन वातावरण लाने के लिए और आर्थिक विकास के कार्य में सार्वजनिक उत्साह की सृष्टि के लिए सहकारी समितियों का सगठन आवश्यक प्रतीत होता है। ये समितियाँ गावों के विकास के प्रकाश-केन्द्र बनेंगी। इनका मुख्य उद्देश्य गाव की भूमि और अन्य प्राकृतिक साधनों का सर्व हित की दृष्टि से विकास होना चाहिए। ऐसी 'सहकारी ग्राम्य व्यवस्था' को आपरेटिव विलेज मैनेजमेंट ही इस प्रकार की राष्ट्रीय योजना को आधार बना सकती है जिसमें दरिद्रता एवं जाति और पद में उद्भूत सामाजिक विषमता का उन्मूलन हो सके। ग्राम विकास के निरीक्षण के लिए और भूमि सुधार की देखरेख के लिए एक "केन्द्रीय भूमि सुधार मस्था" की व्यवस्था भी पंचवर्षीय योजना में है।

१९५१ की जनगणना के अनुसार साठे उनतीस करोड़ गावों में रहनेवाले लोगों में से लगभग २५ करोड़ कृषि में लगे हैं। इनमें अठ्ठारह प्रतिशत भूमि जोतनेवाले और उनके आश्रित लोग हैं। यह आज की कृषि व्यवस्था का बहुत बड़ा दोष है। पंचवर्षीय योजना में विभिन्न उपायों से इसको दूर करने की व्यवस्था है। खेतिहर मजदूरों के कल्याण के लिए निम्नलिखित उपायों की ओर पंचवर्षीय योजना में सकेत है

(क) वंसी भूमि पर जिसमें घर हैं, घरवाले के अधिकार की स्वीकृति और यथासंभव शाक-भाजी के लिए छोटे-छोटे उद्यानों की व्यवस्था।

(ख) भूदान आन्दोलन में सहयोग प्रदान और उसे ग्रामोत्थान का एक स्थायी अंग बनाना।

(ग) श्रम सहकारी समितियों का सगठन और उन्हें ही सिंचाई और निर्माण कार्यों का माध्यम बनाने का प्रयत्न।

(घ) नई भूमि या नये सिरे से प्रयोग में लाई गई कृषि योग्य भूमि पर भूमिहीन मजदूरों या निम्न और मध्य श्रेणी के अनाथिक होल्डिंगों के मालिकों का सहकारिता के आधार पर सगठन,

(ङ) इस प्रकार के सहकारी ग्रूपों को आवश्यकतानुसार आर्थिक सहायता,

(च) छात्र वृत्ति और उद्योग शिक्षा द्वारा विशेष आर्थिक सहयोग,

(छ) गाव के विस्तार कार्यकर्ताओं, खेतिहर मजदूरों के रोजगार और कल्याण का उत्तरदायित्व देना और इन सम्बन्ध में ग्राम पंचायतों के उत्तरदायित्व पर विशेष जोर देना।

हम देखते हैं कि कृषि समस्या के दो पहलू हैं, (१) प्राचीन साधनों और प्रणालियों का बहिष्कार और उद्गीर्ण अर्वाचीन साधनों सामग्रियों और पद्धतियों का प्रयोग, और (२) "भूमि कृषक का" सिद्धान्त के आधार पर भूमि का पुनर्वितरण और भूमि के प्रस्तुत मानवीय सम्बन्धों का तदनुरूप पुनःस्थापन। साधारणतया इन दोनों पहलुओं में कोई विरोध नहीं है। सत्य तो यह है कि किसी भी प्रकार के विकास के पहले मानवीय सम्बन्धों का ही निश्चित होना परमावश्यक है। भारत में कृषि के पहले पहलू पर ही विशेष ध्यान दिये जाने को कुछ अर्थशास्त्रियों ने असंगत माना है। पर खाद्यान्न सकट जैसी एक असाधारण परिस्थिति के उपस्थित रहने के कारण उसके तत्कालीन हल के रूप में यह उलट फेर कुछ अंश तक परिस्थितजन्य भी माना जा सकता है। भूमि सम्बन्धों की समस्या स्वाभावतः दीर्घकालीन है। अतः इसकी जगह पर हमारी चिन्ता का मुख्य विषय हो गया है प्रस्तुत और उपलब्ध साधनों तथा शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित हो जानेवाली प्रणालियों द्वारा अधिकाधिक उत्पादन-वृद्धि। जहाँ इस दिशा में जो प्रयत्न हो रहे हैं उन्हें द्रुतकर बनाने का प्रयत्न होना चाहिये, भूमि सम्बन्धों के पुनःस्थापन का निर्दिष्ट हमारी आँखों से ओझल नहीं होना चाहिये क्योंकि उनकी अनुपस्थिति में उत्पादन वृद्धि की दिशा में भी मार्ग अवरुद्ध होने का डर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन सम्बन्धों के पुनःस्थापन की अनुपस्थिति में यदि कुछ विकास हो भी तो वह सर्वांगीण और स्थायी नहीं हो सकता।

निकट भविष्य में प्लानिंग कमीशन ने राज्य सरकारों को प्रस्तावित भूमि गणना के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक सलाह देने का निश्चय किया है। इस गणना के द्वारा भूमिहीन कृषकों के बीच उपलब्ध भूमि का अन्दाज लग सकेगा। इधर राज्य सरकारों और योजना आयोग के बीच प्रस्तुत भूमि होल्डिंग की ऊपरी सतह को निश्चित करने के विषय में कुछ मतभेद सा हो गया है। इस विषय में विश्वसनीय आकड़े उपलब्ध नहीं हैं। एक मोटे हिसाब से तीस एकड़ की होल्डिंग के आधार पर समूची कृषि योग्य भूमि का आठ प्रतिशत भाग इसके अन्तर्गत आ सकता है। इसमें वैसे भूमि के आकड़े नहीं हैं जिन्हें भूमिपति दूसरों को जोतने के लिए देते हैं क्योंकि ऐसे जोतनेवालों को जोतने और खरीदने का अधिकार देने की बात सोची जा रही है। ऐसी भूमि कुल मिला कर पचास प्रतिशत के लगभग होगी। इस प्रकार लगभग चार प्रतिशत या इससे भी कम भूमि के भविष्य में निर्णय का प्रश्न है। ऐसी भूमि के बारे में विधान के आधार पर बाजार दर पर मुआवजा देना आवश्यक समझा जाता है।

इस प्रकार की भूमि के लिये योजना आयोग ने तत्कालीन और दूसरा स्थायी हल मोच रखा है। इसका प्रयोग भूमि गणना हो जाने और इन कोटि की भूमि का अन्दाज मिल जाने पर होगा। तत्कालीन मुआवजे के अनुसार राज्य सरकारों को कृषि कार्य और कृषि व्यवस्था सम्बन्धी धनराशि के मानदंड को निश्चित करने के लिए कानून बनाने होंगे। जो भूमि इन जाचों में खरी उतर मनेगी, उसके प्रस्तुत सम्बन्धों को ज्यों-ज्यों रखा जायगा जिसमें उत्पादन वृद्धि में बाधा न हो पाए। पर जो भूमि उत्पादन सम्बन्धी इन जाचों में खरी न उतर सकेगी उसे सरकार बिना मुआवजा के लेकर भूमिहीन कृषकों के बीच महकारी या अन्य किसी

ढग से वितरित कर देने का अधिकार रखेगी। इस स्थायी हल में भूमि सम्बन्धी स्वीकृत सिद्धान्त, "भूमि कृषक की" के अनुसार सम्पूर्ण भूमि के पुनर्वितरण और नये सम्बन्धों के पुनःस्थापन तथा कृषि सम्बन्धी नये विचारों और साधनों के उपयोग की बात है।

हाल में ही राष्ट्रीय विकास समिति के द्वारा योजना में अब तक की गई प्रगति पर विचार किया गया था। ग्रामीण जीवन के विकास के लिए कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और नेशनल ऐक्सटेंशन सर्विस तथा अन्य माध्यम से जो कार्य किये जा रहे हैं उन पर सतोष प्रकट किया गया और उसके और विस्तार तथा तदर्थ समुचित जन जागरण के लिए आवश्यक कदमों पर विचार किया गया। यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रस्तुत बेकारी की विकटता को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित व्यय में कुछ वृद्धि करने की बात सोची जा रही है। पंचवर्षीय योजना में जो प्रगति हुई है उसे असतोषजनक माना गया। पर खाद्यस्थिति में कुछ सुधार के कारण अन्नायात में कमी करने की चर्चा हो रही है। इस प्रकार खाद्योत्पादन में कुछ प्रगति हुई है किन्तु और उत्पादन सम्बन्धी कोई भी विकास या लाभ बिना तत्रात्मक परिवर्तन के स्थायी नहीं हो सकता। अतः भूमि सम्बन्धों के बारे में जो निर्दिष्ट उद्देश्य हैं उसकी ओर आख रखना और उस दिशा में अधिकाधिक कार्यशील होना अत्यावश्यक है।

हमारे यहाँ भूमि पर जनसंख्या के गुरुतर दबाव की बात सर्वविदित है। ऐसा भी कहा जाता है कि यदि सारी भूमि वितरण के लिए उपलब्ध भी हो जाय तो सभी को इतनी जमीन नहीं दी जा सकती कि अनाधिक होल्डिंगों से मुक्ति मिल सके। इसलिए ऐसी जनसंख्या को जिसको भूमि पर काम मिलने की आशा नहीं है, अन्य रोजगारों की व्यवस्था भी आवश्यक है। हमारे यहाँ कुशल श्रमिक, समुचित कलपुर्जे और आवश्यक पूँजी सबका नितान्त अभाव है। इसलिए पाश्चात्य ढंग से बड़े पैमाने पर उद्योग-धंधों का इतना विकास होना असम्भव है कि भूमि से हटाये गये विशाल जनसमूह को उनमें लगाया जा सके। उनके अलावा इसके लिए बहुत बड़े पैमाने पर औद्योगिक शिक्षा का भी अभाव है जिसके बिना यह अपार जनसमुदाय बड़े उद्योग-धंधों के लिये उपयोगी नहीं हो सकता।

सम्भवतः इसी दृष्टि से पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में ग्रामोद्योगों को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्हें कृषि उत्पादन के समकक्ष ही प्रश्रय मिला है। इन उद्योगों के विकास के लिए यह आवश्यक है उनके विनाश के जो मूल कारण थे उन्हें दूर करने का प्रयत्न किया जाय। सगठन, सहकारीनीति, शोध एवं शिक्षण तथा आवश्यक वित्त की व्यवस्था अपेक्षित है। बड़े उद्योग-धंधों का विकास और उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं का मूल्य कम होने तथा आयात की वृद्धि के कारण कारीगरों की वनाई चीजों की माग में कमी होने से ही गृह उद्योगों को धक्का लगा था, इसलिए गावों को इस प्रकार सगठन करना चाहिये कि वे बदलते हुए जमाने के साथ चल सकें। गाव के बेकार लोगों के रोजगार की व्यवस्था में उनका विशेष उत्तरदायित्व होना चाहिये। किन्तु इस दायित्व को पूरा करने के लिए सरकारी नीति को भी अनुकूल और सहायक होना चाहिये। इस नीति का प्राथमिक उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों का सगठन होना चाहिये जहाँ गृह-उद्योगों का विकास हो सके। जहाँ कहीं भी बड़े उद्योग-धंधों और

गृह-उद्योगों में सघर्ष होने की आशंका हो दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों और समुचित क्षेत्रों का निश्चय हो जाना चाहिये। पर जब तक गृह और छोटे उद्योगों की टेकनीक का शीघ्र परिवर्तन नहीं होता, सरकारी नीति और सहायता का अल्पकालीन महत्त्व ही क्या हो सकता है। इनकी टेकनीक और सगठन में उन्नति के लिए श्रमिक कार्यक्रम की आवश्यकता होगी। अतः योजना में शिक्षण केन्द्रों एवं उत्पादन केन्द्रों की भी व्यवस्था है और साथ ही तेल, सावुन, धान कूटना, गुड, चमड़ा आदि ग्राम उद्योगों के विकास के कार्यक्रम हैं।

ग्राम उद्योगों के अलावा जो छोटे-छोटे उद्योग हैं, उन्हें तो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, एक वे जो परम्परागत दक्षता एवं हुनर का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे दूसरे जो हाल ही के हैं और जिनका बड़े उद्योगों से भी सम्बन्ध है। किन्तु ग्राम उद्योगों की तरह इनकी भी विशेष शिक्षा की आवश्यकता है एक ओर तो छोटे उद्योगों और दस्तकारियों को बड़े उद्योगों से सम्बद्ध। करने की आवश्यकता है, पर दूसरी ओर इनके आन्तरिक सगठन में उन्नति तथा इनके विकास के लिए समुचित, आर्थिक और शैक्षणिक साहाय्य की भी परम आवश्यकता है। ग्राम उद्योग और कृषि विकास के इन सारे कार्यक्रमों को सम्पूर्ण राष्ट्रीय विकास के अभिन्न अंग के रूप में देखने का प्रयत्न होना चाहिये।

ऊपर जो विचार प्रकट किए गए हैं उनसे लगता है कि गावों की आर्थिक दुरवस्था ग्रामीण जीवन का सबसे पेचीदा प्रश्न है। इसका अनुमान तो इसीसे लगाया जा सकता है कि ग्रामीण समाज एक दुःसह ऋण भार से कराह रहा है। यद्यपि यहाँ पर इस समस्या पर पर्याप्त चिन्तन हुआ है और कुछ सरकारी कदम भी डमे हल करने के मार्ग में उठाए गए हैं पर यह प्रश्न अभी हल नहीं हो सका है। स्पष्ट है कि ग्रामीण जीवन के संस्थापन के प्रयत्नों में सर्वप्रथम ध्यान इस समस्या के समाधान की ओर होना चाहिये। ग्रामीण जीवन के आर्थिक पक्ष की चर्चा करते समय ग्रामीणों के शरीर नाशक दैत्य, आत्मविनाशक अज्ञान, भूमि क्षुधा, महाजनो और जमीन्दारों द्वारा निर्दय शोषण, अनार्थिक होलिडगो तथा जर्जर प्रणालियों के कारण परिवार के मात्र भरण-पोषण के लिये भी पर्याप्त भूमि नहीं पाने में उनकी असमर्थता, और इस कृषि आय को पूरित करने के लिए गृह उद्योगों की अतीव आवश्यकता है इस पर विशेष ध्यान देना चाहिये। पिछली पंक्तियों में इन सभी की चर्चा यत्र-तत्र हुई है और यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया गया है कि गावों के पुनर्निर्माण का प्रश्न उनके आर्थिक संस्थापन का प्रश्न है। हल के रूप में कृषि और भूमि में सुधार तथा ग्रामोद्योगों के पुनरुत्थान की ओर सकेत किया गया है। सर्वत्र मान्यता यह है कि सहकारी ग्राम्य व्यवस्था में निहित विकेंद्रित आर्थिक तंत्र ही इस देश के लिए और हमारे गावों के लिए हितकर होगा। आगे की पंक्तियों में इसी मान्यता को परीक्षा और समीक्षा की जायेगी।

यहाँ एक बात की ओर ध्यान आकर्षित करना आवश्यक प्रतीत होता है। उत्पादन प्रणाली और आर्थिक व्यवस्था द्वारा ही सामाजिक और राजनीतिक भित्तियों का स्वरूप निर्धारित होता है। अतः आर्थिक व्यवस्था सम्बन्धी निश्चय पर पहुँचने के पहले इस के स्वरूप का निश्चय होना चाहिये जिसमें ऐसी आर्थिक व्यवस्था की योजना बनाई जाय जो उस स्वरूप की।

अतः ग्रामीण जीवन के आर्थिक विकास में ग्रामीण जीवन की मुख्य आधार-शिलाओं की ओर भी ध्यान देना परम आवश्यक है। ये आधारशिलाएँ कहाँ तक गावों के निर्धारित भावी रूपको साकार बनाने में सहायक हो सकती हैं, या कहाँ तक उनमें परिवर्तन और सशोधन की आवश्यकता है। एक प्रश्न महत्त्वपूर्ण है क्योंकि तदनुरूप आर्थिक व्यवस्था की योजना करनी पड़ेगी किन्तु गावों के भावी स्वरूप का निर्धारण देश की राजनीतिक और सामाजिक मान्यताओं से परे नहीं हो सकता है। गावों को भारत के राष्ट्रीय जीवन का अभिन्न अंग बनाना है। अपने संविधान में हमने एक शोषणरहित और वर्गविहीन समाज तथा राजनीतिक क्षेत्र में एक पूर्ण क्षेत्र में सहकारी प्रवृत्त और विकेंद्रित तंत्र को स्वीकार करना पड़ेगा।

गत कई वर्षों में हमारे यहाँ उद्योग के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई है। फलस्वरूप कतिपय उद्योगों में सगठन और टेकनीक दोनों दिशाओं में प्रगति का आभास मिलता है। इसके विपरीत कृषि के क्षेत्र में वही पुराने जमाने की लकीर पीटी जा रही है। इस प्रकार आर्थिक और असंतुलित विकास का प्रश्न उठ खड़ा होता है। इस संतुलन को दूर करने की दृष्टि से भी कृषि और पिछड़े उद्योगों की ओर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। कृषि ग्रामीण समाज के जीविकोपार्जन का साधन मात्र ही नहीं है। यह एक विशेष जीवन-दर्शन का प्रतीक है। यह जीवन-दर्शन हमारे रंग-रंग में इस तरह व्याप्त है कि इसे दूर करने का प्रयत्न असम्भव ही नहीं अवाञ्छनीय भी है। एक ही प्रकार की आर्थिक समस्याओं के समाधान विभिन्न राजनीतिक मूठभूमि और सामाजिक सगठन में भिन्न-भिन्न हुआ करते हैं। ये समाधान तभी स्थायी और प्रभावोत्पादक हो सकते हैं, यदि ये सर्वमान्य जीवन दर्शन, सांस्कृतिक परम्परा, राजनीतिक मूठभूमि और सामाजिक सगठन के अनुकूल हों। इस प्रकार स्पष्ट है कि सुसम्बद्ध और स्थायी आर्थिक विकास के लिए जीवन के अन्य पक्षों पर भी ध्यान देना आवश्यक है। वस्तुतः किसी भी योजना की सफलता इसीमें है कि वह आर्थिक प्रगति के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों में भी जागरण पैदा कर सके। एक ऐसी वातावरण पैदा कर सके जिसमें आर्थिक योजना की प्रमुख मान्यताओं में जनसाधारण का विश्वास हो और ये मान्यताएँ जीवन के अन्य क्षेत्रों की मान्यताओं के साथ जोड़ी जा सकें।

इधर कुछ अर्थों से कृषि पर आधारित जीवन दर्शन और उमसे सम्बद्ध राजनीतिक और सामाजिक मान्यताएँ गावों की फँसी हुई शिक्षा के अन्वकार में लुप्तप्राय होती जा रही थीं। यत्र-तत्र शिक्षा के आलोक से, हाल में पश्चिम के औद्योगिक विकास और तदोत्पन्न जीवन की सुख-सामग्रियों की ओर ध्यान गया है। पर आवश्यकता इस बात की है कि अपने इतिहास के पिछले पृष्ठों में वर्णित सुसम्बद्ध समाज और उसके आर्थिक स्वरूप की अभी हमारा ध्यान जाय। इस प्रश्न पर हमें गम्भीर रूपसे विचार करना है कि क्या यहाँ भी विकास का एकमात्र अर्थ है औद्योगिक क्रान्ति और तदोद्भूत अनेक बुराइयों की पुनरावृत्ति। क्रान्ति की आवश्यकता यहाँ भी है पर इसका आधार पूँजी और मशीन नहीं वल्कि जमीन होगा। आर्थिक तंत्र में यह मानवीय स्पर्श ही औद्योगिक जन-कटुता को दूर कर सकेगा। यही स्पर्श सर्वोदय योजना का प्रतीक है। ऐसा भी हो सकता है कि औद्योगिक क्रान्ति के द्वारा दिये गये नवीन साधनों से ग्रामीण जनता के विके-

न्द्रित जीवन को ही अर्वाचीन, सब प्रकार से अर्वाचीन बनाने का प्रयत्न किया जाय। इस रीति से इस मानवीय स्पर्श के साथ-साथ हम अपने प्राचीन मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए भी अर्वाचीन बना सकेंगे।

विकास के इस पहलू पर विचार, पश्चिम की बदलती हुई विचार-धाराके कारण भी आवश्यक प्रतीत होता है। वैसे देशों में जहाँ औद्योगिक-करण की नीति स्वीकृत हो चुकी थी वहाँ भी गावों और कृषि पर फिरसे ध्यान दिया जाने लगा है और विकेन्द्रीकरण को प्रश्रय मिलने लगा है। विशेष कर इंग्लैंड और युगोस्लाविया में इस दिशा में जो प्रयत्न किये गये हैं वे सराहनीय और महत्त्वपूर्ण हैं। इनसे विदित होता है कि औद्योगिक क्रान्ति के अग्रदूत ब्रिटेन के पूजावादी और बड़े उद्योगों पर आधारित युगोस्लाविया के साम्यवादी तंत्र में भी परिवर्तन की आवश्यकता प्रतीत होने लगी है इसलिए हमें भी नये सिरे से निर्माण करने में इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखना चाहिये।

गाव, कस्बे और नगर में सभी आर्थिक सगठन की इकाइयाँ हैं। कृषि की आवश्यकताओं के अनुसार जब थोड़ी-थोड़ी दूर पर लोग बसने लगते हैं तो ये बस्तियाँ गाव का रूप धारण करती हैं। जब तक ये बस्तियाँ कृषि उत्पादन का केन्द्र रहती हैं इनकी लम्बाई-चौड़ाई कम रहा करती है। जैसे इनमें अन्य उद्योग-घरे केन्द्रित होते जाते हैं उनका क्षेत्रफल भी बढ़ता जाता है। इन विभिन्न आर्थिक इकाइयों के साथ-साथ आर्थिक रूप-रेखा का एक दूसरा पहलू भी जुड़ा हुआ है। इस पहलू को उद्योग बनाम कृषि का नाम दे सकते हैं। यह विवाद इधर कुछ ठड़ा पड़ता जा रहा है शायद इसलिए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वारा इस विषय में कुछ महत्त्वपूर्ण निश्चय किये गये हैं। प्रथमतः यह विवाद भ्रामक है क्योंकि उद्योग या कृषि सभी देश में रहनेवाले जनसमूह की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए है। अतः इस क्षेत्र के उत्पादन में कितनी वृद्धि हो और साधनों का कौन सा भाग इस क्षेत्र में लगे इसका निर्णय जनसाधारण की आवश्यकताओं के आधार पर ही किया जा सकता है। जहाँ लोग अन्न की कमी से भूखें

मर रहे हों वहाँ विलास की सामग्रियों के उत्पादन की बात प्राह्य नहीं हो सकती। इसलिए कृषि और उद्योग की सीमा और परिधि का निश्चय विद्वानों के विवादद्वारा नहीं जनसाधारण की आवश्यकताओं और उन्हें पूरा करने के लिए किये गये प्रयत्नों द्वारा ही होना चाहिये। शायद इसी विचार धारा से प्रभावित हो, योजनाकारों के प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि और गृह उद्योगों को सर्वाधिक महत्त्व दिया है।

एक और भी समस्या है जिसकी ओर आये दिन अधिकाधिक ध्यान दिया जाने लगा है। यह समस्या रोजगार की है। इस दृष्टि से भी समाज की आर्थिक व्यवस्था, गृह उद्योगों के विकास और कृषि तथा उद्योगों के प्रश्नों की महत्ता स्वीकार करनी पड़ती है। जिस समय पंचवर्षीय योजना तैयार हो रही थी उस समय बेकारी की समस्या आज की तरह दुस्सह न हो पाई थी। सम्भवतः इसीलिए रोजगार की बढ़ती और जीवन-स्तर को चरम लक्ष्य मानते हुए भी उसमें प्राथमिक और निकटवर्ती उद्देश्य नहीं माना गया। पर आज सर्वसम्मति से इसे प्राथमिक स्थान दिया जाने लगा है। इस दृष्टि से भी ग्रामीण उद्योगों के द्रुतकर विकास की आवश्यकता है। भारत के अर्थ मंत्री श्री देशमुख की राय में विकेन्द्रित उद्योग द्वारा ही समस्या का स्थायी निदान हो सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि चाहे विकास से अधिक जनसंख्या को लाभान्वित करने की दृष्टि से या अधिकाधिक भूभाग को विकसित करने की दृष्टि से, आवश्यक चीजों के उत्पादन और रोजगार की बढ़ती दृष्टि से, यह सम्पूर्ण आर्थिक तंत्र के सतुलित विकास की दृष्टि से, सांस्कृतिक उन्नयन की दृष्टि से यह गणतंत्र के सुदृढ शिलान्यास की दृष्टि से, कृषि और गावों का सहकारी सगठन और विकेन्द्रिकरण के आधार पर पुनरुत्थान आवश्यक है। इसीलिए पंचवर्षीय योजना में ऐसे सुझाव रखे गये हैं कि उनके द्वारा ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था में जान फूकी जा सके और गाव राष्ट्र-निर्माण की योजना की अविच्छिन्न इकाई बन सके।



# बिहार भूमि की देन :

खनिज,  
धातु  
और  
खनिज

श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी

किसी राष्ट्र की राजनीतिक सत्ता और आर्थिक विकास के मूल में उस देश में पाये जानेवाले औद्योगिक साधनों का विशेष महत्त्व है। इंग्लैंड के इतिहास के अध्ययन से स्पष्ट है इस देश का विकास औद्योगिक क्रान्ति के साथ प्रारम्भ हुआ और जब तक इसकी खानों से लोहा और कोयला प्रचुर परिमाण में मिलते रहे, इसके राज्य और बाजार के क्षेत्र बढ़ते ही गए और अन्त में यह विश्व का सर्वशक्तिशाली राष्ट्र हो गया। परन्तु समय ने पलटा खाया और औद्योगिक साधनों के ह्रास के साथ-साथ इसका भाग्य-सूर्य छिपता गया। और आज विश्व के क्षितिज पर अमेरिका सर्वशक्तिशाली राष्ट्र बन कर चमका है जिसका मूल कारण भी औद्योगिक साधनों का विकास ही है। इतना ही नहीं, रूस, जर्मनी, जापान एवं अन्य ऐसे देशों के औद्योगिक इतिहास भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि राष्ट्र को समृद्धिशाली और शक्तिशाली बनाने में उस देश के औद्योगिक साधनों का विशेष महत्त्व है। भारत सरकार भी आज औद्योगिक विकास के लिए कितनी योजनाएँ बना रही है और इस दृष्टिकोण से भारत में बिहार का स्थान विचारणीय एवं महत्त्वपूर्ण है।

## बिहार का औद्योगिक साधन

कहना न होगा बिहार औद्योगिक साधनों में धनी है। यहाँ लगभग सभी खनिज पदार्थ प्रचुर परिमाण में मिलते हैं। अन्य वस्तुएँ भी उद्योग के लिए प्राप्त हैं। ऐसी खेतिहर फसलों की भी कमी नहीं जिनका उपयोग कच्चेमाल के रूप में कल-कारखानों में होती है। सच पूछिये तो प्रकृति ने बिहार को सभी औद्योगिक साधनों से सजाया है। प्रान्त के प्राकृतिक विभा-

जन पर ही विचार कीजिए। उत्तरी बिहार भारत की वाटिका है। चम्पारण के सोमेश्वर से पूर्णिया के खालपोखर तक, न कहीं पहाड़ है और न जंगल ही। सारा उत्तरी बिहार सपाट मैदान है जहाँ ईख, पाट, तम्बाकू, तेलहन, नील इत्यादि फसलें आसानी से उपजायी जाती हैं जिनपर यहाँ के कारखाने कच्चे माल के लिए निर्भर करते हैं। इसके विपरीत छोटानागपुर की उपत्यका भारत की तिजोरी है। इसके गर्भ में कोयला, लोहा, अवरख, ताम्बा, मैंगनीज, क्रोमाइट, इत्यादि प्रमुख औद्योगिक वातुएँ प्रचुर परिमाण में वर्तमान हैं। इसके अलावा चना-पत्थर, बालू-पत्थर, नावून-पत्थर, फायर-क्ले, वाक्माइट अलम इत्यादि खनिज पदार्थ भी कम परिमाण में नहीं मिलते हैं। इतना ही नहीं छोटा नागपुर की यह उपत्यका ऐसे जंगलों में भी आच्छादित है जिनमें यहाँ के कल-कारखानों को कच्चे माल मिलते हैं। इस तरह बिहार के औद्योगिक साधनों पर बिहगम दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता है कि इनके साधनों को तीन श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं प्रथम खनिज पदार्थ, द्वितीय वन्य पदार्थ और तृतीय कृषि पदार्थ। अब प्रत्येक श्रेणी पर अविस्तार विचार किया जाय।

## खनिज पदार्थ

बिहार में वे सभी खनिज पदार्थ प्रचुर परिमाण में मिलते हैं, जिनकी उपस्थिति से कोई भूखंड महत्त्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र हो सकता है। कुछ ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनके लिए पूरे देश को बिहार पर निर्भर करना पड़ता है और कुछ ऐसे भी धातु हैं जिनके लिए विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों को भी बिहार का मुह जोहना पड़ता है। इस रहस्य के मूल में बिहार

की भौगर्भिक वनवट है जिसके कारण तरह-तरह के खनिज पदार्थ ही नहीं प्रत्युत अन्य औद्योगिक क्षेत्रों को कच्चा माल मिलता है।

### भौगर्भिक विशेषता

गंगा के मैदान के दक्षिण की ९० प्रतिशत भूमि प्राचीनतम चट्टान की बनी है जिस चट्टान के भूगर्भशास्त्रज्ञों ने "आर्चियन रौक" की सजा दी है। शेष भूमि "गोडवाना लैंड" कहा गया है जिसके गर्भ में विस्तृत कोयला क्षेत्र स्थित है। उत्पत्ति के दृष्टिकोण से "आर्चियन रौक" को दो भागों में बाटा जाता है, आग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान। आर्चियन समय के इस परतदार चट्टान में नाना प्रकार के खनिज पदार्थ विद्यमान हैं। ये खनिज पदार्थ इस चट्टान में तह-पर-तह जहा-तहा जमे हैं। ऐसी चट्टानें छोटानागपुर उपत्यका के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में मुख्यत पाई जाती हैं। सिंहभूमि का असस्कृत लोहा (कच्चा लोहा) ऐसी ही चट्टान में पाया जाता है। इसी लोहे के क्षेत्र में मैगनीज, ताबा और "कायनाइट" भी प्राप्त होते हैं। उत्तरी छोटानागपुर (हजारीबाग) तथा गया और मुंगेर का अबरख क्षेत्र पेगमेटाइट चट्टान के साथ सम्बद्ध है। आर्चियन समय के आग्नेय चट्टानों में क्रोमाइट तथा आसब्सट्स नामक खनिज पदार्थ मिलते हैं। इसी आग्नेय चट्टान के विस्तृत क्षेत्र में यत्र-तत्र परतदार चट्टान के भी कुछ टुकड़े उभरे हुए हैं। ऐसी चट्टान जिसे चूना पत्थर की सजा दी गयी है जहा-तहा डालटेनगज से रामगढ तक मिलती है जिमसे चूना और सिमेंट बनाए जाते हैं। शाहाबाद के दक्षिण में बालू-पत्थर, चूना-पत्थर, मिट्टी पत्थर तथा 'क्वारजाइट' के परतों से बनी हुई कंमूर की उपत्यका है जिससे भी चूना और सिमेंट बनाने योग्य पत्थर मिलता है। दक्षिणी पलामू और रांची के उत्तरीय पश्चिमी हिस्सों में 'पट' नामक उपत्यका है जो डेक्कन लाखा का पूर्वी हिस्सा है। इस उपत्यका की उपरी सतह पर 'लैटराइट' की उत्पत्ति हुई है जो परिवर्तित होकर 'वाक्साइट' बन जाता है। 'वाक्साइट' से अलुमिनियम बनता है।

उत्तरी मैदान की भौगर्भिक वनावट में कोई विशेषता नहीं। सारा क्षेत्र पुरानी एव नयी अलुवीयल मिट्टी द्वारा निर्मित है। पुरानी अलुवीयल मिट्टी में एक प्रकार का कंकड़ मिलता है जिससे भी चूना और सिमेंट बनता है। ऐसी ही मिट्टी में कहीं-कहीं साल्टपिटर और रेह पाए जाते हैं। नयी अलुवीयल में ऐसी मिट्टी मिलती है जिसका उपयोग वर्तन, ईट, टाइल्स इत्यादि बनाने के उद्योग में होता है। इस तरह से बिहार के भौगर्भिक अध्ययन ने यह निष्कर्ष निकलता है कि यहा निम्नलिखित खनिज पदार्थ पाए जाते हैं

- (क) कोयला,
- (ख) अनस्कृत लोहा या अनशोधित लोहा,
- (ग) चूना पत्थर,
- (घ) बालू पत्थर,
- (ङ) मैगनीज,
- (च) अबरख,
- (छ) अगमृत ताबा,

- (ज) कायनाइट,
- (झ) स्टीटाइट, सोप स्टोन,
- (झ) वाक्साइट,
- (ट) क्रोमाइट,
- (ठ) फायर क्ले, चाइना क्ले, क्ले,
- (ड) आसब्सट्स,

इनके अतिरिक्त कुछ और खनिज पदार्थों का नाम बिहार सरकार के माइनिंग अफसर ने अपनी रिपोर्ट में दी है वे अक्षरानुसार निम्नलिखित हैं :—

- (ढ) अलम,
- (ण) अपाटाइट
- (त) आरसैनिक,
- (थ) आंचर,
- (द) कोएडम,
- (ध) ग्रेफाइट,
- (न) टुंगस्टेन,
- (प) बीसमत,
- (फ) वेरीटीस,
- (ब) यूरेनीटाइट।

### कोयला

कोयला बिहार ही का नहीं बल्कि सारे देश की औद्योगिक शक्ति का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त यह कितने उद्योगों को कच्चा माल भी है। अतएव कोयला जैसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ के आधिक्य के कारण बिहार दुनिया के औद्योगिक क्षेत्रों में अपना एक विशिष्ट स्थान बना सका है। इस उद्योग का प्रारम्भ १८९१ ई० में झरिया के कोयला क्षेत्र की खुदाई के साथ होता है। उस समय से उत्तरोत्तर खानों की खुदाई बढ़ती गयी और सन् १९४४-४६ के आकड़ा के अनुसार बिहार के कोयले का औसत वार्षिक उत्पादन डेढ करोड टन है जो भारत के कुल उत्पादन का ५६ प्रतिशत होगा। माइनिंग अफसर की रिपोर्ट १९५० के अनुसार भारत के मुख्य कोयला क्षेत्रों में से २० से अधिक कोयला क्षेत्र बिहार में ही हैं। इन कोयला क्षेत्रों से देश के कुल कोयले का ६६ प्रतिशत कोयला प्रतिवर्ष मिलता है। अकेले झरिया कोयला क्षेत्र से भारत का ५० प्रतिशत कोयला निकलता है। कोयले का यह वृहद् क्षेत्र बिहार राज्य के मध्य में दामोदर और कोयल नदी की घाटियों में पश्चिम में डालटेनगज से लेकर पूरब में देवघर तक फैला है। कोयला क्षेत्र को निम्नलिखित वर्गों में बाटा जा सकता है —

(क) दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र-इस घाटीके कोयला क्षेत्र से बिहार का ९५.०९ प्रतिशत कोयला निकलता है और कोयले के इस उद्योग में १,१५,००० व्यक्ति काम करते हैं बिहार का कुल कोयला कोप इसक्षेत्र में ही स्थित है। इस घाटी के मुख्य कोयला क्षेत्र (१) झरिया, (२) बोकारो, (३) रानीगज, (४) चन्द्रपुर, (५) उत्तरी करणपुरा, (६)

दक्षिणी करणपुरा और (७) रामगढ है। निम्नलिखित तालिका से विहार की खानों का औसत उत्पादन १९३७-४० पता चल सकता है

कोयले की खाने	उत्पादन	कुल का प्रतिशत
१ झरिया	१०,४२५,०००	७१ १
२ बोकारो	२,१००,०००	१४ ३
३ रानीगज, विहार	८४२,०००	५ ७
४ गिरिडीह	६६९,०००	४ ६
५ करणपुरा	५७६,०००	३ ९
६ जयन्ती, डालटेनगज राजमहल इत्यादि	११,०००	१ २

इस क्षेत्र का सभी कोयला "विट्टुमीनस" अथवा 'कोकिंग' के लिए उच्च श्रेणी का है। कोयला निकालने की प्रणाली में भी काफी सुधार हुआ है। 'स्टोइंग' प्रणाली का व्यवहार झरिया के समीपवर्ती कोयले की खानों में विशेषतः जामाडोवा में होता है। इस प्रणाली के द्वारा खान से शत-प्रतिशत कोयला निकाला जा सकता है और रिक्त स्थान में पानी के साथ बालू भर दिया जाता है। जामाडोवा में बालू दामोदर घाटी से रस्सी के पूरे द्वारा लाया जाता है और "हाइड्रोलिक" प्रणाली द्वारा बालू खान के रिक्त स्थानों में भर दिया जाता है। इस स्ट इग के कारण कोयला निकाला हुआ स्थान नीचे की ओर घस कर 'गोफ' नहीं बनता है और जंगल जमाने या मजदूरों के लिए मकान बनाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। दामोदर घाटी के कोयले के क्षेत्र में आवागमन की काफी सुविधा है। नदियों की चौड़ी घाटियों के कारण रेल और सड़क के जाल से विछ गए हैं।

(ख) हजारीबाग कोयला क्षेत्र जिसके प्रधान केन्द्र है (१) डटेड-कोरी, (२) चोप, और (३) गिरिडीह।

(ग) अडजोय घाटी या देवघर कोयला क्षेत्र जिसके मुख्य केन्द्र हैं, (१) गन्ती (२) साहजोवी, और (३) कुदितकराय।

(घ) राजमहल कोयला क्षेत्र, जिसके मुख्य खान केन्द्र हैं, (१) ब्रालिमनी, (२) पचवारी, चपरवीठा, (४) जलपारी और (५) हुता।

(ङ) कोयल घाटी के कोयला क्षेत्र यह कोयला क्षेत्र पलामू जिले में (१) डालटेनगज, (२) हुतार, और औरंगा कोयला क्षेत्रों के नाम से फँला है। (१) डालटेनगज कोयला का क्षेत्रफल ३० वर्गमील है। इसकी खानों में कोयले की कितनी मोटी परतें हैं जिनमें से एक की मोटाई २५ फुट है। कुल कोय ९० लाख टन है। मन् १९२४।२८ ई० के औसत आकड़ों के अनुसार यहाँ ६००० टन कोयला प्रत्येक वर्ष निकलता है।

(२) हुतार कोयला क्षेत्र ५८ वर्गमील है। इस क्षेत्र की खानों में कोयल की परतें ८, ९ और १४ फीट की हैं। इसका भी कुल कोय ९० लाख टन का है। दो सौ टन कोयला प्रतिवर्ष इस खान से निकाला जाता है। (३) औरंगा क्षेत्र ८७ वर्गमील है, परन्तु ५८।१ वर्गमील क्षेत्र में ही कोयला मिल सकेगा, कुल कोय २ करोड़ टन का है, परन्तु कोयला निम्न श्रेणी का है।

भारत का ४५ प्रतिशत (२५९५ करोड़ टन कोयला विहार के ही गर्भ में है। भारत के उच्च श्रेणी के कोयला कोय २८७२ करोड़ टन

जिसका ६१ प्रतिशत विहार में ही है। इतना ही नहीं, भारत का ८३ प्रतिशत कोकिंग कोयला (१२५ करोड़ टन) विहार में ही छिया है।

इन बातों से विहार के कोयला उद्योग का उत्तरदायित्व कई गुना अधिक हो जाता है। विहार के कोयला उद्योग में कोय-भरण की काफी आवश्यकता है। इधर कोयला अव्यवस्थित रूप से बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग पर निकाला जा रहा है और इस तरह अमूल्य राष्ट्रीय सम्पत्ति के शीघ्र ह्रास का मार्ग खोला जा रहा है। जहाँ पहले ७७५ प्रतिशत निम्नकोटि का तथा २५ प्रतिशत उच्च श्रेणी का कोयला निकाला जाता था, वहाँ अब यह अनुपात ठीक उल्टा हो गया है। यह नीति देश के दीर्घकालीन हितों के लिए घातक और अदूरदर्शितापूर्ण है। "इंडिया कोल फील्ड", कमिटी के अनुसार, वर्तमान उत्पादन की दर से कुल कोय की आयु ६५ वर्ष की होती है। अतएव यदि सरकार कोयले के उत्पादन, वितरण तथा उपयोग की युक्तिसंगत नीति नहीं बना सकी तो उद्योग की बात तो दूर रही, कोई राष्ट्रीय योजना भी नहीं तैयार कर सकती।

### लोहा

विहार के खनिज पदार्थों की दूसरी विशेषता यह है कि मिश्रित लोहा क्षेत्र भी कोयला क्षेत्र के समीप स्थित है। इसी लोहे और कोयले के परस्पर सामीप्य के कारण जमशेदपुर के लोहे और इस्पात के उद्योग नें, जो १९१२ ई० में स्थापित हुआ था, आज कितने सहायक और सहयोगी उद्योगों के साथ दुनिया में आज अपना एक महत्त्वपूर्ण स्थान बना लिया है। इंडियन टेरिफ इंडस्ट्री की रिपोर्ट में कहा गया है, इस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे उत्तम मिश्रित लोहा क्षेत्र स्थित है। लोहे की खान की खुदाई सर्व प्रथम १९०४ ई० में मयूरभज की खानों में प्रारम्भ हुई। इसके बाद सिंहभूम के कोलहन और ब्योन्नार स्टेट्स की खानों में लोहा निकाला जाने लगा। प्रथम और द्वितीय युद्धों के समय में लोहा और इस्पात उद्योग की वृद्धि के साथ-साथ मिश्रित लोहे के उत्पादन में भी बहुत वृद्धि होती गयी। कोलहन के नोआमडी की खान का उत्पादन ७०४, २५१ टन प्रतिवर्ष है और उसी स्टेट अव सिंहभूम का एक भूखंड के गोआ मनोहरपुर में एक दूसरी खान है जो इस धातु के लिए विशेष विख्यात है। १९४४ के आकड़ों के अनुसार सिंहभूम जिले में टाटा द्वारा उत्पादित अनमृत्त मिश्रित लोहे का ४२४ प्रतिशत १,६५८,९९३ टन उत्पादन किया है। सिंहभूम का असंगोचित लोहा बहुत ही उच्च श्रेणी का है। उसमें ६० प्रतिशत से कम लौह द्रव्य कभी भी नहीं रहता है। सी० एम० फाक्स के अनुसार इन लौह-क्षेत्र का असंगोचित लोहा अमेरिका के मुप्रमिद्ध मीनेमोटा और मिमिगन की खानों से निकले लोहे में उत्तम कोटि का है।

कोलहन को छोड़कर सिंहभूम जिले में ७ खानें हैं जिनमें लोहा निकाला जाता है। सिंहभूम का कुल कोय जिनमें ६० प्रतिशत लौह द्रव्य है और १०० फीट की गहराई तक मिलता है, १,०४७,०००,००० टन है।

लोहे और इस्पात के उद्योग में काम आनेवाले बहुत से अन्य खनिज पदार्थ हैं, जैसे चूना, पत्थर, मंगनीज, ट्रामाण्ट, अपाटाइट आदि, असंगोचित लोहा, चूना पत्थर और कोक (कोयले की जलाकर) तैयार



किया जाता है, के साथ मिलाकर 'ब्लास्ट फर्नेस' में गलाया जाता है। अतएव चूना पत्थर, कच्चा लोहा, बनाने के लिए परमावश्यक है। बिहार में चूना पत्थर की तो कमी नहीं है फिर भी जमशेदपुर के कारखाने के लिए मध्य प्रान्त का चूना पत्थर उत्तम और सस्ता पड़ता है।

चूना पत्थर सोनघाटी में कैमूर उपत्यका से काटा जाता है। यही से जपला और डालमियानगर की सिमेंट फैक्ट्रियों को चूना पत्थर भेजा जाता है। इसके अलावा डालटनगंज और रामगढ़ के बीच कितने ऐसे पहाड़ हैं जिनमें से चूना पत्थर काटकर कारखाने में भेज जाता है।

अपाटाइट, टाटा कारखाने में "फास कारिक" कच्चा लोहा बनाने का काम होता है। खेती के लिए खाद तैयार करने में भी इसकी आवश्यकता पड़ती है यह बिहार के तीन क्षेत्रों में पाया जाता है (क) अबरख क्षेत्र में यह 'पेगमटाइट' पत्थर के साथ कई जगह से निकाला जाता है। (ख) धालभूमि सबडिवीजन में ताबा क्षेत्र के समानान्तर १२ मील तक पत्थर गौरा से खजलदारी ग्राम तक के बीच यह पाया जाता है। (ग) और सरायकेला में भी यह मिलता है। टाटा कारखाने में मद्रास से भी अपाटाइट आता है।

इस्पात तैयार करने के लिए कच्चे लोहे में मैंगनीज या क्रोमाइट या डोनोमाइट से किसी धातु को मिलाकर गलाया जाता है। इन धातुओं को अंगरेजी में "एल्लाय मेटल्स" या मिश्रण योग्य धातु कहते हैं। मैंगनीज छोटानापुर के अनेक हिस्सों में पाया जा सकता है, परन्तु अभी तक सिंहभूमि में ही यह खान से निकाला जाता है। इस जिले से प्रतिवर्ष ११,००० टन असशोधित मैंगनीज का उत्पादन होता है। मैंगनीज की मुख्य खान चाइवासा तथा सिंहभूमि जिले के वीस्तापुर, गीटीलपी, कलेन्डा, गूरावामा, लागीया, टेकगसरायी टूटगूट, बराइवुक, जमादा, और गोट-कुरी में है। टाटा के कारखानों में सिंहभूम और क्योन्नर के ही मैंगनीज का उपयोग होता है।

क्रोमाइट का उपयोग मिश्रण के रूप में कड़े लोहे बनाने में होता है। इसका व्यवहार रासायनिक तथा चर्मशोधन उद्योग में भी होता है। क्रोमाइट की मात खाने सिंहभूमि में है। चाइवासा से पश्चिम में स्थित कोरहन की पहाड़ियों में भी यह प्रचुर परिमाण में मिलता है।

लोहा और इस्पात के उद्योग के लिए फायर क्ले और मिलिका तथा निम्नकोटि का वाक्साइट आवश्यक खनिज पदार्थ है। फायर क्ले और मिलिका में फायर त्रिक्रम एक प्रकार की ईंट बनाया जाता है जिसका व्यवहार लोहा गठानेवाले बड़े चूल्हे ब्लास्ट फर्नेस और अल्प हर्ष फर्नेस के बनाने में होता है। इस ईंट की विशेषता यह है कि ब्लास्ट फर्नेस की १४०० डिग्रीवाट की गर्मी में भी नहीं गलती। इसका उपयोग पौरो बनाने वाले चूल्हे में भी होता है। इन खनिज पदार्थों की हमारे प्रान्त में कमी नहीं। हमें तो यह भारत के कई हिस्सों में पाया जाता है परन्तु इरिया प्रांत में ही ता "फायर क्ले" नाम से अच्छा है। मुंगेर के जटगपुर पहाड़ में वाक्साइट मिलता है जिनमें निम्निका का अनुपात अधिक रहता है।

ताबा का चूना पत्थर है जो काया तथा पीतल के उद्योग में विशेष फायदे में आता है। आधुनिक युग में ताबा का महत्त्व बहुत

बढ़ गया है। भाग्यवश बिहार में ताबा का उद्योग बहुत पुराना है। अभी भी यहा ताबा का कुल कोष कम नहीं है। ताबा क्षेत्र ८० मील की लम्बाई में बामिनी नदी के दूर पारम से प्रारम्भ होकर खरसावा, सरायकेला ढालभूमि होते हुए मयूरभज की सीमा तक फैला है। इस क्षेत्र का मुख्य भाग राजदाह और बढिया के बीच में पड़ता है। घाटशीला से तीन मील की दूरी पर मउभडार में "इडिया कापर कारपोरेशन" के नाम के एक बड़ा कारखाना है। यहा से लगभग दश मील की दूरी पर स्थित मोसावनी की खान विशेष विख्यात है। उखा और घोबनी नामक दो और खानें हैं जहा असस्कृत ताबा (कौपर और) निकाला जाता है। मोसावनी का कुल कोष का परिमाण १९४० ई० में १० लाख टन था, जिसमें ताबा का अंश दो से तीन प्रतिशत था। हजारीबाग जिले के बारगुल्ड में भी ताबा की खान की उपस्थिति की सम्भावना थी, परन्तु ८० वर्ष के प्रयत्न के बाद भी वहा कुछ नहीं मिल सका है।

### अबरख

बिहार का अबरख भारत में क्या सारे विश्व में विस्थात है। अबरख के लिए अमरीका, ब्रिटेन, जर्मनी, जैसे महत्त्वपूर्ण देश भी बिहार के मुखपेक्षी है। बिहार का अबरख खड पूरब से पश्चिम दिशा में गया, हजारीबाग, और मुंगेर जिले के कुछ हिस्सों में फैला है। इस खड की लम्बाई ६० मील और चौड़ाई १२ से १४ मील तक है। कोडरमा इस खड का केन्द्र है। इस खड में 'मस्कोवाइट' और "फ्लेगोपाइट" नामक सबसे उत्तम श्रेणी का अबरख मिलता है। २० प्रतिशत अबरख नैलोर मद्रास से आता है। एक साल के आकड़े १९४१ से ज्ञात हो जायगा कि कितना और कितनी कीमत का अबरख निकला था।

स्थान	हज़रवेट	कीमत (रु० में)
हजारीबाग	६१,१०८	२३,३२,८१८
गया	२०,०५५	७,३२,७८८
मुंगेर	३,४६७	९१,९०३
भागलपुर	९२२	६,६४६
मानभूम	२४६	७,७१८
नैलोर (मद्रास)	१५,६४७	६,४८,०७५
निलगिरी और द्रावणकोर	१६७	१८,१६७
राजपूताना	२,८१४	१,११,५०६

### वाक्साइट

भारत का अधिकांश वाक्साइट बिहार में ही मिलता है। वाक्साइट की उत्पत्ति की कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। डा० सी० एस० फाक्स के अनुसार वाक्साइट दो प्रकार का होता है (१) मेडिटरेनीयन और (२) इडियम। गर्म देशों में वाक्साइट पत्थरों में परिवर्तित होने से होता है। पहले पत्थर विंग्रेप मिट्टी के रूप में परिवर्तित होता है और इसके बाद वाक्साइट नामक खनिज पदार्थ में। वाक्साइट राची और पलामू की उपत्यका में तीन हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर मिलता है। लोहरदगा

के समीपवर्ती बगान नामक पठार तो इसका घर ही है। केवल इस पठार पर ५ लाख टन वाक्साइट का कोप है। रासायनिक विश्लेषण के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला गया है कि इस हिस्से के वाक्साइट में ५५ से ५६ प्रतिशत तक 'अलुमीना' द्रव्य पाया जाता है। वाक्साइट अलुमूनियम बनाने के लिए कच्चा माल के अलावे ईकेरस और पेट्रोलियम को साथ करने तथा फायर ब्रिक्स और फिटकरी के उद्योग-वधो में भी काम आता है। राची के पकरीपट और सेरेन्डग तथा पलामू के नेतरहाट में भी यह पाया जाता है। मूरी (राची) की अलुमूनियम फ़ैक्ट्री में इसी इलाके के कच्चे माल की खपत होती है।

कायनाइट बड़े पैमाने पर केवल बिहार में ही मिलता है। सिंहभूमि में कायनाइट का ७० मील लम्बा खन्ड कोइनाइट क्वार्ज पत्थर के साथ लापसुवारू से लेकर खरसावा और सरायकेला तक फैला है। हिसाब लगाया गया है कि तीन फीट की गहराई तक कुल कोप यो है

लापसुवारू	२१४,००० टन
घागीडीह	२०,००० टन
बडीयावक्का	१०,००० टन
कन्यालुका	८,००० टन

टाल्क का व्यवहार सोप स्टोन के ऐसा होता है। खास तरह के टाल्क को 'स्टीयटाइट' कहते हैं। कागज, रग, रबर, चमडा इत्यादि के उद्योग में भी इसकी बुकनी का उपयोग होता है। यह सिंहभूमि के चाईवासा और केडपोसी के समीप मिलता है। राजगीर और बराकर के बीच की पहाडियों में भी और गया जिले में भी पाया जाता है।

बहुत से ऐसे खनिज पदार्थ हैं जिनका उपयोग रग के उद्योग में होता है। ऐसे खनिज पदार्थों में अलम, फिटकरी, औचर तथा ग्रेफाइट नामक धातु बिहार में मिलता है। दस फीट मोटी फिटकरी की परत रोहतास गढ के समीप तथा राजगीर के गर्म पानी के सोते में भी मिलती है। औचर तथा गेरू राजमहल पहाड के 'क्योलीन' के साथ तथा सिंहभूम में कितनी जगहों पर पाए जाते हैं। ग्रेफाइट पेंसिल की लीड बनाने के काम में भी आता है। यह छोटानागपुर की कितनी जगहों के अलावा पलामू के लतेहार के समीप भी मिलता है।

'यूरेनाइट' जिससे यूरेनियम निकाला जाता है, गया की सीगुर अवरख खान में मिलता है। फ सफ्ट जिसके साथ थोरियम मिल सकता है, गया जिल के पीचिल्ली के समीप पेगमेटाइट पत्थर के साथ पाया जाता है। गस्टन नामक खनिज पदार्थ टाटानगर के समीप है। यह प्रमाणित हुआ है कि यह सौ फीट की गहराई पर है।

आसबस्टम रगदार खनिज पदार्थ है। यह कई तरह का होता है। बिहार में अम्पीवोल आसबस्टस सरायकेला में मिलता है, परन्तु बारा-वाना का आसबस्टस आ. से नहीं जलता है। अतएव, कारखाने में व्यवहार करने के लिए इसमें कपडा इत्यादि बनाया जाता है। इसे सिमेंट में मिला कर आग से नहीं जलनेवाली पक्की छत बनाई जाती है।

वेरील एक ऐसा धातु है तो तावा, अलुमूनियम, मँगनेसियम तथा लोहे के मिश्रण से धातु के रूप में व्यवहार किया जाता है। इसे तावा

के साथ मिलाने से जो चीज तैयार होती है वह अधिक कड़ी और मजबूत होती है। बिहार में वेरील, अवरख की खानों से पेगमेटाइट के साथ निकाला जाता है। खासकर गया, और हजारीबाग के कोडरमा, जोरेमार और गावन में यह प्रचुर परिमाण में मिलता है।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि बिहार खान-उद्योग में अन्य प्रांतों से आगे है। लोहा, अवरख, भवन निर्माण सामग्री और तावा की खानों में १,६०,००० आदमी काम करते हैं। मँगनीज, और क्रोमाइट की खानों में ३४,००० व्यक्ति लगे हैं। अलग-अलग कोयले में १,१५,०००, अवरख में २३,५००, असस्कृत मिश्रित लोहे में १०,०००, (१९४८) भवन निर्माण सामग्री में ९,०००, तावा की खान में ३,००० तथा अन्य धातु की खानों में ३४००० व्यक्ति काम करते हैं। इन खनिज पदार्थों के कारण कितने कल-कारखाने स्थापित हो गए हैं जिनमें लाखों आदमी लगे हुए हैं।

इन खनिज पदार्थों पर आश्रित उद्योग-वधो का विशेष महत्त्व है। बिहार की लगभग ८० प्रतिशत औद्योगिक पूंजी और ४५ प्रतिशत औद्योगिक मजदूर इन्हीं उद्योग-वधो में लगे हैं। संक्षेप में नोचे उन कारखानों की तालिका दी जाती है जो कच्चे माल के लिए खनिज पदार्थों पर निर्भर करते हैं। ऐसे कारखाने की संख्या लगभग १५० है

उद्योग का नाम	व्यवहार में आनेवाले खनिज पदार्थ	मजदूरों की संख्या	विख्यात स्थान और कारखानों की संख्या
लोहा और इस्पात का कारखाना	असशोधित लोहा, कोक, चूना पत्थर, मिश्रित धातु।	२९,७३०	१ टाटानगर
सहायक लोहा, इस्पात के कारखाने	इस्पात, टोन, पैट, कच्चा लोहा, छड, फाएर क्ले, सीलीका कोक।	८,७२४	११ जमशेदपुर जमालपुर
फायर ब्रीक्स और टाइल्स	फायर क्ले, सीलीका, कोक।	६,२६८	८ धनबाद और झरिया के समीप
सीमेंट कारखाना	चूना पत्थर, जीपसम्, वाक्साइट	४,०००	६ कल्याणपुर, खीखनपुर, खैलारी, जपला, डालमियानगर
कोक फ़ैक्टरी	कोयला	२९,००९	झरिया के आसपास वेरारी (प्रसिद्ध)
ग्लाम फ़ैक्ट्री	वालू, कोयला इत्यादि	११,५००	११ पटना २, दामोदरघाटी ४, छिटफुट ५
तावा गलाने का कारखाना	असशोधित तावा	१,४००	१, घाटशीला के पास मउ भंडार में
तावाके तार बनाने का कारखाना	तावा	११,२९४	९ जमशेदपुर इत्यादि
अलुमूनियम फ़ैक्ट्री	वाक्मडट		१ मूरी
छोटे-छोटे उद्योग			१०२

खनिज-पदार्थ और उनपर आश्रित उद्योग-धंधे के सिलसिले में एक और औद्योगिक शक्ति, इन्डस्ट्रियल पावर, की चर्चा कर देना आवश्यक है जिसे कुछ वैज्ञानिकों ने सफेद कोयला, व्हाइट कोल, या जल विद्युत, हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी, की संज्ञा दी है। कहना न होगा कि हमारे देश में और खास कर विहार में अभी तक इस शक्ति का विकास नहीं हुआ है। अभी तक पूरे देश की प्रेरक शक्ति पोटेशियल पावर, का १५ प्रतिशत, ५ लाख किलोवाट, मात्र ही उत्पादन हो पाता है। परन्तु सोवियत रूस, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा कनाडा का उत्पादन भारत से क्रमशः ४५, २९ और १५ गुणा अधिक है। फ्रांस, स्वीटजरलैंड, नार्वे, स्वेडन और जापान ऐसे-ऐसे छोटे देशों का उत्पादन हमारे देश से ५ से १० गुणा तक अधिक है। जहाँ स्वेडन में २१०० किलोवाट, स्वीटजरलैंड में १९४४ किलोवाट और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में १६६० किलोवाट बिजली औसत एक व्यक्ति पर खर्च होती है वहाँ भारत में केवल ९२ किलोवाट बिजली की खपत प्रत्येक व्यक्ति पर पड़ती है। परन्तु स्वतंत्रता के पश्चात् इस अभाव को दूर करने के लिए और कोयला संरक्षण योजना को प्रश्रय देने के लिए जल विद्युत के विकास की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट हुआ है। बहु-मुखी योजनाओं की बड़ी चर्चा है, बहुतसी छोटी-बड़ी योजनाएँ केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकार के हाथ में हैं।

विहार भी इस दृष्टिकोण से पीछे नहीं है। दो बहुमुखी योजना दामोदर बहुमुखी योजना और कोशी बहुमुखी योजना, तो भारत में अपना महत्त्व रखती हैं। दामोदर घाटी की बहुमुखी योजना (डी० वी० सी०) अमेरिका की टेनेसी वैली (टी० वी०) के आधार पर नियोजित की गयी है और केन्द्रीय सरकार, विहार सरकार एवं पश्चिमी बंगाल सरकार द्वारा निर्मित कारपोरेशन के हाथ में दे दी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत बाढ़ रोकने, सिंचाई का प्रबन्ध करने तथा जल-विद्युत उत्पादन करने का प्रबन्ध है। आठ बांधे बनाये जायेंगे और एक बांध के साथ एक जल विद्युत का स्टेशन बद्ध रहेगा। इस तरह जल विद्युत पैदा करने वाले स्टेशन से २ लाख किलोवाट बिजली पैदा हो सकती है। इसके अलावा बोकारो थर्मल प्लैंट में निम्नकोटि के कोयला पलभराइज्ड कोल का उपयोग करके दो लाख किलोवाट बिजली पैदा किया जायेगा। बोकारो थर्मल प्लैंट का काम अब आरम्भ हो गया है। यदि ये योजनाएँ पूरी हो जाती हैं तो सारा छोटानागपुर और दक्षिणी विहार के कुछ भाग तथा पश्चिमी बंगाल के कुछ हिस्सों में जल-विद्युत आसानी से उपलब्ध हो सकेगा।

मेट्रोल टेकनिकल पावर बोर्ड के अनुसार बिजली के तार नेट वर्क थ्रोफु ड्रान्मिशन लाइन सरिया और रानीगज के कोयला क्षेत्र से होते हुए हवड़ा में लेकर अवरख क्षेत्र (हजारीबाग और गया) तक फैले रहेंगे। कलकत्ता, जमशेदपुर, टाण्टेनगज इत्यादि शहरों के होते हुए भी बिजली के तार दीयेंगे। जल विद्युत का उपयोग खानों और कारखानों में भी दिया जायगा। जल विद्युत का उपयोग कोयले, अवरख, फायर ब्रिक्, चूना पत्थर की खानों में करके अधिक मुक्त और सुन्दर टंग में खनिज पदार्थ निकाले जा सकते हैं। लोहा, इस्पात, बलुमृत्तियम, मिमेट इत्यादि के कारखानों में यह 'औद्योगिक शक्ति' के रूप में उपयोग किया जायगा।

मिट्टी के तरह-तरह के वर्तन बनाने का उद्योग-धंधा, जिसके लिये उपयुक्त मिट्टी दामोदर घाटी में पाया जाता है, का पूर्ण रूपेण विकास होगा।

उत्तरी बिहार में भी कोशी की बहुमुखी योजना की ओर भी केन्द्रीय सरकार और प्रान्तीय सरकार बहुत प्रयत्नशील है। इस नदी में प्रत्येक वर्ष बाढ़ को रोकने, उसके पानी को सिंचाई और बिजली पैदा करने के उपयोग में लाने के लिए योजनाएँ तैयार हो चुकी हैं। जल विद्युत पैदा करने के दृष्टिकोण से भी कोशी कम उपयोगी नहीं प्रमाणित होगी। बात यह है कि २४० मील तो कोशी हिमालय के पहाड़ी इलाकों में बहती है जहाँ इसे बर्फ का भी सामना करना पड़ता है। इसकी घाटी में वर्षा भी कम नहीं होती। औसत ६ इंच की वर्षा तो इसकी घाटी में हो ही जाती है। इसके फलस्वरूप कोशी नदी अपने साथ ४ करोड़ घन फीट पानी लाती है। भारत में ब्रह्मपुत्र के अलावा इतना पानी अपने साथ कोई दूसरी नदी नहीं लाती है। अतएव कोशी, पहाड़ी इलाकों से बहने और अधिक पानी लाने के कारण, जल विद्युत के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है।

निर्माणवेत्ताओं के अनुसार कोशी की बाढ़ को रोकने के लिए प्रथम बाध चतरा गौर्ज (नेपाल) पर बनाना होगा। इस बाध की ऊंचाई ७५० फीट होगी जो भारत में क्या विश्व में भी उच्चतम बाधों में एक होगा। इस बाध के निर्माण से १ करोड़ दस लाख घन फीट पानी का तालाब बन सकता है। उसी स्थान पर एक पावर प्लैंट भी बँठाया जा सकता है जिससे १०८ लाख किलोवाट बिजली तैयार हो सकती है। यदि इस योजना के अनुसार बाढ़ पर नियन्त्रण होता है, मिट्टी के कटान पर रूकावट होती है तथा फिर से भूमि उपजाऊ हो जाती है, तो जल विद्युत के विकास से इस क्षेत्र में कितने ऐसे कारखाने खुल जायेंगे जिनको कृषि सम्बन्धी कच्चेमाल (जूट, ईख, तम्बाकू, धान, तेलहन, दलहन) प्रचुर परिमाण में मिल सकेंगे।

### जगल से प्राप्त औद्योगिक साधन

छोटानागपुर में एक और दूसरा औद्योगिक साधन वर्तमान है, वह है जगल। जगल अमूल्य तथा आवश्यक राष्ट्रीय सम्पत्ति है। आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है कि देश के सर्वांगीण विकास के लिए लगभग एक चौथाई हिस्सा जगलो से ढँका होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से बिहार कुछ पीछे पड़ जाता है। विहार के अधिकांश जगल छोटानागपुर में ही है। इसके अतिरिक्त केवल सताल परगना और चम्पारण का उत्तरी-पश्चिमी हिस्सा ही जगलो से ढका है।

विहार सरकार के १९५० के आकड़े के अनुसार जगलो का कुल क्षेत्रफल १११,००० वर्गमील होता है जो सम्पूर्ण क्षेत्रफल का केवल १४२ प्रतिशत होता है। इस तरह विहार को अपने वन्य-साधन पूरा करने के लिए कम-से-कम ६ प्रतिशत जमीन पर और जगल लगाने की आवश्यकता है। फिर भी इस समय जो जगल है वह औद्योगिक साधनों में कम नहीं है। १९४६ ई० में इन जगलो से ५० हजार टन टिम्बर निकाला गया था। आज भी छोटानागपुर का साल पूरे भारत में मशहूर है। प्राइवेट प्रबन्ध के कारण सभी जगल तहम-नहस हो रहे थे। अब सरकार ने राष्ट्रीय सम्पत्ति

की और ध्यान दिया है और वह दिन दूर नहीं कि इन्हीं जगलो से ५ लाख टन टिम्बर और ६० लाख टन जलावन की लकड़ी निकाली जायेगी ।

### लाह का उद्योग-धंधा

टिम्बर के अतिरिक्त जगलो में कितने ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनका औद्योगिक महत्त्व है । उन वृक्षों में विशेषतः पलास, कुसुम, बेर, इत्यादि ऐसे वृक्ष हैं जिन पर लाह के कीड़े पाले जाते हैं । लाह के कीड़े छोटानागपुर के कोने-कोने में मिलते हैं । सतालपरगना और गया जिले में भी लाह की फसल होती है । भारतवर्ष का ८० प्रतिशत लाह का उत्पादन बिहार में ही होता है और दुनिया की ४१ प्रतिशत भाग बिहार ही पूरा करता है । बिहार को लाह के उद्योग में एकाधिकार है ।

छोटानागपुर के मानभूम जिले में इस उद्योग का जन्म हुआ था । हाल-हाल तक यह उस इलाके में केवल घरेलू उद्योग-धंधे के रूप में प्रचलित था । 'स्टीम मशीन' के आने पर भी लाह के घरेलू उद्योग-धंधे को अधिक धक्का नहीं लगा है और लगभग ६० प्रतिशत उद्योग तो पुराने ही ढंग से चल रहा है । अधिकांश लाह की मिलें मानभूम में हैं । झालदा तो इसका केन्द्र ही ठहरा । यहाँ लाह तैयार करने की १५ छोटी-बड़ी मिलें हैं, सात मिलें तो ऐसी हैं जहाँ "स्टीम" का खूब उपयोग होता है और बड़े पैमाने पर "कच्चे माल" पीस और गलाकर "सेलेक" तैयार किया जाता है ।

झालदा में इस उद्योग-धंधे के केन्द्रीकरण का दो मुख्य कारण हैं । पहला तो यह कि इस उद्योग के लिए निपुण श्रम की बहुत आवश्यकता पड़ती है जो जहाँ उपलब्ध है । मशीन के सहारे कच्चे माल को पीस कर लाह के दाने (सीलेक) तो आसानी से बनाया जा सकता है परन्तु लाह के दाने को गला करके लाह के चपड़े (सेलेक) बनाने का काम निपुण मजदूरों द्वारा ही हो सकता है । दूसरी बात यह है कि लाह के कीड़े होते हैं जो बेर, कुसुम, या पलास के पेड़ों पर पाले जाते हैं । इनके पालने के भी तरीके हैं । इसके अलावा उन वृक्षों की भी देख-रेख करनी पड़ती है तथा ऐसी दशा पैदा करनी पड़ती है जिनसे कीड़े की फसल लगे और अच्छी तरह लगे । ये सब परिस्थितियाँ इन जगलो में उपस्थित हैं और इन्हीं के फलस्वरूप यहाँ लाह का कच्चा माल प्रचुर परिमाण में मिल सकता है । मानभूम के बाद सिंहभूम और पलामू का नम्बर आता है । गया और हजारीबाग में भी कच्चा माल मिलता है जिससे सेलेक और किटीलैक नामक तैयार माल का उत्पादन होता है । राची इस उद्योग के व्यापार का मुख्य केन्द्र है । सताल परगने में पाकुर लाह के उद्योग-धंधे तथा व्यापार के लिए विशेष विख्यात है । सेलैक जिसे वहाँ के लोग चपड़ा कहते हैं, अधिक स्थान में नहीं बनता । अधिकांश जगहों में लाह के दाने ही बनते हैं । "सेलेक" ही वह वस्तु है जो विदेश भेजा जाता है । इसी 'सेलेक' से लाह की अन्य वस्तुएँ बनती हैं । बिहार में 'सेलेक' का सहायक उद्योग-धंधा है, जो इन्हीं कच्चा माल के रूप में व्यवहार कर सके अभी तक नहीं स्थापित हो सका है । हा, अन्य पैमाने पर कहीं-कहीं लहठी, खिलौने इत्यादि वस्तुएँ बनती हैं । इन उद्योगों में अभी काफी सुधार की आवश्यकता है । कच्चा माल और निपुण श्रम का आधिक्य है । जगलो में आवागमन की भी कम असुविधा नहीं । फिर भी,

कितने ऐसे जगल हैं जहाँ लाह की अच्छी फसल हो सकती है । परन्तु आवागमन की असुविधा और आदिवासियों के अज्ञान के कारण वहाँ कुछ भी नहीं होता है । सरकार को इसकी ओर ध्यान देना है ।

### कागज के उद्योग-धंधे

दूसरा उद्योग कागज का है जो अपने कच्चे माल के लिए जगलो के वास और घासों पर आश्रित है । बिहार में इस उद्योग को चलाने के लिए कच्चे माल की कमी नहीं है । छोटानागपुर में पर्याप्त वास है और पूर्णिया में सवाई घास । केवल एक कारखाना डालमियानगर में है जिनमें १६०३ (१९५०) मजदूर काम करते हैं । इस कारखाने में वास की खपत होती है जो सोन नदी के द्वारा छोटानागपुर से लाया जाता है । उत्पादन के कोई आकड़े नहीं दिए जा सकते क्योंकि समय-समय पर तरह-तरह के कागज और बोर्ड इत्यादि बनते रहते हैं । हा, मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि ३५ टन कागज प्रतिदिन इस कारखाने में तैयार होता है ।

बिहार के पूर्णिया और सताल परगने में भी कागज के उद्योग के लिए सवाई घास पर्याप्त परिमाण में मिलती है । परन्तु यह घास बगाल के कागज के कारखाने के लिए भेज दी जाती है । यदि पूर्णिया या सताल-परगने में कागज प्लैंट बँठाया जाय, तो मिल मालिक को खासा लाभ हो । दामोदर घाटी योजना की पूर्ति के पश्चात् दामोदर घाटी में भी एक कारखाना खुल सकता है । जो हो, बिहार के पास कागज के कारखाना चलाने के लिए प्राकृतिक साधन वर्तमान हैं । यदि इन्हीं आर्थिक साधन मिल जाय और सरकारी प्रोत्साहन प्राप्त हो जाय तो कारखाना आसानी से स्थापित हो सकता है । बिहार सरकार की औद्योगिक विकास-योजना के अनुसार यहाँ एक कागज का कारखाना खुलना चाहिये ।

जगलो पर आश्रित तीसरा लकड़ी काटने और 'टिम्बर' निकालने का उद्योग है जिसे अंग्रेजी में सा मिलिंग कहते हैं । यह उद्योग छोटानागपुर में विशेषतः केन्द्रित है । इसका भविष्य भी उज्ज्वल है । बात यह है कि कुछ वर्ष पहले बिहार में जगल-संरक्षण नामक कोई योजना नहीं थी । जमीन्दार मनमाने ढंग से जगल को तहस-नहस किया करते थे । उस समय भी यहाँ २९ मिलें थी जिनमें १५०० मजदूर काम करते थे । गत पाच वर्षों से जगल संरक्षण पर सरकार ने काफी ध्यान दिया है । फलतः यह उद्योग नियन्त्रित और वैज्ञानिक ढंग पर चलने लगा है ।

इसके अलावा जगलो में कुछ खास तरह के वृक्ष होते हैं जिनसे किसी-न-किसी रूप में उद्योग-धंधे को लाभ पहुँचता है । उदाहरणार्थ बिहार में आसन और अर्जुन के वृक्ष हैं जिसपर रेशम के कीड़े पाले जाते हैं । खैर के वृक्ष से कथ निकाला जाता है । महुआ के फूल से शराब बनती है । सेमर के फल में रूई निकलती है । आवनूस या केन्द के वृक्ष तो आजकल विशेषतः उल्लेखनीय हैं । इसके पत्तों से बीड़ी बनायी जाती है । ऐसे वृक्ष विशेषतः हजारीबाग, पलामू और गया जिले में हैं । बीड़ी का व्यवहार बढ़ने से इन उद्योगों में काफी वृद्धि हुई है ।

अन्त में मैं एक और उद्योग का उल्लेख करना चाहता हूँ जिसके लिए कच्चा माल, बाजार और निपुण श्रम इत्यादि उपलब्ध हैं और वह है नकली रेशम के सूत से कपड़े बनाने का उद्योग-धंधा । नकली रेशमी सूत

से कपडा बुनने का उद्योग बिहार में दिनोदिन बढ़ता जा रहा है। १९४४-४५ के आकड़ों के अनुसार २० करोड़ पाँड रेशमी सूत की ( रेयन यार्न ) तो बिहार के ही करघा उद्योग-घरों में खपत हो जाती है। इसी तरह भारत के अन्य प्रान्तों में यह सूत विदेश से मगाया जाता है। यदि सूत बनाने का कारखाना यहाँ स्थापित होता तो सारे स्टेट की माग पूरी होती ही, सारे भारत के बाजार में विदेश से सूत आना बंद हो जाता।

इस उद्योग के लिए वास, घास, सन, जूट, गेहूँ के खेर इत्यादि कच्चा माल चाहिये जो बिहार में आसानी से पर्याप्त मात्रा में प्राप्त है। बिहार सरकार को इस उद्योग की ओर ध्यान देना चाहिए। यदि रेयन उद्योग के लिए मशीन, मिल, और निपुण रासायनिक की सहायता मिलेगी तो इस उद्योग की स्थापना के लिए भागलपुर उत्तम स्थान है। यहाँ इस उद्योग के लिए आवश्यक साधन, पानी, निपुण श्रम, बाजार इत्यादि मिल जायेंगे। पेनेल रिपोर्ट और आफिसियल सिल्क एंड रेयन इन्डस्ट्रीज का भी यही मत है।

इस तरह बिहार के जगलो और उनपर आश्रित उद्योगों घघों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्र में विकास की बहुत सम्भावनाएँ हैं। जगलो की सरक्षण-नीति और बिहार के औद्योगिक विकास की योजना के कारण इस ओर काफी वृद्धि होगी। रेयन और सलाउ के नये कारखाने खुलेंगे, लाह के उद्योग में विकास होगा और कागज के नए कारखाने स्थापित होंगे। आज भी जगल के उद्योग-घघों का केन्द्रीकरण छोटा नागपुर के अधिकांश हिस्सों में होता जा रहा है और वह दिन दूर नहीं जब बिहार की यह जगली भूमि ( दामोदर घाटी योजना के कारण भी ) बिहार का ही नहीं सारे राष्ट्र का मुख्य औद्योगिक क्षेत्र बन जायगा। १९४४-४६ के आसत आकड़ों के अनुसार बिहार के जगल उद्योग-घघों की दशा निम्नलिखित तालिका से एक नजर में झलक जायेंगी

उद्योग का नाम	कारखाने की मख्या	मजदूरोकी सख्या	विशेष बातें
१ लाह और सेलेक के कारखाने	६०	१९३६	झालदा और विलासपुर में इसका केन्द्रीकरण
२ कागज का कारखाना	१	१६०३	डालमियानगर
३ सा मिल	२९	१५००	छोटानागपुर में इधर काफी वृद्धि हुई है।
४ छोटे-छोटे उद्योगघघे	६	१०१६	"
	९६	६१५५	

### कृषि पर आधारित

यदि छोटेनागपुर में तरह-तरह के खनिज पदार्थ और जगल पर्याप्त परिमाण में विद्यमान हैं तो उत्तरी बिहार में इनका एकदम अभाव है। नगर नगरीय नदी नदिमिया आनाय में बुझा उगलती नगर आती है जो नदिमिया का कोठमा से तरह गोफ, खेयुगी जयवा खान की मुरग की नदी नगरीय नदिमिया को मिला है। यह तो अक्षरशः शस्य ध्यामला कृषि

प्रधान भूखड है। चम्पारण के सोमेश्वर से पूर्णिया के खालपोखर तक न कहीं पहाड है और न जगल ही। सारा उत्तरी बिहार सपाट मैदान है। मिट्टी उपजाऊ है। वर्षा और ताप पर्याप्त परिमाण में प्राप्त है। दर्जनों नदिया इसे सींचती हैं। फलो की बाटिकाएँ इस क्षेत्र की सम्पन्नता को और भी बढ़ा देती हैं। सचमुच, यह बिहार की ही नहीं, सारे भारत की बाटिका है।

इन भौगोलिक विशेषताओं के कारण उत्तरी बिहार में कितनी औद्योगिक फसलें, गन्ना, पाट, धान, तेलहन, तम्बाकू इत्यादि की उपज अच्छी होती है। उत्तरी बिहार को धान और ऊख का इलाका की सजा दी गयी है। बात यह है कि गन्ने के लिए चिकनी मिट्टी चाहिये और सिंचाई का प्रबन्ध रखना चाहिये जो इस इलाके में उपलब्ध है। पूर्णिया तो पाट का घर ही ठहरा। पूर्णिया की कुल उपजाऊ भूमि के ६३ प्रतिशत जमीन में यही व्यावसायिक फसल उपजायी जाती है। तेलहन भी उत्तरी बिहार में कम नहीं उपजता। तम्बाकू मुजफ्फरपुर और पूर्णिया जिले में खूब उपजता है। बिहार के अन्य जिलों में इसकी उपज नहीं के ही बराबर होती है। यहाँ तक कि मुंगेर जिले में जहाँ इनकी खपत आसानी से हो सकती थी वहाँ की कुल उपजाऊ भूमि के १५ प्रतिशत में ही यह फसल उपजायी जाती है।

दक्षिण बिहार में भी धान और गन्ने की उपज कम नहीं होती। नीचे की तालिका से ज्ञात होगा कि लगभग २५ प्रतिशत जमीन में तो धान की फसल होती है। हा, उत्तरी बिहार की अपेक्षा यहाँ की जमीन में अधिक गेहूँ बोया जाता है। छोटेनागपुर तो जगल और पहाडों का मुल्क है। वहाँ के लोग भी सम्यता की दौड में पीछे ही हैं। अतएव न वहाँ खेती करने योग्य अधिक भूमि ही प्राप्त है (कुल जमीन का २१ प्रतिशत) और न ऐसे उद्योग-घघे ही पनपते हैं जो कृषि पर निर्भर करते हैं। औद्योगिक फसलों की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हो जायेंगी

नाम	खेतीकरने योग्यभूमि	खेती की भूमि	धान	गन्ना	तेलहन	पाट	तम्बाकू
तिरहुत कमिश्नरी							
सारन	९०३	७०२	२०३	३५	६५	०	००६
चम्पारण	८९६	६२९	३८३	६०	७३	०१	००४
मुजफ्फरपुर	९८६	५४७	४०१	३०	३३	०२	२६
दरभंगा	७१६	६३४	४९२	३३	७२	००३	०६
पटना कमिश्नरी							
पटना	७६३	७०३	२६०	१३	३७	०	०८
गया	७०३	३९६	४८६	२३	४८	०	००६
शाहाबाद	८०१	५१६	२८१	२३	६०४	०	०४
भागलपुर कमिश्नरी							
भागलपुर	६७५	४६१	४६१	०९	८४	४	३
पूर्णिया	३६४	३६८	४४८	१२	६१	२१६	२५
मुंगेर	८०४	४६१	२४४	८०	४३	०२	६
सतालपरगना	५४९	३३१	४७९	१	७०	०३	०७

नाम	खेती करने योग्यभूमि	खेती की धान भूमि	गन्ना	तेलहन	पाट	तम्बाकू
छोटानागपुर कमिश्नरी						
राची	४२१	४११	६०४	००२	०५००	०२
हजारीबाग	२३५	२०९	४६७	९	१०००	०३
पलामू	१९५	१५५	२८७	८	१२०५	०३
मानभूमि	२०२	२०२	६७८	९	७	०
सिंहभूमि	१८६	१७४	७७४	१	८६	००४

इस सक्षिप्त तालिका से यह स्पष्ट हो जाता है कि विहार में खेतों से, खासकर छोटानागपुर को छोड़कर, उद्योग-घघों के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त होते हैं। इस कच्चे माल की खपत सर्व प्रथम घरेलू उद्योग-घघों में होती थी। परन्तु मशीन का प्रचलन होने से घरेलू उद्योग-घघों को बहुत बड़ा घक्का पहुँचा और अब इनकी अधिकांश खपत फैक्ट्रियों और मिलों में होती है। एक-एक करके प्रत्येक उद्योग-घघों के बारे में विचार करना उचित होगा।

### चीनी उद्योग

कहना न होगा कि गुड़ और शक्कर बनाने का उद्योग विहार में पौराणिक काल से चला आ रहा है। जब मशीन युग की सम्पत्ता आई, तब चीनी की प्रथम फैक्टरी खोलने का श्रेय भारतमें विहार ही को मिला। १९०० ई० में यहाँ प्रथम चीनी मिल की स्थापना हुई। नील के उद्योग में मदी पडने से चीनी के उद्योग में और भी सरगर्मी आई और १९०४ ई० में पुन चीनी के ३ कारखाने खुले। इसी समय पडोसी प्रान्त उत्तर प्रदेश में भी एक कारखाने की स्थापना हुई। परन्तु अभी तक देश के कारखानों में तैयार चीनी विदेशी चीनी से महगी पडती थी और इसी हेतु लोग भारतीय चीनी खरीदना पसंद नहीं करते थे। केन्द्रीय सरकार ने १९३२ ई० में विदेश से आनवाली चीनी पर सरक्षण कर लगाया। इसके बाद तो चीनी के कारखानों की सख्या दिनोदिन बढ़ती गयी और इस समय देश में १४० मिलें हैं जिनमें से विहार में ३६ मिलें हैं। ये मिलें विहार के उसी हिस्से में स्थित हैं जहाँ ईख की फसल बहुत अच्छी होती है। यह इलाका गंगा के उत्तर में राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर पूरव में कोशी नदी तक का भूखंड है। विहार के इसी हिस्से में गन्ना की सबसे अच्छी फसल होती है। यहाँ की मिट्टी और जलवायु इसी फसल के योग्य है तथा नयी भूमि होने के कारण कृत्रिम सिंचाई की भी आवश्यकता नहीं पडती। इस हिस्से की ५९ प्रतिशत जमीन में जिसका क्षेत्रफल २,४५,००० एकड़ है, ईख की खेती होती है। इसके अलावा आरा और गया जिले में भी ईख की फसल अच्छी होती है। परन्तु इन हिस्सों में नहर, पइन, अहरा या अन्य उपायों से सिंचाई का प्रबन्ध करना पडता है।

'विहार का औद्योगिक विकास', (१९५०) शीर्षक एक लेख में डा० महमूद ने बतलाया था कि भारतीय सरकार की योजना के अनुसार विहार में तीन चीनी मिल स्थापित करने का विचार था। इसी योजना के अनुसार

एक मिल वारसलीगज में स्थापित हुई। परन्तु इसके लिए उपर्युक्त भौगोलिक स्थिति होने पर भी अर्थाभाव से यह एक साल में ही बन्द हो गयी। इसी योजना के अनुसार पूर्णिया के करहागोला में भी एक मिल स्थापित होनी चाहिये।

### जूट का उद्योग-घंघा

इस राज्य में पाट की तीन मिलें हैं, दो पूर्णिया और एक दरभंगा जिले में। इन मिलों में १९४६ ई० की रिपोर्ट के अनुसार क्रमश ३,७३६ और १,४३६ मजदूर काम करते हैं। देश के विभाजन से भारतीय जूट उद्योग को गहरा घक्का लगा है। वगाल के विभाजन से ७२८१ प्रतिशत जूट का खेत अब पाकिस्तान में चला गया परन्तु कुल मिलें भारत में ही रह गयी। पाकिस्तान पर कच्चे माल के लिए निर्भर करना अच्छा नहीं। अतएव अपने देश में ही इसकी खेती बढ़ाना आवश्यक है। विहार ही ऐसा राज्य है जहाँ इसकी पैदावार बढ़ायी जा सकती है। इस समय इसकी उपज पूर्णिया, महरसा, भागलपुर, दरभंगा, चम्पारण तथा सतालपरगने में होती है। परन्तु ऊपर के आकड़े से स्पष्ट है कि केवल पूर्णिया जिले में जूट उपजाने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। जूट की खेती में उपज बहुत कम-बेशी हुआ करती है। जहाँ १९३६ ई० में ३, ६२,००० एकड़ जमीन में जूट की उपज होती थी वहाँ १९४७ ई० में सरकारी वार्षिक विवरण के अनुसार केवल १,४४,०० एकड़ जमीन में ही जूट बोया गया था। देश के विभाजन के कारण पुन जूट उपजाने की प्रेरणा बढी है। गत वर्ष सवा दो हजार एकड़ अधिक जमीन में जूट बोया गया। हिमाव लगाया गया है कि यदि परती जमीन को जोता जाय तथा अच्छे बीज और खाद का उपयोग किया जाय तो जूट की पैदावार में शतप्रतिशत वृद्धि होगी। ऐसे तो विहार सरकार के पास तीन जूट मिल स्थापित करने की योजना है। परन्तु पहले हुगली के समीप स्थित वगाल की जूट मिलों को कच्चा माल देकर उनमें जान फूकनी है। इस तरह पाकिस्तान से कच्चा माल नहीं मिलने के कारण जो यदा-कदा बेकारी और मदी पड सकती है, उसे रोकना है।

### कपडे के उद्योग-घंघे

कृषि पर आश्रित उद्योगों में कपडे का विशेष महत्त्व है। कपडे का उद्योग तो अब कच्चे माल के क्षेत्र में ही केन्द्रित होने लगा है। इसी कारण भारत की अधिकांश कपडे की मिलें बम्बई और अहमदाबाद में स्थित हैं जो रुई पैदा करनेवाले हिस्से में पडती हैं। विहार में अब रुई की फसल नाम मात्र को होती है। अतएव यहाँ कोई कपडे का विख्यात कारखाना नहीं है। यहाँ केवल दो मूत कातने और एक कपडा बुनने की मिलें हैं। सूत कातने की मिल एक फुलवारी शरीफ और दूसरी बक्सर सेंट्रल जेल में हैं। 'गया काटन मिल' में मूत की कताई और बुनाई दोनों होती हैं। यहाँ मोटा कपडा तैयार होता है जिसकी खपत मानभूमि और सिंहभूमि के मजदूरों में खूब होती है। १९३९ ई० के आकड़े के अनुसार ६०,००० गज कपडा और २० गाठ सूत प्रतिदिन तैयार होता था। कच्चा माल उत्तर प्रदेश और बम्बई में आता था। इन मिलों में २,८३६ मजदूर (१९५०) में काम करते थे। इस समय इन मिलों की, विशेषतया 'गया काटन मिल' की दशा एकदम अच्छी नहीं है। उत्पादन में बहुत ही मदी आ गयी

है, मजदूरो की सख्या बहुत ही घट गयी है और मजदूर की हडताल तो आम चीज हो गयी है।

कपडे की मिल के लिए बिहार में कोई रूई नही उपजती। पहले रूई की खेती होती थी परन्तु इस समय तो अल्प पमाने पर भी बहुत ही कम जगह होती है। अतएव निकट भविष्य में कपडे का कारखाना खुलना सदेहात्मक दीखता है। परन्तु बिहार में कपडे का बाजार बहुत ही विस्तृत है। यहां की क्रय-शक्ति भी बहुत है। अतएव 'बाजार' में कारखाने खोलने की नयी प्रवृत्ति के कारण यह आशा की जाती है कि बिहार में कपडे के कारखाने स्थापित हो सकते हैं। परन्तु पूजी भी लोग इस उद्योग में लगाने से हिचकते हैं। बिहार सरकार की विकास योजना के अनुसार यहां आठ सूत कातने और बुनने के कारखाने खुलने चाहिये परन्तु इस ओर अभी कुछ काम नही हुआ। शायद पूजी का अभाव और मशीन की प्राप्ति में कठिनाई के कारण यह विचार छोड देना होगा।

### धान का उद्योग

बिहार के उत्तरी छोर पर केवल चावल के उद्योग-धधे होते हैं। इस हिस्से में चावल की उपज ज्यादा होती है। दूसरी बात यह है कि नेपाल में भी धान की खूब उपज होती है। परन्तु वहां न तो आसानी से मिल ही खोली जा सकती है और न चावल के लिए वहां बाजार ही है जहां उसकी खपत हो सके। फलतः नेपाल का धान पहाड की इसी तराई में लाया जाता है। इन्ही मव भौगोलिक अवस्थाओं के कारण बिहार के पहाड की तराई में एक किनारे से दूसरे किनारे तक बहुत सी मिलें खुल गयी हैं। इनके अलावा दक्षिण बिहार में भी कुछ छिटपुट मिलें हैं। इन मिलों के अलावा धनकुट्टी बडे पमाने पर घरेलू उद्योग-धधे के रूप में भी हमारे राज्य में वर्तमान है। यो तो इसका आकडा प्राप्त नही है, फिर भी अन्दाज लगाया गया है कि लगभग आधा चावल से अधिक किसानों द्वारा अपने घर में तैयार किया जाता है।

### मिलेजुले उद्योग-धधे

तेल की मिले साधारणतः उत्तरी और दक्षिणी बिहार में स्थित हैं। भागलपुर में अधिकांश मिलें हैं। १९४९ ई० के आकडे के अनुसार तेल की मिलों की मख्या ८१ हैं जिनमें १,६४५ मजदूर काम करते हैं। तम्बाकू की ६ फैक्टरिया हैं जिनमें ३,६१८ मजदूर काम करते हैं। ये फैक्टरिया मुंगेर और दरभंगा जिले में स्थित हैं। १९४८ ई० के आकडे के अनुसार चावल, तेल, दाल और आटा पीसने की मिली जुली ५२ मिलें हैं जिनमें २,३४८ आदमी काम करते हैं। ये मिलें कुछ-न-कुछ बिहार के सभी गहरों में स्थित हैं। इन दिनों इस तरह की मिलों की गन्ना में बहुत वृद्धि हो रही है और अब तक इनकी मख्या बहुत बढ़ गयी होगी।

अनिरिक्त और भी छोटे-छोटे खाद्य उद्योग-धधे (फुड इन्डस्ट्रीज) को देने मात्र के लिए कृषि पर आश्रित हैं। कृषि पर प्रति उद्योग-धधे तो स्थिति इन तारिका (१९४९) में स्पष्ट हो

मिल का नाम	मिलों की सख्या	मजदूरों की सख्या	स्थान
१ चीनी मिल	३४	२०,६००	उत्तरी बिहार, गया, शाहाबाद
२ जूट मिल	३	६,०८७	दरभंगा और पूर्णिया
३ तम्बाकू	६	३,६१८	मुंगेर और दरभंगा
४ चावल मिल	६०	३,३५१	उत्तरी बिहार और अन्य स्थान
५. तेल मिल	८१	१,६४५	भागलपुर और अन्य भाग
६ मिले जुले चावल, दाल, तेल और आटे के कारखाने	५२	२,३४८	
७ कृषि पर आश्रित छोटे उद्योग-धधे	५०	१,०८९	

इस तरह बिहार के इन औद्योगिक साधनों और उनके विकास की सम्भावनाओं के विश्लेषण करने से और औद्योगिक प्रवृत्तियों के मनन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि खास उद्योगों का केन्द्रीकरण किसी खास भौगोलिक हिस्से में होता जा रहा है। इस राज्य के औद्योगिक विकास के इतिहास के अध्ययन से यह बात भी जाहिर हो जाती है कि कुछ ऐसे भौगोलिक एव अर्थ शास्त्रीय कारण हैं जिनकी वजह से बिहार का औद्योगिक विकास अलग-अलग क्षेत्र में भिन्न-भिन्न चीजों का हुआ है। दक्खिन पूर्वी बिहार में, औद्योगिक धातुओं के आधिक्य के कारण, लोहे-ताबा इत्यादि के कारखाने खुल गए हैं। उसी तरह दामोदर घाटी में, कोयला क्षेत्र होने की वजह, से कोयले पर आश्रित उद्योग-धधे, कोक, खाद, फायर ब्रीक्स होते हैं। उत्तरी बिहार में उपजनेवाले कच्चे माल गन्ना, धान, और जूट के आधिक्य के कारण वहां ऐसे ही कारखाने हैं जिनमें इनकी खपत होती है। इसी प्रकार यदि बिहार के औद्योगिक साधनों की जाच की जाय और उसके औद्योगिक विकास का विश्लेषण किया जाय तो पता चलेगा कि बिहार को निम्नलिखित औद्योगिक हिस्सों में विभक्त किया जा सकता है—

- (१) दक्खिन पूरब का औद्योगिक हिस्सा
- (२) दामोदर घाटी का औद्योगिक हिस्सा
- (३) अवरख क्षेत्र का औद्योगिक हिस्सा
- (४) सोन घाटी का औद्योगिक हिस्सा
- (५) तिरहुत में चीनी मिलों का औद्योगिक हिस्सा
- (६) उत्तरी तराइयों में स्थित चावल मिलों का औद्योगिक हिस्सा
- (७) दक्खिन गंगा के समीप स्थित औद्योगिक हिस्सा
- (८) मिले-जुले उद्योग-धधे

### दामोदर घाटी का औद्योगिक हिस्सा

यह बिहार का दूसरा महत्वपूर्ण औद्योगिक खड है। इस औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करनपुरा की कोयला खान से प्रान्त की पूरबी सीमा तक

है। यहा का मुख्य उद्योग खानो से कोयला निकालना है। कोयले की खानें विशेषत दामोदर घाटी के समीप में स्थित हैं और इसीलिए औद्योगिक कार्य भी नदी की दोनों ओर तक सीमित है।

कोयले की ऐसी प्रचुरता के कारण कितनी तरह के कारखाने स्थापित हो चुके हैं। धनवाद के समीप स्थित सिन्दरी की फ़ैक्ट्री तो भारत ही का नहीं, सारे एशिया के लिए महत्त्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र है। केन्द्रीय सरकार के अथक प्रयास से यह पिछले साल से खाद का उत्पादन कर रही है, फिर फिर भी अभी योजना अधूर्ण ही है। योजना पूरी होने पर 'सिन्द्री फर्टे-लाइजर' प्रतिदिन १,००० टन सल्फेट और अमोनिया (खाद) पैदा करेगा। इस रासायनिक उद्योग का कच्चा माल केवल कोयला, कोक और जिप्सम है। कोयला क्षेत्र में स्थित होने के कारण कोयला तो पर्याप्त मिल ही जायगा, हा, जिप्सम के लिए राजपूताना पर निर्भर करना पड़ता है। पूरी योजना के अनुसार २५०,००० टन कोयला, १७८,००० टन कोक और ५३६,००० टन जिप्सम की खपत प्रतिवर्ष होगी। बेरारी में भी (कोक) फ़ैक्टरी है जहा 'कोक' तथा उसकी उत्पत्ति, जैसे कोलतार, खाद अमोनियम सल्फेट इत्यादि तैयार होते हैं। फायर ब्रीक्स के भी कारखाने हैं। धनवाद के समीप वनसार फायर ब्रीक्स सबसे बड़ा कारखाना है।

इसके अतिरिक्त पलामू और रामगढ के बीच कितने पहाड़ हैं जिनमें से सिमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर काटकर कारखानों में भेजे जाते हैं। इन पत्थरों की प्राप्ति के कारण दो तरह के उद्योग कायम हो चुके हैं, पहला पत्थर काटने का और दूसरा सिमेंट बनाने का। इस उद्योग में 'सोन घाटी खड' सबसे आगे है। महत्त्व की दृष्टि से इस खड का दूसरा स्थान है।

रांची के मूरी नामक स्थान में अलमुनियम का कारखाना है। मूरी स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है और दामोदर औद्योगिक क्षेत्र कुछ दूर पड़ता है। फिर भी इस कारखाने में दामोदर घाटी के कोयले की खपत होती है। अलमुनियम "वाक्साइट" से बनता है। जिसका कोप लोहरदगा के पास बहुत बड़ा है। परन्तु इस उद्योग में जल विद्युत औद्योगिक शक्ति के लिए अधिक उत्तम है। आशा है, दामोदर से जलविद्युत मिलने पर इसके अन्य कारखाने भी खुलेंगे।

### अवरख का औद्योगिक क्षेत्र

उत्तरी हजारीबाग, पूरबी गया और मुंगेर के दक्खिन पश्चिम में अवरख क्षेत्र फैला है। इस क्षेत्र का प्रमुख केन्द्र कोडरमा है। इस क्षेत्र से प्रान्त के ९९७ प्रतिशत अवरख निकलता है। १९३७ ई० के आकड़े के अनुसार दुनिया के कुल अवरख का ९० प्रतिशत उमदा अवरख विहार की ही खानो से निकलता है। इन खानो में ३२ हजार आदमी काम करते हैं। इस हिस्से से औसतन १० हजार टन अवरख प्रतिवर्ष बाहर भेजा जाता है जिसका मूल्य लगभग २१० लाख रुपया होता है।

### सोनघाटी का औद्योगिक क्षेत्र

कोयल और सोन नदियों के सगम से डेहरी तक पश्चिमी सोनघाटी औद्योगिक दृष्टिकोण में विशेष महत्त्वपूर्ण है। इन औद्योगिक खड में सिमेंट, कागज और चीनी के कारखाने हैं। ये कारखाने डालमियानगर में हैं। सिमेंट के तीन चार और कारखाने हैं। जपला सिमेंट के कारखाने

के लिये विख्यात है। यहा ३५ हजार मजदूर काम करते हैं। सिमेंट चूना पत्थर से बनता है जो कौमूर की उमत्काम में प्रचुर परिमाण में मिलता है। जपला के कारखाने में चूना पत्थर "बौलिया कीक्वेटिया" से आता है जहा एक हजार मजदूर काम करते हैं। डेहरी के कागज के कारखाने के लिये मध्यभारत, मिर्जापुर और छोटानागपुर से वास आते हैं। चीनी के कारखाने के लिये स्थानीय ईख ही काफी हो जाती है। डेहरी के आस-पासवाले इलाको में सिचाई का अच्छा प्रवन्ध है। अतएव ईख की फसल अच्छी होती है। फलत उसे दूर से ईख मगाने की आवश्यकता नहीं पडती। कच्चा माल मगाने और तैयार माल को बाहर भेजने के लिए यहा यातायात की काफी सुविधा है। ग्रेड कार्ड लाइन द्वारा यह गंगा के समृद्ध जिलो में अपना माल भेजता है तथा पूरव में कलकत्ता और पश्चिम में दिल्ली से अपना सम्बन्ध स्थापित करता है। इन्ही साधनो के कारण डेहरी का छोटा गाव आज बिहार के औद्योगिक शहरो में एक है।

### दक्खिन-पूरव का औद्योगिक हिस्सा

इस हिस्से में सिंहभूम और मानभूम के पूरे दक्खिनी भाग पडते हैं। यहा कुछ खनिज पदार्थ, जैसे लोहा, तावा, मंगनीज, चूना, पत्थर आदि प्रयाप्त परिमाण में मिलते हैं। जमशेदपुर में लोहा कारखाना और घाट-शिला के तावे का कारखाना विहार में ही नहीं सारे भारत में अद्वितीय है। टाटा आयरन एन्ड स्टील इन्डस्ट्रीज की स्थापना से १९१२ में भारतीय उद्योग में एक नया अध्याय प्रारम्भ हुआ। कच्चे लोहा और इस्पात का उत्पादन उत्तरोत्तर बढ़ता गया। युद्ध के समय तो इसके उत्पादन में और भी अधिक वृद्धि हो गयी थी। १९४१ में ८३९०० टन इस्पात तैयार हुआ था, १९४३-४४ तथा १९४६-४७ के औसत आकड़े के अनुसार इस्पात का उत्पादन क्रमश ८,३१,००० टन और ७४९,००० टन था। इस समय इसका उत्पादन ८ लाख टन के लगभग हो गया है। १९३९ ई० के आकड़े के अनुसार टाटा ने १० लाख टन कच्चा लाह (पिग आयरन) तैयार किया था। उस समय इस्पात का उत्पादन आकड़ा ७७७००० टन मात्र था।

इतना होने पर भी, 'टाटा आयरन एन्ड स्टील कम्पनी' का इस्पात पूरे देश की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाता है। कई और लोहे के कारखाने स्थापित करने की योजनाएँ बनायी जा रही हैं। इन क्षेत्र में उसकी स्थापना करना भौगोलिक एवं अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से श्रेयस्कर है। यदि यह स्थापित हो जाता है, तो भारत को विदेश से इस्पात मगाने की आवश्यकता नहीं पडेगी।

जमशेदपुर के लोहे के कारखाने के आसपास कितने सहायक उद्योग-धंधे कायम हो गए हैं जिनमें टाटा इन्जीनियरिंग एन्ड लोकोमोटिव कम्पनी (टेलको), अग्रीको, टीन प्लेट कम्पनी, नेशनल केवुल कम्पनी इत्यादि विशेष विख्यात हैं। टेलको बोआलर, रोड रोलर इत्यादि तैयार करता है। इजिन भी बनना प्रारम्भ हुआ है। 'एग्रीको' छुपि सम्बन्धी औजार, कुदाल, कुल्हाड़ी, हथौडा, खती, खुर्पी, हल के फाल इत्यादि तैयार करता है। व्हा प्रति माह लगभग ३७,४,००० वस्तुएँ बनती हैं जिनमें कुदाल और कुल्हाड़ी की मख्या क्रमश ५०,००० और १०,००० है। इन उद्योग में विस्तार की बहुत सम्भावनाएँ हैं।



घाटशिला के पास स्वर्णरेखा नदी के दाहिने किनारे पर स्थित ऊ भडार में ताबा गलाने का काम 'घाटशिला कापर कारपोरेशन' नामक १९७७ ने में होता है। असस्कृत ताबा मोसाबनी और घोबनी से 'रोपवे' १२ कारखाने में लाया जाता है। कई प्रणालियों से साफ करने के बाद १९६८ प्रतिशत ताबा बनाया जाता है जिसे "आई० सी० सी० (वेस्ट सलेक्टड कापर) कहते हैं।

यह ताबा पीतल बनाने के लिए मिश्र धातु के ऐसा उपयोग किया जाता है। ६० प्रतिशत ताबा को ४० प्रतिशत जस्ते के इस धातु पिंड को रौलिंग मिल में डालकर तरह-तरह की आकृति का 'सीट' तैयार किया जाता है जिसका उपयोग बर्तन या अन्य वस्तुएं बनाने के काम में किया जाता है। रेडियो तार केबुल इत्यादि में उपयोग करने लायक उच्चकोटि का ताबा अभी तक बिहार में क्या सारे भारत में अप्राप्त है। आशा है, ताबे की ऐसी खान का पता चलेगा। बिहार की सबसे बड़ी सीमेंट फ़ैक्ट्री झीनकापानी इसी भूखड में पढती है जहा सिंहभूम के चूना पत्थर की खपत होती है।

### तिरहुत की चीनी मिलें

गंगा के उत्तर में राज्य की पश्चिमी सीमा से लेकर पूरव में कोशी नदी तक के इलाको में बिहार की अधिकांश चीनी मिलें स्थित हैं। हाल के आकड़े के अनुसार, बिहार के ३४ में से २६ कारखाने तो इसी हिस्से में पडते हैं। मजदूरो और माल उत्पादन के भी आँकड़े कुछ ऐसे ही हैं। १९४१ के आकड़े के अनुसार बिहार में कुछ मजदूरो को जो चीनी मिलो में काम करते थे, ८७ प्रतिशत मजदूर यही काम करते हैं। इस हिस्से का चीनी उत्पादन औसतन १९३६-४१ प्रान्तीय उत्पादन का ७८ प्रतिशत होता है।

### चावल की मिलें

बिहार के उत्तरी छोर पर केवल चावल के उद्योग-धधे होते हैं। यह खड पश्चिम में सोमेश्वर और गडक से लेकर पूरव में पूर्णिया के फारविमगज के बीच तक पडता है। इस खड की चौडाई कही भी २५ मील से अधिक नहीं है। इसी हिस्से में बिहार की ६२ प्रतिशत चावल मिलें हैं। मजदूरो का अनुपात ६७ प्रतिशत है। चावल मिलो के केन्द्रीकरण का एकमात्र कारण चीनी के उद्योग की तरह, कच्चे माल की प्रचुरता है। दूनरी बात यह है कि नेपाल में भी धान खूब होता है, परन्तु वहा मिले

खुलने की सुविधा न होने के कारण वहा का सारा धान पहाड की इस तराई में लाया जाता है। इसी कारण से पहाड की तराइयो में एक किनारे से दूसरे किनारे तक बहुत सी मिलें खुल गयी हैं।

### दक्षिणी गंगा का हिस्सा

दक्खिनी गंगा का वह ऊँचा समतल स्थान जहा बाढ का प्रकोप कम होता है, बिहार के इतिहास में हमेशा महत्त्वपूर्ण रहा है। पहले जब नदिया ही आवागमन का एकमात्र साधन थी, गंगा के किनारे स्वभावत बहुत से व्यापारिक केन्द्र कायम हो गए थे। आजकल उन प्राचीन केन्द्रो का और भी विकास हो गया है तथा कितनी तरह के उद्योग-धधे वहा कायम हो गए हैं जिनसे स्थानीय आवश्यकताओ की पूर्ति होती रहती है। ऐसे शहरो में बक्सर, पटना, दानापुर, फुलवारी शरीफ, जमालपुर, मुंगेर, भागलपुर तथा साहबगज का नाम उल्लेखनीय है जहा कुछ-न-कुछ उद्योग-धधे होते हैं। भागलपुर में रेशमी कपडे की मिलें हैं, मुंगेर में सिगरेट बनती है और जमालपुर में लोहे तथा रेलवे का कारखाना होता है। फुलवारी शरीफ में कपडा बुनने की एक मिल है। कपडे की मिल तो बिहार में केवल गया में ही है जो पटना से ५७ मील की दूरी पर है।

### मिलेजुले उद्योग

मिले जुले उद्योग-धधो में उनका नाम आता है जो इधर-उधर फैले हैं। जैसे जूट-लाह इत्यादि का उद्योग-धधा, जिनका उल्लेख विस्तार में पहले हो चुका है। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे भी उद्योग-धधे हैं जो छोटे पैमाने पर गृह उद्योग-धधे के रूप में चल रहे हैं, जैसे सूती-रेशमी-ऊनी कपडे बुनना, चमडे का काम, लकडी का काम।

बिहार के औद्योगिक साधनो एव उनके वर्गीकरण के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि जितना विकास इनका होना चाहिये था उतना अभी नहीं हो सका है। कहा जा सकता है कि बिहार का औद्योगिक विकास अभी शंशवावस्था में है। नीचे दी हुई तालिका (१९५१) से स्पष्ट है कि यहा के मजदूरो, कारखानो इत्यादि की संख्या अन्य प्रगतिशील प्रान्तो की अपेक्षा कम है —\*

फिर भी बिहार का भविष्य, औद्योगिक दृष्टिकोण से उज्ज्वल है। औद्योगिक योजनाओ के अनुसार निकट भविष्य में ही यहा लोहा, जूट, और कपडे के कारखाने खुलेंगे। यह निश्चित है कि जल विद्युत शक्ति की योजनाओ के कार्यान्वित होने से बिहार का महत्त्वपूर्ण औद्योगिक विकास होगा।

*प्रान्त	कुल कारखाने	कुल मजदूर	कुल मजदूरी	कुल पू जी
पश्चिमी बंगाल	१,२१८	४,७५,११५	२०,८३,०१,४९०	१०३,८७,३३,९५५ रु०
बम्बई	९५९	४,६८,११४	३७,८७,५३,७६२	१,२४,४१,७२,२५१ रु०
मद्रास	१२४४	१,३५,२६६	६,५४,७१,५६८	३५,३२,३७,७७४ रु०
उत्तर प्रदेश	५५९	१४४,१८८	७,२२,६०,८३५	४६,२२,२९,७४८ रु०
गिजर	३१६	७८,२९९	४,७१,५४,९७८	३६,०८,७४,४७० रु०



साहित्य का आदि-स्रोत है मौखिक लोक-वार्ता, जिसके अन्तर्गत लोकोक्ति, लोककथाएँ, लोकगीत, लोकविश्वास, पहेलियाँ और जत्र-मंत्रादि बहुमुखी सामग्री आ जाती है। गोर्की के कथनानुसार जनता ही आदि कवि है और वही आदि दार्शनिक। जन्मभूमि और राष्ट्रीय भावना के गीत प्रत्येक देश के लोक-साहित्य में मिलते हैं। वैसे यह ठीक है कि देश-देश के लोक-साहित्य मानव भावनाओं में समानता का परिचायक है, लेकिन साथ ही यह भी ठीक है कि एक देश का लोक-साहित्य दूसरे देश के लोक-साहित्य से, जलवायु के समान ही, भिन्न होता है। प्रत्येक देश के लोक-साहित्य पर जहाँ उस देश के रीति-रिवाजों की छाप रहती है, वहाँ अपने वीरों के शौर्य के प्रति भी हम लोक भावना को नतमस्तक होते देखते हैं।

भारतीय लोकगीतों में धरती माता की वन्दना के स्वर विशिष्ट स्थान रखते हैं। वुन्देखडी लोकगीतों का एक विशेष उपभेद है "सौरा" जिसे प्रायः किसान खेत में काम करते समय गाते हैं। ध्यान से देखने से सौरा दोहे या सोरठे की जाति का अनगूँ सा छन्द प्रतीत होता है। इसकी एक विशेषता यह है कि इसमें तुकान्त का ध्यान नहीं रखा जाता। "सौरा" की भावभूमि पर प्रकृति तथा मानव जीवन के अनेक छवि-चित्र मूर्त्तिमान होते दृष्टिगोचर होते हैं, एक स्थल पर धरती माता को सम्बोधन करते हुए किसान कहता है

धरती माता तँने काजर दये,  
सँदरन भर लई माग।  
पहर हरिअला ठाडी भई,  
तँने मोह लयो जगत ससार।<sup>१</sup>

सबको जन्म देनेवाली धरती माता के प्रति किसान की यह भावना भारत की अनेक भाषाओं के लोकगीतों में कलापूर्ण और कवित्वमय रूप में अंकित हुई है। धरती के गीत प्रेम और प्रेरणा के प्रतीक हैं। इस भावभूमि पर स्वप्न और आदर्श, आशा और आकांक्षा फिरकती हैं। धरती माता की वन्दना ही राष्ट्रीय भावना की पूर्वजा है, यह भावना भारतीय लोकगीतों को वेदकालीन पृथ्वी सूक्त से जा मिलाती है।

१ हे धरती माता, तुमने आँखों में काजल लगा लिया और सिन्दूर से माग भर ली। हरे वस्त्र पहनकर तुम खडी हुई तो तुमने सारे ससार को मोह लिया।

शत-शत शताब्दियों की स्मृतियाँ लोकगीतों में स्वर भरती हैं। रत्नगर्भा जन्मभूमि की रक्षा का भार पृथ्वी-पुत्रों पर ही आता है क्योंकि जन्मभूमि की मान-मर्यादा को ही वे अपनी मान-मर्यादा मान कर चलते हैं। समय-समय पर ऐतिहासिक कथाएँ भी लोक-साहित्य में स्थान पाती हैं, जन्मभूमि की रक्षा करनेवाले वीरों की दन्त-कथाओं के समान ही ऐतिहासिक कथाएँ भी लोक-मानस की राष्ट्रीय भावना को पुष्ट करती हैं। इन सभी कथाओं में अलौकिकत्व अथवा अतिशयोक्ति का अंश भी रहता है। 'सोने का हल और चादी का जुआ' की कल्पना धरती माता के सम्मान की प्रतीक है। एक उडिया लोकगीत में किसान गाता है -

सोनार हल कुरे रुपार जुआली  
हीरा माणिकर वलद  
हलीया वनमाली हे ।<sup>१</sup>

मथुरा से तीन मील की दूरी पर है महीली गाव। महीली खंडे के अपने विशिष्ट गीत में धरती माता की वन्दना इस प्रकार की गयी है

धरती माता ने हरयो करयो  
गऊ के जाये ने हरयो करयो  
महीली खंडे ने हरयो करो  
गगा माई ने हरयो करयो  
जमना रानी ने हरयो करयो  
धना भगत को हर ते हेत  
विना बीज उपजायो खेत  
घर भर आगन भरयो

फसल को माडते समय वँलो के चक्कर को गढवाल में 'दाई का फेरा' कहते हैं। इमीने ऋतु बदलने की उपमा लेकर जन-कवि देशवासियों को वसुधा की सौन्दर्य-श्री का ध्यान दिलाता है, जब वसन्त का आगमन होता है —

आई गँन ऋतु बीडी, दाई जँयो फेरो, झुर्मलो।  
उचा देसी उचा जाछा, ऊदा देमी ऊदा, झुर्मलो।<sup>२</sup>

१ सोने का हल है चादी का जुआ हीरो और मणियों के हैं वँल। और हलवाहा है स्वयं वनमाली (कृष्ण)।

२ ऋतु लौट कर आ गयी, फसल माडते समय वँलो के चक्कर के समान झुर्मलो। ऊपर के लोग ऊपर चले जायेंगे, नीचे देश के लोग नीचे चले जायेंगे—झुर्मलो।

झुमैलो नृत्य का यह गठवाली गीत ऋतु परिवर्तन का एक सुन्दर प्रतीक प्रस्तुत करता है। 'गाव' की सीमित भावना यहाँ ऊँचे देश और नीचे देश का अन्तर दर्शाती है।

एक राजस्थानी दोहे में ग्रीष्म ऋतु का चित्रण देखिए —

कह लूवा कित जावस्यो पावस घर पडियाह ।  
हिये नवोला नारा रा वालम पीछडियाह ॥<sup>१</sup>

ऋतु-परिवर्तन का अनुभव गायक को जन्म-भूमि के और भी समीप ले आता है। लुप्तो के साथ मानव का कथोपकथन लोक काव्य की प्रिय वस्तु है। वुन्देलखड के एक "सौरा" में राम, लक्ष्मण और सीता को कृषि कार्य में सलग्न दिखाया गया है

राम ववें तो लछमन जोतियो,  
सीता माता कादें काद,  
लछमन दिउरा लौट के हेरिओ,  
मेरी वारी दो-दो कान।<sup>२</sup>

वुन्देलखडी 'सारा' में लक्ष्मण और सीता के प्रश्नोत्तर बार-बार गाये जाते हैं

सीता—काहे को वाघे लछमन धनइया, काहे को पाचो वान ?  
मिरगा वारी ऐसे चुने, जैसे अनाथ की खेत ।

लक्ष्मण—काहे को निरखो भोजी धनइया, काहे को पाचई वान ?  
परा मिरगला मारन चलू, मोए दशरथ की आन।<sup>३</sup>

कृषि प्रधान भारत की जनता द्वारा अपने आदर्श नायको राम, सीता, लक्ष्मण को कृषि कार्य में सलग्न दिखाने की कल्पना महत्त्वपूर्ण है। इस वर्णन में कोई अतिशयोक्ति नहीं। इस प्रकार के गीत जनता की कृषि में निष्ठा के प्रतीक हैं। इनके गान द्वारा उनका आत्म विश्वास वृद्ध होता है।

उत्तर प्रदेश में घाघ की सूक्तिया प्रसिद्ध हैं। एक स्थल पर घाघ ने सुखी परिवार का चित्रण करते हुए धरती पर बँकुठ को उतार लाने की कल्पना प्रस्तुत की है

१ कहो, हे लूपो, तुम यहाँ जाओगी, जब धरती पर पावस ऋतु आ जायगी ? हम उस नवविवाहिता नारी के हिय में जाकर रहेगी जिसका वामन प्रिच्छुट गया हो।

२ राम बीज बो रहे हैं, लक्ष्मण हल चला रहे हैं, सीता माता निराई कर रही हैं। हे लक्ष्मण देवर, लौट कर देखो, मेरे खेत में दो-दो अकुर निकल आये हैं ।

३ नीला कहती है—काहे को धनुष बाधा है, लक्ष्मण, काहे को हें पातो वान। मृग खेत में गेने चरने हैं जैसे यह अनाथ का खेत हो। लक्ष्मण काग देगा ?—काहे तो धनुष को निरग्वती है भावज ? काहे को पाचो वान को गोर देनी ले ? परतो में मृग मारने चलूंगा। मुझे दशरथ की आन है ।

भुइया बंडे हर हवै चार, घर होई गिहियन गऊ दुधार,  
अरहरक दाल जडहनक भात, गारल निवुआ और धिव भात ।  
सहर सखण्ड दही जौ होइ, बाके नैन परोसे जोई  
कहें घाघ तब सब ही झूठा, उहो छोडि हूहवें बँकुठ।<sup>१</sup>

जहाँ कृषि के साधन बहुत सीमित हैं, वहाँ किसान को अनथक परिश्रम की धुन लगी रहती है। जैसे वह स्वयं प्रकृति से यह पाठ पढ़ चुका हो कि नवान्त के लिये भरसक प्रयत्न करे।

राजस्थानी किसान की बड़ी-बड़ी आवश्यकताएँ क्या-क्या हैं। यह वह स्वयं बताता है

नई मूजरी खाट न चवै टापरी,  
मैंसडल्या दो चार क दूझे बाखरी ।  
वाजर इन्दा रोट दही में ओलणा,  
इतरा दे करतार फेर नही बोलणा ॥<sup>२</sup>

एक प्रार्थना गीत में राजस्थानी किसान इसी भाव को और भी स्पष्ट करते हुए कहता है

म्हारा राम रघुनाथ ।  
इतना वर तो म्हाने दीज्यो,  
नित उठ जोड़ू हाथ ।  
आथुणो तो खेत दीज्यो,  
बिच में दीज्यो नाडी,  
घरवाली ने छोरो दीज्यो  
भैंस त्यावे पाडी ।  
दोय तो म्हाने छाली दीज्यो  
दोय दीज्यो लरडी,  
काली भूरी दो नू दीज्यो  
एक वणाला बरडी ।  
म्हारा राम रघुनाथ  
इतना वर तो म्हाने दीज्यो  
नित उठ जोड़ू हाथ ।  
एक तो म्हाने हलियो दीज्यो,  
हाल दीज्यो ठाडी,  
दोय तो म्हाने बँला दीज्यो,  
बिच में दीज्यो गाडी ।

१ ग्राम के समीप ही खेत हो। चार हल हो। घर में कार्य-निपुण पत्नी हो दूध देनेवाली गाय हो। खाने को अरहर की दाल और जडहन का भात हो। उसमें डालने को घी तथा निचोडने को नीवू हो। खाड और दही हो। भोजन परोसनेवाली बाके नेत्रोवाली पत्नी हो। घाघ कहते हैं, यदि ये सब बातें हो तो यही बँकुठ है ।

२ नई मूजरी खाट हो, क्षोपडी टपकती न रहे, दो-चार भैंसें हो, दूसरे उनके लिए कोठा हो, वाजरे का रोट दही में डूबो कर खाने के लिए हो। बम करता ! इतना दे दो तो फिर मुह से कुछ नहीं बोलना ।

वाजरी री रोटी दीज्यो  
उपर सक्कर घी,  
दोय तो उपरा ते दीज्यो  
घणू पडैली सी,  
म्हारा राम रघुनाथ  
इतना वर तो म्हाने दीज्यो,  
नित उठ जोडू हाथ ।<sup>१</sup>

इस प्रकार किसान अपनी मोटी-मोटी आवश्यकताओं का बखान करता है ।

पर शायद किसान को यह समझते देर नहीं लगती कि केवल प्रार्थना से काम नहीं चल सकता । उसे अपने परिश्रम पर भरोसा करना पड़ता है । जब परिश्रम फल देता है और घर में किसी वस्तु का अभाव नहीं रह जाता तो उसके कठ से आनन्द और उल्लास का गान मुखरित हो उठता है । जिसमें किसान अपने भगवान पर व्यग्य कसने से भी नहीं चूकता

वनवारी हो लाल, कोन्या थारे सारे ।  
गिरवारी हो लाल, कोन्या थारे सारे ।  
ऐ महल-मालिया थारे  
थारी वरावरी म्हें करा  
स कोई टूटा टापरी म्हारे ।<sup>२</sup>

आगे चलकर इस गीत में राजस्थानी किसान कहता है—तुम्हारे यहा कामधेनु है, हमारी भी भैंसें हैं । तुम्हारे यहा हाथी-धोडे हैं, हमारे भी ऊट हैं और ऊटनिया हैं । तुम्हारे पास भाला-वरछी है, हमारे पास जई-गडासी । तुम्हारे पास सागर है, हमारी भी तलैया है । तुम्हारे पास तीसक तकिए हैं, हमारी फटी गुदडी ही अच्छी है हमारे लिए । तुम्हारे पास रानी है, हमारी भी तो जाटनी है ।

आदिवासियों के सामाजिक उल्लास और सामूहिक श्रम के गीत भी सामाजिक सत्य की पताका फहराते रहे हैं । शिशु के जन्म पर गाये जानेवाले गीत जाति और वंश की वृद्धि का जयगान करते थे तो नई फसल की खुशी में गाये जानेवाले गीतों का लक्ष्य था श्रम को मधुर बनाना और अनाज से भरी हुई कोठियों की कल्पना प्रस्तुत करते हुए जाति के सुख-समृद्धिपूर्ण भविष्य का रजित चित्र प्रस्तुत करना ।

१. ओ हमारे राम रघुनाथ, मुझे इतना वर देना मैं नित आख खुलते ही हाथ जोडता हूँ पश्चिम में खेत देना, खेत के बीच तलैया हो । घरवाली को छोरा देना, भैंस भी पडिया लाये, दो भेड, काली और भूरी, जिनकी ऊन मे 'वरडी' बुनी जायगी । ओ हमारे राम रघुनाथ, मुझे इतना वर देना मैं नित आख खुलते ही हाथ जोडता हूँ । एक हल देना जिसके साथ मोटी फाल लगी रहे । दो बैल देना जिनके बीच गाडी चल रही हो । वाजरे की रोटी देना जिस पर शक्कर और घी हो । ओढने को देना दो गुदडे खूब जाडा पडेगा ।

२. हे वनवारी, हममें से कोई तुम्हारे आसरे नहीं । हे गिरवारी हममें से कोई तुम्हारे आसरे नहीं । तुम्हारे महल अटारिया हैं, तुम्हारी वरावरी भी करता हूँ, हमारे यहा भी टूटी धोपडी है ।

प्रायः यह समझा जाता है कि आदिम समाज में वैयक्तिक आचारों को तनिक भी प्रमुखता नहीं मिलती और सर्वत्र सामूहिक दृष्टिकोण ही छाया रहता है । पर आदिम जातियों की मौखिक कविता के अध्ययन द्वारा हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि समाज की ईकाई के रूप में व्यक्ति की आवाज कही भी दबती नहीं ।

छोटानागपुर के एक मुण्डा गीत में खेत का चित्र किसी प्रेमी का हृदय-स्पन्दन लेकर आगे बढ़ता है —

बुरु रे दोराडी बेंडा रे गगई  
सागोती, नीदा सिंगी हलाहला आन ।  
सिंगी दो चेंणें नीदा दो कुलाय,  
सागोती, नीदा सिंगी हलाहला आन ।<sup>१</sup>

छोटानागपुर के उरावो में "युवती का गीत" बड़ा ही लोकप्रिय है । ऐसा लगता है यह युवती अपनी मा को नहीं बल्कि बरती माता को पुकार रही है —

सन्नी मने एहें अयगो  
अथाह मेखा नू उडियार आ लगी,  
उडियार आ लगी खत्तरआ हा मलखत्तरई,  
मुन्दा इजआ के के अड्डा बेंडा हो पोल्ली ।  
मन एग है अक्कुन सन्नीम रई, बोलीन रई,  
अक्कुन अन्नु नीदी ताकादिम निदकी रई,  
अरगी अडसा अक्कुन घेंडा परिया आदिची,  
एका तरा अरओय, अजमोम दिया रई ।  
निग अचरन ची अयग, आद बरच की दिन रई,  
मलतो वीडी विल्ली नू इजआ हा पोल्लो,  
एकअम वरन्डो वोगतआ हो टकओ,  
भोखारो बदाली माडा हो टकओ,  
ची अयम अचरन ।<sup>२</sup>

गोडों के एक करमा गीत में जहा प्रेमी अपने चोले का रुदन प्रस्तुत करता है, वहा अपनी बरती का चित्र भी प्रस्तुत करता है

१. पहाड पर है अरहर, तराई पर गगई । हे मखी ! दिन-रात तुम हला-हला किया करती हो । दिन में पक्षी, रात में खरगोन है हे मत्ती, दिन रात तुम हला-हला किया करती हो ।

२. छोटा सा मन मेरा ओ मा, अथाह गगन में विचर रहा है । विचर रहा है—गिर नहीं रहा । अभी उममें सिर्फ हवा ही भरती है । मन मेरा अभी तो छोटा सा है । नन्हा-न्हा । अभी उमका जीवनकाल भी नहीं आया । जिस ओर भी फूका जाय उस ओर ही उठता फिरता है । अपना आचल दे दो, मा उसे थामे रहेगा मेरा मन नहीं तो मूर्य की प्रचण्ड किरणों में वह खडा नहीं रह सकेगा और कोई आधी उने उडा न ले जाय, काले मेघ उसे ढक न ले, अपना आचल दे दो, मा ।

चोला रोवत है राम, बिन देखे परान ।  
 दादर झावर झोडी दूढीं डोगरे बीच मझाय,  
 वं पतेरन तोला दूढीं कहा लुकै है जाय  
 चोला रोवत है राम, बिन देखे परान ।  
 माया ला तें कसके ठोरे, सुरता मोर भुलाई,  
 मोर मडइया सूनी करके, कहा करे पहुनाई,  
 चोला रोवत है राम, बिन देखे परान ।  
 इन नैनो में नीदन आये, हिरदा होइगे सूना,  
 डोगरे डहरी तोला दूढीं विपता बढगं दूना,  
 चोला रोवत है राम, बिन देखे परान ।<sup>१</sup>

१ चोला रो रहा है राम, प्रियतम को देखे बिना । डोगर पहाड के बीच बार-बार चक्कर लगा चुकी, मैं तुझे दादर (पहाडी उच्चतम-भूमि), झावर (कुज), और झोडी (नालो के किनारे) दूढ आई । मैंने सभी पतेरो (झाडियो) में तुझे दूढ लिया, तू कहा छिपा है ? चोला रो रहा है हे राम, प्रियतम को देखे बिना । तुमने मेरी माया कैसे तोड दी ? मेरी सुरत तूने कैसे भुलाई ? मेरी मडैया सूनी करके तुम किसके घर में मेहमान बने बैठे हो ? चोला रो रहा है हे राम, प्रियतम को देखे बिना । इन नयनो में नीद नहीं आती, हृदय सूना हो गया, पहाड-गली में तुम्हे दूढा, मेरी विपता दूनी हो गई । चोला रो रहा है, राम, प्रियतम को देखे बिना ।

एक और गोड गीत में यह दिखाया गया है कि जीवन की समस्यां विकट हो रही हैं । किसी स्त्री का पति अपने बैल लेकर ऊँचे पहाड को पार करके व्यापार के लिए चला जाता है । स्त्री का हृदय आशकित हो उठता है कि शायद यह घरती का लाल गाव के लौटकर न आये ।

बैला चलिन राई घाट करौंदा बैला छोटे-छोटे रे ।  
 डोगरे में आगि लगे जरथे पतेरा,  
 सुन-सुन के हीरा मोर जरथं करेजा,  
 बैला चलिन राई घाट करौंदा बैला छोटे-छोटे रे ॥<sup>१</sup>

घरती का लाल, अपने जीवन संघर्ष की गाथा अपने पीढी-दर-पीढी चले आनेवाले गीतो में बड़े मजे से सुनाता है । और जब भी वह कोई पुराना गीत छेडता है, इस नये युग का सम्पर्क प्राप्त हुए बिना नहीं रहता । यही लोकगीत की शक्ति का रहस्य है ।

१ बैल राई घाट की ओर चल पड़े—करौंदे के रग के ये छोटे-छोटे बैल । पहाड पर आगि लगी है, पत्ते जल रहे हैं । और मेरे हीरे के से प्रियतम, मेरा कलेजा जल रहा है । बैल राईघाट की ओर चल पड़े— करौंदे के रग के ये छोटे-छोटे बैल ।



# कृषि की उत्पत्ति और वैदिक युग में भूमि-व्यवस्था

श्री प्रमथनाथ गुप्त

हम जिसे वैदिक युग कहते हैं, वह कई सौ वर्षों तक फैला हुआ युग है। इस बात को न समझने के कारण वैदिक युग का उल्लेख करते समय कई बार बहुत भारी गलतियां हो जाती हैं। ऋग्वैदिक साहित्य में जिस युग की बातें वर्णित हैं, वह ८०० से १००० वर्ष तक वर्तमान या ऐसा अनुमान किया गया है।

स्वाभाविक रूप से वैदिक साहित्य में इसी युग का उल्लेख है पर इस साहित्य में यत्र-तत्र प्राग्वैदिक युग के भी उल्लेख आ जाते हैं। वैदिक आर्य तो खेती में प्रवीण हो चुका था, पर प्राग्वैदिक युग-सम्बन्धी उल्लेखों में यह ज्ञात होता है कि ऐसा युग इसके पहले मौजूद रहा होगा, जब खेती की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यहाँ यह भी बताया जाय कि जैसे आम तौर से यह समझा जाता है कि खेती के युग के पहले पशुपालन का युग रहा, यह सब विद्वानों को मान्य नहीं है। इस विषय में 'ऐतिहासिक भौतिकवाद' के ये वाक्य विशेष उल्लेखनीय हैं।

अभी तक इस विषय में मतभेद है कि पशुपालन का युग पहले था या कृषि का युग। अधिकांश विद्वानों का मत यह है कि कृषि सर्वत्र पशुपालन से प्राचीनतर है, किन्तु जर्मन इतिहास लेखकों का यह विचार है कि इन दोनों में पूर्वोत्तर सम्बन्ध स्थापित करना गलत होगा, क्योंकि जब एक जगह केवल पशुपालन ही हो रहा था, तो दूसरी जगह केवल कृषि हो रही थी। वी० गार्डन चाइल्ड ने लिखा है कि अब कोई विद्वान इस विषय पर जिद नहीं करता कि सार्वदेशिक रूप से पशुपालन का युग कृषि के पहले था क्योंकि आज भी बहुत से ऐसे कृषक कबीले हैं, जिनमें कोई पालतू जानवर नहीं है। मध्य यूरोप और पश्चिमी चीन में जहाँ दोनों घबे सैकड़ों वर्ष से निश्चित रूप से चल रहे थे, वहाँ के विषय में भी जब पुरातात्विक फावरे से पूछा गया, तो उसने बतलाया कि किसनई का घवा पुराना है, लोग पालतू जानवरों पर किसी प्रकार का भरोसा नहीं करते थे, खेती की ही उपज से काम चलाते थे, और शायद थोड़ा बहुत शिकार भी करते थे। (ऐतिहासिक भौतिकवाद पृ० २०४-२०५)

हमें यहाँ पर इस विवाद में पडने की कोई आवश्यकता नहीं है कि प्राग्वैदिक युग में कृषि पहले आई या पशुपालन। सच तो यह है कि इन प्रश्नों के निर्णय के लिए जितना मसाला होना चाहिये, उतना मसाला नहीं है। श्री जयचन्द्र विद्यालकार ने अपनी पुस्तक 'भारतीय इतिहास की रूप-

रेखा में' वैदिक युग के समाज की बुनियादों का वर्णन करते हुए भूमिका के रूप में जो बातें लिख दी हैं, वे निर्विवाद नहीं हैं।

उन्होंने लिखा है, और ऐसा शायद उन्होंने प्राग्वैदिक युग के सम्बन्ध में अनुमान भिडाते हुए लिखा है—“आरम्भिक मनुष्य का गुजारा शिकार से या फल-मूल वीन कर होता था। उसके बाद पशुपालन का जमाना आता है, और फिर धीरे-धीरे मनुष्य खेती करने लगता है। पशुपालन के युग में जगम और फिर कृषि के युग में स्थावर सम्पत्ति का उदय होता है, और स्थावर सम्पत्ति होने से समाज में स्थिरता आती है। शिकारियों की टोलियाँ या पशुपालकों के गिरोह कियी एक जगह टिक कर नहीं रहता कृषक समाज स्वभावतः एक निश्चित प्रदेश में टिक जाता है। समाज के इस प्रकार स्थिर या अवस्थित होने पर ही राज्य का उदय होता है, और फिर सम्यता का विशेष विकास।”

विद्यालकारजी के इस वक्तव्य में जिस निश्चयता के साथ यह कहा गया है कि पशुपालन के युग के बाद खेती का युग आया, हम दिखला चुके कि यह कम आवश्यक नहीं है, और ऐसा कोई चिरन्तन नियम नहीं है। वाद को चलकर विद्यालकारजी ने स्वयं ही कहा है, 'वैदिक आर्यों का समाज पशुपालकों और कृषकों का था, वल्कि प्राग्वैदिक युग में, इक्ष्वाकु और पुरुखा के समय में भी वे पशुपालक और कृषक ही थे, केवल शिकार पर जीने के युग को पीछे छोड़ चुके थे, तो भी उम युग की याद अभी ताजी थी, जब लोग अनवस्थित-अवस्थित विश थें अर्थात् जब आर्य लोग केवल पशुपालक थे, और कृषक जीवन उन्होंने अपनाया न था।”

प्राग्वैदिक युग में आर्यों का कृषक और साथ ही पशुपालक होना विद्यालकारजी मानते हैं, फिर भी वे महज अनुमान के बूते पर यह कहते हैं कि इसके पहले वे केवल पशुपालकरहे होंगे, और उन्हें खेती न आती होगी। उम अनुमान के लिये उन्होंने किसी उल्लेख का हवाला नहीं दिया। यदि कल्पित चिरन्तन नियम के बूते पर उन्होंने यह वाक्य कहे हैं, तो इस सम्बन्ध में यह बात देना जरूरी है कि खेती के साथ-ही माय मनुष्य अवस्थित हो गये, और स्थायी वस्तियों में बस गये, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इतिहास में इनके कई अपवाद हैं। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं कि खेती की उत्पत्ति होने पर भी लोग बुद्ध बने रहे। चाइल्ड ने यह दिखलाया है कि गत शताब्दी में कनाडा के प्रशान्त महा और के उपकुलों की कुछ

शिकारी तथा मछली मार कर जीनेवाली जातियों के सम्बन्ध में यह ज्ञात हुआ है कि यद्यपि यह लोग खेती नहीं करते थे, फिर भी इनके स्थायी सुन्दर लकड़ी के मकानों के गाव वसे हुए थे। इसी प्रकार बर्फ युग में फ्राम के मंगडेलैनियगण कई पुस्त तक एक ही गुफा में रहते थे, इसमें सन्देह नहीं। दूसरी तरफ खेती के कुछ तरीके ऐसे हैं, जिन्हें काम में लानेवाले को डधर-उधर भटकते रहना पड़ता है। १९३६ तक एशिया, अफ्रीका, विशेष कर दक्षिण अफ्रीका के कुछ किसानों लिये खेती का अर्थ यह था कि जगल के एक टुकड़े को या कुछ झाड़ियों को साफ कर लिया, फिर उसे डडानुमा चीज से चला दिया, फिर उसमें बीज बिखरा दिया, और जब फसल तैयार हो गई तो उसे काट लिया। वे इस जमीन को न तो कभी परती छोड़ते हैं, और न उसमें किसी प्रकार की खाद डालते हैं। अगली फसल के समय फिर उसमें बीज डाले जाते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसी अवस्था में दो-एक बोआई और कटाई के बाद जमीन की उत्पादक-शक्ति विलुप्त हो जाती है या घट जाती है, तब जगल का एक दूसरा टुकड़ा साफ किया जाता है, और जब इस प्रकार जमीन बेकार हो जाती है, तब वहां से कबीला कूच कर जाता है, और वह दूसरी जगह उसी प्रकार खेती शुरू कर देता है।

इन लोगों के पास सामान बहुत थोड़ा होता है, और मकान भी इतने मामूली होते हैं, इसलिए सामान ले जाने या मकान बदलने में कोई दिक्कत नहीं होती। इस प्रकार की खेती प्रागैतिहासिक युग में आल्पस पर्वत के उत्तर गारे यूरोप में प्रचलित थी। ई० सन के प्रारम्भ तक कुछ जर्मन कबीलों में भी इस प्रकार की खेती का प्रचलन था, ऐसा स्ट्रावो से मालूम होता है। उम समय भी ग्रामाम की चावल उत्पादक नागा जाति में, एमेजन नदी की उपकूल की थोड़ी जाति में तथा सूडान के कुछ खेतिहरों में इस प्रकार की खेती मौजूद है। बेरियर एलविन ने यह लिखा है कि दक्षिण की मँकाल पहाड़ियों के पास रहनेवाली कुछ आदिम निवासी जातियों में अब भी कुछ चलती-फिरती खेती होती है। मिर्जापुर के दूधी नामक स्थान के गम्बन्ध में बताया जाता है कि पहले इसका अधिकांश हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ था। यहाँ जो कुछ खेती होती थी, उसका तरीका यह था कि आदिम निवासीगण जंगलों को जलाकर राख से ढकी हुई जमीन में बीज बो देने थे, फिर जिन समय जमीन में उपज घट जाती थी, तब फिर नये जंगलों में आग लगायी जाती थी। (ऐतिहासिक भौतिकवाद पृ० ५४-५५)

हम आज खेती में जो बात समझते हैं, आदिम खेती उस प्रकार की नहीं थी। आदिम खेती में जैसा कि हम इंगित कर चुके, किसी प्रकार हाथ में बीज उगार कर फसल होने पर उसे काट लेना मात्र था। हल जोतना, पाटा लगाना आदि जो बातें खेती के अपरिहार्य अंग समझी जाती हैं, वे सो उस समय अज्ञान थीं। खेती के बाद के युग में पशुओं का जो उपयोग किया जाने लगा, उसका आविष्कार करने-करने मनुष्य जाति को बहुत मदद लग गया। ऐसा माना जाता है कि पहलेपहल पशुपालन का एकमात्र उद्देश्य था कि जिस प्रकार वे नये नये पशुओं से काम भी लिया जा सके, वे नये नये पशुओं को पलायन करा सकें। धीरे-धीरे पशुओं के पचासों उपयोग

होगा कि जिस जमीन में पशु बँधाये जाते हैं, उसमें फसल अधिक होती है। सबसे प्रथम खाद गोबर की ही थी। भारत में अब भी वही आदिम खाद उपयोग में लाई जाती है, जबकि दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है।

यद्यपि पशुपालन चलता रहा, पर पशु के दूध का भी उपयोग हो सकता है, यह बाद को ही पता लगा। ऐसा अनुमान है कि आर्यों के भारत आगमन के पहले यहाँ के आदिवासी खेती और पशुपालन में बहुत आगे बढ़े होने पर भी वे दूध का इस्तेमाल नहीं जानते थे। यदि हम इस बात को देखें कि १९४३ में भी उड़ीसा की बन्डो जाति अपने जानवरों का दूध नहीं दुहती थी, यह बात कोई आश्चर्यजनक बात नहीं होगी। मनुष्य को इस सम्बन्ध में धीरे-धीरे ही ज्ञान हुआ होगा। दुग्ध सम्बन्धी यह ज्ञान बहुत ही उपयोगी था क्योंकि इस आविष्कार के द्वारा पशु से इतना अधिक खाद प्राप्त किया जा सकता था, जितना उसका गोशत खाने पर कभी प्राप्त नहीं हो सकता था। पर हम यहाँ पर विचारधारामों के इतिहास के सम्बन्ध में कुछ कहने नहीं जा रहे हैं, फिर भी चलते हुए, यह इंगित कर सकते हैं कि जब खेती में पशु के उपयोग का पता लगा और दूध का आविष्कार हुआ, तो स्वाभाविक रूप से पशु-हिंसा की तरफ से लोगों का मन हटने लगा। पशुपालक खेतिहर जाति में मांस भक्षण के विरुद्ध कुछ लोगों का हो जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं है।

पशुओं से ऊन मिल सकता है, और शीत निवारण में उसका उपयोग हो सकता है, यह भी बाद को ही पता लगा होगा। ऐसा मालूम होता है कि चमड़े से ऊन को अलग कर काम में लाने के बजाय ऊन समेत चमड़े को ओढ़ने का रिवाज पहले चला होगा। मिश्र निवासियों में ऊन का उपयोग ई० पू० ३००० तक ज्ञात नहीं था, किन्तु इसके पहले ही ईराक में ऊन का चलन हो चुका था। ऋग्वेदिक युग में चमड़े के अतिरिक्त ऊनी वस्त्रों का भी इस्तेमाल किया जाता था। ऊर्ण या ऊन के बनाये हुए कपड़े आर्यों के मुख्य पहिनावे थे। उनमें भी गान्धार का ऊन उत्कृष्ट माना जाता था। ऋग्वेद के एक मंत्र में गान्धार की भेड़ों की तारीफ की गयी है। बकरो से भी ऊन प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद में सूती वस्त्रों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है।

इसी प्रकार से चमड़े के अन्य प्रयोगों का पता भी धीरे-धीरे लगा होगा। धीरे-धीरे पशु के सींग, खुर सभी अंगों का उपयोग मनुष्य को मालूम होता गया।

पशुपालन और खेती के सम्मिलित युग में हम कई जगह पर पशुओं को विनिमय के साधन या सिक्के के रूप में देखते हैं। भारत में गाय बहुत दिनों तक विनिमय का माध्यम रही, तथा राजाओं तक के धन की पैमाइश उनके पशुओं की संख्या से की जाती थी। स्वाभाविक रूप से जब ऐसे युग में लड़ाइयाँ होती थी, तो पशु छीने जाते थे। महाभारत में लडाई में पशु छीनने की कई कहानियाँ आती हैं। जिस समय पांडव राजा विराट के यहाँ अज्ञातवास कर रहे थे, उम समय विराट राजा के पशुओं को लूटने के लिये कौरवों ने उनपर हमला किया था। उस समय राजा के आश्रित पांडवों ने उनकी रक्षा की थी। प्राचीन आर्यों में युद्ध में पशुओं का छीना

जाना इतनी बड़ी बात थी कि युद्ध का प्राचीन नाम ही संस्कृत में गवस्ति अर्थात् गाय की इच्छा कहा गया है।

हल का विकास एक बहुत बड़ी बात है खेती के प्रारम्भिक युग में हड्डी या लकड़ी से जमीन को थोड़ा बहुत चलाकर बीज डाल देना ही एकमात्र तरीका था, बाद को इसीसे हल का विकास हुआ। मित्र में हो याने जमीन उलटने के उपयोग में आनेवाले एक लम्बे फले के औजार का पता मिलता है। प्राचीन जापान में ऐसे फावड़ो का पता मिलता है, जिनको जमीन पर रखकर खींचा जाता था। हेन्राइडिस द्वीप में एक तरह के पदचालित हल का पता मिलता है। ऐसा समझा जाता है कि हम जिसे हल कहते हैं, वह कहीं किसी औजार से और कहीं किसी अन्य औजार से उत्पन्न हुआ।

पहले हलो में पशु का उपयोग नहीं रहा होगा, बाद पशु का उपयोग हुआ, और अब तो ट्रैक्टर का युग है। इस सम्बन्ध में भी खोज की गई है कि किन-किन अनाजों का उत्पादन किस-किस प्रकार से सीखा गया। हमने अपनी 'ऐतिहासिक भौतिकवाद' नामक पुस्तक में डम विषय पर कुछ विस्तार से विचार किया है, यहाँ पर हम कुछ मोटे तथ्य पेश करेंगे। भूमध्यसागर, पश्चिमी एशिया और भारतवर्ष की सम्यतायें विशेष कर दो अनाजों पर निर्मित हुई हैं, एक जौ और दूसरा गेहूँ। यह समझना भारी भूल होगी कि जिस रूप में आज हम गेहूँ और जौ को देखते हैं, वह आदिकाल से ही ऐसा ही रहा है। गेहूँ के पूर्व पुरुष के रूप में दो जगली घासों का पता लगता है। एक का नाम डिकल और दूसरी का नाम ऐंमर है। कुछ विद्वानों ने यह नतीजा निकाला है कि अफगानिस्तान और उत्तर पश्चिम चीन में ही गेहूँ पहले-पहल उत्पन्न हुआ। पर इस समय जो गेहूँ प्रचलित है वह डिकल और ऐंमर से पृथक एक तीसरी ही किस्म का है, जिसका वैज्ञानिक नाम ट्रिटिकम वल्गारी है। जौ भी कुछ पहाड़ी घासों से ही विकसित हुआ है। उपलब्ध प्रमाणों से ज्ञात होता है कि अवीसिनिया और दक्षिण पूर्व एशिया में जौ की पहले-पहल वुआई हुई होगी।

इस प्रकार खेती का विकास होते-होते सैकड़ों वर्ष लग गये। प्रत्येक युग के लोग यह समझते हैं कि उन्हीं के युग में स्वयं अधिक आविष्कार हुये, पर जैसा कि हम दिखा चुके हैं, खेती की उत्पत्ति और विकास के दौरान में कितने ही महत्त्वपूर्ण आविष्कार हुये जिनके विषय में हमें कुछ बुधलासा ही ज्ञान है।

जो कुछ भी हो जब हम ऋग्वेदिक समाज में पहुँचते हैं, तो हम यह देखते हैं कि ऋग्वेद में जिम जाति या कबीलो का वर्णन है, वे खेती करते हैं, मिलाई-बुनाई सीख चुके हैं, तावे का उपयोग जानते हैं, रथ बनाते हैं, मकान बनाते हैं, वर्तन बनाना जानते हैं, और उनमें वैयक्तिक परिवार का सूत्रपात हो चुका है।

पुरातत्त्व का अब निश्चित मत है कि आज से सात हजार वर्ष पहले निकट पूर्व में कृषि-कला का उद्भव हुआ, और मनुष्य खाद्य एकत्रकारी प्राणी से खाद्य उत्पादक हो गया, फिर यह कैसे कहा जा सकता है कि वेद किसी भी हालत में इससे पहले लिखे गये। अन्य अनेक प्रकार के प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि वेद कृषि-कला के आविष्कार के बहुत बाद लिखे

गये। हमें यहाँ वेदों के समय निर्धारण के पचड़े में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। हमारे वर्तमान विषय के लिए इतना ही यथेष्ट है कि वैदिक आर्य खेती करनेवाले लोग थे।

वह समय पीछे छुट गया है, जब भूमि पर सामाजिक अधिकार था। आर्यों के दल-के-दल भारत में आ रहे थे, और वे अनायों से जमीन छीनते जाते थे। पर अभी तक जमीन की कोई विशेष कमी नहीं थी, और अनायें तथा आर्य दोनों खेती कर सकते थे। पर अब अनायें विजित थे और आर्य विजेता। इस कारण आर्यों के मुकाबले में अनायों की परिस्थिति निकृष्ट-तर होती जाती थी। कैसे आर्य-अनायों के इसी सम्बन्ध में पहले दो वर्णों की और बाद को चतुर्वर्ण की उत्पत्ति हुई, इसके बारे में यहाँ जानने की आवश्यकता नहीं है। जिस समय भारतीय आर्यगण अभी बहुत कुछ खानाबदोशी की अवस्था में थे, और जीतते हुए आगे बढ़ते चले आ रहे थे, उस समय उनमें दासता के अधिक प्रचलन या चतुर्वर्ण की सम्भावना न होगी, यह स्पष्ट है।

आर्य नाना कुलों तथा कबीलों में विभक्त थे। जरूरत पड़ने पर कई कुल या कबीले आपस में मित्रता कर लेते थे। परुष्णि और यमुना की लडाई के समय इस प्रकार की सघबद्धता का विवरण मिलता है। युद्ध में विजय या कार्यमिद्धि होने पर प्रत्येक कबीला अलग हो जाता था। एक कबीला विभिन्न देशों में विभक्त होता था। जन शब्द कबीले के अर्थ में प्रयुक्त होता था।

भारतीय आर्यों का जीवन जन, विश, ग्राम आदि के इर्द-गिर्द परिचालित होता था। इन्हीं तीनों शब्दों में आदिम आर्यों की भूमि व्यवस्था की सारी बातें निहित हैं। ऐसा मालूम होता है कि यद्यपि वाद को चलकर जमीन व्यक्तिगत सम्पत्ति हो गई, पर आर्यों के प्रथम सोपान में भूमि किसी न-किसी अर्थ में सामूहिक सम्पत्ति थी।

यद्यपि जन और विश शब्द के सम्बन्ध में विशेष कोई मतभेद नहीं है, पर ग्राम शब्द का क्या अर्थ था, इस सम्बन्ध में विद्वानों में कुछ मतभेद है। आज तो ग्राम शब्द स्थानवाचक है, पर ऐसा ज्ञात होता है कि पहले अमुक ग्राम माने अमुक परिवारवृन्द मात्र था। यदि वह परिवारवृन्द स्थान को छोड़कर चला जाता था, तो ग्राम चला जाता था। डाक्टर वेणी प्रसाद के अनुसार कुछ साथ में रहनेवाले परिवार ही ग्राम के रूप में होते थे। कई ग्राम मिलकर विश या कौन्ट वनता था फिर कई विश मिलकर एक जन वनता था।

श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जन और विश को करीब-करीब एक ही अर्थ में लेते हैं। उनके अनुसार एक जन की ममूची जनता विश (१५।९।१-२) कहलाती थी। प्रत्येक जन के लोग (विश) यह ममझते थे कि हमारा मूल पूर्वज एक जोड़ा था, उसकी सन्तान हुई, सन्तान की फिर सन्तान हुई, इन प्रकार मयुन्त परिवार बढ़ता या फटना गया, उसकी अनेक शाखायें होती गई, जन के सब लोग मजान या मनामि होते अथवा कम-से-कम अपने को मजात और सनामि मानते थे।

जन का चित्र तो बहुत साफ है, पर जन, विश और ग्राम का क्या सम्बन्ध होता था, यह स्पष्ट है। कौय ने दिखाया है कि ऋग्वेद में ये



शब्द बहुत ही अस्पष्टता के साथ व्यवहृत हुये हैं, उदाहरणार्थ भारतीयों को एक जगह पर जन, तथा दूसरी जगह पर ग्राम कहा गया है, इसलिए ग्राम के विद्य के अन्तर्गत होने का कोई प्रमाण नहीं है। विश्व के अर्थ अक्सर वस्ती के भी हैं। यह समझना गलत होगा कि जिस समय शब्द प्रचलित थे, उम समय इनके अर्थ में कोई गड़बड़ी थी। वाद को शब्दों के अर्थ बदलते गये, पर वैदिक साहित्य में जो शब्द जहाँ था, उसे वही रहने दिया गया, इसी कारण वाद को चलकर उनके अर्थों में गड़बड़ी दृष्टिगोचर होती है।

विश्व अपना काम समिति और सभा के जरिये से करती थी। सभा और समिति में क्या अन्तर है, इस सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। लुउविग का कहना है कि समिति में सारी जनता रहती थी, और सभा में केवल मधवन् और ब्राह्मण रहते थे। जिमेर का कहना है कि सभा ग्राम की सभा थी, किन्तु हम वैदिक इन्डेक्स के लेखक हिलब्रान्ड के साथ इस सम्बन्ध में एकमत हैं कि समिति और सभा करीब-करीब एक चीज है। एक तो सभा है और दूसरा प्राथमिक रूपसे सभास्थल के माने में आता है। अथर्ववेद में यह उल्लेख आता है कि सभा और समिति प्रजापति की दो कन्यायें हैं, इस उल्लेख में ये दोनों अलग-अलग सस्थाएँ हो जाती हैं। इन तथ्यों को तोलने के बाद डा० वेणी प्रसाद यह कहते हैं कि अथर्ववेद का यह हिस्सा ऋग्वेद के अधिकांश हिस्से से अर्वाचीनतर है, किन्तु इसके अतिरिक्त हम कुछ जानने में असमर्थ हैं। सभा में वृद्ध ही आते थे, यह कोई बात नहीं है, उममें जवान भी आते थे। आवश्यक कार्यों के बाद निनोद की बातें होती थी और तब वह गोष्ठी का काम देती। इस प्रकार सभा कलव के रूप में बदल जाती थी।

सभा और समिति में क्या भेद था, था या नहीं था, किसी इलाके में वही मन्था सभा कहलाती थी, और किसी में समिति, इन बातों पर कोई अन्तिम फैसला न होते हुए भी यह कहा जा सकता है कि इन सस्थाओं के जरिये में ही लोगों के सब तरह के सामूहिक जीवन, खेलकूद से लेकर

जुआ और दूसरी तरफ सधि-विग्रह की सब बातों की आलोचना इन्हीं में होती थी।

सारी बातों पर विचार करने के अनन्तर हम आसानी से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि वैदिक आर्यों के समाज को हम कई ऐतिहासिक सोपानों में बाट दें, तो हम यह कह सकते हैं कि प्रथम सोपान में पशु और भूमि कबीलो की सामूहिक सम्पत्ति होती थी। बाद को धीरे-धीरे सभा, समिति नाम भर के लिए रह गई, और राजा का विकास हुआ। राजा का विकास बहुत धीरे-धीरे हुआ। पहलेपहल जब राजा दृष्टिगोचर होता है, तो वह एक चुना हुआ, और सो भी सामयिक कार्यसिद्धि के लिए चुना हुआ व्यक्ति होता था, फिर धीरे-धीरे यह चुनाव नाम मात्र का रह गया, और राजा तथा उसके पार्षद सर्वोसर्वा हो गये। भूमि सामूहिक सम्पत्ति से बहुत कुछ राजा की सम्पत्ति हो गई।

कई मन्त्रों में राजा और समिति में सद्भाव की कामना की गई है। अथर्ववेद के एक आशीर्वचन को लीजिए, उसमें कहा गया है—‘तू अविचलित और ध्रुव होकर पशुओं का हनन कर, जो तेरे शत्रु हैं, उनको मार कर नीचे गिरा, समिति तेरे साथ सामजस्य रख कर चले।’ अन्यत्र राजा प्रार्थना करता है—“प्रजापति की दो कन्यायें मेरी अनकलता करें।”

जो कुछ भी हो, अन्त तक समितियाँ लुप्त हो गईं, जैसा कि पारस्कर गृह्यसूत्र से पता चलता है। इस ग्रन्थ में समिति का उल्लेख स्मृति के रूप में किया गया है। जातको के समय (ई० पू० ६००) के पहले ही समिति का अन्त हो जाता है। समिति के अवसान के बाद राजा माध्याकर्षण का केन्द्र बन गया, पर उसके बाद भी अभिषेक आदि के रूप में जो प्रथायें रह गईं, उसमें जनता या समिति की स्वीकृति की बात कैसे छिपी हुई है यह इस सम्बन्धी अनुष्ठानों के अध्ययन से पता लगता है। भूमि राजा के अधीन व्यक्तिगत सम्पत्ति हो गई। इस प्रकार वैदिक काल में ही उस समाज का सूत्रपात हो जाता है, जो भारत में अभी अभी तक मौजूद था, और कहीं कहीं अभी तक मौजूद है।



# नवीन चीन के खेती

## सम्बन्धी कानून सुधार

### श्री वी० एन० गांगुली का एक विश्लेषण

इस लेख में, चीन के जनवादी प्रजातंत्र के खेत सम्बन्धी कानून में जो नये सुधार किये गये हैं इसके विश्लेषण की चेष्टा की गयी है। इसे न समझने या कम समझने के कारण लोगो के मन में नवीन चीन के सम्बन्ध में अजीब धारणाएँ उत्पन्न हुई हैं। सबसे पहले यह बताने की आवश्यकता है कि नवीन चीन में इस सम्बन्ध में जो सुधार किया गया है, उसका अर्थ यह नहीं है कि जमीन की मिल्कियत समाप्त कर दी गयी है, बल्कि जमीन पर जमीन्दार वर्ग के द्वारा सामन्तवादी शोषण का अन्त किया गया है। नये सुधार से केवल उस बेकार वर्ग का अन्त किया गया है, जो जमीन के मालिक होने के कारण हाथ पर हाथ धर कर बैठा रहता था, और शोषण पर पुष्ट होता था।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमला जमीन के सब मालिको पर नहीं किया गया है, बल्कि उस वर्ग पर किया गया है, जो कुछ काम नहीं करता था। जो लोग अपनी जमीन के मालिक होने के कारण उसे जोतते-बोते थे, उन पर किसी प्रकार आच आने देना इस सुधार का ध्येय नहीं है। बात यह है कि चीन के भूमि-सुधारको ने इस बात पर ध्यान रखा है कि कही सामन्तवाद की जड़ उखडने के साथ-साथ देहाती उद्योग-वधो का नाश न हो जाय, इसलिए एक को उखाड फेंकने के साथ-ही-साथ उन्होंने राष्ट्रीय पूजीपति वर्ग के उस हिस्से की रक्षा की है, जो आर्थिक व्यवस्था में एक बहुत आवश्यक हिस्सा अदा कर रहे थे। इसलिए यह अध्यादेश दिया गया है कि उद्योग और व्यापार पर किसी प्रकार हस्तक्षेप न किया जाय।

भारत की तरह चीन में उच्च किसान वर्ग बहुत जटिल सम्बन्ध रखते हैं। उदाहरणस्वरूप एक उच्च किसान एक दृष्टि से तो लगान लेनेवाला जमीन्दार हो सकता है, और दूसरी दृष्टि से अपने खेत पर खेती करनेवाला मामूली किसान, और तीसरी दृष्टि से मजदूरी पर दूसरे के खेत में फसल की कटाई करनेवाला मजदूर हो सकता है। ऐसी जटिल अवस्था में भूमि सुधार का कार्य केवल इतना ही रह जाता है कि एक किसान किस हद तक शोषक है यानी उसकी आमदनी का कितना हिस्सा शोषण से आता है, यह देखा जाय, और फिर यह तय किया जाय कि किस हद तक समाज के हित में उसके शोषण को तरह दिया जा सकता है।

इसलिए केवल लट्ठमार तरीके से यह निर्णय दे देने पर काम नहीं चलता था कि सामन्तवादी शोषणयुक्त मिल्कियत का अन्त कर दिया जाय। यदि बिना किसी और विचार के इस सूत्र को कार्यान्वित किया जाता तो सारी जमीन को जप्त कर उसका राष्ट्रीकरण करना या जप्त की हुई जमीन को छोटे किसान मालिकों में बांटना पडता। इस सम्बन्ध में कोई गड़बडी न हो, इसलिए यह साफ कर दिया गया था कि जमीन पर किसान की मिल्कियत की पद्धति का परिवर्तन किया जायगा। कही इतने से भी कुछ अस्पष्टता न रह जाय, इसलिए आर्टिकल २० में यह साफ कह दिया गया था कि "भूमि-सुधार कार्यक्रम की परिसमाप्ति के बाद जनवादी सरकार लोगो को पट्टे देगी, और जो लोग इस प्रकार जमीन के मालिक बनेंगे, उन्हें अपनी जमीन की व्यवस्था करने, बेचने, खरीदने और स्वतंत्रतापूर्वक लगान पर उठाने के अधिकार स्वीकृत होंगे।"

नवीन चीन में जमीन पर वैयक्तिक मिल्कियत की स्वीकृति किसी मूक्षम सिद्धान्त के आधार पर नहीं हुई है, बल्कि ऐसा केवल उपयोग की दृष्टि से किया गया है। आर्टिकल १ में यह साफ कर दिया गया है कि इस स्वीकृति में इन लाभो की आशा की जाती है (क) देहाती उत्पादन सम्बन्धी शक्तिया मुक्त हो जायगी। (ख) खेती के उत्पादन में वृद्धि होगी, और इस प्रकार (ग) नवीन चीन के औद्योगीकरण के लिए रास्ता साफ हो जायगा।

कहना न होगा कि चीन के नेताओं ने इस सम्बन्ध में बड़े साहस से काम लिया है। जैसा कि लिउ सावची का कहना है कि चीन के औद्योगीकरण को विगाल देगी देहाती बाजारो पर निर्भर करना पडेगा, दूसरे शब्दो में इसका अर्थ यह है कि जब बड़े हुए उत्पादन के कारण देहातो में लोगो की क्रयशक्ति में वृद्धि होगी, तभी औद्योगीकरण का कार्यक्रम ठीक-ठीक चलेगा। इमोलिये गावो की उत्पादन शक्ति की मुक्ति पर जोर है, यानी उनके मार्ग में जितनी बाधाएँ रही हैं, उनके दूरीकरण पर जोर है।

किन जमीनों को जप्त कर लिया गया, इनका स्पष्टीकरण आवश्यक है। केवल वह जमीन जप्त की गयी—जमीन्दारो की वे जमीनें जिन पर वह केवल जमीन्दार के रूप में काबिज था, वे जमीनें जो पूर्व पुरुषो के मन्दिरों (यहाँ यह बताना दिया जाय कि चीन में पूर्व पुरुषो की पूजा होती

है, और उनके मन्दिरों के साथ सम्पत्ति लगी होती है), देव मन्दिरों, मठों, गिरजों, स्कूलों, अस्पतालों तथा अन्य सार्वजनिक ट्रस्टों की जमीनें। मसजिदों के साथ लगी हुई जमीनें ज्व्त नहीं की गईं, धार्मिक सस्थाओं को इस ज्व्ती से जो वित्तिय हानि हुई है, उसे सरकार ने अपने ऊपर लेकर सार्वजनिक कोष से आवश्यकता के अनुसार उसकी पूर्ति की है। उन जमीनों की भी ज्व्ती नहीं की गई है, जिनपर व्यापारियों अथवा उद्योग-पतियों का अधिकार है, साथ ही उनके अधिकार के किसानों के घर भी ज्व्त नहीं किये गये हैं। ऐसे सब जमीन्दारों की जमीनें ज्व्त कर ली गयीं, जो दूसरे काम करते हैं। वशतें कि उस इलाके में जितनी जमीन प्रत्येक व्यक्ति को मिल सकती है, उसकी दुगुनी से अधिक उसके पास है। अर्द्ध जमीन्दार किस्म के मोटे किसानों द्वारा लगान पर उठायी हुई जमीनें भी किसी-किसी हालत में ज्व्त कर ली गई हैं।

यह न समझा जाय कि केवल जमीनें ही ज्व्त की गईं, कुछ हालतों में खेती में काम आनेवाले पशु, खेती के औजार, फालतू अनाज और जमीन्दारों के फालतू देहाती घर भी ज्व्त करने की व्यवस्था की गई। यदि इस प्रकार ज्व्ती से उत्पादन के आवश्यक साधन प्राप्त न किये जाय, तो उत्पादन चालू ही नहीं रह सकता। फिर भी जमीन्दारों की फालतू चीजों की ज्व्ती में नमी से काम लिया गया है, क्योंकि, नहीं तो अराजकता फैलने का डर था, साथ ही इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि यदि जमीन्दार न उत्पादन में पूजी लगा रखी है, तो उससे अन्ततोगत्वा देश को लाभ ही है।

नये सुधार के अनुसार बटाई की इस प्रकार की खेती, जिसमें एक काम करता है और दूसरा खेत का मालिक होने के नाते उसका आधा हिस्सा लेता है, स्वीकृत नहीं है, फिर भी खेती में लगनेवाले खेत के मालिक की मर्यादा स्वीकृत है। आर्टिकल ५ और ६ में ऐसे लोगों को गिनाया गया है, जो खेती न करते हुए भी खेती की उपज के हकदार के रूप में स्वीकृत हैं। गान्धिकारी सैनिक, शहीदों के परिवार, मजदूर, स्टाफ के मदस्थ, पेशेवर मजदूर, फौरीवाले तथा दूसरे कई लोगों की जमीन ज्व्त नहीं की गयी वशतें कि उम इलाके में भूमि के पुनर्विभाजन के बाद प्रत्येक व्यक्ति को जितनी जमीन मिल सकती है, उससे दुगुनी से अधिक इनके पास न हो। पर इन मन्त्रन्व में भी काफी छूटे रखी गई हैं, उदाहरणस्वरूप अनेक रहनेवाले वृद्ध तथा वृद्धाये, अनाथ बालक तथा बालिकाये, अपाहिज, अन्धाय विधवा या विधुर, जो अपनी जमीन पर जीविका के लिये निर्भर हैं, वे दुगुनी जमीनवाली हद से बरी हैं। यदि किसी ने अपने परिश्रम से धन में जमीन खरीदी है, तो वह भी दुगुनी जमीनवाली हद से बरी है।

जिन् माजरी ने इन प्रकार की रियायतों की इस तरह व्याख्या की है कि इन नियमों के अनुसार जितनी जमीन सामाजिक नियम से बरी हो जाती है, उसका जमीन की ३ में ५ फीसदी से अधिक नहीं ठहरनी। उन्होंने इन बातों पर भी जोर दिया है कि जो लोग प्रथम श्रेणी में आते हैं, उनके साथ रियायत करना जरूरी है। उनके अलावा जिन लोगों की श्रम-व्यक्ति नष्ट हो गयीं या जो अनाज या अनाज के बच्चे थे, उनके साथ भी रियायत करना इस कारण जरूरी है कि अभी तक सामाजिक बीमावाला व्यवस्था लागू नहीं किया जा सका।

यह सारी बात तो समझ में आती है, पर आर्टिकल ६ में यह जो रखा गया है कि "मोटे किसानों के पास जिनकी ऐसी जमीन है जिस पर वे खुद खेती करते हैं या मजदूरों से खेती करवाते हैं, उस जमीन की और साथ ही दूसरी सम्पत्तियों की रक्षा की जायगी," यह कम समझ में आती है। बात यह है कि मार्क्सवादी विचारों के अनुसार मजदूरों को रख कर काम करवाना शोषण के अन्तर्गत है। यह न समझा जाय कि चीन के नेता इस विचार से बिल्कुल हट गये हैं, उन्होंने जो रियायत की है, वह बहुत थोड़ी है। यह भी नियम रखा गया है कि एक बार धनी किसानों और जमीन्दारों के माल की ज्व्ती का कार्यक्रम पूरा हो जाय, तो उसके बाद फिर उनके साथ छेड़-छाड़ नहीं की जायगी। इस प्रकार मोटे किसानों की जो रक्षा चीन की आर्थिक पद्धति में की गयी है, वह एक नयी बात है, और साम्यवादी नीति में एक सुधार के रूप में है।

नये कानून में इस बात की व्यवस्था है कि खेती का एक हिस्सा, जहां तक मिल्कियत और व्यवस्था का सम्बन्ध है, राष्ट्रीकृत होगा। यह नियम रखा गया है कि जहां राष्ट्रीकरण के बिना खेती अच्छी तरह नहीं हो सकेगी, वही राष्ट्रीकरण के शस्त्र को काम में लाया जायगा। यह स्मरण रहे कि आर्टिकल १६ के अनुसार ज्व्तशुदा और सरकार द्वारा सामयिक रूप से अधिकृत जंगल, मछलीवाले तालाब, चाय बगान, टुंग तेल उत्पादक स्थान, शहतूत के खेत, बास के जंगल, फल के बगान, सरकडेवाली जमीन तथा परती जमीन और दूसरी विभाजन योग्य जमीन साधारण जमीन के रूप में समझी जायगी, और इन में से सभी उपर्युक्त अनुपात पर विभाजित किये जायेंगे। हा, अगर यह खतरा हो कि इस प्रकार इन चीजों को बाट देने से उत्पादन में कमी होगी, तो इन्हें स्थानीय जनवादी सरकार की देखरेख में ही काम में लाया जायगा। जिन तालाबों और बाधों आदि से सिंचाई होती है, वह भी सरकार की सम्पत्ति मानी गई है। बड़े जंगल, बहुत बड़े जलाशय, विशाल परती जमीन, पहाड़ों के किनारे, जिन पर अभी खेती नहीं हुई है, नमक की बड़ी खानें, दूसरी खानें, झीले, दलदल, नदियां और बन्दरगाह सरकारी सम्पत्ति हैं। हा, जिन क्षेत्रों में यह स्वीकृत हुआ है कि निजी पूजी और व्यवस्था के बिना इनका उपयोग ही न होता, वहां पर निजी पूजी को सरकारी देखरेख में काम करने की आज्ञा दी गयी है।

बड़े कुज, बागान, चारागाह, शहतूत के खेत, बीज प्रयोग क्षेत्र, प्रयोगात्मक फार्म अब सरकार की सम्पत्ति हैं, भले ही वे पहले बड़े जमीन्दारों की सम्पत्ति रही हो। अच्छे दृश्यवाले सुन्दर स्थान, ऐतिहासिक अवशेष, ऐतिहासिक दिलचस्पी के स्थान, जमीन्दारों की ऐसी फालतू देहाती हवेलियां, जो किसानों के काम में नहीं आ सकती और केवल सार्वजनिक काम में ही आ सकती हैं, प्रवासी चीनियों की जमीन और मकान जमीन्दारों या सार्वजनिक सस्थाओं के अधीन की रेतीली या नीकी जमीन, रेल और मडक के पडोस की जमीन, नदी के तट, समुद्र को रोकने के लिये बनाया गया बाध, हवाई जहाज के अड्डों की जमीन, जहाज घाट और किलेबन्दीवाली जमीन, वे भूमिखंड जिनपर एक निर्दिष्ट तारीख तक रेल, मडक, नहर, हवाई अड्डों का निर्माण निश्चित हो चुका है, ये सब सरकारी सम्पत्ति मान लिये गये हैं।

नये कानून के अनुसार जमीन वाटने के कुछ आधारभूत नियम बनाये गये हैं। किसान सघो को जमीन ले लेने तथा वाटने के वाहन के रूप में स्वीकार किया गया है। नये सुधारो को काम में लाने के लिए एक इकाई बनाकर फिर कार्य चालू किया गया है। इस सस्था को लमियाग का नाम दिया गया है। इस बात की गुजाइश रखी गयी है कि प्रत्येक स्थान पर वहा की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार जमीन का विभाजन किया जाय। इस प्रकार चीनी नेताओ ने चीन को अन्व जन-क्रान्ति के हाथों में नहीं छोडा है, और इस प्रकार चीन रूस की तरह व्यर्थ के सम्पत्ति-नाश, आर्थिक अराजकता से बच गया है।

जब हम चीन में अनुभूत भूमि-विभाजन के सिद्धान्तों की जाच करते हैं, तो हमें यह पता लगता है कि वहा अन्व समानतावाद का त्याग कर वास्तविक ढग से सब समस्याओ को सुलझाया गया है। इस बात को याद रखा गया है कि जमीन के पुनर्विभाजन या जमीन्दारी की ज्व्ती का अर्थ जमीन्दार से या किसी से बदला लेना नहीं है। जिनके पास थोडी जमीन है, उन्हें भी पुनर्विभाजन के समय जमीन देने की व्यवस्था की गयी है, भले ही इस व्यवस्था के कारण उसके पास दूसरो से अधिक जमीन आ जाती हो। यद्यपि इस प्रकार अपवादात्मक बहुत से कार्य किये गये, फिर भी जिनके पास जमीन नहीं थी या जिनके पास नाम मात्र जमीन थी, उनका विशेष ख्याल रखा गया है।

आर्टिकल ३१ के अनुसार करीब-करीब यह कह दिया गया है कि चीन में वर्ग रहेंगे। किसान सघो को यह मनमाना अधिकार नहीं दिया गया कि वे चाहे जिसकी जमीन ज्व्त करे या चाहें जिमको जमीन दें। उनके विरुद्ध अपील हो सकती है। नये कानून के अनुसार वे ही लोग जमीन्दार हैं, जो सामन्तवादी शोपण के दोपी हैं। पर यदि कोई जमीन्दार कथित शोपण के वावजूद मध्यम दर्जे के किसानो मे वुरी हालत मे है, तो उसे जमीन्दार मानने का हठ नहीं किया गया। जो लोग लगान पर जमीन प्राप्त कर फिर मजदूरो की कमाई पर जीते हैं, उन्हें उप-जमीन्दार माना गया है। यह तो पहले ही बताया गया कि लाल सेना के लोग, शहीदो के लोग, मजदूर इत्यादि एक हद तक जमीन्दार नहीं माने जाते। यदि किमी व्यक्ति को कई तरीको से आमदनी होती है, तो उसका वर्ग उसकी प्रधान आमदनी से कूतने की व्यवस्था है। मच तो यह है कि जमीन्दार और मोटे किसान मे फर्क कही-कही पर मालूम ही नहीं होता। फिर भी नये कानून मे मोटे किसानो की आर्थिक पद्धति की रक्षा की व्यवस्था किये जाने मे इनके पृथक्त्व का स्पष्टीकरण जरूरी हो गया, और इस सम्बन्ध मे कमीटी तयार की गई। यदि कोई व्यक्ति जितनी जमीन स्वयं जोतता है, उसमे अधिक लगान पर उठाता है, तो वह जहा तक फालतू जमीन है, जमीन्दार समझा जाता है। यदि कोई किसान परिवार खुद कास्त मे तिगुनी या उसमे अधिक जमीन लगान पर उठाता है, तो वह परिवार जमीन्दार-परिवार समझा जाता है, साथ ही जो लोग जमीन्दार घराने मे उत्पन्न होकर भी स्वयं मेहनत-मजदूरी करने पर मजबूर हैं, वे जमीन्दार नहीं समझ जाते। जो कुछ बताया गया, उसने यह स्पष्ट है कि सिद्धान्त की दन्त कटाकटी में न पडकर देस की सुविधाओ पर ध्यान रखकर कार्य करने की परिपाटी विकसित की गयी है। सभी मध्यम किसान केवल खुदकान्त की जमीन का

मालिक न होकर एक हद तक लगान पर जमीन दे सकता है, और कर्ज ले सकता है और दे सकता है। यह माना गया है कि एक ही व्यक्ति एक क्षेत्र में शोपक और दूसरे क्षेत्र मे प्रायः उसी हद तक शोपित होने के कारण उसका शोपण शोपितत्व से कट जाता है। रूस की तरह चीन में मोटे किसान कुलक नहीं माने गये हैं। और उसके अधिकार नष्ट नहीं किये गये।

उन लोगो को गरीब किसान माना गया है, जिनके पास अथयैट्ट जमीन और औजार हैं, जिसे लगान पर जमीन और कर्ज से धन प्राप्त करना पडता है, और जो इस प्रकार बहुत मृदु शोपण का शिकार है।

खेतिहर मजदूर की परिभाषा मे भी कुछ नवीनता कर दी गयी है, जिनके पास जमीन या औजार बिल्कुल नहीं है, और जो दूसरो के खेत में काम करते हैं, वे खेतिहर मजदूर तो हैं ही, साथ ही वे भी खेतिहर मजदूर माने गये हैं, जिनके पास थोडी जमीन या थोडे औजार हैं।

सच बात तो यह है कि व्यवहार मे कौन क्या है, इस बात की परिभाषा बहुत कुछ उस इलाके की परिस्थिति पर निर्भर रखा गया है। चीनियो ने श्रम और पूरक श्रम में फर्क किया है। एक का अर्थ आवश्यक श्रम है, और दूसरे का अर्थ अनावश्यक श्रम है। नियम यह रखा गया है कि यदि एक परिवार में एक व्यक्ति माल मे चार महीने आवश्यक श्रम मे लगा रहता है, तो यह माना जाता है कि वह परिवार श्रम मे लगा है, पर यदि परिवार पन्द्रह से अधिक व्यक्तियो का है, तो कम-से-कम तीन व्यक्तियो का साल में चार महीने आवश्यक श्रम मे लगा रहना जरूरी है। यह इसी आधार पर तय किया जाता है कि कौन क्या करता है। जो लोग जोताई-बुवाई, कटाई में भाग लेते हैं, वे श्रम करनेवाले माने जाते हैं जबकि निराई गोडाई, तरकारी उत्पादन, पशुओ की देखरेख आदि कार्य करनेवाले लोग पूरक श्रम करनेवाले माने जाते हैं। यह न समझा जाय कि सभी क्षेत्रों में कट्टरता के साथ इस परिभाषा का पालन किया जाता है, कई बार अपवादात्मक परिस्थितियो में कडाई के साथ परिभाषा का अनुसरण नहीं किया जाता है।

मोटे किसान और मध्यम किसान में भी फर्क करने के लिए एक नियम यह रखा गया है कि यदि किमी किसान की आय की पचीस फी सदी से अधिक रकम शोपण से प्राप्त होती है, तो वह मोटा या धनी किसान माना जाता है, नहीं तो वह मध्यम किसान माना जाता है। इसी प्रकार और कई छोटे-मोटे नियम रखे गये हैं, परन्तु सब नियमो की तरह भौके के अनुसार ढीलाई वरती जाती है।

अकसर वर्ग निर्णय मे राजनीति का भी ख्याल रखा जाता है। यदि परिभाषा के अनुसार धनी किसान ठहरनेवाले किमी व्यक्ति के सम्बन्ध मे यह पता लगता है कि उनमे अपराधी टग से क्रान्ति का विरोध किया था, तो उनकी सम्पत्ति ज्व्त कर ली जाती है, पर उनके परिवार के मद्र सदस्यों की सम्पत्ति ज्व्त नहीं होती।

चीन में इन वर्गीकरण के सिलमिले मे एक अजीब वर्ग उन लोगों का माना गया है, जो अजीब-गरीब पेशेवाले लोग कहलाते हैं, और किसी तरह पेट पालने हैं।

नये वर्गीकरण में वृद्धिजीवियों को पृथक वर्ग नहीं माना गया है। उन्हें "स्टाफ सदस्य" माना जाता है, पर वे मजदूर वर्ग के अंश के रूप में समझे जाते हैं। जो लोग अनुचित उपायों से जीविका चलाते हैं, वे "आवारे तथा आलसी" वर्ग में रखे गये हैं। अजीब-गरीब पेशेवाले इस कोटि में नहीं आते। पुरोहित और पादरी अनुचित उपायों से जीविका चलानेवाले वर्ग में आ जाते, पर उनके लिए एक अलग वर्ग की सृष्टि की है, जिसका नाम धार्मिक पेशेदार वर्ग बनाया गया है।

ऊपर जो कुछ लिखा गया, उससे यह स्पष्ट हो गया होगा कि क्रान्ति के कारण बहुत से लोगों का वर्ग परिवर्तन हुआ है। सभी यह चाहते हैं कि उन्हें किसान या मजदूर या कुछ नहीं तो अजीब-गरीब पेशेवालों में रखा जाय, कम-से-कम उन्हें आवारों में तो न रखा जाय। मजदूर वर्ग में रखे जाने के लिए यह जरूरी है कि कोई व्यक्ति कम-से-कम एक साल के लिये मुख्य रूप से श्रम करता रहा हो। यदि कोई व्यक्ति सामन्त या पूँजीवादी वर्ग से है, पर इस गुण की कसौटी पर पूरा उतरता है, तो उसको उत्पत्ति भुला दी जाती है। यदि किसी व्यक्ति की हैसियत में विवाह के कारण परिवर्तन हुआ है, तो भी उससे कुछ फर्क नहीं आता वशतः कि वह इस कसौटी पर खरा उतर जाय।

स्वतंत्र दस्तकारों को भी मजदूरों की श्रेणी में रखा गया है। यदि दस्तकार कुछ हद तक किराये के मजदूरों पर निर्भर करता है, तो भी वह मजदूर ही रहता है। पर एक हद के बाद उसका वर्गीकरण मध्यम किसान के अनुरूप माना जाता है। कुछ लोग दस्तकार पूँजीपति भी माने गये हैं, ये लोग मुख्यतः दूसरों के श्रम पर निर्भर रहते हैं, और मुनाफे के लिये काम करते हैं। फिर भी इनको प्रोत्साहन ही दिया जाता है। इसी प्रकार मोटे व्यापारी तथा फेरीवालों को भी प्रोत्साहन दिया जाता है, यद्यपि वे उत्पादक नहीं हैं, और मुनाफे के लिए काम करते हैं। मार्क्सवादी सिद्धान्त के अनुसार मुनाफा शोषण मात्र है। फिर भी दस्तकारों पूँजीपतियों, मोटे व्यापारियों और फेरीवालों के विरुद्ध चीनी प्रशासन का विरोध नहीं है।

इसी प्रकार एक नया दिलचस्प वर्ग वह है, जिसे चीनी साम्यवादी रोसनीवापता भद्र वर्ग कहते हैं। इस वर्ग में वे देशभक्त जमीन्दार आ जाते हैं, जिन्होंने निश्चयात्मक रूप से जनवादी लोकतंत्र को लाभ पहुँचाया है। इन्हें आर्थिक और राजनीतिक मर्यादा दी गयी है, यद्यपि नियमानुसार उनकी जमीन और सम्पत्ति जप्त कर ली गई है। यदि कोई भूतपूर्व जमीन्दार पाच नाल तक श्रम में सलग्न रहे और नकचलनी का परिचय दे, तो वह मजदूर वर्ग में स्वीकृत हो सकता है। धनी किसानों के वर्ग परिवर्तन में तीन नाल ही लगते हैं।

यह पूछा जा सकता है कि वर्गीकरण के सम्बन्ध में इन बातों की आवश्यकता क्या है? इनका उत्तर देना सरल नहीं है, क्योंकि जिस समाज व्यवस्था में वर्गहीन समाज स्थापित करने का लक्ष्य है, वह इन प्रकार के छोटके वर्गों के विभाजन को कर रहा है। इनका उन्मूलन करना आवश्यक है कि परिवर्तन का यह जरूरी है, क्योंकि समाज के वर्गों में वर्गों के परिवर्तन की प्रक्रिया के द्वारा

वर्गहीन समाज की ओर ले जाना है। सँकड़ों नियम और उनके सम्बन्ध में बरते जानेवाले अपवादों का उद्देश्य यह है कि जहाँ तक हो सके, उत्पादन की प्रक्रिया को हानि पहुँचाये बिना, यहाँ तक कि उसमें वृद्धि करते हुए वर्गहीन समाज की ओर कदम बढ़ाया जाय। यद्यपि जैसा कि बताया गया, अनेक क्षेत्रों में शोषण को तरह दी जा रही है, फिर भी न तो इस बात को किसी भी समय भुलाया जा रहा है कि यह शोषण है, और न इस बात को ही भुलाया जा रहा है कि इसे दूर कर के ही दम लेना है। इस प्रकार जो बात आपात दृष्टि में शोषण को तरह देने के रूप में ज्ञात होती है, वह केवल एक सामयिक पैतरे के रूप में स्पष्ट हो जाती है, और नये वर्गीकरण से चीनी वस्तुवाद ज्ञात होता है।

थोड़े में यह बताया जा सकता है कि चीन के भूमि सुधार का क्या अर्थ है। एक तो सामन्तवादी रग-ढग लुप्त कर दिया गया है और सामन्तवादी मिल्कियत समाप्त हो गई है, और उसके साथ-साथ प्राचीन चीन में प्रचलित बेकार, तरह-तरह की लूटें समाप्त हो गयी हैं। अर्द्ध गुलामी अब भूतकाल की बात हो चुकी है। अकेले यही एक बहुत बड़ी बात है। स्वभाविक रूप से किसानों पर बोझ बहुत कम हो गया है। जमीन्दारी प्राचीन चीन में कितनी बड़ी बुराई थी, यह इन आंकड़ों से ज्ञात होगा —

वर्ग	कुल परिवारों का प्रतिशत	कुल जमीन का प्रतिशत
जमीन्दार	३	२६
धनी किसान	७	२७
मध्यम किसान	२२	२५
गरीब किसान	६८	२२

तो इस प्रकार ६८ प्रतिशत गरीब परिवारों के पास केवल २२ प्रतिशत जमीन थी। स्मरण रहे कि यह आंकड़ा खास चीन का है उत्तरी मचूरिया में तो हालत इससे भी गई-गुजरी है। वहाँ गरीब किसानों के ४३ फी सदी परिवारों के पास कुल ९ फी सदी जमीन थी। केवल इन आंकड़ों से ही सारी परिस्थिति साफ नहीं होती, क्योंकि बेगार और तरह-तरह की ज्यादतियों की बात इन आंकड़ों से ज्ञात नहीं होती। एक समय, साम्यवादी जमीन्दार और धनी किसान को एक ही वर्ग में गिनते थे, परा धीरे-धीरे उनकी राय बदल गयी और यह ठीक ही था क्योंकि चीन में कथित धनी किसान, रूम के कुलको, यहाँ तक कि मध्य किसानों की तरह, धनी नहीं थे। इस सम्बन्ध में यह बात नहीं भूलनी चाहिये कि चीन में यह निश्चित नीति रखी गयी कि खेती की प्रगति तथा औद्योगीकरण के आधार के रूप में धनी किसानवाली पद्धति की रक्षा करनी है।

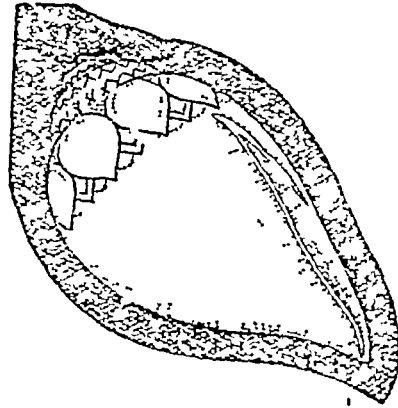
दूसरे शब्दों में कहा जाय तो चीन में भूमि सुधार का सारांश केवल इतना ही रहा कि सामन्तवादी घुरे रिवाजों को दूर कर किसान पर से आर्थिक बोझ हटा लिया जाय। बटाई करीब-करीब बन्द कर दी गयी, और इस प्रकार बहुत से लोग बैठकर ऐंश उड़ाते थे, उसे बन्द कर दिया गया। सेंटिहर मजदूरों को जन्मदा जमीन और औजार देकर

ऐसी परिस्थिति पंदा की गई है, जिससे खेतिहर वर्ग में सबसे परिश्रमी लोगो को देश की उन्नति में हाथ बटाने का मौका मिले। लगान और सब तरह के टैक्स घटाये गये हैं। यह एक बहुत बड़ी उन्नति है, क्योंकि प्राचीन चीन में इनका वीज सम्पूर्ण रूप से घातक था।

यह एक खास बात है कि चीन में लगान जिन्स में अदा किया जाता है। कई अन्य देहाती टैक्स भी ऐसे हैं, जो जिन्स में अदा किये जाते हैं। इस प्रकार से चीन में एक शब्द ही बन गया है—सार्वजनिक अनाज, जिसका अर्थ देहाती टैक्स हो गया है। उद्देश्य यह था कि नयी व्यवस्था में उत्पादन जारी ही न रहे, बल्कि उसमें वृद्धि हो। इसलिए जो भी बात की गई, वह इसी दृष्टिकोण से की गई। एक और बहुत ही ध्यान योग्य बात यह है कि ज्यो-ज्यो शहरी इलाको की उत्पादन शक्ति बढ़ती गई, और शहरी आय में वृद्धि होती गई, त्यो-त्यो उनकी करदान सामर्थ्य में वृद्धि के साथ-साथ उनपर टैक्स भी बढ़ता गया, और उसी अनुपात से सार्वजनिक अनाज या देहाती टैक्सों में कमी की गई। इस प्रकार शहरी उन्नति से देहाती को राहत मिली।

इस प्रकार हम यह देखते हैं कि १९५० के पहले वहा देहाती से सरकारी कोष को सबसे अधिक कर मिलता था, वहा १९५० में इसे दो दर्जा प्राप्त हो गया। पर यह तो स्पष्ट ही है कि जिस देश में राष्ट्रीय आय की ९० फी सदी खेती से आती है, वहा सार्वजनिक अनाज सरकारी कोष का एक महत्वपूर्ण स्रोत रहने के लिये वाध्य है। १९५० में भी राष्ट्रीय आय का ३७२ भाग सार्वजनिक अनाज के रूप में प्राप्त हुआ। १९५१ और १९५२ में शहरी आमदनी में वृद्धि के साथ यह फी सदीवाला अनुपात घट गया, फिर भी यह ३० फी सदी तो बना ही रहा।

सरकार का यह भी उद्देश्य रहा कि शहरी उपज और देहाती उपज के दामों में एक सुन्दर तारतम्य बना रहे। कही देहाती की आमदनी बढ़ने से शहरी उपज का दाम बढ़ न जाय, इसलिये देहाती की क्रय-शक्ति सामूहिक रूप से घटाने के लिये विजय बैंक बौड बंचे गये। पर यह समस्या बराबर बनी है। फिर भी सब बातों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि अवस्था में अभूतपूर्व उन्नति हुई है।



# वन्य-संस्कृति की आधारशिला

श्री जगदम्बा शरण राय

मात्र समाज जीवन पर्यन्त सम्पदा सचय में अर्हनिश व्यस्त रहता है। सम्पदा सचय का मुख्य उद्देश्य है भोग विलास तथा आत्म बड-प्यन का प्रदर्शन और तज्जनित आत्मतोष, आनन्द और शान्ति। जगत में सम्पदाएँ अनेक प्रकार की हैं। उनमें वन सम्पदा का भी एक विशिष्ट स्थान है। कुछ दिन पूर्व अज्ञानतावश इस प्राकृतिक वैभव का समुचित आदर नहीं हो रहा था। पर इधर वैज्ञानिक युग में इसके महत्त्व पर पुन जोर दिया जा रहा है जो समाज और राष्ट्र के कल्याण का शुभ लक्षण है। हमारे यहाँ तो सभार के प्राचीनतम ग्रन्थ वेद में इसकी महिमा पूर्णरूपेण वर्णित है। हमारे महर्षियों को ज्ञात था कि जलदाता मेघ के लिए वन का अस्तित्व कितना आवश्यक था। यही कारण है कि वैदिक साहित्य में वन शब्द का प्रयोग वादल के अर्थ में अनेक जगहों में हुआ है। संस्कृत साहित्य में वन का एक अर्थ "जल" भी होता है। आधुनिक वैज्ञानिकों का भी मत है कि वन की प्रचुरता से जलदों का शुभागमन आसानी से होता है। कारण वनराज में ऐसी कुछ शक्ति है जिसकी ओर मेघों का स्वाभाविक आकर्षण होता है। जहाँ-जहाँ वनों का अभाव होता जा रहा है वहाँ-वहाँ वर्षा की गमी दिनोदिन होती जा रही है। वर्षा की कमी हुई कि वन-वृद्धि रुकी। उम प्रकार वन और वनद ( जलद ) में अटूट सम्बन्ध जान पड़ता है। एक की क्षति में दूसरे में क्षति तथा एक की वृद्धि से दूसरे में वृद्धि होगी है।

एक प्रकार से जलदान होने के कारण वन का महत्त्व बहुत ही बढ़ जाता है और हमारे यहाँ इसी में वनवास की पतिष्ठा बहुत अधिक हुई। प्राचीन मनोषियों ने हमारे जीवन में करने योग्य धर्मों का समावेश पद-पर पर कर दिया है। सम्पूर्ण जीवन को चार भागों में बाटा, ब्रह्मचर्याश्रम, गृह्याश्रम, वानप्रस्थ और मन्थान। प्रथम भाग रखा गया जानार्जन के लिए और आश्रमों में शान्त चिन्तित हुआ नगर के वातावरण से दूर वन स्थानों में, तथा वास्तव्य आश्रमों में विद्याभ्यास कर मकें और नाथ-पार गीतों की शक्ति वृद्धि करने में भी अनुभव त्रियात्मक रूप में कर लें। गीतों का अर्थ है कि पुत्र वानान की व्यस्तता की गई थी जिससे वे अपने जीवन में ही वानप्रस्थ पर जायें। जिन वन को महर्षियों ने आश्रम माना है सो वन्य-वन्य पर महान शक्तिशाली ने तपस्या करने से वनवास में शान्ति प्राप्त की है। हमारा प्राचीन साहित्य

तो वनसम्पदा के महत्त्वों से भरा पड़ा है। जब किसी शूर वीर महान व्यक्ति की शक्ति में ह्रास हुआ कि वह शक्ति-सचय के लिये वन की ओर दौड़ता है, महाभारत, रामायण तथा पुराणों में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं।

जिस प्रकार समुद्र वेष्टित द्वीप के वासियों की शिक्षा तबतक पूरी नहीं समझी जाती है जबतक कि उन्हें सामुद्रिक जीवन का अनुभव नहीं हो जाय, उसी प्रकार हमारे देश के लिए "वनवास" का अनुभव आवश्यक था। यही कारण है कि जब भगवान रामचन्द्र को वनवास के अनुभव बिना ही राजसिंहासन देने की व्यवस्था राजा द्वारा हो गई थी तो कूटनीतिज्ञों ने बाधा डाली और रामको एक दो नहीं, पूरे चौदह वर्षों का वनवास दिलाकर योग्यतम भूपति बनाने का प्रवन्ध कर लिया। पांडवों की यही दशा थी। श्रीकृष्ण भगवान का क्रीडा क्षेत्र, ही नहीं कार्य क्षेत्र तो वन ही रहा। आप तो वनवासी नाम से भी पुकारे जाते हैं। गीत गोविन्द की यह पक्ति "वीर समीरे, यमुना तीरे बसति वने वनमाली" कितनी मधुर और सरस है सहृदय व्यक्ति अनुभव कर विचार विभोर हो जाते हैं।

वन में ही शिक्षा-दीक्षा की पूरी व्यवस्था होने के कारण वैदिक साहित्य के प्रधान भाग का नामकरण ही "आरण्यक" पड़ गया था जिसकी उत्पत्ति "अरण्य" (वन) शब्द से हुई है। उस समय यज्ञ का भी महत्त्व अत्यधिक था। प्रत्येक महान व्यक्ति कोई-न-कोई यज्ञ किया करते थे। यज्ञ करने का मुख्य उद्देश्य था जल प्राप्ति। विश्वास था कि यज्ञ से वर्षा होती है और वर्षा से घाम-पात, अन्न-फल होते हैं और अन्न-फल द्वारा प्राणियों के प्राणों की रक्षा होती है। शिक्षा विशारदों के हृदय में गीता का श्लोक वारार गूजता रहता था और गुरुगण अपने चेलों द्वारा वन में यज्ञ करवाने का आयोजन बिना अपना कार्य अवधूरा समझते थे।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नमभव।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्मममुद्भव।।

अन्न में सम्पूर्ण प्राणी होते हैं और अन्न की उत्पत्ति यज्ञ से होती है और यज्ञ में वृष्टि होती है और यज्ञ कर्मों में उत्पन्न होता है।

कविमुद्र गुप्त कालिदान ने अपने अभिज्ञान शाकुन्तल नाटक में वन सम्पदा की महत्ता को उच्चतम शिखर पर विठाने का सफल प्रयास

किया है। वनलता के समक्ष कृत्रिम उद्यानलतिका निष्प्रभ हो जाती है। राजा दुष्यन्त की दृष्टि में भी वल्कल भूपिता वन पालिता शकुन्तला स्वर्ण प्रासाद की अनुपम रमणियों से श्रेष्ठतर जचती है। पुन वीर प्रसवा शकुन्तला का पचवर्षीय वीर पुत्र भरत वन में सिंह सावक के साथ खेलता पाया जाता है। उसी प्रात स्मरणीय पुरुष पुगव राष्ट्रपति भरत के नाम पर इस महान देश का नाम "भारत" पडा है। धन्य है हमारी वन सम्पदा। और धन्य है वन सम्पदा को चित्रित करनेवाली कालिदास की अनोखी लेखनी। हमारे साहित्य में वन सम्पदा का वर्णन अनेक स्थलों पर सूक्ष्म रीति से वर्णित है। कोई समय था जब कवि की कविता तब तक पूर्ण नहीं समझी जाती थी जबतक वन-वैभव की चर्चा उनकी कविताओं में नहीं आती। जब नगर वास का प्रचार अत्यधिक बढ़ा तब वन अपना रूप उपवन वृहत्वाटिका धारण कर वैभवशाली व्यक्तियों का विहार-स्थल बन गया। हिन्दी के कवि सम्राट, कवि रवि तुलसीदास जी ने तो रामायण का एक कांड ही "आरण्य" के नाम से रच दिया और वन की प्रशंसा करते-करते कभी अधाते नहीं थे। आपकी अधोलिखित चौपाइया इस सम्बन्ध में पठनीय और मननीय हैं।

वेलि विटप सब सफल सफूला। बोलत खग-मृग अलि अनुकूला।  
तेहि अवसर वन अधिक उछाहू। त्रिविध समीर सुखद सब काहू।

वन सम्पदा की उपादेयता अकथनीय है। अकथनीय इसलिए है कि जिस सम्पदा को हम एक समय सम्पदा नहीं समझते, वही कालक्रम से अमूल्य सम्पदा सिद्ध हो जाती है। आज विज्ञान युग में तो वन सम्पदा का महत्त्व पद-पद पर अनुभव होने लगा है। आज तक वन की जिन साधारण वस्तुओं की हम उपेक्षा कर रहे थे वही आज विज्ञान युग में बहुमूल्य प्रमाणित हो रही है। जिस जगली घास-पात को हम नाबीज समझ नष्ट होने देते थे आज उसी घासपात से हम सुन्दर-से-सुन्दर कागज प्रस्तुत कर सकते हैं और कल-कारखाने खोलकर अपने राज्य को वैभवशाली बना सकते हैं।

हमारे विहार में जितने वन भाग की आवश्यकता है, कम है। कहा जाता है जलवायु के विचार से तथा आर्थिक दृष्टिकोण से किसी देश की भूमिका पाचवा भाग जगल होना चाहिये। विहार में लगभग सातवा भाग जगल है। १९४६ ई० के पहले तक लगभग ९ हजार वर्गमील वन जमीन्दारों के नियन्त्रण में था। उसके प्रबन्ध में हस्तक्षेप करने का अधिकार सरकार को नहीं था। राष्ट्रीय दृष्टि में वनों का महत्त्व नहीं जानने के कारण जमीन्दार वन का विनाश कर रहे थे और अपनी आय के ख्याल से जगल काट-काट कर जलावन तथा अन्य कार्य के लिये लकड़िया बच रहे थे पर उनके मन में कभी भी वृक्ष रोपने का विचार तक नहीं उठा। कांग्रेस मन्त्रिमंडल १९४६ ई० में ज्योंही वना कि मन्त्रिमंडल का ध्यान इधर गया। वनोन्निति सुधार कार्य में माननीय कृष्णवल्लभ सहाय जी का प्रबल हाथ रहा। आपने देखा कि भारतीय वन विधि (कानून) सरकार के लिये उतना सहायक नहीं हो रही है। अतः सटपट एक विहार अराजकीय वन कानून बनाया गया जिसमें ९ हजार वर्गमील अराजकीय वन राजकीय अधिकार में आ गए। माय-ही सरायकेला-खरनावा के विहार में मिल जाने से वहाँ की ३ वर्गमील

वन भूमि विहार राज्य के प्रबन्ध में आ गई। इस प्रकार विहार में १३ हजार वर्गमील से अधिक वन राजकीय अधिकार में आ गए हैं।

विहार के वन प्रधानत छोटानागपुर के सभी जिलों तथा सताल परगने में हैं। मुंगेर, सहर्पा, पटना, गया और शाहाबाद जिलों में भी कुछ जगल है। चम्पारण और पूर्णिया के उत्तरी हिस्सों में भी कुछ जगल पाया जाता है पर वह नग्न्य हैं।

सरकारी नियन्त्रण में आने से वनों की रक्षा के लिये अनेक कर्मचारी नियुक्त हुए हैं और नई-नई योजनाएँ बनी हैं। वन सम्बन्धी वैज्ञानिक शिक्षा देने के लिए वन विद्यालय भी खुले हैं, जहाँ अनेक विद्यार्थी वन प्रशिक्षण में प्रशिक्षित होचु के हैं। वन विद्यालय के नजदीक ही पीवा घर भी रखा गया है। जहाँ वन के उपर्युक्त पीवें तैयार किये जाते हैं तथा समय-समय पर नये-नये वन लगाने का प्रबन्ध हो रहा है। ऊँची शिक्षा के लिये देहरादून वन महाविद्यालय कुछ छात्र प्रतिवर्ष भेजे जाते हैं।

विहार के वनों में साबे घास और वास अधिक परिमाण में मिलते हैं। उनकी उपज भी बहुत अधिक बढ़ाई जा सकती है। विहार में आसानी से कागज के कारखाने चल सकते हैं। कारखाने के अभाव में आजकल कागज बनने के लिए साबे घास और वास कलकत्ता भेजे जाते हैं। डालमियानगर के रोहतास पेपर मिल को पलामू विभाग के वनों का ठेका वारह वर्षों के लिए दे दिया गया है। इसी प्रकार एक ठेका इटिया पेपर पल्प कम्पनी को भी दिया गया है। विहार में कोमल काटों की बहुलता है। मेमल की लकड़ी में दियासलाई की थलाकाए, वक्से तथा पार्मल के वक्से बनते हैं। विहार में दियामलाई की थिल्यशाला नहीं रहने के कारण ये लकड़िया बाहर भेजी जाती हैं। इसके अतिरिक्त विहार के जंगलों में अनेक प्रकार की कोमल लकड़िया पाई जाती हैं जिनमें नाना प्रकार के मनमोहक खिलौने और उपयोगी सामान बन सकते हैं। साल या सखुआ तो प्रसिद्ध लकड़ी है जो स्थायित्व के लिए लोहे से भी लोहा लेता है। भवन निर्माण में इसकी उपयोगिता अकथनीय है। पिमाल, गभार, करम आदि भी ऐसी ही उपयोगी लकड़ी हैं। खैर नामक वृक्ष में खैरकय तैयार किया जाता है। आसन, वँर, पलाम, कुमुम, खैर आदि वृक्षों पर तमर और लाह के कीड़े पाले जाते हैं और बाद में तसर और लाह प्रस्तुत की जाती हैं। कहा तक गिनाया जाय वन का एक-एक वृक्ष, एक-एक पीवा, एक-एक डाली नहीं एक-एक पत्ता प्राणियों के सुख मायन में आ सकता है। चाहिये केवल इच्छा, नरक्षण और प्रबन्ध।

वनस्पतियों, औषधियों तथा जड़ी बूटियों के लिये भारत का वन प्रसिद्ध है। इतिहास प्रसिद्ध है कि लका में लदमण जी को मेघनाद के यवित वाण द्वारा आहत होने पर वैद्य सुवैज जी को जड़ी-बूटी धौलागिरि के वन में ही मगानी पड़ी थी। आज भी जड़ी-बूटी के द्वारा प्रतिदिन लाखों व्यक्तियों के दुख दूर हो रहे हैं और उन्हें आत्म-संतोष मिल रहा है। एतदर्थ वनस्पतियों का नरक्षण तथा वैज्ञानिक अनुसंधान आवश्यक है। मुना जाना है कि गया के निकट पहाड़ियों को वनस्पतियों में ढक देने की व्यवस्था सरकार के द्वारा हो रही है।

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है। कृषि के लिए पशुधन भी अत्यन्त आवश्यक है। पशुओं के लिए पर्याप्त चारागाह चाहिये और चारागाह के



लिये वन अत्यन्त ही उपयोगी होता है। सरक्षण के आघार पर भेंड़-वकरियों द्वारा तथा गाय-बैलो के लिये वन भाग चारागाह का काम देता है। उचित व्यवस्था करने पर चारागाह के क्षेत्र कई गुणा बढ सकते हैं। वैज्ञानिको ने जाच द्वारा प्रमाणित कर दिया है कि गौओ का गोबर-मूत सर्वोत्तम खाद है। इसके प्रयोग के बाद खेत की उर्वरा शक्ति में कभी किसी प्रकार की शिथिलता नही आती है। परन्तु हमलोग अधिकतर गोबर को जलावन के रूप में उपयोग करते हैं। यदि वन की लकडियो को हम जलावन के काम मे लगाने का प्रबन्ध कर दे तो गोबर का उपयोग खाद मे हो जा सकता है।

हमारे यहा प्राचीन काल मे वन सम्पदा का महत्त्व अत्यन्त अधिक था। विद्याध्ययन करना हो तो वन जाओ, शक्ति सचय करना हो तो वन जाओ, वैराग्य धारण करना हो तो वन जाओ, समाज के कल्याण की कामना हो तो पहले वन जाकर कल्याण कार्य मे प्रशिक्षित हो जाओ, वैद्य होकर देश कल्याण करना हो तो वन सम्पत्तियो के अध्ययन के लिये वन जाओ।

देश सेवा व्रत के लिये भी घर द्वार छोडकर वनवास का अनुभव करना जरूरी था। राजा तथा वैभवशाली व्यक्ति गण जलवायु परिवर्तन तथा मृगया के लिये नियमपूर्वक वनो की शरण मे जाया करते थे। विद्वानो और महर्षियो की आवास भूमि आज की तरह नगर नही वन प्रदेश ही था। बड़े-बड़े राजा तथा राजनीतिज्ञ शिक्षा और उपदेश के लिए वन बिहार ही किया करते थे। पराजित और निष्कासित पराक्रमी पुरुषो का भी आश्रय स्थान वन ही था। हाल तक अरणा और बाघ के शिकार के लिये भागलपुर जिले का वनैली राज घराना विख्यात था। भूतपूर्व वनैली के भूपतियो को शिकार का अनुपम प्रेम था। प्रतिवर्ष वे हाथी पर चढ कर शिकार करने जाया करते थे।

वन जीवन के बहिष्कार से तथा नागरिक जीवन में लिप्त रहने के कारण जन मत्स्या दिन दुनी रात चौगुनी बढ रही है। जिससे विश्व कल्याण के समर्पणो तथा शासन भूत धारियो का माया ठनक रहा है और जन्म निन्धे के अनेक उपाय सोचे जा रहे है तथा जन्म निरोध यन्त्र प्रस्तुत कराकर विनापन करवा रहे है। ब्रह्मचर्याश्रम और वानप्रस्थाश्रम जनन

नियन्त्रण का अमोघ शस्त्र था। क्या सरकार और विश्वशान्ति समिति इस दिशा में विचार करने का कष्ट करेगी ?

हर्ष का विषय है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हमारी जन सरकार वन-सम्पदा के सरक्षण तथा उन्नयन के लिए पूर्ण रूप से सचेष्ट है। नये-नये जगल लगाने का आयोजन हो रहा है। इसके लिए वजर भूमि की पैमाइश का कार्य आरम्भ हो गया है। राज्य भर में सुसगठित ढग से वन व्यवस्था करने के लिए एक बीस वर्षीय योजना तैयार हो रही है। आशा है बीस वर्षों में हमें कृषि भूमि के साथ-साथ वन भूमि का सुसगठित दृश्य देखने में आयेगा और हम बिहारवासी वन-सम्पदा से उचित मात्रा में लाभ उठा सकेंगे। मेरा तो निश्चय मत है कि इन वन प्रदेशो में यत्र-तत्र कुछ विद्यालय ऐसे खोले जाय जहा छात्र निश्चित अवधि तक शिक्षा प्राप्त कर ही घर लौटें और इन छात्रो को पाठ्यक्रम विशेष विषयो के विशेष उद्देश्यो पर ही निर्धारित रहे। गांधी जी के स्वप्न स्वरूप राम राज्य को साकार करने में वन सम्पदा भी प्रबल सहायिका होगी।

बिहार राज्य में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १९० योजनाएं कार्यान्वित हो रही है जिनका कुल व्यय ५७ करोड ३२० लाख १० हजार रुपये हैं। इनमें १ करोड २५ लाख रुपये वन वैभव विकास के लिए सुरक्षित है। यदि इन रूपयो का सदुपयोग ठोस ढग पर किया गया तो विकसित वन वैभव का मूल्य पचास करोड से भी अधिक हो जा सकता है तथा वन वैभव बिहारवासियो के सुख-साधन का एक अंग हो जायेगा। क्या ही अच्छा हो यदि सरकार प्रत्येक वृहत्वन में वन बिहार और वन यात्रा का प्रबन्ध कर दे। मैसूर राज्य के सुरक्षित वन में इस प्रकार का सुप्रबन्ध है कि यात्री मोटर पर चढकर वन की परिक्रमा कर लेते हैं तथा मार्ग में वन की प्राकृतिक शोभा के साथ-साथ वनैले जन्तुओ का भी दर्शन कर लिया करते हैं। सुरक्षित वन में वनैले पशु भी सुरक्षित रहते हैं। बिहार में जहा तहा बानरो का उत्पात इतना अधिक हो गया है कि उन्हें यमपुरी पहुचाने के लिये अधिकारियो द्वारा पुरस्कार दिया जाने लगा है। वनो के विकसित तथा फलवान वृक्षो से सम्पन्न होने पर वानर स्वयं वनवासी बन जायेंगे और हमारी समस्या भी हल हो जायगी। वन प्रदेश में यदि निवास की सुविधा दी जाय तो वानप्रस्थी लोग शान्ति के विचार से नगर के बदले वन की ओर ज्यादा झुकेंगे और वन प्रदेश फिर जगमगा उठेगा तथा वनचर वनवासी शिक्षित वृद्ध जनो के सम्यक द्वारा शीघ्र ही आगे बढ जायंगे।



# आज के चीन की भूमि

और

## श्री तारकेश्वर प्रसाद वर्मा किसानों की समस्याएं

मिट्टी का मोह जहा मानव की मानवता का प्रतीक है वहा मिट्टी पर चील—क्षपट्टा की दानवी प्रवृत्तिया एव लोलुपता तानाशाही के ताडव नर्तन का मूचक है। निज राष्ट्र की सार्वभौम सत्ता की स्वार्थमयी युक्तियों और पडयन्त्रो द्वारा विश्व के रग-मच पर कुशल राजनीतिज्ञ अभी तक अभिनय करते आ रहे हैं। और इस शतरज की चाल में कितने मात होकर मिट गये। फलत असह्य राष्ट्रों के वक्षस्थल चीरा जाकर उनकी शव परीक्षा हुई। फिर उनके गर्म खून से मिट्टी की लहलहाती दूवों को खाद मिला अवश्य पर खेतों की कल्याणी रानी के सुहाग सिन्दूर लुट गए।

उधर जुलाई सन् १९४० में इटली ने सम्राट हेली सेलासी को कैद कर अवीसीनिया की भूमि पर आधिपत्य स्थापित किया। गेस्टापो और गोबेल्स जैसे कूटनीतिज्ञों का सह पाकर भी नाजीज्म का अग्रदूत हिटलर रूस का शिकार हुआ। जनता का कोपभाजन होकर इटली का भाग्य—विघाता मुसोलिनी अपमानपूर्वक मार डाला गया। सम्राट हिरो-हितो का जापान एक अणुबम के विस्फोट से रसातल पहुच गया। सक्षेप में, भूमि पर आधिपत्य की भयकर भावना ने सारे सत्तार का नक्शा बदल दिया।

पर हमारे भारत की मिट्टी पर विदेशी मत्ता की सनसनाती तोपें टकरा कर ठप हो गई। बड़े-बड़े बम के गोले गल गए। उनकी कूटनीति असफल हुई। मत्य-अहिंसा ने स्वतंत्रता संग्राम में विजय पायी। फिर हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हमें प्राप्त हुआ। अब हिमालय के शिखर पर राष्ट्रीय ध्वजा उडती है। सागर की उत्ताल तरंगों में राष्ट्रीय गीतों के मीठे कलरव सुनाई पडते हैं। अन्य श्यामला वसुन्धरा मुक्त वातावरण में स्वतंत्रता की साम ले रही है। धरती तो अपनी है ही चाद-सितारे और नरिता-गिला भी अपने लगते हैं।

इन प्रकार भारत के साथ ही दूर क्षितिज के अन्य राष्ट्रों में भी स्वतंत्रता की किरणें फूट पडी।

### चीन पर आक्रमण

इधर चीन भी जापानी आक्रमणों से आक्रान्त और जर्जर हो गया था। मार्शल च्यांग काई शेक की आठवी स्ट्रार्मी ने जापानियों के छक्के छुडा दिए। गोरिल्ला कौराल दिखानेवाले माओत्से तुंग, सेनापति चू-तेह, पेग तेह खाई, हो लग, लिन आव, चाउ एन-लाई आदि वीरों की धीरता, चतुरता और दृढता ने जापानियों के दात खट्टे कर दिये।

इस प्रकार कई वर्षों तक प्रजातंत्र चीन ने च्यांग काई-शेक के सारक्षण में शत्रुओं से लोहा लेकर चीन की मिट्टी को मटियामेट होने से बचाया। फासिस्टों को नाको चने चवाने पडे।

### आज का स्वतंत्र चीन

अन्ततोगत्वा सन् १९४९ ई० के दिमम्बर में चीन की मिट्टी को भी प्राची की किरणों ने चूम लिया। वहा की मिट्टी-मिट्टी स्वतंत्रता की लौ से जल उठी, बल उठी। चीन की भूमि में यह स्वर्णिम विहान और सुन्दर प्रभात लाने का श्रेय है कम्यूनिस्ट पार्टी और नेट्रल पिपुल्स गवर्न-मेंट, कम्यूनिस्ट दल और केन्द्रीय लोक शासन को। माओत्से तुंग आज वहा का चेरमैन है। वह स्वयं किमान का बेटा है जिनके मर पर कुछ वर्ष हुए, च्यांग काई शेक ने दो लाख चादी के डालर घोषित किया था। विद्व के इतिहास में किसी भी एक व्यक्ति के सर पर इतना बडा इनाम नहीं घोला गया। उन्ही दिनों में वह गरीब, भूखे, घोषित, और अनपढ किमानों का नेता बनता आ रहा है।

जनतन्त्रात्मक चीन की स्थापना के साथ ही ग्राम्य नुवार की लहर दौड गई। उनके कण-नाण में विद्युत चू गया। कृषि का विकास अपनी चरम सीमा तक पहुच गया। कृषकों के भूमि कर का अन्त-मा हो गया। कृषि सम्बन्धी शोजारों की उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। जमीन्दारी प्रथा का नवनाश हो गया। निर्वनता और दिवालियापन दूर हुआ। महफारी नमिति और पारस्परिक सहायक दलों का निर्माण हुआ। कृषकों के मान-

मिक विकास के लिए अव्ययन-निकेतन की स्थापना हुई। अनावृष्टि के विरुद्ध नहर और बाघ द्वारा सघर्ष चला। वैज्ञानिक रीति द्वारा कृषि कार्य के विशेष ज्ञान के जरिए राजकीय फार्म आयोजित कर प्रदर्शन और प्रवचन हुए। ग्रामीण शिक्षुओं के स्वास्थ्य के लिए गाव-गाव में आरोग्य कुटीर जाल से विछ गए।

इस प्रकार चीन की सर्वांगीण प्रगति हुई। जनता में एकसूत्रता की भावना बलवती हो गई। इस विकास और सुधार के लिए पहली अक्टूबर सन् १९४८ ई० से ही चीनी और अमेरिकन ज्वाएंट कमीशन कार्य कर रहा है। इस सस्या ने चीन में नवचेतना और जागरण लाने के ध्येय से सन १९४९ में अपने पूर्व कार्यक्रम में परिवर्तन लाने का निश्चय किया।

इस प्रकार आधुनिक चीन के विकास में तत्कालीन राष्ट्रीय सरकार को हाथ बटानेवाली इस सस्या का स्थान सर्वोत्कृष्ट है। तो आइए, पहले हम आपको चीनी और अमेरिकन संचालित जे० सी० आर० आर०० ज्वाएंट कमीशन आन रूरल रिक्तसट्रक्शन इन चाइना के कार्यक्षेत्र में ले चले।

### ज्वांयंट कमीशन का अनुभव

(१) उत्तर चीन पर विजयी होकर कम्यूनिस्टो ने नानकिंग, शघाई और हाको पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। राष्ट्रीय सरकार कैंटन चली गई है जहा ज्वाएंट कमीशन ने अपना प्रधान केन्द्र रक्खा है। चीन के विस्तृत विकास के लिए तीन से पाच वर्ष की अवधि अनिवार्य है। अस्तु विशेष कार्यक्रम द्वारा ही यह कार्यान्वित हो सकता है।

(२) केवल दो बातों पर ही राष्ट्रीय चीन कम्यूनिस्टो के पजे से मुक्ति पा सकता है वह यह कि देश में सैनिक सगठन हो। राष्ट्रीय चीन का कुछ भाग अधिकार में रहे, अच्छे शासन की व्यवस्था हो, जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाय और उस क्षेत्र का आन्तरिक संरक्षण शकल हो।

(३) स्थानीय जनता ने लुगिएन योजना का हार्दिक स्वागत किया है जो भूमि सुधार का कार्यक्रम राष्ट्रीय सरकार की देखरेख में वर्षों से चला रहा था।

(४) क्वाग तुंग प्रान्त की रैयती जमीन की दशा दयनीय है। वहा कमीशन ने उच्चाधिकारियों ने देखा है कि स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई योजनाओं ने उपतों की अपेक्षा जमीन्दार ही लाभान्वित हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जमीन्दार और रैयत के सम्बन्ध में सुधार लाना आवश्यक है। रैयतों के कनिष्ठ अधिकारों का आश्वासन अपेक्षित है।

अतः कमीशन जेञ्चान और क्वागनी में शान्त वर्ग के अधिकारियों ने मिन्तर एक व्यापक कार्यक्रम पर विचार-विमर्श करे। यदि ऐसा सम्भव न हो तो कमीशन का अन्तिम मिटा दिया जाय।

### घोरणा पत्र

जो मार्ग भी विचार-निर्माण के लिए कमीशन ने कम्यूनिस्टो के साथ-साथ (मैनिफेस्टो) तैयार किया जिनमें

(१) कम्यूनिस्ट सरकार जहा समस्त चीनी जनता के कल्याण के लिए प्रभावशाली कार्यक्रम तैयार कर रही है वहा यह कमीशन भी हाथ बटाने को तैयार है।

(२) कमीशन को विश्वास है कि उत्साहपूर्ण एवं निश्चित प्रयास द्वारा थोड़े ही समय में कतिपय क्षेत्र प्रमुख पर सीमित साधनों का निदान कर आशातीत प्रगति लाई जा सकेगी।

(३) अधिकांश योजनाओं को दृष्टि में रखते हुए बड़े पैमाने पर निम्न कार्य अपेक्षित है

(क) राष्ट्रीय सरकार के वर्तमान कानून के अनुसार भूमि कर की न्यूनता और रैयतों का काश्तकार का अधिकार कई वर्षों तक, फसल कटने तक, सुरक्षित रहे जिसका संचालन प्रान्तीय सरकार सुचारु रूप से करती रहे।

(ख) निम्न कृषक सस्याओं एवं सगठनों का सरकारी सहयोग अपेक्षित है

भूमि सुधार स्वयं रैयतों द्वारा कार्यान्वित हो और किसान स्वामित्व प्राप्त करें। सम्मिलित रूप में किसान कृषि ऋण ले सकें, ग्रामीण उद्योग-धंधे चलावे, घर और खेती सम्बन्धी चीजें खरीद सकें, खेत की उपज बेच सकें, और वे स्थानीय सस्याओं द्वारा कृषि, स्वास्थ्य और वयस्क शिक्षा में उन्नति कर सकें।

(ग) सिंचाई।

(घ) पशुओं की बीमारी का समुचित उपचार। सूअर के रोगों की परीक्षा पर विशेष ध्यान।

(ङ) ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार। मलेरिया रोक पर विशेष ध्यान और स्वास्थ्य सस्याओं की उन्नति।

(ज) पुष्ट बीज, विशेष कर चावल, गेहूँ, चुकन्दर और कपास की वृद्धि और वितरण।

(झ) नागरिकता, शिक्षा और व्यावहारिक वैज्ञानिक ज्ञान का प्रचार-श्रवण-दर्शन (आडियो विजुअल) माध्यम से ही हो।

(४) सहायता के निश्चित रूप जिसे कमीशन ने अपने कार्यक्रम में रक्खा है वे निम्नलिखित रीति से संचालित हो

(१) शिल्प कला सबकी चीनी और अमेरिकन विशेषज्ञों का प्रदान जो नियुक्तियों को यथासाध्य कार्यान्वित कर सकें।

(२) आर्थिक विकास सम्बन्धी युक्तियों के कार्यान्वित करने के निमित्त कुछ विशेष कोष की व्यवस्था जो प्रान्तीय अथवा स्थानीय साधनों से उपलब्ध हो सके।

### स्वीकृत नव योजना की कार्यवाही

तत्कालीन सरकार ने कमीशन की नई युक्ति की स्वीकृति दे दी। अतः क्वागनी, जेञ्चान और फारमोसा में २७ जून को यह कार्यक्रम आरम्भ हुआ। पर, 'मैनिफेस्टो' में कुछ परिवर्तन हुए और स्थानीय सरकार के

सहयोग से सर्वसाधारण ग्राम्य जनता को पूर्ण रूप से सहायता देने के लिए उचित कानून के प्रयोग पर महत्त्व दिया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत नमन योजनाएँ थीं जिनमें भूमि सुधार का स्थान विशेष महत्वपूर्ण है।

आधुनिक चीन में भूमि सुधार की समस्याएँ डा० सनयात सेन के समय से ही सुलझाई जा रही हैं। उनका उद्देश्य था, "जो जोते उसकी जमीन"। इसमें साम्यवाद का पुट अवश्य था पर हरजोता किसानों और श्रम-मजदूरों को प्रधानता देकर एक प्रकार से "दिहाती सर्वहारा" का एकाधिकार स्थापित करने का सफल प्रयास था। इसके द्वारा कमीशन को सुधार क्षेत्र में काम बढ़ाने का सुअवसर मिला। अतः उक्त स्थानों में प्रतिशत चीनी जनता पर प्रयोग करने का अधिकार मिला। चार-पाच जमीनों में ही चार-पाच लाख खेत खलिहानवाली जनता को लाभ हुआ। अक्टूबर-दिसम्बर १९४९ से प्रधान चीन के कम्युनिस्टों के आधीन आते ही कमीशन की प्रगति शिथिल पड़ गई।

तत्पश्चात् १९४९ ई० के वसंत में राष्ट्रीय सरकार की स्वीकृति तथा सहयोग से कमीशन ने फारमोसा में सुधार आरम्भ किया। स्थानीय सरकार ने किसानों की उपज का ३७.५ प्रतिशत ही कर निश्चित किया तथा भूमि पर का उनका अधिकार विशेष सुरक्षित बना दिया। किसानों और जमीन्दारों के बीच नया पट्टा हुआ जो ३ से ६ वर्ष तक, स्थानीय कृषि अवस्था के अनुसार, चलने को था। यह निश्चय हुआ कि उक्त अवधि की समाप्ति के बाद सरकार की स्वीकृति पर ही पुराना पट्टा का अन्त होगा। अनुचित रूप से रुपये पेशगी देनेवालों को सजा की घोषणा हुई।

कमीशन के इस कार्य में स्थानीय खेतिहरों, निरीक्षकों, रजिस्ट्रारों, किरानियों और श्रमीनों को शिक्षा दी गई जिन्हें भत्ता मिलता था। उनका काम था भूमि सबधी विज्ञापनों का प्रकाशन कर उनका उचित वितरण कराना, भूमि पर उचित अधिकार का निरीक्षण करना और कानून का प्रयोग सामूहिक रूप में कराना था।

इस रीति से करीब ३५०,००० खेतिहर किसानों को लाभ पहुँचा। किसानों की मुख्य उपज और तत्सम्बन्धी कर की जानकारी के लिए सरकार ने जोती हुई भूमि को २६ वर्षों में विभाजित कर दिया।

### कमीशन के प्रशंसनीय कार्य

इस प्रकार भूमि सुधार के बाद कमीशन ने कृषकों की आवश्यक समस्याओं को दूर किया। कृषकों का मगठन हुआ, आदर्श खेती का आयोजन हुआ, चीनी रेशम उद्योग का विकास हुआ, गाव-गाव 'जनता आरोग्य संचालन' (पब्लिक हेल्थ ऐडमिनिस्ट्रेशन) द्वारा स्कूली बच्चों को यक्ष्मा रोक की सूई दी गई तथा घाड़ियों और परिवारिकाओं द्वारा कमीशन निर्मित स्कूलों के छात्रों की मेवा-शुश्रूषा और उनकी मा-बहनों को उचित परामर्श और औषधि दी गई। इनके अतिरिक्त चारों ओर चाटों तथा मानचित्रों द्वारा मलेरिया के कीड़े का इतिहास बताया गया और कीड़े-मकोड़ों की चिकित्सा करवाई की गई तथा दीवार पत्रों द्वारा ग्राम्य सुधार की प्रगति

का इतिहास दिखलाया गया। विशेष उल्लेखनीय जो सुधार हुआ वह था नहर और सिंचाई का।<sup>१</sup>

### कमीशन-सुधार कम्युनिस्ट सरकार की पृष्ठ भूमि

इस प्रकार कमीशन सन् १९५० ई० के सितम्बर तक भूमि सुधार और कृषक समस्याओं के हल में जुटा रहा। इसका सफल मंचालन कर रहे थे चीनी प्रारम्भिक समस्याओं को सुलझानेवाले अनुभवी तथा पीकिंग युनिवर्सिटी के २६ वर्षों तक के चान्मलर एव शिक्षा सचिव डा० चियांग मीन लिन, चीनी राष्ट्रीय कृषि अन्वेषण मंडल के भूतपूर्व डाइरेक्टर डा० शे-शुग-हू, बीस-तीस वर्षों तक चलनेवाले सामूहिक शिक्षा आन्दोलन के जन्मदाता डा० वाई० सी० जेम्स येन, पन्द्रह वर्षों के कृषि कार्यक्रम संचालित करनेवाले डा० रेमाड टी० मोयर, और तीस वर्षों से अधिक समय तक अन्तर्राष्ट्रीय अकाल रिलीफ और अमेरिकन रेड क्रॉस के कर्मठ कार्यकर्ता डा० जान अर्ल वेकर।

कमीशन द्वारा भूमि सुधार आज के चीन की सारी समस्याओं के स्पष्टीकरण में बड़ा सहायक है। वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार ने उन्हीं समस्याओं की ओर ध्यान केन्द्रित कर इन तीन वर्षों में ही अप्रत्याशित अत्युदय प्राप्त किया है। प्रगति अपनी चरम सीमा तक पहुँच गई है। इस अल्पकाल में ही चीन ने जो प्रगति की है उसे देखकर, श्रीमती विजयालक्ष्मी पंडित के सरक्षण में भारत से गए, भारतीय सांस्कृतिक डेलीगेशन अवाक रह गया। अपने धन-धान्य पर गौरव का अनुभव करते हुए माओत्से-तुंग ने कहा था "भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और भारतीयों के सामने अभी तक पूर्ण रूप से अल्प-व्यय की समस्याएँ सुलझ नहीं पाई हैं। ऐसी परिस्थिति में, चीन और भारत के प्राचीन सांस्कृतिक सवध को दृष्टि में रखते हुए, मैं सरकार और जनता की ओर से भारत से आनेवाले किमी भी सस्या के लोक दल को चीन में स्थान दे सकता हूँ।"

### वर्तमान कम्युनिस्ट सरकार और ग्राम सुधार

तो आइये, अब माओ सरकार की भूमि में लें चले आपको।

कम्युनिस्ट सरकार के आते ही उसके मम्मख अनेक समस्याएँ आ खड़ी हुईं। कमीशन द्वारा मंचालित दो-तीन स्थानों को छोड़कर जापानी आक्रमण के फलस्वरूप सर्वत्र वही सर्वनाश दीख रहे थे, जनता क्षुधा में तटप रही थी, शूली पर झूल जानेवाले शहीदों की याद में विधवाओं का प्रलाप गूज रहा था, धरती माना विरहिन बन गई थी और नृजीपतियों का नृशन अत्याचार असह्य हो चला था।

ऐसी परिस्थितियों में कम्युनिस्ट पार्टी ने नवमे पट्टे जो कार्य किया वह था जमीन्दारी उन्मूलन। जमीन्दारों के अत्याचार में रैयतों की दशा युग-युग में गोचनीय होती आ रही थी। चीन की अधिकांश भूमि जमीन्दारों के अधिकार में थी। गमन्त जमीन्दार वर्ग के तून में विमानों के प्रति अपहरण और अत्याचार की भावना दीड नहीं थी। नाल भर

<sup>१</sup>शुगिंगन लील की धान भूमि नई बाघ द्वारा उर्वर बनाई गई। इस क्षेत्र को "चावण का कटोरा" कहते हैं। उन बाघों में ५००,००० एकड़ भूमि धान के पौधों में लहंगा उठे है।

खेतों में पसीनों के मोती बोनो पर भी वे अन्न के एक-एक दाना के लिए ललच रहे थे। उन्हें जो भी अन्न प्राप्त होता वह भूमि कर में शोष हो जाता।

पुराने स्वतंत्र क्षेत्र में सन् १९४६ ई० से ही जो भूमि सुधार हुआ था उससे यह स्पष्ट हो गया था कि जमीन्दारों के भूमि आधिपत्य तथा अर्द्ध भूमि आधिपत्य का उन्मूलन ही सभी समस्याओं का एकमात्र निदान है। सन् १९५० ई० के जून को ग्राम्य सुधार कानून पास हुआ। इसके अनुसार जमीन्दारों से जमीन छीन ली गई और सब किसानों को दे दी गई। इसके द्वारा नवीन चीन में औद्योगीकरण का सूत्रपात हुआ।

वाद सन् १९५० ई० के शरद काल में राष्ट्रव्यापी ऐतिहासिक भूमि सुधार आन्दोलन आरम्भ हुआ। सन् १९५२ ई० के अगस्त तक चीन के ग्राम्य जनावास के ९० प्रतिशत क्षेत्र में यह सुधार लाया गया। जमीन्दारों की ४७ लाख हेक्टेयर भूमि ३०० लाख ऐसे चीनी किसानों में बाट दी गई जिन्हें बहुत थोड़ी जमीन थी या उसका सर्वथा अभाव था। अब इन किसानों को जमीन्दारों को कर नहीं देने पड़ते जिसकी रकम पहले नाज का ३० लाख टन था। बेचारे किसान जो पहले खेतों को केवल जोतते-बोते थे अब पूर्णतः स्वामी बन गए हैं। अब वे जमीन्दारों की सेवा-टहल से मुक्त हो गए हैं और पहले की अपेक्षा वृहत्तर और सुन्दरतर अन्न उगाने लगे हैं।

### पारस्परिक सहायता और सहयोग समितियाँ

छोटे पैमाने पर की खेती से निर्धनता और दिवालियापन दूर होने को नहीं था। इसलिए कृषि उत्पादन के स्तर को ऊँचा करने के ध्येय से लोक-शासन ने पारस्परिक सहायक और सहयोग पद्धति (म्युचुअल एड ऐन्ड कोऑपरेशन) चलाई। इस पद्धति के कार्यक्रम थे ये।

मजदूरी की पारस्परिक सहायता तथा उत्पादन के विभिन्न सहयोग स्वैच्छा एवं पारस्परिक लाभ पर आधारित रहेगा जिसमें लोक-शासन उमंगे उचित प्रसार और प्रचार में हाथ बटायेगा।

सन् १९५२ ई० में देश के किमान परिवारों में ४० प्रतिशत से अधिक विभिन्न रीति के पारस्परिक सहायक दलों में सम्मिलित हो गए। करीब ४,००० कृषि उत्पादक सहयोग समितियाँ और दश सामूहिक खलिहान का देश के विभिन्न भागों में निर्माण हो गया। इन सहायक और सहयोग समितियों द्वारा पुनर्गठन एवं उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। प्राकृतिक नाश रोकने द्वारा दब गए। फसल खेती की नवीन प्रणाली और पशुपालन में प्रगति हुई।

कृषि के उत्पादन की विविध और सफल वृद्धि के लिए सरकार की योजना में किसानों को कृषि मूल्य मिलने लगे। इन मूल्यों द्वारा किसानों ने मजदूरी-मजदूरी के निमित्त नयी प्रकार के औजार खरीदे। जिनका मूल्य २५ लाख था। सरकार ने नव्य आधुनिक खेती के औजारों के प्रयोग के प्रोत्साहन के निमित्त मजदूरी २८०,००० की किसानों को १९५०-५१ तक प्रोत्साहन मजदूरी दी गयी। उनसे हाथ ७००,००० टन अन्न प्राप्त हुए। फिर तब का मजदूरी में सोना उतारने लगे।

सरकार ने किसानों में स्वतंत्रता की भावना पैदा करने के लिए एक अजीब काम किया। उसने हनाम प्रान्त के सिचूयांग गाव में जमीन्दारों के कबालो (टाइटिल डीड्स) का होलिका दहन कर दिया। सभी कबालो की ज्वती करा कर चीनी किसानों के सामने उन्हें एक स्थान पर इकट्ठा कर उनमें दियासलाई लगा दी गई। कबाले चट-चट कर जल गए। खडे किसानों के आनन्द का उस दिन क्या पूछना था। इसके साथ चेकियांग प्रान्त के हैंगसे ग्राम से ही भूमि वितरण आरम्भ कर दिया गया था। भूमि मापी गई थी और आवश्यकतानुसार सभी किसानों को भूदान मिलने लगे थे।

थोड़े दिनों में ही किसानों में नव जीवन का संचार हो गया। सोना उगलनेवाली धरती ने अगड़ाई ली। गल्ले का भाव सरकार द्वारा निश्चित कर दिया गया। सरकारी आयोजनाओं के फलस्वरूप किसानों को कपास, पटुआ, खैनी तथा उस श्रेणी की अन्य फसलों के उत्पादन पर जोर दिया गया। मूल्य नियन्त्रण के कारण किसानों को मुनाफे का अनुभव होने लगा। देखते-देखते उनकी क्रय-शक्ति बढ़ने लगी। अब वे सपरिवार सहयोग समितियों की दूकानों पर जाकर पहनने-ओढ़ने की चीजें स्वैच्छापूर्वक खरीदते थे।

कृषि उत्पादक पारिवारिक सहायक एवं सहयोग समितियाँ व्यक्तिगत किसान के गार्हस्थ्य परिचालन के आधार पर अवलम्बित हैं। दूसरे शब्दों में वे सब किसानों की भूमि पर के उनके प्राइवेट अधिकार पर आधारित हैं। किसान अपनी परिस्थिति और पराक्रम का मूल्यांकन कर ही इन योजनाओं से लाभान्वित होते हैं। आरम्भ में वे छोटे पैमाने पर इन्हें अपनाते हैं। फिर उस दिशा में अनुभव पाकर विशेष उत्पादन और राजनीतिक चेतना की ओर पैर बढ़ाते हैं।

ये नवीन पद्धतियाँ तीन श्रेणी में सरकार द्वारा बाट दी गई हैं।

१ इसका कार्यक्षेत्र सीमित है। साधारणतः इसके द्वारा तीन से पाँच किसान परिवार एक साथ मिल जाते हैं, अथवा कभी-कभी सात या आठ परिवार सम्मिलित हो जाते हैं। युग-युग से आनेवाली सहकारिता की भावनावाले इस पारस्परिक सहायक सगठन की यह प्रारम्भिक अवस्था है। इसके अनुसार किसानों को नया बल मिला है जिसके द्वारा उन्होंने अनावृष्टि का सामना किया है और पशु पालन तथा कृषि उत्पादन की सुविधा पाई है।

२ यह विशेष परिस्थिति में यह समय-समय पर सगठित होता है जब कार्यभार असह्य हो जाता है। पहली योजना की अपेक्षा इसका कार्यक्षेत्र बहुत व्यापक है। इसमें बीस परिवार तक एक साथ मिल सकते हैं। अम-शक्ति की वृद्धि, पशुओं के निरीक्षण और कृषि सवधी उपादानों का संरक्षण तथा अनावृष्टि जनित समस्याओं के निदान में ही इसका कार्य सीमित है। इसके अनुसार कहीं-कहीं ऐसे परिवारों से एक-एक गाव बस गया है। इनके सदस्य एक दूसरे के कार्य कलाप पर टीका-टिप्पणी करते हैं जिसका उद्देश्य उनके कार्यों की विशेष सफलता ही रहता है। प्रत्येक किसान की मजदूरी के दिन लिखे जाते हैं। यह भी देखा जाता है कि किस किसान ने काम में कौसा चमत्कार दिखाया। वह पुरस्कार स्वरूप मुद्रिया वन जाता है या अधिक गल्ले का अधिकारी होता है।

३ यह पहली और दूसरी योजनाओं से उच्चतर और सर्वप्रिय है। इसमें किसानों को अपनी भूमि के सिंचन कार्य का दायित्व लेना पड़ता है। इसे जल संरक्षण योजना (वाटर कनजर्वमेंसी प्रोजेक्ट) कहते हैं। इसके अनुसार जो किसान जितना भूमि पटा सकेगा उतनी ही उसकी मजदूरी होगी जिसकी रकम उसके 'शेयर' में परिणत कर दी जाएगी। इसमें विशेषतः बीस से चालीस और ८० से १००-२०० तक किसान परिवार सम्मिलित होते हैं। इसमें उनके कृषि कार्य बंट जाते हैं। वज्र भूमि भी उपजाऊ बनाई जाती है।

इन योजनाओं ने कृषि की सारी समस्याओं को सुलझा दिया है। कहीं समितियों के सदस्य अपने मुखिया के साथ गेहूँ चुनते, तो कहीं गेहूँ ओसाए जाते, कहीं मध्याह्न में सभी सदस्य एक स्थान बैठ कर खेती की आधुनिक कला का अध्ययन करते, कहीं एक दल बाढ़ के जल को रोकने के लिये बाध बनाते। फिर फसल कट जाने पर समितियों के चेयरमैन खेतियों के सामने वर्ष भर की कार्यवाही की रिपोर्ट देते। इतना ही नहीं प्रतिदिन खेत में काम करने के बाद वे यह नोट करते कि किस मजदूर ने उस दिन खेत में कितना काम किया है। इस प्रकार वे सभी मिलजुल कर फसल काटते, सुखाते और उनका अम्बार लगाते। हा, नई फसल की खुशी में सभी मजदूर स्त्री-पुरुष दोनों, खलिहान में थिरक-थिरक कर नाचते और गाते हैं। सच्चा को अपने-अपने गाव के अध्ययनशाला में जाकर देश-विदेश का समाचार जानते। सभी पुस्तकालय और रात्रि पाठशाला में जाते हैं।

इन सभी योजनाओं के कारण किसानों में राजनीतिक, सांस्कृतिक और नैतिक वातावरण उत्पन्न हो गया है।

### अनावृष्टि और नहर-समस्याएँ

सन् १९५१ ई० में २३ प्रान्तों में अनावृष्टि के चिन्ह स्पष्ट थे। सन् १९५३ के वसन्त में दक्षिण-पश्चिम चीन के १०० गाव से अधिक में वर्षा नहीं हुई। उत्तरी चीन में वर्षा के अभाव के कारण उस वर्ष बीज नहीं बोए जा सके। सरकार की प्रेरणा से जनता ने दिन-रात कुए खोदे, नहर बनाये और उन नहरों अक्रुरों को पटा-पटा कर लहलही बनाया। सक्षेप में, मजदूर सम्पूर्ण जान-शक्ति का प्रयोग कर सघर्ष में जुटे रहे। नदी की धारा को बरफ की चट्टानों से रोककर उसका जल खेतों की ओर बहाया गया है। स्थान-स्थान पर बमत के लिए बरफ सुरक्षित रखी गई। इनके आचार पर हुआइनान और होपेई जैसे प्रान्तों के किसानों ने २,५०,००,००० क्यूबिक मीटर बरफ इकट्ठी की। फलतः वसन्त की बौआई बड़ी सुविधा से हुई। दक्षिण चीन के अधिकांश स्थानों में वर्षा नहीं होती और उनकी भूमि सूख जाती है। अतः स्वतंत्रता के तीन वर्षों में ही सरकार द्वारा सब मिलाकर कुल ३५८ आधुनिक जल संरक्षण योजनाएँ पूरी की गई हैं। पीली नदी का जल दो नदी में लाया गया है। फिर यह जल घुमा कर एक जल पथ की ओर मोड़ दिया गया है जिसका नाम है लोक विजय नहर जो ४८०,००० माउ<sup>१</sup> भूमि तथा निहासियाग गाव एव होनन के आम-पान वाली भूमि को पटानी है। इसके द्वारा वज्र भूमि जगमगा उठी है। पीली नदी के पान रहनेवाले

इसे, "विपथक सर्प और जगली पशु" कहते थे। उनके सपने में भी यह बात कभी न आई थी कि इस नदी से चीन की घरती सुहागिन बन चँठेगी।

शिकियाग प्रान्त में अथक परिश्रम कर लोगों ने एक विद्यालय नहर बनाई है जिससे लाखों माउ भूमि पटाई जा सकती है। हुआई नदी की विशाल योजना, जिससे विभिन्न कार्य होंगे, पूरी हो गई है। इसके द्वारा हुआई नदी घाटी से २२०,०० वर्गमील भूमि की मिचाई हो सकेगी। सरकार द्वारा जबतक ये योजनाएँ कार्यान्वित हो रही थी तबतक चीनी जनता ने स्वयं ३,३६०,०० मिचाई के छोटे गड्ढे, बाढ के फाटक, बाध और खाई आदि बना रखी है। ६००,००० से अधिक कुए खोदे गए हैं या उनका जीर्णोद्धार हुआ है। करीब ३००,००० पनचक्की लगाई गई है। इस प्रकार पृथ्वी के भीतर से जल-उपयोग की सारी सुविधाएँ ठीक कर दी गई हैं। विशेष मिचाई खभे गाडने के यत्न लगाए गए हैं। काओलियागपेन बाध (उत्तरी कियागस) और हुआगवी नहर देख कर बुद्धि चक्कर में पड़ जाती है।

इन सुविधाओं के फलस्वरूप पूर्व छाहर प्रान्त की घासवाली भूमि, सुविस्तृत और भीतरी मंगोलिया के पूरब, बहुत सुन्दर बन गई है। इसके पूर्व पीली नदी के पूरब वाले निगासिया प्रान्त के उस भाग में बालु, कामयी झील थी जहाँ पहाड़ी चचल धाराएँ बहकर सर्वत्र क्षार नमक इकट्ठा करती रहीं। पर अब वह क्षेत्र मिचाई द्वारा सुन्दर उपवन में परिणत हो गया है।

### कृषि नष्ट करनेवाले कीड़ों पर शासन

चीन में टिड्डी आक्रमण की समस्याएँ ईसा के जन्म से ७०७ पूर्व से ही सुलझायी जा रही थी। तबसे आज तक इन २,६६० वर्षों के अन्तर्गत, करीब ८०० भयकर आक्रमण हुए। यांग्गी नदी के बाकेअन के १०,००० अरब कट्टी<sup>२</sup> खेत को इन टुकड़ियों ने नष्ट कर दिया ३,००० अरब कट्टी कपाम भूमि को लाल मकड़ों ने सर्वनाश कर दिया।

सन् १९५१ ई० में सोलह प्रान्तों के २६० से अधिक गावों की कुल १४ लाख माउ भूमि नष्ट हो गई। इन टिड्डियों के नाश के विचार से १२,०००,००० किसानों का एक दल बना जिममें अधिक-से-अधिक सरखा में पतगनाशक "६६६" का वितरण किया। कीड़े पीटे गए, उन पर धूले पड़ी और विषमय चारा चटा कर उनका नाश किया गया। लोक वायु शक्ति का प्रयोग हुआ। इन वायुयानों में पतगनाशक "६६६" की वर्षा कर टिड्डियों के प्राण लिए गए। वर्षों से होतान प्रान्त के पीली नदी की बाढ-वाला जलमग्न क्षेत्र इन टिड्डियों के अडा देने का अष्टा था। वह वज्र भूमि सुधार और यत्र चालित खेत खलिहान की योजनाओं के आरम्भ होते ही ये सभी अड़टे तोड़ दिए गए। सन् १९५२ में इन टिड्डियों ने ३७,७००,००० माउ भूमि को नष्ट कर दिया जो सन् १९५१ के नष्ट प्रदेशों ने २७ गुणा अधिक क्षेत्र था। उन्हें आमूग नष्ट कर देने के विचार ने पतगनाशकवूल "६६६" चार गुणा बाटा गया। सन् १९५१ में ५,९५,००० ने अधिक पतग दीपको का नौ प्रान्तों में प्रयोग हुआ जिममें ६,३२०,०००,

<sup>१</sup> एक माउ करीब एक हेक्टेयर का पन्द्रहवा भाग होता है।

<sup>२</sup> एक कट्टी बराबर है १३ पाँडे के।

००० पतग ५०७ लाख अडो के डेर नष्ट कर दिये गए। फिर ४५ माउ धान के खेतों में बसत और शरदकालीन जुताई हो गई। बाद धान रोपने-वाले मुख्य भागों में ८० प्रतिशत से अधिक धान के खेत रोपे गए। इधर जनता में अधिक जागरण छा गया है। अनहुवाई प्रान्त के एक किसान द्वारा निर्मित एक साधारण "पतगनाश" घर-घर बन गया है जिसके द्वारा गेहूँ के १,३४०,००० माउ भूमि के सभी लाल मकोड़े मार डाले गए। कहीं किसान इन्हे जाल से पकड़े रहे हैं तो कहीं चटाई फेंक-फेंक कर। इस जाल चटाई युक्ति ने बड़ा काम किया है। सरकार द्वारा पतगनाशक और पतग शासित यंत्र के निर्माण के लिये असंख्य कारखाने खुल गए हैं। इस प्रकार "६६६" और "डी० डी० टी०" पर्याप्त मात्रा में मिलती है।

### विशेष खेती कला विकास आन्दोलन

एक समय था जब खेती के विशेषज्ञ पुराने औजार और रीति पर आलोचनामात्र किया करते थे। उनकी अर्वाञ्चानिक प्रणाली पर खिल्ली उड़ाते और पूजापतियों के सिद्धांतों का खडन करते थे। चीनियों ने मिचुरिन और विलियम द्वारा प्रसारित साम्यवादी प्राणी शास्त्र का अध्ययन और उत्पादन सबधी सोवियत सरकार के अनुभव का अनुशीलन किया।

इधर कम्युनिस्ट सरकार ने नए-नए औजारों का प्रचार कर दिया है। खेती की पुरानी रीति में परिवर्तन लाए गए हैं। सन् १९५१ ई० में नौ प्रान्तों में ग्यारह विभिन्न गल्ले का व्यावहारिक प्रयोग हुआ। इससे यह स्पष्ट हो गया कि सात इंच वाले हल से उत्पादन में प्राचीन पद्धति की अपेक्षा, १६८ प्रतिशत वृद्धि हुई। जहां नवीन औजार का व्यापक प्रचार नहीं हुआ है वहां किसानों ने जोताई में तीन से पाच या ६ इंच तक हल की लकीर बनाते गए हैं। इनके द्वारा आशातीत अन्न उगाए गए हैं। राजकीय खेती द्वारा परिवर्तित नाज उत्पादन और दूब आरोपन की व्यावहारिक जाच की गई है। सोवियत की विकसित एव सर्वव्यापी खेती कला पार्व्व आरोपन पद्धति (फ्लोज प्लांटिंग स्कीम) ने चीन में अनुपम फल दिखाया है। इस उद्देश्य के लिए ३०० से अधिक प्रकार के पुष्ट गेहूँ के बीज तथा दस प्रकार के कपास के बीज की व्यवस्था की गई है।

प्रत्येक बृहत्तर नचाहित क्षेत्र में सरकार ने कृषि विज्ञान अन्वेषण महाविद्यालयों की स्थापना की है। यहां अल्पकालीन शिक्षा की व्यवस्था के जरा नाज प्रकार की प्रदर्शनियों और प्रतियोगिताओं का प्रवन्ध रखा है। सन् १९५२ ई० में १६,०० स्टेट फार्मों के सहयोग से कृषि पाठशाला के छात्रों ने होंपेई प्रान्त के करीब ७,३००,००० किसानों के बीच में ही सम्मन्धी भाषण दिए। दूरदर्शन यंत्र द्वारा पुष्ट बीज पहचानने की रीति बताई। प्रयोगशाला में आदर्श खेती का आयोजन कर किसानों को सिखाया गया। तिनारों के पान के खेतों में लड़े जाकर फसलों का तुलनात्मक प्रदर्शन कराया। राज्य आयोजित अल्पकालीन शिक्षण गिरिवर में किसानों का पुनः प्रशिक्षण कृषि मन्त्री का जान कराया। फलतः खेतों में फसल में भी नवीन नवीन नवीन चरनी रहती है। प्रायः खेती के सभी कार्यों में नवीन नवीन नवीन द्वारा ही होते हैं।

इस विकसित आयोजना के फलस्वरूप सन् १९५२ ई० में पारस्परिक सहायक दल के मुखिया ली चिंग वा, सिकियाग स्थित लोक स्वतंत्र सेना दल के एक सदस्य ने प्रति माउ २,०५८ कटटी धान प्राप्त किया। हैनकॉंग गाव के एक किसान शिह अन फू ने सन् १९५१ ई० में प्रति माउ में ८१० कटटी गेहूँ उगाया। एक पारस्परिक सहायक दल के मुखिया तथा सिकियाग स्थित लोक स्वतंत्र सेना दल के सदस्य माल्हे जू ने प्रति माउ १,३७७ कटटी गेहूँ की फसल काटी। इस प्रकार मक्के, कपास और अन्य गल्ले का रिकार्ड रखा गया।

आज प्रत्येक स्थान में पहले की अपेक्षा उत्पादन दशगुणा बढ़ गया है।

### कृषि कर प्रणाली

नवीन चीन के किसानों को कृषि कर के फलस्वरूप फसल के रूप में फसल के सर्वोत्कृष्ट नाज सरकार को देने पड़ते हैं। वे इसे 'देशभक्तिमय लोक अन्न प्रदान' कहते हैं। इस प्रदान का एक त्योहार मनाया जाता है। सभी किसान झाल और ढोल बजाते हुए नाचते जाते हैं। राज्यान्त को वे गाडियों और ठेलों पर लाद कर राज्यान्त कोपगृह ले जाते हैं। दोनों ओर घुडसवार झंडा-पताके लिये चलते हैं। अभी हाल में ही किसानों ने बड़ी लगन और उत्साह से सन् १९५४ का कर भुगतान समाप्त किया है। इस वर्ष किसान अपने विगत प्रयत्नों के अनुपम फल का अनुभव कर रहे हैं। यह उनके तथा समस्त चीनी जनता के उद्योग और मितव्ययिता का सबसे बड़ा फल है जिसके आधार पर चीनी राष्ट्रीय निर्माण की पंचवर्षीय योजना चलाई जा रही है।

इस कर के भुगतान में सभी किसान बड़े प्रसन्न रहते हैं। कारण यह कि यह कर उन किसानों को ही उनके प्रतिनिधियों द्वारा, लोक कार्य और सेवा के निमित्त सौ गुणा अधिक बढ़ा कर लौटा दिए जाते हैं। कुमिनताग सरकार के शासन काल में यह तलवार के बल पर भी संभव न हो सका था। तब सरकारी निश्चित कृषि कर का ७० प्रतिशत भी वसूल न हो सका था।

स्वतंत्रता के बाद कृषि उत्पादन में आशातीत वृद्धि होने के कारण सन् १९५२ का कर देकर भी १९५१ की अपेक्षा प्रत्येक किसान को ६५० किलोग्राम से भी अधिक बचत हुई थी। अपनी उपज के आधार पर ही चीनी किसान अपनी सारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहे हैं। इतना ही नहीं विशेष लगान के व्यय से अन्न रख छोड़ते हैं और सरकार को कर के रूप में पर्याप्त पूजा देकर एशियाई देशों के अन्न निर्यात के लिए कुछ सुरक्षित रखते हैं।

चीन में नवीन कृषि कर चीनी लोक राजनीतिक परामर्शदातृ सम्मेलन द्वारा निश्चित किया गया है जो १९४९ के सितम्बर की ४०वीं धारा के दूसरे परिच्छेद के अनुसार, सार्वजनिक कार्यक्रम की दृष्टि से, स्वीकृत हुआ था। इसके अनुसार राष्ट्र निर्माण, कृषि उत्पादन, और पुनर्वास आदि सभी समस्याओं के निदान पर विशेष ध्यान रखने का सकल्प हुआ।

नये कर विधानों के अनुसार जो परती भूमि को जोत-कोड कर हरा-भरा बना देता है वह उस भूमि के कर से तीन से पाच साल तक मुक्त कर

दिया जाता है। और यदि किसी ने एक साल का छोडा हुआ जोत खेत को आवाद कर दिया तब उसे एक से तीन वर्ष तक का कर नहीं देना पड़ता है। इस रीति के आधार पर जोत जमीन का रकवा उत्तरोत्तर बढ़ रहा है।

यदि वजर भूमि को किसी किसान ने पटा-पटा कर आवाद किया तो उसे तीन से पाच साल तक का कर नहीं लगता है। इसके द्वारा सिचाई पद्धति को प्रोत्साहन मिलता है।

कर विधानो ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कृषि आमदनी का अर्थ है भूमि का वार्षिक औसत उत्पादन। तात्पर्य यह कि कृषि कर निश्चित औसतन दर पर ही निर्धारित रहेगा, उत्पादन के आधिक्य पर नहीं। विशेष श्रम के कारण यदि उपज अधिक हुई तो वह किसान की हुई। पर उसे निश्चित दर के अनुसार कर चुकाना पड़ता है। यदि किसान की सुस्ती से औसत से कम उपज हुई तब दर कम नहीं की जाती। ईश्वरीय प्रकोप के फलस्वरूप किसानों को ऋण, अन्न आदि की सरकारी सहायता दी जाती है। यदि आवश्यक जान पडा तब कर में भी छूट दी जाती है। विशेष परिस्थितियों में असहाय किसानों का कर कम कर दिया जाता है या वे पूर्णतः मुक्त कर दिये जाते हैं। जैसे नि सन्तान विधवाए या बाढ आदि प्रकोप से पीडित किसान। कतिपय अल्पसंख्यक जातिया सदा के लिए इस कर से मुक्त कर दी गई है।

इन सुविधाओं के कारण स्वतंत्रता के तीन वर्षों में ही उत्पादन में महान वृद्धि हुई है जिसका आकडा ये हैं।

आवार वर्ष १९५९-१००

उत्पादन	१९५०	१९५१	१९५२
अन्न	११७	१२९	१५७
कपास	१६०	२३४	२८७

आजकल सर्वमाधारण कृषको को पाच से १० प्रतिशत तक कर देने पडते हैं। मध्य श्रेणी के किसानों को १५ प्रतिशत लगते हैं। कुछ धनी किसानों को, सबसे ऊंची दर, ३० प्रतिशत चुकाना पडता है।

कर विभाग के मिद्धान्त पूर्णतः सरल और सुबोध बना दिए गए हैं। सन् १९५० ई० में यह निर्णय हुआ कि स्थानीय अतिरिक्त कर (सर टैक्स) निश्चित कर से २० प्रतिशत अधिक न हो। सन् १९५२ ई० में सभी अतिरिक्त कर हटा दिए गए। तब से केवल एक ही कर, कृषि कर, रक्खा गया है। पर सांस्कृतिक और विनोदात्मक कार्यों के निमित्त या पुल

और सडक की मरम्मत के लिए उच्चाधिकारी की उचित स्वीकृति के आधार पर स्थानीय अधिकारी वर्ग अपने-अपने क्षेत्र में चन्दा ले सकते हैं। किन्तु यह चन्दा ऐच्छिक होगा और कृषि कर के ७ प्रतिशत से कम रहेगा।

यह कृषि कर अधिकतर अन्न द्वारा ही दिया जाता है। ८० प्रतिशत से अधिक अन्न खाद्यान्न का कर है और १० प्रतिशत में कपास दलहन और अन्य औद्योगिक उत्पादन सम्मिलित हैं। बडे नगरो तथा यातायात केन्द्रो के पास रहनेवाले किसान अन्न के बदले द्रव्य से ही कर दे सकते हैं। इस प्रकार की अदायगी सम्पूर्ण कृषि कर के कुल मूल्य का १० प्रतिशत से भी कम है। अन्न के रूप में कर देने की रीति से किसानों को बेचने के झमेले से छुटकारा मिल जाता है। इसके अतिरिक्त मरकार के अन्न कोषागार में निश्चित गल्ले पहुच जाते हैं। अन्न के मूल्य पर नियन्त्रण कर भाव का चढाव-उतार पूर्णतः बन्द हो गया है।

इन सारे सुख-सुविधाओं ने चीनी जनता को आश्चर्यजनक जीवन दिया है। सतोप और शान्ति के चिन्ह सारे चीज में स्पष्ट दीख पडते हैं। सभी अपने-अपने परिवार के साथ स्वस्थ वातावरण में पल रहे हैं। अब उन्हें अत्याचारी जमीन्दारो को कर नहीं देने पडते। अधिक उपज होने पर भी उन्हें निश्चित कर ही लगते हैं। शादी-ब्याह, खेती-गृहस्थी और मुक्क-श्रद्धा में कम दर पर मरकार से ऋण मिलते हैं। उनकी आमदनी में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जनता के महान कार्य, मडक, रेलपथ और जल सरक्षण आदि कार्यान्वित हो रहे हैं। आज जनता का अहर्निश कल्याण हो रहा है।

बडे गौरव की बात है कि हमारा विहार प्रान्त, माल मंत्री माननीय श्री कृष्णवल्लभ सहाय के जमीन्दारी उन्मूलन कार्यक्रम की कुशलता और व्यावहारिकता के कारण, सारे राष्ट्र का पथ प्रदर्शन कर रहा है। विहार के साथ ही अन्य प्रान्तो में भी इनका विधिवत् अनुमरण कर अधिकारी वर्ग किसानों की समस्याओं के निदान में व्यस्त है। उधर भूदान यज्ञ के सफल मत और स्रष्टा विनोवा जी मरकारी कर्मचारियों के सहयोग में भूमि वितरण योजना में मल्लम हैं।

आशा है, निकट भविष्य में भारत के किसानों की भूमि समस्या भी सदा के लिए मुल्लज जायेगी। और तब स्वतंत्र भारत के मुन्दर इतिहास में "कृष्णवल्लभ-विनोवा" जैसे मेवक मत के नाम सुनहले अक्षरो में चमकते दीख पडेंगे।



“धरती किमकी” ! यह एक अजीब सा प्रश्न है। सुनने में यह एक साधारण सवाल होता हुआ भी सर्वथा इतना रहस्यपूर्ण है कि हममें उत्पन्न गुत्थियों को सुलझाने में मानव समाज को अपनी प्रगति के भिन्न-भिन्न युगों में तरह-तरह के अमानुषिक अत्याचार, चिन्तनीय सघर्ष और भयकर युद्धों तक में सलग्न होना पड़ा है। तो भी भूमि-समस्या सम्य

नमार के समक्ष आज भी एक उलझन ही है, वल्कि कानून और शक्ति द्वारा भौतिक दृष्टि से इसे जितना ही निर्विवाद बनाने का यत्न किया जा रहा है समाज की परेशानियाँ उतनी ही ज्यादा बढ़ती जा रही हैं और त्रासति का आघात होने पर कल्याणच्छु समाज और भी अव्यवस्थित और उद्विग्न हो उठता है। विश्व

के इतिहास में पृथ्वी पर घटित सामाजिक द्वन्द्व के जो विवरण हमारे सामने हैं उनसे ज्ञात होता है कि काल-प्रवाह में वृद्धि पाते हुए मानव समाज से उम प्रश्न के तीन निराकरण अव्यारोपित किये जाते रहे हैं और मानव समाज के विकास पर भी उनके व्यापक प्रभाव पड़ते रहे हैं। वे तीन उत्तर हैं—

- १—धरती ईश्वर की है।
- २—धरती सबकी है।
- ३—धरती मेरी है।

यों तो मानव जाति नृष्टि के वाद से आज तक जहा-जहा गई वह इन्हीं विचारों का उच्चारण करती हुई धरती पर विजय और पराजय की कथाएँ रचती रही हैं और जहा कहीं भी उनके उल्लेख सुरक्षित किये जा सके हैं, पुराणों के ग्रन्थों में उन विचारों के विमर्श भी अवश्य ही विद्यमान हैं किन्तु भारतीय इतिहास में प्रति प्राचीन काल में आज तक के मानवोत्कर्ष में सुदूर और विस्तार विवरण स्पष्टतः लेख्यद्वय दृष्टिगत होते हैं, अतः इस प्रश्न की समीक्षा हमें भारतीय दृष्टिकोण में ही करनी चाहिये।

आरम्भ में मनुष्य कृषि-मानव था या हिम मानव और किन्तनी नस्लों के मेल का मन्व्य रूप में पृथ्वी पर स्थिर हो सका, यह बतलाना हमें तर्क तर्कित है, किन्तु निम्न युग में भारतीय ग्राम्य वैदिक ऋचाओं के द्वारा प्राचीन शक्तियों में अतृप्त भौतिक ऐश्वर्य और परलोक में भी प्रत्यागति की आशाओं में लक्ष्मीयं थे। यह युग एक मन्व्य समाज का रूप था जो कि नृष्टि के मन्व्य का वाहक था। इस युग में मानव जाति नृष्टि का निर्माता ईश्वर के प्रति प्रार्थना करने का आरम्भ कर रहा है, वह एक

अद्वितीय सर्वशक्तिमान अपने दोनों हाथों से मानो आकाशलोको और भूमि को भी उत्पादन करता हुआ सारे ब्रह्माण्ड को एक साथ सम्यक रीति से चलाता है, जैसे “स बाहुभ्या घमति स पत्तत्रयावाभूमी जनयनवेव एक। ऋ१०-८१-३”। वह अपनी अतुल सम्पत्ति के प्रत्येक कण से मानो मनुष्यों पर प्रकाश करता रहता था—“अहभुर्व वसुन पूव्यस्पतिरह धनानि

## धरती किसकी ?

डा० पाण्डेय रामावतार शर्मा

स जयानि शानवत। ऋ० १०-४८-१”। वह युग समझता था कि मनुष्य को चाहिये कि वह “शसदुकथेन्द्राय ब्रह्म वर्धनं यथासत् ऋ ६-२३-५”। उस परमेश्वर की जिससे उसे वृहत् ज्ञान, अन्न-धन आदि की प्राप्ति हुई है, अवश्य ही स्तुति किया करे, क्योंकि मनुष्य अपने पराक्रम से जिन उर्वरा भूमियों में

उस समय रहते (ऋ० १०-५०-३) चले जा रहे थे वे उसी परमात्मा के दान थे जो अन्तराल से उन्हें आदेश कर रहा था “भूम्या त्वच मधुना कि विभेद। ऋ१०-६८ ४।” वह युग ईश्वर से डरने और धर्म की रक्षा में तत्पर रहने का युग था और उसका धर्म सारे लौकिक पदार्थों की ईश्वर की ही सत्ता से पुष्पित मानने का था। उस समय मनुष्य समाज प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता था कि धरती ईश्वर की है और उसकी भोग योग्य ऐश्वर्य की प्राप्ति करना ईश्वर का ही आदेश है वल्कि ईश्वर ने धरती की गोद में मनुष्य का अवतरण इसलिए ही किया। यह मानव जाति की वह स्वाभाविक स्थिति थी जिसकी पृष्ठभूमि में सहयोग, उपकार और कृतज्ञता की भावनाएँ आप-ही-आप लहराया करती थी और समाज में धरती को स्वर्ग से कम आदरणीय नहीं समझा जाता था।

उस वैदिक काल की यह भावना कल्पनागत ही नहीं थी वह स्पष्टतः व्यवहार के भीतर निर्विवाद रूप में सर्वप्राणी थी। धरती ईश्वर की है के माननेवाले उपकृत हो कहते हैं—“माता पृथ्वी महीयम” यह बड़ी विस्तृत आदरणीय और सभी मोहा-पदार्थों को देनेवाली पृथ्वी माता के सदृश है, ऋ० १६४-३३। वे उससे कामना करते थे—“काम कामदुध धुक्ष्य, समस्त कामनाओं का पूरा करनेवाली कृषि-मूल झूमे तू। हमारे सभी मनोरथ पूर्ण करो, यजु० १३७२।” वे अपनी जोत की भूमियों से प्रार्थना करते थे—“ऊर्जस्वती पथमा पिन्वमाताम्मान्मीते पयसाम्याववृत्त्व। यजु० १२-७०। हे मीते! तू मुजल से खूब सीची जाकर अन्न में समृद्ध होकर पुष्टिकारक पदार्थों में हम सब को भलीभांति समृद्ध करो।” सामूहिक रूप में उपदेश किया जाता था—“योगीवत्त मेधावि। पुरुषो। हलो को जानो, जुगो को विविध दिजाओं में ले जाओ क्षेत्र के तैयार होने पर उसमें

बीज बोओ और कृषि-विद्या के अनुसार खूब हृष्ट-पुष्ट अन्न उपजाओ, शीघ्र ही पके अनाज प्रजा को प्राप्त कराओ।” इस तरह ईश्वर की धरती से प्राप्त भाग्य-ऐश्वर्य प्रजामात्र की बहुमूल्य सम्पत्ति थी और ईश्वर के सभी पुत्रों को उस पर अपने कल्याण के लिए धार्मिक अधिकार था।

“धरती ईश्वर की है” के विद्वान के धार्मिक युग में सर्वसाधारण की आवाज “जो खेडे सो खाय” की नहीं थी, दिशाओं में गूजता था— “सब खेडे सब खाय” और चरितार्थ होता था—“रामजी के चिरई, रामजी का खेत, चर जा चिरई भर-भर पेट।” एतदर्थ धरती माता की सन्तान सर्वदा कल्याणकारी यज्ञों में ही तत्पर रहा करती थी और इसकी प्रेरणा उन्हें अपने पूज्य ईश्वर के विशाल विश्व यज्ञ में ही हुआ करती थी। समाज इससे सन्तुष्ट था, कमानेवाले स्वयं खाने को चिन्तित न होकर खानेवाले को खिलाने में ही प्रसन्नता प्राप्त करते थे। लोग ऐसे ही चलते थे। समाज इसी प्रकार मुखी था, युग-पर-युग इसी तरह वीतता गया।

लेकिन उस समय ईश्वर और धर्म से आवद्ध मानव समाज और उसकी धरती की समस्याएँ और ही थी। मनुष्य प्रकृति पूजक थे, वे प्रकृति के पुत्र थे और प्रकृति से प्राप्त मत्ता उनकी सामूहिक विभूतियों के निमित्त उनकी वंशी पवित्र सम्पत्तियाँ थीं जिन पर मनों का यथोचित अधिकार था। धरती में अन्न उपजाने में लगे हुए तत्कालीन किसानों के विचार और कृत्यों में भी ऐसी ही उदारता थी, उनकी पवित्र प्रतीति थी कि सूर्यदेव ने प्रकाश, वायुदेव से शीतल पवन और गरजते मेघ-मडलों से वर्षा के दान की ही भाँति धरती माता से उन्हें अन्न-राशि का भी दान प्राप्त हुआ करता था और उस दान को समाज-यज्ञ में वितरित कर के ही मुखी होता उनका कर्तव्य है। इन तरह प्राप्त अन्न से समाज का भरण-पोषण करना उनका एकमात्र कार्य था और समाज पर उनकी रक्षा का शेष बोझ था, उनकी अधिकृत भूमि उनकी पूजनीया माता थी, जो न आपन में विरोध की वस्तु थी और न हाट में चढा कर विन्नी की कोई माधारण सामग्री, फलतः जमीन के वाटने या हडपने के प्रयत्न की तब न आवश्यकता थी और न समय था। मनुष्य सुनगठित होकर भी ऐसी ही व्यवस्था का निर्वहण करते गए जब तक भिन्न परिस्थिति मामने उत्पन्न नहीं हुई।

वृद्धि और विकास की ओर बढ़ता हुआ मानव समुदाय कालान्तर में उस दशा को भी अवश्य ही पहुँचा जब उर्वरा भूमियों की तलाश में विचरनेवाली टोलियों को दिक्कतें भी महसूस होने लगीं, या तो उर्वरा भूमि ही आवश्यकतानुसार विस्तृत नहीं थी या जनसंख्या का ही आधिक्य था और उत्पादन की सामग्रियों की भी न्यूनता थी तथापि आराम का होना जरूरी था और आराम मनों को ही मिलना चाहिये था। माग की पूर्तियों में झगडेँ और ममज्ञाते की भी जरूरत रह-रह कर पैदा होने लगी और अताडियों तक अवश्य ही यही प्रगम जारी रहा। पर ऐसा भी समय आया जब सामाजिक झगडों को मुलझाने के लिए नामन्त, शानक, मन्दार और राजाओं की जरूरत ममज्ञी गई। धीरे-धीरे वे अपनी जगहों पर प्रमुख होते रहे और झगडेँ के निपटारों में अपने निर्णय का बोध भी समाज के लोगों पर लादते गए। वैसे-वैसे समाज विचारों की नादगी में भी दूर हटता गया और लाचार उने अब यह निर्णय भी मानना पडा

कि धरती ईश्वर की होती हुई भी मवकी है और न्याय द्वारा “धरती मवकी है” के सर्वाधिकार की रक्षा होनी ही चाहिये। अधिकार की रक्षा के लिए उन नियमों का पालन भी अनिवार्य ही प्रतीत हुआ जिनका निर्माण शूर-वीरों या पुरोहितों द्वारा बीच-बीच में किये जा रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में लोकयज्ञ में रत किमान यह भी चाहने लगे कि जन कल्याणार्थ अभिमानियों का अभिमान और आततायियों के अत्याचार रोके जाएँ और उन्हें वैसे शूरवीर प्राप्त हों जो उनकी रक्षा कर सकें। अपने ऐसे सहायकों से उनमें कामना भी की “हे पुरुदूत ! हम तेरे प्रिय कार्यों में सभी शत्रुओं के ऊपर उठे और विघ्नकारी पुरुषों का विनाश और वरण योग्य तनों की प्राप्ति करते हुए बड़े भारी ऐश्वर्य से तेरे द्वारा रक्षा पाकर सुखमय जीवन व्यतीत करे।” तब शानक-मत्ता बढ़ने लगी और मान-मडल भी दृढ होता गया और उससे व्यापक एव गम्भीर राजमत्ता की स्थापना होने लगी। उस पर नियंत्रण के निमित्त राजशक्ति में समुदाय अनुरोध करता रहा कि तू राजपद पर अभिषिक्त होने पर भी उसमें निशुल्क होकर रह, अन्न और ऐश्वर्य का भोक्ता बन कर उत्तम भूमियों का दान करनेवाला बन निश्चय से ऐश्वर्य और अन्न को बढ़ाता रह और प्रजा में ऐश्वर्य, धन, और भूमि पर यथोचित विभाग करने में सफल हो। नाराज कि शनै-शनै नियंत्रित राजमत्ता मनुष्य और धरती पर स्थापित हुई और उसमें नियम और कानून द्वारा भूमि का विभाग कर धरती पर सब के स्वत्व की स्थापना की और व्यक्ति द्वारा स्थापित स्वत्व की रक्षा का भी एक प्रश्न खडा करने की ओर पूरा ध्यान दिया। लोग निर्विवाद कहने और मानने लगे “धरती मवकी है”। परन्तु इस पर भी ईश्वर और धर्म, राजा और प्रजा, दोनों अभी तक दृढ रहा और उसके भीतर भूमि पर सर्वाधिकार की व्यवस्थाएँ चालू की गईं।

व्यक्ति की ही भाँति समाज भी प्रगतिशील है और उसका एक अवस्था में स्थिर रहना अस्वाभाविक और असंभव है। इसलिए निश्चित राजसत्ता समाज के कल्याणकारी विचारों की चिन्ता में ही स्थिर नहीं रही एक माधारण व्यक्ति की भाँति मत्तावारी शूरवीर भी अपने कुछ-कुछ निश्चित व्यक्तित्व और उसके लाभ की चिन्ता करने लगे, उससे समाज में मघर्ष का जन्म भी अवश्य हुआ किन्तु चेष्टायें स्वीकी नहीं, भिन्न-भिन्न परिवर्तनों का सामना करना मानव समाज के लिये अनिवार्य सा हो गया है। समाज भी मानव-सृष्टि के दिन में आज तक जितना लम्बा जीवन व्यतीत कर चुका था और उसके अनुभव भी इस समय तक कितने जटिल और बहुमुखी हो चुके थे। उसकी नादगी शान्ति शक्ति के द्वारा नष्ट की जा चुकी थी और अब उसे अपना जीवन निर्मित कानून के अनुकूल व्यतीत करना था। केवट “शूयपाल स्वस्तिभि. मदान ऋ० ७-९०-१७” की याचना में अब मतोप नहीं था। दशा काफी बदल चुकी थी। मर्दियों के बाद निवर्तित राजमत्ता वशगत राजमत्ता बन बैठी और शान्ति को अन्त और भयभीत भी करने लगी। युगानुकूल शान्ति वर्ग भी उसी रात्रि में डलना हुआ लाभ, न्याय और अन्त्याय के पाठ पढ़ने और दुहगने लगा। अब भूमि की एक व्यक्ति ने ईश्वर का बहना और न मवकी मानना, वह “धरती मेरी है” बहने में अम्यन्त दिमाई देने लगे और एतदर्थ उने धर्म और ईश्वर में भी विवाद करना पडा। समय पर

ईश्वर का विरोध करना या उसके विरुद्ध होना भी जब ज्यादा श्रेयस्कर जान पड़ने लगा। इस प्रकार एक दिन शामक और शामित, राजा और प्रजा, समाज और व्यक्ति, सभी धरती की छाती पर धरती सम्बन्धी तीसरी समस्या को लेकर मेरी और तेरी के न्याय और अन्याय में निमग्न हो पड़े “जमीन मेरी है” के स्वर से दिखाए गूजने लगी, धरती श्रवाक अपने पुत्रों की देखती रही। वेदवाणी लुप्त हो गई। मनुष्य का कानून भूमि का शासन करने लगा।

हमारे देश के इतिहास में महाभारत का युद्ध यह प्रमाणित करता है कि हमारी वैदिक धर्मप्रियता, ईश्वरपरायणता, न्यायशीलता, और कृतज्ञता महाभारत के युद्ध काल तक एकदम बदल चुकी थी। महाभारत के युद्ध की भूमिका में धर्म और अधर्म, न्याय और अन्याय, उपकार और स्वार्थ, लोक निहित और वैयक्तिक लाभ के संघर्ष का ही सजीव चित्र है। कौरव-पिता धृतराष्ट्र के “मामका पाण्डवाश्चैव” में इस धारणा की विद्यमानता स्पष्ट “तत्त्वमसि” के दार्शनिक सिद्धान्त से कितना नीचे गिरा हुआ यह स्कीर्ण विचार था, यह विचारने ही योग्य है। इस युग की नीचवृत्ति की प्रगाढ़ता दुर्योधन के “बिना युद्ध के मृत्युग्र भर भी भूमि नहीं देने के” कथन से साफ-साफ प्रकट होती है। तब से भूमि की समस्या इसी तरह हठ और अन्याय पर ही आश्रित होती गई और भूमि की समस्या स्कीर्ण, अनुदार और स्वार्थपूर्ण हो रही है। स्वार्थ के आगे मनुष्य-निर्मित कानून भी बन रहे हैं, मनुष्य का मोह व्यग्र कानून के बाद में घटता हुआ नजर नहीं आया।

वास्तव में ऐसे विस्मयकारी विचार-विपर्यय का कारण मनुष्य-समाज ही है, धरती तो जहाँ थी बराबर वही रही है और जिसकी है

सदैव उगी ली है और मनुष्य ही उगाता श्रमिष्ठाना और मोक्षा भी बना रहा है। आरम्भ में आज तक मानव मनुष्य का समाज एक प्रकार नहीं रहना ही सामाजिक विषमता और पाण्डुपति विरोध का मुख्य कारण है। आज धरती पर मनुष्य के प्रति मानव मनुष्य का विचार घोर मोह से ग्रस्त और घृणित स्वाथ में उन्मत्त है और उगत पुगतन उदागना और उपकार वृत्ति का सर्वथा अभाव है। व्यक्तिगत लाभ और व्यक्ति विशेष की आय की चिन्ता आज मनुष्य के प्रति मनुष्य को न्याय का आचरण रखने में भी इतना अचित कर देता है कि वह दानवी दुराचरण को भी ठीक और न्यायसम्मत मान लेता है। उगीने सभी कहने लगे हैं— “भूमि मेरी है, मैंने यह भूमि अर्जित की है और मेरा भूमि पर स्वत्व है, मेरे पराक्रम का फल है।” समाज में “मेरी” “मेरी” ही की आवाज प्रवल है। लेकिन हमें जानना पड़ेगा कि ऐसी ही अनुदार व घृणित नीति के कारण भारत को मारी गरिमा और विश्व-वन्द्य महिमा का महार नीति दृष्टि द्वारा भी रोक नहीं जा सका। वमजोर भारत उमके बाद सदियों तक गुलाम ही रहा और स्वतंत्र भारत में भी “मेरी” और “मेरी” का ही घोर स्वार्थ बना रहा। यह देश के दुर्भाग्य और समाज के दुग्नों का ही सूचक है। इसलिए भूमि-समस्या का ठीक-ठीक और धार्मिक मुझाव होना ही उचित है। भूमि समस्या में वाम्त्विक सुधार लाना श्रान्ति नहीं न्याय का व्यवहार करना है और ग्रामीण जीवन के लिए एक ऐमे यज का सपादन करना है जिसके द्वारा लोक-कल्याण और जन तुष्टि की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। अतः इसका युवितयुवन अनुष्ठान कर “व्यचिष्टे बहुयाय्ये यनेमहि स्वराज्ये” ऋ० ५-६६-६” के वैदिक सकल्प को मत्स्य करना शामक वर्ग का कर्तव्य है।



# नये समाज के निर्माण में भूमि-समस्या का समाधान

श्री शारदारजन पांडेय

भारतवर्ष में, यहाँ की अपनी सरकार हो जाने पर, अगर भूमि-समस्या का समाधान नहीं कर सकी तब इस देश में प्रजातंत्र की सफलता की चर्चा करना एकदम फिजूल बात मानी जायगी—एकवारगी मृत्यु से दूर, बहुत दूर। भूमि-समस्या के समाधान करने और उसका हल निकालने के लिए एक अन्तिम निश्चय की आवश्यकता है। निश्चय वँसा होना चाहिये जँसा अचल हिमालय, उसमें ऊँचाई हो, दृढता हो, आवश्यक कठोरता हो, जो व्यवस्थापक और शासक की शोभा होती है। यहाँ समाधान ढूँढने के लिए विषय को अधिक और अनावश्यक तूल दिया जाता है, परिणामों की बेकार चिन्ता की जाती है और स्वार्थ सर्वाधिक प्रचंड हो जा सकते रहते हैं, अपना स्वर बुलन्द करते रहते हैं।

## सघर्षों का ताँता

इतिहास इस बात का साक्षी है कि सृष्टि के आरम्भ में भूमि की ऐपणा मानवों में चली आई है। इसी के लिए सघर्ष हुए हैं, खून की नदियाँ बहती हैं, साम्राज्य बदले जा चुके हैं, तब कहीं एक ऐसी अपराजित चेतना हिलोरे ले सकी है। टाल-मटोल करने की नीति जनता वरदाशत नहीं कर सकती है। हम कई शताब्दियों तक गुलामी की जँजीरों में जकड़े रहने के कारण अत्यधिक सहिष्णु हो गये हैं। सच तो यह है कि समार भर का किमान जरूरत से ज्यादा सहिष्णु होता है। समार भर के किमानों के लिए धरती की अपार सहिष्णुता की उपमा दी जा सकती है। राजनीतिक पार्टियाँ या सरकारें किमानों को केवल आश्रय देकर ही जीवित नहीं रहने दे सकती। यह सत्य है कि हमारे इस बड़े पुराने देश में अभी अन्य देशों की तरह भयंकर रक्तपात नहीं हुआ है। लेकिन ऐसा अनुमान लगा लेना भी गलत होगा कि इस देश में बड़े पैमाने पर जनक्रान्ति भूमि के लिए नहीं होगी। यह एक ऐसी चेतना है जिसकी उपेक्षा एकदम नहीं की जा सकती। समार के किमानों के विद्रोहों के क्रमिक अध्ययन ने पता चलना कि विद्रोहों की पृष्ठभूमि प्रायः उन लोगों द्वारा तैयार की गई थी जो जनता के भाग्य विधाता थे, उनके द्वारा नहीं जिन्होंने किमानों के बन्धाव के लिए एकता का नदंन दिया था या उन्हें उनके अधिकार प्राप्त करने को उकसाया था। जिन देशों में जन-बन्धाव के आदर्श को सामने रखकर

भूमि-समस्या का अन्तिम रूप में समाधान किया गया उनका अध्ययन हमारे लिए लाभकर हो सकता है, पर उन्हीं तरीकों से हम अपने देश में हल नहीं निकाल सकते।

## इतिहास का साक्ष्य

भूमि-समस्या को समाधान देने के लिए हमें न तो इतिहास के गहन अध्ययन करने की जरूरत है और सामाजिक परिस्थितियों या पारस्परिक विशेषताओं के समझ चुकने की आवश्यकता है। किसी देश में या हमारे इसी देश में किस युग में भूमि-समस्या का किस प्रकार समाधान किया गया था, यह जानना भी अविचार्य नहीं है। यह कहना भी अनावश्यक होगा कि अमुक शासन प्रणाली के कारण या अमुक शासन के कारण भूमि-व्यवस्था ऐसी सदिग्ध हो गई है जिसके परिणामों को शीघ्र नहीं मिटाया जा सकता। मेरा दृढ विश्वास है कि जो शासक वर्ग या राजनीतिक दल इतिहास का साक्ष्य उपस्थित करते हैं वे अमली प्रश्न को टालने की नीयत रखते हैं। नवमे बड़ा काम तो यह है कि अधिकाधिक जन-बन्धाव को मद्दे-नजर रखकर विवेक बतने चाहिये और यह देखा जाना चाहिये कि उस पर कड़ाई में अमल किया जाता है कि नहीं। अगणित समस्याओं के इस समार में साधारण किमान को न तो इतिहास पटाया जा सकता है और न मनो-विज्ञान की ट्रेनिंग ही दी जा सकती है। उमकी मानवीय शक्तियों-उत्पादन का काम लेना चाहिये, चाहे वह व्यक्ति जिस तरह का हो। उन्हीं प्रकार मानव की चतुर्दिक उन्नति सम्भव है और उन्नीत होकर ही उमान सुव-चैन की नाम ले सकता है। आरम्भ में लेकर आज तक जितने इतिहास के ग्रन्थ लिखे गये हैं उनका रेकर्डिंग एवम्पक्षीय है—राजा, राजकीयता और राज-व्यवस्था। यह किसी ने भी नहीं लिखा कि राज-व्यवस्था का राज्याचरण में आम जनता किस युग में किस प्रकार सहयोग देती थी। यहाँ तक कि हमारे इस देश में भगवान भी राजा का बेटा ही हो सकता था और दूसरा कोई नहीं। और भगवान के भक्त केवल दामानुदान के अतिरिक्त कुछ नहीं थे। प्रजातंत्र के न्द्रपिन युग में जब हम मानवता का राज्याचरण चाहेंगे तब इतिहास की बड़ी शक्तियों को बड़ी देर के लिए पुन-बाल्यों में या अध्ययन के कमरे में बन्द कर देना होगा। बदल-बदल पर

इतिहास का साक्ष्य स्वीकार करना निश्चयात्मकता से दूर भागना है । इतिहास केवल इसी बात की प्रेरणा दे सकता है कि आज तक शासन की ओर से भूमि-समस्या को हल करने के लिए क्या प्रयास किये जा चुके हैं । पर जैसा कि मैं ऊपर कह चुका हूँ उममें तो एक प्रकार की स्थिति सम्मुखीन हो जायगी चूँकि सही फैसला करने में ऊहापोहा आ जा सकता है । तब एक ही रास्ता रह जाता है अपने आदर्शों एवं लोक भावनाओं के अनुसार हम समस्या का समाधान दें । एकवार की गई व्यवस्था तो बराबर रहती नहीं । उसमें बराबर रद्दोबदल हुआ करती है ।

### हमारी असली अवस्था

भूमिका को अधिक नहीं बढ़ाकर अब मैं सत्य तथ्य पर उतरूँ जिसकी पूर्ण जानकारी के अनन्तर ही किसी प्रकार का कार्यकारी कदम उठाया जा सकता है । किसानों की असली स्थिति क्या है ? जवाब सीधा है । (१) जो लोग असली उत्पादन करनेवाले हैं उनके पास जमीन नहीं है (२) साधन नहीं है (३) सिंचाई, खाद, बीज, कृषि-सम्बन्धी आधुनिक ज्ञान नहीं है (४) किसानों की परम्पराएँ जडीभूत हैं, वे उससे दूर हटकर प्रयोग नहीं करना चाहते हैं (५) सहायक उद्योग, गावों में जो किसी युग में अधिक विकसित था, अब एकदम लुप्त हो गया है (६) उत्तराधिकार कानून आदि ऐसा है जिससे होल्डिंगों के अनावश्यक टुकड़े हो गये हैं (७) गावों का सामाजिक गठन इतना जर्जरित है जिसमें विना परिवर्तन के उत्पादन, श्रम का विभाजन या सामूहिक दायित्व का निर्वाह संभव नहीं हो सकता है (८) गाव इतने छोटे-बड़े हैं और उनका रकबा इतना छोटा-बड़ा है जिसका कारण सम भाव नहीं आ सकता है (९) राजनीतिक पार्टियाँ और सरकारें इतनी असमर्थ हैं कि वे अपने प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं ला सकती हैं । लेकिन सबसे अधिक काम तो सरकार का होता है । आजादी आ जाने के बाद गत आठ वर्षों में ऐसे प्रयास नहीं किये गये हैं जिनसे किसानों में सार्वजनिक चेतना आवे और वे सहकारी कृषि की दिशा में अग्रसर हो सकें । दुर्भाग्यवश सरकार में जो लोग हैं वे भी अपने को, अपने स्वार्थों को छोड़कर बहुजनहिताय कार्य करने में असमर्थ पाते हैं, चूँकि ये भी वही परम्परा की मान्यता का व्यामोह छोड़ नहीं सकते । इसका मूल कारण है कि प्रारम्भ काल में हमारी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस के सदस्यों के समक्ष विदेशी सरकार की नीति के समानान्तर कोई योजना नहीं थी । अगर निश्चित योजना होती तब आज यह कठिनाई नहीं उपस्थित होती जो विकराल रूप धारण कर चुकी है । चीन की कम्यूनिस्ट पार्टी के पास एक निश्चित स्कीम थी कि शासन में आ जाने के बाद वे क्या करेंगे ? अतः उन्हें भूमि-समस्या के समाधान करने में आशातीत सफलता मिल चुकी है जिसे देखकर सारा ससार चकित है ।

### जमीन्दारी उन्मूलन

कोई भी समझदार आदमी यह सवाल पूछ सकता है कि मुआवजा देकर जमीन्दारी उन्मूलन का क्या अर्थ होता है । मुआवजा देने का सम्भवतः यही अर्थ है कि उचित मूल्य पा लेने पर ये जमीन्दार आखिर अपनी व्यवस्था

कर ले । तो वे सारे जमीन्दार क्या जमीन्दारी ले लिये जाने पर गेती का काम नहीं करेंगे ? यदि नहीं करेंगे तब उन्हें मुआवजा देना जायज समझा जाता । अगर वे जमीन्दारी उन्मूलन के पञ्चान भी तृप्ति पर निर्भर रहेंगे, तब तो उन्हें उनके परिवार-गालन भर जमीन ही मिलनी चाहिये जिम्मे वे उत्पादन कर सकें और सामान्य किमान की तरह श्रमशीलता के आधार पर, नयी व्यवस्था में जो पूर्णतया मानवीय आधारे पर निर्मित होनेवाली सम्भावनाएँ हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकें । जमीन्दारी उन्मूलन में ही या मुआवजा दे देने में ही पूर्णरूपेण आगिरी तौर पर भूमि-समस्या का समाधान नहीं हो सकता है । शासन एवं जनता के बीच की दीवार के रूप में जो जमीन्दार थे, वे मान लीजिए हट गये ? लेकिन उनका भविष्य और उनके स्वार्थ दोनों का दायित्व भी समाज पर ही है । स्वार्थ का दायित्व, यह तो कुछ श्रमगत जमा लगेगा । पर दरअसल स्वार्थ का अर्थ विस्तृत भाव और कार्यक्षेत्र में समझा जाना चाहिये । यानी उन जमीन्दारों को जीने की गुन्धिवाएँ देना जंगे दूंगे किमानों को मिलेगी, इतने से अधिक कुछ नहीं । कोई भी कानून बनाने में, हमारे शासनको को बहूवा एक प्रकार का भय बना रहता है, शका शासन रहती है, इसलिए कि युग-युग में चले आनेवाले समाज के प्रबल लोगों की प्रतिक्रिया जानने कमी होगी और उगका परिणाम न जाने क्या होगा ? यह भी एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक भय है । यदि एने भगाने के लिए कटिबद्ध हो जाया जाय तब निर्णय किया जा सकता है और उमने अधिक कल्याण होगा ।

### भूदान की प्रतिक्रियाएँ

जमीन्दारी उन्मूलन कर देने में किमानों में एक प्रकार की आशा का संचार हो चुका है । अब वे स्वप्न देखने लगे हैं कि उनके अच्छे दिन आये । वे हाकिम-हुक्काम के आगे थोड़ा निडर होने का उपक्रम करने लगे चूँकि जमीन्दारों का भय रहा नहीं । लेकिन आचार्य विनोदा भावे के भूदान-आन्दोलन के कारण सारे देश में एक प्रकार की विपरीत प्रतिक्रिया हो गई । भूदान करनेवाले बड़े-बड़े जमीन्दार, राजा-रजवाड़े पुनः दान के बल पर अफसरो और किसानों के बीच दीवार बन कर आ गये । सरकार को उनका कृतज्ञ इसलिए होना चाहिये चूँकि उन्होंने जमीन दी है । इस प्रकार पुरानी परम्परा के अनुसार दान देनेवाले ही सम्मान के पात्र हो गये । भूदान में कौसी जमीन मिली है यह इस छोटे से लेख का विषय नहीं है । असल प्रश्न यह है कि हम किसानों को दान देगे या उनके अधिकार देगे । भूमि पाना प्रत्येक किसान का अधिकार है । अधिकार को दान का स्वरूप देना विडम्बना नहीं तो और क्या है ? मान लीजिए, अमुक राजा साहब से कई सौ एकड़ भूमि भूदान में मिली । उस पर उसी राजा साहब के हलवाहे शीगुर में इतनी जुरअत कहा से आवेगी कि वह फौरन उसे अपना समझने लगेगा । इसके लिए उसे उचित शिक्षा कौन देगा । जो लोग भूदान आन्दोलन के समर्थक हैं उन्हें यह सोचना चाहिये, फिर विधान में जब व्यक्तिगत सम्पत्ति को मान्यता दी गई है तब केवल दान देकर तो किसान को भूमि का मालिक नहीं बनाया जा सकता ।

तब क्या कारण है कि इतना श्रवैज्ञानिक होते हुए भी भूदान का आन्दोलन लोगों की कल्पना को जकड़ कर पकड़ चुका है । इसका कारण

है हमारी वही परम्परा जिसमें अधिकारो की नहीं, दान-धर्म-दया-दाक्षिण्य आदि को मान्यता दी गई है। कुछ लोगो ने प्राचीन आदर्शों के प्रति मोह के कारण इसमें सहयोग देना आरम्भ किया है और कुछ लोगो ने यह समझ कर कि इसी आन्दोलन से शान्तिपूर्ण तरीको से भूमि समस्या का समाधान उचित तथा इप्सित तौर पर हो जायगा। पर दोनो ही गलती पर हैं। हा, इस आन्दोलन से इतना लाभ अवश्य होगा कि लोगो में अपने अधिकारो का ज्ञान फैल जायगा और जिनके पास प्रयाप्त भूमि है वे भी समझने लगेंगे कि धार्मिक आचारो के अनुसार भी उन्हें अधिक भूमि रखने का कोई अधिकार नहीं है। केवल इतनी सी चेतना फैलाने के लिये इतने बड़े आन्दोलन की क्या आवश्यकता थी? इस आन्दोलन से तो देश के लोगो की बहुतायत क्षमता एव कार्यशक्ति का दुरुपयोग हो रहा है और एक ऐसी भावना घर कर रही है जिससे लोग अधिकारो की बात को दान के नीचे दबा देंगे। अब वह समय आ गया है जब सब लोगो को विलकुल स्पष्ट निर्णय करना चाहिये।

### निश्चित उपाय

भूमि-समस्या के समाधान के लिए निश्चित कार्यक्रम कुछ ऐसा होना चाहिये (१) देश भर की कृषि योग्य भूमि की परीक्षा, जिसमें वैसे भूमि भी सम्मिलित हो जो कृषि के लायक बनाई जा सकती है (२) इसका निर्णय कि क्या केवल भूमि उन्ही को दी जायगी जो खेती करते हैं या उन्हें भी जो कृषि के अलावा अन्य व्यवसाय करते हैं जैसे नौकरी, दूकानदारी आदि (३) जिस क्षेत्र में प्राकृतिक व्यवस्था के अनुसार जो उत्पादन होता

हो या हो सकता हो उसके सम्बन्ध में आकडे एकत्र कर उसकी सुविधा प्रस्तुत करना (४) सिंचाई, वीज, खाद आदि की व्यवस्था करना (५) भूमि की सीमा निर्धारण करके पूरे गाव के खेतो को सहकारी चकवन्द बना देना, इससे ग्रामीण समाज में जो चकवन्दी व्यक्तिगत मिल्कियत पर है और जिस कारण अनेको बुराईया फैल गई हैं उसका समूल नाश हो जाय। सहकारिता के आधार पर कृषि प्रारम्भ कर देने से सबके हित भी सम्मिलित हो जायेंगे और उत्पादन में अधिक वृद्धि होगी। यही व्यष्टि को समष्टि के रूप में परिणत करने का बहुत बड़ा अस्त्र सिद्ध हो सकेगा।

इन सब योजनाओ को कार्यान्वित करने के लिए सबसे पहले पूरे देश में भावभूमि तैयार करने की जरूरत पड़ेगी। वातावरण तैयार करने में सरकार राजनीतिक कार्यकर्त्ताओ, समाज सेवियो तथा पढे-लिखे ग्रामीणो की सहायता और सहयोग ले सकती है। अभी जो सीमा निर्धारण पर तरह-तरह के मत व्यक्ति किये जा रहे हैं वे सर्वथा अकार्यकारी जान पडते हैं। लाभकर उत्पादन के लिए किसी भी भूपति के तीन सौ एकड़ की छूट देना निश्चय ही, इस युग में जब भूमि की क्षुधा पूरे देश में है, युक्तिसंगत किसी भी दृष्टिकोण से नहीं कहा जा सकता है।

इसी बीच गावो में यत्र-तत्र छोटे-छोटे उद्योग-घरों को आरम्भ कर देने की आवश्यकता है। जब खेती का काम नहीं होता तब ग्रामीण बेकार अपना समय व्यतीत करते हैं। यदि पूरे देश में इस प्रकार की योजनाएं कार्यान्वित नहीं की जा सकें तो किसी एक भाग के एक गाव में ही प्रयोग आरम्भ किया जा सकता है।



# भूमिहीनों का स्वत्व

रेवरेंड फादर ई० डी० म्युल्डर

अभी ससार के प्रसिद्ध कॅथलिक धर्माचार्यों ने एक ऐसा नारा दिया है जिससे ससार के कुछ भाग के लोगों को बड़ा भय लगने लगा है। यह नारा है, जिन देशों में आवादी अधिक है और जमीन कम बढ़ा के लोगों को उस मुल्क में स्थान मिलना चाहिये जहाँ जमीन अधिक है और जनसंख्या कम। इस नारे से कनाडा, आस्ट्रेलिया और अफ्रीका को भय उत्पन्न हो गया है। डर इसलिए चूँकि इन देशों के निवासियों ने मानवतावाद का स्वर नहीं पहचाना है।

दक्षिण अफ्रीका की जातीय नीति ऐसी है जिसमें सारे ससार के लिए वह समस्या बनती जा रही है। भारत और चीन में जो जन्म-नियंत्रण का आन्दोलन चलाया जा रहा है वह कतिपय निहित स्वार्थों का पडयत्र है।

भारतवर्ष में भी बड़े उद्योग या कृषि के जो अधिपति हैं उनकी वितरण-नीति भी ऐसी है जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर नहीं बढ़ रहा है। किसी भी सम्य समाज में जब तक सबको रोटी नहीं मिल जाय तब तक कुछ लोगों को केक नहीं दिया जा सकता। यदि दिया जाय तब यह सम्पूर्णतया अन्याय होगा। प्रगतिशील विश्व के सभी लोकनायक सम्पत्ति और जन कल्याण के बीच वितरण का औचित्य चाहते हैं। सबसे पेचीदा प्रश्न है इस नीति को कार्य रूप किस प्रकार दिया जाय। कई देशों में सुनियोजित नीति नहीं रहने के कारण बड़े पैमाने पर अशान्ति की सृष्टि हो गई है।

ससार के अधिकांश देशों में वुभुक्षा है। वर्तमान युग के सबसे बड़े इतिहासकार आरनल्ड टायनबी के अनुसार ससार के पाच बड़े देश हैं। इन पाच बड़ों में भारत, चीन, सुदूरपूर्व और पश्चिमी यूरोप आते हैं। इन देशों में उत्पादन एवं वितरण का अनुपात उचित रीति से होना चाहिये। आचार्य विनोबा भावे ने भारत में भूदान का आन्दोलन आरम्भ किया है। लेकिन केवल कुछ जमीन दे देने से ही असली समस्या का समाधान नहीं हो पायगा। यहाँ भूमि की वुभुक्षा और खाद्य की वुभुक्षा दोनों ही विराट स्वरूप लेकर उपस्थित हैं।

भारत में एक और समस्या है, वह है साम्यवाद का। इस वाद के चलते ससार के कई हिस्सों में अशान्तिपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस वाहरी वाद का उतना खतरा नहीं है जितना यहाँ की अतिशय गरीबी से है जिस कारण कई प्रकार की भयकर बीमारियाँ यहाँ फैल गई हैं।

औद्योगिक एवं कृषि उत्पादनों के न्यायोचित वितरण से ही हम देश की समस्या का सही एवं उचित रूप में समाधान संभव है। इस कार्य को सुचारु रूप में चलाने के लिए भारत को एक बीच का रास्ता अस्विकार करना पड़ेगा जो न साम्यवाद का होगा और न पूँजीवाद का। कम्प्यूनिस्ट कहते हैं—उत्पादन के सभी मायनों का राष्ट्रीकरण हो जाय। इसीने हम देश में सामाजिक न्याय संभव हो सकेगा। जो लोग पूँजीवादी अर्थ-व्यवस्था में विश्वास रखते हैं उनका कहना है—स्वतंत्र वाणिज्य में राज्य की ओर में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं। ये समस्त यूनियनों और मधटनों को समाज के लिये खतरा मानते हैं।

१९३४ में आज तक अमरीका में राज्य की नीति से जो भी परिणाम निकला वह भारत में नहीं हो सका है। भारत में भूमि की वुभुक्षा एक नग्न सत्य है यहाँ भूमि का राष्ट्रीकरण ही किसी तरह समस्याओं का समाधान नहीं दे सकता।

पूरे देश में जमीन्दारी के खात्मे के लिए नारा लगाया गया। और यहाँ जमीन्दारी उन्मूलन किया जा चुका है। जमीन्दारी प्रथा के रहते अन्न उपजानेवाले भूखो मरते हैं और रूई उपजानेवाले नगरे रहते हैं। भारत में बड़े पैमाने पर अगर कृषि की जाय तब भी असली समस्या का समाधान नहीं होता। सामूहिक कृषि रूस में की गई है। इस देश में ऐसी कोई भी कृषि प्रणाली सहल नहीं हो सकती है। अगर भारत में किसान मिलकर स्वयं सामूहिक खेती करें, लेकिन शासन की ओर से किसी किस्म का दबाव नहीं पड़े तब सफलता बहुत हद तक मिल सकती है और वास्तव में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था का यही मूलाधार हो सकता है। जब तक किसान जमीनों के मालिक नहीं हो जाते तब तक असली समस्या का समाधान नहीं होने का है यदि। जमीन बड़े-बड़े भूपतियों के पास हो तब वे ट्रैक्टर आदि आधुनिक उपादानों से बड़े पैमाने पर कृषि करेंगे। यदि भूमि किसानों की हो गई तब वे भी अपने साधनों से अधिक उत्पादन कर सकते हैं और ये किसान ऐसा करने को कटिबद्ध हैं। जनोपयोग की जमीनों को छोड़कर शेष भूमि किसानों को बन्दोवस्त कर दी जानी चाहिए।

यही समय है जब भारत के शासक फँसला कर सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की अर्थ-व्यवस्था कायम होगी। इसमें भी ग्रामों की अर्थव्यवस्था

की आकृति सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। सघर्ष दो पक्षों में है, साम्यवाद में और पूँजीवाद में। मध्य व्यवस्था में, सहयोगिता के आधार पर, कृषि कार्य की उन्नति हो सकती है। भारत में पहले कई राज्यों में सहयोग समितियाँ असफल रही हैं। सहयोग समितियाँ जब असफल हो जाती हैं तब व्यवस्थापक या तो पूँजीवादी व्यवस्था की ओर बढ़ते हैं या फिर सामूहिक उत्पादन की ओर चलते हैं। इन दोनों पद्धतियों से किसान की मौलिकता नष्ट हो जाती है। वह केवल एक बड़ी मशीन का पुर्जा भर रह जाता है। अतः सरकार को चाहिये कि वह सहकारिता का शनैः शनैः विकास करे।

अमेरिका में, कनाडा में, हालैंड में, स्वेडन में, जर्मनी में, फ्रांस में और बेलजियम में जिनलोगो ने सहकारिता के आधार पर कृषि-उत्पादन, क्रय-

विक्रय आदि की प्रक्रियाएँ देखी हैं वे इसकी सफलता का रहस्य जानते हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसी सहकारिता भारतीय किसान के लिए लाभजनक हो सकती है। यहाँ की आवादी ऊपर लिखे गये देशों की आवादी जैसी धनी है। अतः जो लोग यहाँ में भुखमरी, दरिद्रता, बीमारी आदि दूर करना चाहते हैं उन्हें इसी प्रकार की व्यवस्था आरम्भ करके राष्ट्र का कल्याण करना चाहिये। यहाँ के खनिज समाप्त हो सकते हैं। लेकिन धरती की पैदावार नहीं समाप्त हो सकती है। कविगुरु रवीन्द्रनाथ ने ठीक कहा था— गाव स्त्रियों की तरह अवस्थित है। इनके गर्भ से ही राष्ट्रों का विकास होता है। पर सचमुच असली भारत का जीवन तो गावों में ही उल्लसित है। उसी उल्लास को सुन्दर गति देना प्रगति का द्योतक होगा।





# सोवियत रूस में सम्मिलित कृषि

सोवियत रूस की कृषि-प्रणाली के संवर्धन में बहुधा अनेक प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे, सामूहिक कृषक की सम्पत्ति कितनी होती है? वे क्या बेंच और खरीद सकते हैं? क्या सामूहिक कृषकों के अपने खेत होते हैं? यदि हाँ, तो वे उसे किस प्रकार जोतते हैं? या उसका इन्तजाम कैसे करते हैं।

सोवियत रूस के किसान की सम्पत्ति सामूहिक होती है। कृषि सघों की समस्त सम्पत्ति होती है और सोवियत किसान उसके मदस्य होते हैं। सामूहिक कृषि-सम्पत्ति में घर, कृषि संवर्धन औजार, जानवर और बीज होते हैं। यह समस्त सम्पत्ति और इसकी आय समाजगत कोष के रूप में संचित रहता है जिसके मालिक किसान वर्ग होते हैं। भूमि उन्हीं वर्गों को दी जाती है।

उदाहरण के लिये ताशकेंत के कागानोविच सामूहिक फार्म का आदर्श लिया जाय। इस समूह को ५६०० हेक्टेयर जमीन मिली है जिसमें ३९९० हेक्टेयर में पर्याप्त उत्पादन होता है। इसके अतिरिक्त इस फार्म में ८००० भेड़ें, १००० अन्य जानवर और १००० घोड़े, गधे और ऊट कुल मिलाकर हैं।

प्रत्येक वर्ष फार्म की स्थिति उत्तरोत्तर अच्छी होती जा रही है। वहाँ उत्पादन की आशातीत उन्नति हुई है। १९४५ में यहाँ ३७०० टन कच्ची रूई का उत्पादन हुआ था जिसकी कीमत १५० लाख रूबल हुए। १९५४ में ५८०० टन रूई का उत्पादन हुआ और आमदनी २०० लाख रूबल अधिक हो गई। सामूहिक कृषि प्रक्षेत्र की कुल कीमत २५८८५००० रूबल है। १९४५ में इसकी कीमत १४७९८००० रूबल थी। इसकी मालिकियत भी सामूहिक है। यही सोवियत कृषकों की आय का सबसे प्रमुख साधन है। १९४५ में प्रत्येक परिवार की आय १४००० रूबल था, नकद के अलावा प्रति परिवार को दो टन गेहूँ तथा अन्य प्रकार के अन्नज दिये जाते थे।

घर के आंग-पांग की लगी जमीन में मालिक भी रूस के किसान हैं। इस जमीन में जो बह बंती करता है वह सामूहिक कृषि के अतिरिक्त है। सामूहिक कृषि के नियमों के अनुसार खोटी-खोटी जमीन प्रत्येक कृषक को दी जाती है। गरीब जमीन प्रति परिवार ०.२५ में एक हेक्टेयर तक होती है। इसका वह हमेशा उन्मोचन कर सकता है।

सामूहिक प्रक्षेत्र अतिरिक्तियों के अनुसार किमान अपने मकान का और उसके आंग-पांग की प्रदत्त भूमि का मालिक होता है। उनके पास खेती के औजार आदि भी होने हैं। वह स्वतः जानवर रख सकता है। मुर्गी पाल सकता है।

किसान अपनी और अपने परिवार की आवश्यकता की चीजें खरीदता है। उसकी अपनी जमीन में जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसे बेंच सकता है। चल और अचल सम्पत्ति में घर, कुछ जानवर, मुर्गी, आदि की मर्यादा होती है। कृषकों को इन्हें बेंचने का, किसी को दे देने का या अपनी इच्छा के अनुसार कुछ भी करने का अधिकार होता है। लेकिन जमीन नहीं बेंची जा सकती है चूँकि सोवियत रूस में भूमि पर सबका अधिकार होता है।

अगर सामूहिक कृषि प्रक्षेत्र के सदस्य के परिवार में वृद्धि हो गई तो उसके वृद्धित सदस्य को अलग घर बनाने का अधिकार प्राप्त है और अन्य सामूहिक कृषकों की तरह उसे भी उत्पादन में हिस्सा मिलता है। उसे वैयक्तिक भूमि भी उसी परिमाण में मिलती है जिस परिमाण में औरों को मिलती है।

रूसी विधान द्वारा वहाँ के नागरिकों की निजी सम्पत्ति का संरक्षण मिला है। निजी या वैयक्तिक सम्पत्ति में उसके श्रम या अन्य कामों से बचत, धरेलू सामान, वैयक्तिक सामान आदि आते हैं जिनका वह वारिस है। इसकी सुरक्षा कानून द्वारा की गई है।

(रूसी समाचार समिति ताशकेंत द्वारा प्रदत्त)

